खण्ड-513, अंक-09
बुधवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1942
(03 मार्च, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, वर्ष 2021)

(खण्ड 513 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश,लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	1-6
प्रश्नोत्तर	...	...	7-128
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	128-130
जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर अन्तर्गत कतिपय गावों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	130
उ0प्र0 में भारत सरकार की छात्रवृत्ति वितरण योजना जातिगत न होकर आर्थिक रखे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		130-131
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर विद्युत व्यवस्था में सुधार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	131-132
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ई0आर0पी0 के माध्यम से टेक महिन्द्रा कम्पनी को दिये गये प्रोजेक्ट की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	132
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा अन्तर्गत विकास खण्ड शिवपुर में ग्राम अरनवा से ग्राम रखौना होते हुए ग्राम गोड़ियाना तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		133
जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियाव एवं जलालपुर में पड़ने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	133
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के तालाबों में बाउन्ड्रीवाल तथा सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	133-134
जनपद मेरठ के अन्तर्गत हापुड़ रोड स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	134
उ0प्र0 सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालय अधिशासी हैंड वर्क्स आगरा नहर ओखला के अन्तर्गत स्थित कैनाल कालोनी परिसर में बनायी जा रही वाल्मी फिल्ड हास्टल के निर्माण में हो रही अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		134-135

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण अन्तर्गत मौजा बाईपुर में पशुपालन विभाग की भूमि पर वेटनरी कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	135
जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में कच्चे गड्ढायुक्त मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत नवादा मोड़ से तिलहर मोड़ तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136-137
जनपद चन्दौली के अन्तर्गत न्यायालय निर्माण हेतु किसानों की जमीन अधिग्रहीत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137-138
जनपद बदायूं के विकास खण्ड समरेर में तिगुलापुर से पंचमइया महराज तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद उन्नाव के अन्तर्गत सेंट घाट पर ड्रम (पीपा) वाला पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत कोप व कुरेंम गांव सहित दर्जनों गांवों में नये सिरे से चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138-139
जनपद बरेली में स्थित राजकीय महिला पालीटेक्निक टूटे बिजली के तार एवं खम्भों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार अन्तर्गत बाबूगंज पटेरवा, लक्ष्मीगंज होते हुए बीकरगढ़ मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद अयोध्या के रूदौली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139-140

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा तैनात ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा अमर्यादित, भ्रष्ट आचरण एवं अपने अधीनस्थ दवा व्यवसायियों के साथ लिपिक के साथ गाली गलौज एवं गोली से मारने की धमकी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निमय-301 के अन्तर्गत सूचना	140
जनपद आजमगढ़ के सदर तहसील अन्तर्गत प्रहलाद नगर कालोनी में जल निकासी हेतु नाली व सीवेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निमय-301 के अन्तर्गत सूचना	140-141
जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत गाजीपुर चौचकपुर मुख्य मार्ग से जैदपुरा गांव तक के मार्ग को शहीद के नाम पर कराये जाने के सम्बन्ध में निमय-301 के अन्तर्गत सूचना	141
जनपद मथुरा में समाज कल्याण विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में निमय-301 के अन्तर्गत सूचना	141-142
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	142
मा0 सदस्यों के वेतन भत्तों के सम्बन्ध में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दलीय नेताओं की कमेटी का गठन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	142-145
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)	145-178
माननीय सदस्यों हेतु मध्याहन भोजन की सूचना	178-179
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)	179-206
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	206-213
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 2018 (खण्ड-1, पृष्ठ-1 से 264) तथा (खण्ड-2, पृष्ठ-265 से 535) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)...	213-214
उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2016-2017	214
उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2017 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	214
श्री सुभाष राय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	214-215

विषय			पृष्ठ-संख्या
श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	...		215
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	...		215-216
श्री किशन लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की पीलीभीत से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	...	...	216
श्री बाबू राम पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	...	...	216-217
श्रीमती पिंकी सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित सात याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...		217
श्री आनन्द शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित सोलह याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...	...	217-219
श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...	...	219
श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...	...	219
श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...	...	219-220
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की पाँच व कानपुर देहात से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)			220-221
श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...	...	221
डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...	...	222
श्री काली प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...	...	222
श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...	...	222
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...	...	223

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री दिनेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	223
श्री राहुल प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	223
कुँ नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	223-224
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	224
श्री संजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	225
श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पाँच याचिकाए (उपस्थित की हुई मानी गयी)	225-226
श्री मूलचंद्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	226
श्री विजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	226
श्री रवि कुमार सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	226
श्री उमाशंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	226
श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	227
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	227
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	227-228
डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	228-229
श्री अरुण कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	229

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	229
श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	229-230
श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	230
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	230
डॉ0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	230-231
डॉ0 संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	231
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर व जनपद उन्नाव से सम्बन्धित एक-एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	232
श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	232
श्री उपेन्द्र नाथ पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	232
श्री प्रमोद उटवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	233
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	233
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	233-235
अनुपूरक कार्य-सूची की मदों को आज ही लिए जाने का अनुरोध ...	236
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक 2021 (पुरः स्थापित)	236
उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित) ...	236
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	237-254

विषय	पृष्ठ-संख्या
बजट चर्चा में प्रतिभाग करने से वंचित मा0 सदस्यों के लिखित भाषण को कार्यवाही में सम्मिलित किये जाने की मांग	254
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	254-282
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल-56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	282
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	282-283
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	283-286
नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत डूडा में व्याप्त अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) ...	286
प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	286-288
जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत भोगनी सागर तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार कटियार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य ...	289-290
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में तमसा नदी के पुनरुद्धार हेतु लघु सेतु/पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	290
प्रदेश में उचित दर की दुकानों में घटतौली रोके जाने हेतु ई-पॉस की प्रक्रिया को अपनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	291-292
जनपद शाहजहाँपुर में अवैध कब्जा हटाये जाने एवं कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशनलाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ...	292-296
जनपद बदायूं में नगर पंचायत उसेहत की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	296

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में हो रहे अवैध खनन की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	297-301
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड फतेहपुर के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	301
जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	302-306
छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय कानपुर में हुए घोटाले की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित) ...	306
उत्तर प्रदेश में जिला अस्पतालों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	307
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)... ...	308
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ...	308-340
नत्थियां	341-361

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 03 मार्च, 2021 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-354

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार सिंह''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
4. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
9. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
12. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
13. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
14. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
15. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
16. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
17. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
21. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
22. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
23. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
24. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
25. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
26. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
27. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
28. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
29. अवधेश सिंह, प्रो0 (डॉ0) — वाराणसी
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
31. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
32. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
33. असलम अली, श्री — हापुड़
34. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
35. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
36. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
37. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
38. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
39. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
40. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
41. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
42. आशुताष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
43. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
44. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
45. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी,श्री — फैजाबाद
46. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
47. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
48. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
49. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
50. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री — कानपुर नगर
51. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया

52. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
53. उषा सिरोही, श्रीमती बुलन्दशहर
54. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
55. ओमकुमार, श्री बिजनौर
56. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
57. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
58. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
59. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
60. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
61. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
62. काली प्रसाद, श्री देवरिया
63. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
64. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
65. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
66. कृष्ण पाल मलिक बागपत
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. केसर सिंह, श्री बरेली
69. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
70. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
71. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
72. गंगा, श्री कुशीनगर
73. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
74. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
75. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
76. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
77. गौरी शंकर, श्री जालौन
78. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
79. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
80. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
81. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
82. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
83. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
84. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
85. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
86. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
87. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
88. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
89. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
90. जितेन्द्र वर्मा श्री आगरा
91. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
92. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
93. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
94. डेनजिल जे0 गोडिन, डॉ0 नाम-निर्देशित
95. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
96. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
97. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
98. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
99. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
100. दल बहादुर, श्री रायबरेली
101. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
102. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
103. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
104. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
105. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
106. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
107. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
108. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
109. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
110. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
111. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
112. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
113. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
114. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
115. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
116. नईम उल हसन, श्री बिजनौर

117. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
118. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
119. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
120. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
121. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
122. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
123. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
124. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
125. नाहिद हसन, श्री शामली
126. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
127. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
128. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
129. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
130. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
131. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
132. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
133. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
134. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
135. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
136. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
137. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
138. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
139. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
140. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
141. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
142. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
143. प्रभाषा कुमार, श्री हरदोई
144. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
145. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
146. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
147. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
148. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
149. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
150. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
151. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
152. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
153. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
154. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
155. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
156. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
157. बावन सिंह, श्री गोण्डा
158. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
159. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
160. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
161. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
162. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
163. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
164. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
165. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
166. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
167. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
168. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
169. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
170. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
171. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
172. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
173. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
174. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
175. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
176. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
177. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
178. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
179. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
180. महबूब अली, श्री अमरोहा
181. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
182. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
183. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा

184. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
185. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
186. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
187. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
188. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
189. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
190. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
191. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
192. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
193. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
194. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
195. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
196. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
197. योगेश धामा, श्री बागपत
198. योगेश वर्मा, श्री खीरी
199. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
200. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
201. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
202. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
203. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
204. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
205. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
206. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
207. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
208. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
209. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
210. रवि शर्मा, श्री झांसी
211. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
212. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
213. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
214. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
215. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
216. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
217. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
218. राज करन कबीर, श्री बांदा
219. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
220. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
221. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
222. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
223. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
224. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
225. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
226. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
227. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
228. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
229. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
230. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
231. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
232. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
233. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
234. राम गोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
235. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
236. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
237. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
238. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
239. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
240. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
241. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
242. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
243. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
244. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
245. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
246. लकी यादव, श्री जौनपुर

247. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
248. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
249. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
250. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
251. विक्रम गुप्ता, श्री फतेहपुर
252. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
253. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
254. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
255. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
256. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
257. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
258. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
259. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
260. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
261. विनय शाक्य, श्री औरैया
262. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
263. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
264. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
265. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
266. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
267. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
268. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
269. वीरेन्द्र, श्री एटा
270. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
271. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
272. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
273. शशांक वर्मा, श्री खीरी
274. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
275. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
276. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
277. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
278. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
279. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
280. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
281. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
282. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
283. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
284. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
285. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
286. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
287. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
288. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
289. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
290. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
291. संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
292. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
293. संजय, श्री बुलन्दशहर
294. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
295. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
296. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
297. संजय यादव, श्री बलिया
298. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
299. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
300. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
301. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
302. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
303. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
304. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
305. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
306. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
307. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
308. सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डॉ0 देवरिया
309. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
310. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
311. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
312. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा

313. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
314. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
315. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
316. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
317. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
318. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
319. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
320. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
321. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
322. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
323. सुभाष राय, श्री अम्बेडकर नगर
324. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
325. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
326. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
327. सुरेश कुमार, श्री शामली
328. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
329. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
330. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
331. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
332. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
333. सुरेश राही, श्री सीतापुर
334. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
335. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
336. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
337. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
338. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
339. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
340. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
341. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
342. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
343. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
344. सौरभ सिंह, श्री खीरी
345. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
346. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
347. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
348. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
349. हरीराम, श्री सोनभद्र
350. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
351. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
352. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
353. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
354. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट : मुख्य मंत्री (श्री योगी अदित्यनाथ) एवं उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी-(क)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नगरपालिका क्षेत्र में कूड़े से खाद बनाये जाने हेतु संयंत्र लगाये जाने विषयक

***1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी नगर पालिका क्षेत्र में कूड़े से खाद बनाये जाने हेतु संयन्त्र लगाये गये तथा उनमें से कितने वर्तमान में सुचारु रूप से काम नहीं कर रहे हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि घनी आबादी में लगे उक्त संयन्त्रों के प्रदूषण से उन क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियां हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे संयन्त्रों को आबादी से बाहर लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, शहरी समग्र विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी")-

जी हाँ।

प्रदेश में 24 नगर निकायों (13 नगर पालिका परिषद एवं 11 नगर निगम) में कूड़े से खाद बनाये जाने हेतु संयंत्र पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मोड पर विगत वर्षों में लगाये गए हैं, जिनमें से 10 अस्थायी रूप से संयंत्र ऑपरेटर से आर्बिट्रेशन/विवाद के कारण सुचारु रूप से काम नहीं कर रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

पहला प्रश्न है श्री मनोज पाण्डेय जी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जो पहले प्रश्न का जवाब दिया है और उसमें स्वीकार किया है कि आर्बिट्रेशन विवाद के कारण 10 ऐसे संयंत्र हैं जो वर्तमान समय में सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमने पूछा था कि क्या उक्त संयंत्रों से प्रदूषण से उन क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियाँ हो रही है ? इसका उत्तर है जी नहीं। तीसरा प्रश्न था कि क्या सरकार ऐसे संयंत्रों को आबादी से बाहर लगाये जाने पर विचार करेंगी ? इसका उत्तर है कि प्रश्न नहीं उठता। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा और आग्रह पूर्वक उनको जानकारी भी देना चाहूँगा कि अगर यह संयंत्र लगे हुए हैं तो निश्चित

तौर से नगर पालिकायें, नगर निकाय कूड़ा वहां पर इकट्ठा कर रही हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि रायबरेली में भी इसी योजना के अन्तर्गत एक संयंत्र लगाया गया था, वह संयंत्र जिन भी कारणों से लगाया गया, वह घनी आबादी के बीच में लगाया गया और वहां पर लगभग 3 हजार ट्रक कूड़ा इकट्ठा है जिसको प्रदूषण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है और यह रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध भी है। प्रदूषण विभाग ने यह भी स्वीकार किया है कि इस कूड़े के कारण काफी संक्रामक बीमारियाँ पैदा हुई हैं और पिछले साल उसी क्षेत्र में 168 डेंगू के केसेज भी आए है। संयंत्र पूरी तरह बंद है, डिस्टिक मजिस्ट्रेट ने भी यह रिपोर्ट दी है। पिछले डेढ़ साल से वहां पर बिजली कटी हुई है, कनेक्शन नहीं है और यदि वह संयंत्र घनी आबादी में लगा हुआ है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि वहां पर किसी प्रकार की संक्रामक बीमारियाँ आगे न फैले और इसमें जैसा कि आपके संज्ञान में होगा कि संयंत्र लगाने वालों को पी0पी0पी0 मोड पर भारत सरकार से भारी अनुदान मिला है किन्तु ये लोग केवल धन का दुरुपयोग कर रहे है और ये लोग दिल्ली में बैठते हैं कभी अपने संयंत्र पर नहीं जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जहां पर प्रदूषण फैल रहा है उसकी जांच करा करके और जो संयंत्र घनी आबादी के बीच में लगा हुआ है क्या जनहानि को देखते हुए उसको वहां से हटवाये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री आशुताष टण्डन "गोपाल जी"-

माननीय अध्यक्ष जी, अब कही संयंत्र लगता कूड़ा निस्तारण का तो पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो गाइड लाइन तय है, अब उसके आधार पर लगता है। 2011 में प्राइवेट पार्टनरशिप में पी0पी0पी0 मोड पर लगा है और 2011 में 30 वर्ष का अनुबन्ध हुआ है रायबरेली का और वहां पर यह संयंत्र चालू है, बन्द नहीं है और जिस समय लगा था उस समय मानक यह थे कि 500 मीटर के अन्दर कोई वहां पर आबादी न हो। 2016 में यह दूसरी गाइड लाइन जारी हुई जिसको 200 मीटर कर दिया गया अब वहां विगत वर्षों में बहुत से लोगों ने अपने मकान बना लिये उसको अच्छा शब्द नहीं है अगर कहें कि अवैध रूप में उसमें संयंत्र लगाने में कोई त्रुटि नहीं है अभी तक किसी संक्रामक रोग की सूचना वहां से प्राप्त नहीं है। रायबरेली संयंत्र के बारे में यह पूरी जानकारी है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से संज्ञान में हम यह लाना चाहते है कि वहां पर विकास प्राधिकरण ने 354 नक्शे पास किये थे और वह नक्शे ऐसे पास है कि 100 मीटर और 50 मीटर पर भी मकान बने हुए है और यह 2009 में पास किये है अगर 2009 में विकास प्राधिकरण ने नक्शे पास किये तो उन्होंने गलत किया 2011 और 2012 में लगा एक संयंत्र 2011 के अन्त तक लग गया था। कृष्णा नगर, तिलक नगर और वहां पर महिमापुर नगर पी0डब्लू0डी0 कालोनी, पी0एच0सी0 कालोनी इन सबकी दूरी 150 मीटर के अन्दर की होगी यह सूचना आप पुनः चेक करा लें, हमें यह लगता है कि यह सूचना अधिकारी गलत दे रहे है।

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

माननीय अध्यक्ष जी, हम चेक करा लेंगे, 2011 में लगा था और रायबरेली तो ऐसी जगह है कि जहां हमारे वरिष्ठ सदस्य मनोज जी हैं और वह वहां मंत्री भी रहे और आदरणीय सोनिया गांधी भी वहां सांसद रही उनका सब लोग बड़ा आदर करते हैं और इतने बड़े-बड़े लोगों के बाद गलत संयंत्र गलत जगह पर 2011 में कैसे लग गया और फिर चलता कैसे रहा ? यह वहां पर बाद में लोगों ने 200 मीटर के अन्दर घर बना लिये है और उसके लिए संयंत्र उत्तरदायी नहीं है फिलहाल वहां काम चल रहा है जो वहां पर कूड़ा इकठ्ठा है उसका निस्तारण भी शुरू हो गया है अब संयंत्र को दूसरी जगह स्थानान्तरित करना यह बहुत बड़ा काम है जमीन की व्यवस्था करना और वहां से ले जाना यह फिलहाल सम्भव नहीं है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है कि 24 नगर निकायों जिसमें से 13 नगर पालिका परिषद एवं 11 नगर निगम में कूड़े से खाद बनाये जाने हेतु संयंत्र लगे हुए है। इसमें माननीय मंत्री जी ने यह भी जवाब में दिया है कि इसमें से 10 जो ऐसे संयंत्र है जिसमें आपरेटरों से आरबीट्रेशन की भी बात चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि अभी तो आपरेटरों से आरबीट्रेशन चल रहा है। ट्रिपल-पी से जब कोई भी अनुबन्ध होते है उसमें एक अंश गवर्नमेन्ट का भी लगता है या तो 20-80 का रेशियो होता है और 30 साल का अनुबन्ध है वह आरबीट्रेशन के वजह से यह बाधित है तो फिर एक बड़ा आरबीट्रेशन आयेगा जिन्होंने ट्रिपल पी में इसको लगाया है और गवर्नमेन्ट को उसमें फिर हारना पड़ेगा बहुत बड़ी राशि मैनुपुलेशन करके आरबीट्रेशन कराया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें और जल्द ही इसका निस्तारण कर दें दूसरा जिस तरह से अभी तक 13 नगर पालिका परिषद में हो कूड़े से खाद बनाने के संयंत्र लगे है। क्या माननीय मंत्री जी आज के प्रदूषण को देखते हुए अन्य नगर पालिकायें आदर्श नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश में है क्या उन सभी जगहों पर इस कूड़े से खाद्य बनाये जाने के संयंत्र लगाये जाने पर विचार करेंगे ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

माननीय अध्यक्ष जी, 24 जो मैंने बताया इनके अतिरिक्त 8 और हैं जहां पर भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस चल रहा है और उसके बाद 15-16 और प्रस्तावित है। हम क्रमशः इसको अन्य जगहों पर भी लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

जिसके पास भी मोबाइल हो या तो आप उसको मृतक प्राय कर दें या अगर यहां न लाया करें तो बड़ी कृपा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कल यहां फोटो ले रहे थे कुछ परम्परायें हैं उनका ध्यान रखिये।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा शिक्षकों की प्रोन्नति एम0सी0आई0 के मानकानुसार भर्ती नियमावली में संशोधन करने विषयक

***1-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा शिक्षकों की प्रोन्नति एम0सी0आई0 के मानक पूर्ण कर लेने के उपरान्त करने हेतु राज्य चिकित्सा शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी नहीं। उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 (यथासंशोधित 2018) वर्तमान में लागू है, जिसमें प्रोन्नति का प्राविधान विद्यमान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश सरकार लगभग हर जिले में मेडिकल कालेज स्थापित कर रही है लेकिन जो पहले से स्थापित मेडिकल कालेज है उनमें एम0डी0 और एम0एस0 की मान्यता इसलिये नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एम0सी0आई0 ने मानक में शिथिलता दी है कि तीन साल में असिस्टेण्ट प्रोफेसर होगा, चार साल पर एसोसिएट प्रोफेसर होगा, आठ साल पर प्रोफेसर हो जायेगा। इसके अतिरिक्त दोहरी व्यवस्था भी लागू है। जहां कान्ट्रेक्ट पर हम नियुक्ति कर रहे है वहां पर हम एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार इनको पोस्ट कर रहे हैं लेकिन जहां लोक सेवा आयोग से हमारे शिक्षक आ रहे है वहां हम उनको एम0सी0आई0 के मानक का लाभ नहीं दे रहे है जिसके कारण शिक्षकों की कमी बनी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि एम0सी0आई0 का जो मानक है कि इतने इतने वर्ष में प्रोन्नति की जायेगी, के अनुसार क्या प्रदेश के हित में सेवा नियमावली में परिवर्तन करने की कृपा करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत हम राजकीय मेडिकल कालेजों में सहायक आचार्य के रूप में भर्ती करते हैं। उसके बाद जब चार साल बीत जाते हैं तो उनको सह आचार्य के रूप में प्रोन्नति देते हैं। यह प्रोन्नति की शत प्रतिशत व्यवस्था है कि

यदि सहायक आचार्य के रूप में चयनित व्यक्ति का चरित्र ठीक है तो चार साल में उसको सह आचार्य पद पर प्रोन्नति मिलनी ही मिलनी हैं। सह आचार्य से आचार्य के रूप में प्रोन्नति के लिए वर्तमान में चार साल का मानक है और उसमें 75 परसेण्ट लोग प्रोन्नति से आते हैं और 25 परसेण्ट सीधे लोक सेवा आयोग के माध्यम से आते है। माननीय वर्मा जी जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है कि एम0सी0आई0 का मानक है कि इसमें तीन साल की सेवा अनिवार्य हो और चार रिसर्च पेपर पब्लिश हो। हालांकि पहले 2005 की जो नियमावली थी उसमें हम प्रवक्ता के रूप में नियुक्त करते थे और उसके बाद सहायक आचार्य बनाते थे, उसके बाद सह आचार्य बनाते थे और तब आचार्य बनने के लिए उसको 11 साल का लम्बा कार्यकाल बिताना पड़ता था। यह सही है कि यदि हम एम0सी0आई0 का मानक लागू करें तो सात साल में आचार्य बनाया जा सकता है। हमारे यहां पर जिसे हम सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति देते हैं उसको आचार्य बनाने में आठ साल लग जाते है। मान्यवर, इस पर हम विचार कर लेंगे और मैं समझता हूँ कि यह प्रदेश के हित में है इसलिये इस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रदेश में क्रिटिकली/सीरियसली प्रदूषित औद्योगिक समूहों को चिन्हित करने व दोषियों पर कार्यवाही विषयक

***2-श्री नाहिद हसन-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्रिटिकली/सीरियसली प्रदूषित कितने औद्योगिक समूहों को चिन्हित कर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कितने औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध दिनांक 24-04-2020 तक क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार प्रदूषित औद्योगिक समूहों की जलीय एवं वायु गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराये गए अनुश्रवण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर देश में कुल चिन्हित 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों में 09 क्रिटीकली पॉल्यूटेड एरिया (मथुरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी-मिर्जापुर, बुलन्दशहर-खुर्जा, फिरोजाबाद, गजरौला, आगरा, गाजियाबाद) एवं 04 सीरियसली पॉल्यूटेड एरियाज (नोयडा, मेरठ, अलीगढ़, सिंगरौली) उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षणों में दोषी पाए गए उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार कारण बताओ नोटिस/बन्दी आदेश एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जाती है, जोकि एक सतत् प्रक्रिया है।

जी हाँ।

उक्त क्षेत्रों के पर्यावरणीय प्रबन्धन हेतु कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-02-2020 द्वारा उक्त क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु कड़े मानक निर्धारित किए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त

प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिये उक्त समस्त क्षेत्रों हेतु कार्य योजनाएँ क्रियान्वित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न किया था उसमें मैंने पूछा था कि सहारनपुर मण्डल में जो दो, तीन जिले हैं उसमें क्रीटिकल प्रदूषित में उसको जोड़ने का सरकार क्या विचार कर रही है और इसके साथ जिन क्षेत्रों के क्रीटिकली पाल्यूटेड में मुझे जो जवाब मिला है इसमें सिर्फ शहरों के नाम हैं उसमें अगर लिस्ट भी मिल जाये कि किसके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की है ? क्योंकि इसमें सहारनपुर नहीं है, मुजफ्फरनगर नहीं है, शामली नहीं है और हमारे क्षेत्र में थोड़ा अलग हो गया है और उसके बगैर मैं प्रश्न भी नहीं पूछ पाऊँगा इसलिए सहारनपुर का मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। हमारे यहां शुगर मिल बहुत सारी ऐसी है जो बिल्कुल शहर से लगती हुई है। खासतौर से शामली में अभी कुछ दिन पहले मिल द्वारा गैस लीक हुई वहां पड़ोस में एक स्कूल था जहां पांच सौ बच्चों को एकदम से गैस लीक होने की वजह से परेशानी हुई जिस कारण उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ा। ऊपर वाले का शुक्र है कि ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। हम लोगों ने जब विरोध किया तब मिल मालिक के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, जिसमें अब जाकर मालूम पड़ता है कि उसने एफ0आर0 लगा दी और वह शहर से बिल्कुल नजदीक में है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो शुगर मिल है उन पर आप अपनी तरफ से किसी इंस्टीट्यूशन से या अपनी तरफ से उसकी जांच करा लीजिए। एन0जी0टी0 के क्षेत्रों में या रेसीडेंसीयल एरिया में जो जुड़े हुए हैं। वहां अगर कोई कमी पाई जाती है तो उनमें क्या-क्या आप कार्यवाही करेंगे ? दूसरी चीज जो स्लॉटर हाऊस हैं, मैं सहारनपुर का बताना चाहता हूं जिस तरीके से वहां पर बदबू आती है कोई आम आदमी वहां से निकल नहीं सकता है और उसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। जहां 100 के काटने की अनुमति है वहां पर हजारों-हजारों काट रहे है और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वहां पर कोई न कोई ऐसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए जो उन लोगों पर नजर रख सके ताकि जितनी परमीशन है उतना ही काटा जाए या फिर शहर से अलग सरकार उनको कहीं बाहर स्थापित करने के लिए जगह दे दे। इस तरह की दो चीजें हैं एक शुगर मिल है, दूसरा स्लॉटर हाऊस है क्योंकि इससे आम जनता को ज्यादा परेशानी होती है। इसमें सहारनपुर नहीं था मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या सरकार इसकी जांच कराकर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

श्री दारा सिंह चौहान-

मान्यवर माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, आपने जिस पर्टीकुलर जिला का नाम लिया है चूंकि आपने 24-04-2020 तक के आंकड़ों के बारे में पूछा है। और क्योंकि आंकड़े तो बहुत बड़े हैं। चूंकि सी0पी0सी0पी0 के द्वारा वर्ष 2016 में जो क्रिटिकल और लिब्रली जितनी प्रदूषित इकाईयाँ थी उनकी कार्य योजना बनायी गयी है और पूरी सूची हमने उस समय जो दोषी थे 2921, उसमें सारा कुछ शामिल है और उसमे 611 के खिलाफ बंदी और कारण बताओ नोटिस दिया गया है। 165 के विरुद्ध प्रासीक्यूशन की कार्रवाई की गयी और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 64 करोड़ 22 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। जो स्लाटर हाउस का आपने पूछा है चूंकि इससे संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी एन0ओ0सी0 देते समय जो भी मानक होते हैं अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ हम बंदी का आदेश करते हैं। क्योंकि हमने उत्तर में दिया है कि एक सतत् प्रक्रिया है जो आपने पूछा है उसके बाद भी इधर 9-10 महीने से हमने कार्यवाही की है। मा0 सदस्य ने सूची जाननी चाही है तो मैं सूची उपलब्ध करा दूंगा।

श्री नाहिद हसन-

क्या सरकार इसमें सहारनपुर और मुजफ्फरनगर को शामिल करेगी ? मेरा कहना है कि इसको शामिल कर लिया जाये और लिस्ट दे दी जाये।

श्री दारा सिंह चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं उसको शामिल करते हुये सूची आपको भिजवा दूँगा।

प्रदेश में पालीथिन बैग से पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के दृष्टिगत पॉलीथिन के उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने विषयक

***3-श्री संजय गर्ग-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पॉलीथिन बैग से हो रहे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के दृष्टिगत प्रदेश में पॉलीथिन बैग के उपयोग पर सरकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-29 सन् 2000) (यथासंशोधित) की धारा 6क, 7, 12 और 13क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के क्रम में निर्गत अधिसूचना संख्या-1056/नौ-7-2018-29 (लखनऊ)/2018, दिनांक 15-07-2018 द्वारा राज्य के समस्त नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी में आने वाले क्षेत्रों में दिनांक 15-08-2018 से प्लास्टिक या धर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों तथा दिनांक 02-10-2018 से समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी

बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध् किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है और सन् 2000 में इसकी गंभीरता को देखते हुये उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम पास किया गया। जिसमें 2018 की राजाज्ञा के द्वारा मा0 मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि इसमें समस्त नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी में आने वाले क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया गया है। मेरे कुछ प्रश्न आपके माध्यम से इस नजरिये के साथ है कि आज भी उन तमाम प्लास्टिक के कपों और उपयोग में आने वाले कैरी बैग की रंगबिरंगी थैलियाँ खेतों में देखने को मिलती हैं। गाँवों में जो साप्ताहिक बाजार है उसमें इसका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। इसके विनिर्माण भण्डारण और परिवहन और आयात और निर्यात पर भी प्रतिबंध है। परंतु इस सबके बावजूद बिक्री करने वाले ना जानकार ऐसे छोटे व्यापारियों का अभी भी नगर निगम, नगर पंचायतों में उत्पीड़न हो रहा है। मेरा केवल यह प्रश्न है कि जो 15-08-2018 का आदेश है उसके माध्यम कितने माइकोग्राम तक के कैरीबेग पर प्रतिबंध लगाया गया है और क्या साप्ताहिक बाजार को इन्क्लूड करते हुये ग्राम पंचायतों को भी इसमें सीमांकित करने की कोशिश करने का काम सरकार करेगी। बजाये इसके कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और राज्य की औद्योगिक नगरी के बजाय समस्त उत्तर प्रदेश में। अध्यक्ष जी, क्योंकि कहीं भी इसकी लीकेज है, तो वहां पर सहूलियत को देखते हुए, उसे इंसान एडाप्ट करता है, इस्तेमाल करता है, इससे ग्रीन हाउस इ इफेक्ट की गैसें पैदा होती है जो धरती की फर्टिलिटी को कम करती है, इसी के साथ गाय-भैंसें उसे खाती है, ड्रेनेज ब्लॉक हो जाते है। इस तरह की तमाम समस्याएं पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 से अभी तक विनिर्माण करने वाली कितनी यूनिटों के चालान हुए हैं ? इसको बनाने वाले उसे जड़ से समाप्त कर दें तो हम समझते है कि कुछ हद तक इस पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। भण्डारण के नाम पर व्यापारियों के कितने चालान किये गये हैं ? उन चालानों की संख्या अत्यधिक ज्यादा है तो इससे अच्छा है कि किसी तरह से उस इकाई को ही बन्द कर दिया जाए जहां पर इनका निर्माण हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से यह प्रश्न है कि वह कितने माइक्रोन तक के हैं, क्या समस्त उत्तर प्रदेश को इसमें सीमांकित करने का सरकार विचार कर रही है या नहीं कर रही हैं ? विनिर्माण करने वाली कितनी इकाइयों के चालान हुए हैं और भण्डारण के कितने चालान हुए हैं ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

माननीय अध्यक्ष जी, सभी तरह के कैरी बैग प्रतिबंधित है वह चाहे कितने भी माइक्रोन के हों। दूसरा आपने कार्यवाही की बात की है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उत्पीड़न

हो रहा है। अब अगर कार्यवाही होगी तो सख्ती जरूर होगी। जो कार्यवाही हुई है उसमें 936.72 टन माल जब्त हुआ है और 12.42 करोड़ रुपये का जुर्माना हुआ है। मा0 सदस्य की बात से सरकार सहमत है कि प्लास्टिक के बहुत दुष्प्रभाव है और इसको सख्ती से लागू किया जायेगा।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र के अलावा जो एरिया छूट गया है। ग्राम पंचायत, साप्ताहिक बाजार को शामिल करते हुए समस्त उत्तर प्रदेश पर सरकार विचार करेगी या नहीं ? इनको बनाने वाली कितनी फैक्ट्रियों का चालान किया गया है ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

माननीय अध्यक्ष जी, इनको बनाने वाली फैक्ट्रियों के भी चालान हुए हैं। मैंने आपको कुल फीगर बताया है और आपको बाकी डिटेल्स भिजवा दूंगा। इसका नगरीय क्षेत्र में पूर्णतया प्रतिबंध है और जो साप्ताहिक बाजार नगरीय क्षेत्र में लगते है उस पर भी प्रतिबंध है और हम आपके सुझाव पर विचार करेंगे।

कोरोना में लॉकडाउन के कारण प्रदेश में प्रदूषण के स्तर व पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखने हेतु योजना विषयक

***4-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोरोना वैश्विक महामारी में किये गये लॉकडाउन में प्रदेश में प्रदूषण (वायु, जल, आदि) का स्तर कम हुआ है ? यदि हां, तो कितना ? क्या सरकार स्वच्छ हुए पर्यवरण को शुद्धता के स्तर पर बनाये रखने के लिए कोई ठोस योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हाँ।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के प्रमुख शहरों यथा आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, नोयडा, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर एवं ग्रेटर नोयडा में संचालित सतत् परिवेशीय अनुश्रवण केन्द्रों के माध्यम से वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य किया गया। सतत् परिवेशीय अनुश्रवण केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह अप्रैल, 2019 (लॉकडाउन के पूर्व) की तुलना में माह अप्रैल, 2020 (लॉकडाउन अवधि) में वायुगुणता सूचकांक (ए0क्यू0आई0) में सुधार परिलक्षित हुआ है। यह सुधार 27.3 प्रतिशत (बुलन्दशहर) से 66.2 प्रतिशत (लखनऊ) के मध्य पाया गया है।

बोर्ड द्वारा माह अप्रैल, 2020 (लॉकडाउन अवधि) के दौरान प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, रामगंगा एवं हिण्डन की जलगुणता का अनुश्रवण कराया गया। गंगा नदी के जल में माह अप्रैल, 2020 में अप्रैल, 2019 (लॉकडउन के पूर्व) की तुलना में प्रदूषण भार नापने के प्रमुख प्रचालक

बी0ओ0डी0 के मान में 4.2 से 42.9 प्रतिशत, यमुना नदी के जल में 9.1 से 38.5 प्रतिशत, रामगंगा नदी के जल में 16.1 से 46.7 प्रतिशत एवं हिण्डन नदी के जल में 9.1 से 70.9 प्रतिशत की गिरावट पायी गयी है।

उक्त के प्रमुख कारणों में से एक कारण नदियों के जल बहाव में वृद्धि होना भी है।

जी हाँ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 तक पी0एम0 10 (पर्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रॉन से कम आकार) एवं पीएम 2.5. (पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रॉन से कम आकार) की मात्रा में 20-30 प्रतिशत की कमी लाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के 15 नान-अटेन्टमेंट शहरों (अतिप्रदूषित) यथा नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, खुर्जा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, अनपरा, गजरौला, मुरादाबाद, रायबरेली, झाँसी एवं बरेली में वायुगुणता सुधार हेतु कार्य योजना तैयार कर तथा उन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से अनुमोदित कराकर क्रियान्वित किया जा चुका है। इस कार्य योजना में कुल 59 कार्यवाही के बिन्दु तथा कार्यवाही किये जाने हेतु 20 विभागों को चिन्हित किया गया है। उक्त कार्य योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन का अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति द्वारा तथा राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित "एयर क्वालिटी मानीटरिंग कमेटी" द्वारा किया जाता है। उ0प्र0 के अन्तर्गत 12 नदियों यथा यमुना, वरुणा, काली, हिंडन, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सरयू तथा सई नदियों के प्रदूषित अंशों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन तथा जल गुणता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु कार्य योजनायें सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा चुकी है। उक्त कार्य योजनाओं के समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन का मासिक अनुश्रवण जिलाधिकारी के स्तर पर गठित जिला पर्यावरण समिति द्वारा एवं राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित "रीवर रीजुवेनेशन समिति" द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आजाद अरिमर्दन-

मान्यवर, मैंने सिर्फ मा0 मंत्री जी से इतना ही पूछा था कि क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वैश्विक महामारी में किये गये लॉकडाउन में प्रदेश में प्रदूषण (वायु, जल आदि) का स्तर कम हुआ है ? पूरा प्रदेश ही नहीं, देश भी जानता है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण कम हुआ था। मा0 मंत्री जी से दो-तीन छोटे-छोटे सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 12 नदियों के प्रदूषित होने के बारे में बताया लेकिन जो जनपद आजमगढ़ में तमसा नदी के किनारे बसा है, मा0 मंत्री जी भी सौभाग्य से हमारे ही जनपद के है, आय दिन नदी में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और तमसा नदी में गन्दा पानी, कचड़ा खुलेआम डाला जा रहा है। क्या मंत्री जी तमसा नदी में गिरने वाले गंदे पानी को तत्काल रोकने का काम करेंगे ? दूसरा, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जल प्रदूषण कम होने का प्रमुख कारण, उन्होंने उत्तर में दिया है

कि नदियों के जल बहाव में वृद्धि, तो नदियों का जल बहाव अनवरत् बना रहे, ऐसी कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है, विशेषकर वर्ष में नवंबर से जून तक, जब नदियों का जल स्तर सबसे कम होता है और उन महीनों में अनवरत् जल बहाव बना रहे, क्या सरकार उस पर कोई कार्य योजना बना रही है ? तीसरा, कोरोना महामारी के दौर में वायु, जल प्रदूषण बहुत कम हो गया, उसी स्तर पर वायु की शुद्धता बनी रहे, उसके लिए क्या सरकार ने कोई कार्य-योजना बनाई है ? अगर बनाई है तो उसके लिए कितना धनावंटन किया गया है ?

श्री दारा सिंह चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य के सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। फिर भी मा0 सदस्य की जिज्ञासा है, खासकर अपने क्षेत्र को लेकर, चूंकि भारत सरकार सी0पी0सी0पी0 के दिशा-निर्देश है कि 2024 तक इसमें 20 से लेकर 30 प्रतिशत कमी की जाये, उस पर हमारा विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। नदी और वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए हमारी कार्य योजना तैयार है। मा0 सदस्य ने जो जानना चाहा है आजमगढ़ की तमसा नदी के बारे में, क्योंकि मैं भी वहीं का रहने वाला हूं, उसके लिए आप जानते होंगे कि जब से हमारी सरकार बनी, पूरे प्रदेश की तमाम नदियों के पुनर्जीवन के लिए वृहद कार्य योजना हमने बनाई है और यही कारण था कि आपने देखा कि कुंभ में जहां करोड़ो लोगों ने स्नान करके प्रमाण दे दिया कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की नदियां साफ-सुथरी है। जहां तक तमसा नदी का सवाल है मैं मा0 सदस्य को बताना चाहूंगा और उनको खुशी भी होगी कि तमसा नदी के लिए कार्य योजना बना दी गयी है, सी0पी0सी0पी0 से अनुमोदन के बाद उस पर भी कार्रवाई शुरू करेंगे।

प्रदेश के इंडिया मार्का हैंडपंपों के जल की शुद्धता जांच कर दूषित पेयजल वाले पम्पों को बंद करने व शुद्ध जल उपलब्ध कराने संबंधी

***5-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित इंडिया मार्का हैंडपंपों के जल का परीक्षण कराकर दूषित पेयजल वाले हैंडपंपों को बंद कराने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में स्थापित हैण्डपम्पों के संचालन/रख-रखाव का कार्य संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा हैण्डपम्प की स्थापना के समय जल का परीक्षण कराया जाता है तथा प्राप्त जल मानक के अनुरूप पाये जाने के उपरान्त कार्य पूर्ण कराकर संबंधित निकाय को हस्तानान्तरित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(मा0 नगर विकास मंत्री द्वारा लिखित उत्तर पढ़ा गया)

श्री मो0 फईम इरफान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि यह जो नगरीय क्षेत्र वाला मामला है, इसमें हैण्डपम्प लगाने की जो व्यवस्था है, वह एक अजीबोगरीब तरीके से है, क्योंकि आपका जो नगर निगम है, वह नगर पालिकाओं से प्रस्ताव लेकर जल निगम से हैण्डपम्प लगवाता है। लेकिन हैण्डपम्प लगाने के बाद ही उन हैण्डपम्पों में जब दूसरे दिन ही दूषित जल आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जल निगम उन्हें लगाने के बाद सारी जिम्मेदारियाँ नगर निगम या नगर पालिकाओं को दे देते हैं, लेकिन नगर पालिकाएँ फिर उनको यह कह कर टाल देती है कि उसे तो जल निगम ने लगाया है, हम लोग उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। माननीय मंत्री जी, जो इण्डिया मार्का हैण्डपम्प से शुद्ध पेयजल के धोखे में लोग दूषित पेयजल पी रहे है, उस सम्बन्ध में मेरे द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। मान्यवर, जितना महत्वपूर्ण मेरा यह प्रश्न है, उसका जवाब उतना ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से मंत्री जी ने दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार प्रदेश भर में लगे समस्त इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के जल को शुद्ध मानती है ? अगर मानती है तो क्या सरकार की जानकारी में कुछ हैण्डपम्प में दूषित पानी निकलने की जानकारी है और सरकार उन हैण्डपम्पों को तुरन्त बन्द करायेगी ? क्या सरकार को हैण्डपम्प लगाने वाली एजेंसी की हैण्डपम्प लगाते समय करायी गयी जाँच पर पूरा भरोसा है और माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हैण्डपम्पों से निकलने वाले जल की नियमित जाँच की व्यवस्था न कराना, सरकार की जनहित के मुद्दों पर लापरवाही का साक्ष्य नहीं है ? तो क्या सरकार मेरे इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में समस्त हैण्डपम्पों के जल की जाँच कराने का आश्वासन सदन में देगी ?

श्री अध्यक्ष-

इसमें तो सभी तरह के उत्तर आ गए।

श्री मो0 फईम इरफान-

नहीं, मान्यवर। हैण्डपम्प लगने के बाद उसकी जिम्मेदारी जब नगर पालिकाओं पर पहुँचती है तो नगर पालिकाएँ उस जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं करती है। मान्यवर, मेरी बिलारी विधान सभा क्षेत्र में लगभग 25 नए हैण्डपम्प अभी लगे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उनकी अगर आप जाँच करायेंगे तो आपको एहसास हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री मो0 फईम इरफान-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार को कुछ हैण्डपम्पों में दूषित पानी निकलने की जानकारी है तो क्या सरकार उन हैण्डपम्पों को तुरन्त बन्द करायेगी ? मैं इस पर कार्यवाही चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य को मैं बता दूँ जब हैण्डपम्प स्थापित किए जाते हैं तो उस वक्त जल की गुणवत्ता की जाँच की जाती है और जल निगम के पास लगभग हर जनपद में उसकी लैब है और जब जल मानक के अनुरूप सही पाया जाता है, तभी वह हैण्डपम्प स्थानीय निकाय को हैण्डओवर होता है। उसके बाद अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो पुनः उसकी जाँच करायी जाती है और उसका रख-रखाव स्थानीय निकाय करता है। यह कहना उचित नहीं है कि सभी स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे है। इसके अलावा भी समय-समय पर जाँच करायी जाती है। अब इस समय भारत सरकार की एक योजना के तहत् जाँच करायी जा रही है और नगरीय और ग्रामीण मिलाकर 01 लाख से ज्यादा हैण्डपम्पों की जाँच हो चुकी है। अब कहीं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, अगर पाया जाता है, जैसे 2019 में कानपुर में राखी मण्डी क्षेत्र में दूषित पेयजल पाया गया था तो वहाँ के हैण्डपम्प को हटाकर पाइपलाइन के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के आदेश 22 फरवरी, 2019 को जारी किए गए और मैं आपको यह भी बता दूँ कि जो हमारे आगे योजना है, जल जीवन मिशन (शहरी), जो केन्द्र सरकार के सहयोग से लागू हो रही है। हम क्रमशः सब जगह हैण्डपम्प हटाकर पेयजल लाइन डालने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मो0 फईम इरफान-

मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा, बिलारी विधान सभा क्षेत्र को बिलारी नगर पालिका परिषद में लगभग 25 हैण्डपम्प लगे हैं, उनकी मा0 मंत्री जी जाँच करा लें।

श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जो से अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ चुकंदीसरॉय जो ब्लाक सम्भल के अन्तर्गत आता है, वहाँ के लिए कई बार मेरे द्वारा शिकायत दी गयी, जिलाधिकारी द्वारा जाँच करायी गयी।

पर जाँच के बाद भी आज भी वहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है और वहाँ पर इतना दूषित जल पाया जाता है कि वहाँ के काफी लोग, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं तो मेरा कहना है कि कृपया आप इसके साथ-साथ इसकी भी जाँच करा लें।

श्री अध्यक्ष-

यह आपके क्षेत्र का विशेष मामला है, आप मा0 मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए, वह इसकी जाँच करा लेंगे।

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

मान्यवर, हम दिखवा लेंगे, दोनों मैटर दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में विभिन्न वित्तीय वर्षों में प्रदेश के कुल बजट का शिक्षा पर व्यय की गई धनराशि का विवरण

***6-हाजी इरफान सोलंकी (अनुपस्थित)-**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 व 2019-20 में प्रदेश के कुल बजट की कितने प्रतिशत धनराशि शिक्षा के मद में व्यय की गई तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत व्यय करने का प्राविधान किया गया है ? क्या सरकार दिल्ली राज्य की भांति शिक्षा के क्षेत्र में बजट का 24 प्रतिशत भाग व्यय करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 के वास्तविक आँकड़ों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रावधानित धनराशि का विवरण नीचे तालिका में अंकित है:-

(धनराशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	शिक्षा पर वास्तविक व्यय/अनुमान	बजट का कुल वास्तविक व्यय/अनुमान	प्रतिशत
2017-18 (वास्तविक व्यय)	52052.50	321822.80	16.17 %
2018-19 (वास्तविक व्यय)	54291.53	391210.61	13.88 %
2019-20 (वास्तविक व्यय)	62874.69	383351.69	16.40 %
2021-21 (बजट अनुमान)	74811.67	512860.72	14.59 %

राज्य के वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए प्रति वर्ष शिक्षा के बजट हेतु प्रावधान किया जा रहा है।

(मा0 अध्यक्ष द्वारा सदस्य, हाजी इरफान सोलंकी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

प्रदेश में नगर विकास विभाग में अधिशासी अधि0 श्रेणी-1,2,3 व(नगर पंचायत) पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने विषयक

***7-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निकाय निदेशालय उ0प्र0 की विज्ञप्ति सं0-6/1570/अ0आ0न0प0/प्रतिनियुक्ति/18 लखनऊ, दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 द्वारा नगर विकास विभाग में अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1, श्रेणी-2, श्रेणी-3, व अधिशासी

अधि0 (नगर पंचायत) के 150 पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये उक्त पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने हेतु अधियाचन प्रेषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

निदेशालय की विज्ञापन संख्या-6/1570/अ0आ0न0प0/प्रतिनियुक्ति/18, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 द्वारा अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1, श्रेणी-2, श्रेणी-3 व अधिशासी अधि0 (नगर पंचायत) के 158 रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु विज्ञापित कराया गया था, जिसके सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों में से साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनोंपरान्त विभिन्न श्रेणियों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 107 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत किए गये। निदेशालय के पत्र संख्या-6/3190/12/643-अधियाचन/अ0अ0 न0पं0/97 (भाग-2), दिनांक 05-11-2018 द्वारा 107 पदों एवं पत्र संख्या-2/13371/12/643-अधियाचन/अ0अ0 न0पं0/97 (भाग-2), दिनांक 01-07-2020 द्वारा 97 पदों अर्थात अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत के कुल 204 पदों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भेजा गया है। शासन के पत्र संख्या-6478/नौ-4-17-64ई/07, दिनांक 14-12-2017 द्वारा अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1/सहायक नगर आयुक्त के 19 पदों तथा शासन के पत्र संख्या-2656(1) /नौ-4-20-64ई/07, दिनांक 23-10-2020 द्वारा अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1 /सहायक नगर आयुक्त के 10 पदों अर्थात कुल 29 पदों का अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। शासन द्वारा प्रेषित उक्त अधियाचन दिनांक 14-12-2017 के सापेक्ष 19 अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1/सहायक नगर आयुक्त के पद पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयन की संस्तुति प्राप्त हो चुकी है। उक्त चयन संस्तुति के सापेक्ष कुल 18 अभ्यर्थियों के तैनाती आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। 01 अभ्यर्थी का आदेश निर्गत किया जाना प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का केवल ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सरकार दिन प्रति दिन जॉब ओरिएण्टेशन के प्रति वचनबद्ध है। हम पढ़ते रहते हैं और विधान सभा में भी सुनते रहते हैं कि हमने 02 करोड़ नौकरी इसमें दी, 01 करोड़ 12 लाख मनरेगा में दी, 04 लाख नौकरी नई दी। अगर जॉब ओरिएण्टेशन के प्रति सरकार वचनबद्ध है तो ये मात्र लगभग 200 पोस्ट है। मैं जानना चाहूँगा और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह भी करूंगा कि क्या सरकार बताएगी कि प्रतिनियुक्ति पर चयनित श्रेणी-1, 2, 3 या जो भी मा0 मंत्री जी ने बताएँ है तो आज के दिन वे कार्य कर रहे है या नहीं। या फिर

अपने विभाग में लौट गए है ? यह जानने की मेरी जिज्ञासा है। दूसरा है कि क्या प्रतिनियुक्ति समाप्त कर सरकार वापस उनको अपने मूल विभागों में भेजने पर विचार करेगी कि नहीं करेगी ? तीसरा मैं जानना चाहूँगा कि प्रतिनियुक्ति के विज्ञापन की तारीख 20 दिसम्बर, 2018 थी और कुल पद 158 थे। तो प्रतिनियुक्ति पर भरने का कारण क्या रहा, जब मात्र इतनी छोटी संख्या थी तो प्रतिनियुक्ति पर भरने का कारण हम जानना चाहेंगे जवाब में जिन पदों को भरे जाने की व्यवस्था विज्ञापित की गयी है क्या इन्हीं पदों के विरुद्ध है या किन्हीं अन्य पदों के विरुद्ध है यह आपसे जानने की जिज्ञासा है।

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

मा0 सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य है लेकिन आपके प्रश्न में विरोधाभास है एक तरफ आप कह रहे हैं कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे है, दूसरी तरफ कह रहे है कि आप प्रतिनियुक्ति पर क्यों ले रहे है ? यह विभाग तय करता है आवश्यकतानुसार अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को चले गये हैं, लोक सेवा आयोग को चले गये है। आप जानते है कि वहाँ पर एक प्रक्रिया है उसमें समय लग रहा है, तब तक आवश्यकता महसूस की गई तो उनको प्रतिनियुक्ति पर ले लिया गया, बाकी कही कोई कमी नहीं है जो भी अधिशासी अधिकारी है उसमें श्रेणी-एक के जो है वह 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से आते है और 50 प्रतिशत पदोन्नति से होते हैं। श्रेणी-दो और श्रेणी-तीन के शत-प्रतिशत पदोन्नति से होते है वह डी0पी0सी0 के द्वारा वहाँ पर आएंगे, सीधी भर्ती के आयोग द्वारा सेलेक्ट होकर आएंगे तब तक के लिए प्रतिनियुक्ति पर ले लिये गये, उन्ही पदों के सापेक्ष उनको लिया गया है और जब वह चयनित होकर आ जाएंगे तो वह अपने मूल विभाग में वापस हो जाएंगे और जो भी अधिशासी अधिकारी है यदि कहीं पर कमी है तो बगल वाले नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को उसका चार्ज दिया गया है या एस0डी0एम0 के पास चार्ज है, या तो प्रतिनियुक्ति पर है या रेगुलर हैं। यह सूचना आपके लिए है।

***8-श्री विनय शंकर तिवारी-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में खाद, कीटनाशक, डीजल, कृषि यंत्रों, मजदूरी आदि में बढ़ोत्तरी के कारण गन्ना मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में

***9-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री बनने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद, कीटनाशक, डीजल, कृषि यंत्रों, मजदूरी आदि के मूल्यों में बढ़ोत्तरी के कारण गन्ने के उत्पादन की लागत बढ़ गयी है ? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसानों की बढ़ी हुई लागत के दृष्टिगत क्या सरकार गन्ना मूल्य को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश कुमार)-

राज्य सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन में आने वाली लागत, वैकल्पिक फसलों के समर्थन मूल्य, चीनी उत्पादन लागत, चीनी मिलों को सह उत्पादों से प्राप्त होने वाले लाभ, चीनी एवं अन्य सह उत्पादों के बाजार मूल्य तथा हितबद्ध पक्षों को सुनते हुए सुसंगत पहलुओं पर विचार कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण निर्णय लेते हुए पेराई सत्र के लिए गन्ने का "परामर्शित गन्ना मूल्य" घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार समस्त पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त पेराई सत्र 2020-21 के लिए निम्नवत् राज्य परामर्शित मूल्य घोषित कर दिया गया है।

अगेती प्रजाति रु0 325.00 प्रति कुन्तल

सामान्य प्रजाति रु0 315.00 प्रति कुन्तल

अनुपयुक्त प्रजाति रु0 310.00 प्रति कुन्तल

प्रश्न नहीं उठता।

पेराई सत्र 2020-21 के लिए राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य घोषित हो चुका है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं हमारा सवाल था कि क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद, कीटनाशक, डीजल, कृषि यंत्रों, मजदूरी आदि के मूल्यों में बढ़ोत्तरी के कारण गन्ने के उत्पादन की लागत बढ़ गयी है ? मा0 मंत्री जी से मैं तीन सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि विगत कितने पेराई सत्रों से गन्ने का परामर्शी मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। नम्बर दो प्रश्न है जब विगत तीन वर्षों से गन्ने का मूल्य बढ़ाया नहीं गया है तो इस बीच में क्या गन्ने के उत्पादन की लागत बढ़ी है या नहीं बढ़ी है ? नम्बर तीन प्रश्न मेरा है कि बीज, कीटनाशक, खाद, डीजल, कृषि यंत्र और मजदूरी बढ़ने से ही गन्ने के उत्पादन का मूल्य बढ़ता है तो मा0 मंत्री जी यह बता दे कि विगत कितने वर्षों से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है और गन्ने की उत्पादन लागत जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के फार्म हाउस है वहाँ से रिपोर्ट आती होगी कि उत्पादन मूल्य आपका बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ?

श्री सुरेश कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य है और उनकी जो मूल भावना है उस मूल भावना के अनुरूप ही यह पूरा उत्तर दिया गया है ऑलरेडी यह स्पष्ट है कि तमाम पहलुओं पर चर्चा करके और सारे पहलुओं को समझते हुए मूल्य घोषित किया जाता है तो इससे स्पष्ट है कि सभी पहलुओं पर चर्चा भी हुई होगी और इस तथ्य से यह अच्छे से भी वाकिफ है कि जो राज्य परामर्शित गन्ना निर्धारण समिति है वह सभी पक्षों को सुनती है, यह किसानों को भी सुनती है, अन्य पक्षों को भी सुनती है और सारे पक्षों को सुनने के बाद गन्ने के मूल्य का निर्धारण होता है और उसी आधार पर एस0ए0पी0 घोषित हुआ है तो यह इस बात से स्पष्ट है कि सारे पक्षों को सुनने के बाद ही गन्ने का मूल्य घोषित हुआ है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 2 सवाल किये कि विगत तय पेराई सत्रों से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। दूसरा, जब गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया तो इस बीच में गन्ने के उत्पादन की लागत बढ़ी या नहीं बढ़ी ?

श्री सुरेश कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य चूंकि हमारे बहुत वरिष्ठ साथी है और पहले गन्ना मंत्री भी रहे है। इन्होंने कहा कि 3 सत्रों से हम आए थे तो आते ही हमने 10 रुपये कुन्तल गन्ने का भाव बढ़ाया। मूल है कि गन्ना किसान की आमदनी को बढ़ाना। मूल है, किसान की आय को दोगुना करना। यदि उस ओर हम गंभीरता से चिंतन करेंगे तो मैं मा0 सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूँ कि जब हम लोग सरकार में आए थे तो उस समय पर हेक्टेयर जो गन्ने का उत्पादन था, वह 72 टन प्रति हेक्टेयर था। आज गन्ने का जो उत्पादन है, वह 81 टन पर हेक्टेयर है। यह 9 हेक्टेयर पर टन गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की नीतियों से और गन्ना किसान के परिश्रम से बढ़ा। 9 टन पर हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन हमने बढ़ाया। जहां तक मा0 सदस्य ने कहा कि 3 वर्षों से हमने भाव नहीं बढ़ाया, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब आप सरकार में थे तो 2013-14, 2014-15 और 2015-16 इन तीनों वर्षों में आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया था। तीनों वर्षों में लगातार सेम भाव था। इसके बावजूद भी आपने जो भुगतान किया, वह दो किश्तों में किया था। एक बार एक भुगतान करते थे और बचा हुआ आप दोबारा करते थे। यह जो आप लोगों ने हमें 5 वर्षों में दिया है, लगातार उस पर काम करते हुए गन्ना किसान को मजबूत करने का काम उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने किया है और गन्ना किसानों के लिए पूरी तरह से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। जहां तक आपने लागत की बात कही, चूंकि हमारे वरिष्ठ साथी है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि लागत पर जो भारत सरकार द्वारा गठित आयोग है, उसमें लागत पर यदि मैं चर्चा करूँ, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने 231 रुपये कुन्तल लागत बतायी है और हमने 325 S.P.A घोषित किया है अभी मे वह दोनों चेहरे दिखाना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मा0 सदस्य के सहयोगियों ने बयान देना शुरू किया था कि सरकार निश्चित रूप से गन्ने पर भाव घटायेगी इसलिए भाव घोषित नहीं कर रही है कि गन्ने पर भाव घटायेगी। अब भाव घोषित हो गया तो दूसरी बातें शुरू कर दी। लगातार किसान के प्रति गन्ना किसान की आमदनी बढ़े और लगातार किसान सशक्त हो और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना और प्रेरणा कि वर्ष 2022 तक किसान की आय दोगुना करनी है इस पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो मा0 वर्मा जी ने मा0 मंत्री जी से प्रश्न पूछा, तो यह बात सही है कि काबिल है, मित्र भी है और अच्छा बोलते भी है लेकिन प्रश्न का उत्तर इन्होंने नहीं दिया और उल्टे आरोप हम लोगों पर लगा रहे थे। वर्ष 2012 में 40 रुपये प्रति कुन्तल की दर

से गन्ने का दाम हमारी सरकार ने बढ़ाया था। वर्ष 2016 में 25 रुपये प्रति कुन्तल, 5 वर्ष में 65 रुपये प्रति कुन्तल की दर से हमारी सरकार ने बढ़ाया है। मा0 सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, उसका मा0 मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं, यह अपना भाषण दे रहे है। गन्ने का मूल्य और किसानों की दोगुना आय बढ़ा रहे है। एक दाम बढ़ाया नहीं और दूना मूल्य भी हो जायेगा तो क्या कोई मंत्र इनके पास है ? अरे, जब गन्ने का दाम बढ़ेगा, तभी तो किसान की आमदनी बढ़ेगी लागत कितनी बढ़ी, इसका भी गोलमोल जवाब दिया। इसलिए यह सरकार गन्ना किसानों की विरोधी है, किसानों की विरोधी है और किसानों को हर तरफ से ठगने का काम कर रही है। मा0 मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे रहे है, छिपा रहे है इसलिए हम आपके माध्यम से और आपसे निवेदन करके मा0 मंत्री जी के सही उत्तर न देने के कारण गन्ना किसानों का अहित करने वाली सरकार के खिलाफ हम सदन का दो मिनट के लिए बहिष्कार करते है।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया)

श्री सुरेश कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी मुझे मालूम था कि वे लोग आँख में आँख डाल करके सदन में कभी भी गन्ना किसान, धान किसान या गेहूँ किसान के विषय पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें अपने बारे में मालूम है कि इन्होंने क्या किया है और में बताना चाहता हूं कि मैं नेता प्रतिपक्ष का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि आपने वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में एक रुपया गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया। मैं स्पष्ट रूप से जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि आपने 05 वर्षों में 10 शुगर मिलों को बंद करने का काम किया। मैं स्पष्ट रूप से जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर 2 हजार करोड़ रुपये का जो ब्याज था उस ब्याज को माफ करने का काम, पाप करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। मै स्पष्ट जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश देश में नम्बर-1 चीनी पैदा करने वाला राज्य है। मैं कह रहा हूँ कि आज देश में गन्ने का उत्तर प्रदेश के अन्दर सर्वाधिक क्षेत्रफल है और सर्वाधिक भुगतान देश में यदि किसी राज्य में होता है तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार किसानों की समृद्धि की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है लेकिन इनके पास सुनने की हिम्मत नहीं है, चूंकि काम किया नहीं है। मैं बोलता तो इनकी सारी बातें सामने आनी थी इसलिए कहा कि हम दो मिनट के लिए जा रहे है, हमारे बड़े भाई हैं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। पर हां, मैं विश्वास से कहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की सरकार में हर सूरत में वर्ष 2022 तक किसान की आमदनी दो गुना करने का जो टारगेट है उस पर काम कर रही है एक छोटी-सी बात कहकर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। वर्ष 2015-16 में समाजवादी पार्टी सरकार के शासन में 18,003 करोड़ रुपये पूरे उत्तर प्रदेश को गन्ना किसानों के खाते में जाते हैं और हमारी सरकार में पिछले वर्ष में 35,800 करोड़ रुपये गन्ना किसानों के खाते में जाते हैं। 18,003 करोड़ और 35,800 करोड़ स्पष्ट हो जायेगा कि आमदनी किस और बढ़ रही है। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

प्रदेश के नगर पंचायतों में बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को रोकने के लिए महानगरों और शहरों जैसी मूलभूत सुविधाये बढ़ाये जाने के सम्बंध में

***10-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर पंचायतों में भी महानगरों और शहरों जैसी मूलभूत सुविधायें बढ़ाये जाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रदेश की छोटी नगर पंचायती/निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से प्रतिवर्ष 01 निकाय का चयन किया जाता है। इस प्रकार 05 वित्तीय वर्षों में कुल 375 निकायों का चयन किया जाना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर अब कुल 261 निकायों का चयन किया जा चुका है। चयनित निकाय से प्राप्त कार्य योजना के अनुसार निकाय की जनसंख्या के आधार पर धनराशि आवंटित की जाती है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सौर पुंज योजना, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (नया सवेरा), नगरीय/झील /तालाब /पोखर संरक्षण योजना, नगरीय पेयजल योजना, पार्कों का निर्माण एवं विकास, शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल का विकास इत्यादि योजनायें भी संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी", मंत्री नगर विकास द्वारा उत्तर पढ़ा गया।)

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत छोटा-सा और बहुत साधारण-सा एक प्रश्न हमारे माध्यम से पूछा गया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महानगरों में शहरों में मूलभूत सुविधायें बढ़ाये जाने के संबंध में माननीय मंत्री जी से जवाब चाहा था, इन्होंने बड़ा लम्बा-चौड़ा जवाब दिया लेकिन हमारी मूलभूत सुविधायें क्या है ? मूलभूत सुविधायें स्वास्थ्य से संबंधित, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़के अच्छी हों, आवारा पशु का भ्रमण न हो, पार्को का निर्माण हो, सीवर लाईन हो। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से छोटे-छोटे 3-4 प्रश्न पूछना चाहता हूं, इन्होंने बजट भी दिखाया है कि इतना बजट हमने दिया है। हर साल एक-एक निकाय का चयन उसके लिए करते है लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इससे परे है।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल क्या है ?

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, सवाल पर ही आ रहा हूं कि क्या माननीय मंत्री जी आपकी जितनी छोटी नगर पंचायतें हैं उनमें जो स्वास्थ्य केन्द्र है, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 हैं, उनमें डॉक्टर्स नहीं हैं तो क्या वहाँ डॉक्टर्स और स्टॉफ की व्यवस्था करायेंगे ? दूसरा, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हैं, नल खराब पड़े हैं, दूषित पानी नलों से निकल रहा है, कई जगह वाटर के कनेक्शन नहीं है क्या उसको करायेंगे ? सड़कों की हालत ठीक नहीं है, क्या उनको ठीक करायेंगे ? आवारा पशुओं की योजना तो इन्होंने बता दी लेकिन जब आप हकीकत में देखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपने योजना ही तो पूछा था। आपका प्रश्न योजनाओं के सम्बन्ध में ही है।

श्री मनोज कुमार पारस-

हमारे जनपद बिजनौर में शेरकोट, मंडावर, सेसपुर, हल्दौर, सहारनपुर, जलालाबाद, झालू ये नगर पंचायते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ये क्षेत्र आपके प्रश्न में नहीं है।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, इन सारी नगर पंचायतों में कोई सुविधा नहीं है और जब इनमें नहीं है तो पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बजट आपने दिया है उससे इन सारी परेशानियों से मुक्ति दिलायेंगे।

श्रीमती आराधना मिश्रा "मोना"-

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुमति हो तो इससे सम्बन्धित एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं। मान्यवर, मूलभूत सुविधाओं से सम्बन्धित यह प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो नई नगर पंचायतें बनी है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि विकास तो बाद में होगा पहले उनके कार्यालय भवन का निर्माण हो जाय। ऐसी बहुत सी नगर पंचायतें है जहाँ उनका कार्यालय या तो सरकारी बंगले में चल रहा है या बना नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहती हूं कि ऐसी नगर पंचायतों में क्या कोई समय सीमा तय करेंगे जिसमें उन नगर पंचायतों के कार्यालय भवन का निर्माण हो।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई।

श्रीमती आराधना मिश्रा "मोना"-

मान्यवर, दूसरा अनुपूरक भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

जो पहला अनुपूरक आपने पूछा यह भी असंगत है।

श्रीमती आराधना मिश्रा "मोना"-

मान्यवर, जहाँ नगर पंचायत होती है वहां पानी की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि घनी आबादी होती है और हैण्डपम्प से पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता है। जहाँ पर नई सड़कों का निर्माण होता है, जो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है चाहे स्टेट हाई-वे के बनने से या एन0एच0 के बनने से हो उनकी जिम्मेदारी न नगर पंचायत लेता है और न ही वह एजेंसी लेती है जो सड़क का निर्माण करती है।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है ? आपकी बहुत लम्बी-चौड़ी बात में प्रश्न नहीं आया।

श्रीमती आराधना मिश्रा "मोना"-

मान्यवर, जैसे मेरे यहाँ लालगंज टाउन एरिया है, ऐसी जगह जहाँ पर पानी की टंकी से पाइपलाइन के द्वारा पानी दिया जा रहा हो और सड़क बनने से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही हो तो क्या उन्हें ठीक कराने की जिम्मेदारी नगर पंचायत लेगा ताकि लोगों तक बिना असुविधा के शुद्ध पानी लोगों तक पहुंच सके। यह मेरे दो छोटे-छोटे प्रश्न है।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इसी से सम्बन्धित मैं भी पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने शहर में या महानगरों में मूलभूत सुविधाओं के साथ श्मशान इत्यादि का भी जिक किया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या जो श्मशान पूर्व से पूरे प्रदेश के जनपदों में बने हुए है और क्षतिग्रस्त हो गये है, हम तमाम सदस्य जिनके पास निधि तक नहीं बची है क्या उनकी मरम्मत कराने के लिए कोई योजना बनाकर अधिकारियों को निर्देश देंगे या योजना बनाने पर विचार करेंगे।

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

माननीय अध्यक्ष जी, नगर पंचायतों के लिए ये जितनी भी योजनाएं है वो व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए ही सारी योजनाएं है। आदर्श नगर पंचायत हमारी सरकार ने शुरू किया, प्रतिवर्ष 75 नगर पंचायतों को आदर्श नगर पंचायत घोषित किया गया। पाँच वर्षों में 375 नगर पंचायतें आदर्श नगर पंचायत हो जाएंगी और 261 अभी तक हो चुकी है, बाकी इस साल में हो जायेंगी। कुल 490 नगर पंचायतें है जो 215 रह जायेगी तो हमारी सरकार फिर आ रही है हम सब करा देंगे। जो 10 हजार तक आबादी की नगर पंचायत है उसको 2 करोड़ रुपया, जो 20 हजार तक की आबादी की है उसको 3 करोड़ रुपया और जो 20 हजार से ज्यादा आबादी की नगर पंचायत है उसको 4 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, इतने में नगर पंचायत की सड़कें-वड़कें दुरुस्त हो जायेंगी। अभी आपने पेयजल के लिए कहा तो शहरी जल जीवन मिशन महत्वाकांक्षी योजना इस साल आ रही है और शहरी क्षेत्रों में आने वाले तीन वर्षों में हम सब

जगह पाइपलाइन से पेयजल पहुंचा देंगे। आपने कहा कि जो निर्माणाधीन है, उसमें यह प्रक्रिया है ही कि जो एजेंसी बना रही है, वह पूरी टेस्टिंग कराकर अगर मानक के अनुसार सारी पाइप लाइनें पड़ गई है, तभी स्थानीय निकाय को हैण्डओवर करेगी। उसमें कहाँ से क्षतिग्रस्तता आती है। उसके बाद अगर किसी कारण से क्षतिग्रस्त होती है तो वह स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है। अब आपने कौन-कौन नगर पंचायते अपने क्षेत्र की बताई है, जरा एक बार फिर से बता दीजिए।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे जनपद बिजनौर की शेरकोट, मंडावर, सेसपुर, हल्दौर, सहारनपुर, जलालाबाद और झालू, ये नगर पंचायते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हर साल एक जिले में एक चयन करते है, इनमें से कौन सी पंचायत का चयन हो गया है ? अगर चयन हो गया है तो क्या उनमें सारी मूलभूत सुविधायें जो इन्होंने बताई है, वह पूर्ण रूप से हो गई है ?

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आने दीजिए।

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

अध्यक्ष जी, एक सज्जन, एक हलवाई की दुकान पर गये और बोले कि दो किलो लड्डू देना, फिर बोले कि बड़ी वाली कड़ाही है, इसमें डाल दो। फिर कहा, दो किलो पेड़ा देना, वह भी इसमें डाल दो, फिर बोले, दो किलो बर्फी देना, वह भी इसमें डाल दो और उन्होंने उसमें खूब सामान डाल दिया और बोले कि अब इसको घोट के भून दो। उसके बाद बोले कि 100 ग्राम हमें दे दो और इसके पैसे ले लो। अरे, इतना लम्बा-चौड़ा सवाल और ले आये अपनी नगर पंचायत में। अरे, उसी में सवाल लगाते। यह सारी योजनायें आपकी नगर पंचायतों में भी लागू होगी। कही कठिनाई हो तो हमें अलग से लिख कर दे दीजिएगा।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

अध्यक्ष जी, श्मशान वाला महत्वपूर्ण प्रश्न था।

(सदस्य श्री मनोज कुमार पारस, श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव और श्रीमती आराधना मिश्रा "मोना" के द्वारा अनुपूरक पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न लेते है। पारस जी, उत्तर आ गया है।

प्रदेश में कैंसर, हार्ट, किडनी आदि की गंभीर बीमारियों के मुफ्त इलाज हेतु योजना विषयक

***11-श्री नफीस अहमद-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कैंसर, हार्ट, किडनी आदि की गम्भीर बिमारियों के मुफ्त इलाज हेतु किसी कार्य योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली 2013 के अन्तर्गत कैंसर, हृदय रोग, किडनी एवं लीवर से संबंधित गंभीर रोगों के निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों, चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा के द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल गम्भीर रोगों से सम्बन्धित है। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर गम्भीर रोगी बढ़ते जा रहे हैं, किडनी के, हार्ट के और खासतौर से लीवर कैंसर के और माननीय मंत्री जी ने जो पिछली सरकार थी, 2013 का जिक्र किया, यह सही बात है और मैं इस सदन में पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन गम्भीर रोगों को समझते हुए और जो गरीब लोग हैं, जो इनका इलाज नहीं करा सकते थे, उन्होंने 2013 में एक नियमावली बनाई थी, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि 2013 की नियमावली में क्या है, जिससे सदन के पूरे सदस्य अवगत हो सकें कि इस नियमावली में क्या काम हुए थे और दूसरा मेरा सवाल यह है कि प्रदेश के कितने ऐसे स्टेट मेडिकल कॉलेज हैं, इंस्टिट्यूशन्स हैं, जिनके अंदर कैंसर का इलाज हो रहा है और किडनी के ट्रान्सप्लांट हुए है, चाहे किडनी के इलाज के लिए नेफ्रोलोजी डिपार्टमेण्ट शुरू हो गया है, उसको बताने की कृपा करें। साथ ही 2020-21 में इस नियम के अन्तर्गत कितना बजट आवंटन किया गया और कितना बजट उसमें खर्च किया गया, यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें।

[सदस्य मा0 असलम "राइनी" (एडवोकेट) के अनुपूरक पूछने का प्रयास करने पर]

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि इसमें पात्रता के लिए लाभार्थियों की श्रेणी, बीपीएल कार्डधारकों एवं बीपीएल सूची के सदस्यों के साथ-साथ सवा तीन एकड़ तक की जोत के कृषक अथवा जिनको आय 35 हजार रुपये वार्षिक से कम हो, सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ दूसरी बात आपने यह पूछी कि इस वर्ष कितना पैसा इसमें क्वान्टीफाई हुआ और कितना पैसा इसमें खर्च हुआ। मान्यवर, वर्ष 2020-21 में इसमें 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी और इस 40 करोड़ में से इस वर्ष 21.9645 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हुआ है। मान्यवर, जब से यह सरकार आई है तो 2018-19 में भी 40 करोड़ रुपया क्वान्टीफाई हुआ था उस समय 53 करोड़ 73 लाख रुपया व्यय हुआ था। वर्ष

2019-20 में भी 40 करोड़ रुपया क्वान्टीफाई किया गया था, उस वक्त भी 56 करोड़ 53 लाख 57 हजार रुपया खर्च हुआ तो मान्यवर, जितना रुपया इसमें क्वान्टीफाई होता है हमने पिछली बार 17 करोड़ रुपया और उसके पिछली बार 13 करोड़ 73 लाख रुपया इसमें रिएप्रोप्रिएशन के माध्यम से बढ़ाया। यानि कहने का ताल्लुक यह है कि यह सरकार पूरी तरह से असाध्य रोगों के प्रति गंभीर है और जहाँ जैसी आवश्यकता अगर होती है, उस पात्रता का व्यक्ति अगर आता है तो उसको पूरी तरह से निःशुल्क इलाज दिया जाता है, यह व्यवस्था है। दो सालों में रिएप्रोप्रिएशन के माध्यम से पैसा दिया गया। इस साल चूंकि महामारी की वजह से काफी समय बंद रहा, इसलिये अभी तक पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाया है।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे तीसरे सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। तीसरा सवाल मेरा यह था कि स्टेट के कितने मेडिकल कालेज इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर लीवर कैंसर खासतौर से चूँकि यह सरकार शराब को बहुत बढ़ावा दे रही है तो लीवर कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे है इसमें लीवर कैसर और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट वर्क कर रहे है और जहाँ मेडिकल कालेज में यह नहीं कर रहे हैं तो सरकार कितनी जल्दी उस डिपार्टमेंट को चालू कराकर उन गरीब बेसहारा लोगों का मुफ्त इलाज कराने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आपने अस्पतालों की संख्या पूछी है कि कहाँ-कहाँ लीवर कैंसर का इलाज हो रहा है?

श्री नफीस अहमद-

मान्यवर, लीवर कैंसर, नेफ्रोलॉजी, किडनी का इलाज कहाँ-कहाँ मेडिकल कालेजों में नहीं चल रहे है और अगर नहीं चल रहे है तो कब तक वह चालू कर देंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर कैंसर का इलाज अभी लखनऊ में जो आप ही के जमाने में प्रारम्भ किया गया था कैंसर इंस्टीट्यूट, उसमें कैंसर का इलाज चल रहा है और किडनी का इलाज पी0जी0आई में भी, लोहिया में भी और के0जी0एम0यू0 में भी बराबर चल रहा है इसके अलावा मान्यवर, आगरा में, मेरठ में, झाँसी में तथा प्रयागराज में कैंसर का इलाज चल रहा है जहाँ तक लीवर और किडनी का सवाल है आगरा में भी इलाज उपलब्ध है, मेरठ में भी उपलब्ध है, झाँसी में भी उपलब्ध है, गोरखपुर में भी उपलब्ध है, प्रयागराज में भी उपलब्ध है। किडनी का इलाज आगरा में भी है, मेरठ में भी है, झाँसी में भी है, गोरखपुर में भी है, प्रयागराज में भी है। मान्यवर, हृदय रोगों का इलाज तो लगभग सभी जगह है। तो विशेष रूप से माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है कि जहाँ कहीं नहीं चल रहे है वहाँ पर इसको प्रारम्भ करेंगे और इसीलिये इस वर्ष 2021-22 में इस 40 करोड़ को बढ़ाकर हमने 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की है, आपने शायद बजट भाषण में इस बात को सुना होगा उसमें 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया गया है, यह सरकार की मंशा को दर्शाता है कि हम असाध्य रोगों के प्रति कितना गंभीर है।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, आजमगढ़ मेडिकल कालेज में यह दोनों डिपार्टमेंट कब तक शुरू हो जायेगा ? यह माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इन्होंने जो अभी पात्रता की श्रेणी बताई है उसमें सवा 3 एकड़ तक के किसान भी शामिल किये गये है।

मान्यवर, अगर किसी के पास रु0 35 हजार की आमदनी का सर्टीफिकेट है, तो उन्हें यह निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। जिनके पास सवा तीन एकड़ भूमि है, उनकी तहसील से रु0 35 हजार प्रतिवर्ष से कम की आय का सर्टीफिकेट नहीं बनता है। तो क्या मा0 मंत्री जी इस बात को दृष्टिगत रखते हुए नियमावली में यह व्यवस्था करेंगे कि जिनके पास सवा तीन एकड़ भूमि है, उन लोगों का भी गम्भीर बीमारियों में निःशुल्क इलाज हो सके।

[इस समय 11 बजकर 16 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए]

श्री मोहम्मद असलम "राइनी "(एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उसको भी ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, बी0पी0एल0 श्रेणी की जो पात्रता थी, वह रिन्यू हो गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः रु0 46,080/-और शहरी क्षेत्रों में रु0 54,460 /प्रति वर्ष आमदनी निर्धारित हो गयी है। जो बी0पी0एल0 श्रेणी की पात्रता रखता है, वह उसमें कवर हो जायेंगे। अगर इसमें कोई विसंगति मानते है, तो 35000 वाली बात डिलीट हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें रु0 35000 व बी0पी0एल0 श्रेणी भी है। जो बी0पी0एल0 श्रेणी का कार्ड धारक है, यह उसकी पात्रता रखता है और वह उसमें निःशुल्क इलाज करा सकता है।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सुनिश्चित कर दे कि उसको रु0 46000/-कर दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वह कर देंगे। जहाँ तक श्री नफीस साहब की बात है, तो हम बहुत जल्दी इसको जनपद आजमगढ़ वगैरा में चालू करेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 मंत्री जी, चूंकि एक जिज्ञासा रह गयी थी। आपने जो बताया कि बी0पी0एल0 कार्ड धारक की रु0 46000 की सीमा निर्धारित कर दी गयी है। मा0 मंत्री जी, जिनके पास

बी0पी0एल0 कार्ड नहीं है और उनकी आय प्रति वर्ष रु0 46000/-से कम है, तो क्या उनको भी यह सुविधा मिलेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह पात्रता बाकायदा निर्धारित की गयी है कि जिसकी बी0पी0एल0 श्रेणी है, उनको मिलेगी। मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको रि-डिफाईन कर दे। मान्यवर, हम इसको देख लेंगे।

(इस समय अपराहन 12 बजकर 19 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

प्रदेश में किसानों को उपज का समुचित मूल्य दिलाने हेतु उत्पादों को प्रसंस्कृत कराने की योजना विषयक

***12-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों द्वारा मटर, अदरक, अरवी, टमाटर व अन्य सब्जियों का भरपूर उत्पादन किया जाता है किन्तु बाजार में उन्हें उचित कीमत नहीं मिल पाती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों को समुचित मूल्य दिलाने हेतु स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे लघु उद्योग लगवाकर किसनों के उत्पादों को प्रसंस्कृत कराये जाने की कोई योजना बनायेंगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

जी हाँ।

प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाईया स्थापित किये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में कृषि एवं खाद्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 बनाई गई है, जो अधिसूचना दिनांक 27-10-2017 से आगामी 05 वर्षों तक लागू है। उक्त नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को निम्नवत वित्तीय सहायता अनुमन्य किये जाने का प्राविधान है खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन पर प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 50.00 लाख तक अनुदान। भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत मेगा फूड पार्क/एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूँजीगत निवेश अनुदान। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि का 10 प्रतिशत अधिकतम रु0 50. 00 लाख की सीमा तक अतिरिक्त पूँजीगत निवेश अनुदान सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर्स पार्टस हेतु बैंक से लिये गये ऋण के ब्याज दर की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम 05 वर्षों तक। अन्य मध्यम एवं वृहद इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर्स पार्टस हेतु लिए गये ऋण के

ब्याज की दर का 07 प्रतिशत अधिकतम रु0 50.00 लाख प्रतिवर्ष 05 वर्षों के लिए प्रतिपूर्ति। उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत नव युवकों को न्याय पंचायत स्तर पर 03 दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान कर इच्छुक अभ्यर्थियों को 01 मासीय प्रशिक्षण देकर उनकों कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु धनराशि रु0 01.00 लाख का अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग (केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 60:40) से असंगठित एवं अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण की सूक्ष्म इकाइयों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से "पी0एम0 एफ0एम0ई0-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" (PMFME) संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत क्लस्टर एप्रोच एवं शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/तकनीकी उन्नयन हेतु परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रु0 10.00 लाख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दिये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय उप मुख्य मंत्री जी द्वारा लिखित उत्तर पढ़ा गया।)

†श्री अध्यक्ष-

माननीय जवाहर लाल जी अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्य मंत्री जी की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है, वह किसानों के हित में लगातार कार्य कर रहे है। परन्तु इसमें हम यह चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड में कोई औद्योगिक इकाई भारत सरकार के सहयोग से लगाने की अनुमति मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जायेगा। बुन्देलखंड में जिस तरह से चमचमाती सड़कों का जाल बिछा है अगर कोई उद्योग वहाँ पर लग जाए तो किसानों के हित में एक बहुत बड़ा काम होगा।

प्रदेश में मेडिकल कालेजों में छात्रों के रहने/खाने/लांड्री की फीस निर्धारित करने के सम्बन्ध में

***13-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की हॉस्टल फीस निर्धारित की गई है? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक सत्र 2020-21 के

† नोट- नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न सं0- 12 के उपरान्त प्रश्नों का समय सामप्त हुआ।

लिए शासनादेश संख्या-342/71-4-2020-37/2015 टी0सी0, दिनांक 17-03-2020 द्वारा छात्रावास शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया गया हैं।

स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस0)

(ए) नॉन ए0सी0 सिंगल आकूपेन्शी-रु0 2.50 लाख प्रतिवर्ष।

(बी) ए0सी0 सिंगल आकूपेन्शी रु0 3.00 लाख प्रतिवर्ष।

(सी) नॉन ए0सी0 डबल आकूपेन्शी रु0 1.75 लाख प्रतिवर्ष।

(डी) ए0सी0 डबल आकूपेन्शी रु0 2.10 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है।

स्नातकोत्तर (एम0डी0एस0)

(ए) नॉन ए0सी0 सिंगल आकूपेन्शी-रु0 1.25 लाख प्रतिवर्ष।

(बी) ए0सी0 सिंगल आकूपेन्शी रु0 1.50 लाख प्रतिवर्ष।

(सी) नॉन ए0सी0 डबल आकूपेन्शी रु0 87500/-प्रतिवर्ष।

(डी) ए0सी0 डबल आकूपेन्शी रु0 1.05 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है।

स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0)

शासनादेश संख्या-1791/71-4-2020-37/2015 टी0सी0, दिनांक 06-11-2020 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल मेडिकल कालेजों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों के छात्रों का हॉस्टल शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया गया है-

मेडिकल (एम0बी0बी0एस0)

(ए) नॉन ए0सी0 रु0-1.50 लाख प्रतिवर्ष।

(बी) ए0सी0 रु0-1.75 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेकफास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

डेण्टल (बी0डी0एस0)

(ए) नॉन ए0सी0 रु0-0.85 लाख प्रतिवर्ष।

(बी) ए0सी0-रु0-1.05 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेकफास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों की सड़कों को गड्ढामुक्त करने अथवा लेपन कार्य में भ्रष्टाचार की जांच कराने विषयक

***14-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में गड्ढा मुक्त अथवा लेपन का कार्य में विशेषकर पूर्वांचल के जनपद श्रावस्ती, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बलिया आदि जनपद में ठेकेदार तथा अधिशासी अभियंताओं ने मिलीभगत से वर्ष 2017 से 2020 के बीच में अकूत संपत्ति अर्जित की है ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों की जांच एसटीएफ, एसआईटी अथवा सीबीआई से कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जी नहीं।

समय-समय पर विभागीय उच्चाधिकारियों, प्रमुख अभियन्ता/शासन द्वारा गठित जांच समितियों तथा टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराई जाती है तथा अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

***15-श्री देवमणि द्विवेदी-**

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

***16-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

प्रदेश में राजकीय निर्माण निगम लि0 में पूर्व से कार्यरत दैनिक भोगी तथा मस्टर रोल के कर्मियों का विनियमितीकरण विषयक

***17-श्री विरेन्द्र कुमार यादव-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में पूर्व से कार्यरत दैनिक भोगी तथा मस्टर रोल के कर्मियों का विनियमितीकरण मूल वेतन संरक्षित करते हुए वर्ष 2003 एवं 2010 में किन नियमों एवं शासनादेश के अनुपालन में निर्गत किये गये है ? क्या सरकार बतायेगी कि विनियमितीकरण हेतु गठित चयन समिति द्वारा वेतन संरक्षित किये जाने की संस्तुति की गई थी ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त वित्तीय अनियमितता की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में पूर्व में मस्टर रोल पर कार्यरत कार्मिकों को उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों के समादर में

समान कार्य समान वेतन स्वीकृत किया गया था। विनियमितीकरण से पूर्व प्राप्त परिलब्धिया के आधार पर मूल वेतन को संरक्षित करते हुए निगम में विनियमितीकरण की कार्यवाही की गयी।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सूडा द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में नियुक्त कर्मचारियों के शैक्षिक योग्यता के संबंध में

***18-पं0 राधाकृष्ण शर्मा-**

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूडा द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में राज्य मिशन प्रबन्धक एस0एम0एम0 शहरी मिशन प्रबन्धक एवं सामुदायिक आयोजक को नियुक्त किये जाने हेतु कोई योग्यता एवं अनुभव निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है और दिनांक 09-12-20 तक उक्त पदों पर आउट सोर्सिग से कितने लोगों को नियुक्त किया गया है तथा नियुक्त किये गये सभी अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि नियुक्त किये गये कतिपय कर्मियों ने फर्जी योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र लगाकर नियुक्ति पा ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां, राज्य मिशन प्रबन्धक, शहर मिशन प्रबन्धक एवं सामुदायिक आयोजकों को नियुक्त किये जाने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत कुल 04 राज्य मिशन प्रबन्धक, 115 शहर मिशन प्रबन्धक एवं 198 सामुदायिक आयोजक नियुक्त किये गये है। नियुक्त किये गये सभी अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुरूप है, जिसका विवरण संलग्न[‡] है।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[‡] देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ संख्या 341-350 पर।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत सड़क के डामरीकरण सम्बन्धी

1-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा चौधरीगांव में पंचराम के घर से अग्निगांव तक दूरी लगभग 2 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा चौधरीगांव पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा पंचराम का घर चौधरीगांव में स्थित है तथा ग्राम अग्निगांव ग्राम सभा परसोहना की बसावट है जो परसोहना सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। दो जुड़े हुये गाँवों को आपस में जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी नीति से आच्छादित नहीं होता है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा करमोहना में सड़क के डामरीकरण सम्बन्धी

श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा करमोहना में मुसाफिर के घर से करमोहना घाट तक लम्बाई लगभग 2 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा करमोहना पूर्व से लेपित मार्ग से संतृप्त है। श्री मुसाफिर का घर करमोहना गाँव में स्थित है। मुसाफिर के घर से करमोहना घाट तक लगभग 1.50 कि0मी0 लम्बाई में खड़ण्जा/कच्चा मार्ग है, जहाँ कोई आबादी नहीं है। इस प्रकार किसी के घर से घाट तक मार्ग बनाने की कोई योजना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से वंचित रह गये स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटकर उनको कारोबार शुरू करने में सहायता किये जाने विषयक

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स जो कि पी0एम0 सम्मान निधि योजना से आच्छादित होने से वंचित रह गये हैं, का प्रत्येक जनपद की तहसील/ब्लॉक वार सर्वे कराकर उक्त योजना से आच्छादित सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2022 तक नगर निकाय के इच्छुक समस्त स्ट्रीट वेण्डर्स को ब्याज अनुदान आधारित ऋण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में नगरीय निकायों में निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जा रहे विकास कार्यों की गुणवक्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु कैमरे से वीडियो रिकार्डिंग कराने पर विचार विषयक

4-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में नगरीय निकायों में निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने वाले विकास कार्यों (नाली/नाला/सड़क/इण्टरलॉकिंग सड़क/सी0सी0 सड़क/पुलिया आदि) की गुणवत्ता शत प्रतिशत सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्माण कार्य क्षेत्र में मानक बोर्ड के प्रदर्शन के साथ-साथ उस स्थान के 25% क्षेत्रीय नागरिकों (जिनके आवास/प्रतिष्ठान के सामने निर्माण कार्य चल रहा हो) से उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता की संतुष्टि मोबाइल कैमरे से वीडियों रिकार्डिंग अथवा लिखित रूप में कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जनपद-मथुरा के नगरीय निकाय में सड़क/नाली/नाला/पुलिया में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच लोक निर्माण विभाग से कराने एवं वहां के संबंधित मा0 पार्षद से उक्त कार्य की गुणवत्ता के संबंध में लिखित पत्र लेने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0जी0आर0एस0 संख्या 18000190112919 दि0 01-10-2019 एवं सदस्य विधान सभा का पत्र सं0-483587 विषयक

श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री योगेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या-क-5 नं0, 483587, दिनांक 03-10-2019 एवं मुख्य मंत्री पोर्टल आई0जी0

आर0एस0 नं0-18000190112919, दिनांक 01-10-2019, जो राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग एवं वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस, डालीबाग, लखनऊ में लोक निर्माण विभाग (विद्युत) अनुरक्षण खण्ड-2 में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के विगत कई माह के वेतन भुगतान न किये जाने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग एवं वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस, डालीबाग लखनऊ में विगत माहों में खण्डीय स्तर पर किसी भी कर्मी की तैनाती/नियुक्ति आउटसोर्सिग के माध्यम से नहीं की गयी है, अपितु कार्यों को ही नियमानुसार कोटेशन/निविदा/ई-निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिस्पर्धी दरों के आधार पर ही आउटसोर्स से कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग, विद्युत अनुरक्षण खण्ड-1 के सहायक अभियन्ता द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता की जांच एवं सरकारी आवासों में सप्लाई हो रहे गन्दे पानी की रोकथाम विषयक

6-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या-क-6 नं0-443284, दिनांक 28-02-2020 जो लोक निर्माण विभाग, विद्युत अनुरक्षण खण्ड-1 ट्रांजिट हास्टल डालीबाग लखनऊ के सहायक अभियन्ता द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता की जांच एवं सरकारी आवासों में सप्लाई हो रहे गन्दे पानी की रोकथाम विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ। राज्य सम्पति विभाग के माध्यम से दिनांक 15-06-2020 को प्राप्त हुआ है। प्रकरण की जाँच हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 22-06-2020 द्वारा जाँच कमेटी गठित की गयी थी। जाँच कमेटी द्वारा पत्र दिनांक 08-07-2020 को जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें सहायक अभियन्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में शहरी आजीविका केन्द्र बैंक खातों एवं वित्तीय आय व्यय का संचालन डूडा के अधिकृत सक्षम अधिकारी (प्रबंधक/परियोजना अधिकारी) के हस्ताक्षरों की जगह शासनादेशों के विरुद्ध राष्ट्रीय मूक बधिर विद्यालय समिति, फिरोजाबाद के डायरेक्टर एवं उनके निकट के रिश्तेदार के संयुक्त बैंक खाते के द्वारा किये जाने जैसी अनियमितता की जांच कराने विषयक

7-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) फिरोजाबाद के द्वारा संचालित शहरी आजीविका केन्द्र का संचालन राष्ट्रीय मूकबधिर विद्यालय समिति, फिरोजाबाद के द्वारा कराया जा रहा है ? क्या सरकार अवगत है, कि वर्ष 2015 में हुये उक्त अनुबंध में लगभग 5 वर्षों (फरवरी, 2020) तक शहरी आजीविका केन्द्र बैंक खातों एवं वित्तीय आय व्यय का संचालन डूडा के अधिकृत सक्षम अधिकारी (प्रबंधक/परियोजना अधिकारी) के हस्ताक्षरों की जगह शासनादेशों के विरुद्ध राष्ट्रीय मूक बधिर विद्यालय समिति, फिरोजाबाद के डायरेक्टर एवं उनके निकट के रिश्तेदार के संयुक्त बैंक खाते के द्वारा किया जाता रहा है किन्तु शिकायतें मिलने पर मार्च, 2020 से उक्त खाते का संचालन शहरी मिशन प्रबंधक डूडा के द्वारा कराया जाने लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच कराते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

नगर निगम, फिरोजाबाद में दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र वाटर वर्क्स, फिरोजाबाद के संचालन हेतु राष्ट्रीय मूक बधिर विद्यालय समिति, सुहाग नगर, फिरोजाबाद को नामित किया गया था, जिसमें सूडा मुख्यालय से प्राप्त धनराशि, मिशन को तत्काल प्रारम्भ किये जाने के उद्देश्य से सीधे नामित संचालक संस्था को प्रेषित कर दी गयी थी क्योंकि उसके लिए कोई पृथक खाता संचालित (खुला) नहीं था। उक्त धनराशि का उपयोग संचालक संस्था द्वारा नियमानुसार अपने खाते से ही किया गया, जिसमे संस्था के ही पदाधिकारी हस्ताक्षर हेतु अधिकृत रहे हैं। और दिनांक 12-08-2015 से जिला गरीबी उन्मूलन निधि के खाते में सी0एल0सी0 की आय की धनराशि जमा करते रहे है। उक्त खाते से किसी भी प्रकार की धनराशि की निकासी अभी तक नहीं की गयी है। संचालन संस्था द्वारा उक्त मिशन को गति प्रदान करने एवं सी0एल0सी0 को आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु शासन से प्राप्त धनराशि सी0एल0सी0 के प्रचार-प्रसार कार्यालय में आवश्यक सामग्री व स्टाफ आदि के मानदेय पर व्यय करते हुए नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये गये हैं, जिन्हें तत्कालीन परियोजना अधिकारी, डूडा एवं सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक डूडा के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रमाणित करते हुये सूडा मुख्यालय को प्रेषित किया गया है। सक्षम स्तर से परीक्षण कराने के उपरान्त किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं पायी गयी। शहरी आजीविका केन्द्र, वाटर वर्क्स की विस्तृत समीक्षा भी जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक

13-12-2020 को की गयी है। जुलाई, 2020 से सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक, डूडा की अनुमति से नियमानुसार उक्त शहरी आजीविका केन्द्र की संचालक संस्था के सचिव एवं शहरी मिशन प्रबंधक, सी0एम0एम0यू0, फिरोजाबाद के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुख्य मंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद की 26 परियोजनाओं की द्वितीय/अंतिम किस्त जारी किये जाने विषयक

8-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद की 26 परियोजनाओं की द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में परियोजना अधिकारी, डूडा फिरोजाबाद के द्वारा कार्यक्रम अधिकारी, सूडा लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 533/डूडा-फिरोजाबाद/2020-21 दिनांक 28/7/2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार अवगत है, कि द्वितीय किश्त प्राप्त न हो पाने के कारण उक्त परियोजनायें अधूरी पड़ी है, एवं क्षेत्रीय नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परियोजनाओं की द्वितीय/अंतिम किश्त जारी कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जनपद फिरोजाबाद में मुख्य मंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनांतर्गत मलिन बस्तियों में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की द्वितीय/अंतिम किश्त अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ के पत्र दिनांक 19-10-2020 एवं 21-01-2021 द्वारा प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्डियो वैस्कुलर थोरौसिक सर्जरी के सुपर स्पेशिलिटी एम सी एच (सी वी टी एस) चिकित्सकों की कमी व हृदय रोगियों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए सुपर स्पेशिलिटी एम सी एच (सी वी टी एस) कोर्स से शैक्षिक सत्र 2020-21 से सर्विस बांड समाप्त कराने विषयक

9-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्डियो वैस्कुलर एवं थोरौसिक सर्जरी (सी0टी0 सर्जरी) की अति विशिष्टता के पाठ्यक्रम से सर्विस बांड को शैक्षिक सत्र 2020-21 से समाप्त किये जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/4 उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित संख्या ए0एम0ई0 3/2020 दिनांक 29/9/2020 प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार को ज्ञात है, कि उक्त सर्विस बांड के चलते हृदय रोग संस्थान, कानपुर में सुपर स्पेशिलिटी एम0सी0एच0 (सी0वी0टी0एस0) कोर्स में एम0सी0आई0 द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त तीन सीटों पर सत्र 2018-19 में तीनों सीटें तथा सत्र 2019-20 में दो सीटें भरी नहीं जा सकी, जिसके परिणाम स्वरूप सी0वी0टी0एस0 विभाग (हृदय रोग संस्थान, कानपुर) में 9 के स्थान पर केवल 2 सीनियर रेजीडेन्टों से काम चला आ रहा है, तथा इसी प्रकार सीटें खाली रहने की समस्या एस0जी0पी0जी0आई0, आर0एल0एम0, के0जी0एम0यू0 ने सी0वी0टी0एस0 विभागों की भी हैं ? क्या सरकार कार्डियो वैस्कुलर थौरौसिक सर्जरी के सुपर स्पेशिलिटी एम0सी0एच0 (सी0वी0टी0एस0) चिकित्सकों की पूरे प्रदेश में कमी एवं हृदय रोगियों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुये सुपर स्पेशिलिटी एमसीएच (सीपीटीएस) कोर्स से शैक्षिक सत्र 2020-21 से सर्विस बांड समाप्त कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में मसीरपुर पिच रोड से इस्माइलपुर तक मार्ग का नव निर्माण कराने विषयक

10-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में मसीरपुर पिच रोड से (नहर) इस्माइलपुर तक की दूरी लगभग 02 कि0मी0 मार्ग का नव निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में बसावट मसीरपुर व इस्माइलपुर एकल मार्ग से संतृप्त है। पूर्व से संतृप्त ग्रामों/बसावटों को पुनः आपस में जोड़ना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में जीयनपुर-बिलरियागंज मुख्य मार्ग से नई हाईडिल तक मार्ग का नव निर्माण कराने विषयक

11-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में जीयनपुर बिलरियागंज मुख्य मार्ग से नई हाईडिल होते हुए उ0मा0 विद्यालय के सामने से अण्डाखोर पिच रोड तक दूरी लगभग 02 कि0मी0 का नव निर्माण कार्य के न होने से आम जनमानस को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग ग्राम सभा अण्डाखोर को जोड़ने से सम्बन्धित है, जो कि पूर्व से ही एकल पक्के मार्ग से जुड़ा हुआ है। अतः प्रस्तावित मार्ग वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में डिप्टी की छावनी गोपालपुर इंटर कालेज मार्ग से दाये मंदरपुर मार्ग का नव निर्माण कराने विषयक

12-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में डिप्टी की छावनी गोपालपुर इण्टर कालेज मार्ग से दायें मन्दरेपुर मार्ग दूरी 400 मीटर का नव निर्माण कार्य न होने से विशेषकर बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का नव निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग मन्दरेपुर मार्ग से डिप्टी की छावनी मार्ग को जोड़ने वाली छूटी कड़ी है, किन्तु उक्त मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार आवश्यक चौड़ाई में भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः भूमि की उपलब्धता न होने के कारण मार्ग का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के प्रचलित किसी योजना से प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त मार्ग पर लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली में पीडब्ल्यूडी के मार्गों के विवरण व मार्गों के श्रेणीवार रख-रखाव हेतु धन आवंटन विषयक

13-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में पीडब्लूडी के ओडीआर, एमडीआर, ग्रामीण संपर्क मार्ग, राज्य हाई-वे के कुल कितने मार्ग स्थित है तथा मार्गों का नाम लंबाई मार्गों की वर्तमान में स्थिति का विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि मार्गों के श्रेणीवार रख-रखाव हेतु धन आवंटन की क्या नीति है ? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कैराना की गड्ढायुक्त व परिवहन हेतु खराब मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में राज्य राज मार्ग श्रेणी का 01 मार्ग, अन्य जिला मार्ग श्रेणी के 13 मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग श्रेणी के 143 मार्ग है। उक्त मार्गों के नाम, लम्बाई एवं वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न[†] है। मार्गों के श्रेणीवार रख-रखाव हेतु वार्षिक अनुरक्षण नीति के तहत राज्य राज मार्ग पर प्रत्येक चार वर्ष में, अन्य जिला मार्ग पर प्रत्येक पांच वर्ष में एवं ग्रामीण मार्ग पर प्रत्येक आठ वर्ष पर नवीनीकरण हेतु धनावंटन का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त गड्ढामुक्ति हेतु समय-समय पर धनावंटन किया जाता है।

जी हां। विधान सभा क्षेत्र कैराना में लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की दशा सामान्यतया संतोषजनक है एवं आवागमन हेतु उपयुक्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ संख्या 351-356 पर।

प्रदेश में जनपद हापुड़ नगर पालिका पिलखुवा में अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की लड़ाई के कारण पिलखुवा में विकास कार्यों के न होने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

14-श्री असलम अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के नगर पालिका पिलखुवा में नगर पालिका के अन्तर्गत विकास कार्य वर्तमान में रुक गया है ? क्या सरकार संज्ञान लेकर उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

नगर पालिका परिषद, पिलखुवा में वर्तमान बोर्ड का गठन दिनांक 12-12-2017 को हुआ था। नगर पालिका परिषद पिलखुवा में आहूत बोर्ड बैठकों में पालिका बोर्ड द्वारा स्वीकृत विकास कार्य संबंधी प्रस्तावों के अन्तर्गत सड़कों व नालों आदि के निर्माण व अन्य कार्य शासन द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि एवं पालिका निधि (लगभग 20 करोड़ रुपये की धनराशि) से कराये गये हैं। नगर पालिका द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली से एवं कोविड-19, महामारी के दौरान शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में निर्माण संबंधी कार्य कुछ समय के लिये स्थगित कर दिये गये थे। उक्त अवधि में भी पालिका द्वारा आवश्यक सेवा संबंधी समस्त विकास कार्य कराये गये है। वर्तमान में सभी विकास/निर्माण कार्य सुचारु रूप से संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में गन्ना विभाग द्वारा बनी सड़क की मरम्मत कराने विषयक

15-श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में गन्ना विभाग द्वारा निर्मित सड़क क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार सर्वे कराकर उक्त मार्गों की विशेष मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जी हां।

गड्ढामुक्त योजनान्तर्गत जनपद के सभी मार्गों का सर्वे कराया गया, किन्तु चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में उक्त प्रयोजना हेतु कोई धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण उक्त मार्ग की मरम्मत का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

16-श्रीमती सरोज सोनकर-

(03 मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा चांदाझार में 500 मी0 सड़क के डामरीकरण हेतु

17-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा चांदाझार में राम मिलन के घर से शिवपाल यादव के घर तक लम्बाई लगभग 500 मीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा चांदाझार एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। ग्राम सभा चांदाझार में राम मिलन के घर से शिवपाल यादव के घर तक (आबादी भाग) का डामरीकरण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद ग्राम पंचायत डासना देहात के भूड़ गड़ी बांबे पर तिर्यश चमड़ा फैक्ट्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के चलने पर कार्यवाही विषयक

18-श्री असलम अली-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की ग्राम पंचायत डासना देहात के भूड़ गड़ी बांबे पर स्थित तिर्यश चमड़ा फैक्ट्री प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये बिना ही वर्तमान में संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गाजियाबाद के ग्राम-भूरगढ़ी, परगना डासना में मैसर्स त्रियश इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0, ग्राम-भूरगढ़ी, डासना, गाजियाबाद नाम से टैनरी उद्योग स्थापित है, जिसको उ0प्र0

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 16-01-2020 द्वारा संचालन हेतु जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सशर्त जल एवं वायु सहमति निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि 31-12-2024 है।

जनपद मऊ में पीपीपी माडल में इंदारा जंक्शन के पास मेडिकल कालेज का निर्माण कराये जाने विषयक

19-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में पी0पी0पी0 मॉडल के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण जनहित में जिला मुख्यालय के समीप विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत इंदारा जंक्शन (रेलवे स्टेशन) के समीप कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित पी0पी0पी0 मॉडल पर प्रदेश के 16 असेवित जिलों में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिनमें जनपद मऊ भी सम्मिलित है। भूमि का चयन नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के आधार पर किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में तमसा नदी पर पीपा पुल के निर्माण के संबंध में पत्र सं ख-6-640242 दि0 19-03-2020 पर कार्यवाही विषयक

20-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में तमसा नदी पर पीपा पुल का निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र स0ख-6-640242 दिनांक 19-03-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद मऊ में विकास खण्ड रतनपुरा, ग्राम पिपरसाथ के निकट गोदामघाट पर पीपे के पुल निर्माण हेतु आंकलित लागत रुपये 33.54 लाख है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड महराजगंज में मोलनापुर संपर्क मार्ग से झोटीपुर संपर्क मार्ग का नवनिर्माण कराने विषयक

21-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में मोलनापुर सम्पर्क मार्ग से झोटीपुर सम्पर्क मार्ग तक की दूरी लगभग 02 कि0मी0 का नव निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में मोलनापुर सम्पर्क मार्ग से झोटीपुर सम्पर्क मार्ग तक की दूरी 2 कि0मी0 प्रदेश सरकार की छूटी कड़ी योजनान्तर्गत है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड बिलरियागंज में वनकट जैगहा-कन्धरापुर मार्ग से जलालुद्दीन पट्टी होते हुए गुलवा गौरी सहर तक व इंदुआ शेखुपुर से तोड़कापुर तक संपर्क मार्ग 2.5 कि0मी0 पिंच रोड का नव निर्माण कराने विषयक

22-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में वनकट जैगहा कन्धरापुर मार्ग के किलोमीटर 4 से जलालुद्दीन पटरी होते हुए गुलका गौरी नहर तक एवं इन्दुआ से तोहकापुर तक सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर पिच रोड नव निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में 250 से अधिक आबादी के असंतृप्त मजरों/अनजुड़ी बसावट को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत बसावट जलालुद्दीनपट्टी (आबादी 468) एवं चकतोहफापुर (आबादी 261) आबादी को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु वनकट जैगहा बिन्दवस जयराजपुर कन्धरापुर कि0मी0 4 से जलालुद्दीनपट्टी होते हुए गुलवा गौरी नहर तक एवं इन्दुआ शेखपुर से चकतोहफापुर तक सम्पर्क मार्ग का आगणन गठित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कैराना झिंझाना मार्ग के नवीनीकरण विषयक

23-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैराना झिंझाना मार्ग गड्ढ़ा युक्त होने के कारण परिवहन योग्य नहीं है ? यदि हां तो क्या सरकार उपरोक्त कार्य हेतु धन आवंटन कर उपरोक्त मार्ग पर गन्ना परिवहन एवं आम जनता की सुविधा के लिए सुधार कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

विधान सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली में कैराना झिंझाना मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग की कुल लम्बाई 12.00 कि0मी0 है। वर्तमान में मार्ग को गड्ढामुक्त कर दिया गया है एवं सुगम यातायात हेतु उपयुक्त है। मार्ग पर वर्तमान पी0सी0यू0-16090 है। मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में देहली-कानपुर लाइन पर स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या 62 पर निर्माणाधीन आर0ओ0बी0 का निर्माण पूर्ण कराने विषयक

24-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में देहली-कानपुर लाइन पर स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या 62 पर निर्माणाधीन आर0ओ0बी0 का निर्माण सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथि अक्टूबर, 2021 है।

विधान सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली में लोक निर्माण के मार्गों के निर्माण व रख-रखाव विषयक

25-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली में लोक निर्माण के कुल कितने श्रेणियों यथा ओडीआर, एमडीआर, ग्रामीण संपर्क मार्ग, राज्य हाई-वे के कुल कितने मार्ग स्थित है तथा उक्त मार्गों का नाम लम्बाई मार्गों की वर्तमान में स्थिति का विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी के उक्त मार्गों के श्रेणीवार रख-रखाव हेतु धन आवंटन की क्या नीति है ? क्या सरकार विधान सभा कैराना की गड्ढा युक्त व परिवहन हेतु खराब मार्गों का सुधार कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शामली में विधान सभा क्षेत्र कैराना में निम्नलिखित श्रेणियों के मार्ग स्थित है :-

क्र0सं0	मार्गों की श्रेणी	मार्गों की संख्या
1	राज्य राज मार्ग	01
2	अन्य जिला मार्ग	13
3	ग्रामीण मार्ग	143

उपरोक्त मार्गों के नाम, लंबाई तथा वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न सूची[†] के अनुसार है।

मार्गों के श्रेणीवार रख-रखाव हेतु वार्षिक नीति के तहत राज्य राज मार्ग पर प्रत्येक चार वर्ष में, अन्य जिला मार्ग पर प्रत्येक पांच वर्ष में एवं ग्रामीण मार्ग पर प्रत्येक आठ वर्ष पर नवीनीकरण हेतु धनावंटन का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त गड्ढामुक्ति हेतु समय-समय पर धनावंटन किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र कैराना में लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की दशा सामान्यतया संतोषजनक है एवं आवागमन हेतु उपयुक्त है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में देहली-कानपुर लाइन पर स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या 63 पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से विलम्ब होने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराते हुये कार्य पूर्ण कराने विषयक

26-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद फिरोजाबाद में देहली-कानपुर लाइन पर स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या 63 पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य पूर्ण होने की कोई तिथि निर्धारित की गयी है ? यदि हां तो क्या उक्त कार्य निर्धारित तिथि को पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराते उक्त कार्य पूर्ण सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रश्नगत रेल सम्पार सं0 63 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य माह मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ संख्या 357-361 पर।

उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा एल्डिको सौभाग्यम, वृंदावन योजना लखनऊ के बिल्डअप एरिया में फर्जी वृद्धि संसूचित कर आवंटियों से वसूले धन को ब्याज सहित वापस कराने विषयक

27-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा एल्डिकों सौभाग्यम वृन्दावन योजना लखनऊ के मानचित्र दिनांक 13-07-2011 में टावर-3 एवं 4 का बिल्डअप एरिया 1258.53 वर्ग मीटर स्वीकृत किया गया एवं संसोधित मानचित्र दिनांक 18-04-2016 में शमनोपरान्त बिल्डअप एरिया में कमी करके 1225.60 वर्ग मीटर मंजूर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिल्डअप एरिया में कोई वृद्धि मंजूर नहीं किये जाने के बावजूद प्रमोटर द्वारा एरिया में फर्जी वृद्धि संसूचित करके आवंटियों से धनराशि वसूली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रमोटर के विरुद्ध कार्यवाही कराकर आवंटियों से वसूली गई धनराशि ब्याज सहित वापस करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हाँ।

सुपर एरिया अथवा धनराशि का परिवर्तन आवंटी एवं विकासकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध से सम्बन्धित है। अनुबन्ध की शर्तों में विवाद की स्थिति में रेरा में निर्धारित प्रक्रियानुसार अनुतोष प्राप्त करने की व्यवस्था है। आवंटी सक्षम फोरम पर आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में स्टांप व निबन्धन विभाग उ0प्र0 में 12 वर्षों से चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पदोन्नति में विलंब की जांच व कार्रवाई विषयक

28-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या स्टांप तथा न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टांप एवं निबन्धन विभाग उ0प्र0 में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की समूह ग में विभागीय पदोन्नित की नीति लागू है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विगत 12 वर्ष में चतुर्थ श्रेणी स्टाम्प तथा कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की गयी है ? क्या सरकार उक्त विभाग में पिछले 12 वर्षों से चतुर्थ श्रेणी क्रार्मिक की पदोन्नति में होने वाले विलंब की जांच कराकर शिथिलता में लिप्त सम्बंधित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री (श्री रवीन्द्र जायसवाल)-

जी हाँ।

जी नहीं।

चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के संबंध में अवगत कराना है कि अब से पूर्व अंतिम पदोन्नति की कार्यवाही वर्ष 2018 में गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर अहर्ता पाये गये कार्मिकों में से योग्य कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में भू-उपयोग व्यावसायिक करने पर विचार विषयक

29-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में अट्ठारह मीटर से चौड़े रास्ते पर भू-उपयोग को व्यावसायिक करने की कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। दिनांक 21-12-2016 से प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर 9.1.7.3 के अनुसार यदि किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल /भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा। ऐसे स्थलों पर महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अनुसार "सामान्यतः अनुमन्य" क्रियाओं को छोड़कर "सशर्त अनुमन्य" एवं विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं की अनुमति उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आवासों पर एकल व्यक्ति द्वारा विक्रय की अनुमति देकर व्यावसायिक उपयोग का प्राविधान करने पर विचार विषयक

30-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आवासों के व्यावसायिक उपयोग का प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत महिलाओं द्वारा घर पर तैयार वस्त्र /खाद्य सामग्री को उनके आवास पर एकल व्यक्ति द्वारा विक्रय की अनुमति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

दिनांक 21-12-2016 से प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर 9.1.7.3 के अनुसार यदि किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या

विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा। ऐसे स्थलों पर महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अनुसार "सामान्यतः अनुमन्य" क्रियाओं को छोड़कर "सशर्त अनुमन्य" एवं विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं की अनुमति उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रियदर्शिनी कालोनी को नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में

31-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्रियदर्शिनी कालोनी को नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रियदर्शिनी योजना की समस्त अवस्थापना सुविधाए दिनांक 28-04-2008 को नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार में भीड़ नियंत्रित करने हेतु बाजार लगने का समय रात्रि में किये जाने के विषयक

32-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने और आवागमन की सुगमता के दृष्टिगत साप्ताहिक बाजार को रात्रि के समय लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

लखनऊ नगर निगम सीमान्तर्गत लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को रात्रि में लगाये जाने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बसंत कुंज व प्रबंध नगर योजना हेतु सुगम यातायात हेतु गोमती नदी के छोर पर सिक्स लेन तटबंध बनाने विषयक

33-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनायी जा रही बसन्त कुन्ज योजना और प्रस्तावित प्रबन्ध नगर योजना के लिए सुगम यातायात हेतु गोमती

नदी के दोनों छोर पर सिक्स लेन तटबन्ध बनाये जाने हेतु आवश्यक बजटीय प्राविधान सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बसन्तकुंज योजना के अन्तर्गत गोमती नदी हार्डिंग ब्रिज के अपस्ट्रीम में दायें तटबन्ध पर गऊघाट पम्पिंग स्टेशन से हरदोई रोड-सीतापुर रोड बाईपास तक 3.036 कि0मी0 की लम्बाई में तटबन्ध के निर्माण हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा सिंचाई विभाग को पुनरीक्षित परियोजना लागत रु0 5742.58 लाख के सापेक्ष रु0 4100.00 लाख अवमुक्त किया जा चुका है।

जनपद बस्ती के ब्लाक रुधौली के ग्राम भितेहरा के सहकारी साधन समिति से रामबुझारत पाण्डेय के घर तक 500 मी0 मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

34-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रुधौली के अन्तर्गत ग्राम भितेहरा के सहकारी साधन समिति से रामबुझारत पाण्डेय के घर तक लगभग 500 मीटर मार्ग जर्जर है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ नगर के जानकीपुरम कालोनी सेक्टर एच में पहाड़पुर चौराहे से सहारा स्टेट जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने विषयक

35-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के जानकीपुरम् कालोनी सेक्टर-एच में पहाड़पुर चौराहा से सामुदायकि केन्द्र होते हुये सहारा स्टेट को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी हाँ। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत स्थल के सुदृढ़ीकरण हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। उक्त मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के मंदिर पार्क महानगर विस्तार सेक्टर सी के पास आवास सं0 सी 55 के आगे साईं अपार्टमेंट के बीच में दबंगों द्वारा बनाये गये ब्रेकरों को तुड़वाने विषयक

36-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के मन्दिर पार्क महानगर विस्तार सेक्टर-सी नये हनुमान मन्दिर एवं विदिशा पार्क के समीप आवास संख्या सी-55 के आगे साईं अपार्टमेन्ट के बीच में कतिपय दबंग लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियम विरुद्ध रोड पर ऊंचे-ऊंचे स्पीड ब्रेकर बनाये जाने के कारण आवागमन में लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्पीड ब्रेकरों को तुड़वायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल से दो स्पीड ब्रेकरों को हटवा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जानकीपुरम कालोनी सेक्टर एच में सामुदायिक केंद्र के सामने बना डिवाइडर को पाटकर हरियाली लगवाये जाने विषयक

37-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के जानकीपुरम् कालोनी सेक्टर-एच में सामुदायिक केन्द्र के सामने बना डिवाइडर (खुला हुआ नाला) जो कि मुकुन्द मिठाई शाप से होते हुये पहाड़पुर चौराहा कुर्सी रोड की ओर जा रहा है, में स्थानीय निवासियों द्वारा कूड़ा फेंकने एवं जानवरों के गिरकर मरने से भीषण दुर्गन्ध के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डिवाइडर (खुला हुआ नाला) को पाटकर हरियाली लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त नाले की मरम्मत करते हुए कवर किये जाने का कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। नाला कवर किये जाने के उपरान्त हरियाली लगाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर स्थित शेखुल हिन्द मौलाना महमूदुल हसन मेडिकल कालेज में आउटसोर्सिंग पर रखे गये कर्मचारियों के विवरण व उन्हें किये गये भुगतान के सम्बन्ध में

38-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर स्थित शेखुल हिन्द मौलाना महमूदुल हसन मेडिकल कालेज में किन-किन पदों पर वर्तमान में कितने कर्मचारी आउट सोर्सिंग पर कार्यरत हैं तथा उन्हें कितना भुगतान कब किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

1. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सहारनपुर में वर्तमान में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 28 प्रकार के विभिन्न श्रेणी के पदों पर कुल 372 कार्मिक कार्यरत है, पदवार सूची संलग्न[†] हैं।
2. सभी आउटसोर्स कार्मिकों को माह नवम्बर, 2020 तक के मानदेय का कुल रु0 59,00,213.00 तथा माह दिसम्बर 2020 का कुल मानदेय रु0 58,92,051.00 का भुगतान किया जा चुका है, पदवार भुगतान का विवरण संलग्न हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र केराकत ब्लाक मुफ्तीगंज ग्राम अमरा में पक्की सड़क का निर्माण कराने विषयक

39-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लॉक मुफ्तीगंज के ग्राम अमरा में पक्की सड़क निर्माण कराने के संबंध में सन्दर्भ संख्या 91919400025225 दिनांक 04-07-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम अमरा को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की। कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। कार्य का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा निर्मित पुरनियां रेलवे ओवर ब्रिज के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारे जाने विषयक

40-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा निर्मित पुरनियां रेलवे ओवर ब्रिज के ड्रेनेज सिस्टम में कमी रह जाने के कारण

[†] छापा नहीं गया।

वर्षा होने पर सेतु का जल बहकर समीप के घरों में जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेतु के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा निर्मित पुरनिया रेलवे ओवर ब्रिज के दोनों तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी अलीगंज स्थित है। पुरनियां चौराहे से रेलवे क्रासिंग की ओर जाते समय सर्विस रोड के किनारे एल0डी0ए0 द्वारा निर्मित नाली स्थानीय निवासियों द्वारा रैम्प बनाकर/कचरा डालकर बन्द कर दी गयी थी, जिसके कारण वर्षा होने पर सेतु एवं सर्विस रोड के जल की उचित निकासी नहीं हो पाती थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा बताये गये स्थल पर नगर निगम, लखनऊ द्वारा संबंधित स्थल एवं नालियों की सफाई का कार्य करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनुपद लखनऊ के मड़ियांव से पुरनिया के मध्य सड़क मार्ग के दोनों तरफ नाली का निर्माण कराये जाने विषयक

41-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के मड़ियांव थाना क्षेत्र से पुरनिया के मध्य लोक निर्माण विभाग की सड़क के दोनों और नाले का निर्माण नहीं कराये जाने से वर्षा होने पर जलभराव से सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के दोनों और नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग (सीतापुर मार्ग एन0एच0-24) के कि0मी0-490 से 492 के मध्य जल निकासी हेतु नाली के निर्माण की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डी0एम0एल0टी0 और डी0एम0आर0टी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल कालेजों को अनुमति प्रदान किये जाने विषयक

42-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डी0एम0एल0टी0 और डी0एम0आर0टी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल कालेजों को भी अनुमति प्रदान किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल कालेजों को भी डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन (डी0एम0एल0टी0) एवं डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन (डी0एम0आर0टी0) पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में नगर निगम लखनऊ तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की अवस्थापना मद की राशि उपलब्ध कराने विषयक

43-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में विकास कार्य हेतु नगर निगम लखनऊ तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण को विगत दो वर्षों से अवस्थापना मद की कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या अवरुद्ध विकास कार्यों के दृष्टिगत इस मद में उपलब्ध धनराशि नगर निगम व लखनऊ विकास प्राधिकरण को सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अवस्थापना मद के अन्तर्गत नगर निगम लखनऊ को विगत दो वर्षों में कुल रु0 12347.45 लाख तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण को कुल रु0 16870820.14 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हुसैनाबाद क्षेत्र में म्यूजिकल फाउण्टेन का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने विषयक

44-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हुसैनाबाद क्षेत्र में म्यूजिकल फाउण्टेन का निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की कोई समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो क्या सरकार निर्धारित समय सीमा में उक्त निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

स्थल पर संदर्भित कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 15-08-2019 तक का समय निर्धारित था। कार्यदायी फर्म द्वारा स्थल पर भौतिक रूप से लगभग कार्य पूर्ण कर दिया गया है, जिसका ट्रायल/परीक्षण भी हो चुका है। उक्त फाण्टेन हेतु विद्युत संयोजन के लिए विद्युत विभाग से सम्पर्क किया गया। तत्क्रम में फिजिबिल्टी के क्रम में विद्युत विभाग के निर्देशानुसार स्थल पर समुचित मात्रा में विद्युत आपूर्ति न होने के कारण विद्युतीकरण/ट्रांसफार्मर आदि की कार्यवाही

व्यवहारित की गयी। कार्य हेतु उपयुक्त निविदा दिनांक 08-10-2020 को प्राप्त हो गयी है। निविदा की वित्तीय बिड् दिनांक 23-12-2020 को सक्षम स्तर से स्वीकृत हुई है। प्रश्नगत निविदा में कार्य की प्रारम्भ तिथि 24-12-2020 एवं समाप्ति तिथि 23-03-2021 निर्धारित है। वर्तमान समय में म्यूजिकल फाउण्टेन क्रियाशील कर दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा बखारी में लगभग 800 मीटर आरसीसी सड़क के निर्माण हेतु

45-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा बखारी में मोती मास्टर के घर से छोटी बखारी तक लम्बाई लगभग 800 मीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा बखारी एवं छोटी बखारी दोनों गांव पूर्व से एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। दो जुड़े हुये गाँवों को आपस में जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी नीति से आच्छादित नहीं होता है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा मधवापुर में लगभग 3 कि0मी0 आरसीसी मार्ग का निर्माण कराने हेतु

46-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा मधवापुर में थिर्रा महतो के खेत से जमुनापुर प्राइमरी स्कूल से होते हुए अमृतपुर काटा तक दूरी लगभग 3 किलोमीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत ग्राम सभा मधवापुर में थिर्रा महतो के खेत से जमुनापुर प्राइमरी स्कूल से होते हुए अमृतपुर कांटा तक के संरेखण में पड़ने वाले ग्राम जमुनापुर को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। कार्य का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा गंगापुर मंडी से 1 कि0मी0 सड़क के डामरीकरण कार्य हेतु

47-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगापुर मंडी से बंगाली डॉ0 की दुकान तक लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत ग्राम सभा गंगापुर मण्डी से बंगाली डॉ0 की दुकान पूर्व से लेपित मार्ग है। वर्तमान में मार्ग पर आंशिक पैच हो गये है, जिसकी मरम्मत का कार्य 15-03-2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

48-श्रीमती सरोज सोनकर-

(03-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश सरकार व सहारनपुर मंडल स्थित वन निवासियों की पुनर्वास योजना विषयक

49-श्री नाहिद हसन-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वनों में निवास करने वाले निवासियों के पुनर्वास की वर्तमान में क्या नीति है ? क्या सरकार की सहारनपुर मंडल में स्थित वनों में रहने वाले परिवारों को वहां से पुनर्वासित करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

प्रदेश के अन्तर्गत वनों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन भूमि के अधिभोग हेतु हक पत्र दिये गये हैं।

सहारनपुर वृत्त के अन्तर्गत पड़ने वाले वन प्रभागों के वनों में निवास करने वाले निवासियों के पुनर्वास हेतु वर्तमान में कोई नीति प्रचलित नहीं है।

सहारनपुर मण्डल के अन्तर्गत पड़ने वाले वन प्रभागों के वनों में निवास करने वाले परिवारों के पुनर्वास हेतु वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं है।

जनपद सहारनपुर में शिवालिक वन प्रभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला समिति के स्तर से टौंगिया

ग्रामों/अन्य परम्परागत वन निवासियों से सम्बन्धित 462 दावे प्राप्त हुये, जिसमें 151 दावे पोषणीय पाये जाने के कारण जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किये गये, जिसके सापेक्ष 29.8252 हेक्टेयर कृषि एवं 3.437404 हेक्टेयर आवासीय भूमि के अधिभोग हेतु हक पत्र दिये गये हैं, 311 दावे पोषणीय न पाये जाने के कारण निरस्त किये गये, जिसमें 209 दावे पुनर्विचार हेतु जिला स्तरीय समिति के स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में भीमबर संपर्क मार्ग से सलेमपुर होते हुए सरदहा बाजार तक जर्जर मार्ग का नव निर्माण कराने विषयक

50-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में भीमबर सम्पर्क मार्ग से सलेमपुर होते हुए सरदहा बाजार तक दूरी लगभग 10 किलोमीटर जर्जर हो जाने से क्षेत्रवासियों की आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ। सलेमपुर से सरदहा तक मार्ग की कुल लम्बाई 8.25 कि0मी0 है, जिसमें से 5.75 कि0मी0 लम्बाई का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जो यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है। मार्ग का शेष भाग, बिलरियागंज सलेमपुर बाजार से महुवई खास होते हुए सिन्धवारा तक के नाम से वर्ष 2010-11 में 2.50 कि0मी0 लम्बाई में मण्डी परिषद्, आजमगढ़ द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था। गड्ढामुक्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में क्षतिग्रस्त भाग में पैच मरम्मत कार्य कराया गया। वर्तमान में भारी वाहनों के आवागमन होने के कारण प्रिमिक्सिंग का लगभग 60 प्रतिशत भाग पुनः क्षतिग्रस्त हो गया है।

मण्डी परिषद के स्वामित्व के मार्ग पर ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण नीति के अनुसार सुदृढ़ीकरण/मरम्मत कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में सेहदा जंगल से दुबरहन बुजुर्ग होते हुए दुल्लह पार तक मार्ग का नव निर्माण कराने विषयक

51-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में सेहदा जंगल से दुबरहन बुजुर्ग होते हुए दुल्लहपार तक का मार्ग जर्जर होने के कारण वहाँ के आमजन मानस को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग सेहदा जंगल से आजमपुर को जोड़ता है, जिसका कुछ भाग पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे होने से एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु मिट्टी/सामग्री ढुलाई होने से ध्वस्त/क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के मरम्मत हेतु पी0आई0यू0-6 यूपीडा, आजमगढ़ को पत्र लिखा गया है। मार्ग के अपग्रेडेशन का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत फेज-3 में स्वीकृत है। मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक मुरसान के इगलास मार्ग से ग्राम परताप के सामने से ग्राम लहरा तक मार्ग के निर्माण विषयक

52-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लॉक मुरसान के अन्तर्गत इगलास मार्ग से ग्राम परताप के सामने से ग्राम लहरा तक मार्ग कच्चा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

ग्राम परताप एवं ग्राम लहरा पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े हैं। पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े हुये ग्रामों को अन्य लेपित मार्ग (डबल कनेक्टिविटी) से जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड सदर के बाईपास रोड के निर्माण हेतु शेष गांवों के मुआवजे के भुगतान विषयक

53-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के बाई पास रोड के निर्माण हेतु अधिगृहीत 17 गांवों में भूमि में कतिपय 12 गांवों का मुआवजा का भुगतान कर दिया है एवं 5 गांवों के मुआवजा का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार शेष 5 गांवों का मुआवजा का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रतापगढ़ बाईपास के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जानी है। अधिग्रहित कुल 17 ग्रामों में से 12 ग्रामों के मुआवजे का भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है। अवशेष 5 ग्रामों में मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत कैरा गौरबारी बाजार से भटका मानापुर मोड़ तक मार्ग का चौड़ीकरण कराने विषयक

54-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत खैरा गौरबारी बाजार से कटका मानापुर मोड़ तक मार्ग जर्जर एवं सकरा है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग अभिलेखों में कटका से गौरबारी मार्ग (कुल लम्बाई 5.200 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.75 मी0) के नाम से दर्ज है, जिस पर आवागमन सुचारु रूप से संचालित है। वर्तमान में मार्ग सुगम यातायात हेतु उपयुक्त है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त मार्ग (ग्रामीण श्रेणी) पर पी0सी0यू0-992 है, जो चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानक से कम है। प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का होने तथा अपेक्षित पी0सी0यू0 न होने के कारण उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना विभागीय मानक से आच्छादित नहीं है।

जनपद मुरादाबाद में आवास विकास परिषद की मझोला योजना-4 के भाग 2 के सेक्टर 6ए में प्रीमियम भूखण्ड सं 8,9,10 व भवन सं 173 पर नक्शे के विरुद्ध निर्माण के ध्वस्तीकरण कराने विषयक

55-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में आवास विकास परिषद की मझोला योजना-4 के भाग 2 के सेक्टर 6ए में प्रीमियम भूखण्ड संख्या 8,9,10 तथा भवन

संख्या 173 पर नक्शे के विरुद्ध अधोतल व बहुमंजिलों का अवैध निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो नक्शे के विरुद्ध अवैध रूप से निर्मित उक्त भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए उक्त अवैध निर्माण के लिये दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये गये हैं, अतएव सम्बन्धित कार्मिकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं बनता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में सहारा इण्डिया में पैसा जमा करने वाले उपभोक्ताओं की एफ0 डी0 पूर्ण होने के बाद भी भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में

56-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में सहारा इण्डिया बैंकों में पैसा जमा करने वाले उपभोक्ताओं की एफ0 डी0 पूर्ण होने के बाद भी उक्त बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं की जमा धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां तो क्या सरकार एफ0 डी0 पूर्ण होने वाले उपभोक्ताओं का धनराशि का भुगतान कराने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रकरण राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। प्रकरण में सेबी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद में मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में कार्यवाही सेबी व सहारा ग्रुप द्वारा ही की जानी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बिलहा अन्तर्गत ग्राम सभा गूढ़ भल्लापुरवा में सोती नाला पुल निर्माण हेतु

57-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गूढ़ के भल्लापुरवा में सोती नाला पुल का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम सभा गूढ़ का मजरा भल्लापुरवा (भोलाकुण्डा) गॉव एकल लेपित मार्ग से जुड़ा है। सोती नाला अल्लापुरवा (भोलाकुण्डा) आबादी से 100 मी0 आगे है। सोती नाला के दूसरी तरफ कोई आबादी नहीं है, मात्र किसानों के खेत स्थित है। इस प्रकार के नाला पर सेतु निर्माण की कोई योजना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा हरखापुर में डामर रोड पर पुल निर्माण हेतु

58-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा हरखापुर में मुरव्वन टोला शिवमन्दिर से धर्मापुर तक डामर रोड पर पुल का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा हरखापुर में मुरव्वन टोला शिवमन्दिर (आबादी भाग) से धर्मापुर (कच्चा मार्ग) के मध्य स्थित झील पर पुल का निर्माण, वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित पुल निर्माण नीति से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा हरखापुर में 3 कि0मी0 रोड का डामरीकरण कराये जाने विषयक

59-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा हरखापुर में मुरव्वन टोला शिवमन्दिर से धर्मापुर तक लम्बाई लगभग 3 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा हरखापुर तथा ग्राम सभा धर्मापुर दोनों ही बसावटें पूर्व से एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं। दो जुड़े हुये गाँवों को आपस में जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी नीति से आच्छादित नहीं होता है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा नैनिहा हाई-वे से अड़गोड़वा मार्ग का निर्माण विषयक

60-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा नैनिहा हाई-वे से अड़गोड़वा गाँव तक मार्ग लम्बाई 7 किलोमीटर डामर रोड का मरम्मत सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मार्ग पर पीरियाडिक रिन्यूवल के कार्य की स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है। कार्य के पूर्ण करने की तिथि 12-04-2021 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा अड़गोड़वा से गूढ़ चौराहा तक मार्ग का निर्माण विषयक

61-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा सु0 के अन्तर्गत ग्राम सभा अड़गोड़वा से गूढ़ चौराहा तक मार्ग लम्बाई लगभग 8 किलोमीटर डामर रोड का मरम्मत सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मार्ग पर पीरियाडिक रिन्यूवल के कार्य की स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है। कार्य के पूर्ण करने की तिथि 12-04-2021 है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जानकीपुरम सहारा एस्टेट में सरकारी तालाब का सौंदर्यीकरण कराने विषयक

62-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के जानकीपुरम् सहारा स्टेट के अन्दर स्थित सरकारी तालाब का सौन्दर्यीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

लखनऊ नगर के जानकीपुरम सहारा स्टेट के अन्दर स्थित सरकारी तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कुर्सी रोड पर जनेश्वर इन्क्लेव के पास व्यावसायिक भूखण्ड पर माल-मल्टीप्लेक्स निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण पर विचार विषयक

63-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के कुर्सी रोड पर जनेश्वर इन्क्लेव के समीप व्यावसायिक भूउपयोग के भूखण्ड आरक्षित है ? यदि हां, तो क्या क्षेत्रवासियों के उपयोगार्थ उक्त भूखण्ड पर माल-मल्टीपेक्स निर्माण के लिए निविदायें आमंत्रित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। जनेश्वर इन्क्लेव एवं सृष्टि अपार्टमेन्ट के कार्नर पर व्यावसायिक भूखण्ड आरक्षित है, जिसमें से लगभग 7972.85 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध है तथा शेष भूमि पर गोदाम बना हुआ है, जिस पर प्रतिकर के संबंध में वाद संख्या-2945/1986 रणवीर इण्डस्ट्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सम्प्रति मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत वाद में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने के पश्चात यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अनुभूति, सृजन व सोपान अपार्टमेंट के विक्रय मूल्य में कमी करने विषयक

64-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अनुभूति सृजन एवं सोपान अपार्टमेण्ट विगत तीन वर्षों से बनकर तैयार है किन्तु मूल्य अत्यधिक होने के कारण उनका विक्रय नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पत्तियों के विक्रय हेतु कीमत में कमी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रिक्त फ्लैटों का आवंटन/विक्रय "पहले आओ पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

जनपद लखनऊ के निराला नगर में नजूल भूमि पर पार्किंग हेतु योजना बनाये जाने विषयक

65-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के निराला नगर में नजूल की भूमि उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती आबादी के दृष्टिगत उक्त नजूल की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग स्थल बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

लखनऊ नगर के निराला नगर में आई0टी0 कालेज के पश्चिम और कुर्सी रोड पर भूमि स्थित है। मोहल्ला हसनगंज पार बन्दोबस्त 1862 ई0 के भूमि खसरा संख्या-1054 तथा 1049 का भाग है तथा कुल क्षेत्रफल 102600 वर्गफिट है जो अभिलेखानुसार नजूल भूमि है। प्रश्नगत नजूल भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित है तथा रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम लखनऊ को सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु दिया गया है। निरालानगर योजना के स्वीकृत पार्ट विन्यास मानचित्र में चिन्हित स्थल ग्रेवयार्ड (कब्रिस्तान) हेतु आरक्षित है। उक्त के अतिरिक्त प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 के पैरा 9.1.7.3 के अनुसार यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा। अतः उक्त भूमि पर पार्किंग बनाया जाना विधिसंगत नहीं होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रियदर्शनी कालोनी, अलीगंज व जानकीपुरम क्षेत्र में भूखण्ड उपलब्ध कराकर फायर स्टेशन बनवाने विषयक

66-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्रियदर्शिनी कालोनी अलीगंज व जानकीपुरम् क्षेत्र में फायर स्टेशन हेतु भूखण्ड का कोई प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण उक्त क्षेत्र में फायर स्टेशन निर्माण हेतु भूखण्ड उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उक्त योजनाओं में फायर स्टेशन हेतु कोई भूखण्ड नियोजित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ नगर पंचायत के विस्तारीकरण क्षेत्र में डूडा द्वारा विकास कार्य कराने विषयक

67-श्री राजकुमार पाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद् बेल्हा प्रतापगढ़ नगर पंचायत की सीमा विस्तार में सम्मिलित ग्राम पंचायतें मजरों में विकास कार्य डूडा द्वारा नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त सरकार नगर पालिका/नगर पंचायतों के विस्तारीकरण क्षेत्र में डूडा द्वारा विकास कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

नगर पालिका/नगर पंचायतों के विस्तारीकरण क्षेत्र में मुख्य मंत्री, नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त उनका परीक्षण कर धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड महराजगंज ग्राम सभा नेवादा से परशुरामपुर मार्ग का नव निर्माण कराने विषयक

68-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में ग्राम सभा नेवादा से परशुरामपुर जाने वाली मार्ग तक दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर का नव निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

ग्राम सभा नेवादा से परशुरामपुर को जाने वाली मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 2.00 कि0मी0 है तथा प्रदेश सरकार की छूटी कड़ी योजना के अन्तर्गत है, जिसकी स्वीकृत वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड बिलरियागंज में जैराजपुर-परशुरामपुर मार्ग से भलुवाई होते हुए मार्ग का नव निर्माण कराने विषयक

69-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में जैराजपुर परशुरामपुर मार्ग से भलुवाई होते हुए भटनी बैदरा को जाने वाला मार्ग जर्जर होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजियाबाद ग्राम डासना देहात के भुडगढ़ी बांबे स्थित त्रियस चमड़ा फैक्ट्री के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

70-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के ग्राम डासना देहात के भुडगढ़ी बांबे पर स्थित त्रियस चमड़ा फैक्ट्री गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद से मानचित्र स्वीकृत कराये बगैर फैक्ट्री का अवैध निर्माण कर संचालित है ? क्या सरकार उक्त चमड़ा फैक्ट्री के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम डासना देहात के भुडगढ़ी बाम्बे पर स्थित त्रियस चमड़ा फैक्ट्री के निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अनुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 30-11-2018 को नोटिस जारी कर वाद संख्या-56/प्रवर्तन जोन-5/2018 संस्थित किया गया। उक्त वाद में प्रश्नगत निर्माण के विरुद्ध दिनांक 26-02-2019 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या-4/ई0एच0ए0/उद्योग/2001 दिनांक 18-04-2001 की प्रति प्रस्तुत करते हुए अतिरिक्त निर्माण को शमन कराने हेतु शमन शुल्क के रूप में दिया गया रु0 4 लाख का चेक प्राधिकरण कोष में जमा करा दिया गया। प्रश्नगत निर्माण स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किया गया है, जो शमनीय सीमा की परिधि के अन्दर है। निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत शमन आवेदन के संदर्भ में कार्यवाही प्रचलित थी, किन्तु कार्यवाही पूर्ण होने से पूर्व शासन द्वारा शमन उपविधि के स्थान पर सीमित अवधि के लिये शमन योजना-2020 लागू की गई। शमन योजना-2020 के आधार पर कार्यवाही के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-15757/2020 में पारित आदेश दिनांक 07-10-2020 के द्वारा शमन योजना-2020 को

स्थगित कर दिया गया है। शासनादेश संख्या-4/2021/644/आठ-3-21-234 विविध/2014 दिनांक 23-02-2021 के आलोक में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में यमुना नदी में पर्यावरण मानकों की अनदेखी कर अवैध खनन करने वाली फर्म के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

71-श्री नाहिद हसन-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 10/09/2020 को अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संबोधित पत्र जो एमएस ट्रेडर्स द्वारा ग्राम मवी, ककोर जनपद शामली में यमुना नदी में पर्यावरण मानकों की अनदेखी कर खनन कार्य करने पर उसकी एनओसी को निरस्त करने और फर्म को ब्लैक लिस्टिड करने विषयक है पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार उक्त जांच का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

मैसर्स एम0एस0 ट्रेडर्स, ग्राम-ममौर एहतमाल साबिक, कैराना, जिला शामली बालू खनन इकाई है। क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत इकाई का निरीक्षण दिनांक 22-10-2020 को किया गया तथा पर्यावरणीय अधिनियिमों का अनुपालन पाया गया। पुनः निरीक्षण दिनांक 15-01-2021 को इकाई की वार्षिक खनन सीमा समाप्त होने के कारण खनन कार्य बन्द पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में केंद्रीय ऑक्सीजन प्लांट (आईसीयू, इमरजेंसी एवं ओ0टी0) की स्थापना के संबंध में प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद का प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक एफजेड़ी/2019/1299 दिनांक 11/12/2019 पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

72-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में केंद्रीय ऑक्सीजन प्लांट (आईसीयू, इमरजेंसी एवं ओ0टी0) की स्थापना के संबंध में प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद का प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक एफजेड़ी/2019/1299 दिनांक 11/12/2019 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ प्रधानाचार्य के संदर्भित पत्र दिनांक 11-12-2019 द्वारा चिकित्सालय में सीवर प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद से सीवर प्लांट के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 24-01-2020 द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में हीमोफीलिया के मरीजों के उपचार आरम्भ कराये जाने हेतु हीमोफीलिया फैक्टर VIII इंजेक्शन उपलब्ध कराये जाने विषयक

73-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में हीमोफीलिया के मरीजों के उपचार आरम्भ कराये जाने हेतु हीमोफीलिया फैक्टर VIII इंजेक्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद का विभागाध्यक्ष, हीमटोलाजी विभाग, एस0जी0पी0जी0जाई, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक एफजेड़ी/2019/1360 दिनांक 16/12/2019 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 के पत्र दिनांक 24-02-2021 द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार हीमोफीलिया कोर कमेटी की बैठक दिनांक 06-02-2021 में जनपद-फिरोजाबाद के निकटवर्ती 02 जनपदों-आगरा एवं अलीगढ़ में हीमोफीलिया केन्द्र उपलब्ध होने के कारण जनपद-फिरोजाबाद में पृथक से हीमोफीलिया केन्द्र बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी (फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज) में पेजयल की समस्या का निदान कराये जाने विषयक

74-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी (फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज) में पेजयल की समस्या का निदान हेतु 1 लाख लीटर की क्षमता का भूमिगत जलाशय के निर्माण कराये जाने हेतु प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी, फिरोजाबाद द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन को प्रेषित पत्र संख्या एफजेड़ी/2019/535 दिनांक 26 जून 2019 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

शासनादेश संख्या-235/71-3-2020, दिनांक 04-03-2020 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एव एस0एन0एम0 चिकित्सालय फिरोजाबाद में भूमिगत जलाशय के निर्माण कार्य हेतु कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में इमरजेंसी सुविधा ट्रामा सेण्टर में दिये जाने के दृष्टिगत मुख्य परिसर में 25 बेड की नई इमरजेंसी ब्लाक बनाने विषयक

75-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में इमरजेंसी की सुविधा ट्रामा सेण्टर जो कि मुख्य चिकित्सा परिसर से लगभग 500-600 मीटर दूर है, में दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इमरजेंसी में आने वाले रोगियों की संख्या तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत मुख्य परिसर में 25 बेड की नई इमरजेंसी ब्लाक बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

वर्तमान में 25 बेड की नई इमरजेंसी ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज में सड़क/नाली निर्माण, प्रकाश व्यवस्था आदि सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने विषयक

76-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर (पूर्व में जिला अस्पताल) सड़क, लाइट, नाली प्रकाश व्यवस्था आदि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वर्षा ऋतु में बहुत अधिक जलभराव, गंदगी आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मेडिकल कॉलेज में सड़क/नाली निर्माण, प्रकाश व्यवस्था आदि सुविधाओं को उपलब्ध करायेगी यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद से सम्बद्ध चिकित्सालय में प्रश्नगत कार्यों हेतु शासनादेश दिनांक 25-02-2021 द्वारा उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ अन्तर्गत ग्राम पड़मई से मोतियारी का पुरवा के क्षतिग्रस्त मार्ग को पुनः निर्माण कराने विषयक

77-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ अन्तर्गत ग्राम पड़मई से मोतियारी का पुरवा मार्ग क्षतिग्रस्त एवं गड्ढेयुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन से कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

वर्तमान में मार्ग को पैच मरम्मत कर यातायात योग्य बनाये रखा गया है। मार्ग के विशेष मरम्मत की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रभारी निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के विरुद्ध विभागीय जांच पर कृत कार्रवाई की जानकारी

78-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2019 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के क्रम में क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर की प्राथमिक जांच मण्डलायुक्त सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी से दिनांक 09-03-18 में प्रभारी निदेशक के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

प्रभारी निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट दिनांक 09-03-2018 में प्रभारी निदेशक, को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। तत्पश्चात प्रभारी निदेशक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। विभागीय कार्यवाही में तत्कालीन प्रभारी निदेशक सम्प्रति अपर निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को अपर निदेशक के प्रारम्भिक वेतनमान

रु0 37400-67000 (ग्रेड वेतन रु0 8900/-) पर प्रत्यावर्तित करते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान कर अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

निदेशक शोध परिषद, शाहजहांपुर कार्यालय में सहा0 निदेशक गन्ना शोध परिषद में आहरण-वितरण अधिकारी स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात होने संबंधी पत्र पर कार्यवाही विषयक

79-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के कार्यालय में सहायक निदेशक गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में आहरण वितरण अधिकारी स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात की जांच संख्या 368 दिनांक 02-08-19 को आवश्यक कार्यवाही एवं जांच के लिए प्रमुख सचिव गन्ना को पत्र प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या प्रमुख सचिव गन्ना ने उपरोक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जी हां।

मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न में पदधारक का सम्बन्ध उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर से न होकर गन्ना किसान संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहाँपुर से है। मा0 सदस्य के पत्र पर निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। जिसमें यह अवगत कराया गया कि गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहाँपुर द्वारा प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार की योजनाओं की तकनीकी जानकारी तथा गन्ने एवं कृषि से सम्बन्धित नवीनतम कृषि अनुसंधानों को कृषकों तक पहुँचाने हेतु कृषकों को प्रशिक्षित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के हितार्थ चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन हेतु कृषि वैज्ञानिक अधिकारियों की गन्ना किसान संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहाँपुर में कमी है। केन्द्र पर कृषि तकनीकी अधिकारियों में एकमात्र सहायक निदेशक कार्यरत हैं। केन्द्र पर अन्य कोई अधिकारी कार्यरत न होने के कारण सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहाँपुर की तैनाती आहरण वितरण अधिकारी के रूप में बराबर बनी हुई है। उक्त से मा0 सदस्य को पत्र दिनांक 15-11-2019 के माध्यम से पूर्व में अवगत कराया जा चुका है।

जनपद बस्ती, पीलीभीत, बहराइच मार्ग पर मनौढ़ी चौराहे से बेवा चौराहे तक मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में

80-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली से गुजरने वाली बस्ती, पीलीभीत, बहराइच मार्ग पर जनपद बस्ती के मनौढ़ी चौराहे से

लेकर बेवा चौराहे तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है यदि हां, तो क्या सरकार बस्ती, पीलीभीत, बहराइच मुख्य मार्ग के उक्त भाग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। पीलीभीत, बहराइच, बस्ती मार्ग के जनपद बस्ती के अन्तर्गत किमी0 391.00 से 395.00 तथा कि0मी0 416.00 से 424.00 तक क्षतिग्रस्त भाग के विशेष मरम्मत की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है जिसे मार्च, 2021 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। मार्ग का शेष भाग सुगम यातायात हेतु उपयुक्त है।

उक्त मार्ग के जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कि0मी0 387.00 से 390.00 तक (बेवा से बस्ती बार्डर) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग सुगम यातायात हेतु उपयुक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट अन्तर्गत फतेहपुर कलसिया मार्ग पर सुगम यातायात हेतु पुल का चौड़ीकरण कराने विषयक

81-श्री नरेश सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में फतेहपुर कलसिया मार्ग पर पुल अत्यधिक सँकरा होने के कारण आवागमन बाधित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सुगम यातायात हेतु उक्त पुल का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत स्थल पर 70.88 मी0 लम्बाई के सेतु निर्माण, पहुँच मार्ग एवं भूमि अध्याप्ति सहित अनुमानित लागत रु0 1400.00 लाख है। सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र बेहट अन्तर्गत सुन्दरपुर मिर्जापुर मार्ग पर ग्राम कुरडीखेड़ा में हिन्दन नदी पर जनहित में यातायात हेतु पुल निर्माण कराने विषयक

82-श्री नरेश सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट अन्तर्गत सुन्दरपुर मिर्ज़ापुर मार्ग पर निकट ग्राम कुरडीखेड़ा में हिन्दन नदी पर यातायात हेतु जनहित में पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत स्थल पर 160.88 मी0 लम्बाई के सेतु के निर्माण, पहुँच मार्ग एवं भूमि अध्याप्ति सहित अनुमानित लागत रु0 961.48 लाख है। सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र बेहट ग्राम बुबका से धौलाकुंआ मार्ग पर नगला झण्डा से बेहट मार्ग पर गागरू नदी पर रपटा/पुल का निर्माण कराने विषयक

83-श्री नरेश सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत ग्राम बुबका से धौलाकुऑ मार्ग पर नगला झण्डा से बेहट मार्ग पर निकट मुर्तजापुर मार्ग में गागरु नदी पर रपटा पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत स्थल पर 151.13 मी0 लम्बाई के सेतु के निर्माण, पहुँच मार्ग एवं भूमि अध्याप्ति सहित अनुमानित लागत रु0 1324.63 लाख है। सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र बेहट अन्तर्गत पुराने जर्जर पुलों का पुनर्निर्माण कराने विषयक

84-श्री नरेश सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत 50 वर्ष पुराने जर्जर पुलों को चिन्हित कर पुनः निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद सहारनपुर में विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत कुल 38 सेतु निर्मित हैं, जिनमें से 3 सेतु पुराने एवं क्षतिग्रस्त है। शेष सभी सेतु वर्तमान में यातायात हेतु सुलभ है।

दिल्ली/यमनौत्री मार्ग (राज्य मार्ग 57) के कि0मी0 185 के चैनेज 184.700 में मस्करा राव नदी क्रॉस करती है। उस पर पुराना सेतु क्षतिग्रस्त है जिसके स्थान पर निर्मित अधूरे सेतु एवं पहुँच मार्ग को पूर्ण करने हेतु लागत रु0 324.71 लाख है।

दिल्ली यमनौत्री मार्ग (राज्य मार्ग 57) के कि0मी0 190 के चैनेज 189.500 में गंगराव नदी क्रॉस करती है। उस पर पुराना सेतु क्षतिग्रस्त है, जिसके स्थान पर निर्मित अधूरे सेतु एवं पहुँच मार्ग को पूर्ण करने हेतु लागत रु0 183.83 लाख है।

3-फतेहपुर, मुजफ्फराबाद कलसिया मार्ग के कि0मी0 30 में हिण्डन नदी काम करती है। जिस पर वर्तमान में पुराना संकरा एवं क्षतिग्रस्त सेतु निर्मित है। उक्त सेतु पर 70.88 मी0 लम्बाई के सेतु की आवश्यकता है, जिसकी पहुँच मार्ग एवं भूमि अध्याप्ति सहित अनुमानित

लागत रु0 1400.00 लाख है। उक्त तीनों सेतुओं का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा गौरा पिपरा में 1.5 कि0मी0 सड़क का डामरीकरण कराने विषयक

85-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गौरा पिपरा में पिपरा चौराहा से बल्लीपुरवा तक दूरी 1.500 किलो मीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा गौरा पिपरा में पिपरा चौराहा पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा प्रश्नगत बल्लीपुरवा राजस्व ग्राम गौरा पिपरा का मजरा है, जिसकी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी 87 है, जो लोक निर्माण विभाग की सम्पर्क मार्ग निर्माण नीति से आच्छादित नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के ग्राम हाबली परगना नकुड़ से ग्राम दरबूजी परगना नकुड़ में सड़क निर्माण कराने विषयक

86-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ग्राम हाबली परगना नकुड़ से ग्राम दरबूजी तक की सड़क टूटी होने से आवागमन में क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम हाबली एवं ग्राम दरबूजी पूर्व से एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं। ग्राम हाबली परगना नकुड़ से ग्राम दरबूजी तक का मार्ग, ग्रामों को परस्पर जोड़ता है। ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम मसूरी गंग नहर के निकट भगवती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी एंड सांइस द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से मानचित्र स्वीकृत कराये बगैर अवैध निर्माण की जांच कराने विषयक

87-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के ग्राम मसूरी गंग नहर के निकट भगवती इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद से मानचित्र स्वीकृत कराये बगैर अवैध निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आख्यानुसार प्रश्नगत स्थल प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। प्रश्नगत स्थल का मानचित्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में सई नदी पर करोड़ी घाट व सिरियामऊ पर पुल निर्माण व किसानों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिलाने विषयक

88-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में सई नदी पर करोड़ी घाट एवं सिरियामऊ पर बने पुल का पहुंच मार्ग का निर्माण न होने से आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलों के पहुंच मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर प्रतापगढ़ में सई नदी पर करौदी घाट सेतु एवं जिरियामऊ घाट सेतु के पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित हो रही भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने पर निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के वि0स0क्षे0 प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन आर0टी0ओ0 ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग व अनियमितता की जांच कराने विषयक

89-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन आर0टी0ओ0 ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग तथा मानक के विपरीत कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आर0टी0ओ0 ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण में की जा रही अनियमितता की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहिं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना का विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता परीक्षण कराया जा चुका है, जो मानक के अनुरूप पाया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ वि0स0क्षे0 प्रतापगढ़ के लो0नि0वि0 द्वारा मीरा भवन चौराहे से 1 किमी के सापेक्ष मात्र 800 मी0 मार्ग के निर्माण व घटिया सामग्री के प्रयोग व फर्जी भुगतान की जांच व दोषियों पर कार्रवाई विषयक

90-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा मीरा भवन चौराहे से पूरे ईश्वर नाथ तक मार्ग की लम्बाई 1 किलो मीटर के सापेक्ष केवल 800 मीटर मार्ग बनाया गया है और शेष मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त मार्ग को पूर्ण दिखाकर भुगतान कर दिया गया है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग तथा फर्जी भुगतान की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत मीरा भवन चौराहे से पूरे ईश्वर नाथ तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य शासनादेश दिनांक 28-11-2019 द्वारा लम्बाई 0.980 कि0मी0 एवं लागत रु0 67.82 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत लम्बाई 0.980 कि0मी0 के सापेक्ष कुल 0.964 कि0मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण है। अवशेष कार्य का निर्माण कार्य प्रगति में है। उक्त कराये गये कार्य के सापेक्ष आंशिक

भुगतान किया गया है। मार्ग का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के वि0स0क्षे0 प्रतापगढ़ अन्तर्गत शुकुलपुर का डवारा में निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण कार्य में अनियमितता की जांच कराने विषयक

91-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत शुकुलपुर काडवारा में राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण कार्य में घटिया मौरंग, सरिया, ईंट व अन्य सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त भवन के निर्माण में की जा रही अनियमितता की उच्च स्तरीय (टी0ए0सी0) जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना का विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता परीक्षण कराया जा चुका है, जो मानक के अनुरूप पाया गया है।

लखनऊ के हरिओम नगर में सड़क नाली निर्माण विषयक संशोधित आगणन को वित्तीय स्वीकृति हेतु भेजने विषयक

92-डॉ0 नीरज बोरा-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2020 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-48 के उत्तर के क्रम में क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के हरिओम नगर में सड़क, नाली निर्माण विषयक संशोधित आगणन प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त की वित्तीय स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

लखनऊ के फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत हरिओम नगर में शिवकान्त तिवारी से धनराज सिंह बाबूराम, शीला तिवारी कीर्ति क्लीनिक तक सड़क व नाली निर्माण के कार्य की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-391/2020/920/69-1-19-39(मु0अ0-37)/2019,

दिनांक 29 मार्च, 2020 द्वारा एवं हरिओम नगर में धनराज सिंह के मकान से हीमेन्द्र व बालाजी स्कूल तक सड़क व नाली निर्माण के कार्य की वित्तीय स्वीकृत शासनादेश संख्या-412/2020/911/69-1-20-122 (मु0अ0-37)/2020, दिनांक 29 मार्च, 2020 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में प्रियदर्शनी कालोनी प्रगति विहार के पास प्लाटों के आवंटन प्रक्रिया के विवरण विषयक

93-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में प्रियदर्शिनी कालोनी प्रगति-विहार के पास कबाड़ बाजार कतिपय प्लाटों का आवंटन नियमानुसार नहीं किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

सेक्टर-सी प्रगति विहार, प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड, लखनऊ में कुल 14 भूखण्डों (भूखण्ड संख्या-119, 119ए, 120, 120ए, 121, 121ए, 122, 122ए, 123, 123ए, 124, 124ए, 125, एवं 125ए,) का आवंटन नियम विरुद्ध रूप से किया गया था, जिसके संदर्भ में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ, सेक्टर-लखनऊ के द्वारा जाँच की गयी। प्रकरण के संदर्भ में थाना-कैसरबाग, लखनऊ में मुकदमा अपराध सं0-350/98 अन्तर्गत धारा 420/120बी, भा0द0वि एवं धारा-13(1)डी सपठित धारा-13(2) भ्र0नि0अधि0, 1988 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित प्रगति विहार क्षेत्र प्रियदर्शनी कालोनी में कबाड़ी बाजार को रिहायशी इलाके से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने विषयक

94-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित प्रगति विहार क्षेत्र प्रियदर्शिनी कालोनी में रिक्त फ्लैटों के विक्रय हेतु प्राधिकरण की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त रिहायशी क्षेत्र में कबाड़ी बाजार संचालित है यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कबाड़ी बाजार अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्राधिकरण द्वारा 'पहले आओ पहले पाओ' योजना के अन्तर्गत प्रियदर्शिनी नगर योजना में स्थित सोपान इन्क्लेव एवं सृजन अपार्टमेन्ट के रिक्त फ्लैटों का आवंटन किया जा रहा है। जी हां प्राधिकरण द्वारा व्यवसायिक भूखण्डों का आवंटन किया गया है जिस पर कतिपय व्यापारियों द्वारा कबाड़ी का व्यापार किया जा रहा है कुछ अवशेष सड़कों पर फैले हुए थे जिसे दिनांक 20-11-2020 से दिनांक 22-11-2020 तक अभियान चलाकर हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच ब्लाक कैसरगंज भकला चौराहे से विवियापारा पर ग्राम इन्छापुर के पास गांधी पुल के निर्माण की जांच विषयक

95-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ब्लाक कैसरगंज अन्तर्गत भकला चौराहे से विवियापारा संपर्क मार्ग पर ग्राम इन्छापुर के निकट गांधी पुल का निर्माण किस वर्ष कराया गया था तथा इस पुल के निर्माण की कितनी लागत थी ? क्या सरकार की जानकारी में है कि घटिया निर्माण के कारण अल्पावधि में ही पुल की रैलिंग आदि टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटिया निर्माण की जांच कराते हुए पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

गाँधीपुल का निर्माण वर्ष 1997 में निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0 बहराइच द्वारा कराया गया, जिसकी लागत रु0 30.00 लाख थी।

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य 23 वर्ष पूर्व कराया गया था, तथा वर्ष 2016-17 में मरम्मत का कार्य उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लिमिटेड बहराइच द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत द्वारा कराया गया। जिसमें रैलिंग मरम्मत कार्य नहीं कराया गया था। इस कारण जाँच का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा के ग्राम सभा कुड़वा में वन वैरियर से जयराम पुरवा तक सड़क का डामरीकरण विषयक

96-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 282 बलहा के अर्न्तगत ग्राम सभा कुड़वा में कुड़वा वन वैरियर से जयराम पुरवा हाइवे तक

दूरी लगभग 2 किलोमीटर डामरीकरण का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा कुड़वा में कुड़वा वन बैरियर तथा जयराम पुरवा दोनों लेपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः दो जुड़े हुए गाँवों को आपस में जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा घटही में 500मी0 सड़क निर्माण हेतु

97-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 282 बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा सेमरी घटही में दिनेश के घर से हल्लईत के घर तक दूरी लगभग 500 मीटर सड़क का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा सेमरी घटही एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। ग्राम सभा सेमरी घटही में दिनेश के घर से हल्लईत के घर तक (आबादी भाग) सड़क निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के वि0स0क्षे0 प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में घटिया सामग्री प्रयोग व मानक विपरीत कार्य कराये जाने की जांच विषयक

98-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज पूरे केशव राम प्रतापगढ़ के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग एवं मानक के विपरीत कार्य कराया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज के निर्माण में की जा रही अनियमितता की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना का विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता परीक्षण कराया जा चुका है, जो मानक के अनुरूप पाया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ की दीवानी न्यायालय की बाउण्ड्री व गेट के निर्माण में राजकीय निर्माण निगम द्वारा घटिया सामग्री प्रयोग की जांच कराने विषयक

99-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की दीवानी न्यायालय की बाउन्ड्री व गेट का निर्माण राजकीय निर्माण निगम द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग कर मानक के विपरीत कार्य कराया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य में की जा रही अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच (टी0ए0सी0) करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना का विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता परीक्षण कराया जा चुका है, जो मानक के अनुरूप पाया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ की वि0स0क्षे0 प्रतापगढ़ में नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ में सीवर निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच कराने व अधूरे कार्य को पूर्ण कराने विषयक

100-श्री राजकुमार पाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ को विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ में सीवर निर्माण जल निगम द्वारा कराया जा रहा कार्य अपूर्ण है ? क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

जी हां।

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (एस0एम0सी0जी0) के पत्र दिनांक 10-12-2020 द्वारा कुल रु0 32.56 करोड़ का आगणन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सीऊजी0), भारत सरकार को प्रेषित है। आगणन की स्वीकृति एवं धनावंटन के पश्चात अधूरे कार्य को पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत ककरहा शुकुलपुर मोड़ से पूरे भइया होते हुए देवघाट तक मार्ग के निर्माण में अनियमितता की जांच कराने विषयक

101-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ककरहा शुकुलपुर मोड़ से पूरे भइया होते हुए देव घाट तक निर्माणाधीन मार्ग में घटिया सामग्री का प्रयोग कर मानक के विपरीत सड़क बनायी जा रही है, जिसमें गड्ढों में पत्थर की मिट्टी के स्थान पर ईट की गिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण में की जा रही अनियमितता की उच्चस्तरीय (टी0ए0सी0) जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

मोहनगंज ईशीपुर शुकुलपुर ककरहा मार्ग राज्य सड़क निधि-3054 योजनान्तर्गत सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण हेतु शासनादेश सं0-63/2020/681 रासनि 23-1-20-51 रासनि/20 दिनांक 17-03-2020 द्वारा लम्बाई 11.30 किमी0 एवं लागत रु0 99.02 लाख की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी थी। स्वीकृति लम्बाई के सापेक्ष 6.00 किमी0 लम्बाई में पाट होल्स की जी-3 पत्थर से भराई कराकर पी0सी0 से नवीनीकरण का कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है। शेष कार्य प्रगति में है। कार्य को मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

आवश्यकता नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की बजाज शुगर मिल कुंदुरखी पर वि0स0क्षे0 पयागपुर, जनपद बहराइच के किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने विषयक

102-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की बजाज शुगर मिल कुदुरखी पर विधान सभा क्षेत्र पयागपुर जनपद बहराइच के कितने किसानों का कब से कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार समयबद्ध सीमा में उक्त बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

पेराई सत्र 2019-20 के अन्तर्गत दिनांक 24-02-2021 की सूचना के अनुसार चीनी मिल कुन्दुरखी पर विधान सभा क्षेत्र पयागपुर, जिला-बहराइच के 3,181 किसानों का कुल देय गन्ना मूल्य रु0 3,104.59 लाख के सापेक्ष दिनांक 06-03-2020 तक आपूर्तित गन्ने का 2,650 किसानों को रु0 2.864.58 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा 531 किसानों का

19 दिवस का मात्र रु0 240.01 लाख भुगतान हेतु अवशेष है। इसी प्रकार पेराई सत्र 2020-21 के अन्तर्गत गन्ना आपूर्ति करने वाले 2,577 किसानी का सूचना की तिथि से 14 दिन पूर्व अवधि तक का गन्ना मूल्य रु0 2,108.49 लाख बकाया है। राज्य सरकार अवशेष गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु सजग एवं कटिबद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर वि0स0क्षे0 के लखनगोण्डा के गन्ना किसानों के हितार्थ गन्ना क्रय केंद्र प्रतापुर तरहर को मैजापुर चीनी मिल गोण्डा को आवंटित किये जाने विषयक

103-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के लखनगोण्डा के प्रतापुर तरहर गन्ना क्रय केन्द्र से चीनी मिल बजाजाकुदुरखी गोण्डा की दूरी लगभग 70 कि0मी0 है जबकि चीनी मिल मैजापुर की दूरी लगभग 22 कि0मी0 है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना किसानों के हितार्थ गन्ना क्रय केन्द्र प्रतापुर तरहर को मैजापुर चीनी मिल गोण्डा को आवंटित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जिला बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के तरहर गन्ना क्रय केन्द्र से चीनी मिल कुन्दुरखी की सड़क मार्ग से दूरी 58.800 कि0मी0 तथा चीनी मिल मैजापुर की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 30.600 कि0मी0 है। प्रदेश में चीनी मिलों को गन्ना क्षेत्र का सुरक्षण/अभ्यर्पण उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-15 एवं तढ़विषयक नियमावली, 1954 के नियम-22 के अन्तर्गत विभिन्न सुसंगत कारकों यथा चीनी मिलों की क्षेत्र से दूरी, यातायात सुविधा, गत वर्षों में चीनी मिल को आपूर्ति किये गये गन्ने की मात्रा, गत वर्ष के सुरक्षण/अभ्यर्पण आदेश, चीनी मिली द्वारा की जाने वाली गन्ना पेराई, गत वर्षों में गन्ना मूल्य भुगतान व अंशदान, सहकारी गन्ना विकास समितियों के विचार, चीनी मिलों द्वारा क्षेत्र में गन्ना विकास हेतु किये गये प्रयास एवं गन्ना सूचना प्रणाली में किये गये कार्य आदि को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। उक्त आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त गन्ना कृषक हित में क्रय केन्द्र तरहर को पेराई सत्र 2020-21 में चीनी मिल कुन्दुरखी को आवंटित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच की सिम्भावली शुगर चीनी मिल मिलवरिया पर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान कराये जाने के संबंध में

104-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच की सिम्भावली शुगर चीनी मिल मिलवरिया पर गन्ना किसानों का कितना तथा कब तक का गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार बतायेगी की उक्त गन्ना किसानों के बकाया धन की अदायगी के

लिए क्या उपाय किये गये है ? क्या सरकार गन्ना किसानो के उक्त बकाया धन की अदायगी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

पैराई सत्र 2019-20 के अन्तर्गत दिनांक 24-02-2021 की सूचना के अनुसार शिम्भावली चीनी मिल, चिलवरिया, जिला-बहराइच पर कुल देय गन्ना मूल्य रु0 14,298.73 लाख के सापेक्ष दिनांक 05-02-2020 तक आपूर्तित गन्ने का रु0 9,821.33 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा 43 दिवस का मात्र रु0 4,477.40 लाख भुगतान हेतु अवशेष है। इसी प्रकार पेराई सत्र 2020-21 के अन्तर्गत सूचना की तिथि से 14 दिन पूर्व अवधि तक का गन्ना मूल्य रु0 9,025.67 लाख बकाया है। पेराई सत्र 2019-20 के अन्तर्गत चीनी मिल चिलवरिया को अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु दिनांक 04-02-2020, 19-05-2020, 13-07-2020, 05-10-2020 एवं 11-01-2021 को नोटिसें निर्गत कर निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में अपेक्षित सुधार परिलक्षित न होने के कारण सिम्भावली शुगर्स लि0 चिलवरिया, जिला-बहराइच के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया। पेराई सत्र 2020-21 के अन्तर्गत अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु दिनांक 11-01-2021 को चीनी मिल चिलवरिया को नोटिस निर्गत किया गया है। इसके साथ विभिन्न स्तर पर लगातार गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार अवशेष गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु सजग एवं कटिबद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा के ग्राम सभा कर्तिनिया में कर्तिनिया पिच रोड से झाला गांव तक रोड का निर्माण कराये जाने विषयक

105. श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा कर्तिनिया में कर्तिनिया पिच रोड से झाला गांव तक 3 किलोमीटर रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा कतर्निया एवं ग्राम सभा झाला पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़े हैं। दो जुड़े हुये गाँवों को आपस में जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी नीति से आच्छादित नहीं होता है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

106-श्रीमती सरोज सोनकर-

(दिनाँक 02-03-2021 को अतारांकित प्र0सं0-194 के अन्तर्गत उत्तरित)

जनपद बहराइच ग्राम सभा भरतापुर विकास खण्ड मिहींपुरवा के विस्थापन हेतु वन विभाग द्वारा चिन्हित भूमि पर विस्थापन की प्रक्रिया कराने विषयक

107-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ग्राम सभा-भरतापुर, विकास खण्ड मिहींपुरवा जो कि वन ग्राम सभा है, के विस्थापन हेतु वन विभाग द्वारा भूमि चिन्हित की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम सभा को विस्थापित सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एन0टी0सी0ए0) द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के क्रम में शासन के पत्र संख्या-460/81-4-2020-803/2019 दिनांक 02-06-2020 द्वारा प्रदेश के टाईगर रिजर्वो के कोर/क्रिटिकल टाईगर हैबिटेट में अवस्थित ग्रामों के स्वैच्छिक विस्थापन एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में मार्ग-निर्देशिका निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग, बहराइच के कोर/क्रिटिकल टाईगर हैबिटेट में अवस्थित राजस्व ग्राम-भरतापुर, ग्राम सभा अम्बा, विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्रामीणों के साथ हुए प्रारम्भिक विचार-विमर्श में वे स्वेच्छा से विस्थापन के लिए तैयार है। इस हेतु कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग, बहराइच के बफर जोन के अन्तर्गत ककरहा रेंज के नवबना वन ब्लाक के ग्राम रंगीलालपुरवा के पास जमीन चिन्हित करते हुए भरतापुर ग्राम के विस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर इकौना संपर्क मार्ग के निर्माण की जांच व दोषियों पर कार्रवाई के संबंध में

108-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के अन्तर्गत पयागपुर इकौना संपर्क मार्ग के निर्माण की लागत व सड़क की लम्बाई कितनी है तथा इसका निर्माण कार्य किस वर्ष में पूरा हुआ है ? क्या सरकार को जानकारी है कि सड़क के घटिया निर्माण के कारण अल्पावधि में ही सड़क जगह-जगह टूट गयी है ? यदि हां, तो सरकार खराब सड़क की जांच कराते हुए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर सड़क को मानक के अनुरूप ठीक करने के दिशा निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

पयागपुर इकौना मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के निर्माण की लागत रु0 4005.21 लाख तथा लम्बाई 18,400 कि0मी0 है, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2019 में पूरा हुआ है। स्थानीय कारणों से मार्ग के कुछ भाग में छोटे-छोटे पैच बन गये थे। ठेकेदार द्वारा उक्त मार्ग के मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। अतः किसी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के नगरीय क्षेत्र में अमृत योजना के अन्तर्गत मो0 घसियारीपुरा/रायपुर राजा अस्पताल चौराहा से स्टेडियम तक नाला निर्माण हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास को संबोधित पत्र पर कार्यवाही के संबंध में

109-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के नगरीय क्षेत्र में अमृत योजना के अन्तर्गत मोहल्ला घसियारीपुरा/रायपुर राजा अस्पताल चौराहा होते हुये स्टेडियम तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण के लिए रुपया पांच करोड़ का आगणन/वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति विषयक अधिशाषी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, बहराइच का पत्र दिनांक 28-09-2019 एवं 13-09-2019, जो प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-5 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच का पत्र दिनाक 28-09-2019 प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से जनपद बहराइच के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत मोहल्ला घसियारीपुरा/रायपुर राजा अस्पताल चौराहा होते हुये स्टेडियम पुलिया तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाले के निर्माण हेतु रु0 493.95 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया है। जनपद बहराइच के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत मोहल्ला घसियारीपुरा/रायपुर राजा अस्पताल चौराहा होते हुये स्टेडियम पुलिया तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाले के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में कतिपय स्लॉटर हाउस के ठेकेदारों के विरुद्ध अनियमितता के सम्बन्ध में

110-श्री नाहिद हसन-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दो पत्र दिनांकित 10-11-2020 जो कि अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण उत्तर प्रदेश को संबोधित हैं तथा अल मनसा स्लॉटर हाउस गंगोह व नगर निगम सहारनपुर के स्लाटर हाउस के ठेकेदार के विरुद्ध अनियमितताओं विषयक हैं, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

अपितु दो पत्र दिनांक 10-09-2020 प्राप्त हैं।

पशुवधशाला, जिला पंचायत गंगोह, जनपद-सहारनपुर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक-07-01-2019 के अनुपालन में बन्द है। पशुवधशाला, नगर निगम, सहारनपुर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त कर संचालित है। अद्यतन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहारनपुर द्वारा क्रमशः दिनांक 15-01-2021 एवं दिनांक 23-01-2021 में किया गया। निर्धारित सीमा से अधिक/निर्धारित आयु से कम प्रतिबन्धित/बीमार पशुवध संबंधी अनियमिततायें नहीं पायी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के कतिपय क्षेत्रों में जानवरों के अवैध चटट्े हटाने के सम्बन्ध में

111-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में जानवरों के अवैध चट्टे हटाने हेतु कानपुर नगर निगम सीमा के बाहर कैटिल कालोनियों के निर्माण के पश्चात भी कानपुर नगर निगम जोन-1 के वार्ड संख्या-89 चेक संख्या 76 में मकान नं0-76/228, 76/184, 76/241 के अतिरिक्त अन्य अवैध डेरी संचालित है तथा सब्जी मण्डी कुलीबाजार गुलियाना, थाना बादशाहीनाका, कानपुर नगर के चट्टे नहीं हटाये गये है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त चट्टे हटवाते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

नगर निगम, कानपुर द्वारा लगातार चट्टा हटाओ अभियान का संचालन कर डेयरी/चट्टों को हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। चट्टा हटाओं अभियान के क्रम में दिनांक 07-01-2021 को जोन-1 के कुलीबाजार, गुलियाना थाना बादशाहीनाका क्षेत्र में संचालित चट्टा/डेयरियों को हटाने की कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही के दौरान चट्टा संचालकों की 15 गाय जब्त कर पशु आश्रय स्थल में निरुद्ध कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के नगरीय क्षेत्र में हैण्डपम्प स्थापित करने हेतु पिछले 03 वर्षों में आवंटित बजट का विवरण

112-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर नगरीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 हैण्डपम्प स्थापित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा

2019-20 में कितने हैण्डपम्पों का कितना बजट आवंटित किया गया तथा उसके सापेक्ष दिनांक 14-05-2019 तक कितने नये हैण्डपम्प स्थापित एवं कितने हैण्डपम्प रिबोर किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में मा0 विधायक जी द्वारा चयनित स्थल पर 100-100 नग नये हैण्डपम्प स्थापित करने की स्वीकृत प्रदान की गयी। स्वीकृत एवं स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण निम्नवत है-

वर्ष	स्वीकृत हैण्डपम्प	स्थापित हैण्डपम्प	स्थापित सबमर्सिबल पम्प
2017-18	100	56	22
2018-19	100	100	-

44 नग हैण्डपम्प के स्थान पर शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुरूप 22 सबमर्सिबल पम्प स्थापित किये गये। दिनांक 14-05-2019 तक कोई हैण्डपम्प स्थापित नहीं किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में हैण्डपम्प रिबोर की स्वीकृत नहीं प्रदान की गयी। अतः कोई हैण्डपम्प रिबोर नहीं किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में हैण्डपम्प स्थापित किये जाने हेतु आवंटित धनराशि निम्नवत है-

(रु0 लाख में)

वर्ष	2017-18	2018-19
आवंटित धनराशि	63.30	63.30

वित्तीय वर्ष 2019-20 में हैण्डपम्प स्थापना हेतु कोई स्वीकृत नहीं प्रदान की गई।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के नगरीय क्षेत्र में पिछले 03 वित्तीय वर्षों में समरसेबल हेतु आवंटित बजट का विवरण

113-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहानपुर नगरीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 1 नया समरसेबल स्थापित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में कितने समरसेबल का कितना बजट आवंटित किया गया तथा उसके सापेक्ष दिनांक 14-05-2019 तक कितने नये समरसेबल स्थापित एवं कितने समरसेबल रि बोर किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जनपद सहारनपुर के नगरीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 1 नया सबमर्सिबल पम्प स्थापित किये जाने की कोई योजना संचलित नहीं है तथा सबमर्सिबल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अलग से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में मा0 विधायक जी द्वारा चयनित स्थलों पर स्वीकृत 100 हैण्डपम्प के सापेक्ष दी गई व्यवस्था के अनुसार 44 नग हैण्डपम्प के स्थान पर 22 सबमर्सिबल पम्प स्थापित किये जाने का प्रस्ताव मा0 विधायक जी द्वारा दिया गया था। प्रस्तावित 22 नग सबमर्सिबल पम्प की स्थापना दिनांक 14-05-2019 के उपरान्त की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत 100 हैण्डपम्प के सापेक्ष सबमर्सिबल पम्प स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव मा0 विधायक जी द्वारा नहीं दिया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0 रुधौली में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मार्गों के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत कराने के सम्बन्ध में

114-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद के बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में वर्ष 2016-17 व वर्ष 2019-20 में नवनिर्माण हेतु स्वीकृति मार्गों की प्रथम किश्त की धनराशि निर्गत कर मार्गों का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ करा दिया गया है परन्तु दूसरी किश्त के अभाव में निर्माण कार्य रुक गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वर्षों में स्वीकृत किये गये मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु दूसरी किश्त की धनराशि निर्गत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनावार द्वितीय किस्त की धनराशि रु0 2942.32 लाख निर्गत की गयी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0 रूधौली बस्ती के रामनगर में जनपद बस्ती व गोण्डा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर कुआनो नदी के ऊपर बाढूघाट व पगारेघाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में

115-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के रामनगर अन्तर्गत जनपद बस्ती व जनपद गोण्डा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के कुआनो नदी पर स्थित बाढूघाट व पगारेघाट पर पुल निर्माण न होने के कारण यात्रियों को

असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कुआनों नदी पर स्थित बाढूघाट व पगारेघाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र-गौरा के ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट के कुआनों नदी के बाढूघाट पर सेतु की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लागत रु0 946.77 का शासनादेश दिनांक 15-02-2021 को निर्गत है। जनपद बस्ती में विकास खण्ड-रामनगर, तहसील-भानपुर के कुआनों नदी पर पगारे-करमहिया मार्ग के पगारे घाट पर 79.88 मी0 लम्बाई के सेतु के निर्माण हेतु लागत रु0 1102.30 लाख आंकलित है। स्वीकृत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों के धनावंटन में भ्रष्टाचार की जांच कराकर कार्यवाही विषयक

116-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगरीय रोजगार गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले आवासों पर पात्र कर्मियों से ब्लॉकों के कर्मचारियों के द्वारा धन की मांग की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवा कर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के जनपद स्तर पर संचालन में ब्लॉक कर्मियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच वि0स0क्षे0 बलहा ग्राम सभा परसोहना बीएडीपी में 1 कि0मी0 मार्ग का डामरीकरण कराने विषयक

117-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा परसोहना बी0ए0डी0पी0 में प्राथमिक विद्यालय से गांव होते हुए चौराहा तक दूरी लगभग 1 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा परसोहना एकल लेपित मार्ग से जुड़ा है। प्रश्नगत ग्राम मटेही लौकाही सम्पर्क मार्ग से परसोहना लम्बाई 2.00 कि0मी0 पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा के ग्राम सभा चमारनपुरवा से भरिया मोड़ तक सड़क निर्माण कराने विषयक

118-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा चमारनपुरवा से भरिया मोड़ तक दूरी लगभग 1.500 किलोमीटर रोड का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा (चमारनपुरवा) हंसुलिया का मजरा है, जो एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है तथा भरिया मोड़ ग्राम सभा भरिया सम्पर्क मार्ग का भाग है। दोनों ग्राम सभा पूर्व से एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं। दो जुड़े हुये गाँवों को आपस में जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी नीति से आच्छादित नहीं होता है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के सभी ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने की कार्य योजना बनाने विषयक

119-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 250 से ऊपर आबादी वाले राजस्व ग्रामों/मजरों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बहराइच के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के 250 से ऊपर आबादी के सभी ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं तो, ऐसे ग्रामों/मजरों को पक्की सड़क से सरकार जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत 250 या उससे अधिक आबादी वाले 86 ग्रामों के सापेक्ष 02 ग्रामों/बसावटों को पक्के मार्ग से जोड़ा जा चुका है तथा 21

ग्रामों/बसावटों को जोड़े जाने की स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है। शेष 63 ग्रामों/बसावटों को पक्के मार्ग से जोड़ा जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद में 01 अप्रैल, 2017 से दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक कतिपय योजनाओं में प्राप्त धनराशि का विवरण

120–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 2017 से 10 नवम्बर 2020 तक नगर निगम फिरोजाबाद में 13वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग अवस्थापना निधि, प्रोत्साहन राशि, राजस्व वसूली, मुख्य मंत्री सड़क सुधार योजना, अमृत योजना, अन्त्योष्ति स्थल सुधार योजना, मुख्य मंत्री नाला सुधार, स्वच्छ भारत मिशन में प्राप्त धनराशि का विवरण सरकार उपलब्ध करायेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त तिथि तक प्राप्त धनराशि में से कितनी धनराशि अवशेष है ? क्या सरकार अवशेष धनराशि को जनहित में उपयोग कराते हुए विलम्ब के लिये सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की जबावदेही तय करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"–

जी हाँ।

01 अप्रैल 2017 से 10 नवम्बर 2020 तक नगर निगम फिरोजाबाद में 13वें वित्त आयोग, अवस्थापना विकास निधि, प्रोत्साहन राशि, राजस्व वसूली, मुख्य मंत्री सड़क सुधार योजना, अमृत योजना अन्त्येष्टि स्थल सुधार योजना, मुख्य मंत्री नाला सुधार, स्वच्छ भारत मिशन में निम्नलिखित धनराशि प्राप्त हुई है–

क्र0	मद का नाम	प्राप्त धनराशि (लाख रु0 में)
1	13वें वित्त आयोग	शून्य
2	अवस्थापना विकास निधि	434.74
3	प्रोत्साहन राशि	शून्य
4	राजस्व वसूली	3541.22
5	मुख्य मंत्री सड़क सुधार योजना	200.00
6	अमृत योजना	123.44
7	अन्त्येष्टि स्थल सुधार योजना	358.31

8	मुख्य मंत्री नाला सुधार	शून्य
9	स्वच्छ भारत मिशन	3448.55

जी हाँ।

01 अप्रैल 2017 से 10 नवम्बर 2020 तक नगर निगम फिरोजाबाद में 13वें वित्त आयोग, अवस्थापना विकास निधि, प्रोत्साहन राशि, राजस्व वसूली मुख्य मंत्री सड़क सुधार योजना, अमृत योजना, अन्त्येष्टि स्थल सुधार योजना, मुख्य मंत्री नाला सुधार, स्वच्छ भारत मिशन में निम्नलिखित धनराशि अवशेष है-

क्र0	मद का नाम	अवशेष धनराशि (लाख रु0 में)
1	13वें वित्त आयोग	शून्य
2	अवस्थापना विकास निधि	357.78
3	प्रोत्साहन राशि	शून्य
4	राजस्व वसूली	153.63
5	मुख्य मंत्री सड़क सुधार योजना	5.24
6	अमृत योजना	92.00
7	अन्त्येष्टि स्थल सुधार योजना	269.56
8	मुख्य मंत्री नाला सुधार	444.74
9	स्वच्छ भारत मिशन	2776.62

अवशेष धनराशि का उपयोग जनहित में किया जा रहा है। शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था अनुसार निर्धारित मापदण्डों व प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन करते हुए कार्यवाही की गयी है। धनराशि के जनहित में उपयोग किये जाने में प्रक्रिया के तहत समय लगा है, जान बूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों पर विलम्ब के लिए जबावदेही/कार्यवाही का औचित्य नहीं बनता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर निकायों को कतिपय निर्माण कार्यों एवं योजनाओं हेतु 14वें एवं 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत शेष धनराशि के विवरण के सम्बन्ध में

121-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों) में सड़क निर्माण, पेयजल योजनाओं, सफाई व्यवस्था हेतु आवश्यक उपकरण, शवदाह ग्रहों के विकास, प्रकाश व्यवस्था, सीवरेज तथा सॉलिड वेस्ट

मैंनेजमेंट आदि आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 14वें वित्त आयोग एवं 15वे वित्त आयोग के अन्तर्गत दिनांक 10/11/2020 तक कितनी धन राशि नगरीय निकायों के खातों में अवशेष है ? क्या सरकार मूलभूत आवश्यक अवस्थापना के विकास कार्यों को कराये जाने हेतु 14वें वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग की धनराशि को समय सीमा के अन्तर्गत उपयोग में लाये जाने हेतु कोई स्थायी एवं ठोस कार्य योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

प्रदेश में नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों) में सड़क निर्माण, पेयजल योजनाओं, सफाई व्यवस्था हेतु आवश्यक उपकरण, शवदाह गृहों के विकास, प्रकाश व्यवस्था, सीवरेज तथा सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेंट आदि आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 14वें वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत दिनांक 10/11/2020 तक नगरीय निकायों के खातों में अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत है-

नगर निगम-15,74,69,53,318.20

नगर पालिका परिषद-14,05,07,37,318.71

नगर पंचायत 6,18,16,83,601.66

कुल 35,97,93,74,238.57

14वें वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग हेतु उक्त की गाइडलाइन पूर्व से ही लागू है तथा 15वें वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग हेतु आपरेशनल गाइडलाइन लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0 रूधौली में अठदमा शुगर मिल को सरकार द्वारा उद्योग हेतु सब्सिडी दिये जाने की योजनान्तर्गत बकाया सब्सिडी धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में

122-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु सब्सिडी दिये जाने की योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती में स्थापित हिन्दुस्थान ग्रुप की शुगर मिल अठदमा रूधौली की लागत के अनुसार उद्योग की सब्सीडी लगभग रु0 92 करोड़ का भुगतान मिल को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सब्सिडी की बकाया धनराशि का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना के सम्बन्ध में दिनांक 24.08.2004 को "नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति-2004" घोषित की गयी थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.06.2007 को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था।

वर्तमान में प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु सब्सिडी दिये जाने की योजना लागू नहीं है। उक्त नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये। निर्णयों के अनुक्रम में वर्ष 2007 में समाप्त की जा चुकी चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति-2004 के अन्तर्गत अनुमन्य विभिन्न सुविधाओं/छूट आदि के क्लेम का भुगतान करने हेतु बजाज हिन्दुस्थान प्रा0लि0की ओर से चीनी मिल अठदमा, रुधौली बस्ती से सम्बन्धित प्रस्तुत दावों का सम्यक् परीक्षणोपरान्त तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कार्यालय आदेश संख्याः 964/46-2-2019-185/2006, दिनांक 26-04-2019 द्वारा उक्त चीनी मिल के पात्रता शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत पात्रता हेतु अर्ह नहीं पाये जाने के फलस्वरूप सुविधाओं/छूट आदि का दावा निरस्त करते हुये निस्तारण किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

चीनी मिल अठदमा, रूधौली-बस्ती द्वारा पात्रता की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण सन्दर्भित चीनी मिल पाचला हेतु अर्ह नहीं पायी गयी।

जनपद बस्ती के नगर पंचायत रुधौली में बारात घर का निर्माण कराने हेतु

123-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत नगर पंचायत रुधौली बाजार में बरात घर न होने के कारण निवासियों को शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों के सम्पन्न कराये जाने में समस्या होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बस्ती के नगर पंचायत रुधौली बाजार में बरात घर का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत नगर पंचायत रुधौली बाजार के सीमान्तर्गत 06 निजी बारात घर स्थित हैं। शादी समारोह आयोजित करने हेतु स्थल के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की असुविधा की शिकायत नगर पंचायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा कुड़वा में मार्ग के डामरीकरण हेतु

124-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा कुड़वा में कल्लू गौड़ी प्राइमरी स्कूल से नन्दलाल के घर तक दूरी लगभग 1000 मीटर मार्ग का डामरीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा कुड़वा एवं मजरा कल्लू गौढ़ी पूर्व से ही एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं तथा नन्दलाल का घर ग्राम कुड़वा व प्राइमरी स्कूल मजरा कल्लू गौढ़ी में स्थित है। अतः इन्हें आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की वर्तमान में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

125-श्रीमती सरोज सोनकर-

(03-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद आगरा के वि0ख0 बरौली अहीर की ग्राम पंचायत नगला कली के नाला तोड़े जाने व सड़क क्षतिग्रस्त करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

126-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर की ग्राम पंचायत नगला कली के अन्तर्गत नगला कली से रजरई मार्ग के किनारे बना नाला तोड़ने एवं सड़क क्षतिग्रस्त करने पर जिला अधिकारी आगरा के निर्देशन पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग आगरा द्वारा दिनांक 28/05/2015 के आदेश सं0 1214-8सी नाला तोड़े जाने व सड़क क्षतिग्रस्त करने वाले प्रधान पति के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही हुयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रधान पति श्री भूपाल दास द्वारा नाला तोड़े जाने व मार्ग क्षतिग्रस्त करने के कारण मार्ग के प्रभारी अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 30-05-2018 को प्रधान पति श्री भूपाल दास के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 03-10-2018 को प्रधान पति द्वारा मार्ग व नाली को पूर्व की स्थिति में करा दिया गया है। वर्तमान मे कार्यस्थल पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

127-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद प्रतापगढ़ में विद्युत दाह गृह की स्थापना कराने विषयक

128-श्री राजकुमार पाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में एक भी विद्युत शवदाह गृह स्थापित न होने से दाह संस्कार में परेशानी होती है ? क्या सरकार प्रतापगढ़ में

सई नदी के किनारे रेलवे पुल व बेल्हा देवी पुल के बीच बौद्ध विहार के दक्षिण सई नदी के तट पर विद्युत शव दाह गृह का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ में नगर पालिका परिषद, बेल्हा को अन्त्येष्टि स्थल निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2334/नौ-7-18-35(ज)/18, दिनांक 02-01-2019 द्वारा रु0 42.62 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये उक्त धनराशि संबंधित निकाय को एकमुश्त अवमुक्त की गयी है तथा शासनादेश संख्या-813/नौ-7-2019-42 (ज) / 19टी0सी0, दिनांक 08-11-2019 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत, अन्तू को अन्त्येष्टि स्थल निर्माण हेतु रु0 28.79 लाख एवं नगर पंचायत, कटरा मेदनीगंज को अन्त्येष्टि स्थल निर्माण हेतु रु0 28.79 लाख तथा नगर पंचायत, पट्टी को अन्त्येष्टि स्थल निर्माण हेतु रु0 28.79 लाख की धनराशि की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये उक्त धनराशि संबंधित निकायों को एकमुश्त अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में कंधरापुर तिराहे से सरायशंकर बनसटी दोमुहा पुल से पारा हमीदपुर मोड़ तक मार्ग का चौड़ीकरण कराने विषयक

129-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में कन्धरा पुर तिराहे से सरायशंकर बनसती दोमुहा पुल से होते हुए पारा हमीदपुर मोड़ तक लम्बाई 12 किलोमीटर सड़क सकरी एवं जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 10.55 किमी0 है जिसका प्रथम भाग कान्धरपुर से चिगुंडा संपर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है। जिसकी लम्बाई 4.50 किमी0 तथा चौड़ाई 3.00 मीटर है, जो वर्ष 2020-21 में विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत नवीनीकरण में स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत 2.50 किमी0 लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण है एवं अवशेष 2.00 किमी0 लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

दूसरा भाग चैनेज-4.500 से 5.450 किमी0 का स्वामित्व सिंचाई विभाग का है, जिस पर सिंचाई विभाग द्वारा सेतु का निर्माण किया गया है एवं पहुँच मार्ग का कार्य शेष है। तीसरा भाग चैनेज-5.450 से 10.550 तक कुल लम्बाई 5.100 किमी0 तथा चौड़ाई 3.00 मीटर लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। वर्तमान में मार्ग सुगम यातायात हेतु उपयुक्त है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसका पी0सी0यू0-779 है, जो मार्गों के चौड़ीकरण हेतु निर्धारित पी0सी0यू0 के मानक से कम है। लोक निर्माण विभाग में ग्रामीण श्रेणी के मार्ग का चौड़ीकरण वर्तमान में किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ में गोड़े के मोछहा नाला से कान्धरपुर रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराने विषयक

130-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में गोड़े के मोछहा नाला होते हुए नरहरपुर कल्याणी मन्दिर में महुअरिया से शिवपुर कलाँ होते हुए कान्धरपुर रोड तक मार्ग जर्जर एवं सँकरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

इस मार्ग में चार मार्ग सम्मिलित हैं, जिनकी कुल लम्बाई 12.00 किमी0 है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

प्रथम भाग अयोध्या, प्रयागराज मार्ग के कि0मी0-91 के दायीं और गोड़े ग्राम से निकल कर मोछहा नाला होते, कल्याणी तक जाता है, जिसकी लम्बाई-7.600 कि0मी0 है, जिसमें 5.300 कि0मी0 का भाग नरहरपुर चौराहे तक पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत 5.50 मीटर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत है। शेष 2.30 कि0मी0 लोक निर्माण विभाग के अधीन है। वर्तमान में मार्ग सुगम यातायात हेतु उपयुक्त है। द्वितीय भाग चैनेज-7.600 से 7.900 किमी0 तक 0.300 कि0मी0 में खड़न्जा स्तर का ग्राम पंचायत के अधीन है। तृतीय भाग में चैनेज-7.900 से 10.500 कि0मी0 तक 2.600 कि0मी0 चौड़ाई 3.00 मी0 लो0नि0वि0 के अधीन है, जिसकी स्थिति संतोषजनक है। चतुर्थ भाग चैनेज-10.500 से 12.00 तक लम्बाई 1.500 कि0मी0 एवं चौड़ाई 5.50 मीटर पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत अनुरक्षणाधीन है, जो अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। वर्तमान में मार्ग सुगम यातायात हेतु उपयुक्त है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसका पी0सी0यू0-788 है, जो मार्गों के चौड़ीकरण हेतु निर्धारित पी0सी0यू0 के मानक से कम है। लो0नि0वि0 में ग्रामीण श्रेणी के मार्ग का चौड़ीकरण वर्तमान में किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ में एन0एच0 फैजाबाद से प्रयागराज की सड़क के चौड़ीकरण व निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री के प्रयोग की जाँच विषयक

131-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ एन0एच0 फैजाबाद से प्रयागराज की सड़क का चौड़ीकरण व कोडडौर बाजार व प्रतापगढ़ शहर में नाला निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग कर अनियमितता की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मार्ग निर्माण में प्रयोग हो रही घटिया सामग्री व अनियमितता की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0 रुधौली की सहकारी समितियों के जर्जर भवन की मरम्मत कराने विषयक

132-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली की अधिकांश सहकारी समितियों के भवन जर्जर होने के कारण निष्क्रिय होने से किसानों को खाद, बीज के लिये बाजार का सहारा लेना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर भवनों का मरम्मत, निर्माण करवा कर समितियों को सक्रिय करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी)-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में कुल 27 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं। इनमें से कोई भी सहकारी समिति भवन जर्जर होने के कारण निष्क्रिय नहीं है। 22 सहकारी समितियों द्वारा व्यवसाय किया. जा रहा है तथा शेष 05 सहकारी समितियों को वित्त की अनुपलब्धता के कारण उसी विकास खण्ड के निकटवर्ती सहकारी समिति से सम्बद्ध कर किसानों को खाद, बीज की सुविधा प्रदान की जा रही है।

जनपद बस्ती में गोदाम मरम्मत कराने की कोई योजना संचालित नहीं है। उक्त 27 सहकारी समितियों में से कोई भी समिति जर्जर होने के कारण निष्क्रिय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा के ग्राम सभा कुड़वा में मातवर के खेत से सतीश वर्मा के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक

133-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा कुड़वा में मातवर के खेत से सतीश वर्मा के घर तक दूरी लगभग 800 मीटर सड़क का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा कुड़वा पूर्व से एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। ग्राम सभा कुड़वा में मातवर के खेत से सतीश वर्मा के घर तक (ग्राम सभा कुड़वा का आन्तरिक मार्ग) सड़क का निर्माण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा ग्राम सभा भगड़िया में अतुल राय के घर से विनोद दास के घर तक डामरीकरण कार्य कराने विषयक

134-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा भगड़िया में अतुल राय के घर से विनोद दास के घर तक दूरी लगभग 200 मीटर डामरीकरण कार्य क्या सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा भगड़िया एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। ग्राम सभा भगडिया में अतुल राय के घर से विनोद दास के घर तक (ग्राम सभा भगडिया का आन्तरिक मार्ग) का डामरीकरण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं होता है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के वि0स0क्ष0 बलहा ग्राम सभा भगड़िया में सुनील सेट्टी के घर से लक्समन दास के घर तक डामरीकरण कार्य कराने विषयक

135-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा भगड़िया में सुनील सेट्टी के घर से लक्समन दास के घर तक दूरी लगभग 200 मीटर डामरीकरण कार्य क्या सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा भगड़िया एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। ग्राम सभा भगड़िया में सुनील सेट्टी के घर से लक्समन दास के घर तक (ग्राम सभा भगड़िया का आन्तरिक मार्ग) का डामरीकरण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम फिरोजाबाद के अन्त्येष्टि स्थल विकास/सुधार हेतु वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में भेजी कुल धनराशि व इसके द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों का सुधार/विकास कराये जाने के विवरण

136-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम फिरोजाबाद की अन्त्येष्टि स्थल विकास/सुधार हेतु वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कुल कितनी धनराशि भेजी गयी है एवं इस धनराशि के द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों का सुधार/विकास कराया गया है तथा 10 नवम्बर, 2020 तक उक्त कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? उक्त मद में कार्यों में की गयी अनियमितता की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

नगर निगम फिरोजाबाद को अन्त्येष्टि स्थल विकास/सुधार हेतु वर्ष 2018-19 में मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत छारबाग रोड पर शमशान घाट के जीर्णोद्धार एवं अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु प्रदत्त धनराशि रु0 42.17 लाख से प्रश्नगत स्थल का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें से धनराशि रु0 30.25 लाख का भुगतान किया जा चुका है। 13 अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2015-16 में प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रु0 50.86 लाख एवं वर्ष

2019-20 में द्वितीय व अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रु0 316.14 लाख अर्थात् कुल धनराशि रु0 367.00 लाख प्रदान की गयी। उक्त 13 अन्त्येष्टि स्थलों में से 9 अन्त्येष्टि स्थलों के सुधार/विकास कार्य पूर्ण हो गये हैं। शेष 04 अन्त्येष्टि स्थलों में से 02 अन्त्येष्टि स्थल पर भूमि विवाद व 01 अन्त्येष्टि स्थल पर स्कूल एवं मंदिर बने होने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा 01 अन्त्येष्टि स्थल का कार्य मा0 मुख्य मंत्री घोषणा वर्ष 2018-19 में प्राप्त धनराशि से पूर्ण करा दिया गया है। उक्त स्वीकृत धनराशि रु0 367.00 लाख के सापेक्ष दिनांक 10-11-2020 तक रु0 140.64 लाख का व्यय किया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्य योजना

137-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मानक के खतरनाक स्तर तक बढ़ने की रोकथाम के लिए सरकार कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हाँ।

वायु प्रदूषण के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित उ0प्र0 के 15 नॉन अटेन्मेन्ट शहरों यथा, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा, फिरोजाबाद, अनपरा, गजरौला, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं बरेली में वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना क्रियान्वित है, जिनमें वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतो से जनित प्रदूषण नियंत्रण के लिए 20 विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं हेतु 59 कार्यवाही के बिन्दु निर्धारित हैं। उक्त कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति तथा राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में गठित "एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक शोध परिषद्, शाहजहांपुर कार्यालय में सहा0 निदेशक, गन्ना शोध परिषद् में आहरण-वितरण अधिकारी के स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात होने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही विषयक

138-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16/07/2019 सहायक निदेशक गन्ना शोध परिषद् शाहजहाँपुर में आहरण, वितरण

अधिकारी के रूप में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध 05 वर्ष से तैनाती एवं प्रभारी निदेशक, गन्ना शोध परिषद् शाहजहाँपुर के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

मा0 सदस्य का संदर्भित पत्र दिनांक 16-07-2019 प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु प्रकरण से सम्बन्धित पत्र दिनांक 26-07-2019 प्राप्त है। मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न में पदधारक का सम्बन्ध उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर से न होकर गन्ना किसान संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहाँपुर से है। मा0 सदस्य के पत्र पर निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। जिसमें यह अवगत कराया गया कि नई गन्ना तकनीकी को कृषकों के हित में सुग्राहय व प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालन हेतु अनुभवी एवं क्षेत्र सुपरिचित अधिकारियों की आवश्यकता होती है। कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से चलाये जाने हेतु तकनीकी अधिकारियों में केन्द्र पर 02 प्रशिक्षक, 02 विषय विशेषज्ञों के साथ ही सहायक निदेशक का 01 पद सृजित है। प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहाँपुर में अन्य तकनीकी अधिकारियों की तैनाती न होने के कारण सहायक निदेशक पद पर कार्यरत अधिकारी गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र, शाजहाँपुर में 05 वर्षों से आहरण, वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उक्त से मा0 सदस्य को पत्र दिनांक 15-11-2019 के माध्यम से पूर्व में अवगत कराया जा चुका है।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा कुड़वा में कतिपय मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक

139-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 282 बलहा के अन्तर्ग ग्राम सभा कुड़वा में विनोद के घर से रानीपुर काली रोड तक दूरी लगभग 2 कि0मी0 तक श्री नन्दकिशोर के खेत से विजेन्द्र के खेत तक दूरी 2 कि0मी0 तक तथा ग्राम सभा कुड़वा में जूनियर हाई स्कूल से कुडवा नाला तक दूरी 01 कि0मी0 निर्माण कर डामरीकरण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं

प्रश्न में वर्णित मार्गों की स्थिति निम्नवत् है

ग्राम सभा कुड़वा एवं रानीपुर दोनों पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः विनोद के घर को रानीपुर काली रोड से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। नन्दकिशोर के खेत से विजेन्द्र के खेत तक खेतों को आपस में जोड़ना लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। जूनियर हाई स्कूल कुड़वा सम्पर्क मार्ग पर स्थित है तथा कुड़वा नाला तक का भाग कुड़वा ग्राम का आन्तरिक मार्ग

है, जिसके सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त मार्ग पर डामरीकरण हेतु मानक के अनुसार चौड़ाई उपलब्ध न होने तथा परियोजना जनोपयोगी न होने के कारण निर्माण कार्य अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के वि0स0क्षे0 छपरौली के कतिपय गांवों में बैंक की शाखा खुलवाने विषयक

140-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के मविकला, असारा, गुलियान जिमाना व बुढपुर गावों में कोई बैंक या बैंक की शाखा नहीं होने के कारण क्षेत्र के ग्रामीणों को पैसों के लेन-देन व खाता खुलवाने के लिए गाँव से बाहर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीणों की सुविधा हेतु उक्त गाँवो में बैंक की शाखा खुलवाए जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

केन्द्र सरकार से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है। गुलियान जिमाना में प्रथम यू0पी0 ग्रामीण बैंक की शाखा कार्यरत है तथा ग्राम-मविकला, ग्राम-असारा व ग्राम-बुढपुर में शाखा खोले जाने हेतु प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

141-श्री मनीष असीजा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बस्ती के लो0नि0वि0 द्वारा स्थापित निरीक्षण भवन सोमहा का उच्चीकरण कराये जाने विषयक

142-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 19/01/2020 का पत्र जो जनपद बस्ती के लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थापित निरीक्षण भवन सोनहा का उच्चीकरण कराकर दो अतिरिक्त सट, अतिरिक्त कक्ष एवं किचन का निर्माण कराये जाने विषयक है, प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद बस्ती में रुधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सोनहा निरीक्षण भवन में स्थित 02 कक्ष एवं किचन के विशेष मरम्मत कार्य हेतु लागत रु0 09.90 लाख की स्वीकृति निर्गत है। उक्त के अतिरिक्त 02 अतिरिक्त कक्ष व किचन के नवनिर्माण कार्य का आगणन लागत रु0 66.83 लाख का गठित है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराने विषयक

143-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वंचित लाभार्थियों को सरकार आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक आवासीय सुविधाओं से रहित देश के पात्र लाभार्थियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में ग्राम सभा सलारपुर में हरी के घर से मेन रोड एस0एस0बी0 कैम्प तक सड़क निर्माण विषयक

144-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा सलारपुर में हरी के घर से मेन रोड एस0एस0बी0 कैम्प तक लम्बाई लगभग 3 किलोमीटर काली रोड का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा सलारपुर एवं एस0एस0बी0 कैम्प एकल लेपित मार्ग से जुड़ा है। हरी का घर सलारपुर गांव के आबादी में स्थित है। डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में ग्राम सभा ककरहा में भगौती लोधी के खेत से मेन रोड तक सड़क निर्माण विषयक

145-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा ककरहा में भगौती लोधी के खेत से मेन रोड तक दूरी लगभग

2 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा ककरहा एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। ग्राम सभा ककरहा में भगौती लोधी के खेत से मेन रोड तक (ग्राम सभा ककरहा का आन्तरिक मार्ग) का डामरीकरण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

146-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

[दिनांक 25-02-2021 को अतारांकित प्र0सं0-113 के अन्तर्गत उत्तरित]

147-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[दिनांक 02-03-2021 को अतारांकित प्र0सं0-195 के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद बस्ती में नगर पालिका द्वारा गरीब वेन्डर्स हेतु खाली स्थान पर दुकान के निर्माण के सम्बन्ध में

148-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में गरीब वेन्डर्स के लिए नगर पालिका बस्ती द्वारा खाली जगहों पर दुकानें बनाए जाने की योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बस्ती के बस्ती शहर में दुकानों के निर्माण के लिए चयनित स्थानों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद्, बस्ती सीमान्तर्गत शहरी जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन†-2017 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, बस्ती पथ विक्रेताओं हेतु कुल 15 वेन्डिंग जोन निर्धारित हैं, जो रोड पटरी पर ही हैं जिसके कारण स्थायी दुकानों का निर्माण सम्भव नहीं हैं।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण अवधि पूर्ण होने के बाद कार्मिकों की पैतृक विभाग में वापसी सुनिश्चित किए जाने विषयक

149-पं0 राधाकृष्ण शर्मा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में कितने लेखा परीक्षा कार्मिकों ने प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी पैतृक विभाग में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ? क्या सरकार उक्त कार्मिकों को पैतृक विभाग में वापसी सुनिश्चित करायेगी यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

02 कार्मिक, जिनके सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है:-

1. शासन के पत्र दिनांक 01-03-2021 के क्रम में निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के आदेश दिनांक 01-03-2021 द्वारा श्री जय प्रकाश, वरिष्ठ लेखा परीक्षक के स्थान पर श्री मनोज कुमार वर्मा, वरिष्ठ लेखा परीक्षक को उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात करते हुए श्री जय प्रकाश को कार्यमुक्त करने हेतु सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र प्रेषित किया गया है।
2. श्री रामनगीना, वरिष्ठ लेखा परीक्षक को पैतृक विभाग हेतु तत्काल कार्यमुक्त करने के लिए निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती को निर्देशित किया गया है। निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पत्र दिनांक 01-03-2021 द्वारा निदेशक, राज्य परियोजना सर्व शिक्षा अभियान को कार्यमुक्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

जी हाँ।

कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में दिनांक 15/02/2018 को विकास कार्यों के प्रस्तावो पर दिनांक 10/11/2020 तक पर भौतिक प्रगति की जानकारी

150-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क मद दिनांक 15/02/2018 को विकास कार्यों हेतु स्वीकृत किये गये प्रस्तावों की दिनांक 10/11/2020 तक की भौतिक प्रगति क्या है ? क्या सरकार अत्यधिक विलम्बित होने वाले उक्त कार्यो को पूरा कराने एवं संबंधित जिम्मेदार लोगों का उत्तरदायित्व तय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क मद से दिनांक 15/02/2018 को 09 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें 07 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा शेष 02 कार्यों की स्थिति निम्नवत् हैः-

क्र0	कार्य का नाम	अभियुक्ति
1	पालीवाल हॉल के पीछे गेस्ट हाउस सौन्दर्यीकरण का कार्य।	इस कार्य की निविदा दिनांक 16-01-2021 को आमंत्रित की गयी जसमें दो निविदायें प्राप्त हुई थीं पर्याप्त निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित की गयी है।
2	नगर निगम फिरोजाबाद में जोनल ऑफिस का निर्माण कार्य।	भूमि का चयन कर लिया गया है निविदा आमंत्रित की गयी है।

शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार निर्धारित मापदण्डों व प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन करते हुए कार्यवाही की गयी है। धनराशि के जनहित में उपयोग किये जाने में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं किया गया है। आमंत्रित निविदा वाले कार्य को शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर, में कानपुर,-टूण्डला,देहली रेल भाग पर चन्द्रवार गेट में रेलवे अण्डरपास/ पुलिया नं0 84 को चौड़ा कराते हुये वाक्स कलवर्ट बनाये जाने के संबंध में

151-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर में कानपुर-टूण्डला-देहली रेल भाग पर चन्द्रवार गेट में रेलवे अण्डरपास/पुलिया नं0 84 अत्यन्त संकरी होने के कारण इसके दोनों तरफ आवागमन के चलते भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को उक्त पुलिया आर्च कलवर्ट को चौड़ा कराते हुये वाक्स कलवर्ट बनाये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र संख्या, 1402/ओ0एस0डी0: प्रो04/2019 पुलिया नं0 89, दिनांक 05/02/2020 (उ0प्र0 रेलवे के आगणन सहित) प्रस्ताव को संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के द्वारा ई0एन0सी0 लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 मुख्य अभियंता सेतु लोक निर्माण विभाग एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ को प्रेषित पत्र संख्या, 108 (2) 23-11-2020 दिनांक 14/02/2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत रेलवे अण्डर पास/पुलिया नं0 84 को चौड़ा किये जाने हेतु जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 05-02-2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुक्रम में विभागीय संस्तुति/प्रस्ताव प्राप्त करके प्रश्नगत रेलवे अण्डर पास के निर्माण हेतु लागत रु0 1189.45

लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-268/2020/488ई/ 23-11-2020-1/2 (121)2020, दिनांक 07-09-2020 द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

प्रदेश में बीते 3 वर्षों के दौरान वनाग्नि से हुए नुकसान और उसके आगणन के तरीके की जानकारी सम्बन्धी

152-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान प्रदेश में वनाग्नि की कितनी घटनाएं घटित हुई हैं ? क्या सरकार ने इन घटनाओं में कितने नुकसान का आँकलन कराया है ? क्या सरकार वनाग्नि में नुकसान के आगणन हेतु प्रचलित तरीके का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

<table>
<tr><td colspan="3">विगत 3 वर्षों के दौरान प्रदेश में वनाग्नि की 1544 घटनाएं घटित हुई हैं।</td></tr>
<tr><td colspan="3">विगत 3 वर्षों के दौरान प्रदेश में वनाग्नि की घटित घटनाओं में रु0 6,11,686 की क्षति का आंकलन किया गया है।</td></tr>
<tr><td colspan="3">जी हां। वनाग्नि में नुकसान के आगणन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी कार्यालय आदेश में क्षति के निर्धारण हेतु मापदण्ड निम्नवत् है</td></tr>
<tr><td>क्र0</td><td>वन संसाधन</td><td>क्षति का मापदण्ड</td></tr>
<tr><td>1</td><td>वृक्षारोपण</td><td>प्रति पौध क्षति का आंकलन वृक्षारोपण क्षेत्र में प्रति पौध रोपण पर होने वाले वास्तविक व्यय (सुरक्षा व्यवस्था पर हुआ व्यय शामिल न करते हुए) के अनुसार।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्राकृतिक वन</td><td>साल वन रु0-1500 प्रति हेक्टेयर
विविध रु0-750 प्रति हेक्टेयर</td></tr>
<tr><td colspan="3">प्रश्न नहीं उठता।</td></tr>
</table>

जिला सम्भल स्थित वीनस शुगर मिल चंदौसी से गन्ना किसानों का वर्ष 2002-03, 2003-04 का बकाया अन्तर गन्ना मूल्य दिलाने संबंधी

153-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वीनस शुगर मिल चंदौसी जिला-सम्भल पर गन्ना किसानों का गन्ना सत्र 2002-03 व 2003-04 की कितनी अन्तर गन्ना मूल्य की धनराशि का बकाया तथा सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बिलारी, जिला मुरादाबाद द्वारा जुलाई, 2006 में किसानों से जमा करा ली गई है ? क्या सरकार उक्त अवधि की तौल पर्चियों का किसी निश्चित समयावधि में ब्याज सहित भुगतान कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

वीनस शुगर लि0 मझावली, जिला-सम्भल पर पेराई सत्र 2002-03 में रु0303.91 लाख अन्तर गन्ना मूल्य बकाया है। पेराई सत्र 2003-04 का कोई अन्तर गन्ना मूल्य बकाया नहीं है। सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 बिलारी, जिला मुरादाबाद में गन्ना कृषकों द्वारा पेराई सत्र 2002-03 की 19,255 पर्चियां, वजन 5,06,528.28 कु0 जमा की गई, जिनमें से 8,606 पर्चियां, वजन 2,46,005.33 कु0 का भुगतान हो चुका है तथा 10,649 पर्चियां, वजन 2,60,522.95 कु0 भुगतान हेतु अवशेष है। पेराई सत्र 2002-03 के बकाया अन्तर गन्ना मूल्य की ब्याज सहित वसूली के सम्बन्ध में निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र के क्रम में तहसीलदार, चन्दौसी, जिला-सम्भल के स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

154-श्री नफीस अहमद-

[03-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती, विकास खण्ड रामनगर की सड़क जो जनपद बस्ती, बलरामपुर, गोण्डा को जोड़ती है, का चौडीकरण/उच्चीकरण कराने विषयक

155-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड रामनगर की जनपद बस्ती को बलरामुपर, गोण्डा को जोड़ने वाली सड़क उकड़ा, भैंसहिया शंकरपुर मार्ग 14 किलोमीटर जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण/उच्चीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग (कुल लम्बाई 13.80 कि0मी0) में तीन मार्ग सम्मिलित हैं, जिनकी स्थिति निम्नवत् है:-

1-उकड़ा भैंसहिया शंकरपुर मार्ग-

इस मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 10.00 कि0मी0) के आबादी भाग में जल भराव के कारण उत्पन्न पैच को ठीक करा दिया गया है एवं शेष भाग में मार्ग की दशा संतोषजनक है। वर्तमान में उक्त मार्ग कुल लम्बाई में सुगम यातायात हेतु उपयुक्त है।

2-शंकरपुर चौराहे से शंकरपुर ग्राम तक-

इस मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.000 कि0मी0) के 300 मी0 आबादी भाग में विशेष मरम्मत कार्य हेतु आंकलित लागत रु0 23.79 लाख है, जिसकी स्वीकृति

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष 700 मी0 लम्बाई का भाग सुगम यातायात हेतु उपयुक्त है।

3-शंकरपुर से पिरैला मार्ग-

इस मार्ग (ग्रामीण मार्ग, कुल लम्बाई 2.80 कि0मी0) पर जल भराव के कारण उत्पन्न पैच को ठीक करा दिया गया। है। वर्तमान में मार्ग सुगम यातायात हेतु उपयुक्त है।

प्रश्नगत मार्ग का यातायात घनत्व (पी0सी0यू0) 5224 है, जो 02 लेन चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानक 6000 से कम है। अतः उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना विभागीय मानकों से आच्छादित नहीं है।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा ग्राम सभा चोखा में चुरवा संपर्क मार्ग से 1 कि0मी0 सड़क का डामरीकरण कार्य कराने हेतु

156-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा चुरवा में चोखा संपर्क मार्ग से बल्ला खमारिया तक लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत ग्राम सभा चोरवा पूर्व से एकल लेपित मार्ग से जुड़ा है। बल्ला खमारिया (महन्त पुरवा) को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। कार्य का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा ग्राम सभा घूमना भारु में मेन रोड से शब्बीर के घर तक सड़क का डामरीकरण कराने विषयक

157-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा घूमना भारू में मेन रोड से शब्बीर के घर तक लम्बाई लगभग 3 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

श्री शब्बीर का घर ग्राम सभा घूमना भारू में स्थित है, जो एकल पक्के मार्ग से जुड़ा है। किसी अन्य संरेखण से श्री शब्बीर के घर को जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा ग्राम सभा चितलहवा से निधिपुरवा तक सड़क का डामरीकरण कराने विषयक

158-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा चितलहवा से निधिपुरवा तक लम्बाई लगभग 800 मीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा चितलहवा एवं निधिपुरवा दोनों पूर्व से एकल लेपित मार्ग से संतृप्त हैं। दो जुड़े हुये गाँवों को आपस में जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी नीति से आच्छादित नहीं होता है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

159-श्री नफीस अहमद-

[03 मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 बिलरियागंज ग्राम सभा अकबरपुर तेन्दुआ से देवरिया जफ्ती मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

160-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में ग्राम सभा अकबरपुर तेन्दुआ से देवरिया जफ्ती माफी तक का पिच मार्ग लम्बाई 02 किलोमीटर का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पिच मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग अकबरपुर तेन्दुआ तथा ग्राम देवरिया जफ्ती माफी को जोड़ने से सम्बन्धित है। वर्तमान में अकबरपुर तेन्दुआ व देवरिया जफ्ती माफी ग्राम सभा पृथक-पृथक एकल पक्के सम्पर्क मार्गों से जुड़े हैं। अतः उक्त मार्ग एक ग्राम सभा को दूसरे ग्राम सभा से

जोड़ने से सम्बन्धित है तथा वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के महराजगंज-कप्तानगंज मार्ग से ग्राम सभा यूसुफपुर कुम्भवट तक मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

161-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के महराजगंज कप्तानगंज मार्ग से ग्राम सभा यूसुफपुर कुम्भवट तक की दूरी 03 किलोमीटर मार्ग जर्जर होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पिच मार्ग का मरम्मतीकरण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत नहर पटरी मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन व अधिक वर्षा के कारण लेपित सतह क्षतिग्रस्त हो गई थी। वर्तमान में मार्ग का मरम्मत करा दिया गया है तथा आवागमन हेतु सुगम हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के नगीना वि0स0क्षे0 अन्तर्गत ग्राम नरैनी-मुस्तफापुर मार्ग पर बने पुल एवं एप्रोच मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

162-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में त्वरित विकास निधि से शुरू कराये गये जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में ग्राम नरैनी से ग्राम मुस्तफापुर उर्फ भूरापुर मार्ग पर बने अधूरे पुल एवं एप्रोच मार्ग को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत प्रकरण का पुनरीक्षित आगणन लागत रुपये 484.18 लाख शासन में प्राप्त है, स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति के उपरान्त कार्य शीघ्रता से पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गौरा पिपरा में मनोरथ की चक्की से बल्लीपुरवा ग्राम तक मार्ग का निर्माण विषयक

163-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गौरा पिपरा में मनोरथ की चक्की से बल्लीपुरवा गाँव तक लम्बाई 3 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं

ग्राम सभा गौरा पिपरा में मनोरथ की चक्की तक पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा प्रश्नगत बल्लीपुरवा राजस्व ग्राम गौरा पिपरा का मजरा है, जिसकी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी 87 है, जोकि लोक निर्माण विभाग की वर्तमान सम्पर्क मार्ग निर्माण नीति से आच्छादित नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा भगड़िया में नौकापुरवा गौतम नगर रजनवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण विषयक

164-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा-भगड़िया में भगड़िया स्कूल से नौकापुरवा गौतम नगर होते हुए रजनवा सम्पर्क मार्ग तक दूरी लगभग 1250 मीटर रोड का निर्माण कार्य क्या सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा भगड़िया एवं रजनवा दोनों बसावटें पूर्व से एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं। प्रश्नगत संरेखण पर कोई भी बसावट 250 से अधिक आबादी की स्थिति नहीं होने के कारण लोक निर्माण विभाग की वर्तमान सम्पर्क मार्ग निर्माण नीति से आच्छादित नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे बलहा के ग्राम सभा भगड़िया में भगड़िया स्कूल से भगड़िया मगहर तक 300 मीटर सड़क का डामरीकरण कार्य कराने विषयक

165-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा भगड़िया में भगड़िया स्कूल से भगड़िया मगहर तक दूरी लगभग 300 मीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा भगड़िया एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। भगड़िया स्कूल से भगड़िया मगहर तक (ग्राम सभा भगड़िया का आन्तरिक मार्ग) का डामरीकरण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-आजमगढ़ के वि0ख0 महराजगंज में ग्राम सभा महेशपुर से कौवापुर मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

166-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में ग्राम सभा महेशपुर से कौवापुर मार्ग लम्बाई लगभग 01 किलोमीटर र्जजर हो जाने से स्कूली बच्चों व आम जनमानस को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मतीकरण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

विषयगत मार्ग महराजगंज-सहदेवगंज मार्ग से निकलकर कौवापुर को जोड़ता है। मार्ग का मरम्मत कार्य करा दिया गया है। मार्ग पर यातायात सुचारु रूप से चल रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के सदर हर्रा की चुंगी बमबम की कुटिया से बैठौली मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

167-श्री नफीस अहमद-

क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सदर हर्रा की चुंगी बमबम की कुटिया से बैठौली बाईपास तक का मार्ग जर्जर होने के कारण लोगों को अवागमन में

परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मत/नवीनीकरण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद आजमगढ़ सदर हर्रा की चुंगी (बमबम बाबा की कुटिया) से बैठौली बाईपास तक मार्ग की लम्बाई 1.25 कि0मी0 है, जिस पर मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

168-श्री नफीस अहमद-

[03-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 बिलरियागंज में खालीसपुर बाजार से अशरफपुर पी0डब्ल्यू0डी0 रोड तक मार्ग का मरम्मतीकरण कराने विषयक

169-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बीलरियागंज में खालीसपुर बाजार से अशरफपुर पी0डब्ल्यू0डी0 रोड तक दूरी लगभग 03 किलोमीटर जर्जर होने से आम जनमानस को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मतीकरण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में खालिसपुर बाजार से अशरफपुर मोड़ (आजमगढ़ दोहरीघाट मार्ग) तक मार्ग की लम्बाई 3.210 मी0 है। उक्त मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग के चैनेज 0.00 से 0.550 किमी0 (550 मी0) में यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के तटबन्ध निर्माण हेतु मिट्टी ढुलाई के कारण मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग की मरम्मत यूपीडा द्वारा की जानी है जिसकी लक्षित तिथि 15-03-2021 है। मार्ग के चैनेज 0.550 किमी0 से 1.500 किमी0 तक (950मी0) की सतह यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है। मार्ग के चैनेज 1.500 से 3.210 किमी0 (1710मी0) क्षतिग्रस्त है जिसके विशेष मरम्मत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

170-श्री नफीस अहमद-

[02-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों/मण्डी परिषद् व समस्त विश्वविद्यालयों की संवर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण कराने विषयक

171-पं0 राधाकृष्ण शर्मा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों/ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों/मण्डी परिषद् एवं समस्त विश्वविद्यालयों की संवर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से न कराए जाने के वित्त विभाग के निर्णय के उपरान्त अतिरेक (सरप्लस) जनशक्ति को विभाग के अन्य कार्यालयों में तैनात किये जाने पर सरकार विचारधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रक्रिया को समय सीमा निर्धारित कर पूर्ण करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों/मण्डी परिषद् में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समायोजन निदेशालय के आदेश दिनांक 28-06-2018 एवं शासन के आदेश दिनांक 20-09-2018 व दिनांक 04-09-2018 द्वारा किया जा चुका है। विश्वविद्यालयों में कार्यरत कार्मिको को तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत निदेशालय के आदेश दिनांक 11-12-2019 के द्वारा मण्डल में चिन्हित जनशक्ति के सापेक्ष समायोजित करते हुए मण्डलीय जनपद स्थित लेखों की सम्परीक्षा सम्पादित कराने हेतु सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशकों को निर्देशित किया गया है। कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप स्थानान्तरण सत्र शून्य घोषित होने के कारण उक्त कर्मियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। आगामी सत्र में स्थानान्तरण नीति के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के वि0स0क्षे0 कटरा में ग्राम नवादा दरोबस्त वि0ख0 खुदागंज अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल को उच्चीकृत कर सी0एन0डी0एस0 संस्था द्वारा घटिया निर्माण कराने की जांच विषयक

172-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर, विधान सभा क्षेत्र कटरा में ग्राम नवादा दरोबस्त विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल को उच्चीकृत कर निर्माण सी0एन0डी0एस0 संस्था द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें घटिया सामग्री एवं मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है एवं पीला ईंट का प्रयोग तथा सरिया, सीमेन्ट की मात्रा कम होने से दीवालें व टाइलें अभी से चटकने लगी हैं ? क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य की जाँच किसी उच्च स्तरीय अधिकारी द्वारा गठित कमेटी से कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो, क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जनपद शाहजहाँपुर, विधान सभा क्षेत्र कटरा में ग्राम नवादा दरोबस्त, विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल के उच्चीकरण का समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कर दिनांक 17-06-2020 को क्लाइन्ट विभाग को हस्तनिरित कर दिया गया है। वर्तमान में भवन उपयोग में है। निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जाँच नियमानुसार करायी गयी। उक्त कार्य का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा समय-समय पर किया गया, जिसमें कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

173-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

[दिनांक 02-03-2021 को अतारांकित प्र0सं0-189 के अन्तर्गत अन्तरित]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में ग्राम सभा गिरगिट्टी में हाईवे से दत्तीपुरवा होते हुए मटहीपुरवा तक सड़क निर्माण विषयक

174-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गिरगिट्टी में हाईवे से दत्तीपुरवा होते हुए मटहीपुरवा में रामगुलाम के घर तक लम्बाई लगभग 2 किलोमीटर खड़न्जा का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत मटहीपुरवा (मटिहापुरवा) एकल लेपित मार्ग से संतृप्त है। दत्तीपुरवा की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 237 है, जो सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मानक आबादी 250 से कम है। अतः लोक निर्माण की वर्तमान सम्पर्क मार्ग निर्माण नीति से आच्छादित नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा कुड़वा में कतर्निया रोड से कुड़वा होते हुए सड़क निर्माण विषयक

175-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा कुड़वा में कतर्निया रोड से कुड़वा गांव होते हुए एयरटेल टावर तक दूरी

लगभग 2 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत ग्राम सभा कुड़वा एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। कुड़वा में कतर्निया रोड से कुड़वा गाँव होते हुए एयरटेल टावर तक मार्ग पर विशेष मरम्मत के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। मरम्मत कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा बिशुनापुर में जगदेव थारू के घर से स्कूल होते हुए रमपुरवा चौराहा तक सड़क निर्माण विषयक

176-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा बिशुनापुर में जगदेव थारू के घर से स्कूल होते हुए रमपुरवा चौराहा तक दूरी लगभग 2 किलोमीटर काली रोड का निर्माण कार्य क्या सरकार कराएगी ? हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा बिशुनापुर एवं रमपुरवा चौराहा तक लेपित मार्ग से जुड़े हैं। जगदेवथारू का घर एवं स्कूल लेपित मार्ग पर स्थित है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

177-श्रीमती सरोज सोनकर-

[03-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

178-श्रीमती सरोज सोनकर-

[दिनांक 02-03-2021 को अतारांकित प्र0सं0-193 के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद झांसी में ग्वालियर मार्ग पर ग्वालियर पुलिस चौकी के पास रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने विषयक

179-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में ग्वालियर पुलिस चौकी के पास रेलवे क्रासिंग पर प्रतिदिन जाम लगने से स्थानीय लोगों को आवागमन में कठिनाई होती

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर ओवर ब्रिज बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद झांसी में उत्तर मध्य रेलवे के झांसी-कानपुर रेल खण्ड कि0मी0-1131/1-2 पर रेल सम्पार संख्या-117 पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की आंकलित लागत रु0 12051.80 लाख है। राज्य सरकार द्वारा प्रश्नगत सेतु को रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित कराने तथा निर्माण लागत में सहभागिता की सहमति महाप्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त सेतु का निर्माण रेलवे से सहभागिता की सहमति प्राप्त होने एवं प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद झांसी के सीपरी बाजार में चित्रा चौराहे पर एवं मऊरानीपुर में झांसी रोड पर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज पूरा कराने के सम्बन्ध में

180-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के सीपरी बाजार में चित्रा चौराहे पर एवं मऊरानीपुर में झांसी रोड पर रेलवे क्रासिंग पर निर्माणधीन ओवर ब्रिज का कार्य सरकार निश्चित समयावधि में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद झाँसी में सीपरी बाजार में चित्रा चौराहे पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण में सेतु निगम का कार्य लगभग पूर्ण है एवं रेलवे ट्रैक के ऊपर का भाग रेलवे द्वारा निर्मित किया जा रहा है। रेलवे का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सम्पूर्ण लम्बाई में वियरिंग कोट का कार्य पूर्ण कराकर सेतु को यातायात हेतु खोला जाना लक्षित है। मऊरानीपुर में झाँसी रोड पर रेल उपरिगामी सेतु का कार्य माह नवम्बर, 2019 में पूर्ण करते हुए यातायात हेतु खोला जा चुका है।

जनपद बिजनौर के वि0स0क्षे0 नगीना, कस्बा किरतपुर (ईदगाह) से ग्राम बुडगरी, वि0ख0 किरतपुर में मालन नदी पर पुल बनाये जाने विषयक

181-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर (ईदगाह) से ग्राम बुडगरी विकास खण्ड किरतपुर में मालन नदी के ऊपर पुल सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत सेतु स्थल से 5.0 किमी0 अपस्ट्रीम एवं 03 किमी0 डाउनस्ट्रीम में पूर्व से सेतु निर्मित होने के फलस्वरूप उक्त स्थल पर सेतु का निर्माण कराया जाना लोक निर्माण विभाग की प्रचलित व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत ग्राम परसिया से सेहुडी मार्ग पर रेरुआ नदी पर पुल निर्माण विषयक

182-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ग्राम परसिया से सेहुडी मार्ग पर रेरुआ नदी पर पुल निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी पर पुल निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रस्तावित स्थल पर 3x5 मीटर स्पान लम्बाई 15 मीटर लघु सेतु की आवश्यकता होगी, जिसकी अनुमानित लागत पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच एवं सुरक्षात्मक कार्य सहित रु0 150.00 लाख आयेगी। जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में ब्राहमण महासभा से सी0एम0एस0 विद्यालय तक जर्जर मार्ग का मरम्मत कराने के संबंध में

183-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की नगर पालिका बस्ती शहर के ब्राह्मण महासभा से सी0एम0एस0 विद्यालय होते हुए पचपेड़िया जाने वाला मार्ग गड्ढ़ायुक्त होने से क्षेत्र के लोगों को आवगमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मत/निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जनपद बस्ती की नगर पालिका परिषद् शहर के ब्राहमण महासभा से पालिका सीमा तक सड़क ठीक है। नगर पालिका परिषद् बस्ती सीमा के आगे पचपेड़िया रोड तक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत आता है, जो सदर ब्लाक बस्ती के अन्तर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम पंचायत हरखापुर, मजरा पृथ्वीपुरवा से माता जी के मंदिर तक सड़क निर्माण विषयका

184-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा में ग्राम पंचायत हरखापुर, मजरा पृथ्वीपुरवा ट्रांसफार्मर चौराहा से माता जी के मंदिर तक दूरी लगभग 2 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम पंचायत हरखापुर एवं मजरा पृथ्वीपुरवा एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त हैं। पृथ्वीपुरवा ट्रांसफार्मर चौराहा से माता जी के मंदिर तक (ग्राम सभा पृथ्वीपुरवा का आन्तरिक मार्ग) का डामरीकरण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम पंचायत गोपिया में साजिद बेग के घर से लोधपुरवा तक मार्ग निर्माण विषयक

185-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम पंचायत गोपिया में साजिद बेग के घर से लोधपुरवा मजरा होते हुए ठाणा मजरे तक दूरी लगभग 3 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम पंचायत गोपिया एवं लोधनपुरवा मजरा एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं। ठाणा मजरा वर्ष 2011 की जनगणना सूची में अंकित नहीं है। ऐसे मजरे को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कोई योजना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

186-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[02-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फिरोजाबाद स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में महिलाओं को बढ़ती उम्र में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु वायल (इंजेक्शन) उपलब्ध कराये जाने पर विचार करने विषयक

187-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय (पूर्व में जिला अस्पताल, फिरोजाबाद) में महिलाओं को बढ़ती उम्र में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु 9 वर्ष से 14 वर्ष की किशोरियों को 5 महीने की अवधि के मध्य 2 टीके लगाये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है अक्टूबर, 2019 में इंजेक्शन खत्म हो जाने के कारण जिन किशोरियों को जून-जुलाई, 2019 में पहला इंजेक्शन लगा था उनको दूसरी डोज का टीका नहीं लग पा रहा है, और इसके कारण पहली डोज भी अनुपयोगी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिये उक्त वायल (इंजेक्शन) उपलब्ध कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

अप्रैल, 2017 से अक्टूबर, 2019 तक निरन्तर 09 से 14 वर्ष की किशोरियों को 05 महीने की अवधि के मध्य 02 टीके लगाये जा रहे थे। तद्नन्तर माह अक्टूबर, 2019 में इंजेक्शन समाप्त हो गये थे। एन0एच0एम0 स्तर से उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

[12:21] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम, 301 की सूचनायें ले रहा हूँ। आज दिनाँक 03/03/2021 को नियम-301 में कुल 39 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें 24 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई हैं। पहली सूचना-श्री उपेन्द्र नाथ पासवान की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर अन्तर्गत कतिपय गाँवों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना-श्री संजय सिंह गंगवार की उ0प्र0 में भारत सरकार की छात्रवृत्ति वितरण योजना जातिगत न होकर आर्थिक रखे जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना-श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर विद्युत व्यवस्था में सुधार कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, चौथी सूचना-श्री शैलेन्द्र यादव "ललई" की ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ई0आर0पी0 के माध्यम से टेक महिन्द्रा कम्पनी को दिये गये प्रोजेक्ट की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के संबंध में है, पाँचवीं सूचना-श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा अन्तर्गत विकास खण्ड शिवपुर में ग्राम अनरवा से ग्राम रखौना होते हुए ग्राम गोड़ियाना तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना-श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भियांव एवं जलालपुर में पड़ने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना-श्री

धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य "पप्पू भइया" की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र शेखूपर अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के तालाबों में बाउन्ड्रीवाल तथा सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है आठवीं सूचना-श्री रफीक अन्सारी की जनपद मेरठ अन्तर्गत हापुड़ रोड पर स्थित राजकीय कन्या इन्टर कालेज में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना-श्री लकी यादव की उ0प्र0 सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालय अधिशासी अभियंता हैड वर्क्स आगरा नहर ओऔंखला के अन्तर्गत स्थित कैनाल कालोनी परिसर में बनायी जा रही वाल्मी कि फील्ड हास्टल के निर्माण में हो रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना-श्रीमती हेमलता दिवाकर जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण अन्तर्गत मौजा बांईपुर में पशुपालन विभाग की भूमि पर वेटंनरी कॉलेज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना-डा0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारवीं सूचना-श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में कच्चे गड्ढायुक्त मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना-प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत नवादा मोड़ से तिलहर मोड़ तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदवीं सूचना-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चंदौली के अन्तर्गत न्यायालय निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया की जनपद बदायूँ के विकास खण्ड समरेर में तिगुलापुर से पंचमइया महाराज तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना-श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत सेंग घाट पर ड्रम (पीपा) वाला पुल बनवाये जाने के समबन्ध में है, सत्रहवीं सूचना-श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत कोप व कुरेम गांव सहित दर्जनों गांवों में नये सिरे से चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाहरवीं सूचना-डा0 डी0 सी0 वर्मा की जनपद बरेली में स्थित राजकीय महिला पालिटेक्निक में टूटे बिजली के तार एवं खम्भों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना-श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार अन्तर्गत बाबूगंज पटेरवा, लक्ष्मीगंज होते हुए बीकरगढ़ मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना-श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के रूदौली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्सीवीं सूचना-श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा तैनात ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा अमर्यादित, भ्रष्ट आचरण एवं अपने अधीनस्थी दवा व्यवसाइयों के साथ, लिपिक के साथ गालीगलौज एवं गोली से मारने की धमकी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना-डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद आजमगढ़ के सदर तहसील अन्तर्गत प्रहलाद नगर कॉलोनी में जल निकासी हेतु नाली व सीवेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेईसवीं सूचना-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत गाजीपुर, चौचकपुर मुख्य मार्ग से जैदपुरा गाँव तक के मार्ग को शहीद के नाम पर कराये जाने के सम्बन्ध में तथा चौबीसवीं

सूचना-श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा में समाज कल्याण विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार कर की गयीं :-

श्रीमती बन्दना सिंह, श्री प्रेम सागर पटेल, श्री सतीश चन्द्र शर्मा, श्री अबरार अहमद, श्री धर्मपाल सिंह, श्री शशांक त्रिवेदी, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, "कैलाश डेरी वाले" श्रीमती निर्मला संखवार, श्री राम प्रताप सिंह, श्री प्रेम नरायरण पाण्डेय, श्री दयाराम चौधरी, मो0 फईम इरफान, श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल, श्री मुकेश चन्द्र वर्मा तथा श्री ओम प्रकाश राजभर।

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर अतर्गत कतिपय गावों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 को अन्तर्गत सूचना

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान-

[महोदय, जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत कई गाँव ऐसे हैं जिनमें पेयजल की अत्यधिक समस्या है। हमारे अन्नदाता किसान को पेयजल हेतु अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, अतः जनहित में निम्नलिखित गाँवों में पानी की टंकी का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है :-

1. ग्राम-नौरंगा, ब्लाक-भीतरगाँव, कानपुर,
2. ग्राम-श्रीनगर, ब्लाक-घाटमपुर, कानपुर,
3. ग्राम-कोटरा मकरंदपुर, ब्लाक-घाटमपुर, कानपुर,
4. ग्राम-हथेडी, ब्लाक-पतारा, कानपुर,
5. ग्राम-गिरसी, ब्लाक-पतारा, कानपुर,
6. ग्राम-तरगाँव, ब्लाक-पतारा, कानपुर,
7. ग्राम-उमरी, ब्लाक-भीतरगाँव, कानपुर,
8. ग्राम-बीबीपुर ब्लाक-घाटमपुर, कानपुर,
9. ग्राम-बारादौलतपुर, ब्लाक-पतारा, कानपुर,
10. ग्राम-सजेती, ब्लाक घाटमपुर, कानपुर।

अतः आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर अन्तर्गत उपरोक्त गाँवों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार के ध्यानाकर्षण की माँग करता हूँ।

उ0प्र0 में भारत सरकार की छात्रवृत्ति वितरण योजना जातिगत न होकर आर्थिक रखे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 को अन्तर्गत सूचना

श्री संजय सिंह गंगवार-

[महोदय, उ0प्र0 में रु0 1 लाख वार्षिक आदनी वाले अल्पसंख्यक परिवारों के कक्षा 1 से 8 तक छात्र/छात्राओं को न्यूनतम 1000/-रुपेय प्रति छात्र केंद्रीय छात्रवृत्ति मिल

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रही है, जबकि बहुसंख्यक समुदाय के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़ा व सामान्य एवं अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को कोई भी छात्रवृति नहीं मिल रही है। इससे इन वर्गों के निर्धन परिवारों के छात्र/छात्राओं के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है व साथ ही शिक्षा के खर्चों को वहन करने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जिस कारण इनका आर्थिक स्तर ऊँचा नहीं हो पा रहा है। इस छात्रवृत्ति का वितरण का आधार विशेष समुदाय न होकर सभी वर्गों के आर्थिक दृष्टि से निर्धन विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए इस कारण सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र भी सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी इस योजना से लाभान्वित हो सकें एवं आर्थिक अभाव से इन्हें शिक्षा से वंचित होना न पड़े। साथ ही इस सुविधा को ग्रहण कर शिक्षित हो करके प्रदेश एवं राष्ट्रहित में अपना योगदान दे सकें। अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए छात्रवृत्ति वितरण की भारत सरकार की इस योजना का आधार जातिगत न होकर आर्थिक रखे जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर विद्युत व्यवस्था में सुधार कराने जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटा शंकर त्रिपाठी-

[महोदय आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि खड्डा विधान सभा क्षेत्र में जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के उपरान्त हमारी सरकार ने निरन्तर विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु सकारात्मक पहल की है जिसका लाभ हमारे क्षेत्रवासियों को भी प्राप्त हो रहा है 18 घंटे की निर्वाध विद्युत आपूर्ति के साथ ही साथ जर्जर तार, पोल व ट्रांसफार्मर बदले गए परन्तु कुछ क्षेत्र में बुनियादी विकास के साथ ही विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसके संदर्भ में लगातार पत्राचार के माध्यम से निवेदन। आग्रह किए गए हैं, परन्तु इसके अतिरिक्त कोई जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं जो इस प्रकार है कृपया बताने का कष्ट करें कि-

- खड्डा विधान सभा क्षेत्र के रेता उस पार में पिछले 6 महीने से विद्युत आपूर्ति बन्द है उसे कब तक प्रारम्भ करा दिया जाएगा।
- खड्डा विधान सभा क्षेत्र में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सबस्टेशन की स्थापना के लिए क्या किसी योजना पर कार्य किया जा रहा है ?
- खड्डा विधान सभा क्षेत्र में जर्जर तार और पोल कब तक बदल दिया जायेगा।
- ग्रामीणों के बकाए गलत बिल का सुधार का कार्य कब तक पूर्ण कराया जाएगा क्या इस दिशा में कोई विशेष अभियान चलाये जाने की योजना है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

- खड्डा विधान सभा क्षेत्र स्थित विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा।
- नवसृजित नगर पंचायत छितौनी में विद्युतीकरण कार्य हेतु कोई विशेष योजना प्रस्तावित है। माननीय मंत्री जी के माध्यम से उपरोक्त के संदर्भ में जानकारी प्रदान करने की कृपा करें।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ई0आर0पी0 के माध्यम से टेक महिन्द्रा कम्पनी को दिये गये प्रोजेक्ट की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव "ललई"-

[†महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ई0आर0पी0 के माध्यम से सारे प्रोजेक्ट टेक महिन्द्रा कम्पनी को 70 करोड़ का ठेका दिया गया जिसको बाद में बढ़ाकर रु0 110 करोड़ कर दिया गया इसमें कम्पनी को लगभग 70 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है लेकिन अभी तक कम्पनी द्वारा ऑनलाइन की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चलाई जा सकी है। प्राधिकरण की माली स्थिति खराब होने के कारण ऐसी क्या परिस्थितियां थीं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को देने के लिए इतना उत्साहित था इसी तरह पूरे प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण है लेकिन सभी प्राधिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट को करने से इन्कार कर दिया गया। लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा उसको दे दिया गया और प्राधिकरण पर कर्जा लगभग 7000 करोड़ का हो चुका है। यहां यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा कतिपय अधिकारियों के इशारे पर कम्पनी को लगभग 70 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा भी आपत्ति उठाई गई थी लेकिन उस मामले को दबा दिया गया। इस प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच होना अति आवश्यक है जिससे कि वह भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुँचा जा सके।

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि इस कम्पनी को जो ठेका दिया गया है उस कार्य को करने में अधिकतम 5 से 10 करोड़ रुपये का खर्च आता लेकिन कतिपय अधिकारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए प्रदेश एवं प्राधिकरण का 100 करोड़ रुपये बर्बाद कर दिया है। उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जाच होनी चाहिए।

अतः मैं मा0 सदन के माध्यम से इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में हुए प्राधिकरण एवं सरकारी धन के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

† नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा अन्तर्गत विकास खण्ड शिवपुर में ग्राम अरनवा से ग्राम रखौना होते हुए ग्राम गोड़ियाना तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र, 283, नानपारा जनपद बहराइच के अन्तर्गत विकास खण्ड शिवपुर में ग्राम अरनवा से ग्राम रखौना होते हुए ग्राम गोड़ियाना तक लम्बाई 4 किमी0 कच्ची सड़क है। जिसमें लोगों का अत्यधिक आवागमन रहता है। जनहित में उक्त कच्चे सम्पर्क मार्ग को पक्का कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

अतः नियम, 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम अरनवा से ग्राम रखौना होते हुए ग्राम गोड़ियाना तक लम्बाई 4 किमी0 कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव एवं जलालपुर में पड़ने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष राय-

[महोदय, में आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव और जलालपुर में पड़ने वाली सड़क जो कर्बला कासिमपुर से रफीगंज-मुण्डेहरा होते हुए बड़ी नहर से सटी हुई आजमगढ़ सीमा तक जाती है। यह सड़क पूरी टूटकर नष्ट हो गयी है और इस सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थति में क्षेत्र के लोगों द्वारा सड़क बनाये जाने की मांग की जा रही है। यह गम्भीर प्रकरण है। अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की माग करता हूँ।]

जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र शेखपुर अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के तलाबों में बाउन्ड्रीवाल तथा सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्या "पप्पू भइया"-

[महोदय, अवगत कराना है कि शेखूपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भिडौली स्थित तालाब में सौन्दर्यीकरण, बाउन्ड्रीवाल एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य एवं ग्राम पंचायत कचौरा गुठायल नगला स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण, बाउन्ड्रीवाल एवं सी0सी0 रोड का जनहित में कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर उक्त तालाबों का सौन्दर्यीकरण एवं बाउन्ड्रीवाल कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ]

जनपद मेरठ के अतर्गत हापुड़ रोड स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रफीक अंसारी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र 48, मेरठ के हापुड़ रोड पर एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज है। जिसका संचालन पिछले 6 वर्षों से हो रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस विद्यालय में प्रदेश में सबसे ज्यादा छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। परन्तु बहुत ही दुःख का विषय है कि फर्नीचर के अभाव मे छात्रायें जमीन पर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मैं पिछले 4 वर्षों से मा0 मुख्य मंत्री जी से लेकर शिक्षा मंत्री तक व इस सदन के माध्यम से भी अपनी गुहार लगा चुका हूँ। बड़े दुःख के साथ उन्हें एक बार आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ। अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त विद्यालय के लिए तत्काल फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

उ0प्र0 सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालय अधिशासी हैंड वर्क्स आगत नहर ओखला के अन्तर्गत स्थित कैनाल कॉलोनी परिसर में बनायी जा रही वाल्मी फील्ड हास्टल के निर्माण में हो रही अमियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लकी यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि उ0प्र0 सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालय अधिशासी अभियन्ता हैंड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला नई दिल्ली के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की स्थित कैनाल कालोनी परिसर में बनाये जा रहे वाल्मी फील्ड हास्टल एवं आवासों की ड्राइंग व डिजाइन स्वीकृत के अनुरूप निर्माण न कराकर सैकड़ों वर्ष पुराने वाल्मी फील्ड हास्टल एवं आवासों की खपरैल उखाड़कर मात्र ईंटों के 11 सार उक्त दीवारों पर रखकर सीमेंट का ऊपर से नया प्लास्टर करके वाल्मी फील्ड हास्टल एवं आवासों के लिए नये निर्माण का स्टीमेट बनाकर बजट स्वीकृत कराया गया है। आवासों के निर्माण में स्वीकृत धनराशि का मात्र 25 प्रतिशत व्यय करके 75 प्रतिशत धनराशि में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है तथा खण्डीय कार्यालय हैंड वर्क्स खण्ड ओखला कार्यालय परिसर में स्थित अतिथि गृह में साज-सज्जा एवं नये निर्माण में स्वीकृत मानकों के अनुरूप कार्य न करके वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 के माह मार्च तक करोड़ों रुपये की धनराशि का व्यय फर्जी रिकार्डों में

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दर्शाया गया है। खण्डीय कार्यालय के अधीन उपखण्ड प्रथम के सहायक अभियंता द्वारा वर्ष 2019 के माह नवम्बर से वर्ष 2020 के माह मार्च तक दो लाख रुपये से कम धनराशि के लगभग 156 अनुबन्धों के कार्य एम0बी0 पर फर्जी दर्शाकर फर्म/ठेकेदारों को 10 प्रतिशत का कमीशन देकर समस्त शेष धनराशि ठेकेदारों से प्राप्त कर ली, सरकारी धन की बड़े पैमाने पर बन्दर, बांट की गयी है जिस कारण वाल्मी फील्ड हास्टल व आवासों के नये निर्माण एवं फर्जी अनुबन्ध के कार्यों में कई करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है जिसकी किसान नेता श्री नरेन्द्र सिंह राठी द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गयी लेकिन 3 माह में सूचना न देकर बार-बार नित नये-नये बहाने बनाकर टहलाया जा रहा है। अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए भ्रष्टाचार की जांच कराकर तत्काल प्रभावी कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण अन्तर्गत मौजा बाँईपुर में पशुपालन विभाग की भूमि पर वेटनरी कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा-

[महोदय, सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के मौजा बाँईपुर में पशुपालन विभाग की लगभग 22 बीघा भूमि उपलब्ध है जिस पर वर्तमान में उसके आंशिक हिस्से पर नन्दी गौशाला बनी हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण होने के कारण क्षेत्र में पशुपालन एवं दुग्ध डेयरी उद्योग का कार्य अधिक है। पशुओं में गम्भीर बीमारियाँ बनी रहती हैं। जिसके कारण आये दिन ग्रामीण जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि उपरोक्त भूमि पर वेटनरी कालेज की स्थापना हो जाये तो पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त स्थान पर वेटनरी कालेज बनाये जाने की माँग करती हूँ।]

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-302 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र देवरिया में बाईपास न होने के कारण देवरिया जनपद वासियों को आये दिन जाम की समस्या से जूझना पड़ता है जिस कारण यातायात बाधित होता है। प्रतिदिन देवरिया वासियों को दो से तीन घंटे जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में कच्चे गडढ़ायुक्त मार्गों को डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहाँपुर के 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत निम्नलिखित कच्चे गडढायुक्त मार्गों का डामरीकरण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है:-

1-विकास खण्ड सिंधौली में तेरा डामर रोड से तेरा गांव के अन्दर तक कच्ची सड़क का डामरीकरण लम्बाई लगभग 1 कि0मी0

2-विकास खण्ड सिंधौली में रक्शा से महासिर तक कच्ची सड़क का डामरीकरण लम्बाई लगभग 2 कि0मी0

3-विकास खण्ड सिंधौली में पिपरिया प्रहलाद से कंजा तक कच्ची सड़क का डामरीकरण लम्बाई लगभग 2 कि0मी0

4-विकास खण्ड सिंधौली में पिपरिया दास नहर पुलिया से जलालाबाद नहर पुलिया तक कच्ची सड़क का डामरीकरण लम्बाई लगभग 1 कि0मी0

5-विकास खण्ड सिंघौली में कोटावारी से नहर हेड तक कच्ची सड़क का डामरीकरण लम्बाई लगभग 1 कि0मी0

6-विकास खण्ड सिंधौली में पाता से रखिया बुजुर्ग तक पक्की सड़क का डामरीकरण लम्बाई लगभग 1 कि0मी0

7-विकास खण्ड सिंधौली में पिपरिया प्रहलाद से सुतनेश तक पक्की सड़क का डामरीकरण लम्बाई लगभग 1 कि0मी0

8-विकास खण्ड निगोही में नेशनल हाईवे पतराजपुर तिराहे से ईसापुर होते हुए भटपुरा भदेग तक सड़क चौड़ीकरण उच्चीकृत कर डामरीकरण लम्बाई लगभग 7 कि0मी0

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत नवादा मोड़ से तिलह मोड़ तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नवादा मोड़ से तिलहर मार्ग का चौड़ीकरण स्वीकृत है, परन्तु अभी तक किन्हीं कारणों

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत न्यायालय निर्माण हेतु किसानों की जमीन अधिग्रहीत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 को अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि चन्दौली जनपद प्रदेश का ही नहीं देश में लगभग 23 वर्ष पूर्व 1997 में इस जनपद का सृजन हुआ, और आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इस जनपद के साथ सृजित हुए सभी जनपद लगभग 15 वर्ष पूर्व ही अपने विकास को प्राप्त कर चुके हैं। परन्तु चंदौली की दशा बहुत ही खराब है। जिसकी आफिसें दूसरे जिलों से चंदौली का बोर्ड लगाकर संचालित होती हैं। जैसे सेल टैक्स, इनकम टैक्स व रोडवेज डिपो वाराणसी से संचालित है। प्रभु श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिनकी बातें सत्ताधारी दल बहुत जोर-शोर से करता है। जनपद चंदौली 23 साल से बनवास झेल रहा है। इसको कब इन्साफ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण जिला न्यायालय आज तक नहीं बना। 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में जिला जज बैठने को मजबूर हैं। जगह का अभाव व गन्दगी की वजह से कई अधिवक्ता व अधिकारी इसी कमरे में चक्कर खाकर गिर चुके हैं। अन्य अदालतों की बात करें तो कुछ तहसील में कुछ लगभग डेढ़ कि0मी0 दूर डिग्री कालेज की चाहरदीवारी में शेड लगाकर संचालित होती हैं। वहीं जूमीनाइल कोर्ट तीन किमी0 जगदीशसराय गांव में एक प्राइवेट रूम में चलायी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कोर्ट पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंदौली के परिसर में बहुत ही बदहाल व संसाधनों की कमी के बीच संचालित हो रही हैं। कई जगह कोर्ट होने की वजह से जल्दबाजी में कई अधिवक्ता व न्यायालय कर्मचारी सड़क व रेल हादसे में जान गवां चुके हैं। न्यायालय के लिए 2014 में दाखिल जनहित याचिका में तत्कालीन मा0 मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री डीवाई चन्द्रचूण जी के भी आदेश जिले के आला अधिकारी पिछले 6 से साल खुलेआम अवमानना कर रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा हाई कोर्ट में दिये गये शपथ पत्र में जिस 52 बीघा जमीन का वादा किया गया था। मात्र 11 बीघा देकर बाकी जमीन देने में आनाकानी की जा रही है। जिससे न्यायालय निर्माण अतीबीलम्बित हो चुका है। वहीं पर इस जमीन के बजाय जबरदस्ती किसानों से उनकी जमीन को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि इनके पास प्रर्याप्त सरकारी जमीन पहले से ही उपलब्ध है। न्यायालय निर्माण में मात्र लगभग 35 बीघे जमीन की ही आवश्यकता है। जबकि जिलाधिकारी, चन्दौली के पास 52 बीघा सरकारी जमीन मौजूद है। जब न्यायालय निर्माण आसानी से उक्त जमीन पर हो सकता है। बावजूद इसके प्रशासन किसानों की जमीन लेकर उन्हें भूमिहीन बनाने पर ही तुला है। अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में लाते हुए मा0 न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए तत्काल कार्रवाई किये जाने एवं किसानों की जमीन न लिये जाने एवं वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बदायूँ के विकास खण्ड समरेर में तिगुलापुर से पंचमइया महाराज तक सड़क का निर्माण कराये जाने से सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

[महोदय, जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड समरेर में तिगुलापुर से पंमइया महाराज तक सड़क निर्माण न होने से आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग के खराब होने से आये दिन दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। इस मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु काफी प्रयास करने के बाद भी शासन एवं प्रशासन के अधिकारियों उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्यवाही न होने से जनमानस में आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है। अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विकास खण्ड समरेर में तिगुलापुर से पंचमइया महाराज तक सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत सेंट घाट पर ड्रम (पीपा) वाला पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद उन्नाव के तहसील बांगरमऊ में स्थित सेरइया घाट में पूर्व में ड्रम वाला पुल चलता था, अब यह पक्का पुल बन चुका है। उसी पुल को हस्तान्तरित कर जनपद उन्नाव में सेंग घाट पर ड्रम (पीपा) वाला पुल लगवाने की कृपा करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। अतः आपसे निवेदन है कि इस लोक महत्व के विषय पर सरकार के संज्ञान में लाने हेतु इस ड्रम वाले पुल को सेंग घाट पर ड्रम (पीपा) वाला पुल बनवाये जाने की माँग करता हूँ]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत कोप व कुरेम गावों सहित दर्जनों गांवों में नये सिरे से चकबंदी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के ग्राम कोप व कुरेम सहित दर्जनों गांवों की चकबन्दी कई दशकों से नहीं की गयी है जिससे किसानों की कई जगहों पर बिखरी हुयी छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन होने से कृषि कार्य करने में अत्यन्त परेशानियों का सामना करने के साथ ही अपनी कृषि उपज को बाजार तक पहुँचाने हेतु समुचित चक मार्ग न होने से तथा अन्य कृषि सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसान हित में जैसा कि सरकार की भी मंशा है कि किसानों की आय दुगनी की जाए इसके लिए जहां पर दशकों पूर्व चकबन्दी की गयी है वहां पर नये सिरे से चकबन्दी करायी जाए जिससे किसानों की बिखरी हुई जमीन एक जगह होने से लागत कम होने के साथ ही उपज भी बढ़ेगी तथा चकबन्दी होने से चक मार्ग भी प्राप्त होंगे जिससे किसानों की कृषि उपज मण्डी तक पहुंचाने में अत्यन्त सुविधा होगी जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जनपद बलिया के कोप व कुरेम गांवों सहित दर्जनों गांव जिनमें दशकों पूर्व चकबन्दी की गयी है वहां पर नये सिरे से चकबन्दी कराये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली में स्थित राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में टूटे बिजली के तार एवं खम्भों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 डी0सी0 वर्मा-

[महोदय, जनपद बरेली में स्थित राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में टूटे जर्जर बिजली के तार एवं खम्भों का अविलम्ब बदला जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार अन्तर्गत बाबूगंज पटेरवा, लक्ष्मीगंज होते हुए बीकरगढ़ मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बम्ध में नियम-301 के अतर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[महोदय अवगत कराना है कि हमारी वि0स0 क्षेत्र ऊँचाहार के वि0ख0 ऊँचाहार, जनपद रायबरेली के बाबूगंज पटेरवा, लक्ष्मीगंज होते हुये बीकरगढ़ मार्ग जो वर्ष 2013-14 में निर्मित हुआ था। उक्त मार्ग लगभग 25 ग्राम पंचायतों की 50,000 से अधिक आबादी को जोड़ने का काम करता है, में एक-एक फीट के गड्ढे हो गये हैं, पटरी क्षतिग्रस्त हो गयी है, आये-दिन दुर्घटनायें होती हैं, आने-जाने वाले लोगों को अत्याधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढामुक्त के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा मिट्टी की भराई की गयी थी जो एक सप्ताह के अन्दर ही पहले की स्थिति में आ गया। आपसे आग्रह है कि जनहित में उक्त मार्ग का नवीनीकरण /पुनः निर्माण कराये जाने की कृपा करें। कृपया जनहित के इस समस्या को वक्तव्य के रूप में स्वीकार किये जाने की कृपा करें।]

जनपद अयोध्या के रूदौली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत रूदौली नगर क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित हो रहा है। वर्तमान समय में उक्त चिकित्सालय किराये के

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भवन में चल रहा है। चिकित्सालय का अपना भवन न होने के कारण न तो मरीजों को इलाज मिल पा रहा है और न ही डॉक्टर व स्टाफ को बैठने की समुचित व्यवस्था हो पा रही है। जिससे सरकार की आयुर्वेद से जुड़ी स्वास्थ्य सेवायें रूदौली में ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पा रही हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है, परन्तु अभी तक उक्त चिकित्सालय के भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। अतः जनपद अयोध्या के रूदौली नगर क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा तैनात ड्रग इस्पेक्टर द्वारा अमर्यादित भ्रष्ट आचरण एवं अपने अधीनस्थ दवा व्यवसायियों के साथ, लिपिक के साथ गाली-गलौज एवं गोली से मारने की धमकी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अतर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जनपद सहारनपुर में तैनात माफिया ड्रग इंसपेक्टर संदीप कुमार के अमर्यादित एवं भ्रष्ट आचरण के कारण जनपद के दवा व्यवसायियों में असंतोष एवं दहशत की स्थिति बनी हुई है। ड्रग इंसपेक्टर अपने साथ माफिया किस्म के गुण्डों को लेकर दवा व्यवसायियों से अवैध धन उगाही का दबाव बनाते हैं, जिससे 5 दिसम्बर, 2020 को दवा व्यवसायी डॉ0 हारून की हृदय गति रुक जाने से मौके पर ही मृत्यु हो गई, इसी तरह 10 दिसम्बर, 2020 को रात्रि में दवा व्यवसायी अमित मल्होत्रा के बेरीबाग स्थित आवास पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने पर उन्होंने आत्म हत्या कर ली। ड्रग इंसपेक्टर के संरक्षण में नकली दवाओं एवं नशीली दवाओं का कारोबार चलाया जा रहा है। इनके द्वारा निरीक्षण के समय दबाव बनाकर दवा व्यवसायी के खाली प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं। दवा व्यवसायी को प्रतिलिपि न देकर बाद में डरा-धमकाकर उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। इतना ही नहीं, विभाग के लिपिक लिट्टी जेम्स ने सहायक आयुक्त औषधि से भी शिकायत की कि उपरोक्त ड्रग इंसपेक्टर ने 21 नवम्बर, 2020 को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गोली मारने की धमकी दी।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर अमर्यादित एवं भ्रष्ट आचरण वाले माफिया ड्रग इंसपेक्टर संदीप कुमार की निष्पक्ष जांच कराकर कठोर कार्रवाई की जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद आजमगढ़ के सदर तहसील अन्तर्गत प्रहलाद नगर कालोनी में जल निकासी हेतु नाली व सीवेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 श्री अनिल कुमार मौर्य-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2000 में प्रहलाद नगर कालोनी, करतालपुर में बना व

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बसा। यह कालोनी आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आती है। प्रहलाद नगर कालोनी में लगभग 300 मकान बने हुए हैं। कालोनी में नाली व जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण कालोनी मे अक्सर नाली के गन्दे पानी से जलभराव की समस्या बनी रहती है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए जनपद आजमगढ़ के प्रहलाद नगर कालोनी में जल निकासी हेतु नाली व सीवेज की व्यवस्था कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत गाजीपुर चौंचकपुर मुख्य मार्ग से जैदपुरा गांव तक के मार्ग को शहीद के नाम पर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत गाजीपुर चौचकपुर मुख्य मार्ग से जैदपुरा गांव तक जो शहीद गांव है। उसका चौड़ीकरण एवं उच्चीकृत कराया जाना आवश्यक है। महेश कुशवाहा जो सेना में था शहीद हो गया। शहीद के गांव को जोड़ने के लिए मात्र यही मार्ग है जो वर्तमान समय में जर्जर अवस्था में है। इसका चौड़ीकरण एवं उच्चीकृत कराया जाना जनहित में आवश्यक है। साथ ही साथ चूँकि शहीद का गांव है इसलिए उक्त मार्ग का निर्माण एवं नामकरण शहीद के नाम पर किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए शहीद के गांव के सम्पर्क मार्ग का शहीद के नाम व उपर्युक्त मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने हेतु आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा में समाज कल्याण विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में निजी शिक्षण संस्थान जिनकी संख्या लगभग 450 से अधिक है जोकि 1-1 निजी शिक्षण संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रम (आई0टी0आई0, एम0बी0ए0, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0 फार्मा, एम0 फार्मा, पैरामेडिकल, नर्सिंग एण्ड फार्मेसी, आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आदि) संचालित किये जा रहे हैं जो कि मानक के बिल्कुल विपरीत है। उक्त संस्थान हेतु दर्शाये गये बिल्डिंग/स्कूल मौके पर अस्तित्व में ही नहीं हैं फर्जी बिल्डिंग दर्शाकर एक ही बिल्डिंग में 05-05 उपरोक्त पाठ्यक्रमों की विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी छात्र-छात्राएं विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के फर्जी दाखिला दर्शाकर फर्जी रूप से अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में करोड़ों रुपये का गबन किया गया है। इतना ही नहीं शासन की गाइडलाइन/मंशा के विपरीत एक ही व्यक्ति संचालक/

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रबन्धक/मैंनेजर द्वारा एक ही बिल्डिंग में विभिन्न पाठ्यक्रमों की निजी विद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त कर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से तथा फर्जी रूप से विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवंटित सीटों के सापेक्ष और अधिक संख्या में फर्जी छात्र दर्शाकर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति का गबन किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया मात्र कागजों पर निजी विद्यालयों के संचालकों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में मान्यता प्राप्त कर भिन्न-भिन्न संस्थान व बिल्डिंग दर्शाकर पूरी की गयी हैं और इसी आधार पर उक्त संस्थानों की मान्यताएं फर्जी रूप से मानक के विपरीत प्राप्त की गयी है। इतना ही नहीं अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति विभिन्न बैंकों में मिलीभगत करके फर्जी खाते खोलकर फर्जी आधार कार्ड लगाकर सरकारी धन के करोड़ों रुपये का गबन किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इन फर्जी निजी शिक्षण माफियाओं की जांच सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी, मथुरा से करवायी जा रही है जिसमें शिकायत सत्य पाते हुए कई मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है परन्तु अभी तक न ही तो किसी भी दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और न ही फर्जी शिक्षण संस्थान प्रबन्धक /संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है और न ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचित जाति के छात्र /छात्रों की छात्रवृत्ति एवं छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति के मद में गबन किये गये सरकारी धन की वसूली की गयी है। इस मामले में कोपरेटिव बैंक के अधिकारियों की भी फर्जी खाते खोलने के सम्बन्ध में मिलीभगत रही है। बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। जनहित में समाज कल्याण विभाग में हुए भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के गबन की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

(12:23) औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज हमारे पास नियम-300 की एक सूचना श्री उमाशंकर सिंह की है।

मा0 सदस्यों के वेतन भत्तों के सम्बन्ध में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दलीय नेताओं की कमेटी का गठन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री उमाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आज जो पूरी तरह से नियम-300 के दायरे में सूचना आती है आपने हमें उस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मै पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह जो मैं सूचना ले करके आया हूँ क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी उपस्थित हैं और उसके साक्षात् गवाह माननीय अध्यक्ष जी आप हैं मेरी यह सूचना पूरे उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों के लिये सूचना है। माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष जी, 28 फरवरी, 2020 को माननीय नेता सदन यानि माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण होता है 2020-2021 का और आज हम फिर बैठे हैं 2021-2022 के बजट सत्र में और आज ही फिर माननीय नेता सदन का बजट पर भाषण होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, आज ही के दिन यह प्रश्न लाने का मेरा उद्देश्य यह था कि अन्य लोगों की जो बात है, अन्य अगर कोई सदस्य विधान सभा में अपनी बात कहता है और रखता है तो मान लीजिये अगर उस बात को इग्नोर कर दिया जाय तो कोई नई परिपाटी नहीं होगी लेकिन नेता सदन द्वारा इस सदन में जो आपकी अमानत है, जो आपका रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अनुसार नेता सदन ने इसी हाउस में जवाब दिया जब यहाँ यह बात उठी कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी क्योंकि यह अच्छा नहीं लगता कि प्रत्येक साल हम सभी माननीय विधायक अपने बारे में, अपनी सैलरी के बारे में, अपने भत्तों के बारे में, अपनी मिल रही सुख-सुविधाओं के बारे में इस बात को हम रखें। इसलिये भी कि जब हम यहाँ विधान सभा में अपनी बात रखते हैं, तो विधान सभा के बाहर यह बड़ा गलत संदेश जाता है कि यह विधान सभा में बैठे हुए लोग अपनी चिन्ता ज्यादा करते हैं। इस पर एक सहमति बनी, एक विचार बना और नेता सदन ने इस बात को कहा कि यह आवश्यक भी है, आज माननीय विधायक लोगों को जो भी भत्ते मिल रहे हैं अगर उसका वास्तविक रूप से मूल्यांकन किया जाय तो मुझे नहीं लगता कि उस भत्ते में एक विधायक अपने यहाँ आने वाले लोगों को चाय भी पिला सकता है, बिल्कुल नहीं पिला सकता। जो पेट्रोल, डीजल के खर्चे हैं, एक माननीय विधायक को जितना उनको अपने क्षेत्रों में दौड़ना पड़ता है उस डीजल की आपूर्ति से उस विधायक की गाड़ी नहीं चल सकती है। इसमें माननीय नेता सदन ने एक बहुत अच्छा विचार रखा और उन्होंने माननीय वित्त मंत्री जी को कहा कि इसमें माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में दलीय नेताओं के साथ एक बैठक करके विचार कर लिया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, देखिये हम इसमें यह नहीं चाहते, सदन का कोई सदस्य नहीं चाहता कि हम प्रत्येक साल खुद अपनी बात रखें तो इसमें माननीय नेता सदन ने एक सहमति दी थी और उन्होंने घोषणा की थी उसका पैरा भी मैंने अपनी सूचना में कोट किया है। ठीक वही पैरा कोट किया है जिसको माननीय नेता सदन ने 28 फरवरी, 2020-21 के बजट भाषण में पढ़ा था। उन्होंने यह घोषणा की थी कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं उनकी अध्यक्षता में सभी दलीय नेताओं के साथ एक बैठक हो जायेगी और बैठक होने के बाद यह तय कर लिया जायेगा कि इसमें हमें क्या और करना है और क्या नहीं करना है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से मँहगाई दर बढ़ती जा रही है। एक बार यह तय हो जाता तो प्रत्येक साल प्रत्येक सत्र में माननीय विधायकों को अपनी पीड़ा सदन के सामने रखने की नौबत नहीं आती। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आप जैसे और भी वरिष्ठ सदस्यों का हम लोग अनुसरण करते हैं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी जब यहाँ बैठते थे। हम भी बगल में बैठते थे और वह दिन देखे थे कि वह किस तरह से बात को प्रस्तुत करते थे, विधायकों की समस्याओं को रखते थे लेकिन आज जब वे उस जगह पर चले गये हैं जहाँ से वह माननीय सदस्यों की समस्याओं का हल कर सकते हैं। आज वह संसदीय कार्य मंत्री ही नहीं हैं। बल्कि उत्तर प्रदेश

के वित्त मंत्री भी हैं और आज उनके वहाँ जाने पर हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ 5 साल बैठने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे आदरणीय महाना साहब भी हैं, वह भी इस बात को उठाते थे, स्वर्गीय हुकुम सिंह जी अब नहीं हैं, यह तीन नेता बहुत जम करके इस बात को उठाते थे तो यह बड़ी उम्मीद जगी थी माननीय सदस्यों की, नये तो नहीं लेकिन पुराने सदस्य जो उस समय बात सुनते थे। आज जब हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी उस चेयर पर बैठे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आज इसका निराकरण हो जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कही गई घोषणा, जिस जिम्मेदारी को माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वित्त मंत्री को दिया था मुझे लगता है कि आज आपका निर्देशन हो जाय और माननीय वित्त मंत्री जी इस सदन को आश्वासन दे दें कि दलीय नेताओं की बैठक आहूत करके माननीय सदस्यों की जो समस्या है उसका हमेशा हमेशा के लिये निराकरण हो जाय। माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक साल यह समस्या हर सदन में एक विधायक को न उठाना पड़े। यह लाने का उद्देश्य भी मेरा यह था, मैंने भी पढ़ा, माननीय नेता सदन जब मेम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट थे तो वहाँ भी लोक सभा के माननीय सदस्यों की यह समस्या आयी थी तो लोक सभा के माननीय अध्यक्ष जी ने हमारे नेता सदन को ही इस समिति का अध्यक्ष बनाया था कि आप इन समस्याओं को देखकर हल करें। बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय नेता सदन ने उस समय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दी गयी जिम्मेदारी का निर्वहन करके लोक सभा के सभी माननीय सदस्यों के लिए बढ़िया संस्तुति की थी, जिसको लोक सभा के माननीय सदस्यों ने और पूरे सदन ने स्वीकार किया था। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय नेता सदन ने कहा है माननीय वित्त मंत्री उसकी बैठक करके जो हमेशा-हमेशा के लिए विधायक अपना रोना रोते हैं। उसको समाप्त करें ताकि प्रत्येक साल यह बात सदन में न लानी पड़े।

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी इस सदन में कई बार यह प्रकरण आ चुका है। जो परिस्थिति है, जिसकी वजह से पूरा प्रदेश, पूरा देश और पूरी दुनिया प्रभावित हुई है उसी वजह से उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। मैं सभी माननीय सदस्यों को इसके लिए बधाई देता हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई दे चुके है कि सभी ने उस महामारी में अपना हृदय से सहयोग किया है। चाहे विधायक निधि के माध्यम से किया हो, चाहे वेतन के माध्यम से किया हो। जहाँ पर यह परिस्थिति पैदा हो गयी कि वेतन से 30 प्रतिशत देना है तो सभी लोगों ने सहयोग किया था। परिस्थिति देखकर ही किसी प्रकार का निर्णय होता है। आप माननीय नेता सदन के बयान को 28 फरवरी के वक्तव्य की बात कर रहे है। उसके तुरन्त बाद मार्च के महीने से ही यह महामारी शुरू हो गयी उसी महामारी की वजह से उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हम लोग जनता से चुनकर आते है। अगर उस समय इस प्रकार की समिति का गठन होता कि विधायकों के वेतन भत्ते के संबंध में समिति गठित की गयी तो इसका संदेश क्या जाता ? चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, सभी को अपने-अपने क्षेत्रों में इस बात को सुनना पड़ता कि एक-एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए, एक-एक व्यक्ति की मदद करने के

लिए इस समय हम महामारी से जूझ रहे है। "कौन सी बात कहां, कैसे कही जाती है। यह सलीका हो, तो हर बात सुनी जाती है।" मेरा तो आपसे विनम्र आग्रह है कि मा0 वर्मा जी को और पूरे सदन के सदस्यों को इस परिस्थिति को समझना चाहिए कि आखिरकार हम किस परिस्थिति से गुजरे है। अगर परिस्थिति समझ लेते तो शायद आज यह प्रश्न नहीं उठाते। मंशा अच्छी है, नीयत अच्छी है, मा0 नेता सदन ने जब खुद यहां पर घोषणा की थी तो इसलिए नहीं की थी कि यह परिस्थिति जाएगी तो इसको स्थगित करना पड़ेगा। वह परिस्थिति के आधार पर देखा जाएगा। परिस्थिति जैसे होगी तो उसके ऊपर जरूर विचार किया जाएगा।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हम यह बात बजट प्रस्तुत करने से पहले भी ला सकते थे। इस कोरोना महामारी के बाद बजट का आकार बढ़ा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई विषय नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें और ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है, किसी बहस की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरे उत्तर से संतुष्ट हो जाना चाहिए था। मेरा आपसे अनुरोध है कि अब इस विषय को समाप्त किया जाए। बजट के ऊपर माननीय नेता सदन को आज बोलना है।

वितीय वर्ष 2021-2022 के आप-व्ययक पर साधारण चर्चा†

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ कि प्रदेश के 2021-22 के आय-व्ययक पर जो वित मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया उस पर विस्तृत चर्चा यहाँ पर माननीय सदस्यों ने की और उस चर्चा के माध्यम से अपने विचारों को प्रदेश के इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सदन में रखकर प्रदेश के विकास की कार्ययोजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। काफी रूचि के साथ सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी और मैं खासतौर पर आभारी हूँ नेता प्रतिपक्ष माननीय राम गोविन्द चौधरी जी का यद्यपि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि उनका जब भाषण हो तो मैं सदन में रहू लेकिन उसी समय मेरा विधान परिषद में कार्यकम था तो उच्च सदन में रहने के कारण मैं यहाँ सदन में नहीं रह पाया लेकिन उनके भाषण को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा मैंने पूरी प्रति मंगाई थी मैंने उनके भाव को भी जाना और समझने का प्रयास किया है। अन्य दलीय नेताओं के बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे सहयोगी अपना दल से जुड़े हुए सभी नेताओं ने भी इस सदन में जो विचार रखे है मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ मेरे सहयोगी जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 39 सदस्यों ने भी यहाँ पर अपनी बातों को रखा विकास का एक नया एजेण्डा प्रदेश को दिया विधान सभा जनपद और प्रदेश के अन्दर विकास की कार्य योजना कैसे आगे बढ़नी है इन सभी के साथ ही अपना दल से जुड़े माननीय तीन सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के 10 बहुजन समाज पार्टी के पाँच कांग्रेस के 3 सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 2 कुल 62 सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में

† दिनांक 25-02-20121 की कार्यवाही से

भाग लिया है और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली का सृजन प्रदेश का विधान मण्डल कर रहा है यह हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से अभिनन्दन करता हूँ। महोदय हम सब जानते है कि जब प्रदेश के अन्दर हमारे सहयोगी वित्त मंत्री मा0 श्री सुरेश खन्ना जी यहाँ पर बजट प्रस्तुत कर रहे थे उस समय देश के अन्दर भी बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में आ रही थी। खास तौर पर बजट पर हम चर्चा करें इससे पहले उन मुद्दों पर चर्चा होनी बहुत आवश्यक हो जाती है इसलिए हो जाती है क्योंकि बजट से उसका सम्बन्ध है और कहीं न कहीं बजट के दायरे के बारे में या करोना कालखण्ड के दौरान मुझे लगता है कि हर एक तबके ने अगर राजनीतिक पूर्वाग्रह उनके साथ नहीं जुड़ा है वह अलग विषय है कि घर के अन्दर उन्होंने बजट की सराहना की होगी लेकिन सार्वजनिक रूप से छोड़ दिया जाए तो हर तबके ने मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत। बजट की यहाँ पर भूरि-भूरि प्रशंसा हर एक तबके ने की है और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश स्तर पर की है। (सत्तापक्ष की तरफ से मेंजों की थपथपाहट)

हमारे पास फिक्की से, सी0आई0आई0 से या अन्य उस फील्ड में काम करने वाले लोगों के जो वक्तव्य जो फोन या आपसी बातचीत में उन्होंने अपने जो वक्तव्य दिये है, हर एक ने उसकी सराहना की है और सराहना ऐसे ही नहीं की है। इस लिये नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बातें यहाँ पर कही और जैसा कि मैंने कहा कि मैं सचमुच उनके भाषण को सुनना चाहता था और मैंने उनके पूरे भाषण का प्रिंट निकाला और उसको देखा। यद्यपि मैंने अनुरोध किया था कि अगर वह अपने बजट भाषण को साढ़े बारह बजे की बजाय तीन बजे के आसपास अपनी बातों को रखेंगे तो मैं सदन में मौजूद रहूँगा और उनके मित्र खन्ना जी ने उनको यह बात बतायी भी होगी, लेकिन जब भी वह खन्ना जी की बात को नहीं मानते है तो उनके साथ धोखा हो जाता है। (सदन में हँसी)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, उन्होंने दोनो बातें बतायी थीं। उन्होंने ही हमसे कहा था कि आपने तीन बजे भाषण करने का अनुरोध किया है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, हम लोग बजट ऐसे समय में लेकर आए हैं जब वैश्विक महामारी कोरोना है। लोग कोरोना से भयभीत हैं, लेकिन भारत ने कोरोना का प्रबन्धन भी बेतहर तरीके से किया और कोरोना प्रबन्धन के साथ ही अब कोरोना से बचाव के लिये भी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किये है उसके तहत अभी पहली मार्च से 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है। यानी भारत की अपनी एक उपलब्धि है। भारत के साथ कुछ न कुछ नयी उपलब्धियाँ जुड़ती जा रही है। और भारत के लोगों को इस महामारी से बचाने के साथ-साथ आरोग्यता प्रदान करने के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे है, पहली मार्च से फेज सेकेण्ड का जो कार्यक्रम चला है और मैं स्वयं भी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में जाकर के उन सभी नागरिकों से जो वरिष्ठ नागरिकजन थे और वैक्सीन लेने के लिये आये थे, अलग-अलग तबके के थे और अपनी लाईन में बैठकर के पूरे धैर्य के साथ वैक्सीन लगाने के

साथ वह अपने को जोड़े हुये थे। यह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, अद्भुत अनुशासन है और कोई भी देश अगर अपने नेतृत्व के इस अनुशासन भाव के साथ जुड़ करके कार्य करता है तो उसको दुनिया की महा ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता है और यह एक शुभ स्थिति वर्तमान में भारत के साथ जुड़ रही है। (सत्तापक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट)

कोविड से प्रदेश भी प्रभावित हुआ है, हमारा राजस्व भी प्रभावित हुआ है, आम जनमानस में भी इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन इस सबके बावजूद प्रदेश ने अपनी सारी व्यवस्था को, वित्तीय अनुशासन को बनाये रखते हुये सारे कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मैं नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूँगा कि बजट पर उन्होंने जो बाते कहीं और खन्ना जी को कुछ शेर-ओ-शायरी भी सुनाई थी, पता नहीं खन्ना जी ने उस शेर-ओ-शायरी का जवाब आपको दिया कि नहीं दिया।

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, कल जवाब देंगे।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर वह कल जवाब देंगे। वह जवाब देने को तैयार हैं और मैं अपील करूंगा कि वह जरूर खन्ना जी की बातों को सुनेंगे। लेकिन महोदय, "सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते है, काँटो में राह बनाते हैं, मुँह से न कभी उफ कहते" यह पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी की है जो देश के लिये भी और प्रदेश के लिये भी अक्षरशः सही बैठती है। (सत्तापक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) बजट के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको देखना हो तो बिना विचलित हुए हम लोगों ने इसका अनुसरण किया है। हम लोग उन बातों को लेकर आगे बढ़े है लेकिन जब मैं आपकी बात सुन रहा था और आपकी बातों को इसमें देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि आप बजट को इस रूप में चाहते है जो समाजवादी पार्टी के समय में होता था क्योंकि आप लोगों का वास्तव में भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता था जो सर्वसमावेशी हो, सर्वकल्याणकारी हो प्रदेश के विकास को एक नई ऊँचाईयों तक पहुँचाने वाला हो। किन्तु वह भाव न होने के नाते मुझे लगता है, कि आप अपनी पार्टी, जो पिछली सरकार में थी वह केवल एक बात पर विश्वास करती थी और वह थी चार्वाक का वह सिद्धान्त "यावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृत्वा पिवेत। यह इनका एक भाव होता था तात्कालिक रूप से मिल जाये, और मुझे लगता है कि तात्कालिक रूप से न उसमें कोई भाव होता था, न उसमें प्रदेश की भावनायें होती थी, न विकास का कोई एजेंडा होता था और न ही प्रदेश के लिए कोई दूरदृष्टि का एजेंडा छपा होता था। इसलिए हर एक तबका नाराज होता था और हर तबके ने उसका जवाब भी दिया है।

महोदय, मैं इस बात को लेकर चर्चा कर रहा था। बजट को लेकर अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग तबके के लोगों ने बजट पर टिप्पणी की है। पूर्व मुख्य सचिव, उन्होंने इस बारे में कहा सरकार का विजन क्या है ? वोट से ज्यादा विकास पर जोर। हमें मालूम है तत्कालिक आवश्यकता के लिए बनायी जाने वाली योजनायें न पार्टी का न प्रदेश का हित कर सकती है।

हमने एक विजन के साथ विकास के रोडमैप को तैयार किया है और उस रोडमैप के अनुसार हम लोगों ने विकास के इस एजेंडे को लागू किया है। यही पार्टी को भी और प्रदेश को भी एक नई ऊंचाई देगा, पार्टी को लंबे समय तक शासन करने के लिए और प्रदेश को विकास की एक नई अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ ने भी इस बात को कहा है कि बजट को सभी वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बजट युवाओं को समर्पित है। पेपरलेस बजट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष बधाई। डाक्टर अरोड़ा ने सरकार द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के लिए विशेष रूप से जो प्रावधान किया है इसके लिए भी उन्होंने आभार व्यक्त करने के साथ ही सुपोषण पर ध्यान देने के लिए भी इसको एक सराहनीय कदम माना है। इस संबंध में स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ की राय हम सबके सामने आती है। चेयरमेन सी0आई0आई0 ने कहा कि यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर, स्वस्थ्य और सुरक्षित बनाने वाला है। ये उस फील्ड से जुड़े हुए लोग है जिनको राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन हाँ अर्थव्यवस्था और बजट के मुद्दे को लेकर के चेयरमेन पी0एच0डी0, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। कोरोना संक्रमण की आपदा ने सभी उद्योगों को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है। अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा इस बजट से उद्योगों को एक नई राहत दिखती है ये पी0एच0डी0 चैम्बर के चेयरमेन का बयान है।

इसी प्रकार के प्रेसिडेंट एसोचैम के द्वारा भी कहा गया कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी समाज के हर वर्ग के लिए अच्छा है। सरकार ने जो बेहतर हो सकता था वह किया है और पिछले वर्ष की तुलना में 7.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी एक प्रशंसनीय कार्य है। फिक्की फ्लो पूर्व अध्यक्ष जो महिला चैपटर है उनके द्वारा महिला व बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए शुरू की गयी मुख्य मंत्री सुपोषण योजना मां और बच्चे दोनों की सेहत को सुधारेगी। इसके अलावा मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना भी मील का पत्थर साबित हुई। ऐसे बहुत सारे तबके के अलग-अलग तबके के लोगों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह प्रतिक्रियायें इस बात को बताती है कि सरकार की कार्ययोजना एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और सरकार सकारात्मक माहौल में कार्य कर रही है और सकारात्मक माहौल के परिणाम भी स्वाभाविक रूप से सकारात्मक ही होंगे। महोदय पिछले चार वर्ष के दौरान जो कार्य किये गये हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अन्दर जो कार्य वर्षों में नहीं हो पाये विगत चार वर्षों के दौरान सभी रास्ते पर आते हुए दिखाई दिये और हम लोगों ने इस बारे में कहा था जब 2017-18 में प्रदेश सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था तब हम लोगों ने 2017-18 के बजट के बारे में कहा था कि हम इसे किसानों को समर्पित कर रहे है। 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित किया था। ओ0डी0ओ0पी0 की जो योजना देश की लोकप्रिय योजना है वह उसी समय हम लोगों ने फरवरी 2018 में उस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश के अन्दर लागू किया था आज उसके बेहतर परिणाम आये है प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है परम्परागत उद्योग एक बार फिर से पुनर्जीवित होता

हुआ दिखाई दिया है। एक नई सम्भावना रोजगार की और विकास की प्रदेश के अन्दर उसके माध्यम से देखने को मिली है। 2019-2020 का बजट हम लोगों ने प्रदेश की मातृ शक्ति को समर्पित किया था और 2020-2021 का युवाओं उनकी शिक्षा उनके कौशल विकास रोजगार मूल भूत आधार भूत इन्फास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट से जुड़े हुए जो कार्य थे उनको एक नई गति देने के लिए समर्पित किया था। 2021-22 के बजट का थीम भी प्रदेश सरकार ने बहुत स्पष्ट भाव के साथ रखा कि प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रखकर यह बजट प्रदेश के विभिन्न तबके के स्वावलम्बन और सशक्तीकरण को समर्पित है और इस बजट इसी रूप में पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने लिया है मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव, वित्त और वित्त आयुक्त को और वित्त विभाग की पूरी टीम को वित्त के हमारे राज्य मंत्री और पूरी टीम को विभिन्न विभागों ने जो समय पर सभी मंत्रियों ने जो समय से अपने विभाग की योजनाओं को इसमें शामिल करवाया है इसके लिए इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ एक अच्छे बजट को प्रस्तुत करने के लिए एक थीम के साथ बजट आगे बढ़ा।

महोदय बजट प्रस्तुत करने के साथ इससे पहले वह उपलब्धियां जो अलग-अलग समय में अलग-अलग थीम के साथ कार्य किया गया उसके परिणाम भी हमारे सामने है। हम सब जानते है कि प्रदेश कहां था और मैं बार-बार इस बात को कहता हूं कि पहला बजट जब सदन में प्रस्तुत किया गया था तभी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से बजट बहुत छोटा है। हमें इसके दायरे को बढ़ाना होगा लेकिन बजट के दायरे को बढ़ाने से नहीं काम चलेगा अपनी आय को भी बढ़ाना पड़ेगा। वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखना पड़ेगा फिजूल खर्ची को रोकना पड़ेगा लीकेजेज जहां भी होंगे उसको हर हाल में नियंत्रित करना पड़ेगा और उस दिशा में पूरी सरकार पूरा तंत्र एक साथ जुटा है, उसके परिणाम भी सामने आये हैं। यह पूरे प्रदेश के लिए कहाँ था आज से चार साल पहले प्रदेश, आज से चार साल पहले देश और दुनिया उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में मानता था। उत्तर भारत के जिन चार-पांच राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था उसमें उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर था।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा टोंकाटाकी करने पर)

मैं आंकड़ों पर आ रहा हूँ। मेरी बात को सुन लीजिये, थोड़ा धैर्य और धीरज रखिये। महोदय, उत्तर प्रदेश चार साल पहले बीमारू राज्य था और इतनी बड़ी आबादी के राज्य का बजट केवल दो लाख करोड़ रुपये का था। उत्तर प्रदेश में उस समय 20-22 करोड़ की आबादी थी और बजट दो लाख करोड़ रुपये का था। यह ऊंट के मुंह में जीरा था। इतने बड़े प्रदेश के लिए गांव के विकास के लिए, नगरों की बुनियादी सुविधाओं के लिए युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, अलग-अलग तबके के लिए योजनायें बनानी थी, लेकिन जब बजट ही नहीं होगा तो कैसे कर पायेंगे। इन्होंने इनकम बढ़ाने पर जोर नहीं दिया और जोर क्यों नहीं दिया जाता था हम उस पर भी आना प्रारम्भ करेंगे। इनकम कहां-कहां से और कैसे-कैसे बढ़ी है, मैं इस पर भी चर्चा करने का प्रयास करूँगा, तो बहुत सारी चीजें सामने आ जायेंगी लेकिन यह सच है कि वर्ष 2015-2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश चौदहवें स्थान पर था। यदि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी स्थिति अच्छी नहीं

है तो कोई बाहरी निवेशक आपके यहां पर नहीं आ सकता। आज उत्तर प्रदेश दूसरे नम्बर पर है। शासन के चेहरे बदले हैं लेकिन तंत्र वही है, सब कुछ वहीं है, सोर्स ऑफ इनकम भी वही है लेकिन हमने कार्य पद्धति बदली है। हमने लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया है। आप लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है तो सुन लीजिये। मुझे आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश आबादी में नम्बर एक पर है।

वर्ष 2015-2016 में उत्तर प्रदेश की आबादी 20 से 22 करोड़ थी लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था देश में पांचवी-छठी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। हमारे यहां उस समय जब कोई बाहर से आता था, विदेशी राजदूत आते थे, कोई राष्ट्र प्रमुख आता था या कोई निवेशक आता था और जब हमारी उनसे बातचीत होती थी तो हम लोग उनसे किस बारे में चर्चा करते थे। हम कहते थे कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। यह सुनकर वह मानते थे और उनकी उत्सुकता यह सुनने की होती थी कि सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते यहां की अर्थव्यवस्था भी सबसे बड़ी होगी लेकिन हम कहते थे कि नहीं हम पांचवे छठें नम्बर पर है तो वह थोड़ा बैक होता था। प्रदेश की कुल जी0डी0पी0 10,90,000 करोड़ रुपये के आस पास थी। ज्यादा समय नहीं हुआ और चार वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह 10,90,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,73,000 करोड़ रुपये हो गई है। अगर यह चार वर्ष में दोगुने से ज्यादा हुई है तो इंतजार करिये जब हम वर्ष 2022 में पांच वर्षो के लिए फिर से आयेंगे तो उत्तर प्रदेश की इकोनामी देश की पहली इकोनामी बनेगी। हमारी यह टीम उसी इकोनामी के लिए कार्य कर रही है। प्रति व्यक्ति आय सुन लीजिए। आप लोगों ने यू0पी0 की क्या बना दिया था ? यहां पलायन हो रहा था। लोग भाग रहे थे। लोगों के पास कोई सहारा नहीं था। सब लोग चिंतित थे। यू0पी0 के बारे में एक परसेप्सन बन चुका था। लोग कहते थे कि अब क्या होगा ? मैंने कहता था कि निश्चिंत रहिये यू0पी0 चेंज हो चुका है। यह नये भारत का नया यू0पी0 है (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)। घबराइये मत यू0पी0 में हम लोग अच्छा करेंगे। मैंने कोरोना के आंकड़े आप लोगों के सामने प्रस्तुत किये थे वह आंकड़े मेरे नहीं थे। वह भारत सरकार के आंकड़े थे। दुनिया के विशेषज्ञों के आंकड़े थे। मैं अपने आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं वह भारत सरकार के हैं और देश के सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के आंकड़े दे रहा हूं। महोदय, प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में कितनी थी, 45 हजार और आज लगभग यह 95 हजार है ? यह परिवर्तन है क्या ? हुआ नहीं कुछ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में ? यह आंकड़े मेरे नहीं हैं। यह दुनिया के वित्तीय संस्थाओं के आंकड़े हैं और यह आंकड़े प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूईंग बिजनेस ही नहीं, ईज ऑफ लीविंग को भी बेहतर करने का जो कार्य हुआ है, हर एक फील्ड में जो कार्य हुआ है यह उसका परिणाम है।

वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, नेता प्रतिपक्ष जी कम से कम आप इसके बारे में मानकर चल देते। देख लेते। कुछ तो सोचा होता कि अपने मित्र की बात को आप कैसे काट रहे हैं ? यानी अपने मित्र को आप हमेशा धोखा देते हैं। महोदय, ईज ऑफ लीविंग में

कितना परिवर्तन हुआ है। हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं ? 1947 से ले करके 2014 तक अगर अटल जी के छः वर्ष के उस काल खण्ड को छोड़ दें तो ईज ऑफ लीविंग के बारे में पिछली सरकारों ने देश के अंदर क्यों नहीं सोचा था और मैं चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर भी क्यों नहीं सोचा ? आज तो बजट में ईज़ ऑफ लीविंग के बारे में भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक लक्ष्य तय किया है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एस0ई0सी0सी0 सर्वे के अन्तर्गत जो भी व्यक्ति 2012 में आया है 2022 तक हर हाल में उसको एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। चार वर्ष में 40 लाख लोगों को आवास मिल जाये यह प्रदेश के अंदर हुआ है। चार वर्ष में 1 करोड़ लोगों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिल जायें यह प्रदेश के अंदर हुआ है। हर गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए यह प्रदेश के अंदर हुआ है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हो जाये। अब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे कि हम भी करना चाहते थे, लेकिन किये क्या ? किये तो नहीं न ? करना तो चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाये इसलिए जनता ने कहा कि देखो आपके बस का नहीं है, आप जहाँ के लायक हैं वहीं बैठिए हम लोगों ने प्रदेश के भावों का सम्मान किया। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सम्भावना वाला प्रदेश है। लोग कहते थे कि यहां कुछ नहीं हो सकता है। यहां तो समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व तय करेगा हम लोग वही करेंगे। मैं तो देखकर ताज्जुब कर रहा था।

महोदय, जब मैं मुख्य मंत्री कार्यालय बैठने के लिए जाने लग गया, मुख्य मंत्री कार्यालय में क्या स्थिति थी। शास्त्री भवन की क्या दुर्गति कर रखी थी। मैंने वहाँ पर पूछा कि श्रीमान् जी यहाँ पर पूर्व मुख्य मंत्रीगण आते थे कि नहीं आते थे। सभी लोगों के चेहरे झुके हुये थे। सभी लोग मौन थे। बाद में एक सज्जन मुझे बोले कि वह तो कभी-कभार मैंने कहा कि कभी-कभार का मतलब ? कहा कि साल में एक-आध बार तो मैंने कहा कि अगर मुख्य मंत्री साल में एक-दो बार ही कार्यालय आयेगा तो प्रदेश का बेड़ा तो गर्ग होना ही होना है और यही होता था। कुछ लोग तो ऐसे थे जो दस मिनट के लिए कैबिनेट की बैठक के लिए जाते थे। बाकी गायब और फिर बड़ा सपना देखते थे कि हम उत्तर प्रदेश को यूरोप बना देंगे। उसका कोई रोडमैप नहीं। योजनायें बनती थीं स्वयं के लिए, परिवार के लिए आप लोग दायरा कभी बढ़ा नहीं पाये। उस सोच से बाहर नहीं निकल पाये। आपने ठीक कहा और मैं मानता हूँ कि कभी इसमें बहुत अच्छे महापुरुष पैदा हुये थे। आचार्य नरेन्द्र देव का कौन सम्मान नहीं करता है, जय प्रकाश जी का सम्मान कौन नहीं करता है, डा0 लोहिया का सम्मान कौन नहीं करता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप तो गाली देते हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैं गाली नहीं देता हूँ। हाथरस में भी अभी कल साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन ? हाथरस की घटना ने कल इस टोपी को फिर

से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुयी क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई सम्बम्ध नहीं है ? और हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है ? मैं यही पूछना चाहता हूँ। यह कौन सी स्थिति है, यह कौन सी मजबूरी है ?

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर, शराबा उत्पन्न हो गया, शोर शराबे के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह फोटो है। इसमें यह आरोपी भाजपा सांसद के साथ बैठे हैं। देख लीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आज वहाँ पर समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाये गये हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाये गये हैं। यह क्या साबित करता है।

(सत्तापक्ष की तरफ से शेम-शेम की आवाजें)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप हमें मजबूर करते हैं कि आपका भाषण न सुनें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपका भी सम्मान है हम लोग इस सदन का सम्मान करते हैं, नेता सदन का, उस कुर्सी का, लेकिन असत्य का हम लोग सम्मान नहीं करते हैं। देखिये यह फोटो अगर यह आपका एम0पी0 न हो तो कहिये। हम लोग आपका सम्मान करते हैं उस सम्मान को बरकरार रहने दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैं पूछना चाहता हूँ कि आज की रैली में उस अपराधी के द्वारा पोस्टर लगाये गये हैं कि नहीं ?

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री योगी आदित्यनाथ-

महोदय, यह जो होल्डिंग और पोस्टर वहाँ अलीगढ़ में लगे हुये हैं यह किसके हैं और क्यों लगाये गये ? कैसे लगा दिये गये ? यह एक दिन में नहीं लगे हैं, आज इनका वहाँ पर सम्मेलन है। माननीय अध्यक्ष जी, उस सम्मेलन में पीड़ित बालिका चिल्ला-चिल्लाकर कह रही है कि उस अपराधी का संबंध किससे है ? हम सच को एकदम झुठलाना चाहते हैं यानी धूल झोंकना चाहते हैं। आपने समाजवादी आंदोलन को एक अस्वाभाविक, अव्यवहारिक और एक

अमानवीय आंदोलन बना दिया है। इसीलिए इसके बारे में लोग अलग-अलग चर्चाएं करते हैं, वह ऐसे ही चर्चा नहीं करते हैं। इन लोगों में सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। इन लोगों में न सच को स्वीकार करने की क्षमता है और न ही आदत है क्योंकि इन लोगों ने प्रदेश को अलग-अलग तरीके से चलाने का प्रयास किया है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बजट के जो प्राविधान किये हैं, ईज ऑफ लिविंग के तहत प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं विगत चार वर्षों में हुईं, यह केवल व्यक्ति के जीवन की सुगमता का ही आधार नहीं बना, सुगमता के साथ-साथ उसकी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का भी आधार बना है। आवास के माध्यम से, विद्युत कनेक्शन के माध्यम से या फिर उसको राशन की पोर्टबिलिटी की सुविधा देने के माध्यम से, आयुष्मान भारत में पाँच लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा देने के कवर के माध्यम से या फिर किसी भी फील्ड में हो या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर भी हर व्यक्ति को आशंका थी। कोरोना के दौरान बड़ी संख्या में माईग्रेट लेबर आयेंगे तो इनका क्या होगा। हमने कहा कि आप चिंता मत कीजिए। उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश उनको सम्मान के साथ लेगा भी और उनकी सम्मान के साथ व्यवस्था भी की जायेगी। हम लोगों ने दोनों काम किये हैं और मुझे प्रसन्नता है कि हमारा जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आया, किन्ही मजबूरियों के कारण उसको प्रदेश के बाहर जाना पड़ा होगा, लेकिन आज वह प्रदेश के अंदर ही ज्यादातर रोजी-रोजगार के साथ जुड़ चुका है और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उनका योगदान ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार बन रहे हैं। हम लोगों ने इन कार्यों को आगे बढ़ाया है। गांव-गांव को सड़कों के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, पेयजल की स्कीम "हर घर नल की योजना" जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कितना बड़ा कार्य होने जा रहा है। अब यह कहेंगे कि यह तो समाजवादी पार्टी भी करना चाहती थी।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने चार सालों में कितने घरों को जोड़ा है ?

श्री अध्यक्ष-

यह बैठे-बैठे टिप्पणी ठीक नहीं है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1947 से लेकर 2017 तक प्रदेश में केवल 02 फीसदी से कम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हर घर नल की योजना से जोड़ा गया था और वर्ष 2017 से लेकर अब तक हम उसको 10 फीसदी तक पहुंचा चुके हैं और मैं इसको बोल रहा हूँ याद रखना हम एक साल के अंदर चुनाव में जा रहे हैं, हमें अगले नौ महीने के अंदर चुनाव में जाना है। अगले नौ महीने के अंदर देखना कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में, विन्ध्य क्षेत्र में और अभी कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग 30 हजार राजस्व गांवों की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर आ रहे हैं और एक साथ पाइप पेयजल की स्कीम इन सभी में लागू करने जा रहे हैं। यह जो योजना लागू होगी वह एक दिन के लिए नहीं होगी, 10 वर्षों तक उसके रख-रखाव की

जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था को निभानी पड़ेगी। जल जीवन मिशन, "हर घर नल की योजना" और पहले यह ग्रामीण क्षेत्र में था, हम आभारी है मा0 प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने यूनियन बजट में भी जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्रों के साथ जोड़ने का काम किया है। हमारी शहरी क्षेत्र की भी कार्य योजना तैयार हो चुकी है, हम उसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह है विकास का रोड़ मैप, ईज ऑफ लिविंग का। आखिर लोग अच्छी सड़क चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, उनको शुद्ध पेयजल मिल जाए। शुद्ध पेयजल आपके लिए एक एजेण्डा हो सकता है, हमारे लिए उसके जीवन की सुगमता के साथ-साथ उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी यह चीजें आवश्यक हैं। नेता प्रतिपक्ष भी और आप भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस की बीमारी के बारे में आप सभी जानते हैं। यह अलग विषय है कि आपने चिकित्सा शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाला है, लेकिन उन बच्चों के प्रति आपने कभी संवेदना नहीं व्यक्त की, जबकि मरने वाले 90 प्रतिशत बच्चे दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के थे। आप वोट बैंक की बात करते थे, कभी आप लोगों ने उस बारे में चिंता नहीं की। गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के साथ-साथ 38 जनपद ऐसे थे, जहां पर इंसेफेलाइटिस से बड़े पैमाने पर मौतें होती थीं। 1998 में मैं पहली बार सांसद बना था, हम लोगों ने इसके लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किये, आन्दोलन किये, संसद में भी कई बार इस मुद्दे को रखा और मुझे लगता है कि हर संसद के सत्र में मैं इस मुद्दे को रखता भी था।

हम लोगों नें व्यापक रूप से सरकार के संज्ञान में इन सब बातों को रखने का प्रयास भी किया लेकिन इंसेफेलाइटिस की समस्या दूर करने में आज हम सफल हुए हैं और 95 फीसदी मौतों को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) दो योजनाओं ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। एक, स्वच्छ भारत मिशन , हर घर तक शौचालय पहुंचाने का कार्य है। इज्जतघर उसका नाम ही रखा गया है। यह उस परिवार की महिला की गरिमा की रक्षा का भी आधर बना, साथ-साथ गरीब के स्वास्थ्य को भी आरोग्यता प्रदान करने का भी एक आधार बना है और स्वच्छ भारत मिशन में हम लोगों ने स्वच्छता और शुद्ध पेयजल दोनों को फोकस किया था। अन्तर्विभागीय समन्वय उसी का एक कारण था और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। यह काम पिछली सरकारें भी कर सकती थीं लेकिन जब गरीब के लिए सोच हो, तब न। जब गरीब के बारे में कोई एजेण्डा हो, तब न। चालीस लाख गरीबों को पहले भी आवास मिल सकता था, एक करोड़ अड़तीस लाख लोगों को पहले भी विद्युत कनेक्शन मिल सकते थे, इन लोगों को पहले भी अन्य सुविधाऐं मिल सकती थीं, रसोई गैस के कनेक्शन इन गरीबों को पहले भी मिल सकते थे, प्रदेश के जिन 56 लाख गरीबों को रसोई गैस के सिलेण्डर मिले हैं, वह पहले भी दिये जा सकते थे, हर परिवार के पास राशन कार्ड पहले भी उपलब्ध कराया जा सकता था लेकिन एजेण्डे का हिस्सा हो, तब न। जब उसके बारे में एक सोच हो, तब न लेकिन वह नहीं था। आज हर क्षेत्र में बैंक की सुविधा है, और अब तो हर ग्राम पंचायत में हम लोग बी0सी0 सखी (बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी) की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम चरण में लेकर आ गये हैं। अब गांव के व्यक्ति को अपना पैसा निकालने, पैसा जमा करने, गांव के 5 कि0मी0 दूर बैंक में

नहीं जाना पड़ेगा बल्कि अपने ग्राम पंचायत के अन्दर ही अपने बी0सी0 सखी उसको यह सुविधा उपलब्ध करायेंगी।

यह सभी कार्य ईज ऑफ लिविंग में है। यानी केवल व्यवसाय की सुगमता नहीं होगी बल्कि हर व्यक्ति को जीवन की सुगमता के साथ जोड़ने का काम भी ईज ऑफ लिविंग के साथ जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। ईज ऑफ लिविंग का आधार है 2021-22 का प्रदेश सरकार का यह बजट, जिसे हमारे वित्त मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत किया है। महोदय, किसानों के बारे में बड़ी चर्चा होती है, और पहले ही दिन से हम लोग चर्चा सुन रहे हैं, अलग-अलग चीजें अलग-अलग बातें सामने आईं। मैंने सोचता था कि नेता प्रतिपक्ष इस दौरान हम सबको राम रतन का हलवा खिला ही देंगे लेकिन लगता है कि खिलाने की उनकी आदात हैं नही। मैंने खन्ना जी से कहा कि आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं,आपको दलीय नेताओं के घर जाकर कभी-कभी उनका हाल-चाल लेना चाहिए कभी-कभी भोजन आदि करके आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक बार हमें भोजन पर बुलाये थे, बाटी-चोखा की दावत देने के बाद कहने लगे कि बर्तन साफ करते हुए तो जाइये। (सदन में हंसी) तो कहा कि जब ऐसा कार्य करने लग जायेंगे तो कैसे काम चलेगा ? यानी कुछ देंगे नहीं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूँगा। आज जिस हलुवा की बात कर रहे हैं, आपने उस संदर्भ में कहा जो कान्ट्रैक्ट खेती के सम्बन्ध में था।

श्री योगी आदित्यनाथ-

कान्ट्रैक्ट फार्मिंग।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हाँ कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के सम्बन्ध में आपने कहा था। हलुवा सही में उसका सुन्दर है और उच्चारण बाबा का भोग लगता है। लेकिन उसने कहा है कि मैं मार्केट से गाजर खरीदता था और बर्तन धोने वाली जो बात है, आप खड़े होकर बताइये। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ इशारा करके) खड़े होकर बताइये ना, जो माननीय नेता सदन ने कहा है, क्या वह सही है ? माननीय नेता सदन, वहाँ के किसान से भी जाकर सूचना विभाग के लोगों ने पूछा कि कान्ट्रैक्ट खेती करते हो ? कहा कि मैं तो अपना खेती, अपना करते हैं और दुकानदार ने भी कहा कि मैं मार्केट से, किसानों से खरीदता हूँ अभी कोई कान्ट्रैक्ट खेती नहीं करता हूँ और अगर आपको हलुवा खाने का है तो जब सदन बन्द होगा, मैं जाऊँगा तो आपके लिए पहुँचा दूँगा। (हँसी) माननीय अखिलेश यादव के यहाँ वह हमेशा हलुता आता था, श्रीमती इन्दिरा गाँधी के वहाँ भी वह हलवा जाता था। आपके यहाँ भी आ जायेगा, लेकिन कान्ट्रैक्ट खेती का जो आपने संदर्भ दिया था, वह सत्य से बिल्कुल परे था। दुकानदार ने ना कर दिया, किसान ने ना कर दिया। बर्तन साफ करने वाली बात पर मैंने कहा कि वह कहें तो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अपने इतिहास में एक व्यक्ति का नाम अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता। उसने यह कहा था कि जिसने 30 बसन्तें बिताई हों, यानी 30 साल की जिसकी उम्र हो,

कम से कम उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है। (हँसी) लेकिन मैं बड़े आश्चर्य के साथ कहता हूँ कि माननीय नेता विरोधी दल तो, मैं समझता हूँ कि 70 बसन्तें बिता चुके हैं। (हँसी) अब उन्हें कम से कम इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि नेता सदन ने जिस परिप्रेक्ष्य में और क्या कहा, मान्यवर, उनको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए। लेकिन 70 बसन्तें देखने के बाद भी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अरे, बर्तन धोने वाली बात बताइये न।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अभी आप समझ नहीं रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

यह तय हैं कि नेता प्रतिपक्ष सदन को हलुवा खिलायेंगे नहीं। अगर पूरे सदन को खिलायेंगे तो मैं भी खाऊँगा। मैं अकेले नहीं जाऊँगा, खन्ना जी की तरह। (हँसी) अब आप जब खिलाते ही नहीं तो फिर कैसे जायेंगे ?

श्री राम गोविनद चौधरी-

यह आपका कहना सही है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

यही तो हम कह रहे हैं। अगर आप खिलाये होते।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपने भी कभी हम लोगों को नहीं खिलाया।

श्री योगी आदित्यनाथ-

नहीं-नहीं, मैंने तो बहुत बार खिलाया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपने भी कभी हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया, खाना तो खाना है, कह देते कि चाय आकर पी लीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

देखिए, जितने भी अतिथि मुख्य मंत्री आवास पर आते हैं, मुख्य मंत्री आवास पर आने वाले हर अतिथि के निमंत्रण का पहला निमंत्रण नेता प्रतिपक्ष को जाता है और बड़े सम्मान के साथ जाता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वह तो हर सरकार में जाता है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

नहीं, हर सरकार की बात नहीं है। यह औपचारिकता से भी हट करके जाता है। तो मान्यवर, यह राम रतन का हलवा अगर नेता प्रतिपक्ष, सभी मा0 सदस्यों को खिलाए होते तो सम्भवतः कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में वे प्रश्न सदन में नहीं उठाते, क्योंकि इनके विधान सभा क्षेत्र में ही सहतवार कस्बे में यह सब होता है और वास्तव में यह तो हम दो लोगों की आपसी सहमति के आधार पर होता है। पुराने समय में कोई भी कान्ट्रैक्ट , किसी लिखित दस्तावेज के आधार पर नहीं होता था। यह तो बाद में समय के अनुरूप बदला है, लोग मॉर्डन होते गए, नई तकनीक आती गयी। पहले केवल बड़े बुजुर्गों के सामने सारी बातें हो जाती थीं, बाद में कागज के टुकड़े में लिखकर सहमति हो जाती थी, फिर स्टैम्प पेपर में हो गया, अब ई-स्टैम्प आ गया है। तकनीक बदली है, समय बदलता है और परम्परा दशकों से चली आ रही है। किसी किसान की आज तक खेती नहीं ली गई है लेकिन किसान की आमदनी जरूर बढ़ी है। वैद्यनाथ जी ने ऐसे ही क्रान्ति बुन्देलखण्ड क्षेत्र में की है। उन्होंने ढिंढोरा नहीं पीटा है जबकि इसका खूब प्रचार होना चाहिए था जिससे हम अन्य लोगों की आमदनी को भी उसके साथ जोड़ करके उनको भी इसके लिए प्रेरित कर सकते। यह किसानों के हित में होगा लेकिन यह सब भी नहीं हुआ। आज जब उसको कानूनी स्वरूप दे करके किसानों की आमदनी को बढ़ाने की दिशा में नया प्रयास प्रारम्भ हुआ है तो उसको हमें गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, गलत मोड़ नहीं देना चाहिए और फिर किसानों को एक विकल्प दिया गया है, बाध्यता नहीं है। आपकी मर्जी आप करिए, नहीं मर्जी मत करिए। लेकिन इसके नाम पर किसी को टारगेट करना, यह अन्याय है।

किसानों के साथ भी है और मुझे लगता है कि देश के साथ भी है। भारत के अन्नदाता किसानों को, भारत की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने पूरा महत्व दिया है। हमारी सरकार जब आई तो हमने पहली कैबिनेट तब तक नहीं की, जब तक हम लोग प्रदेश के अन्दर लघु और सीमान्त किसानों के 01 लाख रुपये तक के कर्जे को माफ करने की कार्य योजना नहीं तैयार कर पाए और पहली कैबिनेट में हम लोग वही प्रस्ताव ले करके आए। प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे चलाया है। अब उस किसान के बारे में कोई हमसे कहे, हमें सर्टिफिकेट देने लग जाए कि साहब, किसान यह कर रहा है, किसान वह कर रहा है। किसान के साथ यह हो रहा है। मण्डियों को ईनाम से जोड़ने व वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था है। ईनाम से जोड़ने की यह कार्यवाही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही की है। यह अपने आप में एक नया परिवर्तन है, समय के साथ सबको जोड़ने का प्रयास है और कैसे हम उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, ये कार्य इस सरकार के दौरान यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ाए गए हैं। महोदय, उसी दिशा में सरकार ने यह योजना बनाई। वह खाद्यान्न के प्रिक्योंरमेंण्ट की हो या उन योजनाओं के साथ किसानों को जोड़ने की हो, स्वायल हेल्थ कार्ड हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो तो कितना व्यापक परिवर्तन इस क्षेत्र में हो रहा है। दशकों से लम्बित परियोजनाओं को एक साथ पैसा दे करके

पूरा कराया जा रहा है। यह किसानों की लागत को कम करेगा, आमदनी को बढ़ाएगा। किसान की आमदनी तब बढ़ेगी, जब उसकी लागत कम होगी तो आमदनी बढ़ेगी ही। हम एम0एस0पी0 के लिए क्रय केन्द्र स्थापित करेंगे, हमारी मण्डियाँ चलेंगी लेकिन मण्डी के साथ-साथ हम किसान को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको सरकारी मण्डी में ही फसल लेकर आनी है। अगर कृषि मण्डी में उसे दास एम0एस0पी0 के बराबर मिल रहा है, 1975 रुपये गेहूँ का दाम अगर मण्डी में 1975 रुपये है और मार्केट में कोई व्यापारी उसको 2500 रुपये में देना चाहता है तो किसान स्वतंत्र होगा कि वह 2500 रुपये में अपना गेहूँ बेच करके आ जाए और कोई उसको रोकेगा नहीं। मण्डी के अधिकारी, मण्डी का कोई कर्मचारी वहाँ छापामारी करने के लिए नहीं जाएगा। कोई वहाँ अतिरिक्त टैक्स लेने के लिए नहीं जाएगा। आज तो यह सुविधा किसानों को दी जा रही है लेकिन किसानों को गुमराह किया जा रहा है।

किसानों को तमाम प्रकार से गुमराह करने का काम हो रहा है। यहाँ पर चीनी मिलों की भी चर्चा हो रही थी। महोदय, प्रदेश के अन्दर मुझे सदन को बताते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है कि अब तक हम लोग 01 लाख 25 हजार 261 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को कर चुके हैं। यह 19 मार्च तक का डाटा है। 01 लाख 25 हजार 261.48 करोड़ रुपये यह प्रदेश के अन्दर गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। पेराई सत्र वर्ष 2020-21 में हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप था तब भी हमने चीनी मिलें चलाई 119 चीनी मिलें चली, जून तक चीनी मिलें चलीं। हम भी जानते थे कि गन्ने में अब रस कम है, चीनी मिलों के लिए घाटे का सौदा है लेकिन अन्नदाता किसान को परेशानी न हो। किसान हमारी शीर्ष प्राथमिकता पर है। किसान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता है कि चीनी मिलें चलेंगी तो इससे रोजगार का भी सृजन होगा और किसान का गन्ना भी चीनी मिल में जायेगा तो किसान के पास पैसा आएगा यह कार्य पहली प्राथमिकता है कि गन्ने की फसल की सुरक्षा हो और उसको उसका भुगतान हो और महोदय अगर हम केवल वर्ष 2019-20 के आंकड़े देखेंगे तो अब तक 98.5 फीसदी गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का हो चुहा है मात्र 538 करोड़ रुपये का बकाया है। अभी करेन्ट सत्र में जब गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है इसमें 10757 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। 52.5 प्रतिशत का भुगतान हो चुका है यानि कोविड-19 के बावजूद एक्सपोर्ट की सम्भावनायें कम दिखती हैं सबके बावजूद भी करेन्ट सीजन में 10757 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। 9700 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का करेन्ट सीजन का बाकी है जिसको तेजी के साथ भुगतान करने के साथ जोड़ने की कार्यवाही हो रही है। यह है किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का आधार। जब हम लोग 2017 में आये थे तो उस समय वर्ष 2011-12 के गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था और जहाँ तक आप पूछ रहे थे कि क्या किया गन्ना किसानों के लिए अगर मैं एक तरफ से आपको बताने लग जाऊँगा कि रामकोला की चीनी मिल वर्ष 2007-08 में बन्द हुई, लक्ष्मीगंज वर्ष 2008-09 में, देवरिया की वर्ष 2007-08, भटनी वर्ष 2007-08, बैतालपुर वर्ष 2008-09, शाहगंज वर्ष 2007-08, बुढ़वल वर्ष 2007-8, घाटमपुर वर्ष 2009-10, छाता वर्ष 2009-10, औराई वर्ष 2007-08, घुरियापार वर्ष 2007-08, कमलापुर वर्ष 2009-10,

सठियांव वर्ष 2007-08, मझौला वर्ष 2010-11, दरियापुर वर्ष 2009-10, कांगलहेड़ी वर्ष 2011-12, मंझावली वर्ष 2011-12, पिपराइच वर्ष 2008-09 और पुआया वर्ष 2011-12 में बंद हुईं और वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017 के बीच में जो चीनी मिलें बन्द हुईं उनमें पडरौना, टोडरमल, सहारनपुर, अमरोहा, बघौली, सरदारनगर, खलीलाबाद, रसड़ा, बस्ती, गोपीगंज, बुलन्दशहर ये चीनी मिलें इनके समय में बन्द हुईं। जो चीनी मिलों को बन्द कर रहे हैं वह किसानों के हितैषी हो गये और जो चीनी मिलों को चला रहे हैं। हम लोगों ने तो चीनी मिलों को चलाया भी है (मेंजों की थपथपाहट)।

महोदय, कांगलहेड़ी का चीनी मिल का हम लोगों ने वर्ष 2017-18 संचालित कर दिया है, मंझावली का वर्ष 2017-18 में, बुलन्दशहर वर्ष 2017-18, पिपराइच और मुण्डेरवा वर्ष 2018-19 में नयी चीनी मिलें लगाकर इनका पुनःसंचालन भी कर दिया गया है। यानि हम चीनी मिलों को चला रहे हैं तो हम किसान विरोधी हैं और कोई चीनी मिलों को बेंच रहा है, कोई बन्द कर रहा है, वह किसान हितैषी हो गया। ये कहाँ का अर्थशास्त्र है और यह कहाँ से हितैषी हो गये। मुझे आश्चर्य होता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वर्ष 2003 से 2007 के बीच कितनी चीनी मिलें लगी हैं वह भी बता दें। करीब 25 चीनी मिलें मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने प्राइवेट सेक्टर से लगवायी, यह तो आप कहेंगे ही नहीं, जबकि आप उनसे प्रेम भी रखते हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

देखिय एक बात बताऊँ मैं कि उस दौरान जो चीनी मिलें लगी हैं उन्हीं पर गन्ना मूल्य का ज्यादा भुगतान बकाया है, एक सच्चाई यह भी सुन लीजिए। सारी लड़ाई तो बकाये को लेकर है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

25 मिलें मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकार में लगवायी। मा0 अखिलेश यादव जी ने दो मिलें लगायीं उसको भी कह दीजिए कभी-कभी किसी की बड़ाई भी करनी चाहिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

देखिये चीनी मिलें क्यों बन्द हुई मैं यही पूछना चाहता हूँ हमारे समय में कोई चीनी मिल बन्द नहीं हुई।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

निगम की 21 चीनी मिलें क्यों बन्द हो गयीं ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

इसके लिए लाल जी वर्मा जी से पूछिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

निगम की 21 चीनी मिलें आपके राज में बन्द हुईं जब आपकी वहाँ सरकार थी। आपकी जब वहां पर सरकार थी, तो निगम की 21 चीनी मिलें बन्द हो गई थीं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना जारी रखिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

देखिए, विकास का जब एजेण्डा होता है, तो व्यक्ति विकास पर बोलता है और विकास के अनुरूप कार्य भी करता है लेकिन जब विकास का कोई एजेण्डा ही नहीं होता है, तो फिर व्यक्ति के मन में जो आता है, वह अपने अनुसार उसको बांचता रहता है, परन्तु जब तथ्य सामने आते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है और यह तथ्य उस जवाब का ही परिणाम है, जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ और जो मैंने आपको बताया है कि किस रूप में यह हुआ है। महोदय, वर्ष 2020-21 में रबी की फसल के लिए गेहूँ केन्द्र स्थापित करने थे परन्तु लॉकडाउन प्रारम्भ हो गया था। इस सबके बावजूद हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर 5 हजार 8 सौ 96 क्रय केन्द्र स्थापित किये, 35 लाख 76 हजार मिट्रिक टन गेहूँ का क्रय किसानों से सीधा किया और 6 हजार 8 सौ 85 करोड़ रुपये का ऑनलाइन भुगतान भी किया। खरीफ विपणन जो वर्ष 2020-21 का ही था, "मूल्य समर्थन योजना" के अर्न्तगत धान क्रय केन्द्रों के लिए अब तक 66 लाख मिट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया गया और 11 हजार 2 सौ करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन भुगतान भी किसानों को सीधे किया गया है। अब भुगतान ऑनलाइन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले चेक के माध्यम से या अन्य कारणों से होता था, आज तो वह नहीं है। अब सीधे भुगतान किसानों के खाते में जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह पैसा दलालों को जा रहा है या अन्य लोगों को जा रहा है। यह तो किसानों को देने का कार्य है।

महोदय, इसी दौरान खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 108 मक्का क्रय केन्द्र स्थापित किय गये, जिसमें 1 लाख 6 हजार मिट्रिक टन मक्के की खरीद की गयी और 197 करोड़ रुपये का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किसान के खाते में किया गया है। 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना', अभी मैंने पिछले दिनों ही सदन में ही अवगत कराया था कि बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भारत सरकर ने उत्तर प्रदेश को पुरस्कार दिया है। आज के दिन पर 2 करोड़ 42 लाख किसाान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पात्रता रखते हैं। एक ही दिन में प्रदेश के किसानों के खाते में 27 हजार 123 करोड़ रुपये सीधे डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों के खाते में गये हैं। 'मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का दायरा बढ़ाया गया है। 5 लाख रुपये का बीमा, जिसमें किसी भी आपदा में किसान, किसान का परिवार, उसका सहयोगी या उसका बटाईदार, यह सभी उसके दायरे में आयेंगे। यह सामाजिक सुरक्षा किसानों के लिए है। यह किसान को दिया जा रहा है और यह सुरक्षा देने के साथ ही इसके दायरे को बढ़ाने का कार्य किया गया है। प्रदेश के हर किसान को आयुष्मान भारत की योजना के कारण, वर्ष 2011-12 में जो राज्य की सरकारें थीं, जिनको वास्तव में गरीबों की चिन्ता नहीं थी, हर किसान को 'आयुषमान भारत योजना' के अन्दर लाने और जो नहीं आ पाया है, उसको हम

'मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजा' से आच्छादित करने के लिए भी इस बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया है।

महोदय, वर्ष 2021-22 के इस बजट में किसानों के लिए ही आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना' के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गयी है। यह किसानों के हित के लिए की जा रही योजनाएं हैं। किसानों को खेती के साथ-साथ समय पर बीज उपलब्ध हो जायें, उन्नत तकनीक के बीज मिल जायें, खाद उपलब्ध हो जाये, यह व्यवस्था तो लागू की जा रही है। हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर एक व्यवस्था बनायी है। खासतौर पर कृषि विज्ञान केन्द्रों की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी की है। कृषि विज्ञान केन्द्र बहुत बड़ा कार्य करते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों की भूमिका बहुत अच्छी और बहुत सकारात्मक है। तकनीकी ज्ञान से किसान को जोड़ने के लिए, खेती के विविधीकरण के लिए भारत सरकार कृषि विज्ञान केन्द्र देना चाहती थी, राज्य सरकार लेना ही नहीं चाहती थी। वर्ष 2016 के बाद वर्ष, 2017 में जब हमारी सरकार आयी तो वर्ष, 2017-18 में हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्र अतिरिक्त लिए। आज प्रदेश के अन्दर हर जनपद में लगभग एक कृषि विज्ञान केन्द्र है और बड़े जनपदों में 02 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ करके तकनीकी ज्ञान से किसानों को आच्छादित करने के सम्यक्र प्रयास प्रारम्भ हुए हैं लेकिन साथ-साथ प्रदेश में किसानों को मुफ्त पानी भी मिले इसके लिए 700 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था भी इस बजट में की गयी है। सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अन्तर्गत भी बजट में 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्रियान्वयन के लिए जो अब फंक्शनल हो चुके हैं उसमें सरका के द्वारा विकास को इंसेन्टिव दिये जाने हैं या फिर उद्योगों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है। केमिकल और फर्टिलाइजर के भण्डार के लिए, स्टोरेज के लिए बजट की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

किसानों को नाबार्ड से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की योजना का प्राविधान किया गया है और एकीकृत सहकारी विकास के माध्यम से भी सहकारी समितियों के समन्वित विकास हेतु जो संचालित योजना है उसके लिए भी बजट में प्राविधान किये गये हैं। यह सब कार्य किसानों के लिए ही किये जा रहे हैं। ये किसान की लागत को कम करने और उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की शासन की योजना का हिस्सा है और इसको समझने की आवश्यकता है लेकिन उसको समझने की बजाय हम उसको नकारात्मक दृष्टि से लेने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम्य विकास की तरफ देख रहा था, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 04 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिला करके 40 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का काम हुआ और साथ-साथ मुख्य मंत्री आवास योजना में भी बहुत सारे गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया। लगता है कि इनके एजेण्डे में बहुत सारे लोग नहीं थे। कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर कमिश्नरी और काशी कमिश्नरी में मुसहर जाति काफी बड़ी मात्रा में हैं और मुझे लगता है कि बहुत हैण्ड-टू-माउथ हैं।

प्रदेश सरकार ने पहले चरण में निर्णय किया कि मुसाहर जाति का जो व्यक्ति जहां पर रह रहा है उस जमीन का पट्टा उसको कर दिया जाय। एक गरीब को जीने का अधिकार मिलना चाहिए और अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो उस आरक्षित श्रेणी की भूमि पर व्यवस्थित पुनर्वास करने के लिए कोई सुरक्षित भूमि उसको उपलब्ध कराने का कार्य किया जाय। यह कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हम लगभग आच्छादन की तरफ बढ़ चुके हैं। देश के अन्दर वर्ष 1910 और वर्ष 1920 के बीच में मुसहर जाति, वनटांगिया गांव बसाये गये थे। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत ऐसे तमाम जिलों में 1947 से ले करके 1952 में देश ने पहला आम चुनाव किया। 1950 में अपना संविधान अंगीकार किया। मतदाता सूची में भी उनका नाम नहीं चढ़ाया गया। उनके लिए न बिजली, न पानी, न सड़क, न स्कूल, न स्वास्थ्य की सुविधा, न राशन कार्ड की व्यवस्था और न ही उन्हें पेन्शन की सुविधा मिलती थी, वे सब गरीब थे, सुविधाओं से वंचित थे। हम लोगों ने संसद में वर्ष 2007-08 में उसकी लड़ाई लड़ी थी, भारत सरकार ने कानून भी बना लिया था लेकिन इम्पीलमेंट तो राज्य को करना था और महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2017-18 में वनटांगिया गांव के विकास के लिए हमने योजना बनाकर उन्हें राजस्व गांव का दर्जा देना प्रारम्भ किया और आज आप जाईये, जहां पर एक भी पक्का मकान नहीं था, जहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, आज वहां सारी सुविधायें मिलती हुई दिखायी दे रही हैं। आज उनके पक्के मकान बन रहे हैं आज उनके चेहरे की चमक तो देखिये न।

आज जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, उस तबके को टच करने का प्रयास हुआ है, जो अब तक वंचित था। यह भी दलित ही थे, अति पिछड़ी जाति के थे। आखिर वह आपके एजेण्डे का हिस्सा क्यों नहीं बन पाये, क्यों नहीं वनटांगियों के लिये काम हुआ। वे प्रदेश के नागरिक थे वनों के संरक्षण के लिये उन्हें बसाया गया था लेकिन नहीं हुआ। थारू, आज भी उनकी कनेक्टिविटी की वही स्थिति है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज इन जनपदों में कुछ गांव हैं, हमने उनको वहाँ पर सुविधा देना प्रारम्भ किया। मुख्य मंत्री आवास योजना यानि जब एस0ई0सी0सी0 का सर्वे हुआ, उस समय इन लोगों को छोड़ दिया गया था और जब यह आच्छादन पूरा हो रहा है इस बार हम लोगों ने बुन्देलखंड की एक-दो जातियाँ जो हमेशा से वंचित रही हैं क्योंकि उसकी कोई वॉयस नहीं थी, इसलिये उन्हें वंचित किया गया था हम लोग उसको जोड़ रहे हैं। हमने इसमें कोल जाति को भी लिया है कोल और अन्य जितनी भी जातियां होंगी, कुछ लोग ही हैं, कोल जाति से जुड़े हुये लोग हैं, बुन्देलखंड की उन जातियों को भी हम लोगों ने अब इस योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया है कि मुख्य मंत्री आवास योजना इन लोगों को आवास उपलब्ध करायेगी। शर्त और नियम वही है शर्त को प्रदेश सरकार ने तय की है लेकिन नियम, कि जिन लोगों के पास आवास नहीं है जो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वंचित रह गये हैं, हम उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

यह आवास की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है, मुझे प्रसन्नता है 2017-18 मे 16,700 लाभार्थियों को, 2019-20 में 34,040 लाभार्थियों को और 2020-21 में 30,250 लाभार्थियों को इस योजना में लाभान्वित किया गया और 2021-22 के बजट में 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था मुख्य मंत्री आवास योजना में इन गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिये की है। गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 8,847 कि0मी0 कार्य को हम लोगों ने एक नई योजना के तहत लिया है और इसमें भी 2021-22 मे 5 हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान इसके लिये कर दिया गया है। महोदय, गांव की स्थिति, गाँव हमारे मिनी सचिवालय हैं, गांव हमारे विकास के आधार स्तम्भ हैं, गांव के विकास के बगैर हम प्रदेश के और देश के विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने कुछ जो गांव बड़े कस्बों में तब्दील हो गये थे उन्हें हमने नगर निकाय के रूप में बदलने का काम किया। लेकिन आज भी 80 फीसदी उत्तर प्रदेश की आबादी गांव में निवास करती है और हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार अगर हमारे पास अच्छी खेती नहीं होती, जल संसाधन नहीं होते तो कोरोना में हमारी अर्थव्यवस्था लुढ़क गयी होती। हमारा आधार बना था खेती-किसानी, गाँव और हमारा युवा। इस दौरान भी उसने अपनी खेती को संभाला। उसकी नौकरी कटी तो वह गाँव में आकर अपनी खेती में जुट गया, अपना पसीना बहाया और आज उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है। हम लोगों ने कहीं भी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं आने दी, जहाँ पर किसी को कहने की आवश्यकता पड़ी हो और कोई यह कहे कि उत्तर प्रदेश लाचार हो चुका है, हताश हो चुका है, नहीं हम लोगों ने तो कभी नहीं इस चीज़ को माना है। हम लोग तो इस बात को मानकर चलते रहे हैं कि-

सागर की अपनी क्षमता है
पर मांझी भी कब थकता है।
जब तक सांसों में स्पन्दन है
उसका हाथ नहीं थकता है
इसके बल पर कर डाले सातों सागर पार
और महोदय यही उत्तर प्रदेश के विकास का है आधार।

यही है हमारा आधार। उस जगह ग्राम पंचायतों में जहाँ पंचायत भवन नहीं हैं हमारी सरकार द्वारा पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय के साथ-साथ गांव के सार्वजनिक कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिये भी एक बड़ी व्यापक कार्य योजना के साथ कार्य प्रारम्भ हुआ है।

प्रयास किया जा रहा है कि हर एक न्याय पंचायत में कम से कम इससे छूटे हुए जो गाँव बचते हैं, उनमें से कोई दो गाँव हम लोग लेंगे, जिसमें महान क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद जी के नाम पर ग्रामीण विकास सचिवालय के निर्माण की कार्य योजना को हम उसके साथ जोड़ेंगे (सत्ता के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) और मुख्य मंत्री पंचायत प्रोत्साहन

योजना के अन्तर्गत भी हम लोग एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है, उत्कृष्ट ग्राम पंचायतें, क्या यह हो सकता है कि हम गाँव की पंचायत को गाँव के विकास के साथ जोड़ें। अब तो बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर गाँव में हो चुके हैं। गाँव के लोगों को गाँव के किसी भी व्यक्ति को आय प्रमाण, पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र यह सभी गाँव में ही बन सकते हैं। हम उन्हें बैंकिंग सुविधा के साथ जोड़ रहे हैं, बिजली के बिल को उसके साथ जोड़ रहे हैं कि यह बिजली के बिल के लिए वहाँ दफ्तर या कार्यालय में न जायें। वहीं पर अपना बिजली का बिल जमा कर लें और बिजली के बिल जमा करने के लिए हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह को भी यह व्यवस्था दी है कि वह जमा करायेंगे तो इसके बदले में 12 से ले करके 20 रुपये प्रति बिल उसको प्राप्त हो जायेंगे। यह भी सुविधा दे दी गई है। कितना व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है। ये प्रोत्साहन की व्यवस्था है और इसी प्रकार से ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण के लिए भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत भी जो ग्राम सचिवालय के निर्माण यानी ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण की कार्यवाही हो रही है, इसके लिए भी 653 करोड़ रुपये की व्यवस्था अलग से की गई है। एक गाँव के विकास की धुरी, ये केन्द्र-बिन्दु बने, उसको उसके लिए जोड़ा जा रहा है और ई-गवर्नेंस के लिए भी पंचायत सशक्तिकरण के तहत धनराशि की व्यवस्था बजट में कर दी गई है। महोदय महिलाओं के सशक्तिकरण की बात चल रही थी और इसमें अनेक चर्चायें होती है और मुझे लगता है कि पूरे सदन को इसके बारे में विचार करना चाहिए। 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और मैं पूरे सदन से अपील करूँगा कि 8 मार्च के दिन हर विधान सभा स्तर पर, हर जनपद स्तर पर महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम होने चाहिए। राज्य सरकार इसके लिए कार्य-योजना बना रही है और ये कार्यक्रम करने चाहिए। आधी आबादी को सम्मान मिलना ही चाहिए, (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) हर स्तर पर मिलना चाहिए। उस व्यापक कार्य योजना के साथ हमें जुड़ना चाहिए। हम लोगों ने इसके लिए एक व्यवस्था की है। 2019-20 में मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये उन बालिकाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था का कार्य इस सरकार ने प्रारम्भ किया था और बजट में 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बार भी की गई है कि इसको कैसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे किसी भी प्रकार से कन्याओं के प्रति भेदभाव को समाप्त किया जा सके। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसी सदन में जब हम लोग इस योजना की घोषणा किये थे तो नेता प्रतिपक्ष नाराज हुए थे। उन्होंने कहा कि यह तो गरीबों का अपमान है और आज डेढ़ लाख से अधिक कन्याओं की शादी मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत हुई है (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई) और मुझे लगता है कि सदन सहमत होगा कि सबसे अधिक डिमाण्ड इस योजना की है। यानी इसका मतलब गरीबों से आपको कोई मतलब नहीं है। गरीब कन्याओं के बारे में आपके मन में कोई सम्मान नहीं है लेकिन राज्य सरकार ने अपनी कार्य योजना को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। कुछ योजनायें नई भी हैं, मुख्य मंत्री सक्षम सुपोषण योजना,

कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार की योजनायें तो थीं, भारत सरकार की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार अपने स्तर पर भी ऐसे लोगों को चिन्हित करके मुख्य मंत्री सक्षम सुपोषण योजना को भी इसके साथ जोड़ेगी, जिसमें 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों और एनेमिया से ग्रसित जो बालिकायें हैं, 11 से 14 वर्ष की जो किशोर बालिकायें हैं। उनके लिए अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रदेश सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया है। यह भारत का भविष्य है, यह जो कुपोषित बच्चे हैं उन बच्चों को सुपोषित करना पूरे समाज का दायित्व है और इस दायित्व का बोध सरकार करा रही है, उसी के साथ उन बच्चों को जोड़ रही है। वह बच्चा इस धरती पर आया है उसने कोई अपराध नहीं किया है अगर किन्ही कारणों से किसी ऐसे परिवार में उसने जन्म लिया है जहाँ पर उसके पास उस प्रकार की सुविधा नहीं हैं तो उसे कुपोषित से सुपोषित करने का दायित्व सरकार निभायेगी, सरकार उस दायित्व के साथ अपने आपको जोड़ेगी। किशोरियों के साथ जो भेदभाव होता था उस भेदभाव को दूर करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। पहले से कुछ व्यवस्थाएं चल भी रही हैं, भारत सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत फोकस किया है। याद रखना ये योजनाएं सफल होंगी तो प्रदेश के अन्दर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के जो रेट हैं वह अपने आप न्यूतम स्तर तक पहुंच जायेंगे, जो अभी कभी-कभी डराने लगते हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए धन की व्यवस्था की गई है और महोदय इस बार हम लोग एक ऐसी नई योजना को भी महिलाओं के लिए चलाना चाहते हैं जिसका एक उदाहरण बुन्देलखण्ड में है। ग्राम्य विकास विभाग और भारत सरकार के सहयोग से एक कार्य योजना पर प्रारम्भ हुई थी बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से। महिलाओं ने कितना जर्बदस्त काम किया है, बहुत अभिनन्दनीय कार्य किया है, एक वर्ष में 46 करोड़ का टर्नओवर और 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2019 में हमने इसे प्रारम्भ किया था। इस प्रकार की कुछ अच्छी योजनाएं प्रदेश के अन्दर न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर हम लागू कर सकें, इसके लिए भी बजट में हमने 2 सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है कि सरकार महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत ऐसी महिलां स्वयं सेवी संगठनों को प्रोत्साहित करने और एन0जी0ओ0 को प्रोत्साहित करने का कार्य करे। आप समझ सकते हैं 100 महिलाओं का समूह किसी एक कार्य के साथ जुड़ा हुआ है और एक साल का उनका टर्नओवर 46 करोड़ तक पहुंच जाए और प्रॉफिट 2 करोड़ का हो जाए तो यह अभिनन्दनीय कार्य है, महिलाएं इस कार्य को कर रही हैं और महिला सशक्तीकरण का यह उदाहरण है, इस कार्य को उस रूप में हमने जोड़ने का कार्य किया है। महोदय, इसके साथ ही निराश्रित पेंशन की योजनाएं, प्रदेश के अन्दर इसके दायरे को भी बढ़ाने का कार्य हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर कार्य हुए हैं, हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर जो कार्ययोजनाएं इसकी बनायीं इसमें भी अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। आज प्रदेश के अन्दर चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो या फिर निराश्रित महिला पेंशन हो, इन पेंशन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य भी हम लोगों ने अच्छे ढंग से प्रदेश के अन्दर किया है। काफी बड़ी संख्या में, इस समय प्रदेश के अन्दर 87 लाख लाभार्थी हैं, जिसमें निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन योजना और दिव्यांगजन पेंशन योजना से

आच्छादित है। कोविड कालखण्ड के दौरान राज्य सरकार ने एडवांस में इनको पेंशन की राशि उपलब्ध करवायी तो 1 हजार रुपए उन पेंशन धारकों को अतिरिक्त देने का कार्य भी हुआ। यानी कि ये सभी कार्य प्रदेश के अन्दर इन तीनों पेंशन योजनाओं के माध्यम से हुए। प्रदेश के अन्दर बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1535 थानों में साढ़े तीन सौ तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क के निर्माण की कार्यवाही की गई और उसको वहाँ पर चालू भी कर दिया गया है।

यह प्रदेश के अन्दर हुआ है। महोदय, प्रदेश के अन्दर कुछ कार्य आगे बढ़ने थे जिस पर हम लोगों ने फोकस किया है। प्रदेश के अन्दर पिछले चार वर्ष के अन्दर चार लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गयी हैं। आज उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, पुलिस भर्ती को कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता है। जितनी भर्ती हुई है, ट्रांसपेरेन्ट तरीके से हुई है। उसमें पूरी पारदर्शिता लाने का प्रयास हुआ है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है।

महोदय, हर एक स्तर पर जहाँ भी किसी ने कोई गड़बड़ी करने का प्रयास किया है, तो उस व्यक्ति के साथ-साथ पूरा खानदान जेल के अन्दर सड़ता हुआ दिखायी दे रहा है (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई।) भर्तियों में अब कोई वसूली का धन्धा नहीं बना सकता। नौजवान युवकों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, लेकिन चार लाख सरकारी नौकरियाँ उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान अन्य विकल्पों की तलाश में काम करते हैं, खासतौर पर उन्होंने निजी क्षेत्र में भी संभावनाएं तलाशी जब प्रदेश के अंदर निवेश हुआ, संभावनाएं बढ़ी तो आज बहुत सारे फील्ड में नौजवानों को नौकरी मिली है, रोजगार मिले हैं।

महोदय, कोविड के दौरान लोगों को इसी बात का अश्चर्य था कि आखिर यू0पी0 में जो 40 लाख प्रवासी लोग आएंगे, वह कहाँ जाएंगे ? हमने कहा कि यू0पी0 अपने एक करोड़ प्रवासी कामगार और श्रमिकों को अपने यहाँ रखकर उनकी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)। ये हमारा 40 फीसदी ही अभी आया है, अभी 60 लाख और हैं, उनके लिए भी भूमिका तैयार हो चुकी है। जिस दिन वे आएंगे, उत्तर प्रदेश की इकॉनमी 'वन ट्रिलियन यू0एस0 डालर' के बराबर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजे थपथपाईं)। इन युवाओं के बल पर। महोदय, नौजवानों की ऊर्जा और दक्षता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक अभिनव योजना प्रारम्भ की है जिसका नाम है "मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना" पहले चरण में प्रत्येक मण्डल स्तर पर इनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गयी है। जो लोग उपस्थित हो सकते हैं, वह फिजिकली वहाँ जाएंगे, वहाँ पर साक्षात जाकर इसका लाभ लेंगे और जो लोग साक्षात उपस्थित नहीं हो सकते, उनके लिए वर्चुअली व्यवस्था दी गयी है। अब तक लाखों यूथ उसके साथ जुड़ चुके हैं और अन्य राज्यों में इसकी माँग हो रही है कि यू0पी0 के "अभ्युदय योजना" के तर्ज पर हमारे राज्यों में भी इस प्रकार की योजना लागू करिये। ये यू0पी0 मॉडल बनता जा रहा है।

महोदय, "अभ्युदय योजना" अपने युवाओं के लिए यू0पी0एस0सी0, यू0पी0पी0एस0सी0, यू0पी0एस0एस0एस0सी0, रेलवे और बैंक की तैयारी के लिए या किसी भी भर्ती के लिए भूमिका तैयार करने, गाइड देने के लिए हर प्रकार के लोग जा रहे है। हमारे सीनियर ऑफीसर्स, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, आई0एफ0एस0 भी जा रहे हैं, प्रशिक्षु आई. ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. और पी.सी.एस. भी जा रहे है, और साथ-साथ उस फील्ड के विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। दुनिया के इस फील्ड के जो विशेषज्ञ है, उनकी भी सेवाएं, इसके साथ फिजिकली और वर्चुली, दोनों प्रकार से ली जा रही है। ये "अभ्युदय योजना" उत्तर प्रदेश के नौजवानों को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को योजना समर्पित करते हुए हम लोगों ने इस बात को कहा कि बहुत सारी जगह होगा, लेकिन हम लोग हमेशा इस बात को मानते रहे कि किसी भी ऐसे समाज को जो सक्षम और दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहता है, उसको अपने को उसी रूप में तैयार भी करना होगा।

महोदय, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि "आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो"। यानी ज्ञान प्राप्ति जिस भी दिशा से हो, उसके लिए सदैव अपने मस्तिष्क को खुला रखो। उत्तर प्रदेश का युवा आज अपने मस्तिष्क को ज्ञान प्राप्ति के माध्यम के रूप में "अभ्युदय योजना" को लेकर आ रहा है और "अभ्युदय योजना" के साथ जुड़ रहा है और बदले में सरकार ने पात्रता की श्रेणी तय की है। यूथ को टैबलेट देने को सुविधा भी उसके साथ जोड़ी है, बजट में उसका प्राविधान कर दिया है और उसको बजट के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं।)

महोदय, इसके साथ ही हमारे यहाँ कुछ और चीजें हैं। उत्तर प्रदेश का सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय कभी देश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय था, अब विभिन्न राज्यों में संस्कृत विश्वविद्यालय बन चुके हैं। अनदेखी और भेदभाव के कारण संस्कृत की स्थिति लगातार खराब होती गयी, विद्यालय बंद होते गए, छात्रों की संख्या नगण्य हो गयी, शिक्षकों की संख्या समाप्त हो गयी। प्रदेश सरकार ने दो निर्णय लिये, एक जब तक परमानेंट शिक्षक संस्कृत विश्वविद्यालय में आते हैं तब तक हम लोग संस्कृत के विद्यालयों में एक निश्चित मानदेय के साथ शिक्षकों की तैनाती की व्यवस्था करेंगे। बाद में आयोग से या जो भी व्यवस्था उसकी बनती है उस व्यवस्था के साथ वहाँ पर परमानेंट शिक्षकों की तैनाती करेंगे। संस्कृत को अपनी पुरातन परम्परा के साथ-साथ अर्वाचीन व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम भी करेंगे, तकनीक के साथ भी जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम संस्कृत के माध्यम से अपने गुरुकुल की पद्धति को फिर से पुनर्जीवित करने का काम करेंगे और गुरुकुल की इस परम्परा को आगे बढ़ायेंगे। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों में, अगर कोई छात्रा भी है जो संस्कृत पढ़ना चाहती है, क्योंकि हमारे वेदों की बहुत सारी ऋचाएं तो विदुषी महिलाओं ने रची है। तो जो भी इस फील्ड में आना चाहती है उनके लॉजिंग-फूडिंग की व्यवस्था का प्रावधान भी, गुरुकुल पद्धति से इस परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने की है और यह व्यवस्था यहाँ पर प्रस्तुत की है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं) और इस बात को ले करके की है कि उनका भाव ही

लोक-कल्याण का यह भाव हर-एक स्तर पर हो और उस लोक-कल्याण के भाव को विश्व कल्याण के साथ जोड़ सकें। "वसुधैव कुटुम्बकम" के उस भाव को हम एक बार फिर से पुनर्जीवित कर सकें, यह कार्य इस योजना के माध्यम से यहाँ पर गुरुकुल पद्धति से प्रारम्भ करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही महोदय, प्रदेश के अंदर **कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम** के आयोजन के माध्यम से भी प्रदेश के यूथ के बारे में, 13 लाख युवाओं का पंजीकरण जिसमें से 9 लाख 48 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 3.50 लाख युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में उनको कार्य प्रदेश के अन्दर अब तक सम्पन्न हुआ है और यह प्रदेश के अंदर जो सरकार की कार्य योजनायें चल रही हैं उसका यह एक हिस्सा है।

युवा और खेल विकास एवं प्रोत्साहन के लिए भी सरकार ने बजट में प्राविधान किया है। महोदय, प्रदेश के अंदर महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के गठन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था और भी अन्य कार्यक्रमों जैसे-ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम, ओपेन जिम के निर्माण के लिए, खेल के मैदान के लिए, ये सभी कार्य युद्धस्तर पर आगे बढ़ सकें इसके लिए भी हम लोगों ने बजट में व्यवस्था की है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) स्पोर्ट्स के लिए मेरठ में एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के लिए भी धनराशि का प्राविधान हम लोगों ने बजट में किया है। मेरठ में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' की अपनी कार्ययोजना है। मेरठ खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्पोर्ट्स आइटम के लिए मेरठ के ही प्रोडक्ट को हम लोगों ने 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' का पार्ट बनाया है और वहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रदेश के अंदर खेल की सम्भावनाओं को कई गुना आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा, इसका भी प्राविधान इसके साथ किया जा रहा है।

महोदय, इसी के साथ ही प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत भी काफी बड़े पैमाने पर कार्य-योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, परम्परागत कारीगर हैं, उनके प्रशिक्षण, उन्हें वित्तीय संस्थाओं के साथ जोड़ना, और वित्तीय समावेशन के साथ ही उन्हें स्वावलम्बन के साथ जोड़ने के साथ ही राज्य सरकार के द्वारा उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने और यह कार्य बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर साढ़े पाँच लाख से अधिक गोवंश अब तक हमारे शासन के द्वारा संचालित निराश्रित गौ स्थलों में हैं। लगभग 78 हजार गोवंश को अब तक हम लोग सहभागिता योजना के अन्तर्गत गौ-पालकों को सौंप चुके हैं जिसमें 900 रुपये हर महीने शासन उन्हें उपलब्ध करा रहा है। कुपोषित परिवारों को भी, जो कुपोषित माँ हो या कुपोषित बच्चा जिस परिवार में है, वहाँ पर एक दुधारू गाय निराश्रित गौ आश्रय स्थल से देने का कार्य भी प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया है और बहुत ही सफलता के साथ यह योजना आगे बढ़ रही है। (मेजों की थपथपाहट) उन परिवारों को भी 900 रुपये प्रतिमाह इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया लेकिन बजट में एक नई घोषणा हम लोगों ने की है। जब कहा जा रहा था कि किसानों के लिये क्या किया गया

है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यह भी किसानों से ही जुड़ी हुई योजना है जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर निराश्रित गौ-आश्रय स्थल खोलने की व्यवस्था हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं और यह कार्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर और नगर निकाय के स्तर पर भी कान्हा उपवन के रूप में इस कार्य योजना को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। महोदय, जो मैंने पहले भी कहा कोविड-19 के लिये। टीकाकरण में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और हमने बजट में भी उसका अलग से प्राविधान भी किया है (मेजों की थपथपाहट) यद्यपि राज्य सरकार जो टीका लगा रही है वह भारत सरकार फ्री में उपलब्ध करा रही है। सारे टीके फ्री में हैं लेकिन एक विकल्प भी दिया गया है क्योंकि संक्रमण की चेन को रोकना है इसलिये यदि कोई चाहे कि वह क्यू में नहीं लगना चाहता है, यह अलग से अपनी व्यवस्था चाहता है तो उसके लिये उनको निजी क्षेत्र में भी यह व्यवस्था दे दी गई है और उसके रेट भी तय कर दिये गये हैं। यही वैक्सीन जो 250 रुपये में यहाँ के मार्केट में मिल रहा है अगर आप बाहर जायेंगे तो इसकी कीमत 5 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये के बीच में है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लोग शासन की योजना के अन्तर्ग फ्री में लगाने के इच्छुक हैं वह लोग अपनी बारी का इंतजार करें, सावधानी रखें, उन्हें फ्री में वैक्सीन मिल रहे हैं लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं हम पहले बिना क्यू के साथ चलना चाहते हैं, हम पहले वैक्सीन लगाना चाहते हैं उनके लिये एक विकल्प भी उपलब्ध करा दिया गया है और यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर पूरी तरह लागू हो चुकी है। प्रदेश में टीकाकरण के लिये जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेप होना है, अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी है, लॉजिस्टिक आदि की व्यवस्था देनी है इसमें केन्द्र और राज्य सरकार मिल करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसके लिये भी बजट की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है और यह कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। महोदय, युवा अधिवक्ताओं के लिये भी व्यवस्था की गई है। मैं यहाँ पर दलीय नेताओं के भाषणों को सुन रहा था। उनके भाषणों को जब मैंने मँगाया तो मैंने उसको देखा। उनके द्वारा अपनी अपनी दलीलें दी जा रही थी लेकिन अधिवक्ताओं के चेम्बर के लिये भी जनपद स्तर पर और युवा अधिवक्ताओं के लिये भी कौफस फंड का हो या फिर उनकी पत्रिका, पुस्तकों के क्रय के लिये धनराशि की व्यवस्था का हो, यह सभी कार्य यहाँ पर प्रदेश के बजट के पार्ट बने हैं, प्रदेश ने इसको आगे बढ़ाया है। महोदय, एक बहुत बड़ा जो हमारे सामने सबक था कोविड-19 के दौरान कामगारों, श्रमिकों का प्रदेश के अन्दर या देश के अन्दर पलायन की स्थिति। एक त्रासदी जैसी थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने तय किया हैं, यद्यपि हम पहले से इसका आयोग गठन कर चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम पहले से इसका आयोग गठित कर चुके हैं। प्रदेश के अन्दर हमारा श्रमिक और कामगार, रोजगार व सेवायोजन आयोग का गठन पहले से हो चुका है। उसने तेजी से कार्य करना प्रारम्भ भी कर दिया है, उसके साफ्टवेयर डेवलप भी हो चुके हैं, वह आगे काम कर रहा है, लेकिन हमने तय किया है निवासी हो या प्रवासी संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हमारा अनुमान है कि लगभग

2 करोड़ लेबर प्रदेश के अन्दर रहता है। 1 करोड़ संगठित क्षेत्र का और 1 करोड़ असंगठित क्षेत्र का लेबर प्रदेश के अन्दर रहता है या प्रदेश से बाहर रहता है। संगठित क्षेत्र को श्रम विभाग के द्वारा अपनी योजना के अन्तर्गत आच्छादित करने की व्यवस्था की जा रही है और जो असंगठित क्षेत्र के स्ट्रीट बेण्डर, ठेला, खुमचा, रेड़ी लगाने वाले हैं या विभिन्न ऐसे तबके से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी अब तक कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई गारण्टी नहीं थी, जो पिछली सरकारों के शासन के एजेंडे के पार्ट नहीं थे, उन लोगों की न सामाजिक सुरक्षा थी और न एस0ई0सी0सी0 के सर्वे में उनका नाम आया था। इस प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि इन सभी 2 करोड़ श्रमिकों को हम प्रदेश के अन्दर उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी के साथ 2 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करायेंगे। एस0ई0सी0सी0 के सर्वे में जो लोग छूट गये हैं, उन सबको भी हम लोग 5 लाख रुपये की आयुष्मान भारत की या मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा से कवर करने का कार्य करेंगे। 2 करोड़ मजदूर स्ट्रीट वेण्डर या यहां का कोई कामगार और श्रमिक देश और दुनिया में जहां कहीं होगा, हमारे पोर्टल से वह जुड़ जायेगा। उसको पहले ही प्रधानमंत्री जी ने नेशनल पोर्टिबिलिटी के माध्यम से राशन की सुविधा उपलब्ध करवा दी है, लेकिन अब हमें सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ अगर दुर्भाग्य से कल उसके साथ कोई घटना-दुर्घटना होती है तो परिवार असहाय नहीं रहेगा, उस परिवार को इस योजना के अन्तर्गत 2 लाख रुपये की सहायता तत्काल उपलब्ध हो जायेगी। उस परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने को नौबत नहीं आयेगी। यह सुविधा उसको प्राप्त होगी, लेकिन साथ-साथ उसके सामने अगर कोई स्वास्थ्य का संकट आया है तो स्वास्थ्य के संकट के लिए भी हम उस परिवार को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा का कवर देने जा रहे हैं। वह देश में हो, विदेश में हो, प्रदेश में हो हमारे पोर्टल पर वह रजिस्टर्ड होगा। इसके साथ ही यह सुविधा उसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था जो पल्लेदार है, श्रमिक परिवार है, असंगठित क्षेत्र के कारीगर हैं, इन सबको यह सुरक्षा इन दोनों योजनाओं के माध्यम से करने का कार्य इसमें किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पहले ही संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, उनके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय व्यवस्था प्रारम्भ की है। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में वह विद्यालय प्रारम्भ हो। श्रमिक जो आज एक कस्बे में है अगले दिन किसी दूसरे शहर में चला जाता है, हर तीन महीने, चौथे महीने उनका अपना ठिकाना बदलता है। उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों की समुचित शिक्षा व्यवस्था अच्छी शिक्षा व्यवस्था एन0सी0आर0टी0 की तर्ज पर उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दे सकें, इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश के अन्दर 18 कमिश्नरी में निर्माणाधीन हैं और इन कार्यक्रमों को उसके साथ जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के ऐसे जो युवा इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, मुख्य मंत्री युवा रोजगार योजना के अन्तर्गत उन्हें शिक्षित युवाओं को भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के माध्यम से 100 करोड़ की व्यवस्था उन लोगों के लिए इस बजट में उसका प्राविधान अलग से किया है। सरकार उन्हें कैसे वित्तीय समायोजन के साथ जोड़ सकती है, कैसे उन्हें आर्थिक उन्नयन के साथ जोड़ सकती है, यह कार्य प्रदेश के अन्दर हम लोग आगे बढ़ाने का कर रहे हैं और यह मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्दर स्वदेशी

गौवंश के संरक्षण और उसके संवर्धन दोनों की दिशा में प्रदेश ने एक गोकुल मिशन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के बजट में इसका प्राविधान है और वाराणसी में इसका कार्य पहले से ही भारत सरकार के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास होगा कि हम इसको फेज वाइज हर एक स्तर पर लेकर जायेंगे, जिससे हर एक स्तर पर किसानों को राहत मिले, गौ-पालकों को, पशु-पालकों को एक नई राहत मिले। गौ-पालकों को पशुपालकों को एक नई राहत मिले और उनको इस फील्ड में जो व्यापक सुधार होगा यह उनकी अतिरिक्त आय के साथ जुड़ पाएगा। व्यापारी कल्याण के लिए भी हम सब जानते हैं प्रदेश का व्यापारी हमारे प्रदेश की इन्कम को बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और प्रदेश के अन्दर जहाँ तक राजस्व की बात है मैं देखकर ताज्जुब कर रहा था कि 2016-17 में वाणिज्य कर उस समय जी0एस0टी0 नहीं था लेकिन वैट था यह कुल 51 हजार 800 करोड़ रुपए की प्राप्ति प्रदेश में हो पाती थी। आज प्रदेश सरकार ने केवल इसमें पारदर्शिता लाने का काम किया है कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है मैं बजट भाषण देख रहा था परसों जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि भगवान राम ने भरत से पूछा कि राजकाज कैसे चल रहा है कैसे कर लेते हो भरत चुप थे लेकिन वह यहीं तक सीमित नहीं रहे उन्होंने इसको अपने तरीके से विस्तार दिया लेकिन बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के अतिरिक्त कर के प्रदेश सरकार ने इसे 91 हजार 568 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है।

श्री संजय गर्ग-

व्यापारियों की हमें चिन्ता है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आप चिन्ता न करिए इसके लिए राज्य सरकार सक्षम है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमें इसलिए चिन्ता है क्योंकि हमें थोड़े दिनों बाद आना है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

सपना देखना अच्छा है। सपना देखना अच्छी बात होती है। आबकारी में 2016-17 में लगभग 14 हजार करोड़ रुपए लक्ष्य था वह भी नहीं पहुँचा था। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ चुका था उसके बाद यहाँ पर कुछ नई व्यवस्थाएं थीं और वह आज बढ़कर पहुंच रहा है लगभग 37 हजार करोड़ रुपए तक यह परिवर्तन है। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में 11 हजार 564 करोड़ रुपए से बढ़कर यह पहुँच रहा है 23 हज़ार 500 करोड़ तक। कोई अतिरिक्त कर नहीं बल्कि रियायत दी गई इसमें और छूट दी गई है। परिवहन में 5148 करोड़ से बढ़कर यह पहुँचता है 12,515 करोड़ तक। भू-तत्व और खनन में यानी कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन और बढ़ोत्तरी के साथ उसको सामने प्रस्तुत न किया गया हो। बिना किसी टैक्स के बिना किसी अतिरिक्त कर के। मण्डी समिति में भी इसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। मण्डी समिति के इन व्यापक परिवर्तनों को हमने बहुत पाजिटिव-वे में लिया है। निगेटिव-वे में नहीं लिया किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आने दी। हमने प्रदेश के अन्दर व्यापारियों को एक

सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी भी दी और कानून व्यवस्था को बेहतर करके लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया कि प्रदेश के अन्दर सुरक्षित हैं। यह हर एक फील्ड में हुआ चाहे वह किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो हर व्यक्ति प्रदेश के अन्दर यह मानकर चल सकता है कि वह प्रदेश के अन्दर सुरक्षित है निवेश के लिए प्रदेश सुरक्षित गन्तव्य है।

लेकिन हमने साथ-साथ यह भी व्यवस्था की है कि जी0एस0टी0 में जो भी व्यापारी रजिस्ट्रेशन करवायेगा, ठीक है उसका टर्नओवर 40 लाख का नहीं होगा, अगर वह रजिस्ट्रेशन कराता है और अपने रिटर्न में यह भरकर दे देता है कि उसका टर्नओवर नहीं है तो कोई समस्या नहीं है वह लिखकर भर दे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ ही उस व्यापारी को 10 लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। (सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) व्यापारी को सुरक्षा की गारण्टी भी प्रदेश सरकार के स्तर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है, तो यह कार्य प्रदेश के अन्दर किस रूप में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष ने और हमारे दलीय नेताओं ने अगर इसको थोड़ा भी ध्यान से देखने समझने का प्रयास किया होता, उपलब्धियों को नजदीक से समझने का प्रयास किया होता तो जिस प्रकार की दलीलें वह यहाँ पर दे रहे थे मुझे लगता है कि उस प्रकार की दलीलें देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिये थी। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अन्दर जिन अन्य क्षेत्रों में जो व्यापक सुधार के कार्य हुये हैं, हम लोग देख सकते हैं कि प्रदेश के अन्दर 2017 तक जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक प्रकार से बन्दी की कगार पर पहुँच चुके थे, हर जगह से शिकायत आती थी, लेकिन आज आप देखिये, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर रविवार को आरोग्य मेला लग रहा है। नेता प्रतिपक्ष, आप सम्भवतः कभी गये नहीं, एक बार आप जा कर के देखें, केवल निरीक्षण करने के लिये जाएं। भगवान न चाहे कि किसी को आरोग्य मेले में भेजने की नौबत आए, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि के नाते भी और नेता प्रतिपक्ष के नाते भी एक बार केवल देखने के लिये जाएं। अगर आप जायेंगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। आपको निरीक्षण करना चाहिये कि क्या यह भी होता है। पूरे प्रदेश के अन्दर 4,600 से अधिक प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लोगों की जो संख्या आती है वह लगभग 3 लाख प्रतिदिन की संख्या आ रही है और उसमें केवल आरोग्यता की ही जाँच नहीं होती है, उनको केवल दवाई ही नहीं मिलती है, बल्कि आरोग्यता के साथ-साथ पोषण तथा केन्द्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी योजनायें हैं उन सबको भी इसके साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, उनके साथ जोड़ा जा रहा है। किसी के पास यदि आयुष्मान भारत का गोल्डेन कार्ड नहीं है तो उसका वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराकर उसको वहीं पर कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। यह सभी सुविधायें भी उसको उपलब्ध करायी जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत भी बजट में प्राविधान किया गया है और साथ-साथ टेली-मेडिसिन और टेली-कन्सल्टेशन के लिये भी जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के लिये भी कठिनाई हो, यद्यपि प्रदेश सरकार ने उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, लेकिन फिर भी टेक्नॉलाजी के माध्यम से हम प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देंगे और कोरोना के दौरान हमने उसका एक मॉडल खड़ा भी

किया है। स्वाभाविक रूप से हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक एस0जी0पी0जी0आई0 में, के0जी0एम0यू0 में, आर0एम0एल0 में थे, यहाँ से वर्चुअल आई0सी0यू0 का एक नया कांसेप्ट दिया गया है कि अगर किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में भी उनकी सेवाएं चाहिये तो वर्चुअली प्रतिदिन 5 से 6 बजे के बीच में वर्चुअल आई0सी0यू0 चलता था, इस टेक्नॉलाजी का व्यापक लाभ हुआ है। हम लोग कोरोना प्रबन्धन वैसे ही नहीं कर पाये, इसके पीछे यह सभी कार्य इसके साथ जोड़ कर के देखे गये। हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये भी कार्य हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में और मेडिकल कॉलेजेज के लिये तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरे बजट की ही व्यवस्था की है। 1947 से ले कर के 2016-17 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और महोदय, 2016-17 के बाद से 2020-21 के बीच में 30 नये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुके हैं। (सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) यह परिवर्तन नहीं है क्या ? बलरामपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है।

श्रद्धेय अटल जी की वह कर्मभूमि रही है, वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मेडिकल कॉलेज को एफिलिएशन के लिए मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में अटल जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। जो 16 असेवित जनपद हैं उन 16 असेवित जनपदों में जहां पर अब तक हम कोई भी मेडिकल कॉलेज किसी भी योजना से नहीं दे पाये हैं चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कोई भी क्षेत्र में वहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं बनाये हैं। राज्य सरकार इस बार उसकी भी एक पॉलिसी लेकर आ चुकी है और हमने बजट में उसका प्राविधान कर दिया है। अब वहाँ पर भी एक-एक मेडिकल कॉलेज पी0पी0पी0 मोड में हम लोग खोलेंगे। वर्ष 2022 के पहले-पहले उत्तर प्रदेश का हर जनपद एक मेडिकल कॉलेज से आच्छादित होगा और वहाँ पर विशेषज्ञ एवं चिकित्सीय सुविधायें लोगों को उपलब्ध होती हुई दिखायी देंगी। ये व्यवस्था, ये स्वास्थ्य क्षेत्रों में की गयी उपलब्धियाँ हैं जो कार्य वहाँ पर किए जा रहे हैं, एस0जी0पी0जी0आई0 के लिए, के0जी0एम0यू0 के लिए या फिर अन्य संस्थाओं में आयुष मिशन के अन्तर्गत भी, आयुष विश्वविद्यालय प्रदेश के अन्दर स्थापित करने की कार्यवाही युद्धस्तर पर आगे बढ़ रही है इसके साथ-साथ एक वॉयरोलॉजी सेन्टर एन0आई0बी0 पुणे की तर्ज पर स्थापित कर सकें हम राज्य के अन्दर इस प्रक्रिया को तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं और उसके लिए धन की व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर प्रारम्भ किया है। ये सभी कार्य प्रदेश के अन्दर और जो भी विशेषज्ञ, स्वास्थ्य सुविधायें प्रदेश के अन्दर हम उपलब्ध करा सकते हैं उनको उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रदेश के अन्दर किया गया है और सरकार की नीति और नियत में किसी भी प्रकार की कोई संदेह न होने के पीछे का उद्देश्य भी यही है हम लोगों ने जो कुछ कहा वह करके दिखाया है। हम लोगों ने 2017 में विधान सभा चुनाव के दौरान एक लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया था। मा0 नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप संकल्प पत्र बनाते हैं हम घोषणा पत्र बनाते हैं। इसी घोषणा ने ही तो प्रदेश का बेड़ागर्त किया है, घोषणा पे घोषणा करते रहे लेकिन करते कुछ नहीं थे और हर बार एक नई घोषणा के साथ

आ जाते थे। हमारा संकल्प पत्र था और संकल्प का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। हम जब एक बार कोई संकल्प लेते हैं तो उसको करते हैं, क्रियान्वित करते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

संकल्प अपने लिए होता है, जनता के लिए नहीं होता है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

कबीरदास जी ने एक बात कही थी कि **"कहे कबीर सुनो नर लोई भुतवा के पुजले, भुतवा होई"** (सदन में हंसी) कबीरदास जी ने ये ऐसे ही नहीं कहा है। नेता प्रतिपक्ष कभी लोक कल्याण की बात करते नहीं हैं और करना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि लोक कल्याण इनके एजेंडे का पार्ट ही नहीं है और इसीलिए कभी उस मुद्दे को लेकर वह आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। संकल्प जब होता है तो वह स्वयं के लिए नहीं होता है लोक कल्याण के लिए होता है, राष्ट्र कल्याण के लिए होता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

धन लेकर पण्डित जी व्यक्तिगत संकल्प करवाते हैं। संकल्प अपने लिए होता है और घोषणा जनता के लिए होती है। इसीलिए हमारा घोषणा पत्र है और संकल्प आपका अपने है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आप मेरी बात सुनिये, एक बार सुन लीजिए। देखिए हम लोग तो चाहते थे, मुझे विश्वास था कि आज आप सचमुच यहां पर हलुवा लेकर जरूर आए होंगे, लेकिन आप खिलायेंगे नहीं। भारत की परम्परा क्या सोचती है ? मुझे लगता है कि अगर आपने उसको सुनने का प्रयास किया होता कि **"स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।।"**

मुझे लगता है कि अगर भारत के संकल्प को भारत के प्रत्येक नागरिक के संकल्प को आपने देखा होगा वह व्यक्ति का नहीं गांव का ही नहीं **'लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु'** की बात वह करता है। समस्त लोकों को और यह संकल्प हर व्यक्ति हर भारतीय नागरिक यही तो हमारा संकल्प है अपने लिये नहीं होता है संकल्प। हमारा संकल्प आपकी घोषणा होती है, आपकी घोषणा आपके अनुरूप ही होती थी क्योंकि आप का संकल्प अपने लिए होता है, की बात कर रहे हैं तो घोषणा भी तो आपके अपने लिए ही होती थी, व्यक्ति और परिवार के लिए जनता के लिए तो कभी नहीं लेकिन हमारा संकल्प व्यक्ति के लिए नहीं होता है लोक के लिए होता है और हमने संकल्प लोक के लिए लिया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र और लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारा उसका आधार बनता है और महोदय लोक कल्याण संकल्प पत्र में हम लोगों ने जो बातें कहीं एक ही कार्य को हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर लागू भी किया। चार वर्ष के अन्दर किया है और प्रभावी ढंग से किया है। हर तबका इसको महसूस भी कर रहा है। किसी को कहीं कोई समस्या नहीं है इस मामले में लेकिन कुछ चीजें जिसको जानना आपके लिए मुझे

लगता है पूरे सदन के लिए बहुत आवश्यक है और जो कार्य आप भी कर सकते थे। खासतौर पर यह जानते हुए जो बातें आप लोग यहाँ पर बजट में कह रहे थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

कुछ बातें संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए भी छोड़ दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

नहीं, वे बोलेंगे उनके लिए पर्याप्त मटीरियल रहेगा, अगर आप उनकी बात को सुनेंगे मैं जानता हूँ कि जब वित्त मंत्री जी अपनी बात को शेर-ओ-शायरी के साथ करेंगे तो आपको यहां से वाक-आउट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, आप उनकी बात को सुन ही नहीं पायेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जब आपकी तीखी बात सुन रहे हैं, वाकआउट नहीं किया तो कल क्यों करेंगे ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

नहीं, नहीं मेरी तीखी बात नहीं है। महोदय जो चीजें कही गयीं नेता विरोधी दल ने कहा कि बजट का कोई थीम नहीं था, हमने तो कहा कि समग्र और समावेशी विकास स्वावलम्बन से सशक्तीकरण यह बजट का थीम था अगर आपने बजट की पहली लाइनों को पढ़ा होता तो प्रस्तावना में भी चीजों का स्पष्ट उल्लेख किया गया था और मुझे लगता है कि फिर उसके अन्दर आप लोग आये होते तो बहुत कुछ जानने, सीखने के लिए मिलता वहां पर लेकिन आपने कहा कि किसान, युवा, कर्मचारी, व्यापारी, बेरोजगार किसी के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं की गयी। हमने तो जो अब तक बोला है इन्हीं सबके लिए बोला है। मुझे लगता है इसमें से कोई भी नहीं छूटा है। न किसान छूटा है न युवा छूटा है न कर्मचारी छूटा है। यानी कर्मचारियों को कोविड के दौरान हर कर्मचारी को समय से वेतन मिला है समय से सारे भुगतान हो गये, कोई कटौती नहीं की गयी लेकिन कोरोना वारियर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने बेहतर कार्य भी किया, सबने टीम वर्क किया लेकिन राज्य सरकार ने समय से वेतन देने का काम किया। आप कैसे कह सकते हैं और बेरोजगारों के लिए आज तो भर्ती की प्रक्रिया जिस पारदर्शी तरीके से चल रही है उसमें भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर किसी को कहने का अवसर मिले लेकिन महोदय मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष को और वह इस बात को लेकर कि जो इन्होंने प्रदेश के अंदर राजकोषीय घाटा और ऋण ग्रस्तता का उल्लेख किया है। इस बात को नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय वर्मा जी ने भी कहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद स्थिति बदली है। अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष 2016-2017 में यह 3.3 प्रतिशत था, वित्तीय वर्ष 2014-15 में वह 3.4 प्रतिशत था, वित्तीय वर्ष 2016 में वह 3.3 प्रतिशत था जिसे हमने एफ0आर0बी0एम0 की सीमा के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की है और हम इसे 2.9 प्रतिशत तक लाने में सफल रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में भी, वित्तीय वर्ष 2018-2019 में भी और वित्तीय वर्ष 2019-2020 में भी यह वही बना रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भारत सरकार ने एफ0आर0बी0एम0 की सीमा को कुछ शर्तों के साथ 4.5 प्रतिशत तक बढ़ाया है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे राज्य इसे 5 फीसदी या 6 फीसदी तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखकर राजकोषीय घाटा को 4.17 परसेण्ट तक ही सीमित करके रखा है और यह तब है जब भारत सरकार ने इसे 4.5 प्रतिशत तक बढ़ाया है और इतनी सुविधा राज्य सरकार को दी है कि राज्य सरकार उस सीमा के अन्तर्गत ऋण ले सकती है और उसके अन्तर्गत अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकती है। राज्य सरकार को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी और हमने अपनी सीमा के अन्तर्गत इसको बढ़ाया है। हाँ, बदले में हमने राज्य की आय को बढ़ाकर इसको रोका है। प्रदेश के अंदर अनावश्यक फिजूलखर्ची को रोकने का काम भी प्रदेश सरकार ने किया है। आप ऋण ग्रस्तता की बात कर रहे हैं तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह लगभग 30 फीसदी थी। आपने स्वयं ही यहां पर आंकड़े उपलब्ध कराये हैं। कोविड-19 के बावजूद हम इसे 28.1 प्रतिशत तक लाने में सफल हुये हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह इतना है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी इसी सीमा के अंदर रहने का अनुमान है। यह बेहतर वित्तीय अनुशासन का एक प्रस्तुतीकरण है और राज्य सरकार इन सभी चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है। केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश के अंदर जो भी प्राविधान होते थे और जो राज्यांश होता है उसके अन्तर्गत तय होता है और राज्य उसका लाभ भी ले रहा है। राज्य सरकार ने उसके अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। जो बात यहाँ पर कही गई कि बजट में विभिन्न विभागों के लिए धनराशि में कटौती की गई है तो मुझे लगता है कि इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। आप देखेंगे तो पायेंगे कि कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट 6648 करोड़ रुपये था जो वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बढ़कर 6819 करोड़ रुपये हो गया है। उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण और रेशम विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 855 करोड़ रुपये का प्राविधान था और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 1278 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पशुपालन विभाग में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 2092 करोड़ रुपये का प्राविधान था जिसे वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 2135 करोड़ रुपये किया गया है। लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 29448 करोड़ रुपये था जिसमें 4346 करोड़ रुपये की धनराशि ऋण अदायगी की थी। इस वर्ष अगर आप देखेंगे कि 29454 करोड़ रुपये का बजट है जिसमें ऋण अदायगी केवल 469 करोड़ रुपये की है।

अगर पी0डब्लू0डी0 का पूरा बजट देखेंगे तो यह 28 हजार 9 सौ 50 करोड़ रुपये का बजट है जो विगत वर्ष की तुलना में 3 हजार 8 सौ 83 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। महोदय, प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिनको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। इस दृष्टि से आकांक्षात्मक जनपदों के लिए प्रदेश सरकार ने जो काम किये हैं यानी देश के अंदर विकसित और सामान्य जनपदों की तर्ज पर अगर हम उनके पैरामीटर्स देखते तो वह एकदम पिछड़े हुए थे, लेकिन प्रदेश ने उसमें बहुत बेहतर प्रगति की है। अतिरिक्त

बजट की नहीं कन्वर्जन के माध्यम से। योजनाएं पहले से थीं, लेकिन उस बजट का बेहतर प्रयोग करने का वहां पर काम किया। आज उसका परिणाम है कि रिजल्ट सामने आ रहे हैं। नीति आयोग स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारे लिए बजट पर चर्चा केवल सरकार का लेखा-जोखा मात्र नहीं है। यह प्रदेश के विकास का एक रोड मैप भी है। जिस रोड मैप को ले करके माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपनी चर्चाएं कीं और वह चर्चा पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से की गयी हैं। उस चर्चा में बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जिन पर और भी अच्छे विचार आते और भी अच्छे ढंग से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि संवाद का माध्यम बना सभी पक्षों ने इस पर चर्चा की। सभी पक्षों ने इस पर विचार रखे। जिस भाव के साथ रखे उस भाव के साथ हम उसका स्वागत करते हैं। महोदय, मैं एक बेहतर विकासोन्मुखी प्रदेश के सर्व समावेशी और समग्र विकास को ध्यान में रख करके जो बजट प्रस्तुत किया गया है इस बजट के लिए वित्त मंत्री जी को, वित्त राज्य मंत्री जी को, वित्त विभाग के हमारे अधिकारीगण अपर मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त के साथ जितने भी अधिकारीगण हैं उन सबको प्रदेश के बेहतर रोड मैप को खींचने के लिए जिसकी सर्वत्र सराहना हुई है। हर एक तबके ने सराहना की है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या युवा, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या उद्यमी हर एक तबके ने इसका स्वागत किया है। ऐसे बजट के लिए आज मैं एक बार फिर से वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यह बजट प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लिए है इसको आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका होगी आपने और नेता प्रतिपक्ष ने और पूरे सदन ने इस पूरे बजट को बहुत सकारात्मक भाव के साथ लेकर आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उन सभी का हृदय से आभारी हूँ। महोदय, मैं एक बार फिर से पूरे सदन को होली और रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। होली और रामनवमी का पर्व बहुत शीघ्र आने वाला है। हम लोगों ने यहां पर कोविड-19 के बावजूद जब मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ तो कुछ चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी यहां दे रहे थे और उन्होंने खासतौर पर जो बात कही थी कोविड-19 के बावजूद बहुत सारी चीजें थीं जिस पर हमें कार्य और घोषणाओं को करना चाहिए था। पब्लिक परसेप्सन और साथ-साथ प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर, बहुत सारी चीजों को अभी नहीं, लेकिन हम समय के साथ लेंगे। विधायक निधि के बारे में 3 करोड़ रुपये का प्रस्ताव जो बजट में किया गया हम लोगों ने इसके बारे में बात की है और इसे हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि विधायक निधि की तर्ज पर इस फण्ड को विधायक अपने प्रस्ताव पर इसका उपयोग करेंगे और इसको हम उसी रूप में ही आगे बढ़ाने की कार्य योजना के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह इस सदन में मेरा प्रस्ताव था। मैं एक बार फिर से आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पूरे सदन का अभिनन्दन करता हूँ कि उन्होंने इस बजट में एक सकारात्मक चर्चा की और इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ और फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मैं बीच में एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, सुनिये तो यह तो पूरा उत्तर भाषण दिये न, यह तो वित्त मंत्री के रूप में भाषण दिये। एक होता है कि हम सारे सदस्य भाषण दे रहे हैं तो मुख्य मंत्री जी का भी भाषण हो, लेकिन उन्होंने पूरा वित्त मंत्री का भाषण, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मा0 मुख्य मंत्री जो आपने कई बार कहा कि समान बैच समान रैंक, इसमें जो है यू0पी0पी0 का तो प्रमोशन हो गया पी0ए0सी0 का क्यों नहीं ? उसका भी करा दीजिए। यू0पी0पी0 का प्रमोशन आपने कराया पी0ए0सी0 का भी प्रमोशन लम्बित है उनका भी हो जाये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से मैंने कहा था, कोविड का आप बहुत बखान करते हैं, कोविड काल में लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं हुयी और लड़के ओवर एज हो गये। कई स्टेट में मांग की गयी और उन्होंने अपने यहाँ उम्र में छूट दे दी है। आपसे भी आग्रह है कि आप भी उनको उम्र में छूट दे दीजिए। उसी तरह से दारोगा भर्ती में जो विलम्ब हुआ और लड़के ओवर एज हो गये उनको भी उम्र में छूट दे दीजिए। तीसरा बिन्दु यह है कि जो शैडो हैं। चाहे आपके हों, चाहे माननीय राज्यपाल जी के हों, चाहे मा0 अध्यक्ष जी के हों, चाहे मा0 मंत्री लोगों के हों, चाहे विधायक लोगों के हों, चाहे हम लोगों के हैं, तो शैडो संवर्ग की यह अफवाह है कि उसका कैडर समाप्त होने जा रहा है। इतने दिनों से वह जनप्रतिनिधियों की सेवा कर रहे हैं तो उनका जो कैडर है वह कैडर रहने दीजिए। यह तीन बिन्दु है, दारोगा और लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उम्र में छूट दे दें। दूसरी बात, जो आपने कहा कि शास्त्री भवन में आप गये तो अखिलेश जी का आपने पूछा तो सब मुँह लटका लिये थे। जब सरकार नई बनती है तो वहीं अधिकारी नये मुख्य मंत्री के सामने मुँह लटका लेते हैं। मैं भी अखिलेश यादव जी के मंत्री-मण्डल में मंत्री रहा हूँ। वह जाते थे, बैठते थे, विधायकों से नहीं जनता से भी वह मिलते थे और टाइम देकर मिलते थे। तो ऐसा नहीं है, हर मुख्य मंत्री अपने आफिस में बैठता है। आप तो दिन भर जहाज में घूमते हैं आप कब बैठते हैं हमको नहीं पता। लखनऊ तो रहते ही नहीं हैं। ठीक है आप काम करते हो मैं नहीं कहता कि आप मौज काटते हो लेकिन रोज आसमान में ही रहते हैं और जहाँ जनपद में जाते हैं वहाँ काम करते होंगे। लेकिन आप कब दफ्तर में बैठते हैं अब तो यही लोग जानते होंगे। हम लोगों को तो कभी बुलाया ही नहीं। आप योगी हैं या नहीं हैं मैं तो जानता हूँ कि हैं लेकिन आप योगी हैं या नहीं हैं, अखिलेश यादव कर्मयोगी हैं और अगली जो लड़ाई 2022 की होगी एक योगी और एक कर्मयोगी के बीच में होगी और जनता कर्मयोगी को जिताकर वहाँ पर लायेगी। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

[02:52] माननीय सदस्यों हेतु मध्याह्न भोजन की सूचना

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, एक सूचना देनी है। भोजन की सूचना है, नीचे भोजन उपलब्ध है और यह चर्चा अभी जारी रहेगी और कल भी होगी।

(इस समय 02 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री विरेन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और अपने नेता विरोधी दल की बातों पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया 2021-22 का बजट, युवाओं को रोजगार, किसानों की फसल का सम्मानजनक मूल्य, गन्ना मूल्य की बढ़ोत्तरी, स्वास्थ्य के लिए सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर डॉक्टरों एवं दवाओं की व्यवस्था एवं पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा तथा आम आदमी को रोटी, कपड़ा व मकान का प्रबन्ध करने में यह बजट पूरी तरह से अक्षम रहा है। मैं अपने बजट भाषण में इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था में न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय जनता की मूलभूत सुविधा होती है, लेकिन इस बजट में कहीं-न-कहीं यह ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, यह निराशाजनक बजट है। यह आम जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट नहीं है। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने वर्ष 2012 से 2017 के बीच में अपना वित्तीय भाषण प्रस्तुत करने का काम किया था। उस समय किसान, नौजवान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, परिवहन, हाई-वे, मेट्रो, अत्याधुनिक अस्पताल, विश्वविद्यालय, लैपटॉप, समाजवादी पेंशन, समाजवादी आवास योजना को प्रदेश के अंदर गति देने का काम किया था। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के सामने जो इन्होंने घोषणा की थी, जो इन्होंने अपने घोषणा-पत्र में कहा था, वह निश्चित रूप से छलावा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने का काम किया था वह उस समय का बहुमुखी विकास का पूरा ढाँचा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये निर्धारित था परन्तु किसानों को धान औने-पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। केन्द्र पर उनका धान नहीं खरीदा गया। मैं कहना चाहता हूँ, हम गाजीपुर जनपद से आते हैं हमारे जनपद में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा स्टेडियम देने का काम किया था लेकिन हमारे जनपद का दुर्भाग्य है कि वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस स्टेडियम को जनपद गोरखपुर में ले जाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि गाजीपुर जनपद में जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने स्टेडियम देने का काम किया था, पुनः उससे बड़ा स्टेडियम वर्तमान सरकार देने का काम करे। जिससे जनपद गाजीपुर के युवाओं का भला हो सके। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने गाजीपुर जनपद को 500 बेड का अस्पताल दिया था और कहीं न कहीं वह पूर्ण रूप से सुसज्जित अस्पताल था लेकिन वहां पर आज भी न कोई सर्जन है और न ही कोई डॉक्टर है, वहां पर अल्ट्रासाउण्ड की मशीन भी नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वहां पर तत्काल इसकी व्यवस्था कराई जाए।

मान्यवर, एक और योजना जो सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, वाराणसी से गोरखपुर तक फोर लेन का मार्ग जो जा रहा है वह हमारी ही विधान सभा क्षेत्र से होकर जा रहा है लेकिन तीन साल से ऊपर हो गया है वह काम बहुत ही स्लो गति से चल रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर उसमें प्रगति हो जायेगी तो वह काम बहुत जल्दी से निपट जायेगा, आने-जाने वालों को राहत हो जायेगी। कहीं-न-कही रोज उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से इस चीज की माँग करता हूँ। दूसरा कुछ हमारे क्षेत्र की समस्याएँ हैं, मैं उसको रखना चाहता हूँ। हमारी जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र के जंगीपुर में सड़क काफी जर्जर हो गयी है, टूट गयी है, उन्हें मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। कटवा रोड काशी माता रोड सुसुन्दी शहीद बाबा की मजार से पारा लहुरीपार होते हुए सरजू यादव के घर तक, बरेन्डा पिच रोड हीरा के घर होते हुए प्राइमरी स्कूल बरेन्डा से ताहीपुर पोखरा तक विशेष मरम्मत कार्य, मलेढी कोडरी मार्ग पर विशेष मरम्मत कार्य, पनसेरवा नहर के पटरी से केलही गांव तक संपर्क मार्ग, बिजौरा से चौथी तक विशेष मरम्मत कार्य, सुलेमापुर देवकली से सरायमुबारक तक संपर्क मार्ग, एन0एच0-29 में उदऊपुपर संपर्क मार्ग, बद्दुपुर से भोजऊपुर संपर्क मार्ग, बरही से बरेन्डा संपर्क मार्ग, एन0एच0-29 से मिठ्ठापारा संपर्क मार्ग, एन0एच0 29 कि0मी0 (84) से बघोल संपर्क मार्ग, गाजीपुर हंसराजपुर मार्ग से मिठ्ठापारा तक विशेष मरम्मत का कार्य, निजामपुर पकड़ी संपर्क मार्ग, जगनापुर से कटैला होते हुए मिठ्ठापारा संपर्क मार्ग, गाजीपुर चोचकपुर मुख्य मार्ग से सकरा तक चौड़ीकरण व उच्चीकरण, गाजीपुर चोचकपुर मुख्य मार्ग से जैतपुरा तक विशेष मरम्मत का कार्य, यह शहीद का भी गांव है इसलिए मैं आपके माध्यम से इसकी मांग करता हूँ कि इसका भी चौड़ीकरण/उच्चीकरण का कार्य किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप संक्षेप करिये।

श्री वीरेन्द्र यादव-

मान्यवर, बस एक मिनट में खत्म कर दूंगा। हमारी विधान सभा में पानी की टंकी की मांग है। विद्यापारा, रूहीपुर, कदियापुर, फदनपुर, भुतन्दरपुर, चौरही, निजामपुर, भदेव, बाबूरायपुर, सहादतपुर, अरसदपुर, गन्नापुर, सरवनडीह, जगदीशपुर औतार, गोविन्दपुर किरत, रायपुर, धनेशपुर में पानी की टंकी की मैं माँग करता हूँ।

(कुछ सदस्यों के आपस में खड़े होकर बातचीत करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्यगण अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइये और अब आप समाप्त करिये।

श्री वीरेन्द्र यादव-

मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ काम कराये जाने की आवश्यकता है। ग्राम श्रवनडीह में श्री श्रवणकुमार मंदिर का सुन्दरीकरण विकास खण्ड मरदह, ग्राम नरवर में

श्री ज्ञानी दास बाबा ब्रह्मस्थान शिवसागर स्थान का सुन्दरीकरण विकास खण्ड मरदह, ग्राम सभा नुरपुर बाबा गरीब दास शिव जी का मंदिर एवं पोखरा का सुन्दरीकरण विकास खण्ड सदर, ग्राम सभा पीपनार समाधिबाबा, शिवजी मंदिर एवं पोखरा का सुन्दरीकरण विकास खण्ड बिरनो। इन सबका सुन्दरीकरण करने का काम कराया जाये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बहोरन लाल मौर्य-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मै आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मा0 वित्त मंत्री जी ने पांच लाख पचास हजार दो सौ सत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का जो बजट पेश किया है इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि यह सर्वजन हितकारी बजट है। मान्यवर, 8 मार्च से बरेली से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा प्रारम्भ हो रही है इसके लिए मैं मा0 प्रधानमंत्री, मा0 मुख्य मंत्री एवं उड्डयन मंत्री जी को बधाई देता हूँ, साथ ही अनुरोध करता हूँ कि बरेली से लखनक तक की उड़ान प्रारम्भ कराएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश का यह ऐतिहासिक, सर्वजनहितकारी, सबका साथ सबका विकास के ध्येय को लेकर बजट प्रस्तुत किया गया है और अभी जैसे विपक्षी लोग किसानों के बारे में घड़ियाली आँसू बहा रहे थे, इन लोगों को भी समझ में आ गया होगा। मा0 मुख्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार के साथ हर बिंदु पर चर्चा की है। किसानों को जो सुविधाएं दी गयी हैं, मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि दी जा रही है, इसके अलावा इस बजट में किसानों को 2022 तक आय दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की गयी है। कृषक दुर्घटना बीमा हेतु 600 करोड़ रुपया नहरों में सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए 700 करोड़ रुपये की योजना, किसानों को सहकारी समितियों से ऋण की सुविधा देने के लिए 400 करोड़ रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा में बड़ी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। महिलाओं को कुपोषण से मुक्त तथा समर्थ बनाने के लिए 6041 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। मान्यवर, यही नहीं युवाओं, बेरोजगारों, किसानों को, उद्यमियों को, व्यापारियों को ऐसा कोई मद नहीं छोड़ा गया है, जिसमें सुविधाएं दी नहीं गयी हों। यह अलग बात है कि जब इनका बजट आता था, एक वर्ग विशेष के लिए, यहाँ तक आपने देखा होगा, 400-400 करोड़ रुपया की कब्रिस्तान को बाउन्ड्री के लिए व्यवस्था की गयी थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी ने हर वर्ग को लिया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मान्यवर, हमारी विधान सभा की कुछ समस्याएँ हैं, उन पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन पर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ। नम्बर-1 बरेली में एम्स स्तर के मेडिकल कालेज की स्थापना की जाए, नम्बर-2 सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा की पेराई क्षमता बढ़ाकर 50 हजार कुन्तल की जाए और एथनॉल प्लाण्ट लगाया जाए। नम्बर-3 बरेली-नैनीताल मार्ग से अभयपुर अग्रास तक चौड़ीकरण तथा मरम्मत का कार्य,

नम्बर-4 अभयपुर रिठौरा मार्ग के चौड़ीकरण तथा मरम्मत का कार्य, नम्बर-5 बरेली-नैनीताल मार्ग से धौरा टांडा मार्ग के चौड़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य। मेरे विधान सभा क्षेत्र 120, भोजीपुरा शेरगढ़ में एक डिग्री कालेज की व्यवस्था की जाए। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत आभार।

***श्री अभिजीत सिंह सांगा-**

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ साथ ही प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने का काम किया है। अधिष्ठाता महोदय, हमारा मानना है कि इस बजट के मूल में, इस बजट के आधार में सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है और यह हमारी मान्यता है कि जहाँ लोक निर्माण है, निश्चित रूप से वहीं पर राष्ट्र निर्माण है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई) इस बजट के माध्यम से लोक कल्याण की भावना हमको देखने को मिल रही है और मैं एक बात जरूर कहूँगा। जब इस बजट को हमने विस्तृत रूप से सुनने का काम किया, पढ़ने का काम किया, यदि मैं आँकड़ों में जाऊँगा, चूंकि समय का अभाव है, आपने समय की बन्दिशों में हमको बांध कर रखा है। किसानों के उत्थान के लिए अनेकों प्राविधान हैं, नौजवानों के रोजगार के लिए अनेकों प्राविधान हैं, गरीबों के लिए अनेकों प्राविधान हैं, दलितों के लिए अनेकों प्राविधान हैं, बेटियों के लिए अनेकों प्राविधान हैं, उद्योगजगत के लिए अनेकों प्राविधान हैं, ऊर्जा क्षेत्र में अनेकों प्राविधान हैं। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से आगे आने वाले समय में कैसे लड़ा जाए, उसके लिए अनेकों प्राविधान हैं। कानून-व्यवस्था को कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए, उसके लिए अनेकों प्राविधान हैं लेकिन अगर सबसे ज्यादा आकर्षित हमको किसी ने किया है तो आज हम सबके लिए श्रद्धा का केन्द्र, आस्था का केन्द्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए जो सैकड़ों करोड़ का पिटारा जो हमारी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने खोलने का काम किया है, मैं उसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) अधिष्ठाता महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम पीछे इतिहास को पढ़ते हैं और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, यह मान्यता है कि इस धरती पर अगर एक पत्ती भी हिलती है तो ऊपर वाले की मर्जी से हिलती है। यह कहा जाता है, यह हमको बताया गया है।

"होइहि सोई जो राम रचि राखा" इस धरती पर कोई भी घटना होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी व्यवस्था होती है तो मर्यादा पुरुषोतम भगवान श्री राम के माध्यम से होती है। हमारे ईष्ट देवों के माध्यम से होती है, यह हमारी संस्कृति हैं, ये हमारे संस्कार हैं, यह हमको सिखाया गया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज अगर राम मन्दिर का निर्माण उनकी जन्मभूमि पर होने जा रहा है तो यह इसलिए होने जा रहा है कि आज वह घड़ी आई है, और इस घड़ी का इन्तजार शायद ऊपर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाले को भी होगा तो आज वह घड़ी आई है। मर्यादा पुरुषोत्तमः भगवान श्री राम ने हमको जो रास्ता दिखाया था, आज उस रास्ते पर यह प्रदेश और देश चलने को तैयार हो चुका है। उन्होंने हमको जो रास्ता दिखाया और जो सन्देश हमको देने का काम किया था, आज उस सन्देश के आधार पर हम चलने का काम कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमको यह सन्देश दिया था, समानता के सन्देश के लिए अगर उन्होंने दलित महिला शबरी के जूठे बेर खाए थे तो उसी तर्ज पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने काशी के घाट पर दलित सफाई कर्मचारियों के पैर अपने हाथों से धोने का काम किया था और समाज में समानता का सन्देश देने का काम किया था। उसी तर्ज पर जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोतम भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का दमन करने के लिए अगर नर को जोड़ने का काम किया, वानर को जोड़ने का काम किया, नल को जोड़ने का काम किया, नील को जोड़ने का काम किया, जसवन्त को जोड़ने का काम किया, जटायु को जोड़ने का काम किया और फिर अहंकारी रावण का वध किया। उसी तर्ज पर हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुण्डा राज रूपी रावण का अन्त करने का काम किया है, इस भ्रष्टाचार रूपी रावण का अन्त करने का काम किया, इस परिवारवाद रूपी रावण का अन्त करने का काम किया तो उन्होंने अपने साथ किसानों को जोड़ने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि दे करके उनकी आँखों में उनके चेहरे पर खुशी लाने का काम किया, आज किसानों के लिए कहीं न कहीं आज नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, किसानों का ऋण मोचन करने का काम किया, किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। अधिष्ठाता महोदय, पूर्व के दौर में जब खाद बंटती थी, बीच बंटता था तब भी धर्म और जाति के आधार पर बंटता था। आज योगी जी के दौर में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है। आज किसानों की समान रूप से विकास कार्यों में सहभागिता लेने का काम यह सरकार कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ और ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे बत्ती देने का काम यह सरकार कर रही है। तहसील क्षेत्र में 21 घण्टे बिजली देने का काम यह सरकार कर रही है। शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली देने का काम यह सरकार कर रही है। आज हम बंटवारा करने का काम नहीं करते, हम भेदभाव करने का काम नहीं करते। आज काशी में उस क्षेत्र के सांसद जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वहाँ 24 घण्टे बत्ती आती है तो हमारे कानपुर और बिठूर में भी 24 घण्टे बत्ती देने का काम यह सरकार कर रही है। पूर्व का दौर याद होगा कि पहले भी 24 घण्टे बत्ती आती थी लेकिन कहाँ आती थी, इटावा में आती थी, मैनपुरी में आती थी, कन्नौज में आती थी और हमारे क्षेत्र में नहीं आती थी। आज यह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। आपसे कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से कहन चाहता हूँ कि यह जो बजट आया है यह निश्चित रूप से बिठूर की धरती के लिए भी है क्योंकि आज अयोध्या के लिए निश्चित रूप से इतने ऐतिहासिक कार्य होने जा रहे हैं। आज जो हवन चल रहा है उस हवन में हम सभी सदस्यों की आहुति जा रही है तो निश्चित रूप से इस बजट में हमारी प्रदेश सरकार का योगदान होने जा रहा है। मैं बिठूर के लिए केवल इतना कहूंगा कि अगर अयोध्या

से निकल करके श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने, मिथिला मे निकल करके माँ सीता अयोध्या में बहू के रूप में आईं तो हमारे बिठूर की धरती पर ही माँ सीता को महत्व मिला और सीता जी को माँ जानकी का दर्जा भी बिठूर की धरती से देने काम किया गया। मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूँ क्योंकि समय का अभाव है, हमारे और भी साथियों को बोलना है। आप सबको धन्यवाद।

श्री सुभाष राय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के संशोधन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मान्यवर, इस बजट में मैं देख रहा हूँ कि तीन दिन से बहुत चर्चा हो रही है। पेपरलेस बजट पेश हुआ मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अखिलेश यादव जी को जिन्होंने वर्ष 2012 में सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश के 18 लाख गरीब लोगों के लड़के और लड़क्यिों को लैपटॉप देकर जो उनकी सोच थी, पूरे प्रदेश को पेपरलेस करने की। सरकार तो चली गयी लेकिन आज तकनीकी के दौर में इस कोरोना काल में जिस तरह से पूरे प्रदेश और देश में संकट उत्पन्न हो गया था मा0 अखिलेश यादव जी का दिया लैपटॉप ही काम आया, जिससे वर्चुअल क्लासेज और जो ऑन-लाइन पढ़ाई हुई उससे गरीबों के लड़कों को पढ़ने के लिए तमाम मदद मिली। इसके साथ-साथ इस बजट में महंगाई को रोकने की कहीं से कोई बात नहीं की गयी है, जब इसके पहले मैं टेलीविजन के माध्यम से देखता था, पूर्व में केन्द्र में दूसरे पक्ष की सरकार रहती थी, तो उस समय जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली की सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर गैस का सिलेण्डर सर पर रखकर प्रदर्शन किया करते थे और गला फाड़-फाड़कर चिल्लाते थे लेकिन आज जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं आज इसी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इसके साथ ही साथ बजट में रोजगार की बात की गई है। आज जिस तरह से रोजगार छीना जा रहा है, दूरसंचार विभाग में जिस तरह से पहले 2-2 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, आज उनकी संख्या घटकर 25 हजार, 20 हजार हो गयी है, रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है। इसके साथ ही साथ आपकी सरकार के द्वारा अभी वर्ष 2018 में जो पुलिस भर्ती का विज्ञापन निकला था उसमें लगभग 49,559 पदों हेतु उसका रिजल्ट भी आ गया, परीक्षायें हो गईं। मार्च, 2020 को उसका फाइनल रिजल्ट आ गया लेकिन सारी परीक्षा पास करने के बाद और सारी औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद अभी भी 38 हजार नौजवान लड़के अपने घरों में बैठे हुए हैं। बजट में रोजगार की बेहतरी की बात की गई है। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जनपद से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे जा रहा है उसमें जनहित का ध्यान नहीं दिया गया है उसमें अण्डर पास जगह-जगह पर नहीं बनाये जा रहे हैं जिससे तमाम गाँवों की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, जिनके खेत सड़क के उस पार हैं, उनको कम-से-कम 2-2, 3-3 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है और इसके साथ ही साथ हमारे बगल में आलापुर तहसील है। आलापुर तहसील के

सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर हजारों लोगों ने मिलकर एक सर्वदलीय धरना किया था एप्रोच मार्ग बनाने के लिए। आलापुर के विषय में कहना चाहता हूँ कि वह वसुधा सिंह की धरती है। वसुधा सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे देश की आजादी के लिए वहाँ एक बाग में सभा कर रहे थे उस सभा में वहाँ पर जो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे, अंग्रेजी हुकूमत के, वह अपने सिपाहियों के साथ पहुँचे और उसके बाद पिस्टल तान दी लेकिन वसुधा सिंह के नेतृत्व में पूरी भीड़ उन अंग्रेजी सिपाहियों और दरोगा को मार डाला और मार कर ऊँट पर लादकर बैण्ड बाजा बजाते हुए ले जाकर सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। ऐसे वसुधा सिंह की धरती पर हजारों लोग एप्रोच मार्ग बनाने के लिए धरना दे रहे हैं लेकिन उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि इस संदर्भ में एस0डी0एम0 और डी0एम0 की रिपोर्ट भी आई है कि वहाँ पर एप्रोच मार्ग गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर चढ़ने के लिए बनना चाहिए। इसके साथ ही साथ कौशल विकास योजना की बात की गयी है। इस योजना में 7 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने की बात की गयी है और 3 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गयी है लेकिन 3 करोड़ लोगों को कौन-कौन सा रोजगार मिला, उनको किन-किन रोजगारों से जोड़ा गया उसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं है। गोवंश संरक्षण की बात की गयी है, मैं अभी रविवार के दिन रात में 9:00 बजे आ रहा था टोल के पास सैकड़ों गाय और बछड़े बैठे हुए थे, एक गाय बुरी तरह से घायल होकर कराह रही थी, उसका पुरसाहाल नहीं था। प्रत्येक जिले में गोवंश के नाम पर केवल घोटाले हो रहे हैं, तमाम जगहों पर ज्यादा मवेशी दिखाकर पैसा निकाला जा रहा है। यह महराजगंज की घटना थी जहाँ पर 16 लाख का घोटाला हुआ था, अधिक मवेशी दिखाकर पैसा निकाल लिया गया था। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास देने की बात कही गई है और मुख्य मंत्री आवास देने की बात की गयी है। प्रधानमंत्री आवास में अभी हमीरपुर जनपद में एक ही गाँव में इक्कीस अपात्रों को आवास दिया गया था जब उसका संज्ञान प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिया तब जाकर इस पर कार्यवाही हुई।

महोदय, अगर इसकी जांच करायी जाये तो प्रदेश के हर जिले में इस तरह से अपात्रों को आवास दिया गया है। इसी तरह से मुख्य मंत्री आवास में यह नियम या कि प्राकृतिक आपदा में जिनका मकान गिरेगा, उनको दिया जायेगा लेकिन मैं अपने जनपद, अपनी विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ कि हमारी विधान सभा में ऐसे तमाम लोगों के मकान पिछले वर्ष अतिवृष्टि में गिर गये थे लेकिन उनको तहसील से सहायता भी लेनी थी लेकिन उनको आज तक आवास नहीं दिया गया। चिकित्सा शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जनपद में पी0जी0आई0 है जो टाण्डा में बना हुआ है, वहां पर एम0आर0आई0 मशीन और सी0टी0 स्कैन मशीन हमेशा बंद रहती है, और वह आज भी बन्द है और कोरोना काल में भी बन्द थी। मरीजों को बाहर एक्स-रे और सी0टी0 स्कैन कराने जाना पड़ता था। किसान दुर्घटना बीमा की बात की गयी है। किसान दुर्घटना बीमा हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने लागू की थी। इसमें शुरुआत में 1 लाख रुपये मिल रहे थे परन्तु जब मा0 अखिलेश यादव की सरकार आयी तो इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया।

इस बजट में बहुत वाहवाही की गयी है। मैं इस बजट को अच्छा तब समझता, जब इसकी राशि और बढ़ा दी गयी होती। इसके साथ-साथ सामूहिक विवाह योजना की बात की गयी है। जनपद गाजीपुर में अभी कुछ दिनों पहले ही मैं समाचार-पत्रों में पढ़ रहा था कि गाजीपुर जनपद के अनेक विकास खण्डों में अवयस्क लड़कियों और पूर्व विवाहित महिलाओं के नाम पर तमाम फर्जी ढंग से पैसा निकाल लिया गया था। बुनकरों की बात की गयी है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार में बुनकरों को फ्लैट रेट फिक्स चार्ज पर बिल ली जाती थी लेकिन इस सरकार में इस कोरोना काल में बुनकर गरीब होता है तो उनके पास खेती-बाड़ी नहीं होती है, वही एक सहारा होता है। किस तरह से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और उनका बिजली बिल बढ़ाया जा रहा है। रोज उनको पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है और बिजली काटी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

सुभाष जी अब आप समाप्त करिए।

श्री सुभाष राय-

मान्यवर, एक मिनट दे दीजिए। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जलालपुर में राजकीय डिग्री कालेज खोला जाये, जलालपुर में 100 शैया का अस्पताल बनाया जाये। विकास खण्ड भियावं में जो असेवित ब्लॉक है, वहां पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज नहीं है, तो वहां पर राजकीय कन्या इन्टर कालेज खोला जाये। अमोला घाट, चौदहप्रासघाट, करमुहा और उड़ारी घाट पर पुल का निर्माण कराया जाये। जलालपुर में बस अड्डा और बाईपास बनाया जाये। कर्बला कासिमपुर नहर की पटरी, रफीगंज से मुण्डेहरा होते हुए आजमगढ़ की सीमा तक पुनर्निर्माण कराया जाये। 132 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन किशनपुर कविरहा ब्रह्म बाबा में लगाया जाये। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

[03:21] श्रीमती संगीता चौहान-

मान्यवर, मै आपकी अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे पति श्री चेतन चौहान जी इस गरिमामई सदन की गरिमा बढ़ा रहे थे लेकिन कोरोना महामारी में आकस्मिक मृत्यु की वजह से आज उनका बचा हुआ शेष कार्य जो उन्होंने नौगावां सादात जनपद में और अमरोहा से करना चाहा था, उसकी पूर्ति के लिए मैं दोबारा से चुनाव लड़ी और नवम्बर में मैं इस सदन में आयी। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं अपने पति के अधूरे काम पूरे कर पाऊँ। वह दो बार अमरोहा से सांसद रहे और एक बार नौगावां सादात से वह अभी वर्ष 2017 में विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने वहां अनेक विकास कार्य शुरू किये थे। एक स्पोर्ट स्टेडियम, अनेक सड़कें एक ई0एस0आई0सी0 का अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर और आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि उनके जो बचे हुए काम हैं, वह किसी तरह से पूर्ण हों। मेरे पास कार्य-समय बहुत कम है और मैं सरकार से भी आह्वान करती हूँ कि जो अमरोहा में और नौगावां सादात में काम हो रहे हैं,

उसमें मेरी मदद करें और जिसके लिए मुझे मदद मिल भी रही है। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया। बजट पर बात करना चाहूँगी कि कोरोना महामारी का शिकार हमारा परिवार हुआ और अनेकों परिवार हुए। इस दुःखद घटना को सहने के बावजूद भी हमारे प्रदेश में जितना काम कोरोना की ओर हुआ और इस देश में हुआ। आज कोरोना वैक्सीन हम सबके लिए एक गर्व का विषय है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस वैक्सीन का प्रयोग करें ताकि ऐसी कोई महामारी हम लोगों को दोबारा परेशान न करे। किसी के लिए भी घर के एक सदस्य का जाना बहुत बुरा है। कोरोना वॉरियर्स ने बहुत काम किया। हमारे हेल्थ वर्कर्स ने जितना काम किया, इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाये, वह कम है। कोरोना महामारी के वक्त मेरे पति लगातार राशन बाँटते रहे। जहां भी बच्चे फँसे थे, जैसे कोटा से बुलवाने का काम था, वह उनका रोज का काम होता था। मैं सरकार को बधाई देती हूँ कि वह इतना काम कर पाए। आज भी कोरोना की लड़ाई को हम लगातार लड़ रहे हैं। इस बजट में सड़क, पानी, बिजली और हर इन्फ्रास्ट्रचर डेवलपमेण्ट पर जो हमारी सरकार का फोकस है, वह बहुत बड़ा है।

क्योंकि कोई भी प्रदेश या देश तभी आगे बढ़ता है जब उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो। आज हमारे यहाँ बिजली 18 से 20 घण्टे आती है। मेरे पति अक्सर कहते थे कि अमरोहा में लोग अंधेरे में पैदा होते हैं और मर जाते हैं। वर्ष 2017 के बाद आज बिजली की स्थिति यह है कि कई जगहों पर हम 24 घण्टे बिजली पाते हैं। ये एक अजूबा है और सरकार की देन है। सड़कें, इन्फ्रास्ट्रक्चर और हाई-वे का डेवलपमेण्ट बहुत जबर्दस्त तरीके से हो रहा है। चीन ने जब प्रगति की तो उन्होंने अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर के बल पर की, यदि भारत प्रगति करेगा तो वह भी इन्फ्रास्ट्रक्चर के बल पर करेगा। हमारा यू0पी0 इतना बड़ा प्रदेश है जहां भारत की 1/6 पापुलेशन रहती है। मुझे पूरा यकीन है की उसकी तरक्की से ही इस देश की प्रगति होगी। मैं चाहती हूँ कि इस बजट में जो भी अच्छी चीजे हैं उसको हम हाईलाइट करें। मैं महाराज योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने 07 एयरपोर्ट का प्राविधान किया, जिसमें मुरादाबाद भी है जो हमारे क्षेत्र से सटा हुआ है और माननीय चेतन जी के गांव में ही बना है और यहां पर बहुत सुन्दरता से हवाई पट्टी तैयार हो गयी है। 08 तरीख को बरेली से दिल्ली की ओर पहली बार उड़ान भरी जायेगी। ऐसी सुविधाओं से ही देश प्रगति करेगा। मुरादाबाद पीतल नगरी है। अमरोहा में "वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क्ट" में बहुत काम हुआ है। ढोलकी जिसे पूरे भारत में हम बहुत प्यार से बजाते ह्रै, हर शादी और ब्याह में उसको "वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क्ट" में रखा गया है। अनेक टेक्सटाइल मिल अब अमरोहा में फेब इण्डिया के थ्रू काम कर रही हैं और ऐसे कई अनेक कार्य एम0एस0एम0ई0 के थ्रू लोग कर रहे हैं और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगायी जा रही है। ये गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और सबसे सुन्दर बात यह है कि गन्ने की पेमेण्ट कोरोना महामारी में न रोकी गयी और न लोगों को कोई परेशानी हुई। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हसनपुर चीनी मिल के लिए सरकार के माध्यम से उसकी कार्य क्षमता दोगुनी करने के लिए एक घोषणा की गयी थी उसको पूरा किया जाय और नौगावां सादात में एक तहसील की बिल्डिंग का 80 प्रतिशत काम चेतन जी के समय में हो गया था,

उसको भी सुचारु रूप से चलाना है जिसके लिए मैं सरकार से आवाह्न करती हूं कि उस कार्य को पूरा किया जाय। मैं इस बजट का पूर्णतः समर्थन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये प्रदेश बहुत तरक्की करे और आगे हम लोग इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेण्ट पर फोकस रखेंगे। महिला सुरक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से आज प्रदेश बहुत सुरक्षित है। महिलाओं के लिए अनेक स्कीम हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुरादाबाद में 2754 सामूहिक विवाह कराये जिसमें हर जाति के लोग सम्मिलित थे। कोई जाति का भेद नहीं, कोई कास्ट का भेद नहीं, ऐसी सरकार को नमन है और मैं मा0 वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने कोरोना महामारी के बावजूद इतना बैलेन्सड बजट दिया।

श्रीमती सरोज सोनकर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हम सबके मुखिया उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले और इस सदन में आये हुए सभी सदस्यों को मैं अपनी और अपने जनपद बहराइच, 282 बलहा की ओर से सभी को नमन करती हूँ, वन्दन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बहराइच का बलहा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। हमारी सरकार जैसे काम कर रही है वह अपने आप में सराहनीय है और अगर इसी रफ्तार से काम हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश का भारत में ही नहीं पूरे विश्व में डंका बजेगा। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश को दंगा कराने वालों व गुण्डों का प्रदेश कहा जाता था लेकिन मा0 योगी जी के नेतृत्व में लोगों का हमारे प्रदेश को देखने का नजरिया बदल गया। मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये दो शब्द बोलना चाहती हूँ-

संघर्षों के मार्ग पर जो पीर चलता है
वही संसार बदलता है वही संसार बदलता है
जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती
सूर्य बनकर वही निकलता है सूर्य बनकर वही निकलता है।

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। अगर गांव की बात करें तो जितना काम ग्राम सभा स्तर पर इस सरकार में हुआ है चाहे वह आवास हो, शौचालय का काम हो, सड़कों का काम हो, नाली का काम हो, सामुदायिक शौचालय का काम हो, अभी तक किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया है। जितना काम मेरी सरकार ने किया।

2020-21 का जो उत्तर प्रदेश का बजट माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा पेश किया गया। यह बजट किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, मजदूरों, महिलाओं और बेटियों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेगी और विकास की गंगा बहेगी और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनेगा। अन्त में अधिष्ठाता महोदय जी, जो सदन में अभी विपक्ष वाले बोल रहे थे

कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। यह लोग हमारी सरकार को बदनाम करने के लिये पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। एक कहावत है कि-

रामचन्द्र कह गये सिया से, एक दिन ऐसा आयेगा
हंस चुगेगा दाना भइया और कौवा मोती खायेगा।

तो 70 सालों से यह लोग मोती ही खा रहे थे और तभी हमारे देश में एक महापुरुष 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बनकर आये और इन लोगों का मोती छीन लिया इसीलिये यह सारे लोग कांव-कांव कर रहे हैं। यही नहीं जब 2017 में एक सन्यासी के रूप में हमारे मुख्य मंत्री योगी जी आये तो उ0प्र0 में पहले की जो सरकारें चल रही थीं, इनका भी मोती छिन गया इसलिये विपक्ष के लोग बार-बार कांव-कांव करते रहते हैं।

मैं ज्यादा समय न लेते हुये अधिष्ठाता महोदय जी अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहूँगी। बहराइच विधान सभा क्षेत्र में कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग है वहाँ पर 05 वन ग्राम हैं। एक वनटांगिया भी है अभी तक मात्र एक ही वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है बाकी 16 वन बस्तियां है। मैं चाहती हूँ कि बाकी के ग्रामों को भी राजस्व ग्राम घोषित किया जाय। हमारे क्षेत्र में करीब 80 प्रतिशत क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है और 50 किमी0 का जंगल है। यहाँ शेर, चीता, हाथी, कछुआ सभी हैं। यहाँ पर विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं लेकिन प्राकृतिक सौन्दर्य होने के बावजूद यहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको डेवलप किया जाये, जिससे सरकार की आय में बढ़ोत्तरी होगी और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

अधिष्ठाता महोदय जी, मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर 05 रेंज हैं और करीब 03 रेंज में 10 साल से ज्यादा समय वनकर्मी तैनात हैं और ये सब वनकर्मी लोकल राजनीति में लिप्त हैं और अभी जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, इन लोगों को यहाँ से तत्काल हटाया जाये, नहीं तो यह लोग पंचायत चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अधिष्ठाता महोदय, जो हमारी यहाँ एक कस्बा मिहीपुरवा है जो कि बलहा विधान सभा क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु है और जनपद बहराइच का सबसे बड़ा ब्लाक है और करीब 86 ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व भी करता है इसको नगर पंचायत का दर्जा दिलाया जाये तो आपकी महान कृपा होगी।

हमारे यहाँ एक समस्या कटान की है क्योंकि बाढ़ वाला क्षेत्र है हर साल बहुत सा एरिया कट जाता है यहाँ एक गांव गोहना कट गया था उसके लिए सरकार ने 6.5 करोड़ रुपया दिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, मैं अन्त में बताना चाहती हूँ कि एक गाँव है, चहलवा है उसमें करीब 4,000 हेक्टेयर खेत कट गये हैं और अगर इस बार बरसात से पहले थोड़ा काम हो जाये तो बहुत से गाँव कटने से बच जायेंगे, नहीं तो फिर कई गाँव कट जायेंगे और इससे जंगल भी प्रभावित हो जायेगा। अधिष्ठाता महोदय, बाकी समाधान तो होता ही रहता है और होगा ही जिस तेजी से समस्या का निस्तारण हो रहा है, उससे मन पुलकित है। आज नहीं तो कल हर

समस्या का समाधान हो जायेगा महोदय मैं इसी आशा और विश्वास के साथ जनता की सेवा के लिए समर्पित हूँ। यहाँ पर आये सभी के लिये दो शब्द कहना चाहती हूँ-

बीतेगा ये दौर, वो दौर भी बीत जायेगा, 2
संघर्ष की इस आँधी के बाद एक नया सवेरा आयेगा-2
डटे रहना मैदान में चाहे कितने ही शोर हो-2
एक दिन यह जमाना तुम्हारे गीत गायेगा-2

धन्यवाद।

***श्री अनिल कुमार दोहरे-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने 2021-22 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हूँ। इसके माध्यम से प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से किसानों के लिएँ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, बिजली के लिए तमाम ऐसी घोषणा की है और देखा जाये तो पिछले चार साल के कार्यकाल के जो बजट आये हैं और आज इस सरकार का जो अंतिम बजट आया है। पिछले चार साल के कार्यकाल के बजट का कोई भी धरातल पर काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से आज यह सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार संकल्पित है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यह कहाँ से गणित लाये हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं और जबकि सच्चाई यह है कि किसान अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधे दामों पर बेचने के लिए मजबूर है और सरकार द्वारा डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस के दाम हों, चाहे खाद, पानी के दाम हों और चाहे बिजली के बिलों के दाम की बात हो, यह दोगुने से अधिक इस सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में किसानों की आय दोगुनी कैसे हो सकती है, यह सोचने पर किसान मजबूर है। आज जिस तरह से हम देख रहे है, पूर्व की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो काम कराये गये है, उसमें जनता का पैसा सरकार द्वारा जनता के हित में लगया गया, जिससे जनता का हित हो सके, जनता का कल्याण हो सके, जनता की उन्नति हो सके। आप देखें कि हमारे कन्नौज क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत तेजी से नारा देते हैं, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" लेकिन हमारे कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहरी नीति अपनाती है। हमारे कन्नौज क्षेत्र में आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा एक काऊ मिल्क प्लांट स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में किया था। सरकार जाने के बाद उस काऊ मिल्क प्लांट का तीन-तीन बार उद्घाटन किया गया। झाँसी से आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मथुरा से उसका उद्घाटन किया, केन्द्रीय मंत्री संजय बालियान जी ने मेडिकल कॉलेज, तिर्वा से उसका उद्घाटन किया। जब वहाँ पत्रकारों ने पूछा कि पास में ही काऊ मिल्क प्लांट है, आप चलकर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसका निरीक्षण कर ले तो उसके लिए माननीय मंत्री जी के पास समय नहीं था। इसी तरह से एक सेंटर बना वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर, उसका उद्घाटन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आपने कार्यकाल में कर लिया। जब सरकार चली गई तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का पत्थर हटाकर वहाँ आदरणीय मुख्य मंत्री जी का पत्थर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पत्थर लगा दिया गया। जबकि उसमें एक नये पैसे का फंड नहीं दिया गया, बजट नहीं दिया गया और वह आज भी बदहाली की स्थिति में है। इसी तरह से एक सोलर प्लांट को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्थापित किया था, फकरपुरा कन्नौज में, उससे 23 ट्यूबवेल चल रहे थे, किसानों को उससे बिजली मिल रही थी, कई आटा चक्की चल रही थी, पूरे गाँव को बिजली मुफ्त में दी जा रही थी, अगर बल्ब फ्यूज होता था, एल0ई0डी0 अगर फ्यूज होती थी, उसको सरकार लगाने का काम करती थी, आज वह प्लान्ट बन्द पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। वहाँ कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिति में सोलर एनर्जी की यह सरकार बहुत लम्बी-लम्बी बातें करती है, जबकि सोलर एनर्जी की स्थिति देखें तो जिसका उद्घाटन ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने किया हो, उस प्लान्ट की स्थिति यह हो सकती है तो क्या हम कहे कि किस तरह से सरकार सबका साथ, सबका विश्वास की बात करती है, हम इसको कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कन्नौज में एक्सप्रेस-वे के किनारे थटिया में विशिष्ट मंडी की स्थापना करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, 40-45 प्रतिशत काम हमारी सरकार में हो जाने के बाद काम जहाँ का तहाँ रोक दिया गया, हमारी सरकार में जनता का पैसा जनता के हित में लगाया गया था ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके, किन्तु वह मण्डी आज भी वैसे ही पड़ी है एक नया पैसा उसको नहीं दिया गया है। इसी तरह से हमारे यहाँ तेरूवां में एक किसान बाजार आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा पूरा बनकर तैयार खड़ा है हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चार साल में उसको चालू नहीं कर पाये, उसमें कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, बना खड़ा है उसको चालू नहीं कर पाये, यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की। इसी तरह से हमारे कन्नौज जनपद को जिस तरह से मुख्य मंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का जो नारा दिया है वह कन्नौज के परफ्यूम को दिया है। पूर्व की सरकार, पूर्व के मुख्य मंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में परफ्यूम पार्क बनाने का काम किया था। सारी जमीन एक्वायर हो गई लेकिन उस परफ्यूम पार्क में एक नये पैसे का काम इस सरकार ने करने का काम नहीं किया है। इसी तरह से यह सरकार बहुत जोर पर्यटन पर देती है, हमारे यहाँ एक बर्ड सेंचुरी है, 18 वर्ग किलोमीटर उसका रेज है, बड़ी झील है, उस झील में देश-विदेश से पक्षी आते है और देश-विदेश से पर्यटक भी आते है, वहाँ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक हेलीपैड बनाया, बढ़िया से उसको रेनोवेट कराया और वहाँ झील में पानी रहे उसके लिए कई स्टेट ट्यूबवेल लगवाये। स्टेट ट्युबवेल तैयार हो गये, यह सरकार उसको चालू नहीं कर पा रही है, हम अभी बीच में गये थे देखा कि झील पूरी तरह से सूखी पड़ी है और पक्षी जो बाहर से आते थे आने बन्द हो गये। पर्यटन की बात करते हैं और इस तरह से सौतेलेपन का काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम

आपसे आग्रह करेंगे कि इसमें कोई पैसा नहीं लगना है इसको चालू करा दे। इसी तरह से यह सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की बात करती है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री अनिल कुमार दोहरे-

हमारे यहाँ पैरा मेडिकल कॉलेज बना खड़ा है, कैंसर इंस्टीट्यूट बना खड़ा है सारी मशीनें लगी हुई है, कार्डियोलॉजी बनी बड़ी है सारी मशीने लगी है लेकिन यह सरकार चार साल के कार्यकाल में चालू नहीं कर पायी है। इसी तरह से शिक्षा की बात करते है इंजीनियरिंग कॉलेज बना खड़ा हुआ 10 परसेंट पैसा देना है चालू करने के लिए लेकिन वह चालू नहीं हो पा रहा है। फोरेंसिक लैब बनी खड़ी है उसको चालू नहीं करवा पा रहे है, हमारे क्षेत्र में स्टेडियम के लिए भूमि अधिग्रहीत की गई, अधिग्रहण के बाद चार साल के कार्यकाल में यह सरकार स्टेडियम में एक ईंट नहीं लगा पायी। यह सरकार दावा करती है कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया, हमारे क्षेत्र में गड्ढामुक्ति के नाम पर सिर्फ लूट हुई, भ्रष्टाचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उन सड़कों पर अपने बोर्ड लगवाने का काम किया है। इसी तरह से कानून-व्यवस्था की बात करें तो कानून-व्यवस्था प्रदेश में बद् से बद्तर है, महिलाओं, बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे है, पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित हो पायेगा, यह स्थिति प्रदेश की है। मान्यवर, शौचालय की बात करते है हमने क्षेत्र में देखा है कि सरकार द्वारा बनाये हुए शौचालय 15 से 20 प्रतिशत भी अगर चालू हो तो बताये उसकी आप जांच करा लें। हमने देखा है किसी में कंडे भरे है, किसी में भूसा भरा है, एक जगह तो हमें बड़ा अच्छा नजारा मिला, सड़क के किनारे दो भाइयों के शौचालय बने, उन्होंने बीच की दीवार तोड़ दी और उसमें अपनी दुकान चला रहे है, तो इस प्रकार के शौचालय बना करके सरकार ढिंढोरा पीटने का कार्य कर रही है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त कर दें।

श्री अनिल कुमार दोहरे-

मान्यवर, जो आवास बनाये गये हमारे क्षेत्र में, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो, चाहे मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत हो, 50 परसेंट आवास अपात्रों को दिये गये है, पात्र लोग छूट गये है, इसकी भी जांच करा ली जाय। हमारा क्षेत्र कन्नौज गंगा किनारे का क्षेत्र है, इतना आवारा पशु है कि किसान 24 घण्टे नहीं सो पाता है, रात में रखवाली करता है, दिन में काम करता है, आवारा पशु की गम्भीर समस्या है सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदस्य श्री धीरेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न होने पर सदस्य पुरुषोत्तम खण्डेलवाल का नाम पुकारा गया।)

श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने हमें बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो बजट आया है, इससे पूरे प्रदेश के लोगों में एक खुशी की लहर है। यह उत्कृष्ट बजट है। गाँव, गरीब, किसान, झोपड़ियों में रहने वाले इंसान, बेरोजगार और नौजवानों की उत्थान के प्रस्तावों में, यह सोने में सुहागा वाला बजट हो गया है।

मान्यवर, मैं सीधे आगरा पर आता हूँ। स0पा0, ब0स0पा0, कांग्रेस की सरकारों से आगरा को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ प्रदूषण के कारण ताज महल को काला होने से बचाने के लिए मा0 सुप्रीम कोर्ट और एन0जी0टी0 की पैनी नजर आगरा पर रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आगरा का जो उजड़ा हुआ फाउण्ड्री उद्योग है, अब वह स्थापित नहीं हो सकता। वर्ष 1995 में मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगरा का फाउण्ड्री उद्योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, आज वह समाप्त हो गया। मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण मा0 योगी जी महराज ने वैराज प्रारम्भ करने की बात कही थी, आज वह भी अटका हुआ है। इसलिए मैं अपनी सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह मा0 सुप्रीम कोर्ट और एन0जी0टी0 में एक मजबूत पैरोकारी करे, जैसे किसी जमाने में मा0 राजनाथ सिंह और मा0 कल्याण सिंह जी की सरकार ने पैरोकारी की थी। वह पैरोकारी मजबूत ढंग से होनी चाहिए, ताकि आगरा के विकास कार्य हो सके। आज आगरा की स्थिति यह हो चुकी है कि नये होटल तथा नये नर्सिंग होमों के निर्माण नहीं हो सकते। इसलिए मा0 सर्वोच्च न्यायालय में हमारी तरफ से मजबूत पैरोकारी अनिवार्य है।

मान्यवर, विभागों के लिए इस बजट में जो धनराशि प्रस्तावित है, जैसे पी0डब्ल्यू0डी0, नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग तथा खेल विभाग ऐसे अनेक विभागों में जो धनराशि निश्चित की गयी है, उसका बहुत बड़ा अंश आगरा के विकास पर लगना चाहिए। क्योंकि आगरा एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है। आगरा कोई ताजमहल के कारण से ही नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि आगरा में अगर आप जाएंगे तो महसूस करेंगे कि आगरा राधा स्वामी मठ का स्थापित स्थल है। तीनों मठ के जो अधिष्ठाता है, जो संस्थापक है, स्वामी जी महाराज, हजुर महराज का जन्म स्थली भी वही है। चारों महादेव बटकेश्वर, कैलाश, राजेश्वर पृथ्वीनाथ, जो आगरा शहर की रक्षा करते हैं। आगरा में गुरु तेग बहादुर से जुड़ा हुआ गुरु का ताज भाई थान था गुरुद्वारा है, जहाँ देश-विदेश से लोग आते है। आगरा में जैन मुनि, जैन तीर्थांकर नैमिषारण्य भगवान का स्थान है। बटेश्वर महादेव की नगरी आगरा में है। मान्यवर, मेरा कहना है कि आगरा बहुत बड़ा अध्यात्म का क्षेत्र है। उसको ब्रज तीर्थ बोर्ड से जोड़ा जाए अथवा एक नया बोर्ड आगरा में स्थापित किया जाये, जिससे आगरा में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को ज्ञान प्राप्त हो सके और वे इन क्षेत्रों से जुड़ सकें।

मान्यवर, जेवर एअर पोर्ट बन रहा है। वहाँ पर एक टेक्सटाइल और फिल्म सिटी प्रस्तावित है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उसको आगरा से जोड़ा जाए। आगरा से

जेवर की दूरी लगभग 100 कि0मी0 है। यदि उसे आगरा से जोड़ दिया जायेगा, तो उससे आगरा को बहुत बड़ा लाभ होगा। आगरा एक पर्यटन स्थली है, उद्योगों की स्थली है।

मान्यवर, आगरा में और भी व्यवसाय खुलने की संभावना है। स0पा0 व ब0स0पा0 ने जब गारन्टी ली थी, तो कांग्रेस की केन्द्र की सरकार ने गारन्टी दी थी कि प्रदूषण के कारण मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगरा उजड़ गया है। हम आगरा को एक नान-पोल्यूटेड इंडस्ट्री देंगे, लेकिन इन सरकारों ने अपने किसी वायदे को पूरा नहीं किया। इसलिए मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि आगरा में उद्योगों की बहुत संभावनाएं हैं। आगरा में आज भी बहुत उद्योग अपने बलबूते पर है। आगरा में बुश का उद्योग और चाँदी सोने का माल बनता है, आगरा का जूता अमेरिका तक जाता है, आगरा में पेठा, दालमोट, कालीन बनते है। एक टेक्सटाइल्स हब यदि आगरा में बन जायेगा तो निश्चित ही समूचा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा तक की मार्केट आगरा के लोगों को मिल सकता है और आगरा व उसके आसपास के क्षेत्रों के लोग राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं जायेंगे तो उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती राज्यों के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय आगरा में स्थापित हो सकता है। लॉ-एण्ड-ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में अच्छी है इसलिए यहाँ आने वाले उद्यमियों की कोई कमी नहीं है। मान्यवर, मथुरा में एक नवी चण्डी (चामुण्डा देवी) का स्थान है जिसको आगरा के लोग सबसे ज्यादा मानते है, वह हिमांचल की देवी की एक पीठ है। उस पीठ को सबसे ज्यादा आगरा के लोग मानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उस स्थान को तीर्थ बोर्ड के द्वारा विकसित किया जाए, अगर वह स्थान विकसित होगा तो निश्चित रूप से आगरा के लोगों को बहुत खुशी होगी। मान्यवर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आगरा में जो प्राचीनतम शमशान घाट था, जिसको देख करके शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, उस शमशान घाट को आगरा से 14 किमी0 दूर स्थानान्तरित करने का षडयंत्र किया गया था, वह तो आगरा की जनता थी जिसने उस शमशान घाट को बचा लिया। आगरा में अनेक शमशान घाट है। दो शमशान घाट तो बिल्कुल आबादी के बीच में हैं, चारों तरफ मकान है। बल्केश्वर शमशान घाट, आवास विकास कॉलोनी का शमशान घाट, इन शमशान घाटों पर मेरी सरकार से आग्रह है कि इसे विद्युत शवदाह गृह के रूप में बनाये तो आगरा के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य संक्षेप करें।

श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल-

मान्यवर, अभी पाँच मिनट हुए हैं अन्य लोगों को ग्यारह बारह मिनट का समय दिया गया है। मान्यवर, आगरा में एक स्मार्ट पार्क बनाया जाए। जिन पाकों में बाउण्ड्री नहीं है वहाँ लोगों ने पार्क की जमीन पर कब्जा कर लिया है, उन पार्कों में बाउण्ड्री बननी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता जी, आगरा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का शहर है, आगरा ने बहुत नुकसान उठाया है, हमें चाहिए कि आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम भी बने। मान्यवर, आगरा में गंगाजल योजना, सीवर योजना में हमारी योगी जी की सरकार में बहुत बड़ा काम किया है, मैं अपनी

सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि कोई गली मुहल्ला कॉलोनी व कोई बस्ती नहीं रहनी चाहिए जहाँ पर गंगा जल से उसको जोड़ा न जाये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब समाप्त करिये।

श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल-

मान्यवर, एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूँगा कि 1947 में जब पाकिस्तान से रिफ्यूजी आगरा में आये थे, आगरा में उनकों बसाया गया था। मेरी सरकार से आग्रह है जो अनेक कॉलोनियाँ बनायी गयी थी उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उनके घरों को किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। यह मैं संकेत में अपनी बात कहना चाहता हूँ। यह बहुत गंभीर विषय है कि जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ आये थे उन लोगों के घरों के साथ छेड़छाड़ करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। मैं सत्तापक्ष का विधायक हूँ फिर भी इस बात को कह रहा हूँ। मान्यवर, श्रम विभाग के जो क्वार्टर है उन क्वार्टरों में भी श्रम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सब बेईमानी करते है इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1952 में जो क्वार्टर बनाये गये थे उन क्वार्टरो को रियायती दरों पर जो उसमे रह रहे है उन सभी लोगों को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। मान्यवर, आगरा सेवा कार्यो में कभी पीछे नहीं रहा है। रक्त दान, नेत्रदान के क्षेत्र में आगरा उत्तर प्रदेश का सबसे आगे है। आगरा के लोग मानते है "रक्त दानं धर्मस्य कार्यम्" "नेत्र दानम् मोक्ष प्राप्तं" से अपनी बात खत्म करूँगा कि जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घरों में बैठे हुए थे उस समय भी आगरा के नागरिकों ने लाखों मजदूरों को भोजन करवाया था, लाखों मजदूरों की मेहमाननवाजी की थी। पूरे आगरा में एस0एन0 मेडिकल कॉलेज जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था इस कोरोना पीरियड में उसने जो सेवा दी है उसका उल्लेख यहाँ होना चाहिए। वहाँ पर नेगेटिव होन के बाद भी रक्त दान करने वालों की भीड़ लगी रहती थी और एस0एन0 मेडिकल कॉलेज ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार ने इस कोरोना टाइम पर बहुत अच्छा काम किया इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री ब्रिजेश-**

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, इस ऐतिहासिक बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यह बजट किसानों का हितैषी, नौजवानों का हितैषी महिलाओं का हितैषी, मजदूरों का हितैषी या कम शब्दों में बात करूँ तो सही मायने में उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली 24 करोड़ जनता का सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी एक ऐतिहासिक बजट हमारे वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है। आदरणीय अधिष्ठाता जी, जब इस बजट पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अंदर महान कवि तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयों का उल्लेख किया था तो संभवतः वह यह भूल गये थे कि राजनीतिक चातुर्य के धनी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ में राजा के कर्तव्य और उसके आर्थिक तंत्र के विकास को सर्वसुलभ बनाने का एक प्रभावी विवरण भी दिया है। उन्होंने यह कहा कि-

प्रजासुखे सुखं राक्षः प्रजानां तु हिते हितम्।
नात्मप्रिय हितं राज्ञः प्रजाना तु प्रियं हितम्।।

अर्थात् प्रज्ञा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। प्रजा के हित में अपना हित दिखना चाहिए। जो स्वंय को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है। हित तो जो प्रजा को प्रिय लगे उसी में है। आगे इसी में कहते है कि-

तस्मानिन्त्योत्थितो राजा कुर्यादर्शानुशासनम्।
अर्थस्य मूलमत्थानमनर्थस्य विपर्ययः।।

इसलिये राजा को चाहिए कि नित्यप्रति उद्यमशील होकर अर्थोपार्जन तथा शासकीय व्यवहार सम्पन्न करे। उद्यमशीलता ही अर्थ और सम्पन्नता का मूल है, उसके विपरीत उद्यमहीनता अर्थहीनता का प्रारम्भ है। मेरा यह मानना है अधिष्ठाता महोदय कि हमारे इस पूरे बजट का मूल कौटिल्य के इन श्लोक के अंदर निहित है। आदरणीय महोदय, बहुत थोड़ा सा समय आपने मुझे दिया है। मैं बहुत विस्तार से चर्चा न करते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र से जुड़े दो चार मुख्य बिन्दुओं की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सम्पूर्ण जनपद सहारनपुर वासियों की ओर से बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने माता शाकम्बरी देवी जो सिद्ध शक्तिपीठ है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये जो बजट शासन की ओर से जनपद सहारनपुर को उपलब्ध कराया है मैं उसके लिये उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आपके माध्यम से एक माँग करना चाहता हूँ कि जैसे माता शाकम्बरी सिद्ध शक्ति पीठ है उसी प्रकार देवबंद के अंदर माता तिरपुर बाला सुन्दरी भी एक सिद्ध शक्ति पीठ के रूप में उनकी पूजा व उपासना की जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि माता तिरपुर बाला सुन्दरी के सिद्ध शक्ति पीठ को भी पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करते हुए उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाय। उस देवी कुन्ड सरोवर का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाय। आदरणीय महोदय, जब महात्मा गाँधी जी की 150 जयन्ती के उपलक्ष्य में जो 36 घंटे तक लगातार यह सदन चला था और एक रिकॉर्ड बना था। मैंने उसमें अपने माननीय पर्यटन मंत्री से पर्यटन सम्वर्धन योजना के तहत मेरी विधान सभा का एक ऐतिहासिक गाँव है जिसको मिरखपुर के नाम से जाना जाता है। उस मिरखपुर गाँव की एक विशेषता है कि उस गाँव के अंदर किसी भी प्रकार का व्यसन उस गाँव के निवासी नहीं करते हैं और यहाँ तक कि जो उनके खाद्य पदार्थ है उसमें तामसिक जैसे कि लहसुन और प्याज का प्रयोग भी वहाँ के निवासी नहीं करते है। वहाँ पर ही महान संत फकीर दास जी का

कर्मस्थल है। पर्यटन सम्वर्धन योजना के तहत मैंने उसको विकसित करने को माँग की थी। मैं अपने पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री नीलकंठ तिवारी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उस योजना के तहत जो उन्होंने 50 लाख रुपये की धनराशि उसके लिये स्वीकार की है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार का उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरी विधान सभा देवबंद है। यदि महाभारत कालीन के मानचित्र पर जायेंगे तो हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच में स्थित है। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच में स्थित होने के कारण महाभारत कालीन कई ऐसे गांव है, जिनको उस समय महाभारत के समय से जोड़ा जाता है। ऐसे मुख्यतः तीन गांव है, जैसे रणखण्डी ऐसा इतिहास में आता है कि वहां पर रणखण्ड गाड़ा गया था। उसके बाद जखवाला अपभ्रंश के रूप में जखवाला हो गया। उसका वास्तव में सांस्कृतिक नाम यक्षवाला था, वहाँ पर वह सरोवर स्थित है, जहां पर यक्ष ने प्रश्न किये थे। उसी के बाद आगे बढ़िये एक जड़ोदापाण्डा गांव का नाम है, वहाँ पर पाण्डु सरोवर स्थित है। मैं अपने पर्यटन मंत्री से आग्रह करूंगा कि मेरी विधान सभा के यह तीनों ऐतिहासिक गांव इतिहास के पन्नों में अपना एक इतिहास संजोए हुए है। मैं आग्रह करूंगा कि रणखण्डी में एक संस्कृत पाठशाला है, यक्षवाला के अन्दर एक सरोवर है और जड़ोदापाण्डा के अन्दर एक पाण्डु सरोवर है। पर्यटन की दृष्टि से इन गांवों का, इतिहास के साम्यिक पन्नों की दृष्टि से हम विकास करेंगे तो देवबंद विधान सभा के अन्दर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेगी। इन तीनों गांवों को यदि हम महाभारत काल से जोड़कर देखेंगे तो हमारी आज वर्तमान पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से सीख लेने की एक ललक बढ़ेगी और हम उस और पर्यटन को और नोजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। इन तीनों गांवों को जोड़ने वाली लगभग 17 कि0मी0 की एक सड़क थी, मैं अपने मा0 उप मुख्य मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे प्रस्ताव पर उन्होंने इन दोनों गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को 7 मीटर चौड़ी करने के लिए 24 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री ब्रिजेश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र देवबंद में एक डिग्री कॉलेज है, उस डिग्री कॉलेज के अन्दर अभी तक विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ मेरे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए, स्नातकोत्तर की पढ़ाई विज्ञान की करने के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। उसमें विज्ञान संकाय की कक्षा को प्रारम्भ करा दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री ब्रिजेश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने जिस ऐतिहासिक गांव का जिक्र किया है, उसकी आबादी लगभग 20 हजार है। उस गांव के अन्दर एक नाला है उस नाले के अन्दर से देवबंद की शुगर मिल और नगर पालिका का वेस्ट पानी निकलता है। इस गांव के बहुत से लोग कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित है। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे प्रस्ताव पर शासन के अन्दर उस नाले को पक्का करने के लिए 24 लाख रुपये की लागत का आगणन लम्बित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उस नाले को पक्का कराकर उस बड़े ऐतिहासिक गांव के लोगों की जानमाल की सुरक्षा करने का प्रयास करें। आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। आपने मुझे इस ऐतिहासिक बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको तथा सरकार को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।

***श्री आशुतोष उपाध्याय-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मै मा0 वित्त मंत्री जी को भी इस सरकार का अन्तिम पूर्णकालिक बजट पेश करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा यह बजट व इस सरकार का अन्तिम बजट पेश करते हुए बजट को उत्तर प्रदेश की जनता को आत्मनिर्भर करने वाला बजट बताया था परन्तु विगत एक वर्ष से प्रदेश की जनता किस भयंकर स्थिति, परिस्थिति से जूझ रही है, जिसे हम सभी भलीभांति जानते हैं तथा जनप्रतिनिधि होने के कारण जनता की परिस्थितियों का सीधा सरोकार हम सभी से जुड़ा हुआ है, खासकर ग्रामीण जनता जो रोजगार हेतु देश के बड़े-बड़े शहरों मुम्बई, दिल्ली, बैंग्लोर व पूना आदि में कार्य कर रहे थे, वह एक-एक हजार कि0मी0 की पैदल यात्रा छोटे-छोटे बच्चों, परिवारजनों, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ पलायन का भयंकर मंजर हम सभी ने देखा है। उक्त भयानक मंजर के प्रति इस सरकार का अमानवीय व्यवहार भी सामने आया है, जो एक क्रूर शासक का परिचय देते हुए जनता को उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया। अभी भी उनमें से बहुतों को नौकरियों और व्यवसाय वापस नहीं मिला है और जिनको मिल भी गया है, वह भी पूर्णतः नहीं है। क्या वह लोग आत्मनिर्भर है ? क्या उन लोगों के प्रति सरकार की कोई संवेदना नहीं है ?

मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, मैं गोरखपुर मण्डल के देवरिया जनपद से दूसरी बार चुनकर आया हूँ हम लोग लखनऊ से देवरिया तक भाटपाररानी विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूँ जब हम लोग यहाँ से जाते हैं रास्ते में गोरखपुर पड़ता है। पहले भी हम लोग आते जाते थे हमारी जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी ने एक फोर लेन सड़क गोरखपुर से सलेमपुर तक दिया था चार साल बीत गए लेकिन आज तक वह सड़क पूरी नहीं हुई जिस तरह से यह सरकार सुस्त चाल से चल रही है उसी तरह से उसका विकास कार्य भी सुस्त चाल से चल रहा है। मैं बहुत कुछ न कहते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यह जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसमें बहुत सारी बातों को कहा गया है जैसे यह दिखाया गया हो कि विपक्ष के साथियों ने कोरोना काल में जनता की कोई मदद नहीं की इन्होंने जनता से कोई सरोकार नहीं रखा अपने घरों में कैद रहे मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने अपनी विधायक निधि देकर अपना फण्ड देकर अपने घर से पैसा देकर क्षेत्र की जनता को राशन देने का काम किया गांव गांव घूमने का काम किया उसी तरह से विपक्ष के साथियों ने भी काम किया ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष के लोगों ने ही जनता की मदद करने का काम किया हम और आप अपने अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता की बदौलत जीतकर आते है और उसके हर सुख दुख के लिए हमेशा तैयार रहते है। अधिष्ठाता महोदय, बेसिक शिक्षा विभाग का आलम यह था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आते है तो उनको उत्तर प्रदेश में ले जाया जाता है और गुजरात में ले जाया जाता है लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के किसी विद्यालय में उत्तर प्रदेश में न ले जाकर न गुजरात के किसी विद्यालय में ले जाकर उन्हें दिल्ली के अरविन्द केजरीवाल की सरकार के विद्यालय को दिखाया जाता है इसी से यह पता चलता है कि बेसिक शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। मैं बहुत कुछ न कहते हुए यह कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय द्वारा उक्त के क्रम में बजट की कोई रूप रेखा प्रस्तुत नहीं की गई किसान मजदूर विवश होकर सड़कों पर उतर रहा है। किसानों को उचित दाम दिलाए जाने की जिम्मेदारी क्या सरकार को नहीं है। इस विषय में बजट में कोई समुचित समाधान नहीं है किसान मजदूर को कुल आबादी प्रदेश की आबादी का 65 प्रतिशत है। उसको धोखा दिया जा रहा है साथ ही निरन्तर नए जुमले गढ़े जा रहे है। शिक्षित बेरोजगारी की भयावह स्थिति सामने है। सरकारी भर्तियों को रोक दिया गया है निजी क्षेत्र के उपक्रम कारखाने शासन की अवहेलना के कारण बीमार पड़े हुए है क्या यह सरकार की प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। जब से यह सरकार बनी पूरे प्रदेश में हमारे जनपद में यह स्थिति है कि थानों तहसीलों में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण जनता त्राहि त्राहि कर रही है। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। परन्तु सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करिए।

श्री आशुतोष उपाध्याय-

अपराध और अपराधी दोनों निरंकुश है आज की स्थिति यह है कि फाइव के0डी0 के बगल में हत्याएं होती है। जहाँ से मुख्य मंत्री गोरखपुर से आते है उस गोरखपुर में हत्याएं होती है बच्चों का अपहरण होता है फिरौती ली जाती है। एक बच्चे की फिरौती न मिलने के कारण उसकी हत्या भी कर दी गई।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करिए।

श्री आशुतोष उपाध्याय-

अभी तीन मिनट हुए है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ उन्होंने डायल 100, 102, 1090, 108 जैसी परियोजनाओं को लागू

किया समाजवादी पेंशन लागू किया आवास देने का काम किया लोहिया ग्राम देने का काम किया जनेश्वर मिश्र गांव देकर प्रदेश के विकास में चार चांद लगाने का काम किया। आज अगर अखिलेश यादव की दूरदर्शी सोच न होती तो डायल 100 नहीं आता और अगर डायल 100 नहीं आता तो उसको बदलकर 112 करने काम नहीं करते। महिला सुरक्षा की जो लोग बात करते हैं महिला सुरक्षा के नाम पर महिला सुरक्षा की यह स्थिति है कि एक साल में 54,900 के आस पास महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। उनका उत्पीड़न हो रहा है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा यह कहा जा रहा था हमने प्रदेश सरकार का बजट बढ़ाकर दो लाख से बढ़ाकर पाँच लाख करने का काम किया मैं बताना चाहता हूँ कि सपा सरकार में लास्ट बजट तीन लाख 46 हजार करोड़ के आस पास था आज अगर सपा सरकार होती तो चार साल बाद 9 लाख करोड़ से ऊपर समाज वादी पार्टी की सरकार का बजट होता।

परन्तु भाजपा की सरकार ने अन्तिम बजट 5 लाख करोड़ के आस-पास रखा है जबकि हमारा बजट 8 लाख करोड़ के आस-पास होता।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूँ। आप बैठ जाईये।

श्री आशुतोष उपाध्याय-

मान्यवर, मा0 योगी जी ने एक बात कही कि गाँव में एक बच्चा जब लाल टोपी वालों को देखता है तो कहता है कि माँ देखो गुण्डे आ गये।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात कहिये। इस बात को तो बहुत लोग कह चुके है।

श्री आशुतोष उपाध्याय-

मान्यवर, लेकिन हम लोग जब बचपन में थे तो सारंगी लेकर साधु जब गाँव में जाता था तो हम लोग डर कर घर में छिप जाते थे और माँ कहती थी कि बच्चा तुमको घरकोशवा पकड़ लेगा।

श्री अधिष्ठाता-

सदस्य, अब आप बैठ जायें। श्रीमती साधना सिंह जी, आप बोलें।

श्री आशुतोष उपाध्याय-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं अन्त में अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं को बताते हुये अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अहिरौली से बतरौली मार्ग, भाटपार मझौली मार्ग, भटनी-भिंगारी मार्ग जर्जर है उनको बनवा दिया जाये। मैं युवाओं को रोजगार, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, छात्रों की छात्रवृत्ति, महिलाओं को पेंशन देने की मांग सरकार से करता हूँ। इसके साथ-साथ मैं भटनी के ग्राम घाँटी को ब्लॉक बनाये जाने की, बनकरा के सोहनपुर को नगर पंचायत एवं लार ब्लॉक के ग्राम चनुकी की ब्लॉक बनाये जाने की मांग इस सरकार से करता हूँ।

(इस मध्य सदस्य श्रीमती साधना सिंह अपने स्थान पर खड़े होकर 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम्' के नारे लगाती रही)

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। अब आपका लिखा नहीं जायेगा। अगर बार-बार कहने के बाद भी आप नहीं मानते हैं तो क्या इलाज है। आप बैठ जाईये। मा0 साधना सिंह जी, आप बोलें।

(इस मध्य भी सदस्य श्री आशुतोष उपाध्याय अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे, लेकिन उनका माइक बंद था)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप बैठ जाइये, आपका लिखा नहीं जा रहा है।

श्रीमती साधना सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, मा0 मुख्य मंत्री जी का स्वागत करती हूँ, मा0 वित्त मंत्री जी का स्वागत करती हूँ और वर्ष 2021-22 का इतना अच्छा बजट प्रदेश में आया है, सराहनीय बजट है। गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला व्यापारी सबके लिये यह बजट लाभकारी है। इस बजट में किसी भी वर्ग के लिये कोई ऐसा विषय नहीं छूटा है कि कोई यह कहे कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने हमको छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश का यह बजट 5 लाख 50 हजार करोड़ से भी ऊपर का है। सबके हित का यह बजट है। वर्षों से हम लोग राम मन्दिर के लिये तरस रहे थे। 500 वर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि राम की पैदाईश अयोध्या में हुयी है। लोग मरते है तो राम-राम सत्य कहा जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार राम को न मानने वाली सरकार है, इन लोगों को बताने में इतना दम लग गया। इन लोगों ने इतनी अफवाहें फैलायी, लेकिन सत्य सत्य होता है और भगवान राम को भी इन लोगों की वजह से टेंट में रहना पड़ा, यह दुख का विषय है और वहीं क्रियाकलाप सब व्यक्तियों के आगे आता है दिखायी देता है। भगवान राम के पास भी आज अपना मकान होने जा रहा है। एक हजार वर्ष के लिये वह मन्दिर बनने जा रहा है और राम को न मानने वाली इस समाजवादी पार्टी की सरकार ने कारसेवकों पर गोली चलवायी, आज वह कारसेवक तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को यह अवसर मिल रहा है कि अपनी जिन्दगी में हम लोग राम मन्दिर देखेंगे और राम मन्दिर में दर्शन करने जायेंगे और **"बच्चा-बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का"** यही संदेश आज पूरा देश पूरा विश्व दे रहा है। बच्चे अपनी गुल्लक, बुजुर्ग माताएँ अपने घर में अपनी अलमारी में जो पैसे रखी हैं उसका समर्पण कर रही है। हर नौजवान, हर महिला, हर किसान, हर व्यापारी, सारे लोग राम के नाम पर अपनी दौलत न्यौछावर करने को तैयार हैं और भगवान राम के लिये आज ऐसा अवसर आ गया है कि पूरा हिंदुस्तान लग के एक हजार वर्ष के लिये मन्दिर का निर्माण करने जा रहा है और आप लोग भी सरयू में जाकर स्नान करिये, पाँच डुबकी

मारिये और जाकर भगवान राम का दर्शन कर लीजिये और कनक भवन का दर्शन कर लीजिये। भगवान राम हम लोगों के आराध्य देव है, अयोध्या में हमारी प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट दिया है, अयोध्या के विकास के लिये इतने कार्य किये है कि पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। हम लोगों के क्षेत्र में हर गांव को लिंक रोड से जोड़ दिया गया है। हमारी विधान सभा में माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने चार पुल दिए है इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ। हमारे सारे गांवों को लिंक रोड से जोड़कर इस सरकार ने यह साबित कर दिया कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह विकास करने वाली सरकार है। अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी संकल्प और घोषणा में अन्तर बता रहे थे और नेता विपक्ष अपनी बात को रख रहे थे। हम सब भी सत्ता से बहुत दिनों तक दूर रहे है, संघर्ष किए है। जब इन लोगों की सरकार थी तब हम लोग शाम के पाँच बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहते थे, सोचते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार है कब क्या हो जाय कुछ पता नहीं, इनकी सरकार में बहन, बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी यह लोगों के लिए एक संदेश था। आज बहन-बेटियाँ पूरे जेवर से लदी हुई, संज-संवरकर गाँव से बाजार जाती है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनसे बोलने वाला कोई नहीं है यही इस सरकार की उपलब्धि है। हम आप लोगों का बता दे कि आप लोगों को अभी चार बार उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं आना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार बनेगी। आप लोगों ने गठबन्धन करके भी देख लिया है और अब प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। मैंने अपनी विधान सभा में गठबंधन को तो ऐसा लताड़ा, ऐसा भगाया कि हमारी विधान सभा में डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी 26 हजार रिकार्ड तोड़ मतो से विजयी हुए, और ये सब लोग गठबंधन करके लड़े तब भी एक लाख वोट पाने में दिक्कत हो गयी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, कोरोना काल में विपक्ष का कोई भी नेता जनता के बीच दिखायी नहीं दिया। जनता इनको याद कर रही है और कह रही है कि 2022 के चुनाव में 10 महीने बचे है इनको सब याद दिला देंगे। एक किलो चावल, एक किलो आटा भी ये लोग क्षेत्रों में नहीं वितरण किए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हम सभी विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र में जो सरकार के, जो संगठन के आदेश थे उसका पालन करते हुए लोगों को खाद्यान वितरण किया है। हमने अपने क्षेत्र में साढ़े 14 किलो के पैकेज 32 हजार वितरण किये है और यह आप आई0बी0एल0आई0यू0 और मीडिया से पता भी कर सकते है। हमारे एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता है जिनको मीडिया ने कोरोना के दौरान घेर लिया और उनसे कहा कि नेता जी विधायक जी अपने क्षेत्र में चार महीने से पाँच किलो आटा, पाँच किलो चावल, आलू, तेल, मसाला आदि-आदि राशन पानी बाँट रही हैं, आप इतने बड़े नेता हैं आप भी कुछ बटवा के पेपर में फोटो छपवा लीजिए। इस पर नेता जी घर से दो-चार किलो राशन पानी लेकर निकले तो मीडिया वालों ने कहा कि यह किसको देंगे तो उन्होंने कहा कि आप बस फोटो खींच लीजिए ताकि आज हमारी फोटो भी पेपर में छप जाय। उसके बाद वह दो-चार किलो राशन लेकर कांशी राम आवास चले गये जिसके बाद वहां के लोगों ने कहा कि इतना कम राशन लेकर आये है इसीलिए तो आप लोगों की यह गति हुई है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी विधान सभा हाइवे पर है और दीनदयाल नगर मुगलसराय

स्टेशन है। लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने सरकार का जो आदेश था, संगठन का जो आदेश था उसके अनुसार पूरे लॉकडाउन में खाद्यान वितरण किया गया है। मध्यम वर्ग के लोग जो लाइन में लग कर, कोटे में जाकर राशन नहीं ले सकते है उनके लिए मध्यम वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राशन उनके घर में पहुंचाया है और हम पहुंचाये है हमारे लोग पहुंचाये है और एक बार भी इस कोरोना महामारी में समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेता नहीं दिखाई दिये और अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां गंगा की कटान हो रही है, बहुत जगह दो गांव लगभग एक से डेढ़ किलोमीटर दूर तक उनका गांव है इस बार यदि बाढ़ आई तो गांव खत्म हो जायेगा कुण्डा कुर्द और कुण्डा कला और हमने माननीय सी0एम0 साहब को दिया भी है और चन्दौली में जहां हम रहते है एक पुराना नाला है कम कम वह 20 गांव का पानी लेते हुए नगर का पानी लेकर जाता है उसका पक्कीकरण करने के लिए और वह जिला मुख्यालय पर है अभी तक बहुजन समाज पार्टी सिर्फ जिला घोषणा करती थी इनकी बहन जी जब उठती थी तो जिला बना देती थी। समाजवादी पाटी ने तहसील घोषित कर दिया लेकिन अपने कार्यकाल में एक ईटा भी इन लोगों ने नहीं रखा। हमारे यहां न्यायालय नहीं है आज भी अधिवक्ता तहसील में अपनी प्रेक्टिस करता है चन्दौली में न्यायालय बनाना बहुत जरूरी है, दीन दयाल नगर में तहसील नहीं है समाजवादी पार्टी की सरकार ने तहसील तो घोषित कर दिया लेकिन बनवाया नहीं, हम सबको बनवाना है हम आग्रह करते हैं सरकार से कि वहाँ तहसील बने और चन्दौली में बाबुरी हमारा गांव है वहां सात हजार की आबादी है और ब्लाक से लगभग 20 किलोमीटर दूर है वहां ब्लाक बनाने की हमने मांग की है सरकार से। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम बजट का समर्थन करते है और अपनी सरकार को धन्यवाद देते है बधाई देते है कि हम लोग 2022 में पुनः जीत कर आयेंगे और हम लोग आज से अपने क्षेत्र में सदन के बाद जायेंगे और हम लोगों ने गठबन्धन को तो पछाड़ दिया है अब गठबन्धन भी इन लोगों ने करके देख लिया है अब कोई दम नहीं है जितने भी आये है उतने भी आयेंगे कि नहीं आयेंगे।

***श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-**

माननीय अध्यक्ष जी, इस ऐतिहासिक और लोक कल्याण कारी बजट के लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतना अच्छा और लोक कल्याणकारी बजट विधान सभा में पेश किया। अध्यक्ष जी प्रदेश में अपार जनमत संग्रह से बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरन्तर और व्यापक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था व मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है। पूर्व की सपा बसपा सरकारों ने शासनतंत्र को स्वयं हित करने की मशीन बना रखा था हमारी सरकार ने शासनतंत्र को लोक कल्याणकारीतंत्र बनाया है और पूरी व्यवस्था प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है कल तक जो सत्ता सपा बसपा के राज्य में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी वहीं सत्ता प्रतिष्ठान आज मुख्य मंत्री श्री योगी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदित्यनाथ जी के ओजस्वी नेतृत्व में गरीबों, किसानों, दिव्यांगों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं के कल्याण के लिए निरन्तर व्यापक प्रयास कर रही है। पहली बार किसी सरकार ने किसानों के श्रम को सम्मानित करने का संकल्प लिया और आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारम्भ करके देश भर के किसानों को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। माननीय मोदी जी का संकल्प है कि वर्ष 2020-22 तक किसानों की आय दोगुनी हो और किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम उन्हें मिले हमारी सरकार गरीबों की समर्पित सरकार है। माननीय अधिष्ठाता महोदय युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की आधारशिला है और भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला युवा देश है। मोदी सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्किल इण्डिया, मेक इन इण्डिया, स्टार्ट अप ऑफ इण्डिया, मुद्रा योजना लागू की। माननीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो।

(इस समय 4 बजकर 24 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

उसके घर में बिजली का उजाला हो, शौचालय बने ताकि महिलाओं और बहनों को खुले में शौच को कुप्रथा से मुक्ति मिले। गरीबों को अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था प्राप्त हो इसके लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अन्नदाता को समृद्धि के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना संचालित की जायेगी। इस योजना के लिए सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये, किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये, रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। हमारी सरकार ने 15000 सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने गरीबों को आवास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 7369 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के लिए 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन हेतु 5548 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर गरीबों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। अन्य प्रदेशों से वापस आये उत्तर प्रदेश के श्रमिक एवं कामगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की घोषणा एवं इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था एक ऐतिहासिक कदम है। हमारी सरकार ने शासकीय प्राथमिक स्कूलों में गरीबों के बच्चों को बस्ता, जूता, मोजा, स्वेटर के साथ ही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की व्यवस्था हेतु लगभग 22000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी योगी सरकार गांव, शहर, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, बच्चे, वृद्ध, मजदूर, दिव्यांग,

अल्पसंख्यक सबके कल्याण के लिए काम कर रही है। सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, पंथ के भेद के बिना पात्रता के आधार पर प्राप्त हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सपा और बसपा की पिछली सरकारों ने जो प्रदेश की जनता के साथ छल किया था आज यह उसी की सजा भुगत रहे है। सपा और बसपा की सरकारे प्रदेश को विकास के विपरीत पथ पर ले गये किंतु हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने हेतु कार्य कर रही है। कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की खुशहाली हमारी सरकार की प्राथमिकता है और निरंतर इस दिशा में कार्य कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्य मंत्री योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यो की बहुत सराहना हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी जी के निर्देशन में हमारा प्रदेश "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के नारे के साथ विकास एवं सुशासन की राह पर अग्रसर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ, हाथरस की जनता की तरफ से यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा बहुत सारे विकास कार्य मेरे विधान सभा क्षेत्र में कराये गये हैं। हमारे यहां पं0 दीनदयाल उपाध्याय आवासीय विद्यालय, कालेज, क्रीड़ा स्थल और 500 गायों के रहने के लिए एक सुन्दर गौशाला का निर्माण कराया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने करीबन 60 करोड़ रुपये के विकास कार्य मेरे विधान सभा क्षेत्र में कराये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले बीस वर्षो से दो-तीन चीजों की आवश्यकता है। सिकन्दराराऊ में एक बस स्टेशन बनाने की जरूरत है। नगला कलुआ से छबरपुरा तक की तीन किलोमीटर की सड़क बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिसका निर्माण कराया जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, सिकंदरामऊ में जामा सेंटर को चालू कराया जाये जो दो वर्ष से बना हुआ खड़ा है। सभी डॉक्टरों की नियुक्ति की जाये और मशीने उपलब्ध कराई जायें। माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में सिद्ध पीठ मां तारागण देवी ग्राम बिसाना मेरी विधान सभा क्षेत्र में आता है यहां हर सोमवार को दसों हजार की भीड़ होती है। यह प्राचीन मंदिर है इसके सौंदर्यीकरण के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आप तो कह रहे थे कि यह अन्त है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

एक-एक पंक्ति की तीन मदें है छोटी-छोटी राम गोविन्द जी से ले ले ? फिर हम नियम-56 पर आते है।

[04:30] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03.03.2021 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पहली सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री लाल जी वर्मा, श्री उमाशंकर सिंह, श्री आजाद अरिमर्दन की दिनांक 01 मार्च, 2021 को ग्राम-नोजलपुर, थाना सासनी, जनपद हाथरस में श्री अमरीश शर्मा की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। मैंने बजट भाषण के दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि महिला अपराध, अभी हमारी एक बहन बोल रही थी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। महिला अपराध में अपहरण, छेड़छाड़, बलात्कार के बाद, जान से मार देना, फूंक देने की घटनाओं में उत्तर प्रदेश दुनिया में एक नम्बर पर है। हिंदुस्तान में मार डालने में 302 के मामले में प्रथम है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी भी कह रहे हैं कि अपराध में बहुत बड़ी कमी आई है। एक महीने के अंदर इस प्रदेश में पचासों मर्डर हो चुके है। एक में मैं खुद गया था जौनपुर में पुलिस ने एक को मार दिया, एक सभासद की हत्या हो गई, एक प्रधान की हत्या हो गई। तभी हाथरस हो गई।

श्री अध्यक्ष-

आप यह किस प्रसंग में आप रख रहे है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हाथरस वाले में रख रहे है। जिसकी बेटी की हत्या हुई उसका कहना था कि छेड़छाड़ हुई। उसमें उसको जेल भी हुआ जब अपराधी जेल से लौटकर आया तब वह सुलह करने के लिए दबाव बना रहा था। वह थाने गया कि हमको धमका रहे हैं मारने के लिए। थाने ने कहा कि आप 112 पर सूचना दीजिए। उसने 112 पर सूचना भी दिया। पता नहीं पुलिस आई कि नहीं आई और दूसरे दिन उस आदमी को खेत में जाकर जान से मार दिया। उसी घटना को माननीय मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में कह रहे थे कि लड़की चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है कि वह आदमी सपा का है। मुख्य मंत्री जैसे गरिमामय पद पर रह कर के इस तरह की असत्य बात कहना शोभा नहीं देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हम हमेशा कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहते है। मेरे पास फोटो है। जो वर्तमान सांसद हैं वहां पर भाजपा के उनके साथ उस आदमी की फोटो है।

***संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

आपके पास तो फोटोकॉपी है।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

अगर होर्डिंग में भी भाजपा के साथ उसकी फोटो है तो भाजपा में तो उसकी फोटो है। पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी फोटो है। यहां के जो माननीय सदस्य है मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सदन की एक गरिमा है। यह भाजपा का आदमी है और फोटो वायरल हो चुका है। मैं आपको फोटो दिखला रहा हूँ, संसदीय कार्य मंत्री जी को दिखला रहा हूँ। और कहा जा रहा है कि अपना गवाह बचाने के लिए कि लड़की को बहला लो यह तो लोगों का बड़ा दिमाग भटकाते है कि हम तुम्हारी मदद करें और तुम सपा का नाम लो, लेकिन यह प्रमाण है कि वह आदमी भारतीय जनता पार्टी का है। पीड़ित आदमी थाने में जाकर कहे कि हमारी जान का खतरा है कि वह हमको मार देगा। उसके बाद भी कोई नोटिस न ले इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। जब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 मुख्य मंत्री जी यह कहते है कि जो अपराधी है वह जेल में है कुछ को मार दिया गया और कुछ खौफ से भाग गये तो मैंने पूछा था कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यह जो अपराध हो रहा है तो जब कोई अपराधी है ही नहीं तो हो कहाँ से रहा है। यह अब खुलकर आ गया है कि जो अपराध हो रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है। इसलिए मैं इस पर कुछ अधिक न कहकर यही कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, देश और दुनिया में हमारा सर शर्म से झुका हुआ है। बहन-बेटियों, माताओं के अपमान के विषय में, 302 मर्डर के विषय में, लूट-डकैती के विषय में, अपहरण के विषय में, छिनैती के विषय में यह सरकार चारों तरफ से फेल हो चुकी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यह तात्कालिक घटना है अविलम्बनीय है निश्चित है इसलिए इसे अग्राहय करें और सदन की शेष कार्रवाई को रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

आपका इसमें नहीं है।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें मेरा है। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी प्रत्येक दिन इस बात का प्रलाप करते हैं कि प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है। लेकिन मान्यवर, जितना ही अधिक यह बोलते है उतना ही अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, अभी जो यह ग्राम नोजलपुर, थाना सासनी, जनपद हाथरस की घटना है इस घटना के साथ-साथ अभी गोरखपुर में व्यापारी के 35 लाख लूट लिये गये। जहाँ के मा0 मुख्य मंत्री जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। कल ही सर्राफा व्यापारी की 35 लाख की लूट हो गयी। मान्यवर, मोहनलालगंज के सांसद है उनके बेटे को दिन-दहाड़े गोली मार दी जाती है। शाहजहाँपुर में तीन बालिकायें लापता हो जाती है। बुलन्दशहर में बच्चों के साथ बदतमीजी होती है। मान्यवर, इसी तरह से इटावा में व्यापारी की हत्या की जाती है। आये दिन अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। और मान्यवर, यह घटना जिसमें अपराधी पहले उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करता है, एफ0आई0आर0 होती है, छूट कर आता है उस मुकदमें की वापसी के लिए दबाव डालता है और दबाव न मानने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मान्यवर, निश्चित रूप से यह महत्त्वपूर्ण तात्कालिक विषय है और इसके कारण आम जनता में आक्रोश भी है। मान्यवर,बार-बार मा0 मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि अपराधियों की खैर नहीं। मान्यवर, और कहीं छोड़ दीजिए, व्यापारी के यहाँ दिन-दहाड़े लूट लेते है। पुलिस वाले व्यापारी को लूट लेते है। मान्यवर, वह भी गोरखपुर में हुआ था कि पुलिस के लोग स्वयं व्यापारी को लूट लेते हैं। इस तरह से यह घटनायें लगातार बढ़ रही है। इसलिए आपसे निवेदन करना है कि यह तात्कालिक है, अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है। मान्यवर, अगर कानून-व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तो प्रदेश का विकास नहीं हो सकता चाहे यहाँ पर जितनी योजनायें आयें। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कार्य-स्थगन को स्वीकार करके इसकी ग्राह्यता के आधार पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस घटना पर मा0 नेता विरोधी दल ने जो बातें कही है, नेता विरोधी दल स्वयं भी इस बात को स्वीकार करते है कि मा0 सदस्य अगर कोई बात हाउस में कहें तो यह माना जाता है कि वह सच बोल रहे है।

मान्यवर, किसी भी सभ्य समाज में आज जो सरकार की मकबुलियत हैं वह एक कानून पसन्द शासन की मकबुलियत है। यही सरकार का इकबाल भी है और हम मा0 नेता विरोधी दल से कहना चाहेंगे कि घटना को कम-से-कम तोड़ मरोड़ कर न कहा जाए तो अच्छा है। दो घटनाएं है, एक घटना दिनांक 16.07.2018 की थाना सासनी की है। उसमें एक छेड़छाड़ का मामला आया और छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ एफ0आई0आर0 थी और उसका प्रथम दृष्टया जेल भेज दिया गया। उस घटना का जो कल घटना हुई है उसका बहुत ज्यादा सीधा-सीधा प्रत्यक्ष संबंध नहीं हैं, लेकिन वह घटना बुनियाद पर है, यह सही है। यह 01.03 की घटना है, गौरव शर्मा धारा-354 के मामले में मुख्य आरोपी था वह एक मंदिर में गया हुआ था। गौरव शर्मा की पत्नी, मौसी गांव के छोटे से मंदिर में आये हुए थे। वहां मृतक की दोनों बेटियां भी मौजूद थी, जिनसे पुराने विवाद को लेकर आरोपी गौरव शर्मा और मौसी में कहासुनी हो गयी, महिलाओं के मध्य हुए विवाक के उपरांत आरोपी गौरव शर्मा व मृतक अमरीश भी बीच-बचाव में सामने आ गये, जहां दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। यह बोन ऑफ कंटेंशन है। अभी मैंने हाथरस के एस0पी0 से दो बार बात की है। मैं कोशिश करता हूँ कि सदन में बात कहने से पहले कम-से-कम यह जानकारी जरूर ले लें कि आखिरकार असलियत क्या है और उन्होंने हमें पूरी बात बताई है। उस वक्त एकदम से स्पॉनटेनियस झगड़ा हुआ। बात

पुरानी थी लेकिन उस बात को लेकर जब दोनों आमने-सामने हुए तो झगड़ा हो गया, झगड़े के दौरान बीच-बचाव भी हुआ और उसमें अमरीश शर्मा मारे गये। इसमें गौरव शर्मा एवं अन्य दो लोग मुल्जिम बनाये गये है एक रोहिताश शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा दूसरा निखिल शर्मा पुत्र मनोज शर्मा और एक मेन मुल्जिम गौरव शर्मा है। चारों आरोपियों के खिलाफ क्राइम नम्बर 52/2021, 147,148,149,302 एवं धारा-506 आई0पी0सी0 की धारा का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जाहिर बात है कि धारा-147 लगी है तो पाँच लोगों का होना जरूरी है, इसें चार लोग नामजद है और दो अन्य लोग है। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जैसे ही संज्ञान में आया वैसे ही गौरव शर्मा के खिलाफ 01 लाख रुपये का इनाम एवं 25-25 हजार रुपये का इनाम रोहिताश शर्मा एवं निखिल शर्मा की गिरफ्तारी पर रखा गया।

सरकार की संवेदनशीलता भी देख लें और त्वरित कार्रवाई का नमूना भी देख लें। सामान्यताः जब काफी दिन हो जाते है तब कहीं लोगों पर इनाम की घोषणा की जाती है। हमने कभी नहीं कहा कि अपराध जीरो हो जायेगा, हमने हमेशा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही है, हमने यह कहा कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति क्यों न हो या किसी स्तर वाला व्यक्ति हो। उसके लिए कोई दूसरा कानून नहीं है। जो अपराधी है उसके साथ अपराधी जैसा सलूक होगा और अभी तक हुआ भी है। इस सरकार ने तुरन्त अगर यह कहा है कि नहीं उस पर कार्रवाई होनी है तो फिर कार्रवाई हुई है और उसका नतीजा यह हुआ कि 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित हुआ और अभी जब यहां से उठे थे तो मैंने 3:15 बजे एस0पी0, हाथरस को फोन किया तो उन्होंने कहा कि रोहिताश शर्मा गिरफ्तार हो गया है, और दूसरे के बारे में हम अभी आपको बताते तो जब हमने आपसे बात की उसी समय 04 बजे दोबारा जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि दूसरा मुल्जिम भी गिरफ्तार हो गया है जिसके ऊपर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये का इनाम था। दोनों जो पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के इनामी थे, दोनों गिरफ्तार हो गये है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा भेजे थपथपाई गयी) मान्यवर, इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई और क्या हो सकती है कि घटना हुई, संज्ञान में आई तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, उसके बाद यह लगा कि जितनी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाये तो पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये इनाम उसके ऊपर घोषित किया और मुख्य मुल्जिम के ऊपर एक लाख का इनाम घोषित किया ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई गतिमान हो जाये। नतीजा यह हुआ कि दो गिरफ्तार हो चुके है बाकी की तलाश जारी है। पूरी सघनता से उसकी भी पड़ताल की जा रही है और उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि जल्दी से जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

मान्यवर, जहाँ तक नेता विरोधी कहते है कि इस सरकार में लूट, हत्या आदि में वृद्धि हुई है, आप चाहे एन0सी0आर0बी0 देख लो, चाहे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसकी बात बार-बार करते हो, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता है, कल आपको बता देंगे कि यह सरकार पूरी तरह से कानून का शासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, पूरे मनोयोग से कर रही है और हर स्तर पर इस बात को चार साल में प्रूफ भी किया है कि अगर हम कानून

का शासन कहते है तो उसे चरितार्थ भी किया है और कितने ही बड़े-बड़े अपराधी क्यों न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गयी है। उसी वजह से पब्लिक में मैसेज भी यही है कि यह सरकार में जो चाहो सो करा लो, यह नहीं होगा, जो चाहे सो कर दे, यह नहीं होगा। यह ईमेज यह पब्लिक परसेप्शन सिर्फ इसलिए बना क्योंकि सरकार कानून का शासन देने में पूरी तरह से सक्षम है। यह कहना कि सरकार में अपराध बढ़े है, कार्रवाई नहीं होती है यह बहुत जातती है। नेता विरोधी दल कभी कभी बहुत जातती करते है और मैं समझता हूँ कि उनको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए इसको अग्राह्य कर दिया जाये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर इन्होंने ठीक दिया और कार्रवाई भी की है लेकिन असल बात से फिर भटका दिये। असल बात यह थी कि जो घटना इन्होने बताया कि मंदिर पर झगड़ा हुआ।

श्री अध्यक्ष-

कार्रवाई तो करा दिये है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

एक मिनट सुन लीजिए। उसको जान से मारने की धमकी मिली कि अगर सुलह नहीं करोगे तो जान से मार दिये जाओगे। वह यह बात थाने पर जाकर कहा, थाने पर नोटिस नहीं लिखा गया और कहा कि जाकर 112 पर सूचना दीजिये। जो आदमी स्वयं कह रहा है कि एक आदमी हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है तो अगर उसी समय उस आदमी को पुलिस तलाश करने लगती, ढूंढने लगती कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तो उस आदमी की जान बच जाती। असल प्वांइट तो यहां है कि थानेदार ने नोटिस क्यों नहीं लिया, आपने मुल्जिम को पकड़ा उसके लिए आपको धन्यवाद, आपने ईनाम रखा उसके लिए भी बधाई लेकिन पुलिस वाला जो यह मर्डर करवा दिया, अगर वह ऐक्शन लिया होता तो यह मर्डर नहीं होता, आपको गिरफ्तारी के लिए इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। जैसे इन्होंने कहा कि पुलिस वाले ने गोरखपुर में लूट लिया तो चारों पुलिस वाले बर्खास्त हो गये। फिर ये क्यों नहीं बर्खास्त हो, जौनपुर में भी पुलिस के ऊपर 395 और 302 के मुकदमें है, वहाँ पर थाने में पिटाई और घर जाकर लूटकर पैसा और मोबाइल से आया, केवल सस्पेंड किया गया, वह रिस्टिकेट क्यों नहीं हुआ, गोरखपुर में लूट हो तो रिस्टिकेट और जीनपुर में 302 और 395 का मुकदमा कायम हुआ तो केवल सस्पेण्ड क्यों नहीं रिस्टिकेट। यह थोड़ा अन्तर है न। पुलिस वालों पर कार्रवाई करिये न, जिससे पुलिस वाले भी आपसे डर। जब वह थाने में जाकर कह रहा है कि हमें जान से मारने की धमकी दी गयी तो पुलिस वाले ने कार्रवाई क्यों नहीं की। इस पर भी आप थोड़ा एस0पी0 से बात करिये कि उस आदमी पर भी ऐक्शन लें, मुल्जिम पर तो ले ही रहे हैं, अगर उसने ऐक्शन ले लिया होता तो यह घटना ही न घटी होती।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इसको अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा जी की है प्रदेश के किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाये जाने के संबंध में। इस पर कई बार बातचीत हो चुकी है और आपकी भी बात आ चुकी है।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और पूरे प्रदेश के किसान इस मामले में पूरी तरह से ग्रसित हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार आयी थी और इन्होंने लगातार आवारा पशुओं से किसानी को निजात दिलाने का वादा किया था। समय-समय पर लगातार हम सब लोग, जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में विधान सभा है।

श्री अध्यक्ष-

आप इस पर कोई नयी बात कहना चाहती थी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहती हूँ और सबसे दुःखद पहलू यह है कि जब सरकार से पूछा जाता है कि इस तरह के आवारा पशुओं से किसानों की फसल को कोई क्षति पहुँची है? तो उसके जवाब में सरकार का उत्तर आता है कि ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं है तो उसको मुआवजा क्यों दिया जाए। अध्यक्ष जी, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जितने भी यहाँ पर मा0 सदस्य बैठे है, जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में विधान सभाएँ है, उन सब के सामने यह बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार लगातार इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहती है कि आवारा पशुओं में फसल को कोई क्षति पहुँच रही है तो मुआवजा कैसे देगी ? सरकार किसानों की दुगुना आय कर नहीं पायी और जो उनके खून-पसीने से उसकी सींची हुई फसल है, उसको भी बचा नहीं पा रही है, उसके बाद भी सरकार सदन में जवाब यह देती है कि इस तरह की कोई घटना सरकार के संज्ञान में नहीं है तो मुआवजे की बात ही नहीं है। इसलिए मान्यवर, यह गंभीर विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का मामला है। मेरा अनुरोध है इस पर आप सदन में चर्चा कराये। उत्तर प्रदेश के सारे किसान इस समस्या से परेशान है, लाखों-करोड़ों रुपये का उनका नुकसान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सूचना को ग्राह्य कर लें और चर्चा करा दे, यह मेरा अनुरोध है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो गए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो बात हम कहने जा रहे थे, उसका आपने स्वयं संज्ञान ले लिया। कई बार इस सदन में गोवंश के बारे में आ चुका है, और कई बार इसका जवाब भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया जा चुका है। आज माननीय चौधरी साहब नहीं है, लेकिन मान्यवर, जितनी कोशिश इस बात के लिए हो सकती है, उस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से छुट्टा जानवरों से किसी प्रकार का नुकसान न हो और उसके लिए कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया है और आज भी उस पर फोकस किया। बजट में खास तौर से इस बात पर फोकस किया गया और हर न्याय पंचायत स्तर पर इस प्रकार की हम व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित भी है और मान्यवर, शहर में तथा ग्रामीण क्षेत्र में गौ-आश्रय स्थल में जो गौवंश इस समय है, वह 5,63,856 है और उसके अलावा 78,668 पशुपालकों को वह सुपुर्दगी में दिए गए है। जो हमारी व्यवस्था है, उसके हिसाब से उनके चारे की व्यवस्था भी की गयी है और हर प्रकार से इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से किसानों का खास तौर से किसी खेत का नुकसान न हो और इस वर्ष व्यापक रूप से हमने न्याय पंचायत स्तर पर कहा है कि हम हर न्याय पंचायत स्तर पर एक छोटा गौ-शाला बनवायेंगे, ताकि उस क्षेत्र की जितने भी गौ-वंश है, उनको उसमें रखा जा सके। साथ ही साथ ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमने बात कही है। इम ब्रीड इम्प्रूवमेंट को इस बार सबसे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि इस समस्या को काफी कुछ जड़ से समाप्त किया जा सके। मान्यवर, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इस पर कई बार जवाब भी दिया जा चुका है, इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार किसानों को इससे हुए नुकसान का मुआवजा देगी ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, माननीय सदस्य को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसे अग्राह्य करते है।

(श्री उमाशंकर सिंह, श्री प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री संजय गर्ग तथा कुछ अन्य सदस्य अपनी बात कहने के लिए खड़े हो गए।)

***श्री उमाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, यदि तीन लोगों के अलावा और किसी को नहीं सुनना है तो मेरी सूचना पर सरकार का ध्यानाकर्षण ही कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

वह तो हमने कर दिया।

***श्री संजय गर्ग-**

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा निजीकरण का बहुत इम्पॉर्टेण्ट विषय है। अगर आप इजाजत दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब मैंने तीन सूचनाएं सुन लीं, आज का जैसा वातावरण है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, हम दो मिनट में अपनी बात रख लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, इसमें लम्बा समय हो जाएगा, अन्य मा0 सदस्य भी खड़े हैं। हमने ध्यानाकर्षण कर दिया।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, यह निजीकरण की बात आ जाए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इनका निजीकरण का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको जाना है, कार्य-मंत्रणा समिति में जाना है तो इसको कल के लिए स्थगित कर दीजिए और इसको कल ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मो0 फईम इरफान-

हमारा भी एक ध्यानाकर्षण का विषय है।

श्री अध्यक्ष-

आप वाला परसों ले लेंगे। अब हम आज का छोटा सा एजेण्डा निपटा लें। अब हम मद संख्या-3 लेंगे।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मान्यवर, मेरी भी नियम-56 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ध्यानाकर्षण करा दिया है।

[04:55] लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 2018 (खण्ड-1 पृष्ठ-1 से 264) तथा (खण्ड-2 पृष्ठ-265 से 535) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

***संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 2018 (खण्ड-1 पृष्ठ-1 से 264) तथा (खण्ड-2 पृष्ठ 265 से 535) (स्पष्टीकरण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड का तेरहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिपदन 2016-2017

***संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को तेरहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2016-2017 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1)(बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पति विरूपण निवारण विधेयक 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा, उ0प्र0-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 02 मार्च, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 में कुछ नहीं हैं।

आगे मद संख्या-7 याचिकाओं से सम्बन्धित है और मद संख्या-7 से लेकर मद संख्या-48 तक जितनी भी याचिकाएँ हैं, वे सब उपस्थित की हुई मानी गई।

(उपरोक्त याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गई और संलग्न हैं)

श्री सुभाष राय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं †

1. जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव के अन्तर्गत हाफिजपुर से करीमनगर नहर पटरी का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्दर यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,
2. जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम जगतूपुर बिल्टई से भिसंवा चितौना मार्ग लम्बाई लगभग 700 मी0 को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगभवन व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,
3. जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम गौरामहमदपुर सम्पर्क मार्ग से फूलेराज यादव गौरामहमदपुर के घर तक लम्बाई लगभग 1.20 कि0मी0 मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फुलेराज यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

† छापी नहीं गई।

4. जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव के अन्तर्गत चैनपुर बाजार से रन्नूगंज नहर की पटरी का अवशेष भाग लम्बाई लगभग 500 मी0 का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पारस नाथ कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका, तथा

5. जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर के ग्राम सरखूपुर से नोनहर सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 1.50 कि0मी0 का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाराम मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

1. जनपद हमीरपुर के तहसील राठ के अन्तर्गत ग्राम रोरो से बरोली के बीच बिरमा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका, तथा

2. जनपद हमीरपुर के तहसील सरीला में बस स्टेशन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बंधित पाँच याचिकाएं †

1. जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम गौरिया में बरातघर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवप्रसाद मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

2. जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम ताजपुर से सर्रापुरवा तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नागबाबू जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

3. जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांव एवं ग्राम सभा बराहिया बार्डर पर पारसनाथ के घर के पास एक पुलिया (15 फुट लम्बी) एवं दोनों तरफ इण्टरलॉकिंग लगभग 300 मी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पारसनाथ गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

4. जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम सुसरौली में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामराज व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गई।

5. जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांव में संतोष पाण्डेय के घर से राजमणि तिवारी घर होते हुए मैलारी लोध के घर तक इण्टरलॉकिंग लगभग 300 मी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बहराइ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री किशन लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की पीलीभीत से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

1. जनपद पीलीभीत, विकास खण्ड मरौरी अन्तर्गत पीलीभीत माधोटांडा रोड स्थित चौकी रिछौला से गोयल व माला कालोनी होते हुए गजरौला तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री विनय कृष्ण बाला व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,
2. जनपद पीलीभीत, विकास खण्ड पूरनपुर अन्तर्गत पीलीभीत पूरनपुर रोड स्थित गोमती गुरूद्वारे से प्रसादपुर गौशाला होते हुए ग्राम रमपुरा फकीरे तक ध्वस्त सड़क को बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतविन्दर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,
3. जनपद पीलीभीत, विकास खण्ड पूरनपुर अन्तर्गत पीलीभीत पूरनपुर रोड स्थित गजरौला थाने से ग्राम शिवनगर नहर की पुलिया तक ध्वस्त सड़क व नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका तथा
4. जनपद पीलीभीत, विकास खण्ड मरौरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत गजरौला कस्बा में नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नेमचन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बाबू राम पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बधित चार याचिकाएं †

1. जनपद पीलीभीत, विकास खण्ड पूरनपुर अन्तर्गत ग्राम दौलतपुर से ग्राम हमीरपुर तक जर्जर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनीत अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,
2. जनपद पीलीभीत, विकास खण्ड पूरनपुर अन्तर्गत ग्राम दुधिया खुर्द से ग्राम विलहरी तक गड्ढामुक्त सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री लज्जाराम दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,
3. जनपद पीलीभीत, विकास खण्ड पूरनपुर अन्तर्गत ग्राम कसगंजा से चकपुर, तहसील अजीतपुर विलहा तक सड़क व पुलिया को बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बलवंत कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका तथा

† छापी नहीं गई।

4. जनपद पीलीभीत, विकास खण्ड पूरनपुर अन्तर्गत ग्राम दुधिया खुर्द से ग्राम वनजरिया तक गड्ढामुक्त सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुरूदेव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती पिंकी सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित सात याचिकाएं[†]

1. जनपद सम्भल के असमौली विधान सभा क्षेत्र में ग्राम गन्धटा केलाश देवी मुख्य मार्ग से विकास खण्ड पवासा चन्दनटी मौजा तक सड़क का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार यादव, निवासी जनपद सम्भल की याचिका,
2. जनपद सम्भल के असमौली विधान सभा क्षेत्र में चन्दनटी मौजा से ग्राम लठीरा (इशापुर शाहनी) तक मार्ग की सड़क का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार, निवासी जनपद सम्भल की याचिका,
3. जनपद सम्भल के असमौली विधान सभा क्षेत्र के पवासा शालीन मुख्य मार्ग से वजरपुरी से चन्द्रकेश के मकान तक नाली एवं सड़क मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभात कुमार, निवासी जनपद सम्भल की याचिका,
4. जनपद सम्भल के असमौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा सोनव से लत्तीपुर पस्तौरा, विकास खण्ड पसासा तक 900 मी0 सड़क का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील यादव, निवासी जनपद सम्भल की याचिका,
5. जनपद सम्भल के असमौली विधान सभा क्षेत्र के रूकनुद्दीन सराय रोड से सलारपुर कला (पूर्व प्रधान) सकरूद्दीन के घर तक जिसकी दूरी लगभग 300 मी0 तक सड़क का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभात कुमार, निवासी जनपद सम्भल की याचिका,
6. जनपद सम्भल के असमौली विधान सभा क्षेत्र के करीमपुर गांव में नहर की पुलिया से हिजखेड़ा रोड तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत कुमार, निवासी जनपद सम्भल की याचिका तथा
7. जनपद सम्भल के असमौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुबारकपुर बन्द से नरैठा होते हुए शाहपुर डसर असमौली लोधीपुर रोड तिराहा तक सड़क मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार, निवासी जनपद सम्भल की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री आनन्द शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित सोलह याचिकाएं[†]

1. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत इटवा डुडैला, मजरा छोटी पाटिन, विकास खण्ड मानिकपुर में बसहड़ी नाला में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश कोल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गई।

2. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत ऊँचाडीह, मजरा टेढ़वा, विकास खण्ड मानिकपुर में अत्यन्त क्षतिग्रस्त कारीबराह पुल को पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुशीला पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,
3. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत खोह में रेलवे लाइन पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज को अतिशीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,
4. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बरगढ़ के खोहर सम्पर्क मार्ग एवं मोहना नदी में पुल को बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौजी लाल पाल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,
5. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बरहरा कोटरा, तहसील मऊ कोटरा नाला में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भइया लाल निषाद व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,
6. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत खरौंध मजरा गढ़ी खुर्द के बाल्मीकि नदी में पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,
7. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत निहीं, विकास खण्ड मानिकपुर में गोबरहाई से औदरपुरवा सम्पर्क मार्ग के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मधुकर व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,
8. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत ऊँचाडीह, मजरा चमरौंहा, विकास खण्ड मानिकपुर में बरदहा नदी पर पिलरदार पुल बनवाए जाने के सम्बन्ध में श्री गणेश जी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,
9. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत सकरौंहा, विकास खण्ड मानिकपुर में धवहिया नाला में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबाबू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,
10. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत मवई कलां, विकास खण्ड मऊ में बरवार रोड सिंघानिया ढलान के पास कौशिकी नदी में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,
11. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत गोईया कला, विकास खण्ड मऊ में गोईया नदी में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम दुबे व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,
12. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बरगढ़, मजरा ओसरी, विकास खण्ड मऊ में चन्द्रभान के डेरा के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

13. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत तरगवां, मजरा मड़हा, विकास खण्ड मऊ के मड़हा के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,
14. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत परदवां, विकास खण्ड म0 के बुन्देला नाला में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवबोध द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,
15. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत तेन्दुवामाफी, विकास खण्ड मऊ के गुन्ता माइनर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबाबू द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका तथा
16. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत रामपुर के मजरा बेलरी से रामपुर सम्पर्क मार्ग तक लगभग 2 किमी0 एवं मार्ग के बीच में चकडैम का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा जनपद लखनऊ से सम्बंधित याचिका †

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में सेक्टर-ज़े स्थित में नर्सरी स्कूल हेतु आरक्षित भू-खण्ड का (प्राधिकरण के अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार) श्रीराम पब्लिक स्कूल के पक्ष में आवंटन सम्बन्धी श्री एस0डी0 द्विवेदी, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बंधित याचिका †

जनपद लखनऊ में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में वर्ष 1994 के पूर्व से कार्यरत उप अभियन्ता/अवर अभियन्ता के रिक्त 139 पदों के सापेक्ष तत्समय कार्यरत (सि0/वि0/यॉ0) संवर्ग के उप अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं को पूर्व तिथि से विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री पी0 डी0 द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित दस याचिकाएं †

1. जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर के अन्तर्गत जर्जर विद्युत लाइन को परिवर्तन कराकर नई विद्युत लाइन ए0बी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,
2. जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर के अन्तर्गत जर्जर विद्युत लाइन को परिवर्तन कराकर नई विद्युत लाइन ए0बी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

† छापी नहीं गई।

3. जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर विद्युत लाइन को परिवर्तन कराकर नई विद्युत लाइन ए0बी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध मैं श्री बृजेश पंडित व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,
4. जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर विद्युत लाइन की परिवर्तन कराकर नई विद्युत लाइन ए0बी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनीत दुबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,
5. जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर विद्युत लाइन को परिवर्तन कराकर नई विद्युत लाइन ए0बी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,
6. जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर के अन्तर्गत जर्जर विद्युत लाइन को परिवर्तन कराकर नई विद्युत लाइन ए0बी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,
7. जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर के अन्तर्गत वार्ड नं0-87 में जर्जर विद्युत लाइन को परिवर्तन कराकर नयी विद्युत लाइन ए0बी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,
8. जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर के अन्तर्गत वार्ड नं0-66 में जर्जर विद्युत लाइन को परिवर्तन कराकर नई विद्युत लाइन ए0बी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,
9. जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर के अन्तर्गत वार्ड नं0-65 में जर्जर विद्युत लाइन को परिवर्तन कराकर नई विद्युत लाइन ए0बी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव बाजपेयी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा
10. जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर के अन्तर्गत वार्ड नं0-65 में दामोदर नगर में पेट्रोल लाइन वैष्णो देवी चौराहा से काठ के पुल से माँ कत्यायनी देवी मन्दिर के तरफ जर्जर विद्युत लाइन को परिवर्तन कराकर नई विद्युत लाइन ए0बी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की पाँच व कानपुर देहात से सम्बंधित एक याचिका †

1. जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद की नगर पंचायत मक्खनपुर के ग्राम जिजौली में लालता प्रसाद मास्टर साहब के घर से हरीओम के घर तक सी0सी0

† छापी नहीं गई।

निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री लालता प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2. जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद की नगर पंचायत मक्खनपुर के बूथ संख्या 227 में राम शंकर के घर से गौरी शंकर के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री राम शंकर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,
3. जिला फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम किशनदासपुरा में कृपाल सिंह के घर से रामभरोसे के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण विषयक श्री कृपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,
4. जिला फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद की नगर पंचायत मक्खनपुर के ग्राम जिजौली में राजा भैया के घर से लाल जी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण विषयक श्री लाल जी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,
5. जिला फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम साढूपुर तक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय साढूपुर से सडामई मार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण विषयक श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा
6. जनपद कानपुर देहात में ग्राम समाज द्वारा खसरा संख्या 262 व 599 में क्रमशः क्षेत्रफल .3120 व .0920 कुल क्षेत्रफल .4040 भूमि पर कब्जा हटाने के सम्बन्ध में श्री श्यामसुन्दर निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बंधित चार याचिकाएं [†]

1. जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड नगवा के आर0पी0के0 रोड डोलिया आमडीह होते हुए सराईगढ़ तक खराब सड़क को बनवाये जाने विषयक श्री महेश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,
2. जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड नगवा के खलयारी के पास स्थित करही बन्धी के उच्चीकरण व झरनवा नाला का पानी करही बन्धी में गिराये जाने विषयक श्री ओम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,
3. जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड नगवा के आर0पी0के0 रोड से खलियारी मुसहर बस्ती होते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलियारी तक खराब सड़क को बनवाये जाने विषयक श्री जुठन बनवासी व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका तथा
4. जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड राबर्ट्सगंज आर0पी0के0 रोड खडन्जा पुल से सिरपाल पुर होते हुए बेठगाई तक सड़क निर्माण विषयक श्री अनूप तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

[†] छापी नहीं गई।

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बंधित तीन याचिकाएं †

1. जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा बड़ी सेमरिया से रम्पुरा किसान देव स्थल तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,
2. जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा रम्पुरा किसानन से बड़ी सेमरिया तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरद्वारी लाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा
3. जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सेमरिया डलेरान में छोटे लाल वर्मा के दुकान से देव स्थल होते हुए मदनापुर मुख्य मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चमन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री काली प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

1. जनपद देवरिया के विकास खण्ड भागलपुर की ग्राम पंचायत भागलपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शम्भू जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,
2. जनपद देवरिया के विकास खण्ड लार की ग्राम पंचायत पिण्डी को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश दूबे व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,
3. जनपद देवरिया के विकास खण्ड सलेमपुर में नदावर पुल पिच मार्ग से नदावर घाट तक पिच निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिन्टू तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका तथा
4. जनपद देवरिया के विकास खण्ड भागलपुर के मईल मगहरा पिच मार्ग से बगहाँ जज साहब के घर तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन लाल व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बंधित दो याचिकाएं †

1. जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर नगर पंचायत में राजकीय बालिका इण्टर कालेज सैदपुर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा
2. जनपद गाजीपुर सैदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नसीरपुर बासुपुर ग्राम सभा के पास एन0एच0-29 के बगल में जागतानन्द बाबा धार्मिक स्थल का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयनाथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका, उपस्थित की हुई मानी गई।

† छापी नहीं गई।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी,सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका†

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड पडरौना में जलपा माई स्थान के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री गोलू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री दिनेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं †

1. जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में जर्जर ध्वस्त सिंचाई विभाग के डाक बंगले के स्थान पर नये बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,
2. जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में विभिन्न विकास खण्ड के बाजारों एवं ग्राम सभा में नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंजित कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,
3. जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में युवाओं को खेलने के लिए स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंजित कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,
4. जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में राजकीय आई0टी0आई0 कालेज खोलने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका, तथा
5. जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत चन्दवक में स्थित पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में 30 शैय्या मैटरनिटी विंग का भवन निर्माण कराये जाने विषयक श्री रंजित कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित हुई मानी गई।

श्री राहुल प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका †

जनपद मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में कतिपय मुख्य सम्पर्क मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बत पाँच याचिकाएं †

1. जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम नयापुरवा में दुर्गा कुआँ से नयापुरवा तक 2.5 किमी0 पक्की सड़क निर्माण कराये जाने विषयक श्री कालका प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

† छापी नहीं गई।

2. जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के कुठौंद ब्लाक के करमुखा ग्राम में दशरथ सिंह के दरवाजे से हरशंकरी के कुआं तक नई सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविंद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,
3. जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी क्षेत्र के जोल्हूपुर मोड़ से मदारीपुर मार्ग में विद्युत पोल हटाने के सम्बन्ध में श्री हरनारायण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,
4. जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी क्षेत्र के ग्राम सिरसाकलार में थाना चौराहा से बावई रोड पर स्थित गंदा नाला तक नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरूण मिश्रा व अन्य की याचिका, तथा
5. जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी क्षेत्र के ग्राम करमचन्द्रपुर में 3 कि0मी0 पक्का रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री शत्रुधन सिंह राठौर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं †

1. जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नेवादा में छपिया मन्दिर मार्ग से नेवादा गांव तक सम्पर्क मार्ग दूरी 2 कि0मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,
2. जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खुटिहन से महराजगंज ग्रन्ट होते हुए बस्ती बार्डर तक सम्पर्क मार्ग दूरी 3 कि0मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिन्टू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,
3. जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत छपिया मन्दिर मार्ग से ग्राम पंचायत नरैचा में सैदनपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,
4. जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत केशव नगर ग्रन्ट पश्चिमी में बाबूडीह होते हुए बिजहरिया तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजीत वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका, तथा
5. जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अगया में कचेरनडीह होते हुए कूकनगर ग्रन्ट पिच मार्ग तक 03 कि0मी0 मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

† छापी नहीं गई।

श्री संजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं †

1. जनपद सोनभद्र की तहसील राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा महुवाव के बलुई बांध से ग्राम चिरहोली के बलुआ बांध तक बांध का पानी ले जाने के सम्बन्ध में श्री परमेश्वर यादव व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,
2. जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा के अन्तर्गत अमरेनिया चंचलिया मार्ग पर बिजुल नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,
3. जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा के अन्तर्गत तरगरा-बरगवां मार्ग पर पीपा का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,
4. जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा के अन्तर्गत खैरटिया-चकाड़ी मार्ग पर रेणुका नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका, तथा
5. जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा के अन्तर्गत जोगवल ग्राम में मोबाइल टावर लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुनाथ खरवार व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं†

1. जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर की ग्राम पंचायत नगदही में दुर्गापुरवा उदवतनगर के मध्य लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुपम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,
2. जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में प्राचीन मन्दिर सिद्धपीठ मां बारही देवी जी के स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित कर समस्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरा सिंह मधुर व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,
3. जनपद गोण्डा की तहसील एवं विकास खण्ड तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जमथा में 84 कोसी मार्ग पर स्थित यमदग्नि मुनि आश्रम को पर्यटन के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रदेव पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,
4. जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर के अन्तर्गत ग्राम सोनौली मुहम्मदपुर में बच्ची माझा में लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका, तथा

---

† छापी नहीं गई।

5. जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर के अन्तर्गत गंगरौली, उतरी, भवानी, आदमपुर, तिरमुहानी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री होली वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मूलचंद्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं †

1. जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम जाजेपुरा में पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार राठौर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,
2. जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत कोंच से महेशपुरा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाखन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,
3. जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत सदूपुरा से रेढ़र सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,
4. जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत धन्जा से महतवानी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामलखन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा
5. जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत कुदारी से नहर तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरू त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद जालीन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका †

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अरनिया के अन्तर्गत ग्राम कहरौला तिराहे से ग्राम कहरोला की आबादी क्षेत्र तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री योगेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रवि कुमार सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका †

जनपद बस्ती की तहसील बस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड बहादुरपुर में चन्दोताल पक्षी विहार के सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक श्री प्रेम प्रकाश चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री उमाशंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका †

जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की ग्राम सभा अतरसुवा से सिलहटा के बीच टोंस नदी के तट पर बने अधूरी रिंग बंधा को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री रमाकान्त सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

1. जनपद आगरा ग्रामीण की खारी नदी में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री मेघ सिंह चाहर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,
2. जनपद आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत बरौली अहीर, बिचपुरी, अकोरा में फायर स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा
3. जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण में पेयजल हेतु पचगाईखेड़ा में गंगाजल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं †

1. जनपद मेरठ के अन्तर्गत ब्लाक खरखौंदा में ग्राम धनौटा में मेरठ-हापुड़ रोड से प्राथमिक स्कूल तक रास्ते का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री आशीष प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,
2. जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम दबथला में महेश पाल के खेत से ओमपाल सिंह के खेत तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कर्मवीर व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,
3. जनपद मेरठ के अन्तर्गत ब्लाक खरखौंदा में ग्राम अतराड़ा नलकूप 86 से नलकूप 13 बधौली वाली रोड तक रास्ते का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,
4. जनपद मेरठ के अन्तर्गत ब्लाक खरखौंदा में ग्राम नंगला कबूलपुर से आश्रम तक रास्ते का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री सत्यवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका, तथा
5. जनपद मेरठ के अन्तर्गत ब्लाक माछरा ग्राम रहदरा में नरेश पुत्र संगत के खेत से श्मशान घाट तक रास्ते का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं †

1. जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड कुन्दरकी की ग्राम पंचायत नगला हाशा को नई ग्राम पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरमान हुसैन व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

† छापी नहीं गई।

2. जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम मानकपुर से ग्राम भैंसोड़ और गुरेर तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री कयूम, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,
3. जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड मूंडापांडे के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महेशपुर भीला को ग्राम पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शादाब अली व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,
4. जनपद मुरादाबाद के ग्राम करनपुर, विकास खण्ड डींगरपुर कुन्दरकी तहसील बिलारी को नई ग्राम पंचायत बनाने के सम्बन्ध में श्री वाजिद अली व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका, तथा
5. जनपद मुरादाबाद के ग्राम अहमदपुर, विकास खण्ड मूंडापांडे को नई ग्राम पंचायत बनाने के संबंध में श्री इरशाद हुसैन व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

1. जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम सभा कटरा दयाराम में कटरा दयाराम बागी बाजार से राम सुमेर के घर तक ल0 1 कि0मी0 काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सुमेर व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,
2. जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में विकास खण्ड सोरांव में ग्राम सभा लखरांवा में काली सड़क से हरिशचन्द्र पुजारी के घर तक ल0 400 मी0 इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,
3. जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहरिया में ग्राम सभा सारीपट्टी में अत्यन्त प्राचीन शिव मंदिर (फुटहवा महादेव मंदिर) को पर्यटन स्थल घोषित कर इसका सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय केसरवानी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,
4. जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम सभा पिपरी में सम्पर्क मार्ग शेखपुर मंदिर से राम निहोर के घर तक ल0 1 कि0मी0 काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम निहोर व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका, तथा
5. जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम सभा जगदीशपुर में काली मां के पूजा स्थल से जगदीशपुर तालाब तक ल0 500 मी0

† छापी नहीं गई।

नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नोखेलाल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अरूण कुमार यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अरूण कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत तमसा कुबेर मझुई ओंगरी नदियों के किनारे घने जंगलों को वन क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की गई मानी गई।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं†

1. जनपद उन्नाव के ग्राम व पो0 रायपुरगढ़ी ब्लॉक नवाबगंज में स्वच्छता मिशन के तहत छूटे लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,
2. जनपद उन्नाव के ग्राम कठिघरा कुरसठ ग्रामीण विकास खण्ड बाँगरमऊ में स्वच्छता मिशन के तहत छूटे लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,
3. जनपद उन्नाव के ग्राम सालेह नगर मजरा करौदी विकास खण्ड सफीपुर में स्वच्छता मिशन के तहत छूटे लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,
4. जनपद उन्नाव के ग्राम कुलहा विकास खण्ड मियाँगंज में स्वच्छता मिशन के तहत छूटे लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरा लाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका, तथा
5. जनपद उन्नाव के ग्राम भेडहाखेड़ा मजरा राजेपुर ग्रान्ट, विकास खण्ड एफ-84 में स्वच्छता मिशन के तहत छूटे लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं †

1. जनपद जालौन के तहसील उरई के विकास खण्ड डकोर के ग्राम ऐंधा में हसनेपुर मौजा के सिंचाई की समस्या के निदान के लिये एस0टी0डब्लू0 के सम्बन्ध में श्री राज जी राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,
2. जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एट नगर पंचागत के कोटरा मोड़ से प्रमोद मित्तल के घर के सामने नाला साधाई एवं अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद मित्तल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

† छापी नहीं गई।

3. जनपद जालौन के तहसील उरई के विकास खण्ड डकोर के ग्राम ऐंथा में तारा के खेत से सोमई तक ऐंथा माइनर को जोडने के सम्बंध में श्री जुझार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका
4. जनपद जालौन के तहसील उरई के विकास खण्ड डकोर के ग्राम टिमरों में जैसारी मोड़ से डकोर माइनर तक चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सोनी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका, तथा
5. जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई-221 के विकास खण्ड डकोर में शारदापीठ (बैरागढ़धाम) के पास प्राचीन कूप के पुनः निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय राठौर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गई।

श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका

जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील बाह के ग्राम बिजौली कस्बे से तहसील रोड तक नाला निर्माण एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका

जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत मन्नू नागर से मानपुर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री आसेराम व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं †

1. जनपद देवरिया के विकास खण्ड देवरिया सदर में मोहल्ला उमा नगर स्थित राजेन्द्र चौक के दक्षिण सड़क के बीचों-बीच स्थित विद्युत पोल को हटवाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,
2. जनपद देवरिया के विकास खण्ड देवरिया के रूद्रपुर मोड़ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के निकट ग्राम कठीनइया ग्राम में विद्युत पोल लगवाने तथा विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र कुमार दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,
3. जनपद देवरिया के विकास खण्ड देवरिया सदर में पुराना पोस्टमार्टम चौराहे पर स्थित श्रीमती पूनम सिंह पत्नी प्रमोद सिंह आदि के मकान के ऊपर से 11 हजार वोल्ट के विद्युत तार को हटवाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूनम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

† छापी नहीं गई।

4. जनपद देवरिया के विकास खण्ड गौरी बाजार के ग्राम देवतहां में शिव मंदिर में विद्युत पोल लगवाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका, तथा
5. जनपद देवरिया के विकास खण्ड देवरिया के ग्राम नई बस्ती दानोपुर में दर्जनों गांवों में विद्युत कनेक्शन बाँस बल्ली के स्थान पर विद्युत पोल लगवाने के सम्बन्ध में श्री विपिन दुबे व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित आठ याचिकाएं †

1. जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा चितार में शहीद भगत सिंह विद्यालय से पाल बस्ती तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री रमेश बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,
2. जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा परमेठ में भटौली मदनही सम्पर्क मार्ग से बसंगित बिन्द के मकान होते हुए काली माता मंदिर तक ढक्कनदार नाली व सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री जीवधन बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,
3. जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा शिकारपुर में विश्वनाथ बिन्द के मकान से लेकर देवकरन बिन्द के घर होते हुए रामकेर बिन्द के मकान तक ढक्कनदार नाली एवं सड़क निर्माण कराने के सम्बन में श्री रामजी बलवन्त व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,
4. जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के नगर पालिका गाजीपुर के अन्तर्गत रजागंज पुलिस चौकी से काली माता मंदिर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,
5. जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम डिलियाँ में रेलपुर चट्टी से हरिहरपुर सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,
6. जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत बनगावाँ सौरम सम्पर्क मार्ग से (बालगोविन्द सिंह के खेत से) बनगावाँ बासा बांध पिच रोड तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,
7. जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम करण्डा में रामऔतार कुशवाहा के घर से सोल्हनपुर बिन्द बस्ती तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा
8. जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा भिक्खेपुर गोडाकलां से पड़री होते हुए छतमा चट्टी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामलक्षन चौहान व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर व जनपद उन्नाव से सम्बन्धित एक-एक याचिका†

1. जनपद हमीरपुर के तहसील सरील के ग्राम बरहरा (ब्रह्मानन्द धाम) में स्थित अति प्राचीन 'बजरंग आश्रम' की चहारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका, तथा
2. जनपद उन्नाव के ब्लाक पुरवा के अन्तर्गत पुरवा मुख्य रजबहा के एक किनारे पर पुरवा बीघापुर मार्ग से लेकर पुरवा-पाटन मार्ग तक डामर रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बेनी प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

1. जनपद मथुरा में छुट्टा घूम रहे गौवंश के लिए गौ-शाला बनाकर संचालित करवाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश मुखिया व अन्य निवासीगण जनपदमथुरा की याचिका,
2. जनपद मथुरा में स्थित स्टेडियम नौहझील, मांट, शेरगढ़ को उच्चीकृत किए जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका, तथा
3. जनपद मथुरा के वृन्दावन से पानीगांव डांगोली होते हुए मांट मार्ग को 4-लेन कराए जाने के सम्बन्ध में श्री केशव उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

1. जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर, विकास खण्ड पतारा के पड़री लालपुर में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंक अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,
2. जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के ग्राम चँवर में होम्योपैथिक अस्पताल के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,
3. जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत नोन नदी पर राहा एवं बम्बुराहा के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका, तथा
4. जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत एन0एच0-34 को 6 लेन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

† छापी नहीं गई।

श्री प्रमोद उटवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

1. जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम नूरनगर से मारकपुर तक सड़क की मरम्मत/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज जोधा व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,
2. जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम चानचक से शेरपुर लिंक मार्ग का मरम्मत/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 ब्रजमोहन व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,
3. जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम सरवट में पचैण्डा रोड से नसीरपुर लगभग 1.5 मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन पाल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा
4. जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम आखलौर में चतर के मन्दिर से भट्ठे तक लगभग 1.5 मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक धीमान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

1. जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुन्दपुर एवं मर्दनपुर के मध्य स्थित नहर की संकरी पुलिया का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,
2. जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली अन्तर्गत कतिपय ग्राम पंचायत बिसारा, मवई, करदहा, नरीचक, असरीखेड़ा, बहवा, हिलौली एवं सगौली में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनमोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका, तथा
3. जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बछौरा में अन्त्येष्ठि स्थल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अध्यक्ष-

अब फिर से चर्चा जारी रहेगी।

(कतिपय सदस्यों द्वारा यह कहे जाने पर कि नियम-51 की सूचनाएं ले लें)

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

सभी नेताओं ने कहा कि नियम-51 की सूचनाएं बाद में लेना है, इसलिए चर्चा जारी होगी। मा0 सदस्यों के भाषण वाली सूची जिसके अनुसार लोग बोल रहे थे। वह सूची हमारे

† छापी नहीं गई।

पास नहीं है इसलिए जो सदस्य इधर से न बोले हों, वे अपना हाथ उठाएं। चलिए ठीक है, आप बोलिए।

श्री रमेश चन्द्र दिवाकर-

मा0 अध्यक्ष जी, अपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारी सरकार ने जो 05 लाख 50 हजार 270.78 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश किया है, उसको पूरे हिन्दुस्तान ने सराहा है। मा0 अध्यक्ष जी, इस बजट में सभी पहलुओं को छुआ गया है। चिकित्सा, सुरक्षा, शिक्षा, यातायात, जवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापरियों के लिए और युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ इस बजट में दिया गया है।

मैं पहले अपने विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा औरैया विधान सभा क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र में पड़ता है और औरैया शहर से जो एन0एच0-2 बाईपास निकला है तो उससे ज्यादा से ज्यादा शहर बाईपास के राइट हैण्ड पर है। कानपुर से जो गाड़ियाँ आती हैं, शहर के अन्दर नहीं घुस पाती हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, औरैया शहर के लिए दो फ्लाई ओवर ब्रिज की बहुत आवश्यकता है एक तो दयालपुर चौराहे से शहर के अंदर और दूसरा फ्लाई ओवर मण्डी समिति से समरथपुर की तरफ जिससे औरेया के वाहन इटावा की तरफ स्वतंत्रता से जा सकें। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र औरैया में लगभग 300000 मतदाता रहते है वहाँ कोई भी पार्क नहीं है। पूरे जिले में कोई भी सौन्दर्यीकृत पार्क नहीं है इसलिए औरैया शहर में एक 11 एकड़ का तालाब पड़ा है उसमें एक आधुनिक पार्क बनवाने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा औरैया जिला प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र के मामले में दूसरा स्थान रखता है, वहाँ पर कोई भी महिला डिग्री कालेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारी औरैया विधान सभा 204, में डिग्री कालेज बनवाने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, देवकली मंदिर जहाँ जयचन्द जो कन्नौज के राजा हुआ करते थे उनकी बेटी की ससुराल जगम्मनपुर में थी और वह देवकली मंदिर जो वहाँ पर बना हुआ है उनकी पूजा-पाठ के लिए एक सुन्दर मंदिर बनवाया गया था। मैं यह चाहता हूँ कि वहाँ पर औरैया जिले के लिए एक स्थायी नुमाइश ग्राउण्ड बनवाने की कृपा करेंगे।

मान्यवर, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि राजकीय इण्टर कालेज बनवाने के सम्बन्ध में मा0 उप मुख्य मंत्री दिनेश शर्मा जी के यहाँ बहुत पहले से फाइल पेण्डिंग पड़ी हुई है लेकिन अभी तक उस पर कोई बजट नहीं मिला है। मैं अपने मा0 वित्त मंत्री जी से जरूर यह कहना चाहूँगा कि इण्टर कालेज का बजट पास करने की कृपा करें और मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं न्याय और कानून के मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा इस सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ कि विपक्ष यह कहता है और खासकर हमारे माननीय और आदरणीय जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है श्री राम गोविन्द चौधरी जी, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप यह देखिए, मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ मैं उस जगह का रहने वाला हूँ जहाँ यह समाजवादी पार्टी पैदा हुई है। माननीय अखिलेश यादव

और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के गढ़ का मैं रहने वाला हूँ, मैं औरैया विधान सभा सदर 204 का रहने वाला हूँ। मैं इस सदन को एक बात बता दूँ कि इटावा में एक हत्या हुई थी, जब आपका शासन था। उस समय भरथना में एक तेज तर्रार एस0आई0 द्वारा स0पा0 के माफिया की शराब पकड़ ली गयी। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनकी सरकार में कैसी कानून-व्यवस्था थी, इटावा में उसी समय चुनाव होने वाले थे, उस एस0आई0 का स्थानान्तरण इटावा में कर दिया गया था। महोदय, मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ ताकि मैं अपने भाइयों को बता दूँ बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं कि ये हो रहा है हमारी सरकार में वो हो रहा है। लेकिन इटावा में क्या हुआ, जब नामांकन के लिए पाँच आदमी जाते हैं, उसकी ड्यूटी उसी गेट पर लगी हुई थी और महोदय उन्होंने एक नेता को रोक दिया और उस निर्दोष एस0आई0 की वहीं अंदर गोली मार कर हत्या कर दी गयी वह भी दिन के 12:00 बजे और आज तक उस विधवा महिला को न्याय नहीं मिला है। बहुत चिल्लाई, बहुत अनशन हुआ लेकिन आपकी सरकार में न्याय नहीं मिला। मैं एक उदाहरण और देता हूँ, मैं अपने समाज का 5-6 जिलों का अध्यक्ष भी हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि एक हत्याकाण्ड हुआ जिसमें चन्दौसी में दो लोग मारे गये और मुझको वहाँ जाना पड़ा, मारने वाले भी हमारे अपने ही आदमी थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मा0 अध्यक्ष जी कि जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ दो लोग गिरफ्तार हुये और चार लोग गिरफ्तार नहीं हुये।

जबकि वह अपोजिट पार्टी के थे। मैं वहां से सीधा लखनऊ आया। लखनऊ आकर मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया, आग्रह किया कि जिन लोगों ने हत्या की है, वह बच गये। मैं आपको बता दूँ कि मैं वहां से उतर नहीं पाया था और मा0 मुख्य मंत्री जी का आदेश हुआ। फिर वे चारों हत्यारे पकड़े गये जबकि वह मेरी ही पार्टी के थे। यह है भारतीय जनता पार्टी, और यह है हमारे मुख्य मंत्री जी का न्याय। मान्यवर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा। जहां मैं रहता हूँ चूंकि मेरा बिहड़ांचल क्षेत्र है, जहां लोग चम्बल नदी के नाम से कांप जाते हैं। वहां पर इनकी सरकार में हमारे प्राइमरी के टीचर, वहां लोग पढ़ाने नहीं जाते थे। महोदय, वह कह देते थे कि हमें सस्पेण्ड कर दो, हमें बर्खास्त कर दो लेकिन मैं वहां पर नहीं जाऊँगा। इतना आतंक था और इतनी भयानक स्थिति थी। हमारी सरकार में, आज जब मैं वहां बीहड़ क्षेत्र में घूमने जाता हूँ तो अपने मतदाताओं के पास भी जाता हूँ। शाम के 6-7 बजे हमारी बहनें बकरियाँ लेकर जा रही थीं चूंकि गांव में उनके लिए कोई रोजगार नहीं है तो हमने उनकी माताओं से पूछा कि माता जी, यह बहनें बीहड़ में जा रहीं तो आपको डर नहीं लगता है ? तो वह कहती है कि बेटा, डर-वर सब भाग गया है, जितने बदमाश थे, सब चले गये। जो जिसका अपराध था, छोटा अपराध और बड़ा अपराध उनके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी की डायरी में सभी अपराधों की अलग-अलग सजा है। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ। जो मैंने कहा है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ी हुई है, उसके लिए मैंने जो यहां से बोला है, उसमें आप अपनी पीठ से मा0 वित्त मंत्री जी को जरूर आदेशित करने की कृपा करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस बजट पर मैं अपनी पूर्ण रूप से सहमति व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अनुपूरक कार्य-सूची की मदों को आज ही लिए जाने का अनुरोध

***वित्त संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, अभी कार्यमंत्रणा समिति की शायद मीटिंग है। आपने 5 बजे का नोटिस जारी किया है। यदि आप एक-दो बिल इस समय टेबल करवा दें। जो सप्लीमेंट्री एजेण्डा आया है। इसके पहले कि मा0 सदस्य बोलें तो यह टेबल हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुजा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

***संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का अंश का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब कल तक चर्चा जारी रहेगी। चर्चा आज भी होगी और कल भी होगी।

(इस समय 05 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री फतेह बहादुर पीठासीन हुए)

श्री सत्यवीर त्यागी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021-22 के पेपरलेस बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति का बोधक्षेत्र है। यहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम तीर्थराज प्रयागराज है। यहाँ वर्ष 2019 में दुनिया के सबसे बड़े कुम्भ मेले का अभूतपूर्व एवं भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्य कुशलता, लगन, निष्ठा एवं धार्मिक आस्था के प्रति समर्पण के लिए हृदय की गहराई से मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। कोरोना काल में प्रबन्धन में सराहनीय योगदान के लिए मैं माननीय योगी जी को कोटि-कोटि बधाई देता हूँ। मान्यवर, मेरठ से प्रयागराज तक 637 किलोमीटर लम्बा गंगा एक्सप्रेस-वे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे होगा, जिसके निर्माण का निर्णय मा0 योगी जी की सरकार द्वारा लिया गया है, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी की जितनी भी प्रशंसा की जाय कम होगी, मान्यवर, किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम यह एक्सप्रेस-वे करेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यह एक्स्प्रेस-वे मेरे विधान सभा क्षेत्र किठौर के अनेकों गांव से होकर गुजरेगा, जैसे बिजौली से शुरू होकर धनौटा, खन्दावली, खानपुर, नंगला, पातु, गोविन्दपुरी, भदौली, अन्तराड़ा, रजपुरा, अटौला, सफियाबाद, लौटी आदि अनेक गांवों के बीच से होते हुए हजारों-हजारों किसानों, युवाओं, मजदूरों, महिलाओं की मालीहालत में सुधार व रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला यह एक्सप्रेस-वे किसानों की उन्नति में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं मा0 योगी जी और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरठ में खेल प्रतिभाओं को सम्मान देते हुए अर्न्तराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के लिए बजट आवंटित कराने का प्रावधान किया गया है। मा0 योगी जी व वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी एवं खेल मंत्री श्री उपेन्द्र तिवारी जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरठ में विश्वस्तरीय खेल विश्वविद्यालय निर्माण कराने का निर्णय लिया। खेल जगत से जुड़े युवा छात्र-छात्राओं की प्रतिभा को निखारने का काम यह विश्वविद्यालय करेगा। मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को इसका लाभ होगा। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी एवं उप मुख्य मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का धन्वाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा निर्माणाधीन सड़कों एवं मार्गों हेतु विभागीय बजट में धन आवंटित कर कार्य कराये जाने का प्राविधान किया। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे क्षेत्र

के ब्लाक माछरा में एक कृषि कल्याण केन्द्र एवं खरखौंदा ब्लाक में दूसरा कृषि कल्याण केन्द्र खोलने की अनुमति देने के लिए बजट आवंटित कराने के लिए मेरे क्षेत्र को शामिल किया है।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का तथा माननीय ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी विधान सभा क्षेत्र के तीन विद्युत उपकेन्द्र नंगली किठौर कैसी व नगर पंचायत शाहजहाँपुर में निर्माण कराने का निर्णय लिया है इसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।

गन्ना मिलों द्वारा 19 जून, 2020 को 418 करोड़ से 1 लाख 23 हजार करोड़ अब तक का रिकार्ड गन्ना बकाया का भुगतान हमारी सरकार ने किया है, इसके लिये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री और माननीय गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र के नंगलामल में किसानों के बकाया भुगतान के लिये मिल मालिकों, प्रबन्धकों को आदेशित करने का भी कार्य किया है। मोहिउद्दीनपुर मिल तथा रमाला मिल की पेराई क्षमता बढ़ाये जाने का भी मैं स्वागत करता हूँ।

मान्यवर, मैं पंचायत राज मंत्री भूपेन्द्र सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 10 पंचायत घरों तथा दर्जनों अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु निर्णय लिया है। मान्यवर, कृषि क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की आय दोगुना बढ़ाने के लिये तीन कृषि कानूनों को लागू करने में माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी व उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पहल करके सराहनीय कार्य किया है। विरोधी दल के नेता जो घड़ियाली आँसू बहाने वाले आपकी सरकारें जिस कानून को लागू करने का साहस नहीं दिखा पायीं उस कानून को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे देश और प्रदेश में लागू कर दिखाया है। किसान अपनी उपज का जिले से बाहर और प्रदेश से बाहर जहाँ भी उसको सही दाम मिलेगा, वह बेचने के लिये स्वतंत्र होगा, इसका प्रावधान इस बिल में किया गया है। वह अपनी उपज को मंडी में भी बेच सकता है इसके लिये सभी विकल्प खुले हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा, मोदी जी द्वारा बार-बार यह स्पष्ट किया जा चुकें है।

"कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता
एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो"।

"किसानों, विपक्षियों के झूठ से सावधान, कृषि विधेयक ने किया है तरक्की का प्रावधान"। जो इनके द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं उसका उत्तर जरूर देना चाहूँगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिये कृषि बिल एक साजिश है, यह झूठ किसानों को परोसा जा रहा है। इसका जवाब है कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना-देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला है, मिल रहा है और मिलता रहेगा। अब मंडियों का अन्त हो जायेगा यह भी झूठ फैलाया जा रहा है। इसका जवाब है कि मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी, जारी है और थी इसलिये यह भी

झूठा प्रचार किया जा रहा है। कृषि बिल किसान विरोधी है, इसमें हमारा कहना है कि कृषि बिल किसान की आजादी है वन नेशन वन मार्केट अब किसान अपने उत्पाद कहीं भी देश के किसी भी कोने में, प्रदेश के किसी भी कोने में बेच सकता है। आढ़तियों और दलालों पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन समितियों के साथ पार्टनर बनकर किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। बड़ी कम्पनियाँ कान्ट्रेक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेंगी यह झूठ फैलाया जा रहा है। इसका जवाब है करार से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी, लेकिन किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जायेगा। किसान किसी भी मोड़ पर करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। वह भी किसी पेनाल्टी की समय सीमा के साथ। ठेका खेती कान्ट्रेक्ट फार्मिंग पहले भी होती रही है, मैं स्वयं ठेकेदार से खेती करा रहा हूँ, मुझे पर बीघा 5 हजार रुपया बटाईदार या ठेकेदार देता है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री सत्यवीर त्यागी-

जबकि अभी तक कई ठेकेदारों के फोन आ रहे हैं कि वह 25 से 30 हजार रुपये बीघा पर लोग लेने को तैयार हैं। यह भी प्रचार किया जा रहा है कि किसानों की जमीन पूँजीपतियों को दी जायेगी या कब्जा हो जायेगा। लेकिन बिल में साफ निर्देश हैं कि किसानों की जमीन की बिक्री लीज और गिरवी रखना पूरी तरह से कानूनी अपराध होगा। यह भी प्रचार किया जा रहा है कि यह बड़े कॉर्पोरेट का फायदा और किसान का नुकसान करेगा। कई राज्यों में किसान सफलतापूर्वक बड़े कॉर्पोरेट के साथ गन्ना, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब छोटे किसानों को बड़ा फायदा, उनको गारंटी मुनाफे के साथ मिलेगा, टेक्नॉलॉजी और उपकरण का लाभ भी उन्हें मिलेगा। अब मैं संक्षेप कर दे रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया आप समाप्त कर दें।

श्री सत्यवीर त्यागी-

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं क्षेत्र की समस्याओं पर आ रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप कहेंगे तो मैं उसे कार्यवाही में जुड़वा दूँगा, अगर ज्यादा हो।

श्री सत्यवीर त्यागी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं विधान सभा क्षेत्र किठौर के लिए कुछ कार्यों को कराये जाने के लिए आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ। मान्यवर, इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र किठौर में पूर्वी काली नदी जो मेरे विधान सभा क्षेत्र किठौर के बीच से होकर गुजर रही है, लगभग 60 गाँवों में प्रदूषित पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं, जिससे वे कैंसर, हृदय रोग,

किडनी जैसी बीमारियों का शिकार होकर मृत्यु के आगोश में समा जा रहे हैं। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उन गाँवों को चिन्हित करके पेयजल योजना हर घर नल, हर घर जल के तहत प्राथमिकता के आधार पर शामिल कराया जाये। अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गाँव नगला मल में जो आदिशंकराचार्य का मन्दिर एवं शंकर ताल जैसी पौराणिक धरोहर है, उसका जीर्णोद्धार कराने की कृपा करें। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र किठौर के नगर पंचायत किठौर के पौराणिक व ऐतिहासिक नाम कृष्णठौर होने के कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे किठौर में पुरातन मन्दिर, शिव मन्दिर में श्रीकृष्ण जी मथुरा से हस्तिनापुर जाते हुए ठहरते थे। हापुड़ पक्का बाग से होते हुए दौयमी, धनौरा एवं बझीलपुर, खडखडी, सफियाबाद लौटी असरा, रथ यात्रा से होते हुए भगवान श्री कृष्ण जी किठौर हस्तिनापुर जैसे ऐतिहासिक मार्ग से जाते थे, उसका नाम श्रीकृष्ण मार्ग करने का निवेदन मैं आपके माध्यम से करता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र स्थित कस्बा नगर पंचायत किठौर का नाम बदलकर पौराणिक व ऐतिहासिक नाम कृष्णाठौर कराने हेतु माननीय अधिष्ठाता जी आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूँ तथा इस ऐतिहासिक मार्ग का नाम श्री कृष्ण मार्ग रखने की मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूँ और अपने विधान सभा क्षेत्र के कस्बा खरखौंदा में 50 बेड का आयुष अस्पताल बनवाने की माँग करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री सत्यवीर त्यागी-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीनों ब्लाकों क्रमशः खरखौंदा, माछरा व रजपुरा में 03 गौशालायें खुलवाने के लिए धन आवंटित कराने की कृपा करें, धन्यवाद।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं बजट पर माननीय नेता प्रतिपक्ष के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखना चाहूँगा। अभी हमारे एक मित्र हैं, औरैया के माननीय विधायक जी, वह शायद सामने खड़े हैं। अभी उन्होंने औरैया का एक दृष्टांत रखा था। मैं अपने यहाँ की आज की घटना बता रहा हूँ। मेरे यहाँ जनपद मैनपुरी की बात है।

(सत्तापक्ष में सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

घटना बताना भी जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता-

आप बजट पर चर्चा करें, उचित रहेगा।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

मान्यवर, घटना बताना जरूरी है, मैं इसके बाद बोलूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

वह किसी नियम में ले आइयेगा। इस समय बजट पर चर्चा करिये।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

आप हमारी कोई बात ही नहीं सुनना चाहते। अभी औरैया वाले विधायक जी बोले तो आपने सुन लिया। अब हम बोल रहे हैं तो नहीं सुन रहे हैं।

(सत्तापक्ष में सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शान्त रहिए।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

अभी औरैया के माननीय विधायक जी हमारे बचपन के मित्र हैं, इन्होंने घटना का दृष्टांत सुनाया था। अब मैं एक दृष्टांत सुना रहा हूँ, आपके यहाँ के व्यक्ति निवासी ग्राम रहटोरिया, थाना अछल्दा, जनपद औरैया, नाम राजू पुत्र श्री सूरजपाल, ये अपनी बहन की अन्त्येष्टि में शामिल होने के लिए मेरे यहाँ आ रहे थे। रास्ते में काफी रात हो गई थी, रास्ते में इनको किसी ने लूट लिया और उनको नशे की गोली खिलाकर चले गये। जब उनको होश आया तो पता चला कि उनकी पत्नी को चार अपराधी एटा की तरफ लेकर चले गये। जब होश आया तो किसी से नम्बर ले करके इन्स्पेक्टर साहब को फोन किया तो थाना बिछवां में अरे साहब, आपने सुनाया तो कम से कम हमारी भी तो सुन लो यहाँ भी बात नहीं सुनी जायेगी तो अधिष्ठाता जी कहाँ सुनी जायेगी। मान्यवर, इंस्पेक्टर का नाम था राजेश पाल सिंह।

श्री अधिष्ठाता-

आप हमें सम्बोधित करें।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

माननीय विधायक जी के क्षेत्र की घटना है, जब इंस्पेक्टर साहब पहुंचे और वह दलित समाज माननीय विधायक जी के समाज की महिला थी, उसे चार अपराधी लेकर चले गये। जब वह व्यक्ति बेहोशी से उठा, जब उसने बताया कि मेरी पत्नी को चार अपराधी पकड़ कर ले गये और मुझे मारा है, मान्यवर, उसको मार-मार करके उसकी पीठ लाल कर दी। चार लोग बेचारी असहाय महिला के साथ दो घण्टे तक बलात्कार करते रहे, उसके बाद कुरवाली थाने में इंस्पेक्टर के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया लेकिन अधिष्ठाता महोदय आज भी उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और चार्जशीट में उसे बचाने का काम किया गया। यह है कानून-व्यवस्था, और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जबसे सरकार बनी है तबसे दलितों के साथ निरन्तर घटनाएं बढ़ी हैं, पूरा दलित समाज अपने आपको दहशत में महसूस कर रहा है, लोगों की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, माताओं-बहनों के साथ जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि आज आम आदमी उत्तर प्रदेश का सरकार के नुमाइन्दों से परेशान है। महोदय, अभी सदन में कोरोना काल के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें हुईं। अभी नेता

सदन माननीय मुख्य मंत्री जी भी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जाने क्या कर दिया। मैं मानता हूँ कि कोरोना एक दैवीय आपदा थी, उस दैवीय आपदा से निपटने के लिए न केवल हम सदन के लोग, राजनीति करने वाले लोग बल्कि सामाजिक लोगों ने और आम आदमी ने बढ़-चढ़ कर सहयोग दिया है लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। एक वीडियो वायरल हुआ था, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उसके बारे में बताऊंगा तो उससे पता चलेगा कि आखिर किस दहशत में आदमी रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक कुत्ता एक्सीडेंट से खत्म हो गया था, प्रवासी मजदूर जा रहे थे और उन प्रवासी मजदूरों में से एक मजदूर इतना भूखा था कि मरे हुए कुत्ते का मांस खाने लगा, इससे ज्यादा शर्मसार बात और क्या हो सकती है। कितने व्यापारियों, कितने लोगों पर मुकदमें लिखे गये, कोरोना की बीमारी से जितने लोग नहीं खत्म हुए उससे ज्यादा लोग इलाज न मिलने के कारण खत्म हो गये। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस कोरोना टाइम में जिन निर्दोष लोगों पर मुकदमें लिखे गये, उनके मुकदमें वापस किये जाएं। मेरे साथी विधायक बहुत लोग पीठ थपथपा रहे थे, हम लोगों ने जब मदद करने की कोशिश की तो हम लोगों पर मुकदमें भी लिखाये गये और राशन बांटने से भी रोका गया, इसके बावजूद भी हम लोगों ने भरपूर मदद की। मान्यवर, बेरोजगारी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक दिन ऐसा आयेगा कि लोग किताबों में पढ़ा करेंगे कि एक रिक्शा चालक का बेटा, झोपड़ी में रहने वाले का बेटा बाजार में जाता था, 10 रुपए का फार्म ले आता था, सौ या डेढ़ सौ रुपए की कम्पटीशन की किताब खरीद लाता था और उसके बाद दीपक की रोशनी में पढ़ करके नौकरी पा लेता था, ये ख्वाब अब किताबों में ही रह जायेंगे क्योंकि अब किसी को भी सरकारी रोजगार मिलने वाला नहीं है। सरकारी रोजगार इसलिए नहीं मिलने वाला है जब सरकार की मंशा सरकारी विभाग रखने की ही नहीं है, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ऐसे प्राइवेटाइजेशन के दौर में कोई भी गरीब आदमी अब रोजगार नहीं पायेगा। जहाँ तक एस0सी0 और दलितों की बात है, इनका इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में आरक्षण खत्म कर दिया गया, फीस की जो तमाम रियायतें दी जाती थीं वह सारी रियायतें खत्म कर दी गई।

मान्यवर, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मेरे मा0 अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री थे, तो उस समय सरकार के बजट में "डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना", "मा0 जनेश्वर मिश्र समग्र विकास योजना" तथा "डा0 भीम राव समग्र विकास योजना" के अन्तर्गत गाँव को विकसित करने का काम किया जाता था। आज बजट में इस तरह की कोई भी योजना नहीं जोड़ी गयी है। मैं इसके आगे अपने क्षेत्र की बात रखना चाहूँगा।

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र जनपद मैनपुरी के तहसील किशनी में मुंसिफ कोर्ट की आवश्यकता है, जिसको खोला जाना आवश्यक है। इसी तरह से विकास खण्ड सुल्तानगंज के ग्राम व्योतीखुर्द में 11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन की आवश्यकता है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जागीर (भाँवत पुल) में एक्स-रे मशीन, कुशमरा में नवीन थाना की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब संक्षेप करें।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

मान्यवर, बस इतना ही पढ़ना है। मेरी विधान सभा जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड करहल के ग्राम सड़ में अनइया नदी पर नवीन पुल का निर्माण, करहल किशनी मार्ग पर कुर्रा में वाँसक रजवाह पर बने पुल के दोनों तरफ कैटल घाट का निर्माण कराने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब बहुत हो गया, आप बैठिये।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

मान्यवर, मेरी विधान सभा में कटरा समान, मंछना कैथोली और तखरऊ में पुलिस चौकी बनाया जाना अति आवश्यक है। मेरी विधान सभा क्षेत्र किशनी से राम नगर मार्ग का चौड़ीकरण, किशनी से शमशेरगंज सौरिख मार्ग चौड़ीकरण, कटरा समान से रैचंदा इटावा रोड का चौड़ीकरण, विकास खण्ड जागीर में पुलिया निर्माण, ग्राम नगला धुरा (ओंग) में सेलपुर माइनर पर ट्रांसफार्मर के पास पुलिया निर्माण, विकास खण्ड करहल में नाला की सफाई तथा पशुपुर से हविलिया होकर उझियानी तक नाला सफाई कराने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

श्री नागेन्द्र सिंह राठौर।

श्री नागेन्द्र सिंह राठौर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2021-22 का जो ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, उसके समर्थन में आपने मुझे अपना विचार रखने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश के ऐतिहासिक बजट को पेश करने का कार्य मा0 वित्त मंत्री जी ने किया है, इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 वित्त मंत्री जी का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए उनको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बजट के विषय में विपक्ष की तरफ से हर बार कोई न कोई टीका-टिप्पणी इस तरीके से की गयी है, जैसे लगता है कि इन्हें कुछ सकारात्मक दिखता ही नहीं। देखने का अपना-अपना नजरिया है। अगर आप नकारात्मक सोच के साथ सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको नकारात्मकता ही नजर आयेगी। आप पूरे बजट के परिदृश्य को देखिये। सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के हितों का बजट में ध्यान रखा है। कोविड काल में सरकार को जो सफलता और लोकप्रियता मिली है, उसके कारण विपक्ष को नकारात्मकता और बढ़ी है, इसलिए बजट में इन्हें कोई अच्छाई दिखायी नहीं देती है।

मान्यवर, आज नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 2022 में कर्मयोगी और योगी का चुनाव होगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनका कर्मयोग से मतलब क्या है? क्या कर्मयोगी उन लोगों

को मानते है जो केवल कुछ परिवार, वर्ग और जनपदों की बात करते है या कर्मयोगी उनको मानते है जो पूरे प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते है?

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जहाँ तक कर्मयोगी की बात है, तो इस धरती पर दो ही बार ऐसे मौके आये हैं जब कर्तव्यपरायणता के आगे या तो भगवान राम अपने पिता की अन्त्येष्टि में शामिल नहीं हुए या इस प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी जी, कर्मयोग के कारण अपने पिताजी की अन्त्येष्टि में शामिल नहीं हुए। ऐसे व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ और विपक्ष से यह कहना चाहता हूँ कि आपके यह ख्वाब धरे रह जायेंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी कर्म योगी के साथ ही योगी भी है। आपके पास सिर्फ ढ़कोसला है। इसके बाद मैं अपनी विधान सभा के विषय में आपके माध्यम से 3-4 बिन्दुओं पर निवेदन करना चाहूँगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधान सभा में श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है। श्रृंगी ऋषि के विषय में कहा जाता है। कि जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था तब श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया था तो उस तपोभूमि को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाए और उसके विकास व उस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक बजट दे करके उसका पूर्ण रूप से विकास कराया जाए। मान्यवर, कमालगंज में मड़ियन का पुल विचाराधीन है उसको स्वीकृत किया जाए और उसकी स्वीकृति के बाद दो जनपदों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी कमालगंज और हरदोई उससे जुड़ जायेंगे तथा तीन विधान सभा क्षेत्रों भोजपुर, अमृतपुर व सवायजपुर को इससे लाभ होगा। तीसरे मेरे जनपद में दो ब्लाक हैं, एक कमालगंज, दूसरा मोहम्मदाबाद। कमालगंज में 119 ग्राम पंचायतें है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि कमालगंज विकास खण्ड का विभाजन कर दिया जाये और जहानगंज को नया विकास खण्ड बनाया जाये। दूसरा ब्लाक मोहम्मदाबाद है, जिसमें 90 ग्राम पंचायतें हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह एरिया इतना बड़ा है कि पूरे विकास कार्यों का अगर सुपरविजन हो तो शीघ्रता मे सफलता नहीं मिलती है इसलिए भौगोलिक दृष्टि से मोहम्मदाबाद में भी संकिसा जो बौद्ध जी की तपोभूमि है उसको नया ब्लाक बनाया जाये। आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं पूज्य योगी जी के चरणों में सिर्फ दो पंक्तियां कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा-

कुछ तो चलते पद्चिन्हों पर, कुछ पद्चिन्ह बनाते हैं।
है वो ही शूरमा इस जग में दुनिया में पूजे जाते हैं।।

इसी के साथ अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री डी0सी0 वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, दो दिन पहले से अपना नाम सूची में लिखा रखा है, चूंकि मेरा क्रम था परन्तु आपने माननीय सदस्य को आमंत्रित कर लिया, ऐसे में हम लोगों का कब नम्बर आयेगा। कल भी हम लोग 8:00 बजे तक इन्तजार करते रहे।

श्री अधिष्ठाता-

अभी मैंने सूची के हिसाब से ग्यारहवें नम्बर को बोलने का अवसर दिया है, इसके बाद आपका नम्बर आयेगा। आप बैठ जाइये।

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, एक बहुत अच्छा बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसके लिए मैं अपने सम्मानित वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, जो हमारा इस वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट है वह 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का है, इससे निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार आयेगा। यह बजट गाँव, गरीब, किसान व मजदूरों के उत्थान के लिए है। जिस तरह से कोरोना ने पूरे देश का नुकसान किया और जब हमारे प्रदेश में कोरोना आया तो हमारे प्रदेश में उस समय कोई भी व्यवस्था नहीं थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी की सूझ-बूझ के कारण हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा जन-हानि नहीं हुई है। उस समय न तो हमारे यहाँ मास्क न अन्य चीजें थीं न ही एल-2 लेविल के लैब थे परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी के अथक प्रयास से आज हमारे प्रदेश में 125 सार्वजनिक लैब, 104 निजी लैब स्थापित करके 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन कराये जा रहे हैं, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, 2017 में हमारे इस उत्तर प्रदेश में केवल 15 राजकीय मेडिकल कॉलेज कार्यरत थे इस समय 30 मेड़िकल कॉलेजों में कार्य चल रहा है। 2 वर्ष के उपरान्त हमारे प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज कार्य करेंगे तब ही तो हमारे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरी होगी। मान्यवर, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में 2 एम्स स्तर के मेडिकल कालेज शुरू हो गये हैं। बनारस में एम्स स्तर के मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। हम इसी के साथ माँग करते हैं कि हमारा जनपद बरेली, लखनऊ और दिल्ली से 250-250 किमी0 है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बरेली में भी एक एम्स स्तर का मेडिकल कॉलेज खोला जाय। इसके साथ ही मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मीरगंज क्षेत्र में नदियाँ ज्यादा हैं। राम गंगा सहित आठ बड़ी नदियाँ हैं।

हमारी सरकार ने मुझे अभी तक 6 पुल दे दिये हैं जिसमें लघु सेतु और बड़े सेतु दोनों शामिल हैं। मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ सरकार का कि हमारे यहाँ राम गंगा का बाबा कैलाश मढ़ी पर एक और पुल दे दिया जाय। साथ ही हमारे यहाँ नरखेडा व सिधौंली के बीच नदी पर एक और पुल की आवश्यकता है और इसके साथ ही दिजोडा नदी पर हमारे यहाँ फतेहगंज पश्चिम के बीच एक पुल दे दिया जाय और इसी के साथ हमारे यहाँ एक रोड एन0एच0-24 मीरगंज से हल्दी को जोड़ता है उसका चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव रखता हूँ और इसके साथ ही दूसरा हमारा एक मार्ग है जो एन0एस0-24 से शंखा नदी के पास से हमारा भोजीपुरा के पास नैनीताल बागेश्वर मार्ग को जोड़ता है वह अगर बन जाय तो बरेली में एक बाईपास बन जायेगा। हमारे जो नैनीताल और बागेश्वर से आने वाले लोग हैं वह सीधे

दिल्ली निकल जायेंगे उनको बरेली नहीं जाना पड़ेगा। मान्यवर, इसके अलावा हमारे यहाँ एक 1400 एकड़ जमीन सिन्थेटिक रबर फैक्ट्री की पड़ी हुई है अगर सरकार उसको अपने पक्ष में ले ले वह जमीन इतनी उपयोगी है कि उसके बीच से रेलवे लाइन भी गई हुई है, रेलवे स्टेशन भी वहाँ है और हाई-वे भी उसके बीच से गुजरता है। अगर वह जमीन सरकार के पक्ष में आ जाय तो वहाँ पर एक बड़ा इण्डस्ट्रियल हब बरेली में बन सकता है, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि हमारे यहाँ बरेली में कोई बड़ा इण्डस्ट्रियल हब नहीं है। इसी के साथ ही मैं केवल सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई फिशरी यूनीवर्सिटी नहीं है। वेटनरी विश्वविद्यालय हैं लेकिन फिशरी यूनीवर्सिटी अगर हमारे उस खादर के क्षेत्र में बन जाय, जमीन जो 1400 एकड़ पड़ी है, तो हमारे उत्तर प्रदेश को एक फिशरी यूनीवर्सिटी मिल जायेगी। बाकी तो अन्य सभी चीजें हमारे यहाँ हो गई हैं। हमारे यहाँ एक जो नया टर्मिनल बना है उसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की थी उसका नाम नाथनगरी रखा था। नाथनगरी टर्मिनल कर दिया जाय। इस 8 तारीख को उसका शुभारम्भ हो रहा है। इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसमें जो उड़ान है वह बरेली से दिल्ली के लिये प्रारम्भ की जा रही है। मैं माँग करता हूँ कि बरेली से लखनऊ की भी हवाई यात्रा शुरू हो जाय जिससे लखनऊ आने वाले लोगों को भी उसका सीधा लाभ मिल सके। मान्यवर, आपने हमें बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, जय हिन्द-जय भारत।

***श्री नईम उल हसन-**

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ।

हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि इस प्रदेश की सूरत बदलनी चाहिए।

माननीय मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट 2021-22 का प्रस्तुत किया है। बजट ही पेपरलेस नहीं, प्रदेश की आय भी लेस है। राज्य सरकार का बजट भी लेस है और प्रदेश का राजकोषीय घाटा भी काफी तरक्की किया है बजट भी लेस है। माननीय वित्त मंत्री जी भाषण में कटौती करके प्रदेश को मजबूत करने का झांसा दे रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण बुक में पिछले वर्ष से इस वर्ष के बजट में अधिकतम अन्तर बजट प्रकाशित नहीं कराया है। माननीय वित्त मंत्री जी इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान पर्यटन बजट अनुमान की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। पूरे बजट भाषण में उत्तर प्रदेश के कई स्थानों को बढ़ावा देने का जिक्र किया गया है लेकिन उनमें से उन स्थानों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया

को छोड़ दिया गया जिसमें किसी विशेष समुदाय का नाम जुड़ा है। दुनिया का कोई भी पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर जब वह आता है तो वह ताजमहल बगैर देखे नहीं जाता लेकन बजट के अंदर कहीं भी ताजमहल की आय का न जिक्र है न ताजमहल का जिक्र किया गया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक पर्यटन स्थल से हो रही आय का ब्यौरा भी सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाए। किसानों के बारे में लगातार चर्चा हो रही है, सदन के बहुत सारे सम्मानित साथियों ने बात रखने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार के लोग कहते हैं, आज माननीय मुख्य मंत्री जी भी कह रहे थे कि हमने इतना किसानों के लिए काम किया है। एक तरफ गन्ना मंत्री जी ने भी आज सदन के अन्दर कहा था कि हमने इतना गन्ना किसानों को बकाया देने का काम किया है। एक तरफ यह कहते हैं कि हमने किसानों का इतना काम किया जो किसान वहां पर धरना दे रहे हैं, आज तीन महीने होने जा रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ देखने वाली सरकार की कोई आंखें नहीं हैं। यह कहते हैं कि विपक्ष भड़का रहा है। मैं पूछता हूं कि विपक्ष कैसे भड़का रहा है, सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, लेकिन आप उन्हें समझाने में नाकाम हैं तो कहीं न कहीं आपकी सरकार फेल हो रही है। उन अन्नदाताओं का जिनको कहा जाता है कि हम भी किसान के बेटे हैं, धरती को जमीन चीर करके गेहूं पैदा करने का काम करते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो वहां पर कीलें ठोकने का काम किया है, जो चाइना और पाकिस्तान के ऊपर लगनी चाहिए थी, वह कीलें इस सरकार ने किसानों के आगे ठोकने का काम किया है। सरकार उन शहीद किसानों को जो वहाँ पर आज तक शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा देने का काम करे। मैं नूरपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर यहां पर आया हूँ। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के लिए भी कुछ रखना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत लम्बे-लम्बे वादे किये हैं। "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट" की भी बात करने का काम सरकार ने किया है, लेकिन हमारे जिले के अन्दर एक ढोलक का इन्होंने कहा था "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट" का नारा दिया, इसके माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का सपना दिखाया था जो पूरी तरह से कागजों पर खानापूर्ति हुई है। 4 वर्ष बीत चुके हैं, एक भी परियोजना स्थापित नहीं हुई है। जहां सरकार अपने को ढोल पीटने का काम करती है, कहती है कि हमने इतना विकास किया। मैं पूछना चाहता हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हो अगर पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया तो दिल्ली एक्सप्रेस-वे किसने बनाने का काम किया ? समाजवादी पार्टी की सरकार में मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने फोर लेन जोड़ने का काम, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट जोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग घमण्ड की राजनीति को चुनना पसन्द करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय के बाद हम उधर होंगे और यह इधर होंगे।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करें।

श्री नईम उल हसन-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा सा मेरे क्षेत्र का विषय है। मैं आपसे पहली बार बोल रहा हूँ। मेरे क्षेत्र नूरपुर के अन्दर कोई भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं आपके माध्यम

से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर बच्चियों की पढ़ाई के लिए एक डिग्री कॉलेज बनवाने का प्रयास करें। मेरे क्षेत्र के अन्दर ताजपुर पंचायत है, जिसको नगर पंचायत के लिए हम कई बार लिख चुके हैं, लेकिन उसको नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। आपके माध्यम से उसे नगर पंचायत का दर्जा दिलवाने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी से, मा0 वित्त मंत्री जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस पर गौर करने का काम करें। आपने पूरे देश के अन्दर हर विधायक के लिए एक नए स्मारक स्थल की योजना चलायी थी, जो भी मन्दिर, मस्जिद हो उसके लिए आपने किया था, मेरे यहां से उसकी पूरी योजना बनकर चली गयी, लेकिन आज तक उस पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र की एक-दो सड़कें हैं, जैसे यह लोग कहते हैं कि हमने गड्ढामुक्त कर दिया है, लेकिन पूरा का पूरा गढ्डा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपसे अनुरोध है कि जो हमारी सड़कें हैं एक नहर के किनारे बल्लानगले से गल्लाखेड़ी तक की सड़क है, उसको दिखवाने का काम सरकार करे, इसी के साथ आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस ऐतिहासिक बजट के अवसर पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस कोरोना महामारी के बावजूद भी ऐतिहासिक बजट पेश करते हुए 5 लाख 50 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है, जो समाज के हर तबके का ख्याल रखने वाला, क्षेत्र के हर तबके का ख्याल रखने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र जनपद बांदा, बुन्देलखण्ड से आते हैं। बुन्देलखण्ड वासियों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वहाँ पर कोई ऐसा मार्ग होगा जिस मार्ग के माध्यम से चार से पाँच घण्टे में आप दिल्ली पहुँच सकते हैं हमारी योगी सरकार ने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे दिया, साथ ही साथ डिफेंस कारीडोर के माध्यम से वहाँ पर दुनियाँ के आधुनिक हथियार यहाँ बनाए जाएंगे तमाम बुन्देलखण्ड के लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं इसके लिए अपनी योगी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारा बुन्देलखण्ड पानी के लिए हमेशा जूझता रहा पर मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है कि माननीय योगी जी ने हर घर नल देने की जो योजना लेकर आए हैं जिसके माध्यम से जब हम विधायक बनकर आए तो लोग हमसे हैण्डपम्प मांगा करते थे बुन्देलखण्ड की भाषा में कहते थे कि विधायक जी हमें एक हैण्डपम्प दे देना। विधायक के पास एक लिमिटेड हैण्डपम्प की संख्या होती थी डिमाण्ड ज्यादा होती थी हम लोग उस डिमाण्ड को पूरी नहीं कर पाते थे मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने टार्गेट बना लिया, लक्ष्य बना लिया है कि हम हर घर को पानी देंगे जैसे शहरों में, महानगरों में लोग नल की टोटी घुमाते थे और पानी ले लेते थे वही व्यवस्था हमारे गांवों में होने जा रही है। मैं इसके लिए योगी सरकार को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतना ही नहीं अधिष्ठाता महोदय, इतना ही नहीं यहाँ पर एक पार्टी के नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे थे कि योगी

जी ने उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन करके उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज को कुम्हार समाज को मिट्टी के काम से पुनः जोड़ने का इनका प्रयास है ताकि यह समाज मिट्टी के काम से बाहर न निकल पाए।

मैं आपके माध्यम से ओम प्रकाश राजभर जी को और साथ ही ऐसी सोच रखने वाले तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि माटी कला बोर्ड यह कतई नहीं कहता है कि आप अपनी नौकरी छोड़कर मिट्टी के काम में लग जाएं। माटी कला बोर्ड यह कतई नहीं कहता है कि आप जो भी उद्योग धंधे या फैक्ट्री लगाए हैं उसको छोड़कर आप मिट्टी के बरतन बनाने शुरू कर दीजिए। माटी कला बोर्ड यह भी कतई नहीं कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़कर मिट्टी के बरतन बनाने शुरू कर दीजिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे प्रजापति समाज के परिवार हैं जो गरीबी के कारण मिट्टी के काम को नहीं छोड़ पाया। ऐसे में वह अपने बच्चों की, परिवार को अच्छी परवरिश नहीं कर पाता है, अच्छी शिक्षा-दीक्षा नहीं दे पाता है। जो लोग पढ़ लिख गये हैं विकास के दरवाजे पर खड़े होकर विकास को धक्का मार रहे हैं वह आगे बढ़ने के तमाम रास्ते खोज सकते हैं परन्तु जो आज भी गरीबी के कारण मिट्टी के काम को नहीं छोड़ पाया है, वह आगे कैसे बढ़ेगा मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन किया है उससे जो प्रजापति समाज के गरीब परिवार के लोग हैं, वह लोग भी विकास की दौड़ में आगे बढ़ सकेंगे। यह सिर्फ बनावटी बोर्ड नहीं है, पिछली बार भी इसमें 10 करोड़ का बजट दिया गया था, इस बार भी 10 करोड़ के बजट का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक मिनी स्टेडियम बनाने का काम शुरू कराया है जो काम लगातार तेजी के साथ चल रहा है।

इसके साथ ही साथ अटल आवासीय विद्यालय हमारे विधान सभा क्षेत्र जनपद बांदा में प्रस्तावित है जहाँ श्रमिक मजदूरों के बच्चे निःशुल्क वहाँ पर रहकर पढ़ाई करेंगे। यह लगभग 70 करोड़ की परियोजना है जो हमारे विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित है इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ डिमाण्ड भी करना चाहता हूँ। हमारे बुन्देलखण्ड का एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि चूँकि बुन्देलखण्ड का एरिया काफी दूर पड़ जाता है राजधानी लखनऊ से, तो वहाँ पर भी एक राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण होना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों की प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल सके। इसके साथ ही साथ जनपद बांदा में वहाँ जितने भी कालेजेज हैं वह सभी विद्यालय झांसी के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। हम चाहते हैं कि जनपद बांदा में एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो ताकि जो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित काम हो उसके लिए हमें झांसी न जाना पड़े। बांदा के आस पास जो जनपद हैं महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट उनको वहीं बांदा में समाहित किया जाए। हमारे बुन्देलखण्ड में इलाज के लिए हम लोगों को लखनऊ या बाहर जाना पड़ता है, जब गम्भीर बीमारी में हमारे लोग फंस जाते हैं मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी एम्स या पी0जी0आई0 स्तर का हास्पिटल बुन्देलखण्ड बांदा में बनाने का फैसला हमारी सरकार ले।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसके साथ ही साथ मुझे बताते हुये प्रसन्नता है कि पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अगर फिल्मों की शूटिंग देखनी होती थी या फिल्मी कलाकारों के दर्शन करने होते थे, उनको देखना होता था तो उनको मुम्बई जाना पड़ता था, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी योगी जी की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए उत्तर प्रदेश में ही फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में उसका निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे बुन्देलखण्ड का चूंकि कल्चर भी अलग है और वहाँ पर बहुत सारी चीजें अलग तरीके से हैं और वहाँ पर सुन्दरता भी है, नेचुरल ब्यूटी भी है इसलिये वहाँ पर भी एक मिनी फिल्म सिटी बनायी जाये। इसके साथ ही साथ हमारे जनपद बांदा में वर्षों से जो कताई मिल बंद पड़ी है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्षों से एक कताई मिल बंद पड़ी हुयी है, जिसके संबंध में मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलकर अनुरोध किया है और इस बार उन्होंने इसे बजट में लिया भी है कि जो भी कताई मिलें बंद पड़ी हैं उनको किस रूप में हम लोग औद्योगिक रूप में ले सकते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे बांदा जनपद की जो कताई मिल है उसको भी लिया जाए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा मण्डल मुख्यालय जनपद बांदा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से किसी भी मार्ग से सिक्स लेन या फोर लेन से जुड़ा हुआ नहीं है और महोदय, यह बहुत जरूरी है कि मण्डल मुख्यालय कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी से सिक्स लेन अथवा फोर लेन से जुड़ा हो, इसलिये कम से कम इसमें से किसी एक मार्ग से हमारे जनपद बांदा को जोड़ने का काम करें। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग सरकार में आये थे तो उसके पहले उत्तर प्रदेश की एक पहचान बन गयी थी और उत्तर प्रदेश को गुण्डाराज, माफियाराज और बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पहले उत्तर प्रदेश के बाहर के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री तथा उद्योग-धंधे लगाने के लिये नहीं आते थे और यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है, पलाबड़ा है, वह अगर कमाई कर लेता था और उसको फैक्ट्री लगानी होती थी तो वह गुजरात जाता था, महाराष्ट्र जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री नहीं लगाता था, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से गुण्डे-माफिया लोगों को खत्म करना शुरू किया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बेहतर, सुन्दर और सुरक्षायुक्त वातावरण देने का काम किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जब इन्वेस्टर्स समिट हुयी तो लगभग साढ़े चार लाख करोड़ के आस-पास के एम0ओ0यू0 उसमें साइन हुये, इसके लिये मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ। हमारे मा0 मोदी जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हम लोगों को करना है तो जो यह बजट हमारी सरकार ने पेश किया है आत्मनिर्भर भारत के

निर्माण में, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार को और मा0 वित्त मंत्री जी को यह बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह जी

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी की बगल की सीट का हूँ और इनके बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि रोम-रोम तपाना पड़ता है तब कोई सुरेश खन्ना बनता है। (सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) मैं इनकी बगल की सीट का हूँ। इनका आदर्श व्यक्तित्व और इनकी योग्यता जो निश्चित रूप से आज के बजट में परिलक्षित होती है, दिखती है, आपके आशीर्वाद से मैं उस बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं पहली बार विधायक चुनकर आया हूँ। एक माइंडसेट था कि विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, बड़ी अग्रणी भूमिका होती है। हम ऐसा सुनते थे कि आधा विपक्ष बैठता है आधा सदन बैठता है, लेकिन यहाँ आकर देखा तो उलटा नजारा था। हमारे गाँव-देहात में एक कहावत है कि "बड़ा शोर था हाथी की दुम का जा करके देखा तो सुतली टंगी थी।" यह इनके कर्मों का फल है कि सिमट करके एक बटे छः हिस्से में आ गये हैं और फिर भी विधवा प्रलाप करते हैं। मैं लगातार विपक्ष का विधवा प्रलाप सुन रहा हूँ कि भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। अरे, भेदभाव और पक्षपात जो आपके जमाने में हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2015-2016 की बात है, केन्द्र सरकार में दैवीय आपदा राहत के तहत कोष भेजा गया था। मैं मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र से हूँ। मेरे यहाँ भी गाँव-गाँव में कोष बंट रहा था। मैंने तत्कालीन अधिकारी से कहा कि साहब मेरे गाँव में भी बाँट दीजिये तो वह बोले आपका गाँव तो जनसंघ का गाँव है वहाँ नहीं बँट सकता, वह समाजवादी पार्टी के चिन्हित गाँवों में ही बंटेगा। मान्यवर, दैवीय आपदा के राहत कोष में भी इन लोगों ने ऐसा करने का काम किया है और आज यह कहते हैं कि पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। साहब, कहाँ पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है ? कांवड़ लेकर निकलते थे, अपने चौराहे पर खड़े हो करके हम लोग चाय पिला रहे थे।

डीजे बज रहा था, भगवान का भजन हो रहा था उसके लिए पुलिस ने तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज करके हमारे लोगों को जेल भेज दिया और आज यह कह रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है। आज वही कांवड़िया जब कांवड़ लेकर निकलते हैं तो एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज लगा होता है और एक तरफ केसरिया ध्वज लगा होता है और मन तब और गौरवान्वित होता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हेलीकाप्टर से उन कॉवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने का काम करते हैं। मान्यवर, बड़ी आदर और विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग किसान पर चर्चा कर रहे थे, मैं एक किसान हूँ, मैं स्वयं खेती करता हूँ इसके अलावा मेरा और कोई

व्यवसाय नहीं है, मैं धान, गन्ना और गेहूं की पैदावार करता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको गेहूं और जौ में अन्तर नहीं मालूम होगा, अभी इनको खेत में ले जाकर खड़ा कर दें तो ये बता नहीं पायेंगे कि ये गेहूं है या जौ है। मैं एक किसान हूँ और मैंने किसानों का दर्द और हित देखा है। इनके कार्यकाल में किसान ने खाद के लिए लाइन लगाई है और लाठियां खाई है। एक वह भी कालखण्ड था जब डीजल के लिए किसानों को परमिट बनवाना पड़ता था तब जाकर कहीं 20 लीटर डीजल मिलता था। आज किसानों को आसानी से खाद मिल रही है, डीजल मिल रहा है। मैं आदरणीय सुरेश राणा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनकी वजह से मेरी विधान सभा क्षेत्र में दो चीनी मिलें हैं और दोनों चीनी मिलों का पेमेन्ट 10 दिन के अन्तराल से चल रहा है, लगातार पेमेन्ट हो रहा है और गन्ना माफिया खत्म हो गये हैं। वह एक सीजन में 3-3 करोड़ रुपया अपना सेन्टर लगाकर पैदा करते थे वह आज खत्म हो गये हैं। अब किसान को सीधे पर्ची मिलती है और उसके गन्ने का भुगतान होता है। इनको देख कर तो ऐसा लगता है कि जैसे "गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए जनाब" मान्यवर, कानून व्यवस्था को लेकर प्रलाप किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज रिकार्ड उठाकर देख लें जितने संगठित अपराध हैं, डकैती, चोरी, लुटैती, छिनैती, सब बंद हो गये हैं। हम लोग खेती करते थे तो सिंचाई करने के लिए रात में इंजन लगाते थे और सुबह खेत जाते थे तो मौके पर इंजन नहीं मिलता था। इनके कालखण्ड मे मेरी स्वयं की तीन-तीन मोटरें चोरी हुई हैं। आज किसान खेत में खड़ा होकर मुस्कराता है न उसके इंजन की चोरी होती है, न मोटर की चोरी होती है, न अपहरण होता है, न डकैती होती है, न छिनैती होती है, न सेंध कटती है हां इतना जरूर है कि अपराध करने वाले जेल के रास्ते जाते हैं और भारत माता को गलत बोलने वाले भी जेल के रास्ते जाते हैं। मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि "वो सलीबों के करीब क्या आये हमको कायदे-कानून समझाने लगे, अरे मौलवी की डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे।" आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे एक काबिल दोस्त ने जिक्र किया कि कोई साधू-सन्यासी किसी गांव में चला जाता है तो वहाँ के बच्चे डर के भाग जाते हैं। मान्यवर, मैं ऐसे बयान पर शर्मशार हूँ। यह देश परम्परा, सांस्कृतिक, धार्मिक और मार्यादा का देश है, यह ऐसी भूमि है जहां पर लोग पीपल में ब्रह्म का वास देखते हैं, नीम में देवी का वास देखते हैं और पत्थर में भगवान शंकर का रूप देखते हैं, सड़क से निकलते हैं तो गुरुद्वारा और मंदिर को प्रणाम करते हैं और जिन्नादबाबा की मजार को देखते हैं तो चादर चढ़ाते हैं।

ऐसे देश में, सदन में यह कहा जाय कि कोई साधू-सन्यासी किसी गांव में चला जाता है तो वहां के बच्चे डर के भाग जाते हैं यह शर्मनाक है। मैं इस बयान की घोर भर्त्सना करता हूँ और घोर निन्दा करता हूँ। कोरोना कालखण्ड की बड़ी चर्चा हुई मान्यवर, कोरोना कालखण्ड में निश्चित रूप से सरकार ने जो काम किया है, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। महीने में दो बार राशन दिया गया 5 किलो प्रति यूनिट चावल दिया गया। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के एक गांव में एक मीटिंग कर रहा था। एक भाईजान बैठे थे मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको चावल मिला है ? तो उन्होंने कहा कि हाँ मिला है तो मैंने कहा कितने यूनिट है तो उन्होंने कहा

कि 12 यूनिट मिला है। मैंने पूछा कि 60 किलो चावल मिला है क्या ? तो बोले हाँ 60 किलो चावल मिला है तो फिर मैंने बोला कि बोलो जय योगी की तो वह खड़े होकर कहते हैं जय-योगी की। यह कोरोना कालखण्ड में हमने किया। इनके पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल यह है कि फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। मैं बस समापन पर आ रहा हूँ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं पर आ जाता हूँ आप मुझे शार्ट कहेंगे तो शार्ट कर दूंगा चार दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूँ समय मिला इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, बिजली के क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ है, बिजली के क्षेत्र में ऐसा कोई मजरा, पुरवा तक नहीं बचा है, जहाँ का विद्युतीकरण न हो गया हो 33/11 के0वी0ए0 के बहुत सारे पावर हाउस प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में खुले। मैं इसी निमित्त अपनी विधान सभा क्षेत्र में उचौलिया में एक 33/11 सब-स्टेशन देने की मांग करता हूँ। विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का प्रावधान भी सराहनीय पहल है मान्यवर, मेरी विधान सभा में मेरी तहसील में मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, वहीं वकालत भी करता था, मेरी तहसील में चार सौ अधिवक्ता हैं, बैठने की जगह नहीं है यदि कृपा हो जाये यदि चैम्बर मिल जायेंगे तो बड़ी कृपा हो जायेगी। मान्यवर, गोकशी बन्द हो गयी है। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने का बहुत अच्छा प्राविधान है।

महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूं कि यह जो अभ्युदय योजना जो सरकार ने लान्च की है यह निश्चित रूप से सराहनीय है, इससे गरीब, मजदूर, किसान के बेटे भी कोचिंग प्राप्त करके और अच्छी बड़ी नौकरियों में जा सकेंगे, मैं अभी चर्चा कर रहा था नेट पर देख रहा था तो इस वर्ष 10 हजार ऐसे छात्र को अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग मिलने का प्राविधान प्राप्त हो गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यहाँ गोमती है और गोमती सूख गयी है, वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया है। गोमती कोई पहाड़ से निकली नदी नहीं है अपने स्रोत पर आधारित नदी है मेरा आग्रह है कि गोमती को शारदा नदी से जोड़ देंगे तो लखीमपुर जनपद की शारदा के बाढ़ से पीड़ित होता है, लखीमपुर जनपद बाढ़ से मुक्त हो जायेगा और मेरी मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र में हमको गोमती में आचमन के लिए जल मिल जायेगा। मेरा आग्रह है मान्यवर कि गोमती को लेकर आप गम्भीरता से इस पर मनन करेंगे। एक अन्तिम बात करूंगा कि मेरा मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र जिला मुख्यालय से 70 से 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी जानते हैं क्योंकि मैं इनकी बगल की विधान सभा से हूँ, प्रशासनिक कार्यों में बड़ी असुविधा होती है। हमारे यहां बार एसोसिएशन से लेकर तमाम राजनीतिक, सामाजिक संगठन लगातार शनिवार को लगभग 7-8 वर्षों से धरना-प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं। मेरा आग्रह है कि मोहम्मदी को जिला बनाने की कृपा की जाये। यह चार पंक्तियाँ समर्पित करना चाहता हूँ। अभी हमारे एक काबिल दोस्त ने एक शेर कहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि चुन-चुन कर बताऊंगा किस-किस को मारना है। मान्यवर, भगवान करे ऐसी स्थिति न आये। मैं यह शेर अर्ज करता हूँ-राजमहल को छोड़ झुकाया सर पथ को पगडण्डी को, अपना हर प्रणाम अर्पित इस राष्ट्र पुरुष सन्यासी

को, दुनिया भर में हम भारत है, यह आचरण हमारा है धनुष धर दिया था हमने और मारा नहीं सिखण्डी को। बहुत-बहुत धन्यवाद।

बजट चर्चा में प्रतिभाग करने से वंचित मा0 सदस्यों के लिखित भाषण को कार्यवाही में सम्मिलित किये जाने की मांग

*** श्री उमाशंकर सिंह-**

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, चूंकि यह परम्परा रही है और यह व्यवथा भी है कि क्योंकि सभी 403 माननीय सदस्य बोल नहीं पायेंगे तो हमेशा पीठ से एक व्यवस्था आती रही है कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वह अगर नहीं बोल पायें तो वह अगर लिखित दे देते हैं तो वह भी कार्यवाही का भाग हो जाता है।

***वित्त, संसदीय कार्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अधिष्ठाता जी, अध्यक्ष जी से बात हो गयी थी, जो लोग नहीं बोल पायेंगे वे लिख कर दे दें उसे कार्यवाही का अंग बनवा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

जो भी माननीय सदस्य, भाषण अपना लिखित दे देंगे उसे कार्यवाही में जोड़ दिया जायेगा। कृपया 5 मिनट से ज्यादा समय न लें।

[06:05] वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री असलम अली-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस बार जो बजट आया है, उसमें किसान, मजदूर और गरीब आदमी का हक मारा गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र धौलाना की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मेरा विधान सभा क्षेत्र धौलाना जनपद हापुड़ और गाजियाबाद के अन्तर्गत आता है। यहां पर विद्युत विभाग के कुछ संविदाकर्मी गांवों में सुबह चार-पाँच बजे जाते हैं और फर्जी वीडियो बनाकर लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का झांसा देकर उन्हें लूटने का काम करते हैं। मसूरी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत इस तरह के कुछ संविदाकर्मी और एक जे0ई0 भी जेल में गये हैं। मेरा अनुरोध है कि जो लोग इस खेल में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर सिकरोड़ा तहसील सदर गाजियाबाद के रजापुर ब्लाक में एक अमानत नाम का राशन डीलर है। तीन बार सप्लाई इनसपेक्टर की जांच के आधार पर यह दुकान निरस्त की गई है किन्तु हर बार उसी इन्सपेक्टर की जांच रिपोर्ट पर फिर से बहाल कर दी जाती है। मैंने इसमें ए0डी0एम0 साहब को पत्र लिखा तो ए0डी0एम0 साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इसमें एक कमेटी बनाऊँगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया

लेकिन आज तक इसमें कोई कमेटी नहीं बनाई गयी है। ऐसा आदमी जो 35-40 साल से बिस्तर से नहीं उठ सकता है उसके लड़के, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, जांच में साफ आया है। जितनी भी इस तरह की दुकानें हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिये। मैं हापुड़ और गाजियाबाद जनपद की बात बता रहा हूँ लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी राशन की दुकानें है जहां पर आज भी चार किलो चावल और अनाज दिया जा रहा है। इन राशन डीलरों पर कार्यवाही करके गरीबों को पूरा राशन दिलवाया जाये।

मान्यवर, मैं जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना में गर्ल्स डिग्री कालेज के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग करता हूँ हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगा रही है लेकिन मैं पिछले चार सालों से इस मामले को कई बार उठा चुहा हूँ लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ग्राम मसूरीनाहल, देहरा, बझेडा कला व गालन्द को नगर पंचायत बनाने के लिए मैं पिछले कई सत्रों से सदन में मांग कर रहा हूँ लेकिन अब तक इसमें कार्यवाही नहीं की गई है। यह गांव चालीस-चालीस हजार की आबादी वाले हैं, इसलिए मैं जनहित में नगर पंचायत बनाने की मांग करता हूँ, जनपद गाजियाबाद के धौलाना विधान सभा क्षेत्र के सम्पर्क मार्ग जर्जर हैं। वहां पर हाई-वे बनाने के लिए जो मिट्टी उठाई गयी है, उसमें समयपुर नाहल, नूरपुर चितौड़ा, डासना इत्यादि के रोड पूरी तरह से जर्जर हो गये हैं, इसलिये इनको बनवाने की कृपा करें। इसी के साथ हापुड़ जिले में ग्राम भोवापुर से मदापुर तक सम्पर्क मार्ग को बनाने के लिए 04 वर्षों से लगातार मैं याचिका लगा चुका हूँ। नियम-51 में मांग कर चुका हूँ। मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को भी पत्र लिखा है। जिला योजना में भी प्रस्ताव दिया है लेकिन पिछले चार वर्ष से इस डेढ़ किलोमीटर के टुकड़े की सड़क को नहीं बनाया गया है, जबकि इससे पांच गांव जुड़ते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसको बनवाने की कृपा करें।

मान्यवर, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 शेखपुर खिचरा हापुड़ में एम0जी0 रोड पर फैक्ट्री एरिया है। वहां पर हजारों की तादाद में फैक्ट्रियां हैं लेकिन वहां पर अभी तक कोई भी फायर स्टेशन नहीं बना है। यदि वहां पर किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है या कोई दिक्कत हो जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हापुड़ या गाजियाबाद से आती हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वहां पर एक फायर स्टेशन बनवाने की कृपा करें। मैं एन0एच0-9 मसूरी से गुलावटी रोड का चौड़ीकरण कराने की मांग करता हूँ। इसी के साथ-साथ कुशलिया नहाल, ढबारसी, समयपुर, चितौड़ा, नूरपुर की सर्विस रोड हाई-वे बनाने की सामग्री ढोने के कारण जर्जर हो गई है, उन्हें भी बनवाने की कृपा करें। मान्यवर, पिलखुवा कस्बा मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है लेकिन वहां के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के आपसी झगड़े के कारण कोई प्रस्ताव पास नहीं हो पा रहा है इसलिये वहां पर कार्य कराने का काम करें।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ-साथ ग्राम पिलखुआ देहया की पुलिया के सामने एक नाला और सड़क है जिसके लिए मैं लिखकर दे चुका हूँ। यह नगर पालिका में आता है।

उस नाले और सड़क को बनाने की कृपा करें। इसी के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री अरविन्द गिरि-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है, आज इस माननीय सदन में जो बजट प्रस्तुत हुआ है मैं तो यूँ कहूंगा कि आदरणीय खन्ना जी को जो संसदीय अनुभव है, वह सारा इस बजट में दिखाई देता है। पिछले कई दिनों से हम लोग यह सुन रहे थे, देख रहे थे कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी किस तरह से बजट और बजट के साथ-साथ तमाम बातों का उल्लेख कर रहे हैं। हम तो समझते हैं कि उनको यह सब चीजें दिखायी देनी चाहिए। यह वह बजट है जिस पर आज हर माननीय सदस्य गर्व कर रहा है। यह वह बजट है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक आइने में उस तरीके से देख रहा है कि किस तरीके से हमारी आय दोगुनी करने का काम केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से चाहे कोई भी विधा हो, चाहे कोई भी विषय हो, धर्म, जाति राजनीति तमाम मेजों से ऊपर उठकर इस बजट में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आधारित यह बजट निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। अधिष्ठाता महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जिनकी एक स्पष्टवादिता, जिनका अपना स्पष्ट निर्णय आज इस बजट में दिखाई देता है जो उनके मार्गदर्शन में आदरणीय खन्ना जी ने तैयार किया है। आज पूरा उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान का कोई भी प्रदेश हो तब तक कोई भी चुनाव सम्पन्न नहीं होता जब तक यहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी का भाषण नहीं होता है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारा आपका नहीं पूरे हिंदुस्तान के सवा सौ करोड़ लोगों का यह सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने पूरे प्रदेश, पूरे राष्ट्र के किसानों की बात चाहे यह राज्य सभा में बोले हों चाहे लोक सभा में, चाहे मैदान में उनका एक ही एजेण्डा है किसान और किसान, लेकिन विपक्ष के लोग, जिस तरीके से किसान की बात करते हैं हम तो कहते हैं कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में 1 वर्ष के अंदर 44 हजार किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जो लोग हिंदू-मुसलमान की बात करते हैं, हमने इस राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर 44 हजार किसानों का कर्जा माफ हुआ है तो उसमें 30 प्रतिशत हमारे मुस्लिम भाइयों का माफ हुआ है। हजारों महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत गैस दी है। आज हम किसी भी पुरवें में हों, किसी भी गांव में खड़े हों चाहे कोई भी एक परिवार हो उसको पांच-पांच छः-छः परियोजनाओं से लाभान्वित किया गया है। चाहे शौचालय लाभ मिला हो, चाहे आवास दिया गया हो, सौभाग्य योजना के तहत उसके घर को रौशन करने का काम किया गया हो किसी भी योजना में हिंदू-मुसलमान का फर्क नहीं किया गया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं जनपद लखीमपुर खीरी से आता हूँ। लखीमपुर खीरी से इसी विधान सभा क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों में विभिन्न नियमों के तहत मैंने अपने जनपद की विभीषिका जो बाढ़ और कटान की थी प्रतिवर्ष हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। मैं यशस्वी मुख्य मंत्री जी को

धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार जब मैंने निवेदन किया और उन्होंने एक बड़ी योजना स्वीकृत करके मेरी विधान सभा क्षेत्र को उस विभीषिका से बचाने का काम किया।

यही नहीं पिछले पूरे वर्ष जब हमारे यहाँ बाढ़ और कटान का मामला चल रहा था उन्होंने 06 बार दौरा करने का काम किया लेकिन हम इस सदन में अपने बाढ़ और राहत मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आज जो विभीषिका है पिछले 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि कभी बाढ़ के नाम पर 20-25 करोड़ रुपया कहीं बाढ़ के समय राहत बाँटने के नाम पर 20-25 करोड़ रुपया बाढ़ जाने के बाद सुधार के नाम पर 20-25 करोड़ रुपया जनपद लखीमपुर में पिछले 20 वर्षों में देखा जाये तो प्रतिवर्ष यह नुकसान होता है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। हम स्थायी हल की मांग करते हैं। हम जानते है कि प्रदेश और केंद्र के बिना इसका स्थायी हल सम्भव नहीं है। हम आदरणीय खन्ना जी से अनुरोध करते हैं कि इस बजट में निश्चित रूप से लखीमपुर जनपद की इस समस्या का स्थायी हल करने का काम करेंगे। अगर सौ रुपया खर्च होगा तो हजार रुपये का फायदा लखीमपुर ही नहीं आस-पास के जनपदों के जो हमारे भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि उपलब्ध हो सकेगी। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, सब जगह एक पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। हमारी संस्कृति की धरोहरों को बचाने का काम चल रहा है। हमारे जनपद में भी चाहे टेढ़नाथ बाबा का मंदिर हो, चाहे गणेश जी का मंदिर हो, चाहे समता देवी का मंदिर हो, एक सुधार की योजना चल रही है। वहाँ पर तमाम पैसा देने का काम हुआ है। लेकिन हम आदरणीय खन्ना जी को याद दिलाना चाहते हैं कि जब वह पर्यटन मंत्री थे तो देवाधिदेव महादेव गोला गोकर्णनाथ का दर्शन करने का काम किये थे और उस समय भी उन्होंने कहा था कि यह पर्यटन स्थल घोषित होना चाहिए। पिछली बार मा0 मुख्य मंत्री जी भी सौभाग्य से गये थे। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ का मंदिर जो छोटे काशी के नाम से विख्यात है और वहाँ प्रतिमाह मेला लगता है। श्रावण का मेला एक-एक माह का लगता है। भूतनाथ का मेला एक दिन का होता है लेकिन 10 लाख श्रद्धालू वहाँ जाने का काम करते हैं। हमारे बहुत से मा0 सदस्य वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मेरा अनुरोध है कि इसको पर्यटन स्थल घोषित करने का काम किया जाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिजली को लेकर तमाम बातें हुयीं। मैं मा0 ऊर्जा मंत्री जी को बधायी देना चाहूंगा कि 220 के0वी0ए0 का विद्युत गृह हमारे यहाँ स्वीकृत हुआ जिसकी वजह से 20 किमी0 परिधि में विद्युत की तमाम समस्याओं का हल हो गया। 33 क0वी0ए0 का मालपुर में मैंने मांग की है जिसको मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने स्वीकार भी कर लिया है, बजट की दिशा में है।

मैं आदरणीय खन्ना जी से अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से उसमें वह कृपा करने का काम करेंगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जनपद लखीमपुर खीरी वन क्षेत्र और वन्य जीव जन्तुओं के लिए मशहूर है। दुधवा नेशनल टाइगर पार्क पूरे देश में मशहूर है। जनपद बहराइच का कतर्नियाघाट, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, पीलीभीत में है। यह तीनों जनपद एक साथ मिलकर काम करते। हैं। हम वन मंत्री जी को बधायी देंगे कि

पिछले 3-4 वर्षों में दुधवा, कतर्निया और पीलीभीत में जो सुधार करने का काम किया है वह पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ। बड़ी योजनायें दी जा रही हैं, बड़े रूप में काम किया जा रहा है, अधिकारी भी मेहनत से काम कर रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी भी दुधवा नेशनल पार्क जाकर उसको राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का काम किये हैं। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तरफ मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वह यह है कि पिछले 15 दिनों के अंदर हमारे इन तीनों नेशनल पार्कों के अंदर अन्तर्राष्ट्रीय शिकारियों की निगाह लग गयी है। पिछले 10-15 दिन के अंदर आधा दर्जन बाघों की हत्या हुयी है। उनके शिकार करने का काम हुआ है और जनपद के अधिकारी सतर्क हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको यहाँ से तत्काल अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है जिससे इन वन्य जीवों को बचाया जा सके। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कुछ लिख कर दे दें तो अगर इजाजत मिल जाये तो मैं भी लिख कर दे दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री अरविन्द गिरि-

अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शशांक त्रिवेदी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बजट पर बोलने के लिए अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवादा मैं आपका आभारी हूँ कि 3-4 दिन बाद समय मिल पाया और मैं पहली बार बोल रहा हूँ तो मेरा अनुरोध है कि मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय ज्यादा मिल जाए अपनी बात शुरू करने से पहले मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दूरदर्शिता के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नयी ऊर्जा, नये आयाम के साथ बजट पेश किया है, उस बजट के लिए पहले दो लाइन कह दूँ-

"हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है,
विपक्षियों जैसे मुंह छिपाना आसान होता है,
डरने से कुछ नहीं मिलता जिंदगी में,
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।"

इस बजट में मुख्य मंत्री जी के विजन आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अनुसार समग्र विकास की रूपरेखा समाहित है। यदि वर्ष 2017 से अब तक देखें तो स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार ने कैसे माइक्रो एवं मैक्रो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम किया है। मैं माक्र मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ जिनकी वजह से सकल राज्य घरेलू उत्पाद दूसरे नम्बर पर पहुँच गया है। आज मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी बताया है, उसी के अनुरूप आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की स्थापना में उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका निभा रहा है। जब इस बजट को पढ़ेंगे तो बस बजट को पढ़कर जो ध्यान में आता है यह मैं कहना चाहता हूँ-

मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूँढ लेती हैं
बड़ी शातिर है ये दुनिया फिर बहाना ढूंढ लेती है,
विपक्ष जिद किए बैठा है चकनाचूर करने को,
मगर हर आँख फिर सपना सुहाना ढूंढ लेती है।

यह बजट किसानों के स्वप्न को हकीकत में बदलने वाला है। किसानों की आय वर्ष 2022 तक दुगुनी करने हेतु आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। मैं किसान हूँ और मैं जब पढ़-लिखकर बी0टेक0 करके किसानी करने अपने क्षेत्र में पहुंचा तो मैंने देखा कि क्या-क्या समस्याएं आती थीं और जो आपके एवं प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी हैं, इन्होंने किसानों के लिए जो बजट पेश किया है, उसमें पहली बार फसली ऋण उपलब्ध कराया गया है, मुफ्त पानी, सिंचाई का पम्प लगाने के लिए अनुदान दिया गया है। ऐसे-ऐसे किसानों के लिए प्रावधान किए गये हैं कि किसानों को किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए जरूरत नहीं पडेगी पहला बजट जब पेश किया गया तो उसमें ऋण माफ हुआ और अब पाँचवें बजट में न्याय पंचायत स्तर पर कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज लगाने का प्राविधान किया गया है, वह एक-एक किसान के लिए बहुत लाभकारी होगा। संक्षेप में कहें तो यह बजट "ईज ऑफ डुइंग बिजनेस व ईज ऑफ लिविंग" तक सभी आयामों को स्पर्श करते हुए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की सभी अपेक्षाओं के अनुकूल है। मैं अपने क्षेत्र के विषय में भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसी पूर्वी उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, उसी तरीके से हमारे महोली विधान सभा क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन किसी कारणवश चीनी मिल बन्द कर दी गयी है और अब उस चीनी मिल को चलाने की मांग पूरी जनता कर रही है और उस चीनी मिल को चलाने के लिए मैं आपके माध्यम से महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूँ। महोली विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है जबकि वहाँ पर बहुत सालों से एक ही सरकार, एक ही पक्ष का एम0एल0ए0 रहा है। वहाँ की छोटी-छोटी बच्चियों को 60-70 किमी0 दूर डिग्री कॉलेज, सीतापुर पढ़ने जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि वहां पर एक डिग्री कॉलेज बना दिया जाए। अन्त में कुछ ज्यादा न कहते हुए इसी विधान सभा क्षेत्र के एक पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जो आपके भी साथी रहे होंगे, उनकी दो लाइन कहना चाहता हूँ कि-

चरण चूम लेगी स्वयं आके मंजिल,
जरा पांव अपना बढ़ाकर तो देखो,
धरा तो दबी है चरण से तुम्हारे,
जरा आसमां को झुकाकर तो देखो,

मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में दिखा दिया है कि कैसे आसमाँ झुकाया जाता है और कैसे आसमाँ झुकाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे मंत्रीगण बैठ हुए हैं और हमारे पर्यटन मंत्री जी बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि पर्यटन मंत्री जी ने क्या किया है ? पर्यटन मंत्री जी ने

बहुत कुछ किया है, पर्यटन मंत्री जो ने हर विधान सभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए अनुदान दिया है। इसी तरह से नगर विकास मंत्री जी ने हर नगर पंचायत को कुछ न कुछ दिया है और हमारी महोली की नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत घोषित किया। हमारी महोली नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत घोषित हुई है उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मा0 उड्डयन मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि सबन कुछ न कुछ दिया है, तो आप भी एक हेलीपैड वहां पर देने का कष्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ और फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ-

"दूर है मंजिल, राहें मुश्किल आलम है तन्हाई का,
आज इन्हें अहसास हुआ है अपनी शिकस्तापाई का।"

श्री सोवरन सिंह यादव-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मा0 वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के संबंध में अपने विचार रखने का अवसर दिया। महोदय, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी से अपने को सम्बद्ध करता हुआ, उनकी बात पर बल देता हुआ अपनी बात को आप सबके बीच कहना चाहता हूं। जब-जब चुनाव होते हैं, हमारे सभी सम्मानित साथी र्स्वाधिक किसी के प्रति जिम्मेदार हैं तो वह किसान के प्रति जिम्मेवारी का निर्वहन करने का प्रयास करते हैं और उसी को देखते हुए आदरणीय मुख्य मंत्री या जो भी सरकारें आती हैं, अपनी सोच, अपनी दिशा और अपने अनुसार उसी दिशा को आगे बढ़ाती हैं। प्रदेश के लिए विकास करने का काम सभी लोग अपनी-अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी-अपनी नीति के अनुसार किया करते हैं। मुझे एक बड़ी पीड़ा है और बहुत दिनों से मैं बोला भी नहीं हूँ, मैं इस सम्मानित सदन में वर्ष 2002 में आया था, उस समय से लोगों का मेरे ऊपर भरोसा रहा है। श्रीमन् किसान की बात मैंने कही है, मुझे याद है कि 1967 में गेहूं का समर्थन मूल्य 70 रुपया कुंटल था, उस समय बेसिक के सम्मानित अध्यापक साथी को भी 70 रुपया मिलता था और उस समय कोई किसान अपनी बेटी के लिए एक तोला. चार तोला शादी के समय कुछ जेवर बनवाता था तो सोना 200 रुपया तोला था। 70 रुपया के गेहूं में तीन कुंटल बेचकर अपनी बेटी को एक तोला सोना खरीदता था। बेसिक अध्यापक जिन्हें 70 रुपया मिलता था, आज उन्हें लगभग 60,000 रुपया मिलता है, किसान जो 70 रुपया में एक कुंटल गेहूं बेचता था, आज 2000 रुपये के लगभग है या उससे भी कम है। तो अध्यापक का तो नब्बे गुना बढ़ गया और किसान का जो तीन कुंटल में एक तोला सोना लेता था, आज तीस कुंटल में एक तोला सोना लेने की स्थिति में आ गया है। (विपक्ष के सदस्यों ने मेंजें थपथपाईं) खाद बढ़ी, उर्वरक बढ़ा, बिजली बढ़ी, डीजल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा, किसान की खेती को पैदा करने वाली सारी आवश्यकताएं बढ़ीं, बुजुर्ग पिता का उपचार बढ़ा, बेटी की शादी महंगी हुई, भवन निर्माण सामग्री महंगी हुई। बहुत अच्छा लगा जब घोषणा हुई कि किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। इस तरह के नारे दीवारों पर लिखे गये कि न गुण्डाराज, न भ्रष्टाचार, अबकी बार भाजपा सरकार मन में बड़ी गुदगुदी हुई, भ्रष्टाचार मिट जायेगा, लगा भी,

नहीं रहेगा गुण्डाराज मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, चूंकि राष्ट्रीय चरित्र में यह गिरावट आई है जिसके लिए यहाँ बैठे हम सब जिम्मेदार भी हैं। प्रयास होना चाहिए कि जो एक जनप्रतिनिधि से निर्वाह करने की अपेक्षा की गयी है, हम उसके अनुरूप काम करें। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, तो आप यह बताओ, श्रीमन् आपके माध्यम से सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि उस किसान की आमदनी कैसे दोगुनी हो जायेगी ?

श्री अधिष्ठाता-

आप संक्षेप कर लीजिए।

श्री सोवरन सिंह यादव-

श्रीमन, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। यह जो एमएसपी है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइज है, मेरी करहल विधान सभा क्षेत्र है। मैनपुरी जनपद की, 1800 रुपया मक्का का समर्थन मूल्य था। वहाँ एक सरकारी कांटा लगा हुआ था, मैंने पता किया, रीजनल फूड कन्ट्रोलर के विभाग का कांटा था, 200 रुपया कुन्तल खरीददार ने अपने विचौलिए तय कर लिए, 1200 रुपये बाजार की कीमत थीं, 1800 रुपया समर्थन मूल्य था, लेकिन यह किसान को मिल ही नहीं पाया। 200 रुपया कुन्तल सीधा खरीददार ने जो उसका इन्सपेक्टर था, उसने लिया। इस बात को मैंने जब हमारे प्रभारी मंत्री, डिप्टी सी0एम0 श्री केशव मौर्य साहब वहाँ गए तो कहा, उन्होंने जिला योजना की बैठक में इस बात को रखा, सभी अधिकारियों को मैंने अवगत कराया। श्रीमन् तहसील में, थानों में लोगों को लॉकअप में बन्द कर दिया जाता है और होता यह है कि जैसे पुलिस अधीक्षक जाते हैं, उनके चलन और आचरण के अनुसार ही दरोगा लोग, एस0आई0 लोग, इन्सपेक्टर लोग काम करते हैं, तो इतनी स्थिति खराब है कि बन्द कर देते हैं, श्रीमन् जहाँ अभाव होता है, वहाँ विरोध होता आया है। परिवारों में थोड़ी-बहुत कलह होती है, बन्द कर देते हैं, सुबह रुपया लेकर छोड़ देते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है किसान का, जो किसान बीज को दुकानों से बीज लेकर आता है, इतना फर्जी बीज, श्रीमन् इतना फर्जी बीज, किसी समय टीडीसी तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन इन्सपेक्शन करता था और सारे बीज जो किसान पैदा करता था, उन्हें पैक करवाकर वह बाहर भिजवाता था। यहाँ का बीज बिहार और पीछे का बीज यहाँ आता था, हरियाणा पंजाब से अब इतना कन्ट्रोल खत्म हो गया है। बीज के दुकानदार सिर्फ रिप्यूटेड कम्पनियों के बोरी खरीद कर लाते हैं, उनमें वही भर देते हैं और बेचारा किसान मर जाता है, जब बीज बोने के बाद कुछ भी उसके खेत में नहीं होता।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री सोवरन सिंह यादव-

श्रीमन् अन्त में एक बात जो लिखा है-

"चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो,
नहीं जिए यदि लिए देश के, तो तुम अपराधी हो।"

श्रीमान् चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई दल हो, चाहे कोई धर्मावलम्बी हो, अब अकेले धर्म के नाम पर तो नहीं चल सकता। अन्त में अपनी एक बात कह कर समाप्त करता हूँ। जहाँ पूर्वांचल विकास निधि है, बुन्देलखण्ड के लिए भी पैकेज जाता है, पश्चिम जहाँ गन्ना होता है, कुछ जिले तो हरियाणा और पंजाब के बराबर खड़े होते हैं। लेकिन श्रीमन, हमारा मध्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ सिर्फ गेहूँ और धान ही पैदा होता है और गेहूँ तथा धान के उत्पादक तो इतनी निराशा की स्थिति में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ऐसा जीवन जीने वाले वह लोग जितना तंगी में अपने परिवार के बच्चों और महिलाओं के साथ गुजर-बसर कर लेते हैं, वही उनको बचता है, उनके पास परिवार चलाने को कुछ नहीं रहा, खेती निरन्तर बंटती जा रही है। श्रीमन, इन सब बातों पर बड़ी जिम्मेदारी से ध्यान देना होगा, सरकार जिसकी भी हो, उसे देखना ही पड़ेगा। अन्त में आपको बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हुआ, किसान के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उसका हम निर्वाह करें, इसी के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ, जय हिन्द, जय भारत।

श्री राजीव तरारा-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे 2021-22 के इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। यह बजट स्वावलम्बन से सशक्तीकरण की तरफ ले जाने वाला बजट है। यह बजट नये भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने वाला बजट है। हम सभी देशवासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें आदरणीय मोदी जी के रूप में एक महायोगी पुरुष प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं और इस भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय योगी जी इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिन-रात लगे हुए हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विशेष रूप से कानून व्यवस्था की यहाँ पर विशेष चर्चा करना चाहूँगा और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की धनौरा विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था पिछली सरकार में बहुत ज्यादा खराब थी और जिस तरह से चौराहों पर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सम्पत्तियों पर पशुओं को लूटकर लोगों कँ हत्या कर दी जाती थी तो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजक प्रदेश की श्रेणी में आ गया था। जबसे हमारे आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने, तबसे कानून का राज यहाँ पर स्थापित हुआ है और जो गुण्डे हैं या तो वे उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं या फिर से जेलों के अन्दर हैं। हमारे जो पिछले चार बजट आए हैं उससे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए, किसानों के सशक्तीकरण के लिए युवाओं के रोजगार के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए यानी कि कहा जाए तो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। विशेष रूप से मैं अपने आदरणीय योगी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा उत्तर प्रदेश जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को पूर्व की सरकारों ने जिस स्थिति में छोड़ा था, वह बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन कोरोना के संकट काल में भी उत्तर प्रदेश को कोरोना से बचा करके उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसकी प्रशंसा केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में हुई है। डब्लू0एच0ओ0 ने भी इसकी प्रशंसा की है। इसके लिए मैं बधाई

देता हूँ अपने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मुख्य मंत्री जी को और अपनी इस भाजपा सरकार को जिन्होंने ये सराहनीय काम किए है।

हमारे प्रदेश वासियों को कोरोना से बचाने के लिए हमारे कोरोना योद्धाओं ने जो योगदान दिया है, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने उन कोरोना योद्धाओं को जिन्होंने अपने जीवन की बाजी को हारकर प्रदेश वासियों को बचाने का काम किया है, देशवासियों को बचाने का काम किया है। हमारा उत्तर प्रदेश आज नई दिशा में जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत सम्पन्नता की श्रेणी में जाना जाता है। हमारा वह क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ पर कृषक बड़ी संख्या में रहते हैं। कई बार उसको नजर अन्दाज भी किया जाता रहा है, लेकिन हमारे योगी जी की सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले तिगरी धाम के लिए भी मैं आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने वहाँ जो एक ऐतिहासिक और पौराणिक मेला लगता है, उसको सरकारी मेला घोषित करके हमारे जनपदवासियों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों की भावनाओं का ध्यान रखा और उसको सरकारी मेला घोषित किया। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने परिवहन मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने गजरौला में जो हमारा रोडवेज बस स्टैण्ड है उसको ठीक कराके पुनः चलाने का काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जल शक्ति मंत्री जी का जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के शेरपुर से लेकर दड़वड ठेठ तक तटबन्ध बनाने का जो काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ अपने आदरणीय उप मुख्य मंत्री जी का जिन्होंने चकनवाल और सीझोवाली जो एक बाहा नाला पड़ता है, आजादी के बाद से आज तक डेढ़ दर्जन गाँव ऐसे थे जहाँ के लोग आज भी नाव से निकलते हैं जो क्षेत्र हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है, वहाँ पर एन0ओ0सी0 कराने के बाद हमारे आदरणीय उप मुख्य मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने उसको स्वीकृत किया है और गजरौला से मुण्डामुकारी मार्ग तक का चौड़ीकरण करने का काम किया है। शेरपुर से धनौरा तक मार्ग का चौड़ीकरण करने का काम किया है और अभी स्वीकृति उन्होंने दी है, कमेलपुर से धनौरा के चौड़ीकरण के लिए और गजरौला थाना चौराहे से लेकर तिगरीधाम की तरफ जो रास्ता जाता है उसको फोर लेन बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपने ऊर्जा मंत्री जी का जिन्होंने डीगरा बिजलीघर जो कि 18 वर्षों से बंद पड़ा था पूर्व की सरकारें उसको चालू नहीं करा पायीं आदरणीय हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने उसको चालू कराकर 18, 20, 22 से 24 घंटे बिजली देने का काम किया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और साथ ही एक माँग और करता हूँ कि जो हमारे उपभोक्ता हैं अभी हमारे जनपद से एक मैसेज आया कि जो एकमुश्त समाधान योजना लागू हो रही है उसको 1 मार्च से शुरू कर दिया गया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, चाहे कामर्शियल उपभोक्ता हो, चाहे वह घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे वह कृषि से जुड़े हुए किसान भाई, उन सबके लिए हम एकमुश्त समाधान योजना लेकर आए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जहाँ एक ही घर में डबल कनेक्शन कर दिये गये हैं या जिनका ट्यूबवेल का सामान रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं मिल पाया है उसके लिए मैं आपके माध्यम

से मांग करता हूँ कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी इस पर अब ध्यान देंगे और हमारे किसान भाइयों को उनके ट्यूबवेल लगवाने के लिए उनके कनेक्शन और उनका सामान देने की कृपा करेंगे।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यहाँ पर हमारे आदरणीय पर्यटन मंत्री जी उपस्थित हैं, जो तिगरी धाम है, वहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावना है, क्योंकि ब्रजघाट में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, हाई-वे है तथा तिगरीधाम और ब्रजघाट की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। उसको यदि हम पर्यटन की दृष्टि से विकसित करते हैं तो वहाँ पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे और तिगरी में अभी गंगा के किनारे घाट नहीं बने हुये हैं जबकि वहाँ पर प्रत्येक दिन 5 हजार से 6 हजार की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और साथ ही मैं एक विद्युत शवदाह गृह की मांग करता हूँ, जहाँ पर प्रत्येक दिन 25 से 30 अंतिम संस्कार होने के लिए शव आते हैं, इसलिए मैं माँग करता हूँ कि एक विद्युत शवदाह गृह वहाँ पर बनाया जाये और पर्यटन की दृष्टि से उस तिगरीधाम को विकसित किया जाए, जिससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

मैं अपने आदरणीय नगर विकास मंत्री जी से भी माँग करता हूँ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि गजरौला में हमारे प्राधिकरण के द्वारा एक कॉलोनी विकसित की गयी लेकिन उसको नगर पालिका को हैण्डओवर कर दिया गया है। उसकी सड़कों की मरम्मत पिछले 11 वर्षों से नहीं हो पायी है। पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए आदरणीय नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अतिशीघ्र वहाँ के मार्गों को बनाने की कृपा करेंगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि मुरादाबाद मण्डल में कोई सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। अमरोहा जनपद का इस बार आज हमारे हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान आया है, मैं अपनी माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, बहन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अमरोहा पर विशेष ध्यान दिया। हमारे उप मुख्य मंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया, हाई स्कूल में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान और इण्टरमीडिएट में तीसरा स्थान अमरोहा का है लेकिन वहाँ पर बच्चे हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन विश्वविद्यालय बरेली मण्डल में भी है और मेरठ मण्डल में भी है लेकिन मुरादाबाद मण्डल में कोई सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है जिसके कारण हमारे बहुत सारे भाई-बहन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जैसे आई0एफ0टी0एम0 तथा टी0एम0यू0 इनकी भारी-भरकम फीस है, वेंकटेश्वराय की भारी भरकम फीस है। कई बार विद्यार्थियों को वहाँ पर प्रताड़ित भी करते हैं और अधिक फीस वसूलते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ सरकारी विश्वविद्यालय बनाने की कृपा करें। गजरौला मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता हैं, जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे और स्थानीय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की मैं माँग करता हूँ। हमारे स्थानीय भाई-बहन बहुत सारा प्रदूषण अपने शरीर के अंदर सहन करते हैं, उनको वहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें और जितनी भी स्थानीय समस्यायें हैं गजरौला की उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठायें, प्रदूषण से मुक्ति दिलायें। एक और छोटी-सी माँग करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करूंगा मा0 अधिष्ठाता महोदय कि हमारा जो जनपद है पूर्व में महात्मा ज्योतिबाफूले जी के नाम पर जिसका नाम था, जो कि डा0 भीमराव

अम्बेडकर जी के गुरू रहे हैं मैं उसको पुनः ज्योतिबाफूले जी के नाम से अमरोहा जनपद के नामकरण की माँग करता हूँ कि उसको पुनः ज्योतिबाफूले के नाम से बनाया जाये और अमरोहा के विकास के लिए जहाँ पर लगभग 55 हजार किसानों की ऋण माफी हुई 1 लाख 31 हजार 310 गैस कनेक्शन दिये गये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री राजीव तरारा-

मान्यवर, थोड़ा समय और दे दें। 1 लाख 62 हजार शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्र में 40 हजार, शहरी क्षेत्र में 87 सौ, हमारे नगर विकास मंत्री जी ने नगरीय क्षेत्र में आवास बनाने का काम किया और ग्रामीण क्षेत्र में आवास बनाये जा रहे हैं। आयुष्मान योजना के माध्यम से बहुत सारे भाई-बहनों को चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने इस 5 लाख 50 हजार 2 सौ 70 करोड़ 78 लाख रुपये के बजट का समर्थन करता हूँ और इसकी बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूँ कि यह नये उत्तर प्रदेश को बनाने में अग्रणी साबित होगा। मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको मन की अनन्त गहराई से धन्यवाद देता हूँ। मैं मा0 वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। बजट में सबका साथ, सबका विकास का वास्तव में ध्यान रखा गया है। चाहे वह युवाओं की बात हो, चाहे वह युवाओं की उच्च शिक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो या किसानों के सिंचाई हेतु पानी की बात हो, गरीब किसानों हेतु आवास की बात हो, सम्पर्क मार्ग, पुलिया सभी का बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। मान्यवर, इतना अच्छा बजट पेश किया गया है। कोरोना काल में भी बड़ी लड़ाई के बाद भी इतना बेमिसाल बजट जो पेश किया गया है, इसके लिए मा0 वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी ने जो कि शिक्षा किसी स्टूडेन्ट की एक नींव होती है, तो उन स्टूडेन्ट्स के लिए निःशुल्क कोचिंग का जो प्रावधान रखा है, यह वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। आत्मनिर्भर किसान विकास योजना, मुख्य मंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के तहत, फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने के तहत अनुदान की व्यवस्था भी की गयी है। पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4 हजार 94 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु व्यवस्था की गयी है। महिला शक्ति केन्द्र की भी मुख्य रूप से व्यवस्था की गयी है। यहां तक कि अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक मदद की भी व्यवस्था इसमें की गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूँ कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े इतने बड़े-बड़े काम किये गये हैं कि केवल इन्वेस्टीगेशन के लिए 1 हजार 73 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। आरोग्य केन्द्रों हेतु 425 करोड़ रुपये ब्लाक स्तर पर लोक स्वास्थ्य के लिए 77 करोड़ रुपये, वर्ष 2017 से पहले केवल 7 और 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे परन्तु स्वास्थ्य मंत्री और मा0 मुख्य मंत्री जी की कृपा से 30 नये मेडिकल कालेज जिसमें से बहुत सारे मेडिकल कालेज चालू हैं और कुछ मेडिकल कालेज चालू होने को हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि अटल बिहारी बाजपेयी, चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था है। यह वास्तव में बहुत ही बड़ा बजट है। मा0 अध्यक्ष जी रेटिनोपैथी उपचार हेतु सेन्टर की व्यवस्था के लिए भी बड़ा इंतजाम सरकार ने किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि अयोध्या में एक इतना विशाल मंदिर, जिसमें हजारों करोड़ रुपया लगेगा और श्री राम के जो सखा थे, परमपूज्य महाराज निषादराज गुह्य, मेरी बात हुई और मैंने सपना में देखा, भगवान राम ने कहा कि अगर मेरे मित्र निषादराज गुह्य की मूर्ति मेरे पास नहीं होगी तो मैं आधा साबित होऊंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महाराज श्री राम के साथ महाराज निषाद की मूर्ति होना अति आवश्यक है।

अधिष्ठाता महोदय, जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र में एक इन्टर कालेज मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिया है और मैं इसी क्रम में कहना चाहूंगा कि अगर एक आई0टी0आई0 स्कूल बन जायेगा तो जनपद फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र में जो वास्तव में शिक्षा से हजारों साल दूर रही है। अगर हम कहें तो 70 साल देश को आजाद हुए हो गये हैं, परन्तु आज तक वहां पर बच्चियों के लिए न तो इंटर कालेज है, न आई0टी0आई0 है और न पॉलिटेक्निक कालेज है। यदि यह व्यवस्था हो जाएगी तो हमारी बेटियों को बहुत सारा एजुकेशन में लाभ मिलेगा और हमारी बेटियां भी इस देश की अधिकारी बन सकेंगी। उच्च शिक्षा के माध्यम से इस देश को चलाने में उनकी भी अग्रणी भूमिका रहेगी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि एक फलोर नगरिया यानि फिरोजाबाद जनपद में पानी काफी नीचे होने के कारण वहां पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है इसलिए वहां फलोर नगरिया में एक बड़ा सा बांध बन जायेगा जो कि आगरा तक उस डार्क जोन को बचाने में लाभ मिलेगा।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद, फतेहाबाद मार्ग के बरी चौराहे से बसई मोहम्मदपुर होकर अन्ते की मडइयाँ मडुआ होकर फतेहाबाद मार्ग पर चौड़ीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी मैं दो लाइनें और पढ़ूंगा कि-

नजर लक्ष्य पर थी, गिरे और संभलते रहे,

हवाओं ने पूरा जोर लगा दिया, फिर भी चिराग जलते रहे।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि 04-05 करोड़ की विमुक्त जाति की आबादी के मल्लाह, केवट, निषाद व मझवार जाति के लोगों को पिछली सरकार में जाति प्रमाण-पत्र मिले थे। पंडित दीन दयाल उपाध्याय का भी यह सपना था कि हम दबी-कुचली जातियों को यानि अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्तियों को लाभ दिला सकें। माननीय अध्यक्ष जी, यह बिरादरी

यह नहीं, रही है कि उसे नौकरी मिल जाये केवल उसे जाति प्रमाण-पत्र मिल जाये जिससे कि उन जातियों के छोटे-छोटे बच्चे अच्छे-अच्छे स्कूलों में पढ़कर शिक्षित बनें और हमारे देश का भविष्य बनें। माननीय अध्यक्ष जी, यह सब किताब में लिखा है उसके बावजूद भी यहां के जो लोकल आफिसर हैं, वो उनके जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाकर उनको बेवजह परेशान करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं सभी को दिल की अनन्त गहराई से धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट-**

आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने आपको अपने नेता प्रतिपक्ष के दिये गये प्रस्ताव के साथ सम्बद्ध करते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार द्वारा जो बजट लाया गया, उसमें दावे बड़े-बड़े किये गये, बजट में दावों की पूरी भरमार है, लेकिन असलियत में क्या है ये गांव के किसानों से पूछिये गांव के लोगों से पूछिये आज इस सरकार में, जो अपने आपको किसान समर्थक सरकार बताती है, किसानों के धानों की खरीद नहीं हुई। मैं राजधानी लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज से आता हूं। हमारी विधान सभा क्षेत्र चूंकि एक ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र है और यहां पर ज्यादातर हमारे किसान भाई रहते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय खेती ही है। हमारी विधान सभा क्षेत्र में आवारा पशुओं की बात करें तो चारों तरफ आवारा पशु, मवेशी घूम रहे हैं और हमारा किसान रात-दिन अपने खेतों पर रहने को मजबूर है। आज हमारे विधान सभा क्षेत्र में तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर हो चुके हैं, उनके निर्माण के लिए सरकार द्वारा कोई घोषणा नहीं की गयी और आज बच्चे अन्यत्र स्थानों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की ही बात करूंगा जो राजकीय नलकूप है, और जो लोगों के व्यक्तिगत नलकूप हैं, उनका बिल इस समय इतना ज्यादा आ रहा है कि वह उसको कैसे भरें। किसान की आय दोगुनी करने की जो सरकार की योजना है, वह कैसे सफल होगी, जब लोग अपने खेतों में महंगी खाद, महंगी बिजली से वहां पर सिंचाई कर रहे हैं और उनकी लागत का मूल्य नहीं निकल पा रहा है तो आय दोगुनी करने की तो कोई बात ही नहीं है। इस सरकार द्वारा यह छलावा प्रतीत होता है। हमारा क्षेत्र चूंकि लखनऊ का ही क्षेत्र है लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र की सड़कें पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। तमाम ऐसी सड़कें हैं जिसको लेकर मैं विगत 04 सालों से इस सरकार से मांग करता आ रहा हूँ, लेकिन सरकार द्वारा विपक्ष का विधायक होने के कारण राजधानी की जो हमारी तमाम सड़के हैं उनको बनाने का काम इस सरकार द्वारा नहीं किया गया। इसमें सबसे प्रमुख मार्ग है, हमारा नगराम से गंगागंज मार्ग, जिस पर पैदल चलना भी दूभर है। अगर आप उस पर पैदल चलेंगे तो आपके पैर मोच के कारण खराब हो जायेंगे। तमाम ऐसी रोडें हैं, हमारे माननीय अधिष्ठाता महोदय हमारी पूर्वी विधान सभा क्षेत्र का एक ब्लाक है गोसाईगंज जिसमें पुलिया टूटी हुयी है जो फरीदपुर की तरफ है, उसके लिये मैं विगत 8 महीने से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारियों से कह रहा हूँ, लेकिन अधिकारियो द्वारा अब तक उस पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूर्व की माननीय अखिलेश यादव की सरकार में हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही थी। हमारे क्षेत्र में आई0टी0, अमूल डेरी तथा कैंसर हास्पिटल जैसी तमाम बड़ी-बड़ी योजनायें माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में आई। लेकिन इस सरकार द्वारा जो उस सरकार के समय में बनी रोडें थीं, वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद भी दुबारा उसका निर्माण नहीं कराया गया, जिसमें सबसे बड़ी प्रमुख रोड है खुजौली से लेकर नगराम तक, जोकि पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, उसका भी निर्माण या लेपन का कार्य इस सरकार द्वारा नहीं कराया गया।

हमारे विधान सभा क्षेत्र में चारों तरफ भ्रष्टाचार है। थानों में जमकर अवैध वसूली हो रही है, अगर कोई थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंच गया तो वह बगैर चढ़ावा चढ़ाये थाने से वापस आने वाला नहीं है। यह भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा करने वालों की हकीकत है। तहसील में जमकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। चारों तरफ लेखपाल और राजस्व अधिकारी बगैर पैसा लिये कोई कार्य करते नहीं हैं, जब तक उनको पैसे के रूप में चढ़ावा न मिले।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस देश में किसानों का आन्दोलन चल रहा है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के किसान भी आज पूरी तरह इस आन्दोलन के साथ हैं और अपनी मांगों को लेकर बराबर आन्दोलन कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का विधायक होने के नाते उनका समर्थन करता हूँ और उनकी हर आन्दोलन में हर वक्त साथ खड़े होने का वादा करता हूँ। मैं सरकार के विषय में केवल दो पंक्तियां कहूंगा, इस बजट के लिये कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।

(श्री प्रतीक भूषण सिंह का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2021-22 के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। पूज्य योगी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का परिचायक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धान्त लक्ष्य अन्त्योदय, प्रण अन्त्योदय और पथ अन्त्योदय को परिभाषित करता है। यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवाओं, महिलाओं के सशक्तीकरण और प्रदेशवासियों के लिये सेवा और सम्मान का भाव प्रस्तुत करता है। इसलिये पूरे विश्वास से पूर्ण बहुमत के साथ कह सकते हैं कि 2021-22 का बजट भारतीय जनता पार्टी के 2022 से 2027 तक के कार्यकाल के लिये नींव तैयार करने का काम करेगा। एक लाइन में बजट पर कहना चाहता हूँ, भाजपा के राजतिलक की तैयारी है, भाजपा सभी पे भारी है।

पूज्य योगी महाराज जी ने 2018-19 वित्तीय वर्ष में मेरे विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के लिये तीन महत्वपूर्ण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसमें एक फायर स्टेशन, जो कि

निहुआडीह में बन रहा है, दूसरा सी0ओ0 सर्किल उभांव थाने में और तीसरा राजकीय इण्टर कालेज जो अखोप ग्राम सभा में निर्माणाधीन है। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्यों के लिये बजट की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

साथ ही साथ बेल्थरा रोड विधान सभा क्षेत्र के लिए एक सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय की माँग करता हूँ और माननीय उर्जा मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि नगरा विद्युत उपकेन्द्र जोकि 33/11 का विद्युत उपकेन्द्र है, वहाँ अधिकाधिक सरकारी भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लिए 132/33 के विद्युत उपकेन्द्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें जिससे जनता की वर्षों पुरानी माँग पूर्ण हो सके। साथ ही साथ भीमपुरा को नगर पंचायत घोषित करने की कृपा करें, मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करता हूँ। साथ ही साथ माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि बेल्थरा रोड तहसील जिला मुख्यालय से 60-70 कि0मी0 की दूरी पर पड़ता है और ऐसे कई सुदूर ग्राम सभायें हैं, जहाँ से जिला मुख्यालय पहुंचने में डेढ़ से दो घण्टे लगते हैं, 100 किमी0 तक की दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही साथ सन् 2001 से 2002 के बीच बेल्थरा रोड को जिला बनाने के लिए एक सर्वे का कार्य कराया गया था। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसके आधार पर सर्वे का कार्य आगे बढ़ाया जाये और बेल्थरा रोड को जिला बनाने के लिए जनपद बलिया का पुनर्गठन करने का कार्य करें। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास की राजनीति होती है तो निश्चित रूप से इससे बहुतायत संख्या में यहाँ के नागरिकों को विकास कार्यों से लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण माँग आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसा कि 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ सामाजिक समरसता दिवस का भी आयोजन भारतीय जनता पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा पूरे देश में किया जाता है। मेरा निवेदन है कि पूज्य संत गाडगे जी जोकि जीवनपर्यन्त शिक्षा, स्वच्छता और समरसता के लिए अपने पूरे जीवन को उन्होंने समर्पित किया। उनका जन्म दिवस 23 फरवरी को मनाया जाता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे संत शिरोमणि श्री संत गाडगे जी के जन्म दिवस को जो अभी विगत 23 फरवरी को हम सभी ने 145वें जन्म दिवस के रूप में जयंती समारोह का आयोजन किया था, मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस को राष्ट्रीय, सामाजिक समरसता दिवस के रूप में आयोजित करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

मान्यवर, मैं आज के इस अवसर पर माननीय उप मुख्य मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। स्टेट हाई-वे जो कि बिन्द्रा बाजार चिरैया कोट, बेल्थरा रोड के लिए घोषित हुआ था, उसमें 4 कि0मी0 मेरी विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। उसके लिए उन्होंने आज

ही के दिन जी0ओ0 जारी करने की महती कृपा प्रदान की है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत-बहुत अभिवादन करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता जी, जब सपा की सरकार रहती है तो ऐसी इनकी बहुत सी कार्य-प्रणाली देखी जाती है कि हमेशा घमंड में और हवा-हवाई कार्यों को करने का कार्य करते हैं। एक परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, एक पक्का मकान का निर्माण और दूसरा बेटी की शादी। लेकिन यही सपा सरकार है जोकि यह कहा जाये कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री आवास की सूची सारे प्रदेशों से केन्द्र को भेजी जा रही थी, लेकिन सपा की सरकार ने ऐसी सूची केन्द्र को नहीं भेजी और ये ऐसा अपराध करने का कार्य किये। आज जब योगी जी की सरकार ने 40 लाख प्रधानमंत्री आवास पूरे प्रदेश में दिये हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सपा की सरकार जोकि लाल टोपी के काले कारनामे, ऐसे बहुतायत की संख्या में हैं। पूरा जगजाहिर है और आज विशेषकर जब पूरा सदन बजट पर अपनी प्रस्तुति दे रहा है। योगी जी की सरकार के बजट पर अपनी बात रख रहे हैं तो यह अपने समय के बजट की चर्चा करने लगते हैं। जबकि अगर यह ध्यान से याद करें तो वह 2016 का समय जब इनका आखिरी बजट प्रस्तुत हुआ था तो ये उस समय अपने परिवार के ही चाचा-भतीजा का खेल कर रहे थे, मुखिया की धोती फाड़ने और उनके मुंह में ठूसने का काम कर रहे थे, ये कारनामे ये लोग अपने अन्तिम बजट के समय कर रहे थे। ये बातें इनको सदन में रखनी चाहिए तो आज ये दूसरी बातों को सदन में रख कर गुमराह करने का काम करते हैं। इनकी लाल टोपी, इनके काले कारनामों की लम्बी फेहरिश्त है। एक विषय और रखना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की योजना लाती है, मिशन शक्ति की योजना लाती है, एण्टी रोमियो स्क्वायड लाती है इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जब ये सत्ता में रहते है तो बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं पर कहते है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये सारे बयान इस देश की संस्कृति, संस्कार एवं मानवीय मूल्यों को तार-तार करने वाले हैं।

श्री अधिष्ठाता-

जो शेष रह गया हो उसे आप दे दें, मैं कार्यवाही में जुड़वा दूंगा।

श्री धनन्जय कनौजिया-

मान्यवर एक लाइन कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूज्य योगी जी के नेतृत्व में भगवाधारियों की सरकार है, जो जप, तप, त्याग, तपस्या, सेवा, सम्मान और राष्ट्रवाद के प्रतीक है जबकि दूसरी और सपा जो कि लाल टोपी और काले कारनामों के संरक्षक है, रखवाले हैं, वह भय, भूख, भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी के प्रतीक हैं। लाल टोपी दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित के शोषण का प्रतीक है, लाल टोपी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की दुर्व्यवस्था की प्रतीक है। इन्होंने अपने बीस सालों के कार्यकाल में ये सभी काले कारनामे किये हैं, बीस साल भारतीय जनता पार्टी को मिलने दीजिये न यह लाल टोपी होगी और न ही काले कारनामें होंगे सिर्फ और सिर्फ राम राज्य होगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का सपना साकार होगा। इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ जय हिन्द, जय भारत, जय श्री राम।

***श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य पाँच-पाँच-मिनट में बोल ले तो ज्यादा लोगों को बोलने का अवसर मिल जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मैं भी यही कह रहा हूँ, अब जो माननीय सदस्य पाँच मिनट से ज्यादा बोलेंगे उनका भाषण कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। कृपया पाँच मिनट का ही समय लें।

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं अपनी सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवंटन किया है। मैं सहारनपुर से आता हूं वहाँ पर पहले से ही एक मेडिकल कॉलेज है, लेकिन पूर्व की सरकारों ने उस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर शेखूधन कर दिया था और जो मेडिकल कॉलेज था, वह मान्यवर कांशीराम जी के नाम से था इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसका नाम संत गुरु रविदास मेडिकल कॉलेज, मान्यवर अटल बिहारी बाजपेयी या डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज कर दिया जाय। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या थी, लगातार हम लोग बोलते भी आ रहे थे, हमने प्रश्न भी किये, मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ग्रामीण मिशन के रूप में मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी योजना टंकी के माध्यम से आई जिसमें हमारे क्षेत्र की जनता को स्वच्छ जल मिला, मैं इसके लिए अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि वह इतनी बड़ी योजना हमारे क्षेत्र में लेकर आये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई तो हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्या यूनिवर्सिटी की थी क्योंकि पढ़ने-लिखने के बाद उच्च पढ़ाई के लिए दिल्ली, उत्तरांचल, हरियाणा जाना पड़ता था लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की इस बहुत बड़ी कठिनाई का समाधान किया और हमारे जिले सहारनपुर में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी देने का काम किया। मैं उप मुख्य मंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्या जी को धन्यवाद देता हूं कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ खनन की वजह से सड़कों की बहुत दुर्दशा थी, हम जब दूसरे राज्यों में जाते थे तो लोग हमारे जिले में आने से डरते थे।

मान्यवर, सड़कों का इतना बुरा हाल था कि पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं। जब से हमारी सरकार आयी, हमने लगातार हाई-वे बनाने का कार्य किया। हमारे विधान सभा में बहुत व्यापक रूप से सड़के बनी। हमारे यहाँ से दिल्ली की कनेक्टीविटी के लिए दिल्ली को फोरलेन से जोड़ा गया। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बहुत जल्द "माँ शाकुम्भरी देवी" तक फोर लेन ले जाने का काम करेंगे। मैं इसके लिए अपनी सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं एक बार पुनः उप मुख्य मंत्री मा0 केशव प्रसाद मौर्या जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी विधान सभा में रु0 14 करोड़ का पुल देने का काम किया। इससे हमारे क्षेत्र की जनता को आने-जाने में बहुत सहूलियत होगा। इस पुल के न होने पर हमारे क्षेत्र की जनता को काफी दूरी चल करके आना-जाना पड़ता था। बरसात में उनको सहारनपुर से आवाजाही बंद हो जाती थी। मा0 मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा राजकीय महाविद्यालय दिया, उसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते है वहाँ के किसान बहुत अधिक गन्ना उगाने का काम करते हैं। पहले की सरकारों ने चीनी मिलों को बंद करने का काम किया था। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि बंद पड़ी "दया चोनी मिल" को पिछले पेराई सत्र में चलाने का काम किया। इसके लिए मैं मा0 गन्ना मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो शेष बंद पड़ी चीनी मिलें हैं, उनको भी चलाने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जो से आग्रह करता हूँ।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में यमुना नहर पड़ती है। वहाँ पर कलरपुर गाँव है। वहाँ एक सेतु की बहुत आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि उस पुल का निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराया जाय। दूसरा पुल इंदल नदी पर पड़ता है, जो हसनपुर-भलसवा को जोड़ता है। उसकी भी माँग बहुत दिनों से थी। मा0 मुख्य मंत्री जी से मैंने भी इस बावत कई बार बात को है। मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि इस पुल का निर्माण करा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, संक्षेप करें।

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे शहरी विकास मंत्री जी यहाँ पर बैठें है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि रामपुर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया जाय। नागल क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया जाए। हामरे यहाँ पर फायर स्टेशन नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा कि मेरे क्षेत्र 'रामपुर मनिहारन' और 'नागल' में एक फायर स्टेशन कि स्थापना कि जाए। हमारे विधान सभा क्षेत्र में जब कभी आग लग जाती है, तो हम लागो को आग बुझाने के लिये सहारनपुर फायर स्टेशन पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए हम अपने क्षेत्र के जनमानस कि तरफ से फायर स्टेशन बनाने कि माँग करते है। हमारे यहाँ पर मानक माऊँ पट्टी से जोड़ने वाला मार्ग बहुत दिनों से क्षतिग्रस्त है, उसको बनाने की भी मैं माँग करता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बजट में बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट के लिए अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अधिष्ठाता-

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2021-22 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रस्तुत बजट से किसान, गाँव, गरीब,

महिला, व्यापारी तथा युवा मजबूत हो रहे हैं। इस बजट से स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, समावेशी विकास अत्यधिक मजबूत होगा।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं एक किसान परिवार से हूं। हमारे संस्कार, व्यवहार, जीवन-मरण यहां तक की हमारी आत्मा किसान है। प्रस्तुत बजट में किसानों की आय दुगनी करने के लिए इतनी योजनाए बनाई गयी है। ''आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना'' के लिए सौ करोड़ रुपये ''मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना'' के अन्तर्गत छः सौ करोड़ रुपये, किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए सात सौ करोड़ रुपये, रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान के लिए चार सौ करोड़ प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान के अन्तर्गत 2021-22 में 15000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके लिए मैं आदरणीय योगी सरकार और अपने मुख्य मंत्री जी को कोटिशः बधाई देता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विपक्ष के साथी जो उधर बैठे हैं, कोरोना काल में व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे थे। मान्यवर हमारे देश के रगड़गंज के निवासी श्री शिव शंकर कौशल की पुत्री सृष्टि कोटा, राजस्थान मे पढ़ रही थी, वह माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा भेजे गये बसों से नहीं आ पायी थी। श्री शिव शंकर कौशल ने परेशान होकर मुझे फोन किया, मैंने तुरन्त अपर मुख्य सचिव, गृह से बात की। उन्होनें पूछा कि गाड़ी भेजना है या बेटी अपनी गाड़ी से आयेगी। मैंने कहा श्री शिव शंकर कौशल के पास गाड़ी है और उसी से वह कोटा जाना चाहते है, पास की आवश्यकता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ 10 मिनट के अन्दर पास बन करके मेरे व्हाट्सअप पर आ गया। सामने बैठे हुए विपक्ष के साथियों से अनुरोध है कि सदन में ऐसा सफेद झूठ न बोला करें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहाँ तक व्यवस्था की बात है, हमारे क्षेत्र के कुछ प्रवासी श्रमिक गुजरात सूरत से एक गाड़ी से आ रहे थे। मध्य प्रदेश के गुना के पास उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दो लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये और 3-4 लोगों को हल्की चोटे आयी थी। रात के 12:00 बजे हमने उस समय प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, गृह को फोन किया और मध्य प्रदेश में वहां उनकी व्यवस्था हुई। दूसरे दिन के0जी0एम0यू0, लखनऊ में उनके इलाज की व्यवस्था हो गयी। इस तरह से कोरोना काल में हमारे मुख्य मंत्री जी की व्यवस्था थी। मैं बार-बार आदरणीय मुख्य मंत्री जी व योगी सरकार को कोटिशः धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब संक्षेप करें।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विपक्ष के जो साथी बैठे हुए है, वह विकास की बात करते है। हमारे गोण्डा जनपद में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। गोण्डा जाने में उस समय छः घंटे लगते थे। आज हमारी योगी सरकार हैं, हम लखनऊ से गोण्डा डेढ़ से दो घंटों में

पहुंच जाते हैं, यह विकास की स्थिति है। गोण्डा ऋषियों-मुनियों की धरती रही है। हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया था, आयोध्या से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है।

माननीय अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारी विधान सभा क्षेत्र मे चमचमाती सड़कें हैं, घर-घर बिजली पहुँच रही है, पेय जल की व्यवस्था हो रही हैं, हर खेत को पानी पहुंच रहा है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण कैथी घाट के पुल के निमार्ण के लिए आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि यह पुल अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसे बनवाने कि मैं सरकार से अपील करता हूं। हमारे क्षेत्र में जो मजरे विद्युतीकरण के अच्छादन से छूट गए है, उन्हें पुनः इस 2021-22 में अच्छादित करने का अनुरोध करता हूं। इसी के साथ 05 लाख, 50 हजार, 270 करोड़, 78 लाख रुपये का बजट है उसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

***श्री किशन लाल राजपूत-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2021-22 के प्रस्तुत बजट के समर्थन पर बोलने का मौका दिया। वर्ष 2021-22 आय व्ययक पेपर लेस बजट अपने सीमित साधनों मे आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं के आधार पर, क्षेत्रों में होने वाले कार्यो की जो रूप रेखा तैयार होती है, उसे आय-व्ययक बजट की संज्ञा दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट अंकन रुपये 5 लाख 50 हजार करोड़ से ऊपर का बजट परमपूज्य महाराज योगी जी के कुशल नेतृत्व में बनाकर प्रस्तुत किया गया है। यह उत्तम व अति उत्तम ही नहीं बल्कि अति उतकृष्ट, जन कल्याणकारी, समावेशी बजट हैं। परम आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय वित मंत्री जी ने बिना रूके, बिना थके जो बजट प्रस्तुत किया उनको भी मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं। खासतौर से युवाओं के लिये इस बजट में बहुत अच्छी जगह दी गई है तो युवाओं के लिए मैं दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा।

कृपाणों की नंगी धारों पे जग की आजादी पलती है,

और इतिहास मोड़ ले जाता है जिस ओर जवानी चलती है।

(मेजों की थपथपाहट) कोरोना महामारी ने प्रदेश सहित पूरे देश में एक महामारी का रूप ले लिया था तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने जो साहस और दृढ़ता, का परिचय दिया, पूरे देश और प्रदेश को कोरोना महामारी से बचाने का काम किया। जहां अपने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपदों से अलग-अलग प्रदेशों मे छात्र पढ़ने के लिए, श्रमिक, मजदूर अपने घरों से काम करने के लिए बाहर गए हुए थे, उनको सकुशल वापस घर तक पहुंचाने तक का काम किया। यही नहीं भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक जिन्होंने कोरोना काल के अन्तर्गत मध्यान्ह् भोजन को जरूरतमंदों के घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। माननीय परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने एक सच्चे धर्म की राजनीति का परिचय दिया। जहां एक ओर पूरा प्रदेश कोरोना महामारी में जल रहा था और वहीं उनके पिताश्री का आकस्मिक निधन भी हुआ। एक सच्चे राजा का धर्म निभाते हुए उन्होनें अपने पिताश्री के अंतिम दर्शन भी नहीं किए और अन्त्येष्टि में भी नहीं पहुंच पाये। उन्होने 24 करोड़ जनता को कोरोना महामरी से बचाने के लिए एक सच्चे राजा का जो धर्म होता है, उनका पालन किया। हमारे विपक्ष में बैठे हुए साथी लोग कटाक्ष भी करते है, और टीका-टिप्पणी भी करते है तो उस पर भी दो पंक्तियां कहना चाहूँगा कि-

कथनी मीठी खाँड सी और करनी विष की लोय,

करनी तज करनी करो तो विष से अमृत होय।

(मेजों की थपथपाहट) कहने मे और करने मे बहुत बड़ा अन्तर होता है, जरा करेंगे तो पता लगेगा। शिक्षा की बात करें तो बेसिक शिक्षा, जैसे हमारे शरीर मे रीढ़ की हड्डी का जो कार्य होता है ठीक उसी प्रकार से बेसिक शिक्षा का भी कार्य होता है। हमारे शिक्षा मंत्रियों ने छात्रों के लिए एक-एक नहीं बल्कि दो-दो रंगीन ड्रेस देने का काम किया। साथ मे जूते दिये, मोजे दिये, और सर्दियों मे पहनने के लिए गर्म स्वेटर भी दिया। और मध्यान्ह् भोजन भी छात्रों को मानक के अनुरूप दिया। ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था है। अगर छात्र के माता-पिता अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठकर नहला-धुलाकर बालों मे तेल कंघी करके अगर विद्यालय को भेजते है तो मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस समय के बेसिक स्कूल किसी कॉन्वेन्ट स्कूल से कम नजर नहीं आयेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर बिजली की बात करे तो हमारे ऊर्जा मंत्री जी, जिनके पास से होकर निकल जाओं तो शरीर मे ऊर्जा का संचार हो जाता है। हमारे बरखेड़ा विधान सभा क्षेत्र मे ऐसे तमाम छोटे-बड़े मजरे थे, जब से देश आजाद हुआ और गांवों की बसावट हुई, तब से उन गांवों मे बिजली के नाम से एक बल्ब भी नहीं जला है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और प्रदेश मे आदरणीय श्री श्रीकान्त शर्मा जी ऊर्जा मंत्री बने, तबसे उन छोटे-बड़े मजरों मे भी बिजली पहुंचाने का काम किया है। मैं उनको भी एक शेर कहना चाहूंगा।

''आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जायेंगी।

बस वहीं साख बचेगी जो लचक जायेंगी।।''

अन्त में मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन बहुत ही मूलभूत आवश्यकतायें हैं, जनपद पीलीभीत मे चार विधान सभा क्षेत्र हैं। एक ऐसी विधान सभा क्षेत्र है, जिसकी अपनी कोई निजी तहसील नहीं है जनपद पीलीभीत मे पाँच तहसीले हैं, पाँचों तहसीलों में क्षेत्र बंटा हुआ है। मैं सदन के माध्यम से अधिष्ठाता महोदय जी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जनपद पीलीभीत की गजरौला तहसील गजरौला में एक नई तहसील की स्थापना की जाये, जिससे कि वहां के क्षेत्र

की जनता का विकास होगा और कार्य भी सुगमतापूर्वक होंगे। जनपद पीलीभीत मे इन्टर तक की कृषि शिक्षा का प्राविधान वर्ष 1948 से है, लेकिन कृषि से इससे आगे की शिक्षा के लिए अन्य-अन्य जिलों में या अन्य प्रदेशों में जाने के लिए छात्रों को मजबूर होना पड़ता है, जिनका कृषि रूचिकर विषय है। जनपद पीलीभीत में शाहगढ़ में 38 हेक्टेयर का राजकीय कृषि फार्म है। अगर वहां पर कृषि महाविद्यालय खोल दिया जायेगा तो जनपद पीलीभीत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यहीं नहीं जनपद पीलीभीत के मझौला में एक सुगर मिल काफी लम्बे समय से बंद चल रही है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि उस शुगर मिल को भी पुनः चालू कराने का काम किया जाये। अन्त में दो पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

''भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं।
वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।।''

एक बार फिर अपने समर्थ साथियों की ओर से बजट को समर्थन देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।

श्री तेजेन्द्र निर्वाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। तीन दिन का इन्तेजार करने के बाद आपने मुझे समय देकर कृपा की है। मैं 2021-22 के बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और हमारे मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने जो बेहतरीन बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारी सरकार का यह पाँचवा बजट है, और हर बजट में हमेशा देखते है हमारे नेता प्रतिपक्ष जिनका हम बेइनतंहां आदर करते हैं, यह पहला बजट है जिसमे वह कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहे थे वरना पहले बजट मे उनकी दहाड़ हजरतगंज तक सुनाई देती थी, लेकिन इस बजट के दौरान वह बार-बार पूछते थे कि मैं कुछ बोलू या नहीं बोलूं। कभी पड़ोस मे इधर देखते थे कभी उधर देखते थे, लेकिन बसपा की तरफ से भी नहीं कहा गया कि आप बैठ जाओ कभी कांग्रेस की तरफ देखते लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया और पहली बार उनकी बॉडी लेंग्वेज यह बता रही है कि उनके अन्दर इस बजट को देखकर कितनी निराशा और कितनी हताशा है। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा है कि जिन जातियों को वह कम वोट बैंक समझकर वह छोड़ देते थे। मुसहर जाती बहुत छोटी सी है, कितना वोट बैंक है, हम इनके लिए क्यों करें, थारू के लिए हम काम क्यों करें, कोन के लिए हम काम क्यों करें, वनटांगियों के लिए क्यों काम करें, क्योंकि उनका वोट बैंक बहुत छोटा था। उन्हें यकीन नहीं था कि मा0 योगी जी की सरकार और हमारे मा0 वित्त मंत्री जी की नजर उस व्यक्ति तक पहुँच जायेगी जो विकास की कड़ी अन्तिम स्थान तक खड़ा है। वहां तक जाकर सोचने और बिना वोट बैंक का ध्यान किये ''सबका साथ, सबका विकास'' की भावना से काम करेंगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि कोरोना के काल मे जहाँ दूसरे दलों के ज्यादातर लोग छिपे हुए थे, वही हमारे सब कार्यकर्ता माननीय योगी जी के नेतृत्व मे किस तरह से जगह-जगह जाकर अपनी सरकारी व्यवस्थाओं को चेक कर रहे थे। गरीब लोगों तक पहुँचकर उनके भोजन की व्यवस्थाओं को देख रहे थे। गरीब लोगों तक पहुँकर उनके भोजन की व्यवस्थाओं को देख

रहे थे। उन्हें इस बात का भी यकीन नहीं कि 40 लाख श्रमिक आ सकते थे उनको उनके गृह जनपद तक पहुँचाने के लिए सरकार इस तरह से कर सकती थी सबको भोजन की व्यवस्था कर सकती थी। 20 लाख पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनके लिए हजार-हजार रुपये की दो बार व्यवस्था करना, गांव में भी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उसके लिए भी हजार रुपये की व्यवस्था करना टेस्टिंग की व्यवस्था जीरो से लेकर दो लाख प्रतिदिन पहुँचाना मान्यवर मेरे मन भी एक आक्रोश था कि दिल्ली की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा खेल क्यों खेला।

जब हम कोरोना से लड़ने के लिए योजनाओं मे लगे हुए थे तब दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मजदूर को और बिहार का मजदूर जो वहां रहता था उसे गुमराह किया कि यूपी के लिए बसें खड़ी हैं, चलो और 50 हजार से एक लाख तक आदमी कई दिनों तक एक दूसरे से सटे हुए खड़े रहें, महाराष्ट्र की सरकार ने भी ऐसा ही किया। कई दिनों तक लोग स्टेशन तक आते और वापस चले जाते। लोग एक दूसरे से सटे हुए खड़े रहते थे। मेरे मन में यह सवाल आया कि यह हुआ कैसे ? दो-दो सरकारें इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हैं ? धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष का जब उन्होंने बताया कि मैंने सबको पत्र लिखे थे, लेकिन उत्तर केवल महाराष्ट्र और दिल्ली से आया नेता विरोधी दल ने पत्र में क्या लिखा था, जो महाराष्ट्र और दिल्ली ने ऐसा उत्तर दिया। कौन सी योजना थी उनकी ? अगर हम दो मुख्य मंत्री की तुलना करे तो एक मुख्य मंत्री जी रामराज्य की परिकल्पना करके मर्यादा मे रहता है केवल और केवल कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उनके पिता जी के देहान्त की सूचना आती है, चेहरे पर मास्क था, मीडिया मे किसी ने कहा कि आंखे थोड़ी गीली हो गयी थी। दूसरे चैनल ने कहा कि आवाज थेड़ी भर्रा गयी थी लेकिन मीटिंग के अन्दर जो कोरोना को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के अन्दर कोई भी अधिकारी यह जज नहीं कर पाया कि उनके पास उनके पिता जी के देहान्त की सूचना आई थी। उस कोरोना के प्रोटोंकॉल का पालन करने के लिए महाराज जी अपने पिता के अन्तिम दर्शन करने भी नहीं गए। यह हमारे मुख्य मंत्री माननीय योगी जी हैं। दूसरे मुख्य मंत्री से हम तुलना करे तो अपने पिता जी के 75वें जन्मदिवस पर सैकड़ों करोड़ रुपय खर्च करके नर्तक्यिों को नचा रहें थे हीरोइनों को नचा रहे थे, जबकि उस समय सारा देश एक भयंकर आपदा से जूझ रहा था देश का किसान एक प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था। यह फर्क हैं हमारी और उनकी सोच में।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री तेजेन्द्र निर्वाल-

मान्यवर मेरा बहुत धीरे बोलने का स्वभाव हैं, लेकिन मैं बहुत तेज बोल रहा हूं। पाँच मिनट मे खत्म कर दूंगा। हमारी पॉजिटिविटी है, हम लोग नेता प्रतिपक्ष के प्रति भी इतना आदर रखते है कि हमने उनके लिए भी अगर वह बीमार हो तो हमने उनके लिए भी वी0वी0आई0पी0 व्यवस्था की उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं हमने की सारा ट्रीटमेंट बेहतर से बेहतर किया ताकि उनके अन्दर सकारात्मकता रहे, लेकिन हमारे 42 दिन प्रयास करने के बाद

भी 43 वें दिन निगेटिव के निगेटिव ही निकले। पता नहीं कहां से उनके अन्दर इतनी नकारात्मकता है। हमारा सारा प्रयास विफल गया। इन लोगों ने अपने नाम रख लिए धरती पुत्र, किसान पुत्र, माटी पुत्र, किसानों के मसीहा, दूसरों के लिए बोलते हैं कि किसान विराधी पार्टी, व्यापारी की पार्टी, जमाखोरों की पार्टी, वह सारे तमगे जो इन्होंने खुद को दिए हैं, अपने आपको किसान पुत्र मानते हैं। धरती पुत्र मानते हैं। मैं कुछ योजनाओं की तरफ ध्यान इंगित करना चाहूंगा, जो हमारे कार्यकाल में हमारी सरकार लाई है। पहली बार जब माननीय कल्याण सिंह मुख्य मंत्री हुए किसान बही लेकर आए, जो किसान के लिए पहचान-पत्र था। उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर को 72 घण्टे में बदलने की व्यवस्था की। इसके पहले कभी भी ट्रान्सफार्मर के लिए दिन निश्चित नहीं थे। पहली बार माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार में हमने तहसील दिवस की व्यवस्था की। बाद में चाहे किसी की भी सरकार आई, किसी ने भी उसको बंद नहीं किया। एक दिन निश्चित किया गया कि जहां पर किसानों की सारी समस्याएं एक दिन अधिकारी बैठकर सुन सके और उसका निराकरण कर सके। यूरिया के ऊपर समय-समय पर झगड़ा होता रहा हर दो साल में ब्लैक होता था। लाठीचार्ज होता था। हमने परमानेंट समस्या को हल किया और यूरिया को नीम कोटेड कर दिया। इसके बाद इस समस्या का परमानेंट हल हो गया। कोई व्यापारी यूरिया को खरीद नहीं सकता, वह केवल किसान के काम आयेगा। हमने सीधा किसान के खाते मे गन्ने का पेमेंट भेजना शुरू किया, यह भी माननीय कल्याण सिंह जी के समय में काम हुआ।

(इस समय सांय 07 बजकर 38 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

उस समय भी बहुत से लोग धरने पर बैठे, एक बड़ा आन्दोलन हमारे जिले में भी चला कि किसानों का पैसा सीधा खाते में नहीं जाना चाहिये। आज हर एक किसान खुश है और सब जानते है कि सीधा खाते में पैसा आता है और पहले हमारी पर्चियां गुम हो जाने के कारण पैसे के लेन-देन मे जो फर्क रहता था। वह फर्क अब नहीं रहता हैं और पहले हम पैसे को खतरे के साथ बीच से गुजर के अपने घर तक ले जाने मे भी असमर्थ थे हम भूमि अधिग्रहण बिल लाये। सबने धरना दिया, सबने प्रदर्शन किया, लेकिन आज मैं देख सकता हूं कि जितनी भी सड़कें सरकार दे रही है और हर किसान परिवार में अगर चार भाईयों की इकट्ठी जमीन है तो हर भाई चाहता है कि मेरे हिस्से कि जमीन भूमि अधिग्रहण के तहत आ जाये और मुझे उसका मुआवजा मिल जाये। मा0 अध्यक्ष जी, हमने सरकार बनने के मात्र 25 दिन बाद 14 अप्रैल को डा0 भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन से 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था शुरू कर दी। हमने पहली बार गांव और शहर के फीडर अलग-अलग-किये। किसान के लिए किसी भी क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिये क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अब आप संक्षेप करिये।

श्री तेजेन्द्र निर्वाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल दो मिनट का समय और लूंगा। नाम इनका धरती पुत्र, नाम इनका किसान पुत्र, लेकिन किसानों के लिए जो हमने काम किए, वह मैं गिना रहा हूं। ऐथेनॉल के लिए सब भाषण देते थे, 11 रुपये 80 पैसे का रेट था, आज 50 रुपये का रेट है और सभी गन्ना मील मालिक दोबारा से मांग कर रहे है। अब इस दर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर ज्यादा किया जाये, ज्यादा ऐथेनॉल मिलने की उन्हें परमिशन मिले। खांडसारी उद्योग के लाईसेंस की सीमा जो पहले 15 किलोमीटर थी, हमने उसको घटाकर 8 किलामीटर कर दी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री तेजेन्द्र निर्वाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी केवल चार लाईने ही बाकी रह गयी है। अपनी सरकार के कार्यो के बारे मे ही पढ़ रहा हूँ। हमने एक लाख करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रचर फंड दिया, लेकिन किसान पुत्र वह कहलाते है। हमारे जिले मे रोज 10 से 15-20 झगड़े किसानों के विभिन्न जगहों पर हो जाते थे, किसान का मेढ़ पर झगड़ा होता था या जमीन को लेकर किसी से विवाद होता था, किसान के सारे झगड़े समाप्त करने के लिए और समस्या को जड़ से हल करने के लिए हमने घरौनी बनाई और खतौनी को भी डिजिटलाईज कर दिया जिससे भविष्य मे कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं करेगा कि पैसे लेकर फीता इधर से उधर डाल दे। हमने हमेशा के लिए समस्या का समाधान कर दिया। हमने किसान सम्मान निधि दी, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन मा0 मोदी जी ने खुद से सोचा कि किसानों के लिए एक सम्मान निधि होनी चाहिये। हमने सिंचित भूमि का दायरा बढाया और केवल इसी वित्तीय वर्ष 2021-22 में हम 20 लाख हेक्टेयर भूमि को फिर से सिंचित करने जा रहे हैं। सोलर आधारित ट्यूबवेल चलाने के लिए केन्द्र सरकार के बज़ट मे 28 लाख ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई है। हम **'वन ड्राप मोर क्राप'** की योजना लाए, क्योंकि बुन्देलखण्ड मे पानी की बहुत कमी थी। हमारी सरकार ने पहली बार समर्थन मूल्य डेढ़ गुना दिया। मान्यवर, मेरा केवल यह सवाल है कि नाम तो इनके धरती पुत्र, नाम इनके किसान पुत्र, लेकिन काम सारा हमने किया है और विपक्ष का कोई भी नेता सामने आकर बताए, हमारी फेहरिस्त देख ले और अपने सारे धरती पुत्रों की फेहरिस्त देख ले। अगर हमारा काम इनसे ज्यादा होगा तो बात करें। सचमुच में किसान के हक मे काम करने वाले केवल हम हैं। उनका तो केवल एक ही तरीका है कि काम का खूब जिक्र करों, काम की खूब फिक्र करो, लेकिन काम कतई न करों, यह फंडा उनका हमेशा से रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य बहुत अच्छा, अब आप बैठ जायें।

श्री तेजेन्द्र निर्वाल-

मान्यवर, हमने जो काम किया है, वह समस्या को परमानेंटली हल करने के लिए किया है। अन्तिम योजना नदी जोड़ने की योजना है, जो किसानों के हक में देश में सबसे बड़ी योजना

हैं। जल जीवन मिशन में हर घर में टोटी से पानी मिले, इसके लिए हमने यह व्यवस्था की कि हर घर में टोटी से पानी मिले, जबकि वह लोग टोंटी उखाड़ कर ले जाते हैं। हम उसी टोटी को घर-घर मे लगा रहे हैं। मान्यवर आज तक जितने भी बजट प्रस्तुत हुए उनमें यह सबसे बेहतर बजट हैं। उसमें किसान का बच्चा भी अटल आवासीय विद्यायालय में पढ़ सकता है, उसमे मजदूर का बच्चा भी ट्यूशन ले सकता है, कोचिंग ले सकता है। आज तक इससे बेहतर बजट कभी पेश नहीं किया गया। मैं मा0 वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और माननीय योगी जी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की गरीब, कमजोर तथा असहाय जनता को ध्यान में रखकर इतना बेहतर बजट प्रस्तुत किया है कि इससे उत्तर प्रदेश के विकास की गति और तेजी से बढ़ेगी। इस बजट के समर्थन मे अपना पक्ष रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा में एंग्लो इंडियन परिवार से एक मा0 सदस्य मनोनीत होते हैं। क्या वह मा0 सदस्य यहां पर उपस्थित हैं ?

***डॉ0 डेनजिल जे0 गोडिन-**

मान्यवर, मैं उपस्थित हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या कहना चाहते थे ?

डॉ0 डेनजिल जे0 गोडिन-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्रीगण और .....

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम लोग तीन दिन से बैठे हैं। हमें भी बोलने का अवसर मिल जाये ताकि हम भी कुछ बात कर सकें। अगर इस समय को आप थोड़ा और बढ़ा दे तो बाकी लोगों को बोलने का अवसर मिल जायेगा। सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा नम्बर आयेगा लेकिन आज भी नहीं आया है, कल भी नहीं आया था और परसों भी नहीं आया था। इसलिये मेरा निवेदन है कि सदन का समय बढ़ा दिया जाये ताकि सबको अवसर मिल जाये। दो-दो, ढाई-ढाई मिनट आप हमको दे दीजिएगा, ज्यादा समय हमको नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अभी बोलने के लिए कल भी मौका मिलेगा।

***श्री सुनील कुमार शर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी तीन दिन से लगातार हम बैठे हैं।

(सदन में व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

मा0 अध्यक्ष जी, आप नियम-51 की सूचनायें ले लें उसके बाद जो भी मा0 सदस्य जितनी देर तक बोलना चाहते हैं, बोल लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव ठीक है, अगर आपकी अनुमती हो तो नियम-51 की सूचनायें पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम नियम-51 पढ़ दें।

(सदन में व्यवधान)

डॉ0 डेनजिल जे0 गोडिन-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष का कोई सदस्य या हमारे कोई साथी इस समय इस तरह की टिप्पणी करें तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि हम बोलना शुरू कर चुके हैं और अब आपसे निवेदन है कि आप हमको बोलने की अनुमति दें ताकि हम अपनी बात को सदन में रख सकें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बोल लीजिये।

डॉ0 डेनजिल जे0 गोडिन-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्रीगण एवं सदन के सम्मानित सदस्यों सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद करना चाहूँगा, कि आपने मुझे बोलने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार के पहले पेपरलेस बजट, जो कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी और वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, जब इरादे नेक हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, समाज सेवा का संकल्प हो, सकारात्मक परिवर्तन का विजन हो, दूर दृष्टि तथा काम करने करने की भावना हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। वर्तमान बजट इसी भावना तथा संकल्पना का परिचायक है और मैं इस सुन्दर बजट का समर्थन करते हुए अपने मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा पूरी बीजेपी सरकार एवं हमारे साथी जो विपक्ष के हैं, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक अच्छी सरकार को पहचाना हैं, उसको समर्थन दिया है और हम एक साथ ''सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'' और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्तरूप देने वाले हैं। मान्यवर, हमको इस बजट मे एक चीज बहुत अच्छी लगी जिसको किसी विधायक ने नहीं बोला हैं और वह हम कहंगे कि सतत विकास लक्ष्य के 17 मूल बिन्दू Sustainable development goals 2030 To change the world उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल देश मे ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण बनके दिखाया है। फिर चाहे गरीबी का खत्म करना हो, भुखमरी समाप्त करना हो, सबको जल, बिजली, स्वच्छता को सुनिश्चित करने के

लिए आधार पर शांतिपूर्ण और समावेशी समुदाय की ओर भ्रष्टाचार मुक्त समाज की ओर हर जगह विजन, ही विजन एक पारदर्शी प्रभावी और जवाबदेही प्रदेश, प्रशासन और सरकार समाज और राष्ट्र के हित में हो। अन्त में अपनी बात को समाप्त करने से पहले महोदय हम एंग्लो इंडियन या एंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि होते हुए आपको अवगत कराना चाहते है कि हमारा हर युद्ध भले वह पाकिस्तान के साथ रहा हो, चीन के साथ रहा हो हमारे समुदाय के सदस्य ने हमेशा एक अहम रोल निभाया है। हमारे डिफेन्स फोर्सेज में और इस समय जिस समुदाय से हम आते हैं जहां पे ''सर्विस बिफोर सेल्फ'' या सेवा परमोधरमा हम लोग सबको साथ ले करके चलते हैं। इस समय हम लोगों को वृद्धाश्रम की आवश्यकता है, इसलिए हम मा0 मुख्य मंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से कुछ मांग करते हैं। मान्यवर, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज और झासीं में दो बीघे जमीन की मांग हमने की है। एक कम्युनिटी हॉल, जहां पर शादी-ब्याह, महिलाओं और लड़क्यिों का स्किल डेवलपमेन्ट हो, वृद्धाश्रम आदि की मांग करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी 20 करोड़ की मांग भी हमने की है। हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे की आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021†

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 का पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[07:51] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपको अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 का पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आज अभी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ है कि दिनांक 04 मार्च 2021 को भी वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा जारी रखी जाये।

दिनांक 05 मार्च, 2021 से वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मदें ली जायें, शेष कार्यक्रम यथावत् रहेंगे।

---

† दिनांक 16-03-2021 के असाधारण गजट के परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा की समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51-के अन्तर्गत कुल 82 सूचनाएं प्राप्त हुईं। निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

पहली सूचना-श्री राम गोविन्द चौधरी की लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश में नियम विरुद्ध डिग्री धारी अवर अभियन्ताओं की पदोन्नती रोके जाने के सम्बन्ध में है, दूसरीं सूचना-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत नींबू पार्क से हैदरगंज चौराहे तक ओवर ब्रिज का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना-श्री अमिताभ बाजपेयी की कानपुर नगर निगम के धनकुट्टी अस्पताल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना-श्री नितिन अग्रवाल की जनपद हरदोई के निर्मित ट्रामा सेन्टर में चिकित्सकों की नियुक्ति एवं क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में है, पाँचवीं सूचना-श्रीमती नीलम करवरिया की जनपद चित्रकूट के नगर पंचायत राजापुर में की गयी भारी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना-श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के तिलहर मे पॉलीटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना-श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड भियांव में राजकीय इन्टर कॉलेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना-श्री शीतल पाण्डेय की पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत यशपाल होटल एवं रिसॉर्ट की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना-श्री असलम राईनी की जनपद श्रावस्ती में लोक निर्माण मे विभाग द्वारा बनवायी गयी गुणवत्ताहीन सड़क की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना-श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा मे कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना-श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद जौनपुर में अनाधिकृत अस्पतालों का संचालन रोके जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना-श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी के गौरीगंज में राजस्व विभाग द्वारा परिवारों को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना-श्री राम चन्द्र यादव की जनपद आयोध्या के रुदौली के प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र, रुदौली का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना-श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में राजकीय इन्जीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना-श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर मे जहरीली शराब के सेवन से मृतकों के परिवारीजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में हैं, सत्रहवीं सूचना-श्री लालजी वर्मा की मया-टाण्डा राजमार्ग पर बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा अट्ठारहवीं सूचना-श्री आशुतोष उपाध्याय की राजकीय मेडिकल कालेजों में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्राचार्यों के स्थान पर अनुभवहीन प्राचार्यों की नियुक्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे है।

निम्नलिखित सूचनायें ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत :-

पहली सूचना-श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के रेता उस पार के कतिपय ग्रामों को खड्डा तहसील में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना-श्री विनोद सरोज की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिटारा, बिहार, प्रतापगढ के निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त कर पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना-श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपूर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर मे लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना-श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी में वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर अण्डरपास बनाये जाने के सम्बन्ध मे है पाँचवी सूचना-श्री शशांक त्रिवेदी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महोली के स्वास्थ केन्द्र में एक्स-रे मशीन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना-श्री श्रीकांत कटियार की जनपद उन्नाव के बांगरमऊ में 100 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध मे है, सातवी सूचना-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद मे नगर पंचायत कंकोड का सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवी सूचना-श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा की तहसील अमरोहा में गलत विद्युत कनेक्शन एवं त्रुटिपूर्व बिल प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध मे है, नौवीं सूचना-श्री भुपेश चौबे की जनपद सोनभद्र स्थित ब्लाक चोपन अन्तर्गत ग्राम कोटा में नवनिर्मित राजकीय इन्टर कॉलेज में पठन-पाठन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना-प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा फर्जी वृद्धावस्था पेंशन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना-श्री शैलेन्द्र यादव ललई की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में बी0पी0डी0 मेमोरियल अस्पताल में फर्जी चिकित्सकों के कार्य किये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना-श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर की जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना-श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ के हापुड़ रोड पर ओडियन नाले की पुलिया का पुनर्निमाण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर खास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर भटनी को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे है, पन्द्रहवीं सूचना-श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के नगर पालिका रसड़ा में राजकीय महिला महाविद्यालय बनाए जाने के

सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना-श्री मौहम्मद फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी सहसपुर को नगर पंचायत बनाए जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना-श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव के फत्तेपुर चौरासी में भू-माफियाओं द्वारा कब्जित भवन को मुक्त कराए जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना-श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली के मुख्य मार्गों के किनारे हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना-श्री डॉ0 डी0 सी0 वर्मा की जनपद बरेली के मीरगंज में बिना नम्बर के ट्रक एवं ट्रालों को रोके जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना-श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के ऊँचाहार मे मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध मे हैं, इक्कीसवी सूचना-श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा में सड़क निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना-श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर मे हो रहे प्रदूषण की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना-श्रीमती बन्दना सिंह की प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में लम्बित पदोन्नति कराए जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना-श्री देवमणी द्विवेदी की जनपद आगरा के नगला पट्टे के नवीनीकरण मे हुई त्रुटि को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना-प्रो (डॉ0) श्याम बिहारी लाल जी की जनपद बरेली के फरीदपुर मे डामर रोड का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना-श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद प्रयागराज की तह0 हण्डिया मे आर0सी0सी0 सड़क को तोड़े जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना-श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में गन्दा एवं दूषित पानी किसानों की खेती मे डाले जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना-श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के तहसील किठौर मे जीर्ण-शीर्ण की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में है, उन्नतीसवीं सूचना-श्री अनिल कुमार दोहरे की जनपद कन्नौज के तिर्वा में पक्की नाली एवं सड़क का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है। तीसवीं सूचना-श्री सोबरन सिंह यादव की जनपद मैनपुरी मे करहल मे पक्का डामर रोड बनाए जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना-श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर में जर्जर सड़क का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है तथा बत्तीसवीं सूचना-डॉ0 मुकेश वर्मा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकाहाबाद में विमुक्त जातियों के जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचना अस्वीकार की गई :-

1	मेजर सुनील दत्त दिवेदी	22	श्री आशीष सिंह पटेल आशू
2	श्री बाबा गोरखनाथ	23	श्री दयाराम चौधरी
3	श्री संजय सिंह गंगवार	24	श्री बम्बा लाल
4	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	25	श्री शैलेश कुमार सिंह ''शैलू''
5	श्रीमती अनुपमा जायसवाल	26	श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया
6	श्रीमती माधुरी वर्मा	27	श्रीमती जय देवी

7	श्रीमती निर्मला संखवार	28	श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल
8	डॉ0 अनीता लोधी राजपूत	29	श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा
9	श्री राजकुमार अग्रवाल	30	श्री नरेश सैनी
10	श्री मूलचन्द्र सिंह	31	श्री मसूद अख्तर
11	श्री पूरन प्रकास एडवोकेट	32	श्री सोहिल अख्तर अंसारी
12	श्री प्रेम नारायण पाण्डेय		
13	श्री प्रभात कुमार वर्मा		
14	श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया		
15	श्री लकी यादव		
16	श्री दुर्गा प्रसाद यादव		
17	श्री अबरार अहमद		
18	श्री महेश कुमार गोयल		
19	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव		
20	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य''पप्पू भईया''		
21	श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव		

नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत डूडा मे व्याप्त अनियमितता की जांच कराए जाने के सम्बन्ध मे डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

यह वक्तव्य डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी का है। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों मे कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी उपस्थित हैं ?

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उपस्थित हूं। अभी वक्तव्य बंटा नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा अभी वक्तव्य बंटा नहीं हैं। वक्तव्य बांटने की जिम्मेदारी किसकी हैं ?

(सदस्यों को वक्तव्य की प्रतियाँ वितरित की गईं)

श्री अध्यक्ष-

श्री नरेन्द्र जी, क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश और देश में कोरोना का जो संकट काल रहा उस संकट काल में उत्तर प्रदेश के लाखों वित्तविहीन शिक्षक व वित्तविहीन विद्यालय के अन्य स्टाफ को किसी भी तरीके से कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाई। हमने आपके माध्यम से सरकार से यह अपेक्षा की है कि वर्ष 2016 में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में प्रदेश के वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने की जो शुरुआत हुई थी, वह मानदेय वर्ष 2017, 2018, 2019 एवं 2020 में नहीं मिला। यह तो खैर सरकार का निर्णय हैं और हम मांग करते हैं कि वित्तविहीन शिक्षकों एवं उनके अन्य स्टाफ को मानदेय वर्तमान सरकार भी दे, लेकिन कोरोना के संकट काल में जहां नौ महीने विद्यालय बंद रहे। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी देहात क्षेत्र से चुनाव लड़ कर आते हैं। कई शिक्षकों ने कोरोना काल में सब्जी बेची हैं क्योंकि उनका वेतन और मानदेय बहुत कम था और प्राइवेट स्कूल वाले अपने शिक्षकों और स्टाफ को वेतन नहीं दे पाए। शिक्षकों ने सब्जी बेची है और मजदूरी की हैं इसलिए आपके माध्यम से हमारा सरकार से आग्रह है कि वित्तविहीन शिक्षकों के लिए श्री अखिलेश यादव ने जो वर्ष 2016 में शुरुआत की थी, कम से कम यह सरकार शुरुआत तो करें। अगर सरकार नहीं दे रही है तो कोरोना के संकट काल में जो उन्होंने राशन और अन्य चीजे उधार लेकर अपना जीवन व्यतीत किया है उनके लिए हमे उम्मीद है कि आपके माध्यम से सरकार कोई मदद की घोषणा जरूर करेगी।

***माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती गुलाब देवी)-**

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि वित्तविहीन एवं वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा-7 क (क) के अन्तर्गत मान्यता दी जाती है। वित्तविहीन विद्यालयों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत परीक्षा संचालन के उद्देश्य से छात्रों के पंजीकरण एवं पठन-पाठन की मान्यता दी गई हैं। राज्य सरकार वित्तविहीन विद्यालयों के सम्बन्ध में नियामक के रूप में भूमिका का निर्वाहन करती हैं। वित्तविहीन विद्यालय के प्रबंधतंत्र द्वारा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन एवं अन्य मदों पर आने वाला व्यय भार अपने निजी स्रोतों से वहन किया जाता हैं। वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को शासनादेश संख्या-ई0एम0-1443/15-7-2001-1 (191)/2000, दिनांक 10-08-2001 द्वारा सेवा शर्तें निर्धारित हैं, माननीय अध्यक्ष जी, जिसके अनुसार वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की परिलब्धियों के भुगतान का दायित्व

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संस्था प्रबन्धतंत्र का है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अशासकीय माध्यमिक विद्याालयों में अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय दिये जाने हेतु बजट में रुपये 200.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था। उक्त प्राविधानिक धनराशि से वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकगण को विशेष प्रोत्साहन मानदेय दिए जाने हेतु शासनादेश संख्या-1157/15-8-2016-3023/2012, दिनांक 12-09-2016 द्वारा मात्र एक बार इस प्रतिबन्ध के अधीन व्यवस्था की गई कि वित्तविहीन विद्यालयों के अध्यापकों को प्रबन्धतंत्र द्वारा वेतन एवं परिलब्धियों का भुगतान किया जाता हैं, उसके अतिरिक्त ओवर एंड एबव विशेष प्रोत्साहन मानदेय का भुगतान शासनादेश में निर्धारित प्रकिया के अनुरूप किया जायेगा तथा इसे भविष्य के लिए दृष्टान्त नहीं माना जायेगा। वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को नियमित मानदेय दिये जाने की कोई नीति/व्यवस्था नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर 2016 में कोई वैश्विक महामारी नहीं थी और न ही कोई दैवीय आपदा थी। वैश्विक महामारी तो फरवरी, 2020 में आई। मैंने आपके माध्यम से बार-बार सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है कि उस महामारी में राज्य सरकार और भारत सरकार के अनुसार कई लोगो की मद्द की है। जब नौ महीने विद्यालय बंद रहे और विद्यालय के प्रबन्धकों ने शिक्षकों को एक रुपये की भी सहायता नहीं की। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जब 2016 में 200 करोड़ रुपये दिया गया तो उस समय न कोई दैवीय आपदा थी और न ही कोई कोरोना का संकट था। हमारा आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह है कि थोड़ा दिल बड़ा करिए और उन गरीब शिक्षकों के लिए आज सदन मे कोई घोषणा करिये वह आपको भी आशीर्वाद देंगे और पूरे सदन को आशीर्वाद देंगे। कुछ तो उनके लिए कर दीजिये।

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, यह सही है कि 2016 में कोई दैवीय आपदा नहीं थी। यह भी सही है कि कोई महामारी नहीं थी, लेकिन चुनाव था। मान्यवर, मा0 गुलाब देवी जी ने पूरी बात स्पष्ट कर दी है। आपका जो मूल सवाल था, उसके जवाब में कह दिया है कि निजी स्रोतों से व्ययभार वहन किया जायेगा। मान्यवर, उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण यह प्रश्न का जो आप कह रहे हैं, बार-बार उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। मान्यवर, जब उत्तर में साफ-साफ कहा गया है तो उस पर कोई औचित्य नहीं बनता है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, आपने कहा कि चुनाव था और चुनाव कल भी है तो चुनाव के दृष्टिगत कर दीजिए। अन्तिम बजट उस समय भी था और अन्तिम बजट यह भी है। चुनाव तब भी था और चुनाव आज भी है। कुछ तो दरियादिली दिखा दीजिये। खन्ना साहब आप पहले इतने कठोर नहीं थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब स्पष्ट जवाब आ गया है तो मैं समझता हूँ कि इस पर किसी और प्रश्न की अब आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत भोगनी सागर तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार कटियार द्वार नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य

***पर्यटन, संस्कृति एवं धर्माथ कार्य मंत्री (डॉ0 नीलकंठ तिवारी)-**

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठ जाइये इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[वक्तव्य पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया]

[उ0प्र0 पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है, अपितु पर्यटन विकास की दृष्टि से पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाए उपलब्ध कराने एवं सौन्दर्यीकरण हेतु आवश्यक निर्माण कार्य किराये जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद कानपुर देहात स्थित भोगनी सागर तालाब भोगनीपुर के पर्यटन विकास के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2018-19 में महानिदेशक पर्यटन के पत्र संख्या-4981/6-1-1 (988)/2018, दिनांक 02-11-2018 के माध्यम से प्रस्ताव/आगणन प्राप्त हुआ था, जिसके सम्बन्ध में यू0पी0पी0सी0एल0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए शासन के पत्र संख्या-3698/41-2018-119 (बजट)/2018, दिनांक 18-02-2019 द्वारा महानिदेशक, पर्यटन से 03 प्रतियों में चेक लिस्ट सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन से अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृति के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।]

***श्री विनोद कटियार-**

मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का तालाब है और लास्ट तीन साल से इस पर हम बार-बार माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अगर समय सीमा के अन्तर्गत इसका सुन्दरीकरण हो जाये तो बहुत कृपा होगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डॉ0 नीलकंठ तिवारी-

मान्यवर, प्रस्ताव के लिए निर्देशित कर दिया गया है। महानिदेशक पर्यटन से तीन प्रतियों में चेक लिस्ट सहित शासन से उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। यह जैसे ही आयेगा अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री विनोद कटियार-

मा0 अध्यक्ष जी तीन साल हो गए हैं।

श्री अमिताभ बाजपेयी-

मननीय अध्यक्ष जी, यह तालाब राष्ट्रीय समस्या बन चुका है इसका निस्तारण करा दीजिये।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में तमसा नदी के पुनरोद्धार हेतु लघु सेतु, पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निमार्ण मंत्री का वक्तव्य

***लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय)-**

मान्यवर, इसमें अवगत कराना है कि जनपद अयोध्या में विधान सभा रुदौली के अन्तर्गत तमसा नदी के जीर्णोद्धार का कार्य मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराया गया है। जीर्णोद्धार हो जाने के कारण नदी के संरेखण में पड़ने वाले मार्गों पर निर्मित ह्यूम पाइप के स्थान पर प्रस्तावित 07 लघु सेतुओं के निर्माण हेतु कुल रु0 677.80 लाख की लागत का आगणन शासन में प्राप्त है, जो परीक्षणाधीन है, जबकि 01-भवरिया नाला पर पटरंगा मंडी से पटरंगा गाँव सम्पर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त लुघु सेतु के स्थान पर आर0सी0सी0 बॉक्स सेल, लघु सेतु व पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 19-01-2021 द्वारा रु0 84.22 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्नगत 07 सेतुओं की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, तमसा नदी महत्वपूर्ण नदी है और इसके जीर्णोद्धार के बाद 06 ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग हैं जिनके पुराने पुलों के निर्माण पर चल रहा था, लेकिन जब से जीर्णोद्धार हुआ है और यह रामायण कालीन महत्वपूर्ण नदी है। इस पर मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि जो आगणन शासन में परीक्षणाधीन है उनको जल्दी करा दे जिससे उसका जल्दी से जल्दी निर्माण पूर्ण हो जाये क्योंकि नदी का पुनरोद्धार हो गया है नदी के खुद जाने के बाद कभी भी कोई भी दुर्घटना भी हो सकती है इसलिए उसका निर्माण अति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें ज्यादातर काम तो स्वीकृत हो चुके हैं।

श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

यह स्वीकृति के लिए शासन में प्रस्तुत है आशा है जल्दी हो जायेगा।

श्री राम चन्द्र यादव-

धन्यवाद।

प्रदेश में उचित दर की दुकानों में घटतौली रोके जाने हेतु ई-पास प्रक्रिया को अपनाये जाने के सम्बन्ध मे श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम.....

***श्री उमाशंकर सिंह-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य संलग्न है)

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[2013 मार्च, 2016 से प्रभावी है। भारतीय खाद्य निगम के डिपो से उचित दर विक्रेता तक सब्सिडाइज खाद्यान्न के उठान एवं वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसके अन्तर्गत त्रिस्तरीय सत्यापन की व्यवस्था प्रभावी है। गोदामों से उचित दर विक्रेताओं को शत-प्रतिशत तौलकर खाद्यान्न की निकासी द्वितीय स्टेज पर नामित कर्मचारी/अधिकारी की उपस्थिति में दी जाती है एवं उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्राप्त मात्रा एवं बोरे की सदिनांक प्राप्ति संबंधित गोदाम प्रभारी/डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदारों को दी जाती है। प्रदेश के सरकारी गोदामों/ब्लाक गोदामों मे इलेक्ट्रानिक कांटें स्थापित हैं। इस प्रकार सरकारी गोदामों/ब्लाक गोदामों से उचित दर की दुकानों को आंवटित किए जाने वाले अनाज पर घटतौली की सम्भावना नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि सप्लाई चेन मैंनेजमेन्ट के अन्तर्गत विभागीय पोर्टल पर प्रेषित/प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा की ऑनलाइन फीडिंग की जाती है, जिसे आम जनता द्वारा भी विभागीय पोर्टल पर देखा जा सकता है। इस प्रकार घटतौली रोकने के लिए, तौल करने वाले कांटों से तौल करने की प्रक्रिया को ''ई-पास मशीन'' से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नागरिकों के बीच में उनके जीवन स्तर को आच्छादित करने वाली योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के विषय में सदन के सामने निवेदन कर रहा हूं कि जब से मा0 योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो भोजन का अधिकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मैं समझता हूँ कि इतना अभूतपूर्व कार्य हुआ है जिसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती है। पहले ही चरण में 50 लाख फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करके पात्र लाभार्थी परिवारों को राशन कार्ड दिलवाये गये। कोरोना काल में हम सब लोगों ने देखा, अप्रैल से लेकर नवम्बर, 2020 तक लगातार 08 महीने, हर महीने की 15 तारीख को मुफ्त लाभार्थी परिवारों को राशन दिया गया। एक बार तो निःशुल्क दिया गया। डोर स्टेप डिलीवरी चालू की गयी। बीच में जो राशन लीकेज होता था, ई-पास के माध्यम से अंगूठे के निशान के माध्यम से लाभार्थी परिवारों को उनकी आइडेंटिटी सुनिश्चित करते हुए राशन दिया गया। मा0 अध्यक्ष जी, इन सारी क्रियाओं के बाद भी एक बिन्दु ऐसा है कि जब लाभार्थी राशन की दुकान पर जाता है और अपना अंगूठा लगाता है तो उसके बाद जो इलेक्ट्रानिक मशीन है कांटा, उस पर उसको जो तौल दी जाती है उस पर घटतौली की शिकायतें मैं समझता हूं कि सभी मा0 विधायकों की जानकारी में होगी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ई-पॉज की मशीन और इलेक्ट्रानिक वेइंग मशीन को आपस में जोड़ दिया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, इसको लखनऊ के सर्वर के साथ जोड़ दिया जाए। इससे यह होगा कि जो लाभार्थी आधार कार्ड के साथ अंगूठा लगायेगा वैसे ही उसके नाम की पहचान के साथ, जो उसको माल तौलकर मिलेगा वह विभाग के पोर्टल पर लाइव दिखेगा। इससे घटतौली की समस्या समाप्त हो जायेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि राशन डीलर की इलेक्ट्रानिक वेंइग मशीन को ई-पॉज मशीन से जोड़कर, उसको आनलाइन करके विभागीय पोर्टल के साथ जोड़ दिया जाए। जिससे लाभार्थी के अंगूठे के चिन्ह के साथ-साथ आधार कार्ड में उसके नाम के साथ-साथ वजन भी विभाग के पोर्टल पर दिख जाए कि लाभार्थी को इतने वजन का राशन मिला है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में काफी काम हुआ है और मा0 सदस्य ने जो अपेक्षा की है उस पर जरूर विचार कर लेंगे क्योंकि शासन की मंशा यह है कि जितना अनाज दिया जाए वह कन्ज्यूमर तक पहुँचे, उसी मात्रा मे पहुँचे। आपने जो सुझाव दिया है उस पर विचार कर लेंगे और मैं समझता हूं कि सुझाव उत्तम है।

जनपद शाहजहाँपुर में कब्जा हटाये जाने एवं कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

***अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (श्री रमाशंकर सिंह)-**

माननीय अध्यक्ष जी, अवगत कराना है कि सुशील कुमार पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर, नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राम किशोर, शिव कुमार पुत्र स्व0 कालीचरन आदि निवासी कस्बा .....

***श्री उमाशंकर सिंह-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ऊर्जा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[निगोही तहसील तिलहर शाहजहाँपुर एवं अन्य ग्रामीणों के गाटा सं0-291, 296, 297, 298 पर कब्जा बेदखल होने क बावजूद भी श्री सुशील कुमार पुत्र श्याम सुन्दर से मनोज कुमार पुत्र रोशन लाल वर्मा, सचिन कुमार वर्मा पुत्र रोशन लाल वर्मा, अखिलेश कुमार पुत्र राजवीर द्वारा अवैध रूप से बैनामा करा लिया गया और राजस्व विभाग से साठ-गांठ कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया। उक्त भाग पर करीब 46 वर्षों से विद्युत विभाग का कब्जा दखल है। निगोही विद्युत उपकेन्द्र की भूमि उत्तर-पश्चिम दिशा में 04 पोषक (एक गंगेपारा पोषक, दो निगोही पोषक, एक तालगांव पोषक) स्थापित है, जिसमें आवासीय कालोनी के पीछे से गंगेपारा पोषक की दो रेल पोल बाउन्ड्रीवाल से होकर क्षेत्र में निकली है जिसके प्रारम्भिक तीन पोल विद्युत उक्त गाटा की भूमि जो कि विद्युत विभाग के कब्जे में है, पर स्थापित है।

विद्युत उपकेन्द्र के उत्तर-पूर्व के कोने में निगोही-पुवायां मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित पर सीमांकित बाउन्ड्रीवाल पोल को तोड़कर लगभग 50-150 फीट चौड़ी पट्टी पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे भविष्य में विद्युत उपकेन्द्र के स्विच यार्ड पर लगे परिवर्तक की मरम्मत व प्रतिस्थापना में काफी कठिनाई होगी।

विद्युत उपकेन्द्र के पूर्व दिशा में निगोही-पुवायां रोड सीमांकित बाउन्ड्रीवाल सीमेन्टेड पोल की बनी है जो वर्तमान समय में जर्जर अवस्था में स्थापित है जिस पर रोड पट्टी से लगे हुए चार पोषक (एक पोषक ढकिया पोषक व एक विश्व बैंक पोषक एवं पोषक एस0पी0एन0 पोषक एवं एक जिन्दपुरा पोषक) बने हैं। चारों पोषक के प्रथम पोल विद्युत उपकेन्द्र की बाउन्ड्रीवाल पर स्थापित है, लेकिन जिन्दपुरा पोषक का द्वितीय पोषक का द्वितीय पोल पॉवर हाउस के मुख्य द्वार के पास भी लगा है। पॉवर हाउस के कई पोल स्थापित हैं, जिसके द्वारा क्षेत्र में पोषक बनाकर विद्युत सुचारु व निर्वाध रूप से शासन व प्रशासन की मंशानुरूप आपूर्ति की जाती है। विद्युत उपकेन्द्र के मुख्य द्वार के सामने बिलिंग सेन्टर स्थापित है जिसके दक्षिण साइट से होकर विभागीय कालोनी तक रास्ता जाता है जिसके उत्तर व दक्षिण दिशा में विद्युत विभाग की खाली भूमि पड़ी है जिसमें विद्युत पोल व परिवर्तक तार आदि अन्य विद्युत सामग्री को सुविधानुसार रखने हेतु विभाग द्वारा किया जाता है।

विद्युत उपकेन्द्र के चारों ओर सीमांकन के रूप मे सीमेन्टेड पोल स्थापित किये गये हैं जिस पर तार स्थापित थे जो वर्तमान समय में काफी जर्जर अवस्था में स्थापित है और राजस्व अभिलेख एवं विद्युत उपकरणों का अवलोकन करने से प्रतीत/ज्ञात हुआ कि उक्त विद्युत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपकेन्द्र लगभग 46 वर्ष पूर्व स्थापित है जिससे सिद्ध है कि विद्युत विभाग का उक्त भूमि पर वास्तविक रूप से अनवरत् कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर विद्युत विभाग के सीमांकित भूमि, जो उसके आस-पास खाली पड़ी है, पर किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं है। उक्त सभी भूमि विद्युत विभाग के कब्जे में है।

उक्त पॉवर हाउस की खाली पड़ी भूमि पर दिनांक 01-09-2019 को 40-50 लोग साजिशन इकट्ठा होकर मिट्टी डालकर बाहुबली, दबंग एवं राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लोगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था और जिसकी शिकायत की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01-09-2019 को थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर में दर्ज करायी गयी थी जिसमें कब्जाधारियों द्वारा सीमांकन पर लगे उत्तर-पश्चिम दिशा में विद्युत विभाग के सीमेन्टेड पोल को पूर्णतया क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।

उक्त बेनामे में क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व विभाग के कार्मिकों से साठ-गाठ करके अपने प्रभाव का प्रयोग कर बैनामा करा लिये गये हैं एवं राजस्व अभिलेखों में दाखिल खारिज भी करा लिया गया है क्योंकि वर्तमान मे क्षेत्रीय लेखपाल श्री अग्रसेन सिंह द्वारा गाटा सं0-298 कब्जा रकबा-0.1470 फसली वर्ष 1426 में कालम सं0-18 व 19 के नीचे अंकित किया है, कुछ जगह विद्युत विभाग को सरकारी कार्य हेतु जारी किये गये उक्त गाटे के खसरे में मात्र आबादी और बिजली घर अंकित किया है।

उक्त प्रकरण में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) लखनऊ से विधिक अभिमत प्राप्त किया गया, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :-

(क) भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण विधिवत आवेदन देकर प्रथम बन्दोबस्त, द्वितीय बन्दोबस्त, तृतीय बन्दोबस्त का करके यह सत्यापन करना चाहिये कि सन् 1359 फसली में अंकित खतौनी एवं खसरे का इन्द्राज सत्य है ? यदि सत्य है, तो उस दशा में 1359 फसली में अंकित काश्तकारों का अधिकार किस रूप में अंकित है, क्योंकि 1359 फसली से पूर्व भूमि का स्वामित्व तत्कालीन जमींदारों के पास था और आसामी/पट्टेदार के रूप में काश्तकारी करने का अधिकार विभिन्न श्रेणी के काश्तकारों को प्राप्त थे और 1359 फसली में ही उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के प्राविधान लागू होने एवं जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति पर काबिज काश्तकारों की तत्कालीन (यू0पी0 टेनेन्सी ऐक्ट) श्रेणी के अनुसार भूमि में अधिकार सिरदार एवं आसामी के रूप मे सृजित हुए थे, जो कालान्तर में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत असंक्रणीय भूमिधर एवं संक्रमणीय भूमिधर के रूप में नामित किये गये।

(ख) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा-144 यह प्राविधानित करती है कि यदि किसी भूमिधर की भूमि का प्रयोग कृषि, औद्योगिक एवं पशुपालन कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है तो उस अकृषक प्रयोग की दशा मे भूमि पर अध्यासित व्यक्ति के विरुद्ध धारा-209 के अन्तर्गत बेदखली का वाद योजित कर सकेगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति (उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद्/उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एक विधिक व्यक्ति है) द्वारा किसी भूमिधर की भूमि पर अनाधिकार अध्यासन कर लिया गया है तो उस दशा में भी

उक्त अधिनियम की धारा-209 के अन्तर्गत उक्त अनाधिकृत कब्जेदार के विरूद्ध बेदखली का वाद संबंधित भूमिधर योजित कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा-210 यह प्राविधानित करती है कि यदि किसी भूमिधर द्वारा बेदखली का वाद योजित करने के अपने अधिकारों का प्रयोग ससमय नहीं किया गया है, तो उस दशा में संबंधित भूमिधर के जो भी अधिकार उस भूमि पर होंगे, वह समाप्त हो जायेंगे और अनाधिकृत अध्यासी भूमिधर हो जायेगा। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत नियमावली के नियम-338 के अन्तर्गत निर्दिष्ट परिशिष्ट-3 के क्रमांक-30 पर उल्लिखित ऐसे वाद योजित करने की समय सीमा 03 वर्ष और अधिकतम 12 वर्ष है। चूँकि संबंधित भूमिधरों द्वारा उक्त आशय का कोई वाद विद्युत विभाग/कारपोरेशन के विरुद्ध निर्दिष्ट समयावधि में योजित नहीं किया गया है। ऐसी दशा में राजस्व अभिलेखों की अंकनाएं अर्थहीन है, अर्थात् उक्त में अंकित व्यक्तियों का कोई अधिकार भूमि पर अवशेष नहीं रह गया है। तद्नुसार यह विधिक अभिमत है कि राज्याधीन सेवाओं के लिए 46 वर्ष पूर्व स्थापित विद्युत उपकेन्द्र एवं निर्माण की भूमि वस्तुतः परिषद्/कारपोरेशन में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत निहित हो गयी है और उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता-2006 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त विधिक अधिकार के अनुरूप राजस्व अभिलेखों में परिषद्/कारपोरेशन का नाम अंकित किये जाने विषयक कार्यवाही सम्पादित की जानी चाहिए। यह भी विदित कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा सिविल अपील नं0 7764/2014 (रविन्दर कौर ग्रेवाल प्रति मंजीत कौर (प्रकाशित, 2019, एस0सी0सी0 आनलाइन एस0सी0, पृष्ठ 975) अपने निर्णय दिनांकित 07-08-2019 में यह विधिक सिद्वान्त स्थापित किया गया है कि यदि किसी वास्तविक भू-स्वामी की अनुमति के बगैर प्रतिकूल अध्यासन किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर कर लिया जाता है और वास्तविक भू-स्वामी द्वारा उक्त प्रतिकूल अध्यासन/कब्जे की तिथि से 12 वर्ष की अवधि व्यतीत होने तक अपनी भूमि पर कब्जा वापस प्राप्त करने का कोई वाद योजित नहीं किया जा सका है तो उस दशा में वास्तविक भू-स्वामी के भूमि में निहित समस्त स्वत्व एवं अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेंगे। मा0 उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ के उक्त बाध्यकारी न्याय निर्णय का भी संज्ञान लिया जाना जनहित में परम आवश्यक है।

विद्युत उपकेन्द्र के संबंध में दो विवाद जो एक मा0 सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन शाहजहाँपुर में मूल वाद सं0 344/2018 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, शाहजहाँपुर बनाम श्री सुशील कुमार पुत्र श्री श्याम सुन्दर न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद में अग्रिम तारीख 09-03-2021 नियत है, तथा दूसरा वाद मा0 ए0डी0जे0-10 शाहजहाँपुर के सिविल रिवीजन सं0 05/2020 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, शाहजहाँपुर बनाम सुशील कुमार आदि न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई दिनांक 05-03-2021 नियत है।

***श्री रोशन लाल वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि ऊर्जा विभाग की तरफ से चार पन्नों की सूचना आई है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को भी इससे पहले अवगत करा चुका हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन चार पन्नों की सूचना में एक भी शब्द सत्य नहीं है, सारे शब्द असत्य है। इसमें मेरी एक विनती है कि जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर राजस्व विभाग की रिपोर्ट और ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के लिए आप टाइम बाउण्ड करा दीजिए और आज इसे स्थगित कर दे। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट आई है जिसमें सारे तथ्य छिपाये गये हैं एक भी तथ्य सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी आप इसको टाइम बाउण्ड करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, फिर से जांच करा देंगे।

***वित्त, ससंदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, आपने स्वयं कह दिया कि इसको वापस लेते हैं, स्थगित करने की वार्ता करते हैं और दोबारा रिपोर्ट मंगवा लेंगे।

जनपद बदांयू में नगर पंचायत उसेहत की जर्जर सड़कों का निर्माण कराए जाने के संबंध मे श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निमार्ण मंत्री का वक्तव्य

वित्त, ससंदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, जनपद बदायूँ मैं नगर पंचायत उसेहत की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने.....

***श्री उमाशंकर सिंह-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[के संबंध मे स्थिति निम्नवत् है :-

1. **उसेहत नगर पंचायत ककराला चौराहे से कटरा बस स्टैण्ड तक**-विषयगत मार्ग का यह भाग दातागंज-उसेहत मार्ग के कि0मी0 30 में उसेहत नगर पंचायत का आबादी भाग है एवं इसी भाग में बस स्टैण्ड स्थित है, मार्ग के उक्त भाग (300 मी0) में कुछ पैच है, जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।
2. **कटरा चौराहे से अटेवा पक्के पुल तक**-विषयगत मार्ग का उक्त भाग सोत नदी पहुंच मार्ग का भाग है, जिसकी लेपित सतह गड्ढामुक्त है। पहुंच मार्ग की पटरी क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3. **ककराला चौराहे से कमलेनगला रोड तक**-विषयगत मार्ग का उक्त भाग उसेहत कमलेनगला आकारी घाट सथरा बरौलिया मार्ग के कि0मी0-01 का भाग है। मार्ग की लेपित सतह गड्ढामुक्त है, मार्ग की पटरी कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।]

प्रदेश में हो रहे अवैध खनन की जांच कराये जाने के सम्बंध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 क अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, कार्यालय अभिलेखानुसार श्री मनफूल सिंह के नाम से कार्यालय में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि.....

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[उनके पुत्र श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री मनफूल सिंह निवासी ग्राम मथुरापुर मोर, तहसील-नजीबाबाद, जिला-बिजनौर द्वारा दिनांक 11-02-2019 को नियम-52 के अन्तर्गत आवेदन किया गया था। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना हैं कि शिकायती-पत्र में उल्लिखित प्रार्थीगण नकुल अग्रवाल, ओम प्रकाश सिंह, करन सिंह द्वारा पूर्व में शासनादेश सं0 2883/86-2017-198/2011 टी0सी0-1 दिनांक 02-11-2017 तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 (यथासंशोधित) के नियम-52 'क' के अन्तर्गत कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरंग को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दी गयी व्यवस्था के क्रम में अपनी निजी भूमि पर एकत्रित उपखनिजों को हटाकर कृषि योग्य बनाने हेतु आवेदन क्रमशः दिनांक 11-02-2019, 21-11-2017, 13-11-2017 व 11-02-2019 को किया गया था जिसकी जांच उप वन संरक्षक बिजनौर वन प्रभाग व सम्बन्धित तहसील से कराये जाने हेतु पृथक-पृथक कार्यालय पत्र निर्गत किये गये थे। उक्त आवेदन पत्रों को जांच/परीक्षण में नियमानुसार पात्र न पाये जाने की स्थिति में तत्कालीन जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा अपने आदेश दिनांक क्रमशः 11-05-2019, 02-01-2018, 02-04-2018 व 11-05-2019 मे आवेदक के उक्त प्रार्थना पत्रो को निरस्त कर दिया गया। तदोपरान्त निर्गत शासनादेश सं0-1955/86-2019-57(सा0)/2017 दिनांक 20-08-2019, जिसके बिन्दु सं0 11 के अनुसार नियम-52(क) में कृषि भूमि पर खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु बालू/मौरंग के साथ बजरी/बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली जुली अवस्था में हो को जोड़ा गया है। खनन

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आशय पत्र स्वीकृत करने हेतु जांच विषयक बिन्दुओं में यह अपेक्षित है कि भूमि विगत पाँच वर्षों में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी, के आधार पर स्वामित्व की दोगुनी धनराशि अग्रिम रूप से जमा कराकर खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया जा सकता है। तत्क्रम में पत्र में उल्लिखित प्रार्थीगण श्री नकुल अग्रवाल व ओम प्रकाश सिंह द्वारा पुनः अपनी निजी भूमि में एकत्रित उप खनिजों को उठाकर कृषि योग्य बनाये जाने हेतु पृथक-पृथक आवेदन-पत्र दिनांक 05-10-2019 को कार्यालाय में प्रस्तुत किये गये है जिनकी जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी नजीबाबाद/नगीना एवं उप वन संरक्षक बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद से कराये जाने हेतु पृथक-पृथक कार्यालय पत्र प्रेषित किये गये। उक्त पत्रों के अनुपालन में प्राप्त आख्याओं का विवरण निम्नवत है।

1. श्री नकुल अग्रवाल पुत्र श्री विजय कुमार अग्रवाल, निवासी-सेवाराम, तहसील-नजीबाबाद जिला-बिजनौर के आवेदन-पत्र पर उपजिलाधिकारी नजीबाबाद एवं सहायक भू-वैज्ञानिक/खान अधिकारी बिजनौर द्वारा अपनी पृथक-पृथक जॉच आख्या दिंनाक 25-02-2020 में अवगत कराया गया है कि ग्राम बीरुवाला परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के खाता संख्या 171 गाटा सं0 193 रकबा 5.540 हे0 भूमि पर मौके पर नदी की धारा प्रवाहित होने के कारण शासनादेश दिनांक 20-08-2019 के क्रम में उपखनिजों को हटाये जाने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, के क्रम में तत्समय नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया था, जिसकी निस्तारण आख्या से आवेदक को कार्यालय पत्रांक 2041/खनिज अनुभाग-20 दिनांक 07-03-2020 द्वारा अवगत करा दिया गया था।
2. श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री होरी सिंह निवासी-मो0 अम्बेडकर नगर तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर के आवेदन-पत्र पर उपजिलाधिकारी नगीना व सहायक भू-वैज्ञानिक/खान अधिकारी बिजनौर द्वारा अपनी पृथक-पृथक आख्या दिनांक 18-12-2019 व 20-12-2019 में अवगत कराया गया है कि मौके पर ग्राम नसीरुद्दीनवाला, परगना बढापुर तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर के खाता खतौनी सं0-08 के गाटा सं0 21 रकबई 0.233 हे0 व 96 रकबई 0.623 हे0 भूमि पर बालू जमा है। उक्त आवेदित भूमि के समीप नदी प्रवाहित होने एवं कुछ भाग पर पानी भरा होने क कारण शासनादेश दिनांक 20-08-2019 के क्रम मे उक्त आवेदित क्षेत्र से उपखनिजों को हटाये जाने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, के क्रम में तत्समय नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया था, जिसकी निस्तारण आख्या से आवेदक को कार्यालय पत्रांक 1850/खनिज अनुभाग-20 दिनांक 29-01-2020 द्वारा अवगत करा दिया गया था।

   वर्तमान में शासनादेश दिनांक 20-08-2019 के क्रम में श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री मनफूल सिंह, निवासी ग्राम मथुरापुर मोर,तहसील-नजीबाबाद व श्री करन सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी-ग्राम मथुरापुर मोर, तहसील-नजीबाबाद, जिला बिजनौर द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इनके द्वारा पूर्व में शासनादेश दिनांक 02-11-2017 के क्रम में आवेदन किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत है-

1. श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री मनफूल सिंह निवासी-ग्राम मथुरापुर मोर, तहसील-नजीबाबाद, जिला बिजनौर के आवेदन पत्र दिनांक 11-02-2019 पर उपजिलाधिकारी नजीबाबाद व प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपनी पृथक-पृथक आख्या दिनांक 31-05-2019 व 03-05-2019 में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम मथुरापुर तहसील नजीबाबाद के गाटा सं0 98 रकबा 0.244 हे0 में से 0.112 हे0 भूमि मे कछियाना (तरकारी की फसल) खड़ी है। प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 03-05-2019 में अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र मे बालू/मोरम हटाकर भूमि कृषि योग्य बनाये जाने हेतु उपयुक्त नहीं है, के क्रम में तत्समय नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया था, जिसकी निस्तारण आख्या से आवेदक को कार्यालय पत्रांक 494/खनिज अनुभाग-19 दिनांक 16-05-2019 द्वारा अवगत करा दिया गया था।
2. श्री करन सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी-ग्राम मथुरापुर मोर, तहसील-नजीबाबाद, जिला बिजनौर के आवेदन-पत्र दिनांक 11-02-2019 पर उपजिलाधिकारी नजीबाबाद प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपनी पृथक-पृथक आख्या दिनांक 01-05-2019 व 03-05-2019 में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम मथुरापुर मोर, तहसील नजीबाबाद के गाटा सं0 98 मि0 रकबा 0.244 हे0 में से 0.228 हे0 भूमि पर गेहूँ की फसल खड़ी होने एवं अवशेष 0.016 हे0 भूमि पर खो नदी की धारा प्रवाहित होने के कारण शासनादेश दिनांक 02-11-2017 के अन्तर्गत अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, के क्रम में तत्समय नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया था, जिसकी निस्तारण आख्या में आवेदक को कार्यालय पत्रांक 496/खनिज अनुभाग 19 दिनांक 16-05-2019 द्वारा अवगत करा दिया गया था।

जनपद-बांदा-

शासन के शासनादेश सं0-2027/86-2019-57(सा0)/2017 दिनांक 30-08-2019 द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-52(क) के अन्तर्गत कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण एकत्रित बालू/मौरंग, बजरी, बोल्डर आदि को हटाये जाने हेतु तीन माह के लिये खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये है। जनपद बांदा के अन्तर्गत शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई-2020 के अन्तर्गत किसी किसान द्वारा बाढ़ के कारण एकत्रित बालू/मौरंग को हटाने हेतु कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया है। कालान्तर मे निदेशक भूतत्व एवं खनिक्रम निदेशालय, लखनऊ के पत्र सं0 634/एम-228/2017 (खनन नीति) (V) दिनांक 27-07-2020 द्वारा कृषि भूमि पर बाढ़ से एकत्रित बालू/मौरंग आदि को हटाये जाने हेतु आवेदन की ऑनलाइन प्रकिया विभागीय पोर्टल updgm.in पर online Application Mine Mitra पर प्राप्त कर निस्तारण करने के निर्देश दिये, जिसके क्रम मे अब तक 03 आवेदन पत्र प्रप्त हुए थे, जिसमें से दो प्रकरणों में

आवेदित क्षेत्र में फसल खड़ी होने एवं बालू/मौरंग उपलब्ध न होने के कारण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये गये हैं, शेष एक आवेदन-पत्र की जांच तहसील स्तर से करायी जा रही है, जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है और न ही अवैध खनन कराकर सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति पहुंचायी जा रही है।

जनपद-हमीरपुर-

जनपद हमीरपुर पठारी नदी बेतवा व यमुना से घिरा हुआ है। मानसून सत्र में उक्त नदियों का जल स्तर सामान्य रूप से बढ़ता है। ऐसी स्थिति में कृषि भूमि पर बालू/मौरंग का जमाव नहीं होता है। जनपद हमीरपुर की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-52(क) के अन्तर्गत बाढ़ के कारण जमा बालु/मौरंग को हटाने सम्बन्धी आवेदन पत्र नियमों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण कोई भी अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत नहीं किया जा सका। जनपद हमीरपुर मे वर्तमान समय मे 39 खनन पट्टे संचालित है, जिनसे बालु/मौरंग की पर्याप्त मात्रा मे आपूर्ति हो रही हे तथा रु0-13 से 20 प्रति घन फुट (रु0-450 से 700/-प्रति घन मी0) की दर से खदानों पर बालु/मौरंग का विक्रय हो रहा हैं।

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत सूचना मे उल्लिखित बिन्दु कि निदेशालय पर मुख्य खान अधिकारी श्री अनिल शर्मा द्वारा जनपद के खनन अधिकारियों से मिलकर अवैध वसूली कर खनन के पट्टे दिये जा रहे हैं, शासन की नीति का पालन न करने से रेत/मौरंग/बजरी आदि के कीमतें आसमान छू रही है, के सम्बन्ध में निदेशक भूतत्व एवं खनिक्रम द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन की पारदर्शी नीति एवं इज आफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत उपखनिजों के खनन परिहार स्वीकृत किये जाने हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से भारत सरकार की संस्था एम0एस0टी0सी0 द्वारा प्रक्रियात्मक कार्यवाही किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा लेटर ऑफ इन्टेन्ट तथा अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति होने पर खनन पट्टा विलेख का निस्पादन किया जाता है। खनिज से सम्बन्धित विभिन्न सेवाओं जिसमें आवेदन पत्र से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रिया सम्मिलित है, को आनलाईन किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिक्रम विभाग उ0प्र0 द्वारा UP Mine Mitra आनलाईन पोर्टल विकसित किया गया है। कृषि भूमि पर बाढ़ से एकत्र बालू/मौरंग आदि को हटाये जाने हेतु नियम-52क के अन्तर्गत आनलाईन आवेदन-पत्र विभागीय पोर्टल पर प्राप्त कर निस्तारण किये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। निदेशालय स्तर के किसी भी अधिकारी द्वारा खनन परिहार स्वीकृत किये जाने में हस्तक्षेप सम्भव नहीं है। उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि नियमावली, 1963 के अध्याय-4 एवं अध्याय-6 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति की सम्पूर्ण कार्यवाही पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। अतः प्रश्नगत शिकायती बिन्दु तथ्यहीन व आधारहीन है।

कृपया प्रश्नगत नियम-51 की सूचना के सन्दर्भ में उपरोक्तानुसार तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत हैं।]

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, एक लाइन कहना चाहते हैं कि चार पन्नों का जवाब आया है, लेकिन अधिकारियों ने सारी शिकायतों को तथ्यहीन एवं आधारहीन कह दिया है। मेरा निवेदन है कि अगर सम्भव हो तो इसकी थर्ड पार्टी से जांच करा ली जाये, स्पेसिफिक शिकायत होगी और मुख्य खनन अधिकारी से सम्पत्ति की जांच करा ली जाये जिससे पूरी बात साफ हो जायेगी। इस पर बहस तो होनी नहीं है क्योंकि यह केवल वक्तव्य है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड फतेहपुर के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद उन्नाव में विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी के अन्तर्गत.....

***श्री मनीष असीजा-**

मान्यवर इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता हैं।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[ग्राम सभा राजेपुर के मजरा तेजागंज से प्राइमरी पाठशाला मनिकापुर होते हुए उमरपुर तक प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 3.50 कि0मी0 है, जिसमें 0.800 कि0मी0 खडण्जा स्तर व शेष लम्बाई 2.70 कि0मी0 शून्य स्तर की है।

मजरा-तेजागंज बॉगरमऊ-बरूआघाट मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-9 से दायीं ओर निकलने वाले तेजागंज सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है, जिसकी लेपित लम्बाई 1.00 कि0मी0 है। उक्त मार्ग जिला पंचायत, उन्नाव द्वारा निर्मित है तथा यातायात हेतु सुगम है।

ग्राम-मनिकापुर (प्राइमरी पाठशाला) इसी मार्ग के कि0मी0-10 से दायीं ओर निकलने वाले मनिकापुर सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है, जिसकी लेपित लम्बाई 1.30 कि0मी0 है। उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जो यातायात हेतु सुगम है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम-उमरपुर (उमरपुर प्रीतम) जगतनगर-सहजनी सम्पर्क मार्ग (अन्य जिला श्रेणी का मार्ग) के कि0मी0-12 में स्थित है। उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जो यातायात हेतु सुगम हैं।

इस प्रकार उपरोक्त तीनों ग्राम पूर्व से ही लेपित सम्पर्क मार्ग से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में पूर्व से संतृप्त ग्रामों/मजरों को दोहरी कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जोड़े जाने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।]

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम्-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस संबंध में जिलाधिकारी पीलीभीत से प्राप्त आख्या के अनुसार निम्नवत् अवगत कराना है कि ग्राम खमरिया नवदिया की भूमि.....

***श्री मनीष असीजा-**

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[गाटा संख्या-522 रकबा 0.231 हे0-

वर्तमान खतौनी में श्रेणी-6(1) तालाब के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या पर जमुना प्रसाद पुत्र धनीराम, चन्द्रभान पुत्र लीलाधर, हरनन्दन प्रसाद पुत्र दुजाराम, हरिप्यारी देवी पत्नी नित्यानन्द, देवेन्द्र पाल पुत्र रामस्वरूप, प्रेमराज पुत्र रामस्वरूप, ओमकार पुत्र रामस्वरूप, पूजा देवी पत्नी वेदप्रकाश, लालाराम पुत्र आशाराम के आवासीय मकान बने हैं तथा रमाकान्त पुत्र ओमप्रकाश व ओमकार व रामचरन का बुनियाद भरा हुआ आवासीय प्लाट है। उक्त समस्त व्यक्तियों की भूमि पूर्व में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा दिनांक 05-06-1990 को 50 रु0 सालाना किराये पर बोर्ड प्रस्ताव संख्या-05 दिनांक 05-06-1990 को किराये पर दी गयी थी। उक्त भूमि नगर पालिका परिषद बीसलपुर की सीमा के अन्तर्गत है। उक्त अवैध कब्जेदारों की बेदखली हेतु नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी बीसलपुर के समक्ष पी0पी0ऐक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत वाद योजित किये जा चुके हैं, जो कि विचाराधीन है। शेष अवैध कब्जेदारों की बेदखली हेतु अभिलेख संकलित किया जा रहा है।

ग्राम खमरिया नवदिया की भूमि गाटा संख्या-523 रकबा 0.053 हे0-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त गाटा वर्तमान खतौनी में श्रेणी-5-3-ड़ बंजर के रूप में दर्ज है, जिस पर नन्हेलाल पुत्र छोटेलाल, हीरालाल पुत्र मिश्रीलाल, रामनिवास पुत्र मिश्रीलाल, श्रीपाल पुत्र रामपाल का आवासीय मकान बना हुआ है। उक्त भूमि नगर पालिका परिषद बीसलपुर की सीमा के अन्तर्गत है। उक्त अवैध कब्जेदारों की बेदखली हेतु नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी बीसलपुर के समक्ष पी0पी0ऐक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत वाद योजित किया जा चुका हैं, जो कि विचाराधीन है।

ग्राम खमरिया नवदिया की भूमि गाटा संख्या-524 मि0 रकबा 0.259 हे0 एवं 524 मि0 रकबा 0.235 हे0-

उक्त गाटा वर्तमान खतौनी 1427-1432 फसली के खाता संख्या-232 की गाटा संख्या-524 मि0 रकबा 0.259 हे0 राजेश कुमार व रत्नेश कुमार पुत्रगण तोलेराम निवासी बीसलपुर एवं खाता संख्या-105 की गाटा संख्या-524 मि0 रकबा 0.235 हे0 तोलेराम पुत्र रोशनलाल निवासी बीसलपुर के नाम बतौर श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। भूमि चकबंदी प्रक्रिया के बाहर थी, अर्थात सरकार (तालाब) की भूमि थी, जो जोत चकबंदी आकार पत्र-41 के अनुसार उक्त गाटा संख्या पुरानी गाटा संख्या-814 के 0.64 एकड़ भाग से निर्मित है। गाटा संख्या-524 मि0 रकबा 0.259 हे0 खतौनी सन् 1359 फसली में गाटा संख्या-814/2 रकबा 0.64 एकड़ डल्लू बेटा घस्सू निवासी बीसलपुर के नाम एवं खाता संख्या-105 की गाटा संख्या-524 मि0 रकबा 0.235 हे0 पुरानी गाटा संख्या-814 के 0.58 एकड़ भाग से निर्मित है। खतौनी सन् 1359 फसली में उक्त गाटा संख्या-814/1 रकबा 0.58 एकड़ रामस्वरूप बेटा परमाई निवासी बीसलपुर के नाम बतौर श्रेणी-(10) दर्ज कागजात है। इस प्रकार के भूमिधरों को दाखिलकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जोत चकबंदी आकार पत्र-2(क) के कॉलम नम्बर-26 में उक्त दोनों गाटा संख्या तालाब के रूप में दर्ज कागजात है।

न्यायालय परगनाधिकारी बीसलपुर के समक्ष योजित वाद रामस्वरूप बनाम गांव सभा आदि द्वारा योजित दो अलग-अलग वादों में दिनांक 03-01-1997 को वादी का दावा स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया कि 'भूमि गाटा संख्या-524 मि0 रकबा 0.259 हे0 व गाटा संख्या-524 मि0 रकबा 0.235 हे0 स्थित ग्राम खमरिया नवदिया, परगना व तहसील बीसलपुर पर श्रेणी-3 के स्थान पर वादी का नाम श्रेणी-1 में अंकित किया जाता है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त (प्रशासन) बरेली मण्डल, बरेली एवं मा0 राजस्व परिषद खण्ड पीठ-इलाहाबाद के समक्ष योजित निगरानी में निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी। उक्त आदेश के बाद भूमि गाटा संख्या-524 मि0 रकबा 0.259 हे0 पर अंकित खातेदारों द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 31-12-1998 से राजेश कुमार व रत्नेश कुमार पुत्रगण तोलेराम को विक्रय कर दी गई एवं गाटा संख्या-524 मि0 रकबा 0.235 हे0 तोलेराम पुत्र रोशनलाल को विक्रय कर दी गई, जो कालान्तर में अकृषिक घोषित कर दी गई। सिविल जज (सी0डि0), पीलीभीत के समक्ष मूल वाद तोलेराम आदि बनाम उ0प्र0 राज्य आदि में पारित निर्णय दिनांक 17-04-2019 को आदेश हुआ कि गाटा संख्या-524 रकबा 1.22 एकड़ स्थित ग्राम खमरिया नवदिया, परगना व तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत पर वादीगण के शान्तिपूर्ण अध्यासन व

उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। मौके पर उक्त गाटा संख्या-524 रकबा 1.22 एकड़ पर देव मैरिज लॉन, देवांश फिलिंग स्टेशन, तारा बैंकेट हाल संचालित है व कुछ भाग पर आबादी निर्मित है।

ग्राम खमरिया नवदिया की भूमि गाटा संख्या-525 रकबा 0.231 हे0-

वर्तमान खतौनी में श्रेणी-6(1) तालाब के रूप में दर्ज है। जिसके आंशिक भाग पर सुधा गुप्ता पत्नी प्रबोध कुमार गुप्ता का अस्थाई कब्जा व सुशीला देवी पत्नी बुद्धसेन निवासी ग्राम पकडिया मंगली का स्थाई कब्जा (पक्का निर्माण) है। सुधा गुप्ता की बेदखली हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत तहसीलदार बीसलपुर के समक्ष वाद विचाराधीन है तथा सुशीला देवी पत्नी बुद्धसेन की बेदखली हेतु अधिशासी अधिकारी बीसलपुर द्वारा अभिलेख संकलित किया जा रहा है।

ग्राम खमरिया नवदिया की भूमि गाटा संख्या-526 रकबा 0.125 हे0 एवं गाटा संख्या-527 रकबा 0.120 हे0-

वर्तमान में उक्त गाटा श्री बाला जी महाराज मढी सरबराकर छेदालाल, रामगोपाल श्रेणी-1(क) के नाम दर्ज कागजात है। मौके पर खाली पड़ा है, कोई अवैध कब्जा नहीं है।

ग्राम खमरिया नवदिया की भूमि गाटा संख्या-532 मि0 रकबा 0.806 हे0-

वर्तमान खतौनी में श्रेणी-6(1) तालाब के रूप में दर्ज कागजात है। जिसके आंशिक भाग पर महेशपाल पुत्र चुन्नीलाल, वेद प्रकाश पुत्र कालीचरन, ओमकार पुत्र शिवनन्द का आवासीय मकान निर्मित है जिनकी बेदखली हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत वाद न्यायालय तहसीलदार बीसलपुर के समक्ष विचाराधीन है। पूजा पत्नी वेदप्रकाश की मसाला चक्की निर्मित है, जिसकी बेदखली हेतु पी0पी0ऐक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत वाद न्यायालय उप जिलाधिकारी, बीसलपुर के समक्ष विचाराधीन है।

ग्राम खमरिया नवदिया की भूमि गाटा संख्या-532 मि0 रकबा 0.287 हे0-

वर्तमान खतौनी में श्रेणी-6(1) तालाब के रूप मे दर्ज कागजात है। उक्त भूमि पर राजेश्वरी देवी पत्नी दिनकिशोर, नन्ही देवी पत्नी राधेश्याम, नन्ही देवी पत्नी देवस्वरूप, अमित कुमार शर्मा पुत्र राकेश शर्मा, रामप्यारी पत्नी रामसहाय, मेवाराम पुत्र छेदालाल, रामादेवी पत्नी रामचन्द्र का आवासीय मकान निर्मित है तथा अन्य व्यक्तियों के बुनियाद भरे हुए आवासीय प्लाट हैं। उक्त अवैध कब्जेदारों की बेदखली हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत वाद न्यायालय तहसीलदार बीसलपुर के समक्ष वाद विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त सुधा गुप्ता पत्नी प्रबोध कुमार गुप्ता के द्वारा उक्त गाटे के आंशिक भाग पर वाउन्ड्रीवाल करके कब्जा किया गया है, जिसके सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) पीलीभीत के समक्ष मूल वाद संख्या-50/2019 सुधा गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 विचारधीन है। उक्त वाद में न्यायालय द्वारा वाद के अन्तिम निस्तारण तक दोनों पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के लिए आदेश पारित किया जा चुका है।

ग्राम खमरिया नवदिया की भूमि गाटा संख्या-532 मि0 रकबा 0.380 हे0-

वर्तमान खतौनी 1427-1432 फसली के खाता संख्या-105 की गाटा संख्या-532 मि0 रकबा 0.380 हे0 तोलेराम पुत्र रोशनलाल निवासी बीसलपुर के नाम बतौर क्षेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त गाटा संख्या जोत चकबंदी आकार पत्र-45 में रामस्वरूप पुत्र परमी निवासी बीसलपुर के नाम बतौर श्रेणी-3 आसामी दर्ज कागजात है। दर्ज खातेदारों को कोई भूमिधरी अधिकार नहीं दिया गया है। खतौनी सन् 1359 फसली में रामस्वरूप बेटा परमाई निवासी बीसलपुर के नाम बतौर श्रेणी-(10) दर्ज कागजात है। इस प्रकार के भूमिधरों को दाखिलकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जोत चकबंदी आकार पत्र-2(क) के कॉलम नम्बर-26 में उक्त गाटा संख्या-816/3 रकबा 0.94 एकड़ तालाब के रूप में दर्ज कागजात है। न्यायालय परगनाधिकारी बीसलपुर के समक्ष योजित वाद रामस्वरूप बनाम गांव सभा आदि द्वारा योजित वाद में दिनांक 03-01-1997 को वादी का दावा स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया कि भूमि गाटा संख्या-532 मि0 रकबा 0.380 हे0 श्रेणी-3 के स्थान पर वादी का नाम श्रेणी-1 में अंकित किया जाता है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त (प्रशासन) बरेली मण्डल, बरेली एवं मा0 राजस्व परिषद् खण्ड पीठ-इलाहाबाद के समक्ष योजित निगरानी में निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी। उक्त आदेश के बाद भूमि गाटा संख्या-532 मि0 रकबा 0.380 हे0 रामस्वरूप पुत्र परमी द्वारा तोलेराम पुत्र रोशनलाल को विक्रय कर दी गई, जो कालान्तर में अकृषिक घोषित कर दी गई।

श्रीमती शोभना आदि द्वारा न्यायालय सिविल जज (जूडि0) बीसलपुर, जिला पीलीभीत के समक्ष मूल वाद संख्या-16/2018 शोभना आदि बनाम नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में पारित आदेश दिनांक 03-04-2018 द्वारा उभय पक्ष गाटा संख्या 532 मि0 रकबा 0.380 हे0 पर निर्मित बारात घर के सम्बन्ध में अग्रिम नियत तिथि तक मौके पर यथा-स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। उक्त सिविल वाद अभी विचाराधीन है। मौके पर उक्त गाटा संख्या-532 मि0 रकबा 0.380 हे0 पर देव मैरिज लॉन व तारा बैंकेट हाल का पृष्ठ भाग निर्मित है।

ग्राम खमरिया नवदिया की भूमि गाटा संख्या-532 मि0 रकबा 0.033 हे0 जिल्द बन्दोवस्त में श्रेणी-1(क) रामेश्वर दयाल, भूपराम आदि के नाम दर्ज कागजात है। वर्तमान खतौनी में शोभना पुत्री राजेन्द्र पाल के नाम हैं तथा मौके पर देव मैरिज लॉन व तारा बैंकेट हाल बना है। गाटा संख्या-532 मि0 रकबा 0.024 हे0 जिल्द बन्दोवस्त में श्रेणी-1(क) दीन दयाल, प्रेमराज आदि के नाम दर्ज कागजात है। वर्तमान खतौनी में शोभना पुत्री राजेन्द्र पाल श्रेणी-1(क) दर्ज है तथा मौके पर देव मैरिज लॉन व तारा बैंकेट हाल बना है। गाटा संख्या-532 मि0 रकबा 0.024 हे0 जिल्द बन्दोवस्त में श्रेणी-1(क) नत्थू पुत्र चेता आदि के नाम दर्ज कागजात है। वर्तमान खतौनी में जसोदा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार के नाम श्रेणी-1(क) है तथा मौके पर देव मैरिज लॉन व तारा बैंकेट हाल बना है। गाटा संख्या-532 मि0 रकबा 0.024 जिल्द बन्दोवस्त में श्रेणी-1(क) रामेश्वर दयाल, भूपराम, रामप्रताप पुत्रगण हीरालाल के

नाम दर्ज कागजात है। वर्तमान खतौनी में शोभना पुत्री राजेन्द्र पाल श्रेणी-1(क) दर्ज है। तथा मौके पर देव मैरिज लॉन व तारा बैंकेट हाल बना है।

ग्राम खमरिया नवदिया की भूमि गाटा संख्या-559 मि0 रकबा 0.161 हे0-

वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1427-1432 फ0 की खाता संख्या-344 गाटा संख्या-559 रकबा 0.161 हे0 श्रीमती तारावती पुत्री झम्मनलाल निवासी दुगीपुर बडगवां के नाम बतौर श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। खतौनी सन् 1359 फसली में उक्त गाटा संख्या-829 रकबा 0.40 एकड़ रामचरन व पूसे पुत्रगण जीवन निवासी बीसलपुर के नाम बतौर श्रेणी-(10) दर्ज कागजात है। इस प्रकार के भूमिधरों को दाखिलकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जोत चकबंदी आकार पत्र-2(क) के कॉलम नम्बर-26 में उक्त गाटा संख्या-829 रकबा 0.40 एकड़ तालाब के रूप में दर्ज कागजात है। गाटा संख्या-559 रकबा 0.161 हे0 को श्रेणी-1 संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में अंकित करने हेतु न्यायालय परगनाधिकारी पूरनपुर, जिला पीलीभीत के समक्ष योजित वाद पूसे बनाम छविनाथ आदि में न्यायालय द्वारा वादी का दावा निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध पूसे द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त, न्यायिक (प्रथम) बरेली मण्डल, बरेली के समक्ष योजित अपील में वादी पक्ष में निर्णय हुआ। उक्त आदेश के बाद भूमि गाटा संख्या-559 रकबा 0.161 हे0 पर अंकित खातेदारों द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 26-02-1993 से तारावती पुत्री झम्मनलाल को विक्रय कर दी गई, जो कालान्तर में अकृषिक घोषित कर दी गई।

श्रीमती तारावती द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) पीलीभीत के समक्ष योजित वाद तारावती आदि बनाम हरीशचन्द्र में मा0 न्यायालय द्वारा गाटा संख्या 559 रकबा 0.161 हे0 में प्रतिवादी वादिनी के शान्तिपूर्ण अध्यासन व उपयोग में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने व उसमें बनी दीवारों को नुकसान पहुंचाने व जबरिया रास्ता निकालने से बाज रहे, का आदेश पारित किया गया। वर्तमान में उक्त गाटा संख्या का विक्रय अंकित खातेदारों द्वारा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में बैनामा के माध्यम से किया जा चुका है।

ग्राम ग्यासपुर की भूमि गाटा संख्या-390 मि0 रकबा 0.235 हे0-

वर्तमान खतौनी में श्रेणी-5(1) अन्य बंजर के रूप में उक्त गाटा सं0 दर्ज है। दिनांक 19-02-2009 को नगर पालिका परिषद् बीसलपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 मैमो 2008-09 के जरिये आराजी सं0 390 रकबा 0.235 हे0 को श्री शकील अहमद खां पुत्र श्री शफी अहमद खां व अकील अहमद खां पुत्र शफी अहमद खां व श्रीमती मलका बेगम पत्नी श्री अनीस अहमद खां निवासीगण मो0 हबीबुल्ला खां जनूवी बीसलपुर को 5000.00 प्रीमियम एवं 500 रु0 वार्षिक किराये पर दिये जाने का उल्लेख है। मौके पर शकील खां, अकील खां पुत्रगण शफी खां व श्रीमती मलका बेगम पत्नी अनीस अहमद खां का कार्यालय बना है। उक्त किरायेनामे की अवधि तय नहीं की गयी है। मौके पर ब0स0पा0 का कार्यालय एवं एक बरात घर बना दिया गया है जो कि किराये की भूमि पर विधिक रूप से नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट पीलीभीत में योजित वाद में मा0 न्यायालय ने

उभयपक्षों को वाद के अन्तिम निर्णय तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया है, जो कि वर्तमान में भी लागू है।]

छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय कानपुर में हुए घोटाले की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्ज्वल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-64 स्थगित है।

उत्तर प्रदेश में जिला अस्पतालों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई है.....

***श्री मनीष असीजा-**

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[उक्त सूचना के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 से आख्या दिनांक 02-03-2021 को प्राप्त हुई है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के किसी भी उपकेन्द्र पर चिकित्सा अधिकारी की तैनाती नहीं है। फार्मासिस्ट का मुख्य कार्य कम्पाउडिंग एवं डिस्पेंसिंग का है अतएव उपकेन्द्रों पर चिकित्साधिकारी की तैनाती न होने के कारण फार्मासिस्ट का पद सृजित किये जाने सम्बन्धित मांग औचित्यहीन है।

प्रश्नगत सूचना के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20558/2009 उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम संतोष कुमार मिश्रा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-08-2010 एवं अवमाननावाद संख्या-347/2010 हरित कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम प्रदीप कुमार शुक्ला व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27-11-2012, 15-04-2013, 29-04-2013 तथा अवमाननावाद संख्या-115/2015 इन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20558/2009 (विनय कुमार गिरि बनाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रवीण कुमार व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 23-09-2014 तथा रिट याचिका संख्या-1855/एस0एस0/2017 भूपेन्द्र सिंह व 06 अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में विज्ञापन दिनांक 12-11-2007 के सापेक्ष वर्ष 2002 बैच तक के फार्मेसी डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों की चयन/नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में फार्मासिस्ट के कुल स्वीकृत पद 6762 के सापेक्ष मात्र 12 पद रिक्त हैं। अतः प्रदेश के समस्त इकाईयों में स्वीकृत पदो के सापेक्ष फार्मासिस्ट कार्यरत हैं।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-66 स्थगित है।

[08:14] वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

बजट पर चर्चा जारी है।

श्रीमती मनीषा अनुरागी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। परम आदरणीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सूबे के यशस्वी वित्त मंत्री मा0 सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जो पेपरलेस बजट पेश किया गया है उसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री, आदरणीय वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूं। मान्यवर, कोई भी बजट सरकार की रूपरेखा और जनता के प्रति सोच एवं योजनाओं को प्रदर्शित करता है। हमारी सरकार का यह बजट श्रद्धेय पं0 दीनदयाल उपध्याय जी के अन्त्योदय की भावना से परिपूर्ण है, जो नये भारत के नये उत्तर प्रदेश की संकल्पना को आकार प्रदान कर रहा है। हम सभी ने वर्ष 2020 को देखा है और इस वर्ष 2020 हम सबके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। जहां विश्व के अनेक देशों ने कोविड-19 महामारी के सामने घुटने टेक दिये, देश के कई राज्यों में व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हो गयीं, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य में हम सभी ने कोविड काल के समय मा0 मुख्य मंत्री का प्रदेश की जनता के प्रति समर्पण को देखा। उस समय मा0 मुख्य मंत्री जी के पिता का शरीर शांत हो गया था लेकिन उन्होंने उस समय कहा कि मेरे लिए सर्वप्रथम प्रदेश की 24 करोड़ जनता है और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मान्यवर, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर यही हालात पिछली सरकारों में होते, तो वह सिर्फ परिवारवाद और भाई-भतीजावाद में ही उलझे होते। हमारी जो प्रदेश की जनता है वह हाहाकार कर रही होती। लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में किये गये कार्यों के प्रशंसा स्वयं डब्लू0एच0ओ0 के अध्यक्ष द्वारा की गयी है।

कोरोना काल में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों जैसे प्रदेश में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करना, संक्रमण से बचाव, प्रदेश के हर असहाय एवं गरीब को निःशुल्क भोजन, पानी की सुगम व्यवस्था, अन्य राज्यों के फंसे लोगों को सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाना आदि कार्यों की प्रशंसा सम्पूर्ण विश्व के लोगों द्वारा की जा रही है और आज हमारा प्रदेश मा0 मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को नई-नई योजनाओं के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। कोरोना के कारण राज्यों की अस्थिर अर्थव्यवस्था के समय में पेश किये गये अकल्पनीय, अविश्वसनीय बजट के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी के सम्मान में कुछ पंक्तियां पेश करना चाहती हूँ-

'मंसूबों और हौसलों का पावन सहयोग अनोखा है,
मोदी-योगी दो दीवाने, यह मिलन बड़ा ही चोखा है।
सूरज होगा अब मुट्ठी में, रोली में उसे मिला लेंगे,
भगवान राम के माथे पर, दिग्विजय का तिलक लगा देंगे।'

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

हम सभी की जो लम्बे अरसे से प्रतीक्षा थी, वह आज पूरी हो रही है। भगवान राम का भव्य मंदिर आज बनने जा रहा है। मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र से आती हूं, हमारा क्षेत्र काफी सम्भावनाओं का क्षेत्र है। लेकिन पूर्व की सरकारों में यह क्षेत्र उपेक्षित रहा, हमारे क्षेत्र की अधिकतर जनता कृषि से ही अपना जीवन यापन करती है, लेकिन सिंचाई हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रही है। सरकार ने उक्त बजट में केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये प्रस्तावित करके हमारे किसान बंधुवों को खुशहाल करने का काम किया है। हमारी सरकार बुंदेलखण्ड के हर घर के साथ खेत तक शुद्ध पानी पहुंचाने हेतु प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कार्यवाही भी हो रही है। बुंदेलखण्ड की एक मुख्य समस्या जो बहुत लम्बे समय से रही है, मजदूरों एवं बेरोजगारों का पलायन बराबर होता रहा, लेकिन जबसे हमारी सरकार बनी है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली सरकारों की नजर सिर्फ वहां की खनिज सम्पदा पर रही। मा0 मुख्य मंत्री जी ने बरसों से उपेक्षित रहे बुन्देलखण्ड को अब धरती का स्वर्ग बनाने का निर्णय लिया है। हमारा बुन्देलखण्ड धरती का स्वर्ग बनने जा रहा है। इसकी यह छाप बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के रूप में परिलक्षित हो रही है। आगामी समय में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के माध्यम से पलायन तो रूकेगा ही, किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य हमारी सरकार का है, वह भी पूरा होगा।

(इसी मध्य रात्रि 08 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

छोटे लघु उद्योग भी स्थापित होंगे। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य की तीव्रता को देखकर लगता है, मानो वीरों की यह तपस्थली सदियों के पिछड़ेपन से मुक्त होने के लिए अधीर है। एहसास होता है कि यह मशीनों का शोर नहीं, वरन् सदियों के बहुप्रतीक्षित विकास

की हुंकार रूपी साध है, जो एक राजयोगी की सरपरस्ती में आकार ले रही है। हैरत होती है कि प्रचुर खनिज सम्पदा, विपुल वन्य क्षेत्र एवं समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से पूरित यह शस्य श्यामला धरा कैसी अव्यवस्था, अराजकता और पिछड़ेपन का पर्याय बन कर रह गयी थी। हुकूमतें आयीं और चली गयीं, मुख्य मंत्री बने और बदल गए, लेकिन नहीं बदले तो बुन्देलखण्ड के हालात। रोजगार से राहगीर तक, कृषि से कमाई तक, आबरू से अवसर तक, सब कुछ असुरक्षित था। वजह सिर्फ राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी व विकासपरक् दृष्टि का अभाव। तभी तो वर्ष 2017 में नई हुकूमत के तख्तनशी होते ही उसी 'बंजर' बुन्देलखण्ड में विकास की कोपलें फूट पड़ती हैं। पलायन से पेयजल तक, स्वास्थ्य से स्वरोजगार तक, इन्फ्रास्ट्रक्चर से इण्डस्ट्री तक, अध्यात्म से आजीविका तक, सभी पहलुओं पर एक साथ कार्य प्रारम्भ हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के आस-पास बनने वाले डिफेंस कॉरीडोर से गाँव की गरीब जनता एवं बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती मनीषा अनुरागी-

माननीय अधिष्ठाता जी, बस 02 मिनट। बुन्देलखण्ड के किसानों की सबसे बड़ी समस्या जोकि अन्ना पशु हैं, उससे निजात दिलाने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण करवाया है। इसके साथ-साथ हर विधान सभा क्षेत्र में एक वृहद् पशु संवर्धन केन्द्र की स्थापना भी करायी है। माननीय अधिष्ठाता जी, हमारी सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तावित किय गया है, वह प्रदेश के हर वर्ग वंचितों, गरीबों, असहायों, महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों एवं छात्रों को ध्यान में रख कर बनाया गया है।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अपने क्षेत्र की कुछ माँगें आपके सामने रखना चाहूँगी। हमारे यहाँ एक स्वामी ब्रह्मानन्द जी हुआ करते थे, जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में वहाँ पर अलख जगाई, उनके नाम से वहाँ पर एक बाँध बना हुआ है। वहाँ से एक लिफ्ट कैनाल बना करके, क्योंकि वहाँ के 40 ऐसे गाँव हैं, जो असिंचित रहते हैं, अगर उससे एक लिफ्ट कैनाल बन जायेगी तो वहाँ के वह 40 गाँव सिंचित हो जायेंगे, वहाँ का किसान भी खुशहाल रहेगा। हमारे जनपद में एक तहसील सरीला है, उसमें एक ग्राम पंचायत है, जलालपुर, वहाँ पर करीब 100 से अधिक भगवान शिव के मन्दिर हैं, जिसको छोटा काशी भी हमारे यहाँ कहा जाता है। उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करके वहाँ पर अपार सम्भावनाएं बना सकते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे यहाँ 20 हजार से अधिक की आबादी का एक ग्राम पंचायत है मुस्करा, उसको नगर पंचायत कराने की माननीय अध्यक्ष जी कृपा करें। मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण विषय है। हमारे क्षेत्र में गन्ने की पैदावार होती है, वर्षों पुरानी वहाँ पर एक चीनी मिल हुआ करती थी, जो लम्बे अर्से से बन्द है, उस चीनी मिल को चालू कराने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्रीमती मनीषा अनुरागी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। लोकतंत्र के इस पावन मन्दिर में एक बार पुनः बजट चर्चा पर सुअवसर प्रदान करने के लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। इस अवसर पर मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। महोदय, आपके माध्यम से प्रदेश के विकास पुरुष एवं असंख्य किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं युवाओं की आकांक्षाओं के प्रतीक हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कई विकास के क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनाने का कार्य विगत 3 वर्षों में किया है और उनका यह भगीरथ प्रयास अनवरत् जारी है। मैं इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के विकासोन्मुख वित्त मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है जो देश का सबसे बड़ा बजट है और उत्तर प्रदेश में अभी तक इतना बड़ा बजट आज तक नहीं आया है, धन्यवाद देता हूँ। माननीय खन्ना जी ने जिस प्रकार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से पूरे हिन्दुस्तान में सभी विधान सभाओं को यह गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने मिसाल कायम की है, उसी तरीके से हिन्दुस्तान की सभी विधान सभाओं को भी पेपरलेस बजट प्रस्तुत करना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता जी, किसान व गाँव दोनों ही इस प्रदेश व देश की आभा हैं और इसलिए हर गाँव सड़क व हर खेत पानी का संकल्प निश्चित ही इस बजट के माध्यम से चरितार्थ हो सकेगा। हर गाँव सड़क का मतलब, हर गाँव विकास के रास्ते को खोलता है।

इस दिशा में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियोजन, कृषक दुर्घटना योजना जिसमें मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा इस बार जो व्यक्ति वाकई में काश्तकारी करता था, हम लोग बटाई पर अगर अपना खेत देते थे, मगर मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना बीमा उसको कभी नहीं मिलता था। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा इस चीज को एक गरीब के लिए इस योजना को जमीन पर, धरातल पर लागू किया गया, जिसमें वाकई में किसानों को या जो व्यक्ति मजदूरी करता है, उसके लिए भी मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा। मा0 अधिष्ठाता जी, इसी प्रकार से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र से गंगा एक्सप्रेस-वे निकलता है और यह गंगा एक्सप्रेस-वे निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में पुरजोर विकास करेगा क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र कटरा लगता है जिसमें तीन-तीन नदियाँ बहती हैं। वह क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। राम गंगा के तट से निकलता हुआ गंगा एक्सप्रेस-वे निश्चित रूप से लाभकारी होगा। इसके लिए हमारे क्षेत्र में जमीन की खरीददारी भी चालू हो गई है और हमारे क्षेत्र में पूरी तरीके से इस गंगा एक्सप्रेस-वे का पूरा लाभ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के

अन्तर्गत लगभग 06 पुलों का निर्माण कराया गया है। जबसे देश आजाद हुआ तबसे लेकर वहाँ कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं था। मा0 मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ। हमारे विधान सभा क्षेत्र में कोई राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं था, हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र को 02 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिले। हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था, मा0 मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से 02 राजकीय इंटर कॉलेज मिले। इसी प्रकार मैं मा0 विद्युत मंत्री जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन-तीन 33 के0वी0ए0 के उपकेन्द्रों का शिलान्यास किया और 01 करीब-करीब पूर्ण हो गया है। वे उपकेन्द्र जिनकी क्षमता कम थी, उनकी पूरी तरीके से क्षमतावृद्धि करके हमारे क्षेत्र को विद्युत का पूरा लाभ मिल रहा है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार में बहुत कम बिजली आती थी। रात में किसान इन्तजार करता था कि कब बिजली आएगी और कब वह गाँव में अपने खेत-खलिहानों में जाकर मोटर चलाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में इतना ज्यादा विकास मा0 केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया है कि लगभग 100 डामरीकरण के कार्य हमारे क्षेत्र में स्वीकृत किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से जो कुछ शेष रह गया है, बताना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बोजीघाट का पुल जिसकी अत्यन्त जरूरत है, उसका निर्माण कराया जाए। एक पच्चड़ घाट का पुल जो हमारे क्षेत्र में अत्यन्त आवश्यक है जो बरेली और जनपद शाहजहाँपुर को जोड़ता है और यहाँ पर मा0 श्याम बिहारी लाल जी बैठे हैं उनके क्षेत्र को भी जोड़ेगा। हमारे क्षेत्र में नगर पंचायत कटरा पड़ती है, इसको नगर पालिका का दर्जा दिया जाए। हमारे क्षेत्र में कोई भी अग्निशमन केन्द्र नहीं है, एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराई जाए। तिलहर से नेवादा मोड़ तक दोहरीकरण का कार्य जो लगभग स्वीकृत है लेकिन पता नहीं उसका शिलान्यास क्यों नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि उसका शिलान्यास कराया जाए ताकि वहाँ अच्छा विकास हो जाए। फतेहगंज पूर्वी से बदायूँ बॉर्डर तक का डामरीकरण जो बिल्कुल जर्जर हालत में है। इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया जाए। एक आई0टी0आई0 विद्यालय की स्थापना कराई जाए। हमारे क्षेत्र में एक उप मण्डी प्रस्तावित है, आशा करता हूँ कि अगर आप मेरी बात सही जगह तक पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से उक्त उप मण्डी भी बन सकती है। हमारे क्षेत्र में एक गाँव दहेलिया पड़ता है, देहेलिया गाँव में लगातार बाढ़ आती है। कई बार पशु हानि होती है, कई बार खेत कट जाते हैं, फसलें कट जाती हैं उसमें परियोजना शासन स्तर पर लम्बित है। अगर उसको दिखवा लिया जाए तो निश्चित रूप से काफी विकास होगा। हमारे यहाँ एक गांव परौर पड़ता है, परौर से लेकर जिला मुख्यालय तक लगभग 85 किलोमीटर पड़ता है। अगर परौर को विकास खण्ड का दर्जा दे दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में बहुत विकास होगा। मेरे पड़ोस में बैठे मा0 श्री मुकेश वर्मा जी विधायक शिकोहाबाद ने अभी बताया कि उनके सपने में महाराज निषाद राज गुह्य आए थे जो भगवान श्री राम जी के परम मित्र थे और भगवान श्री राम जी के प्रिय सखा थे, आज मैं इनके बगल में बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी मूर्ति की स्थापना भी अयोध्या में की

जाए तो निश्चित रूप से महाराज गुह्यराज निषाद जी का मान-सम्मान और भी ज्यादा बढ़ेगा। अधिष्ठाता जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिनेश चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट पर अपने विचार रखने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको बार-बार नमन करता हूँ। वर्ष 2021-22 का विधान सभा में पेश किया गया बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है जोकि 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 71 लाख रुपये का भारी बजट है। राष्ट्रनायक युग पुरुष माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत, सबका साथ सबका विकास की आस्थाओं को पूरी क्षमता से पूरा करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष मा0 श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के विकसित उत्तर प्रदेश, सक्षम उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की उम्मीदों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश के महान अर्थशास्त्री, विद्वान वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी ने जितना उच्च कोटि का बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मंत्रि मण्डल के समस्त सम्मानित सदस्य बन्धुओं, विधान सभा और विधान परिषद् के सम्मानित सदस्य बन्धुओं, सदन के समस्त अधिकारी और कर्मचारी बन्धुओं मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ, मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 मुख्य मंत्री महोदय और मा0 वित्त मंत्री महोदय को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जहाँ पिछली सरकारों ने पूर्वांचल की भरपूर उपेक्षा की थी, उसके साथ सौतेला व्यवहार किया था, पूर्वांचल के पिछड़ेपन के लिए विपक्ष की सरकार को शर्म आनी चाहिए वहीं इसके ठीक विपरीत इस बजट में पूर्वांचल के विकास के लिए भरपूर बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारा पूर्वांचल इस देश की आत्मा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे, अमेठी, बलरामपुर मेडिकल कालेज, पूर्वांचल विशेष योजना, वाराणसी, गोरखपुर मेट्रो, अयोध्या एयरपोर्ट, पयर्टन और विकास, प्रयागराज, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, हाईकोर्ट इलाहाबाद का व्यापक विकास, विन्ध्याचल और नैमिषारण्य तीर्थ स्थान के विकास के साथ-साथ अनेक लाभकारी योजनायें इस बजट में दी गयी हैं। मैं इस बजट के समर्थन में कहना चाहूँगा कि-

"निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे।
हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे।।"

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मुझे याद है कि बुन्देलखण्ड में पिछली सरकार में भीषण जल संकट और किसानों की भीषण उपेक्षा, किसानों द्वारा की गयी आत्महत्यायें तथा वहाँ की गरीबी और निर्धनता, विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी सौगात थी, और आज भी विपक्षियों को उनकी पीड़ा का अहसास नहीं हुआ। आज बुन्देलखण्ड की जनता, हमारे महान राजनेता, मुख्य मंत्री महोदय के बुन्देलखण्ड विकास की परियोजनाओं पर भूरि-भूरि प्रशंसा कर रही है। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध क्षेत्र के विकास के लिए भी कई लाभकारी योजनायें दी गयी हैं। इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ-

''रख हौसला वो मंजर भी आयेगा, प्यासे के पास चलकर समुन्दर भी आयेगा, थक कर न बैठ,
ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।''

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहली बार पेपरलेस बजट का मजाक उड़ाते हुए विपक्षी पार्टियां जो लेस शब्द का दुरुपयोग कर रही हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि यह लोग खुद ही बुद्धिलेस हैं, विकास लेस हैं। पिछले चुनाव में प्रदेश की जनता इसलिए इनके कुकर्मों को अच्छी तरह पहचान गयी थी। इन्हें वोटलेस करके पैदल कर दिया। तबसे सारे विपक्षियों की मति भ्रमित है। यह विश्वासलेस हो चुके हैं। वर्तमान सरकार की महान महत्वकांक्षी प्रगति इन्हें दिखायी नहीं दे रही है। सिर्फ सरकार की आलोचना करना इनका घृणित कर्म हो गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जनहित कार्य, समाज-सेवा और जनता के प्रति अपार स्नेह का चरित्र कोरोना काल में देखने को मिला। प्रदेश सरकार ने महामारी से मुक्ति के लिए जो महान प्रयास किया उसकी तारीफ पूरे देश ने ही नहीं अपितु पूरे विश्व ने की। डब्लू0एच0ओ0 ने तो पूरी दुनिया को सीख दी कि योगी आदित्यनाथ से महामारी के विरुद्ध लड़ना सीखें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विपक्ष के लोगों को जहां सरकार की तारीफ करनी चाहिए थी, वहीं दूसरी तरफ जमकर विरोध ही नहीं कर रहे बल्कि जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं। मैं विपक्ष को कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता सरकार की अच्छाइयों और आपके काले कारनामों को पहचान चुकी है। चुनाव नजदीक है, आपका काला चेहरा छद्म और फरेब को अगले चुनाव में इस प्रदेश की जनता आपके कारनामों पर आपको करारा जवाब देगी। आप विपक्ष की भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। बाबा तुलसीदास ने कहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री दिनेश चौधरी-

अधिष्ठाता महोदय, आज चौथा दिन है।

श्री अधिष्ठाता-

आप विषय पर आ जाइये, अपने क्षेत्र की समस्या बता दीजिए, वरना वह रह जाएगी और बाकी सब हो जायेगा।

श्री दिनेश चौधरी-

बाबा तुलसीदास ने कहा है **'उघरे अन्त न होइ निबाहू, कालनेमि जिमि रावण राहू'।** मैं उनको कहना चाहता हूँ कि-

'चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गयी होंगी,
यही इल्जाम है मुझपर चमन की बेवफाई का,
मगर फूलों को रौंदा और कलियां मसल डाली,
वही दावा किये हैं, इस चमन की रहनुमाई का'।

श्री अधिष्ठाता-

बस समाप्त कर दीजिए। जितने लोग यहां बैठे हैं, वह सब अपनी-अपनी बात कह लें। सबको अपनी बात को कह लेने दीजिए।

श्री दिनेश चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें रख रहा हूँ, अब मैंने बहुत शार्ट कर दिया है। मैं जहां से विधायक हूँ, उस जनपद का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र केराकत है। मेरी कुछ बहुत जरूरी आवश्यक क्षेत्रीय समस्याएँ हैं, जिसकी तरफ आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। युवा बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते एक आई0टी0आई0 का प्रशिक्षण केन्द्र। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। खेल-कूद के लिए एक स्टेडियम। केराकत विधान सभा क्षेत्र जिला मुख्यालय से करीब 35 किमी0 से शुरू होता है और 60-70 किमी0 है। जहां 3 बार्डर हैं-गाजीपुर बार्डर, आजमगढ़ बार्डर और बनारस बार्डर। वहां एक रोडवेज बस अड्डे की बहुत बड़ी आवश्यकता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि रोडवेज के लिए हमने उपयोगी जमीन भी ढूँढ ली है। लघु सिंचाई का करीब 30-35 साल पहले का डाक बंगला है, जो जर्जर हो चुका है। पेड़-पौधे हो गये हैं और लगभग वह ढाई बीघा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि उसको रोडवेज को दे दें। हमारे केराकत विधान सभा क्षेत्र में चन्दवक का बाजार है, जहां 25 हजार की जनसंख्या है, वहां एक नगर पंचायत की मांग हम आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रख रहा हूँ, हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये। श्री बैजनाथ रावत जी।

श्री दिनेश चौधरी-

मैं अन्त में एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास के लिए, जनता की सुरक्षा सेवा और ईमानदार शासन के लिए, युग पुरुष माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं उनके मंत्री मण्डल के सहयोगियों को, अन्तर्मन से कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश सतत् विकास के मार्ग पर पूरे देश का सर्वोच्च प्रदेश बने, इसकी कामना करता हूँ। सरकार की समस्त योजनाओं में अपनी तरफ से तन-मन-धन से सहयोग करने का वादा करता हूँ। वर्तमान बजट विकास के लिए सर्वोत्तम बजट है, निश्चित ही हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ सदन के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विनय कुमार द्विवेदी-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो साढ़े

5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को इस ऐतिहासिक बजट के लिए प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देना चाहता हूं। प्रदेश की जनता इस विशाल बजट से बहुत ही खुशहाल है। मान्यवर, वर्ष 2020-21 कोरोना महामारी की वजह से पूरे विश्व के लिए अत्यंत चुनौती भरा वर्ष था। हमारा प्रदेश अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है लेकिन जिस प्रकार महामारी के संकट से हमारे योगी जी ने प्रदेशवासियों को निकाला है उसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी, डब्लू0एच0ओ0 और समस्त देशवासियों ने की है। मान्यवर, यह बजट प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए है, समाज के सभी वर्गों के हित को देखते हुए यह बजट है। मान्यवर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सतत् विकास की ओर हमारे मुख्य मंत्री जी ने गरीबी, भुखमरी को खत्म करने के लिए जो कदम उठाया है, इसका लक्ष्य-2030 तक निर्धारित किया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, 2022 में आजादी का हम 75वां वर्ष मनायेंगे। मान्यवर, मैं गोण्डा जिले के मेहनौन विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। वहां पर मुझसे पहले 15 साल तक समाजवादी पार्टी की विधायक थीं। विपक्ष के साथी आरोप लगाते हैं कि 04 वर्षों में सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया जबकि सत्यता यह है कि पूर्वांचल की पूर्ववर्ती सरकारों ने उपेक्षा की, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। लेकिन मैं आदरणीय मुख्य मंत्री योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने गोण्डा, जो पिछड़े जनपदों में से एक था, का कायाकल्प किया। हमारे मेहनौन विधान सभा क्षेत्र में जहां सैकड़ों किलोमीटर के कच्चे रास्ते थे वहां माननीय उप मुख्य मंत्री केशव मौर्य जी द्वारा डामर सड़कों का निर्माण कराया गया है। ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी ने हमारे यहां सैकड़ों ऐसे गांवों के मजरे, पुरवे थे जहां पर विद्युतीकरण नहीं था, वहां पर विद्युतीकरण कराया। हमारे क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। 132 के0वी0ए0 के उपकेन्द्र बने, 33 के0वी0ए0 के 02 उपकेन्द्र बने, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। कल विपक्ष के वरिष्ठ साथी ने पाकिस्तान से हमारे इस बजट की तुलना की। हमारे ख्याल से हमारा जो बजट है वह पाकिस्तान के बजट से भी ज्यादा होगा। अगर पड़ोसी राष्ट्रों से तुलना करनी है तो चाईना से तुलना कीजिये। चाईना कैसे आगे गया ? मान्यवर, मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, जिन्हें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक सड़क है, इटियाथोक-बाबागंज मार्ग जो हमारे विधान सभा क्षेत्र की लाइफलाइन है। यह अन्य जिला मार्ग में से है और बहुत पहले यह सड़क बनी थी, इसकी लम्बाई 20 किमी0 है और वर्तमान समय में इस सड़क से अत्यधिक आवागमन है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाय। मान्यवर, गोण्डा-बलरामपुर मार्ग जिसका निर्माण हमारी ही सरकार में हुआ है, यह 42 किमी0 की सड़क है, यह पूरी सी0सी0 रोड बनी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री, माननीय उप मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है लेकिन इटियाथोक बाजार जो हमारे विधान सभा क्षेत्र की बाजार है, उस पर बिसुही नदी पर बहुत पुराना पुल बना हुआ है, जो बहुत जर्जर है, उस पर रोज घन्टों जाम लगता है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इस पुल का निर्माण कराया जाय और इसकी चौड़ाई

बढ़ायी जाए। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक स्टेडियम की आवश्यकता है वैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे जनपद को बहुत कुछ दे दिया है अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने विश्वविद्यालय देने की घोषणा की है और राजकीय खेल महाविद्यालय देने की घोषणा की है, उसकी जमीन भी ढूंढी जा रही है। हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐतिहासिक कार्य हुये हैं। अन्त में मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अविनाश त्रिवेदी जी नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री शीतला प्रसाद 'पप्पू पटेल'-

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री तथा सदन के अपने सभी माननीय सदस्यों को नमन करना चाहता हूँ जिनके समक्ष मुझे आज इस अभूतपूर्व बजट के विषय में अपनी बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विश्वव्यापी महामारी कोरोना से उबारते हुये ऐसे स्वर्णिम बजट को अपने आप में एक मिसाल कहा जाना अतिशयोक्ति न होगा। मान्यवर, 5.50 लाख करोड़ से अधिक के इस बजट में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर जोर देते हुये अन्नदाता किसानों को फ्री में पानी, सस्ता एग्रीकल्चर लोन, स्वच्छ पेयजल, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये मुफ्त कोचिंग, कोरोना वैक्सीन के लिये राहत, प्रदेश में एक्सप्रेस-वे और मेट्रो तथा रोडों का जाल बिछाने के साथ-साथ एयरपोर्टों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया गया है जोकि इस बजट के मुख्य स्वर्णिम बिन्दु हैं। जैसे कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते हुये अभिकथित किया है यू0पी0 सरकार का यह बजट युवाओं और रोजगार को समर्पित है मैं भी अपने भाषण की शुरुआत युवाओं को सबल बनाने की योजनाओं से करना चाहता हूँ। बजट में 1200 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य के युवाओं के लिए विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लिये आवंटित की गयी है। इस योजना द्वारा लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान, युवा के द्वारा रोजगार द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। इसके लिये प्रत्येक जिले में युवा हब स्थापित किये जायेंगे। इन हब्स को स्थापित करने के लिये 50 करोड़ रुपये बजट में प्रस्तावित किये गये हैं। इसके साथ ही जो युवा कुछ सलेक्टेड इन्डस्ट्रीज और स्वरोजगार के लिये ट्रेनिंग करेंगे, उनको राज्य सरकार द्वारा एक हजार रुपये प्रतिमाह और केन्द्र सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया जायेगा। इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गयी है जोकि युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने की ओर मजबूत कदम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके लिये मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से आभार एवं शुभकामनायें अर्पित करता हूँ। मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर जिक्र करें तो बजट में भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के नाम पर रखा जाना तय किया गया है, जो इस बजट को अत्यंत ही शानदार तथा विकास की राह में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर बनाता है। बजट में महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा के लिए किये गये प्रावधानों की बात करें तो बजट में महिलाओं की सुरक्षा के प्रावधानों को भी प्रमुखता से पिरोया गया है। इनके मुख्य बिन्दुओं का

उल्लेख करें तो रात के समय ऑफिस से लौटने वाली महिलाओं के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस द्वारा महिलाओं को सुरक्षित घर पहुँचाने की योजना का शुभारम्भ किया गया है। जिसका लाभ डायल 112 के माध्यम से लिया जा सकता है। इसके अलावा अन्य ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, कृषि, चिकित्सा, सुरक्षा, मूलभूत आवश्यकतायें आदि आते हैं, जिनके लिए इस स्वर्णिम बजट में अभूतपूर्व प्रावधान किए गए हैं। सारांशतः कह सकते हैं कि यह बजट जनता के पूर्ण हित में है व समाज के हर क्षेत्र व हर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करता है। जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र सिराथू, जिला कौशाम्बी के विकास खण्ड कड़ा में माँ शीतला का मन्दिर है, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि विन्ध्याचल की तर्ज पर उसका भी जीर्णोद्धार कराया जाये, उसको भी कहीं न कहीं से बजट में ले करके पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार कराया जाये। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र सिराथू कड़ा में एक संत मलूक आश्रम है, जिनकी कहावत मशहूर है-'अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गये, सबके दाता राम।' उनका एक समाधि स्थल है, उसको भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसका भी जीर्णोद्धारा कराया जाये। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में दारानगर कड़ाधाम के नाम से एक नई नगर पंचायत सृजित हुई है, जिसके कार्यालय के लिए और जरूरत के सभी सामानों के लिए मैं नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके लिए धन अवमुक्त करके उसको पूर्ण रूप से संचालित कराने का काम किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त कर दीजिए।

श्री शीतला प्रसाद 'पप्पू पटेल'-

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक फूड पार्क की स्थापना कराने की कृपा किया जाये, जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में 51 शक्तिपीठों में से एक माँ कड़ावासिनी का मंदिर है, जो एन0एच0-2 से लगभग 7 से 8 कि0मी0 पर पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री शीतला प्रसाद 'पप्पू पटेल'-

मान्यवर, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वहाँ दोनों तरफ लाइट के खम्भे गड़ जायें और स्ट्रीट लाइट लग जाये ताकि वहाँ तक लोगों को आने-जाने के लिए पूर्ण रूप से रोशनी की व्यवस्था हो जाये।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सभी बातें आ गई हैं, समाप्त करिए।

श्री शीतला प्रसाद 'पप्पू पटेल'-

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र सिराथू में एन0एच0-2 सैनी में बस अड्डा है जो चौड़ीकरण के कारण टूट गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसका पूर्ण रूप से फिर से जीर्णोद्धार करा करके नये रूप में किया जाय। मेरी विधान सभा क्षेत्र में अजुहा में कोई बस अड्डा नहीं है। वहाँ नगर पंचायत की जमीन है, वहाँ एक नया बस स्टॉप बनवाया जाये। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में सिराथू विकास खण्ड में माँ गंगा के तट पर स्थित संदीपन घाट है, जो हमारी विधान सभा क्षेत्र सिराथू एवं चायल विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है, जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा पाई थी। मान्यवर, भगवान श्रीकृष्ण ने वहीं शिक्षा पाई थी, लेकिन आज पूर्ण रूप से वह वीरान जैसा पड़ा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा जी बोलें।

श्री शीतला प्रसाद 'पप्पू पटेल'-

मैं सदन के माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसका पूर्ण रूप से विकास कराकर जीर्णोद्धार कराया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

बैठ जाइये, समाप्त करिये। अब आपका नहीं लिखा जायेगा। अभी बहुत लोग हैं और समय कम है। बैठ जाइये।

श्री शीतला प्रसाद 'पप्पू पटेल'-

मान्यवर, हमारे वहाँ एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाये। मान्यवर, आज आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा-**

माँ बराही देवी की जय, बाला जी महाराज की जय। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का शुभ अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट निश्चित तौर पर प्रदेश के किसान, गांव गरीब, मजदूर, युवा, मातृशक्ति को समृद्धशाली बनाते हुए आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा ऐतिहासिक कदम साबित होगा। युवाओं को टैबलेट प्रदान किये जाने का निर्णय डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को उभारने में सुअवसर प्रदान करेगा। सरकार द्वारा प्रत्येक मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना गुणवत्तापरक् शिक्षा व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा। ओपेन जिम, स्टेडियम की स्थापना खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणादायक होने के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

साथ युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहायक होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने चाहे राम जन्म भूमि में पर्यटन की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया लेकिन हमारे यहाँ भी पर्यटन की दृष्टि से माँ बराही देवी धाम में 44 लाख एक बार, 50 लाख रुपया एक बार देने का काम किया। वहाँ पर दादूपुर का स्टेशन है, हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, माननीय मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री केशव मौर्या जी ने दादूपुर स्टेशन का नाम बदल कर माँ बराही धाम कर दिया, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इससे वहाँ और भी जनता आयेगी। मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के इतने वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में सड़कों की दशा बहुत दयनीय थी लेकिन जबसे माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी, हमारे उप मुख्य मंत्री केशव मौर्या जी के आशीर्वाद से आज रानीगंज में बहुत सी सड़कें लगभग 90 नई सड़कें बनीं, मैं इसके लिए उप मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हुँ 10 नये पुल, 11 छोटी पुलिया का निर्माण माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने कराया, मैं उनको बधाई देता हूँ। जयगोर से जगनीपुर 27 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण का काम कराया, चिटपुट्टी-शेखूपुर 7 किलोमीटर सड़क देने का काम किया, खतरपुर से वीरापुर 12 किलोमीटर के चौड़ीकरण का काम कराया, इसके लिए मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से हमारे दो टाउन एरिया बने, एक पृथ्वीगंज और एक सवंशा, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय नगर विकास मंत्री जी को बधाई देता हूँ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले की सरकारों में अपराध प्रतापगढ़ में बहुत होते थे, डेली किसी न किसी अधिवक्ता को मार दिया जाता था, एक अधिवक्ता को उसी कोतवाली में मार दिया गया तहसील के अन्दर और मारकर चला गया। जब हमारी सरकार बनी तो थाने का निर्माण कर रही है, चौकी का निर्माण हमारे क्षेत्र में तेल्हूपुर में किया जा रहा है इसके साथ ही दिलीपपुर का थाना हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ। हम आपसे कहना चाहते हैं कि तीन-तीन कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे हमारे प्रतापगढ़ क्षेत्र से लेकिन वहाँ पर वह विकास नहीं हुआ लेकिन आज हमारे प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज देने का काम किया गया और वह बन करके तैयार हो रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज एक भी नहीं था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा करके इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया, पॉलीटेक्निक देने का काम किया, आई0टी0आई0 देने का काम किया। एक मिनी स्टेडियम नजियापुर में बन करके तैयार हो रहा है, हमारे युवा वहाँ खेलेंगे, इसको भी देने का काम हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि 50 बेड का ट्रामा सेंटर बन रहा है, एक 50 बेड का महिला अस्पताल भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा में देने का काम किया, यह प्रतापगढ़ के लिए उपलब्धि है। विद्युत व्यवस्था के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिजली के लिए 132 के0वी0ए0 का स्टेशन खतरपुर में बनकर तैयार हो गया है, 33/11 पूरेहिलावन में और जितने हमारे सब-स्टेशन है चाहे खातापुर हो, चाहे पांड़ेतारा हो, चाहे बेलूपुर हो, चाहे गौरा हो, चाहे रानीगंज हो, चाहे दिलीपपुर हो, सभी का 5 एमवी से 10 एमवी का ट्रांसफार्मर हो गया है, अब वहाँ बिजली जल्दी नहीं जाती है जबकि पहले ट्रांसफार्मर फुंक जाता था, इस सुविधा के लिए मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारे यहाँ शहीद स्थली है कहला और नमकसार, कितने मंत्री आये और चले गये लेकिन

वहाँ का विकास नहीं हुआ। किसान आन्दोलन होता था और वहाँ पर हमारे किसान शहीद हुए थे, वहाँ का भी विकास हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 25 वर्षों में जिन नहरों की सफाई नहीं होती थी, नालों की सफाई नहीं होती थी लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री और जल मंत्री के सहयोग से चाहे उमरडोल हो, चाहे कहला हो, चाहे नमकसार हो, सभी नहरों की सफाई हो गई, वहां पहले सिंचाई नहीं हो पाती थी। वहाँ पर किसानों की सौ बीघे की सिंचाई होने लगी, इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त कर दीजिये।

श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा-

महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये यदुवंशी बनते हैं। अब तो कुर्सी इनके पास है, ये भग गये हैं। यादव की भी सड़क इन्होंने नहीं बनवाया। हम लोगों ने तीन-तीन सड़क बनवाने का कार्य किया है और रनजीत यादव, जो सी0आर0पी0एफ0 में शहीद हुए थे, उनको भी गेट देने का काम इन लोगों ने नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, बैठ जाइये। सहयोग कीजिये। बोलने के लिए और लोग भी हैं।

श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा-

महोदय, हर जगह पंचायत भवन बन रहे हैं, सामुदायिक शौचालय हर गाँव में बन रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ माँगें हैं। हमारे यहाँ आँवला बहुत होता है। वहाँ का आँवला पूरे देश में प्रसिद्ध है। महोदय, मैं आपके साथ-साथ पूरे सदन के मा0 सदस्यों को वहाँ का मुरब्बा खिलाऊँगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जैसे केला पर सब्सिडी है, उसी तरह से हमारे आँवला किसान भाइयों को भी सौ प्रतिशत सब्सिडी दें, तो हमारे प्रतापगढ़ का किसान और समृद्ध होगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये।

श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा-

महोदय, खरवई में एक पंक्षी विहार है, जहाँ पर 56 एकड़ का तालाब है। उस पंक्षी विहार को नमामि गंगे में प्रस्तावित करा दें। हमारा नवरेड़ा राजकीय इण्टर कॉलेज और रानीगंज, गोपालपुर में एक हाई स्कूल है, इसको आप ठीक करा दें। सई और बकुलाही नदी को साफ करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप बैठ जाइये।

श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात और कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे यहाँ पूर्व की सरकारों में कानून-व्यवस्था ध्वस्त थी। सी0ओ0 मारे जाते थे, कोतवाल मारे जाते थे। सपा के गुण्डे चले गये हैं, नहीं तो मैं उन्हें बताता।

श्री अधिष्ठाता-

श्री नंद किशोर गुर्जर जी।

श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा-

महोदय, इनके राज में प्रतापगढ़ में सी0ओ0 कोतवाल भी नहीं बचता था। आज मा0 योगी जी की सरकार में गुण्डा राज का खात्मा है। आज सबका साथ, सबका विकास है। मैं दो लाइनें विपक्ष वालों के लिए कहना चाहता हूँ, जो किसान भाइयों के नाम पर अपनी रोटी सेंकते हैं। मैं दो शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम दूँगा।

औरों के खयालात की लेते हैं तलाशी।
अपने गिरेबान में झाँका नहीं जाता।।
पसीने की स्याही से लिखते हैं जो इरादों को।
उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते।।
उन्हें गुमान है कि हमारी उड़ान कम है।
और हमें यकीन है, ये आसमान कम है।।
कभी जिया करो किसानों की जिन्दगी।
लोग महलों में रहकर भी खुद को परेशान कहते हैं।।
समझ जाओगे किसानों का दर्द।
एक बार खेतों में हल चलाकर तो देखो।।
किसी जमीन के टुकड़े में कभी अनाज उगाकर तो देखो।
कभी जून की धूप में, तो कभी दिसम्बर की जाड़ में।।
एक बार खेतों में जाकर तो देखो।।
"बराही देवी" की जय, "बाला जी" महराज की जय।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये। मा0 नन्द किशोर गुर्जर जी।

श्री नन्द किशोर गुर्जर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2021-22 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी सरकार द्वारा बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा तथा कानून-व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र लोनी दिल्ली का बॉर्डर है और बहुत ज्यादा पिछड़ी विधान सभा क्षेत्र थी। वहाँ पर

तीन-तीन फिट के गड्ढे थे। हमारे विधान सभा क्षेत्र की 18 लाख की आबादी होने के बावजूद न कोई हास्पिटल था, न कॉलेज था और हालात बिल्कुल खराब थे। अगर कोई घटना घटित हो जाए, तो अधिकारियों को दिल्ली होकर आना पड़ता था। सरकार बनने के बाद कॉलेज, आई0टी0आई0, इण्टर कॉलेज और सड़कों के साथ तमाम अभूतपूर्व विकास हुए। कानून-व्यवस्था इतनी ध्वस्त थी कि बॉलीवुड में लोनी को लेकर जिला गाजियाबाद में मूवी बनी। ढाई सौ से तीन सौ मर्डर गैंगवार में हुए। व्यापारियों के रोजाना मर्डर होते थे। समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने एक व्यापारी की 12 साल की बच्ची को उठाकर गैंगरेप किया। इस तरह के हालात थे कि लोनी से व्यापारी पलायन कर रहा था, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद वहाँ अपराधियों पर कार्यवाही हुई। बजट के साथ मेरे यहाँ जो-जो विकास हुआ है, उसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री और मा0 वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और मैं यह माँग करता हूँ कि मेरी जो विधान सभा क्षेत्र है, उसके अंदर लोनी में हमारे यहाँ दो स्कूल बने हैं। उन स्कूलों में पद सृजन करके उसमें स्टाफ दिया जाये, जिससे उसको शुरू कराया जा सके। आई0टी0आई0 बनकर तैयार है, उसमें भी पद सृजन किया जाए, जिससे उसको भी चालू कराया जा सके। हमारे यहाँ पर एक स्टेडियम प्रस्तावित है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक गाँव भड़ेरा खुर्द पड़ता है, उसके लिए फण्ड रिलीज करा दिये जाएं। मैट्रो का विस्तार मण्डोला तक कराया जाय। बेहटा नहर, लोनी के अंदर जैसे ही आप दिल्ली से इण्ट्री करते हैं तो यह नहर नाले में तब्दील हो गयी है और बदहाल स्थिति में है। मान्यवर, यह नहर पक्का करा दिया जाए और उसका सौन्दर्यीकरण हो जाए। हमारी विधान सभा क्षेत्र में भूमि उपलब्ध है। बागपत और गाजियाबाद में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसलिए वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराने की कृपा करें। एक केन्द्रीय विद्यालय दे दिया जाए। जैसे ही हम दिल्ली से इण्ट्री करते हैं तो लोनी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। जो हालात थे, उसमें सुधार तो हुआ है लेकिन लोनी को नगर निगम बनाने की हमारी माँग है और लोनी को नगर निगम बना करके उसके विकास के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। इतना विकास कराने के बावजूद लोनी की सड़कें बहुत खराब हैं। लवणासुर राक्षस के नाम पर लोनी का नाम पड़ा है। भगवान परशुराम जी ने भगवान राम से कहकर शत्रुघ्न महाराज के द्वारा उसका वध कराया था, मेरी माँग है कि भगवान परशुराम जी के नाम पर लोनी का नाम ''परशुराम नगर'' किया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक घटना हुई जो दिल्ली का बॉर्डर है किसानों के नाम पर आजाद हिन्दुस्तान में कोई इस तरह से सोचा भी नहीं होगा, जहाँ लाखों कुर्बानियाँ हुईं। हमारे पूज्य राजा राव उमराव सिंह के नेतृत्व में हमारे समाज के 40 हजार से ज्यादा लोग शहीद हुए। वहाँ खालिस्तानियों के साथ बैठ करके तिरंगे का अपमान हुआ और हम पर झूठा आरोप लगाया गया। चूँकि मैं समझता हूँ कि विपक्ष के लोग वहाँ जाकर राजनीति कर रहे हैं और खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। लाल किले व तिरंगे का पूरी दुनिया में अपमान किया, अब ऐसे लोग दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। क्या लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि हाई-वे के ऊपर बैठ करके आन्दोलन किया जायेगा, शहीदों का व तिरंगे का अपमान किया

जायेगा ? मान्यवर, इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

***श्री विजेन्द्र सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2021-22 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरी खुर्जा विधान सभा क्षेत्र में ब0स0पा0 और काँग्रेस के विधायक रहे हैं परन्तु उन्होंने कोई विकास के कार्य नहीं कराये। जब से मैं विधायक बना हूँ और 2014 में जब से हमारी केन्द्र में सरकार आयी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का और यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जिन्होंने जेवर में एअरपोर्ट बनवाया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने टी0एच0डी0सी0 का पॉवर प्लाण्ट जो 415 करोड़ से मेरी विधान सभा क्षेत्र में बन रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ नगर विकास मंत्री आदरणीय श्री आशुतोष टण्डन जी का जिन्होंने खुर्जा नगर का सीमा विस्तार कराया जिसकी लगभग 26 कॉलोनी वंचित थी जो अब खुर्जा नगर में शामिल हो गयी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2021-22 के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, मेरी जो विधान सभा क्षेत्र है खुर्जा उसमें बसपा और काँग्रेस के विधायक रहे हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं कराया। मान्यवर, 2014 में हमारी केन्द्र में सरकार आई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का, यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जिन्होंने जेवर पर एयरपोर्ट बनवाया। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जिन्होंने टी0एच0डी0सी0 पॉवर प्लान्ट जोकि लगभग 415 करोड़ की योजना से मेरी विधान सभा क्षेत्र में बन रहा है। मैं नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने खुर्जा नगर का सीमा विस्तार कराया जिसकी लगभग 26 कालोनी वंचित थी जो अब खुर्जा नगर में शामिल हो गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को उप मुख्य मंत्री आदरणीय श्री केशव मौर्या जी को जिन्होंने खुर्जा झाझर सम्पर्क मार्ग लगभग 16 किमी0 का निर्माण कराया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय उप मुख्य मंत्री श्री केशव मौर्या जी को जिन्होंने खुर्जा से शिकारपुर मार्ग 17 किमी0 का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया। मान्यवार, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और आदरणीय कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को जिन्होंने मेरी विधान सभा क्षेत्र में आई0टी0आई0 बनवाई जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपये है। मान्यवर, धन्यवाद देता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा जी का जिन्होंने मेरे क्षेत्र में बिजलीघर बनवाया। मान्यवर, मेरी दो माँगें हैं मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे यहाँ पर एक एन0आर0ई0सी0 कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1901

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

में हुई थी, वह विश्वविद्यालय बनने के सारे मानक पूरे करता है। 2012 में यू0जी0सी0 से नेट में ए ग्रेड प्राप्त है। मेरठ विश्वविद्यालय से पाँच संकाय बी0एड0, विधि संकाय, विज्ञान, कला, वाणिज्य अनुमोदित है। यह कॉलेज लगभग 55 एकड़ भूमि पर है। खुर्जा का सी0सी0एस0 विद्यालय मेरठ से 95 किमी0 दूरी है। प्रत्येक वर्ष कॉलेज में 10 हजार संस्थागत और व्यक्तिगत विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। खुर्जा शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि एन0आर0ई0सी0 कॉलेज में गौतमबुद्ध नगर व अलीगढ़ के भी छात्र-छात्राएं अध्ययन करने के लिये आते हैं। खुर्जा जिला बुलन्दशहर व अलीगढ़ की सीमाओं से लगा हुआ है। मेरा अनुरोध है कि कॉलेज की विभागीय जाँच इस दृष्टि से कराने की कृपा करें क्योंकि कॉलेज विश्वविद्यालय के सभी मानक पूरे करता है। मान्यवर, एक मेरे यहाँ पर चीनी मिल है, वह काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है। जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत जहाँगीरपुर स्थित चीनी मिल पड़ती है जो कि काफी दिनों से बन्द है। जहांगीरपुर क्षेत्र के किसानों को अपना गन्ना वेव शुगर मिल बुलन्दशहर, त्रिवेणी शुगर मिल तक ले जाना पड़ता है जोकि काफी दूर पड़ता है और आने-जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गन्ना सीजन में ट्रैक्टर-ट्राली से खुर्जा नगर में जाम की स्थिति बन जाती है और खुर्जा नगर में गन्ना ट्रक पलटने से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। किसानों की समस्याओं को देखते हुए जहाँगीरपुर स्थित चीनी मिल को बनवाने की कृपा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार चल रही है 2014 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने और 2019 में भी जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी दोबारा से इस देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 से लेकर माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है 2021 तक उनकी सरकार में कोई मंत्री, कोई ऐसा सांसद नही होगा जो भ्रष्टाचार या किसी चीज में आरोपित हो। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उनकी सरकार में कोई मंत्री या कोई विधायक ऐसा नही होगा जो किसी भ्रष्टाचार में आरोपित हो।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपसे यही कहना चाहूँगा कि यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, यह साफ सुथरी सरकार चल रही है और यह हमारा सौभाग्य है कि इस देश को आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी जैसे और पूज्यनीय योगी आदित्यनाथ जैसे दोनों नेता मिले हैं जो गंगाजल की तरह पाक-साफ हैं। मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका

दिया, इसके लिये मै आपको कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सुभाष त्रिपाठी 'एडवोकेट'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2021-22 के बजट पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वस्थ, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाये जाने की दिशा में काम कर रही है। हमारी सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा श्रमिकों की समस्याओं के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उस दिशा में हमारी केन्द्र की सरकार और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्नतशील तकनीक प्रशिक्षण एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले की सरकारों में क्रय केन्द्र तो खोल दिये जाते थे, लेकिन खरीद बिल्कुल नहीं होती थी। हमारी सरकार के समय में 2020-21 में गेहूं फसल की 35 लाख 76 हजार मीट्रिक टन की खरीद की गयी है, ऑनलाइन भुगतान भी किसानों के खाते में 6 हजार 885 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह से क्रय केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीद 65 लाख 50 हजार मीट्रिक टन 15 फरवरी तक खरीद की गयी है, जिसका भुगतान 11 हजार 145 करोड़ ऑनलाइन के माध्यम से किसानों के खाते में कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से दो-दो हजार की तीन किश्तें कुल 6 हजार रुपये साल में किसानों के खातों में जाना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो छोटे किसान हैं, उनके लिए खाद, बीज और अन्य सामान भी खरीद के लिए आसानी से सुविधा मिल जाती है और इस तरह से 2 करोड़ 40 लाख किसानों को 27 हजार 123 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि की किसान सम्मान निधि उनके खाते में स्थानान्तरित की गयी है। मैं बताना चाहता हूँ कि किसान सम्मान निधि 78 हजार 518 किसानों को हमारी विधान सभा क्षेत्र में दी जा रही है। पहले की सरकारों के समय में प्रधानमंत्री आवास कहीं दिखायी भी नहीं देते थे। लेकिन हमारी केन्द्र सरकार बनने के बाद भारी मात्रा में प्रधानमंत्री आवास और शौचालय बने। 2011 में सर्वेक्षण हुआ था और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास बनाये गये। उसके बाद तमाम ऐसे पात्र लोग छूट गये थे, जो गरीब थे, उनके कच्चे मकान थे, मा0 मुख्य मंत्री आवास योजना लागू की गयी, उसके माध्यम से हमारे गांव के लोगों और शहर के लोगों के आवास बनाये जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों के लिए है। अगर परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका मुखिया नहीं रह जाता है तो 5 लााख रुपये की सहायता उस किसान परिवार को दी जाती है। उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसके माध्यम से अगर बटाईदार किसान है तो उसको भी मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ मिल रहा है और इसी तरह से किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मैं इसके लिए सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। बिजली के क्षेत्र में मैं पहले कभी एम0एल0सी0 हुआ करता था तब विधायकों

को विद्युतीकरण के लिए पाँच गांव ही मिलते थे। पूरी विधान सभा क्षेत्र में पाँच गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराना बड़ा कठिन होता था। जिन गांवों में विद्युतीकरण कराया जाता था, उसके पुरवे व मजरे छूट जाते थे हमारी सरकार के समय में ऐसा कोई गांव या ग्राम पंचायत नहीं होगी, जहाँ कम से कम 100 नए खम्भे से लेकर हजार, डेढ़ हजार तक नए बिजली के खम्भे न लगाए गए हों। पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत लोगों को मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। आज 80 प्रतिशत से अधिक गांवों के लोगों के घरों में बिजली पहुँच चुकी है यही नहीं मान्यवर पहले की सरकारों में गांव में केवल 6-7 घंटे बिजली आती थी, आज हमारी सरकार के समय गांवों में 18 घण्टे बिजली, तहसील केन्द्रों पर 21 घण्टे बिजली तथा इसी तरह से जिला केन्द्रों पर 24 घण्टे बिजली सप्लाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में गांवों और शहरों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जा रही है और इसके लिए 24 हजार मेगावाट विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री सुभाष त्रिपाठी 'एडवोकेट'-

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए स्टेडियम और ओपेन जिम केन्द्रों के निर्माण किए जा रहे हैं। इसी तरह से अभ्युदय योजना के अन्तर्गत निर्धन छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों में निःशुल्क भोजन व आवास की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है इसके लिए सरकार की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री सुभाष त्रिपाठी 'एडवोकेट'-

गाँवों में परिषदीय विद्यालय, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ विद्यालय के भवन बहुत खराब स्थिति में थे, वहाँ अब भवनों में टाइल्स लगा दिए गए हैं, तथा उनका कायाकल्प कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए चहारदीवारी बनाई जा रही है जो अभी तक नहीं बनी थी। ग्रामीण सड़कों के लिए पर्याप्त धन हमारी सरकार दे रही है। इस बजट में 12441 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में कैसरगंज, हुजूरपुर और पयागपुर मार्ग को स्टेट हाई-वे के रूप में घोषित कर दिया गया है। मेरे विधायक होने के पहले विधान सभा क्षेत्र में हमको टूटी-फूटी सड़कें मिली थीं। विधायक बनने के बाद हमारी सरकार ने पयागपुर से इकौना तक के लिए चौड़ी सड़क का निर्माण कराया है। इसी तरह से पयागपुर से हुजूरपुर और कैसरगंज तक के लिए 78 करोड़ का बजट दिया गया है जो 32 कि0मी0 चौड़ी सड़क बनेगी। मैं बताना चाहता हूँ लखनऊ से बहराइच होते हुए जो लोग बलरामपुर जाते थे तो बलरामपुर जाने के लिए उनको बहराइच होकर जाना पड़ता था। अब वह कैसरगंज से ही पयागपुर होते हुए बलरामपुर जा सकेंगे तथा

अब 32 कि0मी0 दूरी भी कम हो जाएगी। मैं इसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में कुछ काम हो रहे हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दो बड़े पुल हमारे यहाँ बन रहे हैं एक सिरौला घाट पर पुल बन रहा है जो साढ़े चौहद करोड़ की लागत का है। एक अन्य चन्दईपुर घाट पर पुल बन रहा है जो साढ़े दस करोड़ की लागत का है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इन पुलों का निर्माण शीर्घ कराया जाए, क्योंकि कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। हमारे क्षेत्र में एक फायर स्टेशन का निर्माण हो रहा है उसमें भी तेजी लाने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में एक प्राकृतिक बघैल तालाब है जो चार सौ इक्तालीस हेक्टेएयर का है इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए तथा हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 कॉलेज खोलने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। मैं इन शब्दों के साथ योगी आदित्यनाथ जी को और श्री सुरेश कुमार खन्ना को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए बजट पर अपनी बात रखने के लिए अधिष्ठाता महोदय आपको धन्यवाद देता हूँ।

***श्री संजय कुमार-**

अधिष्ठाता महोदय धन्यवाद, आज मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको अपनी विधान सभा क्षेत्र चायल की जनता की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारा यह बजट भारत के सभी प्रदेशों में पेश अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पाँच लाख पचास हजार करोड़ का यह बजट जो कि अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे देश में दूसरे नम्बर का आज की डेट में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश का बजट बना है। मैं मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं उनके वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्य मंत्री मा0 केशव प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ तथा अपनी सरकार के सभी मंत्रिगण और इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने 2017 से लेकर अब तक 04 साल में, 50 साल बनाम 04 साल का एक इतिहास रच दिया है। 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश की अगर तुलना की जाये, चाहे कानून-व्यवस्था में तुलना की जाये, चाहे बिजली की व्यवस्था में तुलना की जाये, 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में 06 घंटे से लेकर 08 घंटे की बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती थी और वह भी एक हफ्ते दिन में और एक हफ्ते रात में मिलती थी, इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हो रहा था। सपा सरकार में सिर्फ 05 जिले वी0आई0पी0 थे, बाकी बिजली के मामले में सबको रुलाया गया। हम लोगों ने उस समय आन्दोलन किया था। आज बिजली नाम का कोई विषय चर्चा में नहीं है कि बिजली कब आयेगी। आज चर्चा यह होती है कि बिजली कब गयी थी। सबसे पहले मैं एक आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपने मा0 ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी को इस सदन की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय, 04 अप्रैल, 1997 को उस समय की तत्कालीन मुख्य मंत्री मायावती जी द्वारा इस जनपद का सृजन किया गया था। हमारे जनपद में 03 विधान सभा क्षेत्र हैं। उस समय पैसा बहुत आया था, मगर सारा पैसा सिर्फ एक विधान सभा क्षेत्र में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

एक कद्दावर नेता उस समय हुआ करते थे और उन्होंने पूरे जनपद की विकास की धनराशि का 90 परसेंट पैसा सिर्फ अपनी विधान सभा क्षेत्र के विकास, अपने लोगों के विकास और अपने स्वयं के विकास में हजारों-हजारों करोड़ का खुद का निवेश उन्होंने दुनिया के और देश के तमाम स्थानों पर किया है। मगर हमारी चायल विधान सभा क्षेत्र के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ, बगल में प्रयागराज और कौशाम्बी के बगल में मंझनपुर, इन दोनों के बीच में चायल फंसा था और कैसे फंसा था, जैसे बरगद के नीचे कोई दूसरा पौधा नहीं पनप पाता वैसे ही पूर्ववर्ती सरकारों में हमारे चायल की लगभग वही स्थिति थी। जब सरकार बदली और सपा की सरकार आयी तो हम लोगों को लगा कि शायद हमारी विधान सभा क्षेत्र का कुछ भाग्योदय होगा, मगर सपा की सरकार तो हत्यारिन निकल गयी। जैसे ही मुलायम सिंह की सरकार आयी तो सबसे पहले तो कौशाम्बी की हत्या कर दी, कौशाम्बी का जिला का दर्जा ही समाप्त कर दिया, यह तो मा0 उच्च न्यायालय की कृपा हुयी जिसकी वजह से स्टे मिला और हमारा जिला बचा, फिर भी जिद के कारण सपा वालों ने जब तक उनकी सरकार थी, तब तक मात्र ए0डी0एम0 और एडीशनल एस0पी0 से इस जिले को चलाया। इतना बड़ा सौतेला व्यवहार पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जिले के साथ नहीं किया गया था जितना सौतेला व्यवहार हमारी कौशाम्बी के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे चायल की तस्वीर बदल गयी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज अयोध्या विश्व के सबसे बड़े पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आयी है। चित्रकूट जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष व्यतीय किये हैं, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक जाने वाला राम वन गमन मार्ग लगभग 2000 करोड़ की एक परियोजना मेरी विधान सभा क्षेत्र में, जिसमें गंगा पर एक नाया फोर लेन का पुल, एक नयी ग्रीन बेल्ट में फोर लेन की सड़क, हमारे विधान सभा क्षेत्र से उसकी तस्वीर बदलते हुए जाने वाला एक प्रोजेक्ट हमको प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं मा0 मोदी जी की सरकार और मा0 केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का इस सदन के माध्यम से आभार प्रकट करता हूँ। हमारी विधान सभा क्षेत्र में प्रयागराज से झलवा से एक फ्लाईओवर जो प्रयागराज एयरपोर्ट आकर उतरेगा और प्रयागराज एयरपोर्ट से एक नया फोर लेन जो मेरी विधान सभा क्षेत्र होते हुये हमारी मंझनपुर विधान सभा क्षेत्र के कौशाम्बी खास को जोड़ने वाली सड़के दस सौ करोड़ की परियोजना हमारी विधान सभा क्षेत्र को मिली है, हमारे जिले को मिली है इसके लिए मैं पूरी सरकार का, मा0 मुख्य मंत्री जी का, मा0 उप मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आई0टी0आई0 हमको मिला है, सारे विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है। अब आप किसी गांव में जाइये जहां भी सुन्दर भवन दिखे तो समझ लीजिए कि सरकारी स्कूल हमारे प्राइमरी और जूनियर पाठशाला हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में स्कूलों की क्या दशा रहती थी यह सबको पता है, मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आए हुए विधायक सब जानते हैं मगर आज प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर हमारे सरकारी स्कूल सजे हैं, संवरे हैं, एक अच्छा माहौल बना है। आज हमारी नामांकन की संख्या बढ़ी है। लोगों का विश्वास फिर से सरकारी स्कूलों पर कायम हुआ है। इसके लिए अपनी सरकार को मैं

बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक नया आई0टी0आई0 कॉलेज मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिया है, एक भरवारी नगर पालिका परिषद् में एक बस स्टॉप दिया, हमारे नेवादा ब्लॉक के तिलगोरी गांव में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्टेडियम दिया है, मैं इसके लिए अपनी सरकार का हृदय आभार प्रकट करता हूँ। हमारी सरकार ने मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक नगर पालिका सृजित किया है, मेरे यहां एक ऐसा गांव है जो उत्तर प्रदेश में दूसरे नम्बर की सबसे बड़ी ग्राम सभा थी। पहले नम्बर पर अगर गाजीपुर का गहमर है तो दूसरे नम्बर पर कौशाम्बी की चरवा थी, जो सबसे बड़ी है और उसे हमारी सरकार ने नगर पंचायत का दर्जा देकर उसका भी बहुत बड़ा कायाकल्प करने जा रही है। चरवा वह स्थान है जहां पर भगवान श्रीराम ने प्रथम रात्रि वन गमन के दौरान चरकमुनी के धाम पर विश्राम किया था श्रृंगवेरपुर से गंगा पार करके, कुरई घाट उतर के चरवा के चरकपुरी के धाम पर रात्रि विश्राम करके चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया था। उस ऐतिहासिक चरवा को हमारी सरकार ने नगर पंचायत बनाया है, इसके लिए मैं अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बजट में सब कुछ मिला है, चाहे छात्र-छात्राओं के लिए अभ्युदय योजना हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे श्रमिकों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो। मैं तो किसानों के मुद्दे पर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। विपक्ष के तमाम लोग किसानों पर राजनीति कर रहे हैं। कभी-कभी दिल्ली का मुख्य मंत्री भी किसानों पर बोलता है। मुझे तो शर्म आती है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन दो करोड़ है, वह किसान पर बात करेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार दो करोड़ चालीस लाख किसानों के खाते में खाली किसान सम्मान निधि भेजकर किसानों का सम्मान करती है। ये सरकार कभी किसान विरोधी नहीं हो सकती, ये सरकार किसानों के कोख से पैदा हुई है, ये सरकार गरीबों के घर से निकली सरकार है। इस सरकार में टोटल चाहे केन्द्र से लेकर स्टेट तक अगर आप देखेंगे तो 75 प्रतिशत हमारे चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, वह किसान के पुत्र निकलेंगे। मैं कह सकता हूँ कि किसानों की कोख से जन्मी यह सरकार है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह है बेरोजगारी। पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे यहां उद्योग धन्धे, रोजगार देने के बारे में कभी नहीं सोचा है। बेरोजगारी भत्ता बांटकर, लाइन में लगाकर युवाओं को सिर्फ आलसी बनाने का काम किया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने एक संकल्प के माध्यम से अपनी विधान सभा क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र बनाने का आग्रह किया था जिसे आपकी पीठ द्वारा स्वीकार किया गया है यू0पी0एस0आई0डी0सी0 ने जमीन सर्वे शुरु कर दिया है जैसे प्रयागराज में नैनी, जौनपुर में सतहरिया, फतेहपुर में मलवा उसी तरीके से कौशाम्बी के अन्दर चायल को हमें औद्योगिक क्षेत्र बनाना है क्योंकि चायल हमारा प्रयागराज से सटा हुआ है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बहुत बड़ा हिस्सा मेरी विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित है, उसे औद्योगिक क्षेत्र बनाके हमारे यहां से लाखों लोग जो दूसरे प्रान्तों में, दूसरे शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं उनका भी पलायन रोकना है, उनको भी रोजगार देना है। हमारा यह संकल्प है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट में कहना चाहूंगा कि हमारे यहां शिक्षा की मजबूती के लिए एक राजकीय महाविद्यालय की

आवश्यकता है। एक लड़कियों के लिए राजकीय महाविद्यालय हमें चाहिए एक राजकीय इण्टर कॉलेज बने। हमारे यहां चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेडिकल कालेज दिया है, उस मेडिकल कालेज द्वारा हमारे यहां चिकित्सा की सुविधा बहुत अच्छी होने वाली है। मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि चायल का भाग्योदय हुआ है। हजारों हजार की परियोजना मिली है। कानून व्यवस्था ठीक हुई है। प्रयागराज में जिस तरीके से गुण्डों के घर गिराये जा रहे हैं, जमीने खाली कराई जा रही हैं, इसका प्रभाव हमारे चायल में दिख रहा है। किसी की औकात नहीं है कि थाने को कैप्चर कर ले, किसी की जमीन कब्जा कर ले, किसी को भयभीत कर ले और अगर देश में मोदी और प्रदेश में योगी का अगर खौफ रहता है अपराधियों के अन्दर तो चायल में विधायक संजय गुप्ता का खौफ रहता है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में जो छोटी-मोटी परियोजनायें हैं जैसे राजकीय इण्टर कालेज, राजकीय बालिका डिग्री कालेज और एक प्रयागराज विश्वविद्यालय का कैम्पस में अपने विधान सभा क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैम्पस चाहता हूँ, कार्यवाही में इसको अंकित कराइये इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस बजट पर मैं अपनी सरकार का भरपूर समर्थन करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

***श्री सुनील कुमार शर्मा-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ महोदय, यह बजट कोरोना काल की त्रासदी के बाद आया है, इतनी बड़ी महामारी के बाद इतना अच्छा और श्रेष्ठ जनकल्याणकारी बजट माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय वित मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने एक पांच लाख पचास हजार दो सौ सत्तर करोड़ अठहत्तर लाख रुपये का बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई। अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं बहुत कम समय में अपनी बात कहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का पहला, हजारों यात्री हिन्दुस्तान से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं वह दिल्ली के होटलों में भटकते थे। उनके लिए कोई व्यवस्थायें नहीं थीं, दूसरे धर्मो के लोग विदेशों में यात्रा करते हैं, उनके लिए स्थान बनाये गये थे लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कोई स्थान नहीं था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिन्दुस्तान का पहला कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद की साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरापुरम में बनाया इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट में सभी के साथ और सबके विकास का ध्यान रखा गया है। युवाओं को उच्च शिक्षा व नौकरी, किसानों के लिए सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

गरीब किसानों हेतु आवास, आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग तथा पुल आदि के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सक्षम सुपोषण योजना, महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बन्द पड़ी कताई मिलों के जीर्णोद्धार की व्यवस्था की गयी है। बजट में मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान की व्यवस्था, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। माननीय अधिष्ठाता जी, बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा अभ्युदय योजना, करियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम, युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना, युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता, मुख्य मंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमी विकास योजना, गोवंश संरक्षण एवं निराश्रित पशुओं की देखभाल हेतु बजट में व्यवस्था की गयी है। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में विशेष व्यवस्था की गयी है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व0 श्री अटल बिहारी बाजपेई जी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। लोक निर्माण विभाग हेतु सड़कों के निर्माण व चौड़ीकरण के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है। संस्कृत विद्यालयों में गरीब छात्रों को गुरूकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास व भोजन दिया जायेगा ऐसी व्यवस्था भी बजट में की गयी है। बजट में ग्रामीण स्टेडियम और ओपेन जिम के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। खेल विश्वविद्यालय के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बजट में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई जिसमें कक्षा-6 से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मुख्य मंत्री दुर्घटना बीमा योजना, असंगठित कामगारों के लिए 12 करोड़ रुपये तथा मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11 लाख मतदाता हैं। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाये तो हिन्दुस्तान के नौ राज्यों से अधिक आबादी साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र में है। मेरे यहां हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों और सभी जनपदों के लोग रहते हैं। यह एक ऐसा गुलदस्ता है जिसको लघु हिन्दुस्तान के रूप में देखा जा सकता है। यह बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। मेरा विधान सभा क्षेत्र आज जगमगा रहा है। सड़कें चौड़ी हैं, मेट्रो चल रही है, फ्लाईओवर बने हैं, एलीवेटेड रोड बनी है, एयरपोर्ट बना है, कैलाश मानसरोवर भवन बनाया गया है और तमाम अण्डरपास बनाये गये हैं, अगर मैं उस पर बोलना शुरू करूंगा तो बहुत समय लगेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं जिनका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र होड़ा मखनपुर है। वहां लगभग पांच लाख की आबादी है जो दिल्ली, नोएड और गाजियाबाद के बीच में है। वहां सरकारी पानी की कोई सप्लाई नहीं है। भूमिगत जल 400 फिट नीचे पहुंच गया है जिसका टी0डी0एस0 3000 से ऊपर है। लोगों में भारी पेयजल का संकट है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम 127 करोड़ रुपये से वहां पेयजल की व्यवस्था करेंगे। मेरा अनुरोध है कि इस आश्वासन को शीघ्र पूरा करने का काम सरकार करे और वहां

पर पेयजल की व्यवस्था करे। इसी प्रकार गाजियाबाद नगर निगम के मोहननगर जोन में भी पेयजल की भारी दिक्कत है और वहां पर गंगा जल की आपूर्ति किया जाना बहुत आवश्यक है इसलिये वहां पर प्राथमिकता पर गंगा जल की आपूर्ति कराई जाये। ट्रांस हिंडन एरिया में एक सरकारी अस्पताल तथा एक-एक सरकारी इण्टर कालेज, स्कूल और डिग्री कालेज की बहुत आवश्यकता है, इसकी भी व्यवस्था की जाये। नौजवानों और छात्रों के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की आवश्यकता है जो वसुन्धरा क्षेत्र में ही कहीं पर स्थापित कराने की कृपा करें। वसुन्धरा में इसके लिए स्थान उपलब्ध है केवल आवश्यकता है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से इसके लिए भूमि लेकर सरकार वहां स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाये। सेक्टर-62 से मोहननगर तक और वैशाली से मोहननगर तक मेट्रो को लिंक किया जाना बहुत आवश्यक है इसलिये मेट्रो लिंक की जानी चाहिये। संस्कृत विद्यालयों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि संस्कृत विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं है। माननीय योगी जी की सरकार जबसे आई है तबसे संस्कृत विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और नये संस्कृत विद्यालयों को मान्यता भी दी गई है। मेरा गाजियाबाद भगवान दुधेश्वर नाथ की भूमि है और यह पौराणिक शहर है। भगवान कृष्ण ने जब युधिष्ठिर का दूत बनकर दुर्योधन से पांच गांव मांगे थे तो उसमें से एक गांव का नाम गजप्रस्थ था। यह गजप्रस्थ गाजियाबाद बना जहां पर भगवान दुधेश्वर नाथ विराजमान हैं। मेरा अनुरोध है कि गाजियाबाद का नाम बदलकर गजप्रस्थ कर दिया जाये। हमारे गाजियाबाद में जो एयरपोर्ट है उससे अगर लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी की उड़ान शुरू कर दी जाये तो पूरे प्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

डा0 मन्जू शिवाच-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और साथ ही सरकार के साढ़े पांच लाख करोड़ से ज्यादा की बजट की मैं सराहना करती हूँ कि उसमें विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि माननीय योगी जी ने हर मण्डल में सैनिक स्कूल देने की घोषणा की है। मैं पिछले तीन साल से इसके लिए कोशिश कर रही हूँ और मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में इसके लिए समुचित भूमि भी उपलब्ध है तो यदि मण्डल का सैनिक स्कूल मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित करवा दिया जाये तो उससे हमारे जो स्थानीय नागरिक हैं वह बहुत खुश होंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, साथ ही साथ अपनी सरकार शिक्षा, उच्च शिक्षा में भी बहुत ध्यान देती है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में अब से 20 साल के दौरान काफी मिलें बंद हो गयी थीं। बच्चों को एक आई0टी0आई0 और पॉलीटेक्निक टाइप का कॉलेज मिल जाये तो मजदूरों के बच्चों का बहुत कल्याण हो जायेगा और उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरा जो क्षेत्र है वह डाईमण्ड शेप्ड है। उसमें बीच में मोदी नगर में शिक्षा की संस्थाए बहुत ज्यादा प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, लेकिन एक कोने पर तलहटा और दूसरे कोने पर खिंदौड़ा में राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। मान्यवर, वह भी

मेरे क्षेत्र को मिल जाते हैं तो गाँव के जो बच्चे हैं उन्हें साईकिल से या टैम्पो से बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। अधिष्ठाता महोदय, मेरे यहां दो पुल सौदा ओर निवाड़ी में है जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, उनको थोड़ा सा इंस्पेक्शन करके मुझे लगता है कि वह बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तो उसका पुनरुद्धार करना चाहिये या नया पुल बना देना चाहिये। मेरे क्षेत्र में कोई भी अपग्रेडेड, बहुत हाई लेवल का पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 सेन्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, जबकि मेरी विधान सभा क्षेत्र में लगभग ढाई सौ, तीन सौ गांव के मरीज रोज आते हैं। यदि वहां पर कोई आयुर्वेदिक कॉलेज बना दिया जाये जिसका सरकार प्रस्ताव भी रख रही है तो मेरे क्षेत्र के लोगो का इलाज में काफी सुविधा मिल जायेगी।

मान्यवर, मेरे यहां खासतौर पर जो ग्रामीण बच्चे हैं वह खेलकूद में काफी आगे रहते हैं उसके लिये यदि गांव के क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम या ग्रामीण स्टेडियम बना दिया जाये तो उससे मेरे जो खिलाड़ी बच्चे हैं उनको आगे सेना में जाने के लिये या पुलिस में जाने के लिये तैयारी करने के लिये काफी आसानी रहेगी। साथ ही साथ मेरे यहां दो शहीद हुए हैं। एक मेरे पड़ोसी विधान सभा क्षेत्र से और एक मेरे क्षेत्र से। मान्यवर, मेरा बड़ी ही विनम्रता के साथ निवेदन है कि निवाड़ी गांव के शहीद और पास के ही बसाटीकारी के शहीद दोनों के नाम पर एक पार्क या एक प्रदर्शनी स्थल जोकि इस बजट में प्रस्तावित है कर दिया जाये तो मैं आपकी बहुत अभारी रहूंगी। साथ ही साथ ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं आदरणीय योगी जी को और आदरणीय खन्ना जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है। मान्यवर, सतत् विकास की प्रक्रिया में यदि हमें पूरी दुनिया को आगे ले जाना है तो हिन्दुस्तान आगे बढ़ेगा और जब यू0पी0 आगे बढ़ेगा तभी हिन्दुस्तान आगे बढ़ेगा। खासतौर में उत्तर प्रदेश की महिलायें और बच्चे आगे बढ़ंगे चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे उनका न्यूट्रीशियन हो। इस बात के लिए विशेष धन्वाद देती हूं कि महिलाओं और बच्चों के पोषण का विशेष ध्यान रखा गया है। हमने सी0डी0पी0ओ0 के माध्यम से अपने क्षेत्र के कुपोषित बच्चे और छः महीने से तीन साल के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का बहुत ही अच्छे ब्राण्ड के घी, मिल्क पाउडर, दालें और चावल दिया क्योंकि अगर बच्चा कुपोषित है तो वह एक कुपोषित कम श्रम करने वाला मजदूर बनेगा या कम दिमागी काम करने वाला क्लर्क या ऑफिसर बनेगा। आदरणीय योगी जी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन न्यूट्रीशियन के लिए योगी जी जो कोशिश कर रहे हैं उसकी मैं बहुत सराहना करती हूं क्योंकि कल को हमें एक अच्छा किशोर मिले, अच्छा नागरिक मिले, उसके लिए एक अच्छा पोषण होना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं योगी जी को बहुत धन्यवाद देती हूं। मान्यवर, जैसे सभी के अपने मंदिर होते हैं। काशी वालों के बाबा विश्वनाथ हैं। आयोध्या वालों के रामजी हैं। मैं छोटी सी विधान सभा क्षेत्र से आती हूँ। मेरा शीखरी माता का मंदिर है। मेरा विनम्रता के साथ निवेदन है। मैं काफी समय से इसमें काम कर रही हूँ। मेरे पास 12-15 करोड़ रुपया भी है। उसे खर्च करने की अनुमति मिल जाये जिससे हमारा शीखरी माता मंदिर के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण हो जाये, सड़कों का चौड़ीकरण हो जाए और मेला लगने पर अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो एम्बुलेंस निकलने भर के रास्ते भी ठीक हो जाएं। मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं कि मेरे यहां

जमीनें बहुत खरीदी और बेची जाती हैं जिससे राजस्व का लाभ जी0डी0ए0 को भी दिया जाता है। जी0डी0ए0 के माध्यम से मेरी विधान सभा क्षेत्र में कुछ न कुछ काम हो जाए क्योंकि मेरे क्षेत्र में अभी तक जी0डी0ए0 के माध्यम से कोई विशेष काम नहीं हो पाया है। अन्त में आपको धन्यवाद देती हूं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमारे जैसे छोटे विधान सभा क्षेत्र और शहरों का डेवलपमेंट चार्ज कम किया है उसके लिये मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

डा0 अवधेश सिंह, श्री नरेन्द्र पाल सिंह जालौन, शीतल पाण्डेय जी, अनुपस्थित

***श्री राम चन्द्र यादव-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने उत्तर प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक बजट के समर्थन में हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में जब माननीय योगी जी ने सरकार का दायित्व संभाला तबसे लेकर आज तक देश की जो आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाने का जो एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, सबका साथ, सबका विश्वास को समाहित करते हुए यह जो दास्तावेज उत्तर प्रदेश की इस विधान सभा में उत्तर प्रदेश के विद्वान वित्त मंत्री मा0 श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक बजट में आयोध्या का जो ध्यान रखा गया है इसके लिये मैं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के सभी माननीय मंत्रीगण का और पूरे आयोध्यावासियों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनन्दन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आयोध्या की उस ऐतिहासिक धरती को जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूरी दुनिया को मर्यादा का संदेश दिया था। आज उस राम की धरती को जिस तरह से सजाने का, सँवारने का और वहाँ की जो आम जनता है, किसान है, नौजवान है, विद्यार्थी है उनकी आधारभूत सुविधाओं को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें सबमें आयोध्या की उन आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुये आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी 2017 से लेकर अब तक 18 दौरे कर चुके हैं और अनके दौरे में वहां पर उनकी जो उपस्थिती होती है तो निश्चित रूप से अयोध्या की एक-एक विधान सभा क्षेत्र जिसमें हमारी रूदौली विधान सभा भी आती है उस रूदौली विधान सभा के विकास और तरक्की के लिये जो बड़े फैसले प्रदेश की सरकार ने लिये हैं, इसके लिये मैं निश्चित रूप से जहाँ हमारा रूदौली विधान सभा क्षेत्र का वह हिस्सा जब हम 2012 में आज बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब इसी विधान सभा क्षेत्र में उस तरफ हम लोग बैठते थे और अपने क्षेत्र की बहुत सारी आवश्यकताओं को लेकर नियमों और वैसे भी जब हम लोग अपनी बात रखते थे तो हम लोगों की बातें अनसुनी कर दी जाती थीं और आज हम गर्व से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

कह सकते हैं कि वह हमारे क्षेत्र की बहुत सारी मांगें आज अटल आवासीय कॉलेज, हमारी रूदौली विधान सभा क्षेत्र को मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिया। आज 132 के0वी0ए0 का बड़ा पावर हाउस रूदौली विधान सभा क्षेत्र को मिला। आज रूदौली विधान सभा क्षेत्र में जहाँ रूदौली नगर के लोगों को आने-जाने मे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आज उस रूदौली को रेलवे क्रासिंग, ओवरब्रिज की जो बहुत पुरानी मांग थी उसको उत्तर प्रदेश के उप मुख्य मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्या जी ने पूरा करके हमारे क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान किया है। आज माँ कामाख्या मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए, माँ कामाख्या मंदिर जो हमारे आयोध्या की धरती पर दैवीय स्थानों में नम्बर एक का स्थान है, उस स्थान की सर्वांगीण विकास की जो योजना बनी। मा0 अधिषठाता महोदय, आज वहां पर चारों तरफ से आने वाले मार्गों को 28-28 किमी0 की लम्बाई में चौड़ीकरण का काम शुरू कराकर वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरा बनवाकर, वहां पर अतिथि गृह बनवाकर उप मुख्य मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने माँ कामाख्या मंदिर की महत्ता को बढाने का काम किया है। मैं माँ कामाख्या मंदिर पर होने वाले विकास कार्यों के लिए उप मुख्य मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्या जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से आज हमारे क्षेत्र में रौजा गांव में चीनी मिल थी, जिस चीनी मिल पर आए दिन धरना-प्रदर्शन और पिछली सरकारों में ऐसे आन्दोलन हुए हैं ,जिसमें पूरे क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के ऊपर मुकदमें दर्ज हुए। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि रौजा गांव में चीनी मिल पर उस क्षेत्र के किसान अपनी गन्ने की ट्राली ले जाते हैं, वहां पर गन्ना बेचकर आते हैं और उसके 15 दिनों बाद खाते में पैसा स्थानांतरित हो जाता है। आज पूरे क्षेत्र का गन्ना किसान, धान किसान, अन्य फसलों का उत्पादन करने वाला किसान, खासतौर से रूदौली की भूमि जहां पर सब्जी के किसान हैं, औषधीय खेती करने वाले किसान हैं आज उनकी उपज का लाभकारी दाम सरकार दे रही है। इसके नाते हमारे देश का किसान भी खुशहाल है।

आज हम पूरे के पूरे बजट में गरीबों का कल्याण कैसे हो सकता है हमारी सरकार ने बजट में प्राविधान करके, आज हर ग्राम पंचायतों में पंचायत घर बनाने का काम किया है, पंचायतों में सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना हो रही है, हमारी विधान सभा के 246 ग्राम पंचायतों में शौचालयों के निर्माण की प्रगति और साथ ही साथ एक भी ग्राम पंचायत नहीं बची है जहां पर पंचायत घर निर्माण न शुरू हो गये हों। मैं निश्चित रूप से अपनी सरकार के गांव गरीब, कल्याण की योजनाओं को खासतौर से जो जमीन पर उतारने के लिये 15 हजार से ज्यादा रूदौली चिधान सभा क्षेत्र के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने बाढ़ से प्रभावित किसानों एवं गरीबों को मुख्य मंत्री आवास दिलाकर, प्रधानमंत्री शहरी योजना से रूदौली नगर क्षेत्र के वासियों को, जिनमें कम से कम 3 हजार गरीबों को ढाई लाख रुपये से एक-एक आवास की स्वीकृति दी गयी। आजादी के बाद पहली बार इस देश में, इस प्रदेश में ऐसी योजना आयी, जिस योजना से आज गरीबों का इतना बड़ा कल्याण हो रहा है।

मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मा0 नगर विकास मंत्री जी का इसलिये भी स्वागत और अभिनन्दन करता हूं क्योंकि उन्होंने रूदौली नगर पालिका को आदर्श महापालिका क्षेत्र में घोषित करने का काम किया। हमारी रूदौली विधान सभा क्षेत्र की ऐसी स्थिति थी, मवई ब्लाक की जहां पर पढ़ाई-लिखाई के लिए न तो कोई कार्य स्थान था, न तो कोई संस्थान था, आज वहां पर मवई आई0टी0आई0 की स्थापना, रूदौली आई0टी0आई0 की स्थापना की गयी वहीं दूसरी तरफ सोनवा में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना, सी0एच0सी0 की स्थापना की गयी। आज जिस तरह से मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र के विकास की योजनाओं को उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने, मा0 मुख्य मंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है और आज उसका परिणाम यह है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में आयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुसार हर तरह से मोदी जी का, योगी जी का डंका बज रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप बैठ जाईये।

श्री राम चन्द्र यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार का यह 2021-22 का बजट है। इस बजट से अयोध्या के वासियों को और खासतौर से रूदौली विधान सभा क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ मिलने जा रहा है। मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लाल बहादुर-

मान्यवर आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका अभारी हूं। जो यह 2021-22 का बजट पेश किया गया है वह ऐतिहासिक है जिसमें गांव के लिए, गरीबों के लिये, युवाओं के लिए, बेटियों के लिए प्रावधान किया गया है। मैं कौशाम्बी से आता हूं जहां कृषि योग्य भूमि ज्यादा है, औद्योगिक क्षेत्र न होने से रोजगार की काफी समस्या है। वहीं पर रत्नावली धाम है, जो महाकवि तुलसीदास जी की प्रेरणा स्थली है, उसे पर्यटन से जोड़ा जाये जिससे युवाओं को रोजगार मिले। उसी के बगल में अलवारा झील है जो कि हजारों एकड़ में फैली हुई है, वहां पर साइबेरियन पक्षी प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में आते हैं, उसको अगर पर्यटन का स्थल मिल जायेगा तो बहुत ही क्षेत्र का विकास होगा। मेरे क्षेत्र में जी0जी0आई0सी0 कॉलेज नहीं है, अगर वह मिल जायेगा तो बेटियों की पढ़ाई में सुविधा हो जायेगी। एक वृहद गौ-शाला की आवश्यकता है, यमुना नदी से लगा हुआ मेरा क्षेत्र है उस पार से जानवर काफी आ जाते हैं। उसके बन जाने से किसानों को काफी सुविधा होगी। मान्यवर, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां पर रेलवे लाइन नहीं है। एक रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव विधान सभा के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजा जिससे वहां रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन हो सके। मान्यवर, कौशाम्बी रोडवेज डिपो जोगापुर पंप कैनाल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को देकर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चूँकि कौशाम्बी मे गन्ने की खेती

पहले बहुत होती थी, वहां पर कांटे की व्यवस्था हो जाए जिससे पुनः गन्ने की खेती आगे बढ़ सके और किसानों को सुविधा मिल सके। मान्यवर, दो लाइने कह कर अपनी बात पूरी करूंगा-

'नई चेतना, नया विकास, नया निर्माण कराऐंगे।
शहीदों के बलिदान को याद करके पुनः उत्तर प्रदेश में आएंगे। '

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, आपने मुझे वर्ष 2021-22 के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका अभारी हूं। मैं इसके लिए अपने वित्त मंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह बजट दलित, शोषित, वंचित किसान और गरीब, गांव के विकास के लिए है। जो यह बजट पेश हुआ है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने वाला बजट है। मैं साथ में यह बताना चाहता हूं कि जिस विधान सभा क्षेत्र का मैं विधायक हूँ आज हमारी सरकार में विपक्ष के लोग जिस तरह से आवाज उठाते हैं, क्या विकास हुआ है। मैंने हमेशा यह बात कही है कि 50 वर्ष बनाम 4 वर्ष। और 4 वर्ष में अगर एक वर्ष कोरोना में चला गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तीन वर्ष में बदलापुर में जहां आई0टी0आई0 बन रहा है, फायर स्टेशन बन रहा है, बस स्टेशन बन रहा है, तीन-तीन पंप कैनाल है, जो 20 वर्षों से बंद था, वह आज चालू हो गया है। यहां तक जितने हमारे प्रमुख बाजार है, सभी का सी0सी0 रोड एवं इंटरलॉकिंग हो गया है। श्रीकृष्णा नगर रेलवे स्टेशन पर घंटों जाम लगता था, वहां पर 45 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाई ओवर बनने जा रहा है। हमारे यहां 210 ग्राम सभा है, 210 ग्राम सभाओं में लगभग सभी ग्राम सभाओं में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, शुलभ शौचालय बनकर तैयार हो गया है। मान्यवर, आज जन-जन यह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो 50 वर्षों में नहीं हुआ, वह आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने 03 वर्षों में करके दिखा दिया है। मैं अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को, अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को, अपने उप मुख्य मंत्री केशव प्रशाद मौर्या जी को, अपने सिंचाई मंत्री जी को, अपने वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पूरे बदलापुर की एक-एक जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश के एक एक जन की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं और साथ में ही हमारे यहां लगभग सब काम हो गए, लेकिन कुछ कामों के लिए मैं आपसे आग्रह भी करता हूं कि आपके माध्यम से हमारे कुछ कार्य चले जायें। हमारा जो विधान सभा क्षेत्र है, सई और गोमती के मध्य हमारा विधान सभा क्षेत्र बसता है और सई मध्य के बीच में रहने से हमारे यहां नदियों का, चूँकि नदी पार करने में काफी कठिनाई होती है। हमारे यहां दो पुल बनना बहुत आवश्यक है, कारोबीर और बौझनाथ घाट, इस पर हमारे दो पुल बन जाये, साथ में जो ढाई हेक्टेयर जमीन हमारे यहां औद्योगिक भूमि के नाम से है, उस औद्योगिक भूमि पर एक मिनी उद्योग लग जाए। साथ में हमारे यहां कुछ गांव ऐसे है, जैसे बैलावी, रामनगर, बाबूगंज यहां पानी की समस्या है। यहां पर पानी की टंकी लग जाए। साथ में मैं आग्रह करना

चाहूंगा, एन0एच0-56 से हमारे यहां जो मिसरौली से इमिलिया घाट होते हुए पट्टी नरेन्द्रपुर सरपतहा मोड़ से एस0एस0-4 तक हमारे इस रोड का चौड़ीकरण हो जाए। साथ ही लोहिंदा बक्सामार्ग जो कि पीएमजीएसवाई योजना से बना था, लेकिन वह पूर्व की सरकार में बना था, वह सड़क पूरी-पूरी टूट गई है मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, उसको पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण में ले करके उस सड़क का भी निर्माण कराया जाए। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, आज चूँकि विपक्ष के लोग नहीं हैं, नहीं तो मैं उनको बताता, जो हमारे क्षेत्र के कई-कई बार के विधायक हैं, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी को, अपने सभी मंत्री जी को, जिन्होंने एक बेहतरीन उत्तर प्रदेश आज बनाकर रखा है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 350 से ऊपर सीटें आयेंगी और पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द-जय भारत, जय चौकियामाई की।

श्री अधिष्ठाता-

यह चर्चा जारी रहेगी। अब हम कल 11:00 तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 10 बजकर 06 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 03 मार्च, 2021

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर पीछे पृष्ठ ... पर)

उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या– 1061/69–1–13–14(104)/2013
लखनऊः दिनांक 27-06-2014

कार्यालय–ज्ञाप

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) और शहर स्तर पर शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0यू0) की व्यवस्था है। राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई में 06 तकनीकी निशेषज्ञों की नियुक्ति की जायेगी तथा शहर मिशन प्रबन्धन इकाई में जनसंख्या के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजको की नियुक्ति की जायेगी। तकनीकी विशेषज्ञों की शैक्षिक योग्यता, कार्य एवं उत्तरदायित्व, भर्ती प्रक्रिया, पारिश्रमिक /मानदेय एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा एन0यू0एल0एम0 के उद्घाटक क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण (Capacity Building and Training) के प्रचलनात्मक दिशा–निर्देशों में विस्तार से किया गया है।

2. तकनीकी विशेषज्ञों का कार्यक्षेत्रः–

तकनीकी विशेषज्ञ अपने–अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में विशेषज्ञ सूचनाओं एवं सेवाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में प्रभावी एवं कुशल भूमिका निभाएंगें। मिशन प्रबन्धन इकाई के राज्य एवं शहर के इंचार्ज पदाधिकारी को अपने विषय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ एक केन्द्रीय व्यक्ति (Key Person) होगा।

राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) के तकनीकी विशेषज्ञः–

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1	राज्य मिशन प्रबंधक– सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (State Mission Manager - Social Mobilization & Institution Development)	1
2	राज्य मिशन प्रबंधक– आश्रय और सामाजिक अवस्थापना (State Mission Manager - Shelter & Social Infrastructure)	1
3	राज्य मिशन प्रबंधक– कौशल और आजीविका (State Mission Manager - Skill & Livelihood)	1
4	राज्य मिशन प्रबंधक– वित्तीय समावेश और लघु उद्यम (State Mission Manager - Financial Inclusion & Micro Enterprises)	1
5	राज्य मिशन प्रबंधक– एम0आई0 और एम0ई0 (State Mission Manager - Management of Information System and Monitoring & Evaulvation)	1
6	राज्य मिशन प्रबंधक– एच0आर0 और क्षमता संवर्धन (State Mission Manager - Human Resource & Capacity Building)	1
	योग	6

शैक्षिक योग्यता एवं अनुभवः–

S.N	Position	Education and Experience Particulars	Competencies
1	State Mission Manager - Social Mobilisation and Institution	Two year full time Post graduate diploma in Management/ MBA or Masters in any other relevant discipline with 5 years of experience Or Graduate from government recognised institutes with 8 years of experience in Social	The person should be Proficient with MS office; should have acknowledged

	Development	Development work with poverty reduction programmes of considerable size and scale	capabilities in partnership management; strong analytical, conceptual and strategic thinking skills; ability to handle large scale planning; handling MIS etc. Experience of working with government institutions will be given preference
2	State Mission Manager – Shelters and Social Infrastructure	Two year full time Post graduate diploma in Management/ MBA or Masters in any other relevant discipline with 5 years of experience Or Graduate from government recognised institutes with 8 years of experience in poverty reduction programmes involving social development and establishment/ monitoring / maintenance of community infrastructures	
3	State Mission Manager - Skills and Livelihoods	Two year full time Post graduate diploma in Management/ MBA or Masters in any other relevant discipline with 5 years of experience Or Graduate from government recognised institutes with 8 years of experience in implementation of skill training and placement programmes with considerable size and scale	
4	State Mission Manager – Financial Inclusion & Micro Enterprises	Two year full time Post graduate diploma in Management/ MBA or Masters in any other relevant discipline with 5 years of experience Or Graduate from government recognised institutes with 8 years of experience in dealing with credit linkages, social security and/or micro enterprises promotion in poverty reduction programmes / financial institutions	
5	State Mission Manager – HR & Capacity Building	Two year full time Post graduate diploma in Management/ MBA or Masters in any other relevant discipline with 5 years of experience Or Graduate from government recognised institutes with 8 years of experience in staff recruitment, training and capacity building work with state level projects	The person should have, in addition to the above mentioned competencies, acknowledged capabilities in client management; excellent negotiation skills; ability to handle large scale recruitment; developing a theme based capacity building strategy and modules etc.
6	State Mission Manager – MIS & ME	Two year full time Post Graduate diploma / Masters in Computer Science, M.Sc. (computer science), B.Tech (computer science) or MCA from government recognized institute / university with at least 5 years of experience in designing and implementation of MIS and ME for large development projects, preferably poverty reduction project and full understanding of Data Analysis Technique	The person should have, in addition to the above mentioned competencies, very good documentation skills and should be very good at preparation of reports; Proficient with Project

			Management software; Database Management systems; website development and management

3. शहर मिशन प्रबंधन इकाई(सी0एम0एम0यू0) के तकनीकी विशेषज्ञः–

शहरों की जनसंख्या मानक	शहरों की संख्या	तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या	कुल पदों की संख्या	तकनीकी विशेषज्ञों का पदनाम
5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर	15	4	15X4 = 60	1 प्रबंधक–सामाजिक विकास और अवस्थापना (Manager-Social Development & Infrastructure) 2 प्रबंधक–कौशल और आजीविका (Manager-Skill & Livelihood) 3 प्रबंधक–वित्तीय समावेश और लघु उद्यम (Manager-Financial Inclusion & Micro Enterprises) 4 प्रबंधक–एम0आई0एस0 और एम0ई0 (Manager-MIS & ME)
3 से 5 लाख की जनसंख्या वाले शहर	4	3	4X3 = 12	1 प्रबंधक–सामाजिक विकास और अवस्थापना (Manager-Social Development & Infrastructure) 2 प्रबंधक–कौशल और आजीविका (Manager-Skill & Livelihood) 3 प्रबंधक–वित्तीय समावेश और लघु उद्यम (Manager-Financial Inclusion & Micro Enterprises)
3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर	63	2	63X2 = 126	1 प्रबंधक–सामाजिक विकास और अवस्थापना (Manager-Social Development & Infrastructure) 2 प्रबंधक–कौशल और लघु उद्यम (Manager-Skill & Micro Enterprises)
योग	82	–	198	

4. शैक्षिक योग्यता एवं अनुभवः–

S.N	Position	Education and Experience Particulars	Competencies
1	Manager - Social Development & Infrastructure	Two year full time Post graduate diploma in Management/MBA or Masters in any other relevant discipline with 3 years of experience Or Graduate from government recognised institutes with 6 years of experience in Social Development work with poverty reduction programmes	The person should be Proficient with MS office; strong analytical skills; Experience of working with government institutions will be given preference
2	Manager - Skills and	Two year full time Post graduate diploma in Management/MBA or Masters in any other	

25

	Livelihoods	relevant discipline with 3 years of experience Or Graduate from government recognised institutes with 6 years of experience in implementation of skill training and placement programmes	
3	Manager – Financial Inclusion & Micro Enterprises	Two year full time Post graduate diploma in Management/MBA or Masters in any other relevant discipline with 3 years of experience Or Graduate from government recognised institutes with 6 years of experience in dealing with credit linkages, social security and/or micro enterprises promotion in poverty reduction programmes/ financial institutions	
4	Manager – MIS &ME	Two year full time Post Graduate diploma / Masters in Computer Science, M.Sc. (computer science), B.Tech (computer science) or MCA from government recognized institute/ university with at least 3 years of experience in designing and implementation of MIS and ME for large development projects, preferably poverty reduction project	The person should have, in addition to the above mentioned competencies, very good documentation skills and should be very good at preparation of reports; Proficient with Project Management software; Database Management systems; website development and management

5. तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया:–

राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई एवं शहरी मिशन प्रबन्धन इकाई में तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति वाह्य एजेंसी का चयन कर उसके माध्यम से की जायेगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की गाइड लाइन्स में वाह्य एजेंसी के कार्यक्षेत्र, चयन की प्रक्रिया, कार्य की अवधि, पात्रता के मापदण्ड आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। वाह्य एजेंसी का चयन गाइड लाइन्स में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप निविदा आमंत्रित कर किया जायेगा। यह चयन गुणवत्ता एवं मूल्य आधारित चयन (क्यू0सी0बी0एस0) पर आधारित होगा जिसके अन्तर्गत तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा। तकनीकी निविदा के विस्तृत मूल्यांकन के उपरान्त वित्तीय निविदा का परीक्षण कर नियमानुसार वाह्य एजेंसी का चयन किया जायेगा। चयनित वाह्य एजेंसी योग्य एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगी। वाह्य एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन किया जाये जो निर्धारित पात्रता एवं योग्यता रखते हो। किसी भी दशा में भर्ती की निर्धारित प्रक्रिया को शिथिल नहीं किया जायेगा। चयनित वाह्य एजेंसी द्वारा योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करने आदि की विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। वाह्य एजेंसी द्वारा मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थी समर्पित एवं पूर्णकालिक कार्मिक होगें।

वाह्य एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थियो को साक्षात्कार के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा अंतिम चयन किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु शासन द्वारा

निदेशक राज्य शहरी आजीविका मिशन की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की जायेगी। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव सम्बन्धी अभिलेखों का परीक्षण करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से संस्तुति की जाएगी। यह सम्पूर्ण चयन की कार्यवाही मिशन निदेशक, की देख–रेख में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न होगी। सामुदायिक आयोजकों का चयन भी उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा।

6. तकनीकी विशेषज्ञों की कार्यक्षमता का मूल्यांकनः–

चयनित तकनीकी विशेषज्ञों को प्रारम्भ में दो वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जायेगा तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की सेवा अवधि परिवीक्षा अवधि होगी। यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो सक्षम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित तकनीकी विशेषज्ञ के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जा सकती है जिसके अन्तर्गत कम से कम 01 माह की नोटिस देकर सेवाएं समाप्त भी की जा सकती हैं। राज्य मिशन निदेशक, एवं सिटी प्रोजेक्ट आफिसर द्वारा 02 वर्ष के सेवाकाल के अन्त में तकनीकी विशेषज्ञों के कार्य का पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा तथा पुनर्मूल्यांकन के आधार पर ही उनकी संविदा का नयीनीकरण किया जायेगा। संविदा नियुक्ति का प्रारूप मिशन गाइडलाइन्स के साथ संलग्न किया गया है।

7. तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा समाप्तिः–

राज्य शहरी आजीविका मिशन/स्थानीय नगरीय निकायों की कार्मिक नीति के अन्तर्गत गम्भीर कदाचरण, संदिग्ध सत्यनिष्ठा तथा नान् परफारमेन्स पाये जाने पर 01 माह की नोटिस के स्थान पर 01 माह का पारिश्रमिक देकर तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।

8. प्रशिक्षण व अन्य क्षमता विकास सहायताः–

मिशन प्रबन्धन इकाई को उच्चगुणवत्ता युक्त टीम बनाने के लिए समय–समय पर तकनीकी विशेषज्ञों एवं टीम के अन्य सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के उपयुक्त प्रशिक्षण संस्थाओं को चिन्हित कर एक पैनल बनाया जायेगा मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा चयनित प्रशिक्षण संस्था के साथ एक एग्रीमेन्ट किया जायेगा जिसमें क्षमता विकास इनपुट (Capicity Building Input) का समावेश किया जायेगा। क्षमता विकास इनपुट के अन्तर्गत इन्डक्शन एवं ओरिन्टेशन प्रशिक्षण के साथ–साथ शैक्षणिक भ्रमण एवं स्थलीय निरीक्षण शामिल होगें।

9. सामुदायिक आयोजकः–

शहर स्तर पर गठित शहरी मिशन प्रबन्ध इकाई (सी0एम0एम0यू0) में सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) नियुक्त किये जाने का प्राविधान है। एन0यू0एल0एम0 की गाइड लाइन के अनुसार एक सामुदायिक आयोजक कम से कम 3000 शहरी गरीब परिवारो को आच्छादित करेगा। सामुदायिक आयोजक शहरी गरीबो से निकट और सीधे सम्पर्क में रहेगा तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समस्त लाभो को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगा। सामुदायिक आयोजक के कार्य एवं दायित्व शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव, पारिश्रमिक तथा भर्ती की प्रक्रिया आदि का विस्तृत विवरण क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण उपघटक के दिशा–निर्देशों में किया गया है।

10. सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) की शैक्षिक योग्यता एवं वर्ष अनुभव, कार्य क्षेत्र, मुख्य उत्तरदायित्व निम्नवत् होगाः–

कार्य क्षेत्रः–

1. सी0ओ0 को प्रारम्भ में संविदा पर दो वर्ष के लिए रखा जायेगा जिसकी संविदा प्रत्येक दो वर्ष पर कार्य मूल्यांकन (Performance appraisal) के आधार पर बढायी जायेगी।
2. सी0ओ0 सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, के अधीन कार्य करेगा तथा उसे या उसके द्वारा नामित अधिकारी को सीधे रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
3. सी0ओ0 को क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषा में लिखने एवं बोलने पर अच्छा नियन्त्रण होना चाहिए।

शैक्षिक योग्यता एवं अनुभवः–

1. सी0ओ0 की शैक्षिक योग्यता किसी भी वर्ग में इण्टरमीडिएट (10+2) होगी।
2. सी0ओ0 के पद के लिए सामाजिक विकास के कार्यो में लोगो के साथ कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। साथ ही साथ कम्प्यूटर एम0एस0 आफिस– (वर्ड, एक्सल, पावर प्वाइंट, आदि) पर प्रवीण होना अपेक्षित होगा।
3. यदि पूर्व में रखे गये सी0ओ0 उक्त मानक पूर्ण कर रहें हो तो उनको चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

कार्य एवं उत्तरदायित्वः–

1. सी0ओ0 अपने कार्य क्षेत्र में शहरी गरीबों हेतु सामाजिक गतिशीलता (Social Mobilization) का कार्य करेगा और एन0यू0एल0एम0 समस्त लाभ उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।
2. समुदाय को समूह/संघो के गठन में सहयोग करना।
3. अपने कार्य क्षेत्र में मिशन के विभिन्न उपघटकों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं देखरेख आदि के कार्य में सहयोग करना।
4. समुदाय स्तर पर अवस्थापना, परिसम्पत्तियों एवं सामाजिक पहलू इत्यादि के व्यापक आंकडों का डेटाबेस विकसित करना और उनको यथासमय अपडेट करते रहना।
5. स्वयं सहायता समूहो (एस0एच0जी0) एवं उनके संघो सहित विकलांग व्यक्तियों के एस0एच0जी0 को सहयोग करते हुए सुदृढ़ बनाना।
6. शहरी गरीबों हेतु सामाजिक गतिशीलता (Social Mobilization) को सुनिश्चित करना।
7. एस0एच0जी0 बैंक लिंकजेज को प्रोत्साहित करना।
8. सरकार के विभिन्न विभागों से अभिसरण (Convergence) हेतु संपर्क स्थापित करना।
9. एन0यू0एल0एम0 संबंधी सर्वेक्षणों में सहायता करना।
10. विकास कार्यो यथा सामुदायिक कार्यो के क्रियान्वयन एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों के प्रचालन और रख–रखाव (ओ.एण्ड एम.) इत्यादि में सहयोग करना।
11. अच्छे अभ्यासों (Best Practices) का अभिलेखीकरण करना।
12. आवश्यकतानुसार समुदाय स्तर पर बैठकों और प्रशिक्षण का आयोजन करायेगा एवं उसमे प्रतिभाग करना।
13. मासिक रिपोर्ट तैयार कर जमा करना।

14. सिटी प्रोजेक्ट आफीसर द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य कार्यों को करना।

11. तकनीकी विशेषज्ञों और की सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) का पारिश्रमिक:-

1. राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) में नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञों को अधिकतम पारिश्रमिक रू0 75,000/- प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
2. शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0यू0) में नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञों को अधिकतम रू0 60,000/- प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
3. तकनीकी विशेषज्ञों को भुगतान किये जाने वाली पारिश्रमिक धनराशि की अधिकतम 40 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त धनराशि तकनीकी विशेषज्ञों के यात्रा टी0ए0/डी0ए0 ठहरने एवं भोजन इत्यादि, कार्यालय व्यय, एकाउटेन्ट, डाटाइन्टरी आपरेटर, मल्टी टास्किंग ऑफिशियंल्स आदि पर व्यय की जायेगी।
4. 02 वर्ष बाद तकनीकी विशेषज्ञों के पारिश्रमिक दरों को पुनरीक्षित कर अधिकतम 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
5. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई में रखे जाने वाले सामुदायिक आयोजको (सी0ओ0) अधिकतम पारिश्रमिक रू0 10000/- प्रतिमाह होगा।

12. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही मिशन निदेशक/निदेशक सूडा द्वारा समयबद्ध रूप में सुनिश्चित की जायेगी।

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

सं-1061 (1)69-1-13-14(104)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
2 निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0।
3 निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उ0प्र0।
4 निजी सचिव, मा0 श्रम व रोजगार मंत्री, उ0प्र0।
5 निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उ0प्र0।
6 निजी सचिव, मा0 उद्योग मंत्री, उ0प्र0।
7 निजी सचिव, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उ0प्र0।
8 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
9 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
10 सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
11 प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
12 प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
13 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
14 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
15 प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
16 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
17 प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
18 प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0शासन।

19 प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
20 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0शासन।
21 निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
22 मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
23 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या– 1061 /69–1–13–14(104)/2013
लखनऊः दिनांक 10 जुलाई, 2014

शुद्धि–पत्र

कार्यालय ज्ञाप संख्या–1061/69–1–13–14 (104)/2013, दिनांक 27.06.2014 द्वारा राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) तथा शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0यू0) के तकनीकी विशेषज्ञों एवं शहर प्रबंधन इकाई के सामुदायिक आयोजकों के कार्य क्षेत्र, शैक्षिक योग्यता तथा चयन की प्रकिया संबंधी दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.06.2014 के प्रस्तर–5 में तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजकों को वाह्य एजेन्सी के माध्यम से रखे जाने की प्रकिया का प्राविधान किया गया है। वाह्य एजेन्सी के माध्यम से रखे गये कार्मिक संविदा पर नियुक्त कार्मिक नही होगे। अतः इसके दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.06.2014 का प्रस्तर–6 "तकनीकी विशेषज्ञों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन", प्रस्तर–7 "तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा समाप्ति" एवं प्रस्तर–10 (1) "सी0ओ0 को प्रारम्भ में संविदा पर दो वर्ष के लिये रखा जायेगा, जिसकी संविदा प्रत्येक 02 वर्ष पर कार्य मूल्यांकन (Performance appraisal) के आधार पर बढ़ायी जायेगी" को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।

2– उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.06.2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष प्राविधान यथावत रहेगें।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव

संख्याः– 1061 (1)69–1–13–14(104)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
2 निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0।
3 निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उ0प्र0।
4 निजी सचिव, मा0 श्रम व रोजगार मंत्री, उ0प्र0।
5 निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उ0प्र0।
6 निजी सचिव, मा0 उद्योग मंत्री, उ0प्र0।
7 निजी सचिव, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उ0प्र0।
8 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
9 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
10 सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
11 प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
12 प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
13 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
14 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
15 प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
16 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।

17 प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
18 प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0शासन।
19 प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
20 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0शासन।
21 निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
22 मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
23 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
24 निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ।
25 समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उ0प्र0।
26 समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
27 समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी (डूडा), उ0प्र0।
28 समस्त उप नगर अधिकारी, नगर निगम, उ0प्र0।
29 समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
30 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0-13 का उत्तर पीछे पृष्ठ ... पर)

जनपद शामली में विधान सभा क्षेत्र कैराना में पड़ने वाले मार्गों के नाम व लंम्बाई एवं वर्तमान स्थिति का विवरण

क्र0सं0	मार्ग के नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	वर्तमान स्थिति
1	राज्य राज मार्ग:– 01		
1	कैराना खतौली मार्ग रा0ज राज मार्ग श्रेणी का मार्ग है	19.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
2	अन्य जिला मार्ग:– 13		
1	कैराना निरीक्षण भवन मार्ग	0.150	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
2	बिडौली चौसाना मार्ग	12.900	मार्ग की कुल लम्बाई 12.900 कि0मी0 है। लम्बाई 6.06 कि0मी0 में, जिसकी स्वीकृति शासनादेश सं0 368/2020/215(3)/23.11.2020–1/2(143)/2020 दिनांक 08.12.2020 के द्वारा प्राप्त हुई है। निविदा आमंत्रित कर अनुबंध गठन की प्रक्रिया में है। शेष लम्बाई में मार्ग की दशा संतोष जनक है।
3	भूरा से जन्धेड़ी मंगलपुर होते हुए सुनहेटी बरनावी मार्ग	6.250	उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्वामित्व का मार्ग है।
4	ऊन चौसाना मार्ग से ग्राम टोडा गंगारामपुर खेड़की होते हुए शामली शामला होते हुए मोनेट शुगर मिल तक मार्ग	6.00	3.900 किमी0 लम्बाई 2021–22 की नवीनीकरण की कार्य योजना में प्रस्तावित है। शेष लम्बाई 2.100 किमी0 पी0एम0जी0एस0वाई0 2021–21 की नवीनीकरण कार्य योजना में प्रस्तावित है।
5	चौसाना बस्सी चुन्धियारी मार्ग वाया शामली श्यामला मार्ग	9.00	5.00 किमी0 लंम्बाई 2021–22 की नवीनीकरण की कार्य योजना में प्रस्तावित है। शेष लंम्बाई में यातायात का आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है।
6	कैराना खुरगान सुनहेटी बरनावी मार्ग	14.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
7	ऊन चौसाना मार्ग	9.900	मार्ग पर पैच रिपेयर का कार्य कराया गया है। मार्ग पूर्णतः गढढामुक्त है तथा यातायात का आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है।
8	मेरठ करनाल मार्ग से मंसूरा डोकपुरा मार्ग	8.750	वर्ष 2021–22 की नवीनीकरण की कार्ययोजना में सम्मलित कर रु0 70.00 लाख का आगणन गठित कर प्रेषित की प्रक्रिया में है।
9	पानीपत खटीमा मार्ग का कैराना शहरी भाग	4.190	नगर पालिका कैराना के स्वामित्व का मार्ग है।
10	चौसाना से मुण्डेट मार्ग	15.600	आबादी भाग में सी0सी0 का कार्य स्वीकृत है एवं 4.00 किमी0 नवीनीकरण में प्रस्तावित है शेष लम्बाई में आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है।
11	मेरठ करनाल मार्ग पर टिटौली पुलिया से प्रारम्भ होकर बामनौली कसेरवा होते हुए पानीपत खटीमा मार्ग तक	6.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
12	कैराना झिंझाना ऊन थानाभवन मार्ग	43.100	विधान सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली में कैराना झिंझाना मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग की कुल लम्बाई 12.00 किमी0 है। वर्तमान में मार्ग को गढ्डामुक्त कर दिया गया है एवं सुगम यातायात हेतु उपयुर्क्त है। मार्ग पर वर्तमान पी0सी0व्यू0–16090 है। मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण की आंकलित लगात धनराशि रुपये 1799.83 लाख का आगणन गठित कर प्रेषित किया गया है। जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।
13	कैराना तितरवांडा इस्सोपुरटील मार्ग	3.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।

4	ग्रामीण सम्पर्क मार्ग:-143		
1	केराना आर्यपुरी से केराना बाईपास मार्ग	0.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
2	केराना बाईपास से भूरा कण्डेला मार्ग	4.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
3	डण्डखेड़ा से गढ़ी रामकौर मार्ग	2.150	मार्ग 2020–21 में विशेष मरम्मत में प्रस्तावित है।
4	पावटी कला से बीबीपुर हटिया मार्ग	1.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
5	कनाल पुर सम्पर्क मार्ग	0.600	उक्त मार्ग 2021–22 की नवीनीकरण की कार्य योजना में प्रस्तावित है।
6	भूरा से ग्रन्द्राव मार्ग	4.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
7	मलकपुर से मौहम्दपुर राई मार्ग	1.425	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
8	केराना झिंझाना मार्ग गोरावान मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
9	मलकपुर से गन्द्राव मार्ग	1.180	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
10	केराना झिंझाना मार्ग	0.450	मार्ग 2021–22 की नवीनीकरण की कार्य योजना में प्रस्तावित है।
11	पानीपत खटीमा मार्ग	1.420	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
12	केराना सितरवाडा से बुच्चाखेडी मार्ग	0.950	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
13	गंगेरू से के0जी0आई0टी0 मार्ग वाया गढ़ी रामकौर मार्ग	2.300	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
14	मामौर से सहपत मार्ग	1.00	पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्वामित्व का मार्ग है
15	पंजीठ से बुच्चा खेडी मार्ग	1.800	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
16	खेड़ा कुतान से जनपद बागपत सीमा तक	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
17	झिंझाना ऊन मार्ग से रंगाना मार्ग	1.825	उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई की 2020–21 की नवीनीकरण की कार्य योजना में प्रस्तावित है।
18	झिंझाना ऊन मार्ग से नीमगंगली मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
19	मेरठ करनाल मार्ग के कि0मी0 80 से बीबीपुर मार्ग	1.250	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
20	चौसाना गढ़ी असनपुर मार्ग से दथेड़ा की ओर	1.080	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
21	शामली श्यामला मार्ग से लावदाऊपुर मार्ग	2.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
22	ऊन से खेड़ा माऊ मार्ग	2.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
23	दथेड़ा से पान्धुपुरा सहारनपुर सीमा तक	2.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
24	शामली श्यामला मार्ग से खेड़ी खुशनाम मार्ग	3.200	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
25	मेरठ करनाल मार्ग से उलादीनपुर मार्ग	1.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
26	खानपुर जटान से डेरा भगीरथ मार्ग	0.770	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
27	अलाउदीन नगर से खोखसा होते हुए सीगरा आमवाली बाबरिया कालोनी तक	1.390	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
28	केराना झिंझाना ऊन थानाभवन मार्ग से ऊन सम्पर्क मार्ग	0.860	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
29	के0जी0यू0टी0 मार्ग के कि0मी0 21 से मंमेडी शाहपुर मार्ग	1.920	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
30	मुण्डेट से खेड़ी होते हुए दथेड़ा की ओर	2.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
31	केराना राजवाहे से केराना कांधला मार्ग	4.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
32	म्यान कस्बे से शीतलागढ़ी मार्ग	1.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।

33	मेरठ करनाल मार्ग से उल्हैनी मार्ग	1.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
34	ऊन थानाभवन मार्ग से बझेडी मार्ग	0.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
35	मेरठ करनाल मार्ग से लूबरी मार्ग	2.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
36	झिंझाना ऊन मार्ग से होसंगपुर मार्ग	3.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
37	बीबीपुर हटिया से डेरा सरदार मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
38	भूरा से कण्डेला मार्ग	2.750	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
39	हिंगोखेडी से कसेरवा राजवाहे की पुलिया मार्ग	1.940	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
40	पीरमाजरा से कैराना रामडा मार्ग	1.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
41	मेरठ करनाल मंसुरा मार्ग से वेदखेडी मार्ग	0.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
42	ऊन चौसाना मार्ग से बल्लामाजरा मार्ग	0.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
43	चौसाना मुण्डेट मार्ग से नाई नंगला मार्ग	2.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
44	झिंझाना ऊन मार्ग से सिकन्दपुर मार्ग	0.250	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
45	कैराना झिझाना मार्ग के किमी0 12 से जमालपुर पावटी कलां होते हुए बीबीपुर हटिया मार्ग	4.700	उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई के स्वामित्व का मार्ग है।
46	शामली कैराना रोड से जगनपुर मार्ग	2.300	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
47	बेहडा से रंगाना मार्ग	1.400	उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 की 2021–21 कार्य योजना में प्रस्तावित है।
48	मेरठ करनाल मार्ग से रामनगर मार्ग	1.590	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
49	कैराना झिंझाना मार्ग से रज्जाक नगर मार्ग	1.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
50	झाडखेडी से बुच्चाखेडी होते हुए पंजीठ मामौर मार्ग	3.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
51	मन्ना माजरा बाईपास मार्ग के छूटे भाग का निर्माण कार्य	1.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
52	झाडखेडी से ऊँचा गांव मार्ग	3.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
53	गंगेरू से इस्सोपुरटील से कन्या जूनियर हाईस्कूल इस्सोपुरटील मार्ग	1.780	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
54	नंगला राई से रामडा मार्ग	1.300	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
55	कैराना तितरवाडा से ऊचा गांव मार्ग	2.850	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
56	डुंडुखेडा से इस्सोपुरटील मार्ग	2.700	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
57	पानीपत खटीमा मार्ग से ऐरटी मार्ग	5.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
58	शामली कैराना मार्ग से शेखुपुररा मार्ग	2.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
59	कांधला इस्सोपुरटील मार्ग से इस्सोपुर राजबाह मार्ग	1.200	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
60	जहानपुरा से अलीपुर मार्ग	1.040	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
61	कैराना से जहानपुरा मार्ग	2.800	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
62	कैराना झिंझाना मार्ग से सरकारी अस्पताल मार्ग	0.350	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
63	टिटौली कसेरवा मार्ग	1.835	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
64	पानीपत खटीमा माग्र से पंजीठ होते हुए मामौर ग्राम से तीतरवाडा बाईपास होते हुए ऊँचा गाव	7.705	उक्त मार्ग पी0एसम0जी0एस0वाई के स्वामित्व का मार्ग है।

क्र0	पावटा कला से जगधडा मार्ग	1.300	उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्वामित्व का मार्ग है।
66	कैराना बाईपास से जाहिद के मकान तक	0.830	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
67	मौहम्मदपुर राई से नंगला राई तथा कैराने की ओर	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
68	ल्हेडी खुर्द लिंक मार्ग	2.950	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
69	मवी गैर अहलमाल मार्ग	0.800	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
70	मण्डावर लिंक मार्ग	1.200	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
71	कैराना राजवाहे की पटरी मार्ग	5.800	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
72	कैराना तितरवाडा से सहपत मार्ग	1.630	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
73	कैराना काधला मार्ग से किशोरपुर	1.200	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
74	भोग माजरा से मिलवाली काली सड़क	3.550	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
75	मंसुरा से वेदखेडी मार्ग से मंगलपुर होते हुए बीबीपुर जलालाबाद मार्ग	2.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
76	कैराना इस्सोपुरटोल मार्ग से गंगेरू बाया गढीरामकौर मार्ग	3.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
77	खन्द्रावली से बिन्दडा मार्ग	2.200	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
78	ऊन चौसाना मार्ग के कि0मी0 07 से महेन्द्रगढ मार्ग	2.240	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
79	बिडौली चौसाना मार्ग से उदयपुर मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
80	मेरठ करनाल मार्ग से तिसंग मार्ग	3.600	उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्वामित्व का मार्ग है।
81	तिसंग से औदरी मार्ग	0.720	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
82	आमवाली से मछरौली मार्ग	3.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
83	मछरौली बाईपास मार्ग	1.200	उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 2020–21 की नव निर्माण की कार्ययोजना में स्वीकृत है।
84	बिडौली चौसाना मार्ग से अलीपुर मार्ग	1.010	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
85	मेरठ करनाल मार्ग से मंसूरा वेदखेडी मार्ग	1.550	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
86	बिडौली चौसाना मार्ग से अलीपुर मार्ग	2.250	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
87	होशंगपुर सम्पर्क मार्ग	0.330	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
88	अभयनगर सम्पर्क मार्ग	0.220	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
89	अकबरपुर सुन्हेटी से पठेड मार्ग	1.500	उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्वामित्व का मार्ग है।
90	मंसुरा से युसुफचीतरा मार्ग	3.400	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
91	खुरगान नया गाव से मण्डावर मार्ग	2.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
92	कैराना बाईपस मार्ग से नंगला राई मार्ग	5.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
93	कैराना खुरगान मार्ग से बसेडा मार्ग	1.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
94	मेरठ करनाल मार्ग के कि0मी0 75 से रज्जाक नगर मार्ग	0.610	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
95	जमालपुर से पावटी खुर्द मार्ग	3.050	उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्वामित्व का मार्ग है।
96	कैराना सालहाखेडी खन्द्रावली मार्ग	6.610	उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत है।
97	दथेडा से बसी चुन्धयारी मार्ग	3.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।

98	[illegible]	8.560	मार्ग का दशा संतोषजनक है।
99	मेरठ करनाल मार्ग से बिडौली सईद मार्ग	1.050	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
100	चौसाना से अमलापुर मार्ग	0.260	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
101	ऊन से चौन्दाहेडी मार्ग	0.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
102	मेरठ करनाल मार्ग से घरमपुरा	1.125	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
103	मुरा से कसेरवा खुर्द मार्ग	5.665	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
104	चौसाना बिडौल से गुज्जरपुर मार्ग	1.185	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
105	नगला राई से भडी मार्ग	3.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
106	मेरठ करनाल मार्ग से दमेडी बुजुर्ग मार्ग	2.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
107	सीगरा अलीनगर झिझाना मार्ग से रंगाना फार्म मार्ग	2.340	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
108	कैराना काँधला मार्ग के किमी0 4 से आई0टी0आई0 तक	1.340	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
109	सुन्दर नगर सम्पर्क मार्ग	0.400	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
110	सिंगापुर सम्पर्क मार्ग	0.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
111	झिझाना ऊन से मेरठ करनाल मार्ग वाया चन्दनपुरी सम्पर्क मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
112	भूरा सम्पर्क मार्ग	1.950	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
113	बुद्धपुरा से बघाला मार्ग	1.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
114	के0के0 रोड से डुंधार मार्ग	3.300	उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्वामित्व का मार्ग है।
115	जन्धेडी से मंगलपुर मार्ग से सुन्हटी मार्ग	2.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
116	के0टी0आई0टी0 से डुन्डखेडा मार्ग	0.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
117	पानीपत खटीमा मार्ग से मायापुर मार्ग	2.300	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
118	पानीपत खटीमा मार्ग से माजरा मार्ग	1.050	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
119	पानीपत खटीमा मार्ग से हिंगोखेडी मार्ग	1.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
120	कण्डला बाईपास मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
121	कैराना पब्लिक कॉलेज से जगानपुरा मार्ग	3.700	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
122	चौसाना मुण्डट मार्ग से दाढीनगर मार्ग	2.135	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
123	चौसाना मुण्डट मार्ग से कुण्डा मार्ग	1.380	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
124	सकोती नाई नंगला मार्ग	1.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
125	बिडौली चौसाना से लक्ष्मीपुरा मार्ग	2.510	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
126	मेरठ करनाल मार्ग से आल्हदपुर मार्ग	2.480	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
127	सुबरी से थाली सम्पर्क मार्ग	2.080	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
128	मेरठ करनाल मार्ग से खेडी जुनारदार याहियापुर शाहपुर मार्ग	2.800	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
129	तिसंग जैनपुर मार्ग	0.800	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
130	सुबरी से उल्हैनी मार्ग	0.915	मार्ग की दशा संतोषजनक है।

131	मरु करनाल मार्ग स खडा अजाजपुर मार्ग	3.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
132	मंसूरा मार्ग के किमी0 02 से पांवटी खुर्द मार्ग	1.660	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
133	मंसूरा मार्ग से रतौध होते हुए श्यामनगर मार्ग	2.060	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
134	मंसूरा मार्ग से अशरफपुर मार्ग	0.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
135	मंसूरा चौतरा मार्ग से फतेहपुर मार्ग	1.060	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
136	काजीखेडा से डोकपुरा मार्ग	0.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
137	हरसाना से मंगेडी शाहपुर मार्ग	1.400	उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 की 2020–21 की नवःनिर्माण की कार्य योजना मे स्वीकृत है।
138	खेखडा से बसी की	0.700	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
139	पानीपत खटीमा मार्ग से रामडा मार्ग	2.050	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
140	भामौर से सरदारो के डेरे से होकर यमुना बांध तक	2.200	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
141	सरदारो के डेरे से गडरियो के डेरे तक	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
142	मुकंदपुर सम्पर्क मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
143	खिंझाना से अगडीपुर मार्ग	1.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
शामली

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0-25 का उत्तर पीछे पृष्ठ ... पर)

जनपद शामली में विधान सभा क्षेत्र कैराना में पडने वाले मार्गो के नाम व लम्बाई एवं वर्तमान स्थिति का विवरण

क्र0 सं0	मार्गो के नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	वर्तमान स्थिति
1	**राज्य राज मार्गः– 01**		
1	कैराना खतौली मार्ग	19.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
2	**अन्य जिला मार्गः– 13**		
1	कैराना निरीक्षण भवन मार्ग	0.150	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
2	बिडौली चौसाना मार्ग	12.900	इस मार्ग की 6.06 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति शासनादेश सं0 368/2020/215(आ)/23–11–2020–1/2(143)/2020 दिनांक 18.12.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष निविदा आमंत्रित कर अनुबंध गठन की कार्यवाही प्रकियाधीन है। शेष लम्बाई में मार्ग की दशा संतोषजनक है।
3	भूरा से जन्धेडी मंगलपुर होते हुए सुनहेटी बरनावी मार्ग	6.250	उक्त मार्ग वर्ष 2021–22 की नवीनीकरण कार्य योजना में प्रस्तावित
4	ऊन चौसाना मार्ग से ग्राम टोडा गंगारामपुर खेडकी होते हुए शामली शामला होते हुए मोनेट शुगर मिल तक मार्ग	6.00	इस मार्ग के 3.900 किमी0 लंम्बाई का भाग वर्ष 2021–22 की नवीनीकरण की कार्य योजना में प्रस्तावित है। शेष लम्बाई 2.100 किमी0 पी0एम0जी0एस0वाई0 2021–22 की नवीनीकरण कार्य योजना में प्रस्तावित है।
5	चौसाना बसी चुन्धियारी मार्ग वाया शामली श्यामला मार्ग	9.00	इस मार्ग के 5.00 किमी0 लंम्बाई का भाग 2021–22 की नवीनीकरण की कार्य योजना में प्रस्तावित है। शेष लम्बाई में यातायात का आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है।
6	कैराना खुरगान सुन्हेटी बरनावी मार्ग	14.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
7	ऊन चौसाना मार्ग	9.900	मार्ग पर पैच रिपेयर का कार्य कराया गया है। मार्ग पूर्णतः गड्ढामुक्त है तथा यातायात का आवगमन सुचारू रूप से हो रहा है।
8	मेरठ करनाल मार्ग से मंसूरा डोकपुरा मार्ग	8.750	उक्त मार्ग को वर्ष 2021–22 की नवीनीकरण की कार्ययोजना में सम्मलित कर रु0 70.00 लाख का आगणन गठित कर प्रेषित किये जाने की प्रक्रिया में है।
9	पानीपत खटीमा मार्ग का कैराना शहरी भाग	4.019	यह मार्ग वर्तमान मे नगर पालिका कैराना के अधीन है।
10	चौसाना से मुण्डेट मार्ग	15.600	इस मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 का कार्य स्वीकृत है एवं 4.00 किमी0 लम्बाई नवीनीकरण मे प्रस्तावित है। शेष लम्बाई मे आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है।
11	मेरठ करनाल मार्ग पर टिटौली पुलिया से प्रारम्भ होकर बामनौली कसेरवा होते हुए पानीपत खटीमा मार्ग तक	6.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
12	कैराना झिंझाना ऊन थानाभवन मार्ग	43.100	विधाना सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली में कैराना झिंझाना ऊन थानाभवन मार्ग (अन्य जिला मार्ग) की कुल 12.00 किमी0 लम्बाई को वर्तमान में गढ्डामुक्त कर दिया गया है, जो सुगम यातायात हेतु उपयुक्त है। इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु लागत रू0 1799.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 146/2021/380(आ)/23–11–2020–1/2(284)/2020 दिनांक 19.02.2021 द्वारा प्रदान की गयी है।
13	कैराना तितरवाडा इस्सोपुरटील मार्ग	3.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
3	**ग्रामीण सम्पर्क मार्गः–143**		
1	कैराना आर्यपुरी से कैराना बाईपास मार्ग	0.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।

2	कैराना बाईपास से भूरा कण्डेला मार्ग	4.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
3	डूण्डूखेडा से गढी रामकौर मार्ग	2.150	यह मार्ग वर्ष 2020–21 में विशेष मरम्मत में प्रस्तावित है।
4	पांवटी कला से बीबीपुर हटिया मार्ग	1.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
5	कमाल पुर सम्पर्क मार्ग	0.600	उक्त मार्ग वर्ष 2021–22 की नवीनीकरण की कार्य योजना में प्रस्तावित है।
6	भूरा से ग्रन्द्राव मार्ग	4ण्00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
7	मलकपुर से मौहम्दपुर राई मार्ग	1.425	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
8	कैराना झिंझाना मार्ग गोगवान मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
9	मलकपुर से गन्द्राव मार्ग	1.180	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
10	कैराना झिझाना मार्ग	0.450	यह मार्ग वर्ष 2021–22 की नवीनीकरण की कार्य योजना में प्रस्तावित है।
11	पानीपत खटीमा मार्ग	1.420	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
12	कैराना तितरवाडा से बुच्चाखेडी मार्ग	0.950	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
13	गंगेरू से के0जी0आई0टी0 मार्ग वाया गढी रामकौर मार्ग	2.300	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
14	मामौर से सहपत मार्ग	1.00	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
15	पंजीठ से बुच्चा खेडी मार्ग	1.800	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
16	खेडा कुर्तान से जनपद बागपत सीमा तक	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
17	झिंझाना ऊन मार्ग से रंगाना मार्ग	1.825	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
18	झिंझाना ऊन मार्ग से नौनांगली मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
19	मेरठ करनाल मार्ग के किमी0 80 से बीबीपुर मार्ग	1.250	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
20	चौसाना गढी असनपुर मार्ग से दथेडा की ओर	1.080	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
21	शामली श्यामला मार्ग से लावदाऊपुर मार्ग	2.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
22	ऊन से खेडा भाऊ मार्ग	2.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
23	दथेडा से पान्थुपुरा सहारनपुर सीमा तक	2.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
24	शामली श्यामला मार्ग से खेडी खुशनाम मार्ग	3.200	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
25	मेरठ करनाल मार्ग से उलादीनपुर मार्ग	1.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
26	खानपुर जटान से डेरा भगीरथ मार्ग	0.770	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
27	अलाउदीन नगर से खोखसा होते हुए सीगरा आमवाली बावरिया कालोनी तक	1.390	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
28	कैराना झिंझाना ऊन थानाभवन मार्ग से ऊन सम्पर्क मार्ग	0.860	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
29	के0जी0यू0टी0 मार्ग के किमी0 21 से भमेडी शाहपुर मार्ग	1.920	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
30	मुण्डेट से खेडी होते हुए दथेडा की ओर	2.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
31	कैराना राजवाहे से कैराना कांधला मार्ग	4.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
32	म्यान कस्बे से शीतलागढी मार्ग	1.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
33	मेरठ करनाल मार्ग से उल्हैनी मार्ग	1.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
34	ऊन थानाभवन मार्ग से बझेडी मार्ग	0.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।

35	मेरठ करनाल मार्ग से सूबरी मार्ग	2.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
36	झिंझाना ऊन मार्ग से होसंगपुर मार्ग	3.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
37	बीबीपुर हटिया से डेरा सरदार मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
38	भूरा से कण्डेला मार्ग	2.750	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
39	हिंगोखेडी से कसेरवा राजवाहे की पुलिया मार्ग	1.940	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
40	पीरमाजरा से कैराना रामडा मार्ग	1.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
41	मेरठ करनाल मंसुरा मार्ग से वेदखेडी मार्ग	0.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
42	ऊन चौसाना मार्ग से बल्लामाजरा मार्ग	0.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
43	चौसाना मुण्डेट मार्ग से नाई नंगला मार्ग	2.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
44	झिंझाना ऊन मार्ग से सिकन्दपुर मार्ग	0.250	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
45	कैराना झिझाना मार्ग के किमी0 12 से जमालपुर पावटी कलां होते हुए बीबीपुर हटिया मार्ग	4.700	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
46	शामली कैराना रोड से जगनपुर मार्ग	2.300	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
47	बेहडा से रंगाना मार्ग	1.400	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
48	मेरठ करनाल मार्ग से रामनगर मार्ग	1.590	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
49	कैराना झिंझाना मार्ग से रज्जाक नगर मार्ग	1.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
50	झाडखेडी से बुच्चाखेडी होते हुए पंजीठ मामौर मार्ग	3.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
51	मन्ना माजरा बाईपास मार्ग के छूटे भाग का निर्माण कार्य	1.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
52	झाडखेडी से ऊँचा गांव मार्ग	3.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
53	गंगेरू से इस्सोपुरटील से कन्या जूनियर हाईस्कूल इस्सोपुरटील मार्ग	1.780	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
54	नंगला राई से रामडा मार्ग	1.300	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
55	कैराना तितरवाडा से ऊचा गांव मार्ग	2.850	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
56	डुंडुखेडा से इस्सोपुरटील मार्ग	2.700	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
57	पानीपत खटीमा मार्ग से ऐरटी मार्ग	5.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
58	शामली कैराना मार्ग से शेखुपुररा मार्ग	2.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
59	कांधला इस्सोपुरटील मार्ग से इस्सोपुर राजबाह मार्ग	1.200	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
60	जहानपुरा से अलीपुर मार्ग	1.040	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
61	कैराना से जहानपुरा मार्ग	2.800	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
62	कैराना झिंझाना मार्ग से सरकारी अस्पताल मार्ग	0.350	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
63	टिटौली कसेरवा मार्ग	1.835	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
64	पानीपत खटीमा माग्र से पंजीठ होते हुए मामौर ग्राम से तीतरवाडा बाईपास होते हुए ऊँचा गाव	7.705	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
65	पांवटी कला से जन्धेडी मार्ग	1.300	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
66	कैराना बाईपास से जाहिद के मकान तक	0.830	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
67	मौहम्मदपुर राई से नंगला राई तथा कैराने की ओर	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
68	दभेडी खुर्द लिंक मार्ग	2.950	मार्ग की दशा संतोषजनक है।

69	मवी गैर अहतमाल मार्ग	0.800	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
70	मण्डावर लिक मार्ग	1.200	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
71	कैराना राजवाहे की पटरी मार्ग	5.800	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
72	कैराना तितरवाडा से सहपत मार्ग	1.630	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
73	कैराना कांधला मार्ग से किशोरपुर	1.200	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
74	भोग माजरा से मिलवाली काली सडक	3.550	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
75	मंसुरा से वेदखेडी मार्ग से मंगलपुर होते हुए बीबीपुर जलालाबाद मार्ग	2.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
76	कैराना इस्सोपुरटील मार्ग से गंगेरू वाया गढीरामकौर मार्ग	3.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
77	खन्द्रावली से बिन्दडा मार्ग	2.200	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
78	ऊन चौसाना मार्ग के किमी0 07 से महेन्द्रगढ मार्ग	2.240	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
79	बिडौली चौसाना मार्ग से उदपुर मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
80	मेरठ करनाल मार्ग से तिसग मार्ग	3.600	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
81	तिसंग से औदरी मार्ग	0.720	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
82	आमवाली से मछरौली मार्ग	3.100	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
83	मछरौली बाईपास मार्ग	1.200	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
84	बिडौली चौसाना मार्ग से अलीपुर मार्ग	1.010	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
85	मेरठ करनाल मार्ग से मंसूरा वेदखेडी मार्ग	1.550	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
86	बिडौली चौसाना मार्ग से साल्हापुर मार्ग	2.250	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
87	होशंगपुर सम्पर्क मार्ग	0.330	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
88	अभयनगर सम्पर्क मार्ग	0.220	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
89	अकबरपुर सुन्हैटी से पठेड मार्ग	1.500	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
90	मंसुरा से यूसुफचौतरा मार्ग	3.400	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
91	खुरगान नया गाव से मण्डावर मार्ग	2.100	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
92	कैराना बाईपस मार्ग से नंगला राई मार्ग	5.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
93	कैरान खुरगान मार्ग से बसेडा मार्ग	1.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
94	मेरठ करनाल मार्ग के किमी0 75 से रज्जाक नगर मार्ग	0.610	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
95	जमालपुर से पावटी खुर्द मार्ग	3.050	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
96	कैराना साल्हाखेडी खन्द्रावली मार्ग	6.610	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
97	दथेडा से बसी चुन्धयारी मार्ग	3.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
98	सिंगरा से अलीनगर मार्ग	8.560	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
99	मेरठ करनाल मार्ग से बिडौली सईद मार्ग	1.050	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
100	चौसाना से अमलापुर मार्ग	0.260	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
101	ऊन से चौन्दाहेडी मार्ग	0.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
102	मेरठ करनाल मार्ग से धरमपुरा	1.125	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
103	भूरा से कसेरवा खुर्द मार्ग	5.665	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
104	चौसाना बिडौल से गुज्जरपुर मार्ग	1.185	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
105	नगला राई से भडी मार्ग	3.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
106	मेरठ करनाल मार्ग से दभेडी बुजुर्ग	2.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।

	मार्ग		
107	सींगरा अलीनगर झिंझाना मार्ग से रंगाना फार्म मार्ग	2.340	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
108	कैराना कांधला मार्ग के किमी0 4 से आई0टी0आई0 तक	1.340	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
109	सुन्दर नगर सम्पर्क मार्ग	0.400	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
110	सिंगापुर सम्पर्क मार्ग	0.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
111	झिंझाना ऊन से मेरठ करनाल मार्ग वाया चन्दनपुरी सम्पर्क मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
112	भूरा सम्पर्क मार्ग	1.950	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
113	बुद्वपुरा से बराला मार्ग	1.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
114	के0के0 रोड से डुंधार मार्ग	3.300	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
115	जन्धेडी से मंगलपुर मार्ग से सुन्हेटी मार्ग	2.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
116	के0टी0आई0टी0 से डुन्डुखेडा मार्ग	0.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
117	पानीपत खटीमा मार्ग से मायापुर मार्ग	2.300	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
118	पानीपत खटीमा मार्ग से माजरा मार्ग	1.050	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
119	पानीपत खटीमा मार्ग से हिंगोखेडी मार्ग	1.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
120	कण्डेला बाईपास मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
121	कैराना पब्लिक कॉलेज से जगनपुरा मार्ग	3.700	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
122	चौसाना मुण्डेट मार्ग से दाढीनगर मार्ग	2.135	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
123	चौसाना मुण्डेट मार्ग से कुण्डा मार्ग	1.380	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
124	सकोती नाई नंगला मार्ग	1.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
125	बिडौली चौसाना से लक्ष्मीपुरा मार्ग	2.510	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
126	मेरठ करनाल मार्ग से आन्नदपुर मार्ग	2.480	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
127	सूबरी से थाली सम्पर्क मार्ग	2.080	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
128	मेरठ करनाल मार्ग से खेडी जुनारदार याहियापुर शाहपुर मार्ग	2.800	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
129	तिसंग जैनपुर मार्ग	0.800	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
130	सूबरी से उल्हैनी मार्ग	0.915	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
131	मेरठ करनाल मार्ग से खेडी अजीजपुर मार्ग	3.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
132	मंसूरा मार्ग के किमी0 02 से पांवटी खुर्द मार्ग	1.660	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
133	मंसूरा मार्ग से रतौंध होते हुए श्यामनगर मार्ग	2.060	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
134	मंसूरा मार्ग से अशरफपुर मार्ग	0.500	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
135	मंसूरा चौतरा मार्ग से फतेहपुर मार्ग	1.060	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
136	काजीखेडा से डोकपुरा मार्ग	0.900	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
137	हरसाना से भमेडी शाहपुर मार्ग	1.400	उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया गया है।
138	दथेडा से बसी की	0.700	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
139	पानीपत खटीमा मार्ग से रामडा मार्ग	2.050	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
140	मामौर से सरदारो के डेरे से होकर यमुना बांध तक	2.200	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
141	सरदारो के डेरे से गडरियो के डेरे तक	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
142	मुकंदपुर सम्पर्क मार्ग	1.00	मार्ग की दशा संतोषजनक है।
143	झिंझाना से अगडीपुर मार्ग	1.600	मार्ग की दशा संतोषजनक है।

पी0एस0यू0पी0-एल0-90 विधान सभा (147)-02-06-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।